रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-73

REGISTERED No. D. (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 14, 1980/ज्येष्ठ 24, 1902
No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 14, 1980/JYAISTHA 24, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence by Central Authorities other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 14 मई, 1980

का० आ० 1582.--निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 20-तिरुपती (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मुनास्वामी, थीम्माराजु, खन्द्रीजा, पुत्तर तालुक, चित्तूर जिला (आन्ध्र प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मुनास्वामी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० आ०प्र०-लो०स०/20/80(4)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDERS

New Delhi, the 14th May, 1980

S.O. 1582.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Munaswamy, Thimmaraju Khandriga, Puttar Taluk, Chittoor District (Andhra Pradesh), a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 20-Tirupati (SC) Constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Munaswamy to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-HP/20/80(4)]

नई दिल्ली, 23 मई, 1980

का० आ० 1583.--यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 9-त्रिचुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री के० आर० माधवन, पो०आ० वेट्टुकड, त्रिचुर-5 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री के० भास्करन माधवन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० केरल-लो०स०/9/80 (1)]

New Delhi, the 23rd May, 1980

S.O. 1583.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri K. R. Madhavan, P.O. Vettukad, Trichur-5 (Kerala), a contesting candidate for general election to the House of People held in January, 1980 from 9-Trichur Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri K. R. Madhavan to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-HP/9/80(1)]

का० आ० 1584.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 9-त्रिचुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एम० एम० बेन्नी, मरेट्टीक्कल हाउस, शंकर आय्यर रोड, पो० पूथोले, त्रिचुर-4 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री एम० एम० बेन्नी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० केरल-लो०स०/9/80 (2)]
आदेश से,
धर्मबीर, अवर सचिव

S.O. 1584.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri M. M. Benny, Marottickkal House, Sankara Iyer Road, P.O. Poothole, Trichur-4 (Kerala), a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 9-Trichur Constituency, has failed to lodge an account of his elelction expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri M.M. Benny to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-HP/9/80(2)]
By Order,
DHARAM VIR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 20 मई, 1980

का० आ० 1585.—आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए फरवरी, 1978 में हुए साधारण निर्वाचन में 3-टेक्कली सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी श्रीमती हुसाना बेगम धर्मपत्नी श्री अब्दुल रहमान खान, निवासी 52ए, पुराने विधान सभा सदस्य क्वार्टर, हैदराबाद और वर्तमान में निवासी, 31-साउथ ऐवन्यू, नई दिल्ली को निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों के द्वारा, यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण इस आयोग के 26 मार्च, 1979 के आदेश सं० आ०प्र०-वि०स०/3/78(23) के द्वारा निरर्हित किया गया था ;

और, उक्त श्रीमती हुसाना बेगम ने उनके ऊपर अधिरोपित निरर्हता को हटाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें उन्होंने विधि द्वारा यथा अपेक्षित निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के कारण बताए हैं और इसके समर्थन में अब एक शपथ पत्र भी दाखिल किया है ।

और, निर्वाचन आयोग ने उक्त अभ्यावेदन पर विचार किया है तथा अर्जीदार श्रीमती हुसाना बेगम की सुनवाई भी की है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग ने अपने तारीख 20 मई, 1980 के आदेश द्वारा उन पर अधिरोपित निरर्हता की कालावधि घटाकर उतनी कर दी है जितनी कि वह पहले ही भोग चुकी है और तदनुसार कालावधि के लिए उनकी निरर्हता तारीख 21 मई, 1980 से हटा दी है ।

[सं० आ० प्र०-वि०स०/3/78(1)]
आदेश से
के० गणेशन, सचिव,

ORDER

New Delhi, the 20th May, 1980

S.O. 1585.—Whereas, Smt. Hussana Begum W/o Shri Abdul Rahman Khan resident of 52A, Old M.L.A. quarters, Hyderabad at present residing at 31, South Avenue, New Delhi, a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in February, 1978 from 3-Tekkali assembly constituency was disqualified by the Election Commission vide its Order No. AP-LA/3/78(23) dated 26th March, 1979, under section 10A of the Representation of the People Act, 1951, for the failure to lodge the account of her

election expenses as required by the said Act and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said Smt. Hussana Begum has submitted a petition before the Election Commission of India for the removal of the disqualification imposed on her, giving reasons for her failure to lodge the account as required by law and has also since submitted and affidavit in support thereof ;

And whereas, the Election Commission has taken into account the said representation and also heard the petitioner Smt. Hussana Begum.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 11 of the said Act, the Election Commission has by an order dated the 20th May, 1980 reduced the period of disqualification imposed on her to the period of disqualification already suffered by her and removed the disqualification for the unexpired period w.e.f. 21st May, 1980.

[No. AP-LA/3/78(1)]

By Order,

K. GANESAN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 1980

का० आ० 1586.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए केरल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 36-तिरुरानगाडी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जय चन्द्रन, मंगलथ हाउस, चिराक्कल, पो० आ० तानूर (केरल) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जय चन्द्रन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० केरल-वि० स०/36/80(1)]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th May, 1980

S.O. 1586.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jaya Chandran, Mangalath House, Chirakkal, P.O. Tanur (Kerala), a contesting candidate for general election to the Kerala Legislative Assembly held in January, 1980 from 36-Tirurangadi Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jaya Chandran to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-LA/36/80(1)]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

सूचनाएं

नई दिल्ली, 26 मई, 1980

का० आ० 1587.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री जार्ज लारेंस फेरिस, एडवोकेट, कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलौर ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए ।

2 उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए ।

[सं० 22/45/79-न्या०]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

NOTICES

New Delhi, the 26th May, 1980

S.O. 1587.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri George Lawrnc Ferris, Advocate, High Court of Karnataka at Bangalore, for appointment as Notary to practice in the whole of Karnataka.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within forufeen days of the publication of this Notice.

[No. F. 22/45/79-Jus.(Judl.)]

का० आ० 1588.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री दुर्गा शंकर दवे, एडवोकेट, मोहल्ला ओसवाल दाडा (राज०) ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे बांस वाडा जिले में व्यवसाय के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए ।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्त पर किसी भी प्रकार का आदेश इस सूचना के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए ।

[सं० 5(14)/80-न्या०]

S.O. 1588.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Durga Shanker Dave, Advocate, Mohalla Oaswalwads, Banswars, Rajasthan for appointment as a Notary to practise in District Banswars

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(14)/80-Judl.]

का० आ० 1589.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री कृष्ण स्वरूप आर्य, एडवोकेट ई० प० 241, पक्का बाग रोड, नया बाजार ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे जलन्धर (पंजाब) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए ।

2 उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप मेरे पास भेजा जाए ।

[सं० 5(28)/80-न्या०]

S.O. 1589.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Krishan Swaroop Arya, Advocate, E.P. 241, Pacca Bagh Road, Naya Bazar, Jullundur City for appointment as a Notary to practise in Jullundur.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(28)/80-Judl.]

का० आ० 1590.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कु० सत्यवन्त वारिच, एडवोकेट, 385 मांडेल टाऊन, जलन्धर शहर, पंजाब ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे जलन्धर शहर में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति किया जाए ।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन की भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए ।

[सं० 5(37)/80-न्या०]

के० सी० डी० गंगवानी, सक्षम प्राधिकारी

S.O. 1590.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Miss Satwant Waraich, Advocate, 385 Madel Town, Jullundur City, Punjab, for appointment as a Notary to practise in Jullunder.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(37)/80-Judl.]

K. C. D. GANGWANI, Competent Authority

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 31 मई, 1980

का० आ० 1591.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के नियमित मामला संख्या 2/80-सी० अ०ई० यू० (ए) से उत्पन्न श्री जरैनल सिंह खालसा पुत्र सरदार जोगिन्दर सिंह भिन्द्रवाला द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर किए गए अग्रिम जमानत के प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए श्री ए० एस० मुल्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है ।

[संख्या 225/36/80-ए० वी० डी० II]

बी० सी० वंजानी, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 31st May, 1980

S.O. 1591.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri A. N. Mulla, Senior Advocate, Delhi, as a Special Public Prosecutor for conducting proceedings, arising out of the Delhi Special Police Establishment Regular Case No. 2/80-CIU(A) in connection with anticipatory bail application filed by Shri Jarnail Singh Khalsa son of Sardar Joginder Singh Bhindranwala, in the Delhi High Court, New Delhi.

[No. 225/36/80-AVD II]

B. C. VANJANI, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 3 मई, 1980

आयकर

का० आ० 1592.—राजस्व विभाग की 26 अप्रैल 1979 की अधिसूचना सं० 2784 (फा० सं० 404/22 (क० व० अ०—पश्चिम बंगाल)/79-आ० क० स० क०) के पैराग्राफ 1 और 2 में क्रम सं० 11 के सामने प्रयुक्त "11-एन० डी० मुखर्जी" अंकों और शब्दों के स्थान पर "11-एन० के० मुखर्जी" अंक और शब्द पढ़े जाएं ।

[सं० 3284 (फा० सं० 404/22 (क० व० अ०—पश्चिमी बंगाल)/79-आ० क० स०क०)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd May, 1980

INCOME-TAX

S.O. 1592.—In paragraph 1 and 2 of Department of Revenue's Notification No. 2784 (F. No. 404/22 (TRO-WB)/79-ITCC dated 26-4-1979 for the figures and words "11-N. D. Mukherjee" appearing against Sl. No. 11 read the figures and words "11-N. K. Mukherjee".

[No. 3284 (F. No. 404/22 (TRO-WB)/79-ITCC)]

का० आ० 1593.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उप-खंड (iii) को अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की 26 अप्रैल की 1979 की अधिसूचना सं० 2784 (फा० सं० 404/22 (क० व० अ०—पं० बं०)/79-आ० क० स० क०) में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् उक्त अधिसूचना में —

"1. श्री राज नारायण घोष
2. श्री ए० एल० बरता
3. श्री विद्युत कुमार भट्टाचार्जी
4. श्री अशोक कुमार राय
5. श्री परिमल चन्द्र विश्वास
6. श्री सरत कुमार घोष
7. श्री तुलसी दास मुखर्जी
8. श्री सी० डी० शुक्ल
9. श्री बी० पी० त्यागी
10. श्री हरे कृष्ण पाल

11. श्री एन० डी० मुखर्जी (जिसमें दिनांक 3 मई, 1980 की अधिसूचना सं० 3284 (फा० सं० 22/ क० वा० अ०-पं० बं०/79-आ० क० म० क०) द्वारा संशोधन करके एन० के० मुखर्जी किया गया)

12. श्री शंकर नारायण गुह
13. श्री रणजीत मण्डल
14. श्री बिभूति भूषण सरकार
15. श्री सुरेश च० राय
16. श्री सतीश च० राय
17. श्री सुब्रत डे
18. श्री वेलुथक्कल केशवन नायर
19. श्री जैनेन्द्र कुमार राय
20. श्री रवीन्द्र नारायण
21. श्री कालीदास चटर्जी
22. श्री प्रबीर सेन गुप्ता

को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये, " शब्दों और अक्षरों के स्थान पर—

"1. श्री राजनारायण घोष
2. श्री ए० एल० दत्ता
3. श्री विद्युत् कुमार भट्टाचार्जी
4. श्री अशोक कुमार राय
5. श्री परिमल चन्द्र विस्वास
6. श्री सरत कुमार घोष
7. श्री तुलसीदास मुखर्जी
8. श्री सी० डी० शुक्ल
9. श्री वी० पी० त्यागी
10. श्री हरे कृष्ण पाल
11. श्री शंकर नारायण गुह
12. श्री रणजीत मण्डल
13. श्री बिभूति भूषण सरकार
14. श्री सुरेश च० राय
15. श्री सतीश च० राय
16. श्री सुब्रता डे
17. श्री वेलुथक्कल केशवन नायर
18. श्री जैनेन्द्र कुमार राय
19. श्री रवीन्द्र नारायण
20. श्री कालिदास चटर्जी
21. श्री प्रबीर सेन गुप्ता

को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए" शब्द और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएगें ।

[सं० 3286/फा० सं० 404/22(क०व०अ०-प०बं०)79-आ०क०स० क०]

S.O. 1593.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 2784 [F. No. 404/22 (TRO-WB)/79-ITCC] dated 26-4-1979 namely ; in the said Notification for the words and letters."

1. "S/Shri Raj Narain Ghosh
2. A. L. Dutta
3 Bidyut Kr. Bhattacharjee
4. Ashoke Kr. Roy
5. Parimal Chander Biswas
6. Sarat Kr. Ghosh
7. Tulsidas Mukherjee
8. C. D. Shukla
9. V. P. Tyagi.
10. Harekrishna Pal
11. N. D. Mukherjee (Modified as N. K. Mukherjee vide Notification No. 3284 (F. No. 22/TRO-WB/79-ITCC) dated 3rd May, 1980
12. Sanker Narayan Guha
13. Ranjit Mondal
14. Bibhuti Bhushan Sarkar
15. Suresh Ch. Roy
16. Satish Ch. Roy
17. Subrata Dey
18. Veluthakkal Kesavan Nair
19. Janendra Kumar Roy
20. Rabindra Narayan
21. Kalidas Chatterjee
22. Prabir Sengupta

being gazetted officers of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act" the words and letters:

1. "S/Shri Raj Narain Ghosh
2. A. L. Dutta
3. Bidyut Kr. Bhattacharjee
4. Ashoke Kr. Roy
5. Parimal Chander Biswas
6. Sarat Kr. Ghosh
7. Tulsidas Mukherjee
8. C. D. Shukla
9. V. P. Tyagi
10. Harekrishna Paul
11. Sankar Narayan Guha
12. Ranajit Mondal
13. Bibhuti Bhushan Sarkar
14. Suresh Ch. Roy
15. Satish Ch. Roy
16. Subrate Dey
17. Veluthakkal Kesavan Nair
18. Janendra Kumar Roy
19. Rabindra Narayan
20. Kalidas Chatterjee
21. Prabir Sengupta

being gazetted Officers of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act" shall be substituted.

[No. 3286/F. No. 404/22 (TRO-WB)/79-ITCC]

नई दिल्ली, 15 मई, 1980

आयकर

का० आ० 1594.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री वी० के० बालकृष्णन् को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के प्राधिकृत करती है ।

2. 20 नवम्बर 1979 की अधिसूचना सं० 3007 (फा० सं० 404/97-क० व० अधि०-तमिलनाडु/79—आ० क० स० क०) के अन्तर्गत की गई श्री एम० वीरस्वामी की नियुक्ति को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है ।

3. यह अधिसूचना श्री वी० के० बालकृष्णन् द्वारा कर वसूली अधिकारी के पद का कार्य भार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी ।

[सं० 3303 (फा० सं० 398/6/80-आ० क० स० क०)]

New Delhi, the 15th May, 1980

INCOME-TAX

S.O. 1594.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri V. K. BALAKRISHNAN being a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. The appointment of Shri M. VEERASAMY made under Notification No. 3007 (F. No. 404/97-TRO-TN/79-ITCC) dated 20-9-79 is hereby cancelled.

3. This Notification shall come into force with effect from the date Shri V. K. Balakrishnan takes over charges as Tax Recovery Officer.

[No. 3303(F. No. 398/6/80-ITCC)]

का० आ० 1595.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री एस० वैद्यनाथन् को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

2. 21 जनवरी, 1977 की अधिसूचना सं० 1628 (फा० सं० 404/7/77-आ० क० स० क०) के अन्तर्गत की गई श्री एस० कण्णन की नियुक्ति को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है ।

3. यह अधिसूचना श्री एस० वैद्यनाथन् द्वारा कर वसूली अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी ।

[सं० 3301 (फा० सं० 398/6/80-आ० क० स० क०)]

S.O. 1595.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri S. VAIDYANATHAN, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. The appointment of Shri S. KANNAN made under Notification No. 1628 (F. No. 404/7/77-ITCC) dated 21-1-77 is hereby cancelled.

3. This Notification shall come into force with effect from the date Shri S. VAIDYANATHAN takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 3301 (F. No. 398/6/80-ITCC)]

नई दिल्ली, 20 मई, 1980

का० आ० 1596.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) का अनुसरण करते हुए और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 14 जून, 1979 की अधिसूचना संख्या 2859 [फा० सं० 404/113 (क० व० अ०-रोहतक)/79-आ० क० स० क०] का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एच० एल० चानना को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

2. यह अधिसूचना श्री एच० एल० चानना के कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी ।

[सं० 3391 (फा० सं० 398/13/80-आ० क० स० क०)]

एच० वेंकटरामन, उप सचिव

New Delhi, the 20th May, 1980

S.O. 1596.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 2859 [F. No. 404/113-(TRO-Rohtak)/79-ITCC] dated 14-6-79 the Central Government hereby authorises Shri H. L. Chanana being a gazetted officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri H. L. Chanana takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 3391 (F. No. 398/13/80-ITCC)]

H. VENKATARAMAN, Dy. Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1979

का०आ० 1597:—भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड ने, 30 जून, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के बारे में, भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति तथा प्रगति पर यह वार्षिक रिपोर्ट, भारत सरकार को प्रस्तुत की है।

अध्याय 1

प्रस्तावना

1978-79 में बैंकिंग क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं पायी गयीं। उक्त विशेषताएं इस प्रकार थी : जमाराशियों और ऋणों में निरंतर वृद्धि होती रही, कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों का योगदान अधिकाधिक रहा और विशेष रूप से क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने के लक्ष्य के साथ तीन वर्षों के लिए शाखा विस्तार की नीति शुरू की गयी। मार्च 1979 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पहले निर्धारित दो राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति करनी थी : पहला लक्ष्य यह था कि बैंकों को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि उनके बकाया ऋण के एक-तिहाई से अन्यून मात्रा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उपलब्ध हो। दूसरा लक्ष्य यह था कि कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों से बैंकों ने जो जमाराशि जुटायी उसका 60 प्रतिशत उन्हीं क्षेत्रों में काम में लाया जाए। इन बातों में भी 1978-79 में उल्लेखनीय प्रगति हुई।

1.2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में 1978-79 (जुलाई-जून) में 4,556 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई; यह वृद्धि 1977-78 में हुई 4,410 करोड़ रुपयों की वृद्धि की तुलना में थोड़ी सी अधिक थी। किन्तु वृद्धि की दरों की दृष्टि से कुल जमाराशियों की वृद्धि दर 1977-78 के 23.3 प्रतिशत के मुकाबले घटकर 19.5 प्रतिशत हो गयी। इसका प्राथमिक कारण यह था कि जहां 1977-78 में राष्ट्रीय आय में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहां 1978-79 में उसमें केवल 4 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

1.3. 1978-79 के दौरान ऋण की प्रवृत्तियों के दो अलग-अलग चरण पाये गये। पहला चरण इस वर्ष के प्रारंभिक भाग में पाया गया जब चलनिधि काफी अधिक जमा हो चुकी थी; उसके बाद दूसरे चरण में ऋण में तीव्र वृद्धि पायी गयी। विशेष रूप से 17 नवंबर 1978 को समाप्त आठ सप्ताहों के दौरान खाद्येतर बैंक ऋण में असाधारण रूप से प्रति सप्ताह लगभग 100 करोड़ रुपयों की उच्च दर पर वृद्धि हुई। वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपातों की दृष्टि से इन आठ सप्ताहों का अनुपात लगभग 100 प्रतिशत था। बैंक ऋण में असाधारण वृद्धि की स्थिति के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने वृद्धिशील (सकल) खाद्येतर ऋण जमा अनुपात को 1 दिसम्बर 1978 से मार्च 1979 के अंत तक की अवधि के लिए 40 प्रतिशत तक सीमित करने की नीति निर्धारित की। वास्तव में जनवरी 1979 के अंतिम सप्ताह तक ऐसे ऋण में काफी अधिक वृद्धि हुई। खाद्येतर (सकल) बैंक ऋण में 1978-79 के पूरे वर्ष में 17.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि पिछले वर्ष हुई लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि के अनिरियत थी। 1978-79 में लगभग 7.6 प्रतिशत का औद्योगिक विकास हुआ जबकि 1977-78 में उक्त प्रतिशत 3.9 था और साथ ही चीनी जैसे उद्योग क्षेत्रों में भारी मात्रा में स्टाक जमा रखने की आवश्यकता थी। यदि इन सब के लिए अपेक्षित ऋण की मात्रा को स्वीकार कर भी लिया जाए तो भी 1978-79 में खाद्येतर (सकल) बैंक ऋण का विस्तार अपेक्षा से अधिक था। इस अवधि में ऋण नीति संबंधी जो कार्रवाइयां की गयी उनपर इस पृष्ठभूमि में विचार करना होगा।

1.4 पिछले वर्ष के अनुभव से ऋण के आकड़ों/सूचनाओं अथवा आम तौर पर बैंकिंग संबंधी निर्देशकों का अनुशीलन करने के वर्तमान तंत्र में पायी गयी कमियों में तीव्र सुधार आया। व्यापक स्तर पर बकायी जाने वाली ऋण आयोजना के लिए अलग-अलग बैंक के स्तर पर सूचना तंत्र की व्यवस्था द्वारा काफी सहायता मिलनी चाहिए। इससे उक्त बैंक अपनी शाखाओं की कार्य प्रणाली का तत्काल सफलतापूर्वक अध्ययन कर सकता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अलग-अलग बैंक के स्तर पर अनुशीलन तंत्र में सुधार लाने की कार्रवाई की जा चुकी है।

1.5 भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि, लघु उद्योग और छोटे ऋणकर्ता जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जानेवाले अग्रिमों की राशि मार्च 1979 तक उनके बकाया ऋण के एक तिहाई अंश से कम नहीं होनी चाहिए। मार्च 1979 के अंत में 50 बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों का अंश, जो कुल बैंक ऋण का लगभग 95 प्रतिशत था, कुल बैंक ऋण (शुद्ध) में 30.5 प्रतिशत था जबकि एक वर्ष पहले उक्त अंश 28.2 प्रतिशत था। बढ़ते हुए कुल ऋण (शुद्ध) में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्राप्त ऋण का अंश 1978-79 (अप्रैल-मार्च) में 13.0 प्रतिशत था जो 1977-78 के 46.9 प्रतिशत के तदनुरूप अंश के मुकाबले कम था।

1.6 किन्तु ग्रामीण क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के संबंध में निर्धारित लक्ष्य के मामले में बैंकिंग तंत्र को अभी और बहुत कुछ करना है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह आशा की गयी थी कि वे अपनी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं के संदर्भ में कम से कम 60 प्रतिशत के ऋण-जमा अनुपात के अलग-अलग लक्ष्य की पूर्ति मार्च 1979 तक कर देंगे। समग्र देश की दृष्टि से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के मामले में उक्त अनुपात जून 1978 के अंत में क्रमशः 52.5 और 47.4 प्रतिशत थे। प्रस्थिल भारतीय अनुपात कम जरूर है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी क्षेत्रों/जिलों में उक्त अनुपात निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम रहा है। वस्तुतः दक्षिणी प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 76.3 प्रतिशत था जो लक्ष्य से काफी अधिक था और उसके अर्ध शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच गया है। अर्ध शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 59.7 प्रतिशत था। इसी प्रकार ग्रामीण बैंक शाखाएं तथा अर्ध शहरी बैंक शाखाएं जिन जिलों में कार्यरत हैं उनके क्रमशः 38 प्रतिशत और 33 प्रतिशत जिलों में ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत और अधिक थे। इससे यह विदित होता है कि ऋण-जमा अनुपात की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों और यहां तक कि जिलों में भी असमान प्रगति हुई है।

1.7 ऋण प्रदान करने के क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों का जो दृष्टिकोण इन राष्ट्रीय लक्ष्यों के माध्यम से प्रकट होता है उससे कुछ वर्षों में ऋण विन्यास में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। उदाहरण के लिए कुल बैंक ऋण में बड़े और मझौले उद्योगों का अंश पिछले कुछ वर्षों में कम हुआ है; किन्तु कृषि जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का अंश काफी बढ़ गया है। भारत सरकार द्वारा अक्तूबर 1978 में गठित पांच कार्यकारी दलों की सिफारिशों के आधार पर हाल ही में बैंकों को जारी किये गये कुछ मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के परिणामस्वरूप शायद उक्त परिवर्तन की गति में तीव्रता आ सकती है। इसके अलावा खण्ड विकास योजनाओं और अभी हाल ही में जिला उद्योग केन्द्रों में भी बैंकों का योगदान बढ़ता रहा है। इन नये और जटिल कार्यों को पूरा करने में बैंकिंग तंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे कितनी जल्दी इन नये कार्यों के अनुरूप ऋण प्रदान करने से संबंधित अपने दृष्टिकोणों, क्रियाविधियों और क्षमता को नयी दिशा प्रदान कर सकते हैं।

1.8 क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने और ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में बहु एजेंसी दृष्टिकोण को मजबूत बनाने के स्थान सिद्धांत को लेकर सितंबर 1978 में 1979—81 के तीन वर्षों के लिए एक व्यापक शाखा विस्तार नीति घोषित की गयी। बहु एजेंसी दृष्टिकोण का मूलभूत उद्देश्य यह है कि ग्रामीण ऋण के क्षेत्रों में योगदान प्रदान करने वाली सभी एजेंसियां अर्थात वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों और सहकारी बैंकों का कार्य अपेक्षाकृत अधिक कारगर हो, विषमता पूर्ण नीतियों को हटाया जाए और ग्रामीण क्षेत्र को अधिकाधिक संस्थागत ऋण उपलब्ध हो। शाखा लाइसेंसीकरण नीति बैंकिंग तंत्र का सुव्यवस्थित स्वरूप तैयार करने और बैंकिंग विकास

में विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने के मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बनायी गयी है। 1979—81 के तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लगभग 6,500 शाखाएं खोलने का कार्यक्रम बनाया गया है। इस कार्य के लिए जिलावार योजनाएं तैयार की जा रही हैं। परिस्थिति की अपेक्षानुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

अध्याय 2

वाणिज्य बैंक व्यवसाय

शाखा विस्तार : नीति और प्रगति

2.1 चौदह प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद पहले दशक में देश भर में 21,900 नये बैंक कार्यालय खोले गये; इससे कार्यरत कार्यालयों की कुल संख्या जून 1969 के 8,262 से बढ़कर जून 1979 के अंत में 30,202 हो गयी। नये कार्यालयों में से आधे से अधिक (11,476) कार्यालय ऐसे केन्द्रों में खोले गये जहां पहले वाणिज्य बैंक कार्यालय नहीं थे। प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या जून 1969 के 65,000 से घटकर जून 1979 में लगभग 18,000 हो गयी। कुछ क्षेत्रों में बैंकिंग से संबंधित मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता में कमियां होने के बावजूद यह उल्लेखनीय प्रगति हुई। जून 1979 के अंत में प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या 13 राज्यों संघशासित क्षेत्रों में औसत से भी अधिक थी (सारणी 2.1)।

सारणी 2.1—जून 1977, जून 1978, दिसम्बर 1978 और जून 1979 के अंत में बैंक कार्यालयों का राज्यवार वितरण

राज्य/संघशासित क्षेत्र	निम्नलिखित वर्षों के अंत में कार्यालयों की संख्या				1977-78 के दौरान खोले गये केन्द्र (जुलाई 1977 से जून 1978 तक)	उनमें से बैंक रहित	1978-79 के दौरान खोले गये केन्द्र (जुलाई 1978 से जून 1979 तक)	उनमें से बैंक रहित	प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या (हजारों में) निम्नलिखित वर्षों के अंत में		
	जून 1977	जून 1978	दिसम्बर 1978	जून 1979					जून 1978	दिसम्बर 1978	जून 1979
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	1,844	2,134	2,314	2,366	289	218	232	162	20	19	18
असम	354	414	437	446	60	44	32	24	35	33	33
बिहार	1,176	1,397	1,498	1,594	222	162	198	151	30	38	35
गुजरात	1,883	2,077	2,143	2,162	194	143	85	43	13	12	12
हरियाणा	604	674	695	720	71	50	46	32	15	14	14
हिमाचल प्रदेश	253	292	311	313	39	32	21	14	12	11	11
जम्मू और काश्मीर	285	337	356	371	52	41	34	30	14	13	12
कर्नाटक	2,138	2,339	2,480	2,531	204	135	193	132	13	12	12
केरल	1,705	2,011	2,059	2,098	306	238	87	59	11	10	10
मध्य प्रदेश	1,247	1,465	1,578	1,626	218	175	162	122	28	26	26
महाराष्ट्र	2,671	2,913	3,062	3,113	243	123	200	98	17	16	16
मणिपुर	23	32	33	35	9	9	3	1	34	33	31
मेघालय	41	49	53	53	8	6	4	4	21	19	19
नागालैंड	22	29	32	33	7	5	4	3	18	16	16
उड़ीसा	529	660	698	718	131	104	59	46	33	31	31
पंजाब	1,271	1,425	1,461	1,469	154	118	44	22	10	9	9
राजस्थान	1,022	1,150	1,277	1,317	128	94	167	136	22	20	20
तमिलनाडु	2,307	2,552	2,635	2,675	246	181	123	87	16	16	15
त्रिपुरा	49	67	69	69	17	11	2	2	23	23	23
उत्तर प्रदेश	2,714	3,055	3,246	3,369	342	221	313	239	29	27	26
पश्चिम बंगाल	1,626	1,804	1,866	1,910	179	97	106	52	25	24	23
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	7	12	12	12	5	4	—	—	10	10	10
अरुणाचल प्रदेश	11	13	17	17	2	2	4	3	36	28	28
चंडीगढ़	71	74	75	76	3	1	2	1	3	3	3
दादरा और नागर हवेली	4	4	4	4	—	—	—	—	19	19	19
दिल्ली	709	768	810	820	60	7	54	2	5	5	5
गोवा, दमण और दीव	190	216	223	225	26	21	9	7	4	4	4
लक्षद्वीप	5	5	5	5	—	—	—	—	6	6	6
मिजोरम	4	6	12	12	2	—	6	6	55	28	28
पांडिचेरी	37	42	43	13	5	3	1	—	11	11	11
जोड़	24,802	28,016	29,504	30,202	3,222	2,245	2,191	1,478	20	19	18

टिप्पणी : (1) जुलाई 1977 से जून 1978 तक की अवधि के दौरान 8 कार्यालय बंद किये गये।
(2) जुलाई 1978 से जून 1979 तक की अवधि के दौरान 5 कार्यालय बंद किये गये।
(3) सिक्किम से संबंधित आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।
(स्रोत : बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक)

2.2 सितम्बर 1978 में 1979-81 के तीन वर्षों की अवधि के लिए एक नयी शाखा लाइसेंसीकरण नीति बनायी गयी; यह इस वर्ष की महत्वपूर्ण गतिविधि थी । इस नीति का समग्र उद्देश्य यहां पहले की तरह कम बैंक सुविधायुक्त क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना तथा इस संबंध में राज्यों और जिलों के बीच विद्यमान असमानताओं को कम करना है, वहां दूसरे निम्नलिखित तत्वों को भी ध्यान में रखा गया है: ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया था; विकासपरक कार्यकलापों के लिए आवश्यक समर्थन दिया गया था तथा दांतवाला समिति, जेम्स राज समिति और कामथ कार्यकारी दल ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं । यह नीति बहु एजेंसी दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें वित्तीय संस्थाओं अर्थात् वाणिज्य बैंकों, सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच समन्वयन पर बल दिया गया है ताकि निरर्थक प्रतियोगिता न हो और अलग अलग संस्थायें एक ही प्रकार के प्रयास न करें । इस नीति की रूपरेखा नीचे दी गयी है:

(1) ऐसे क्षेत्रों—राज्यों और जिलों—का पता लगाया गया है जहां प्रति कार्यालय जनसंख्या जून 1978 के अंत में 20,000 के राष्ट्रीय औसत से अधिक होने के कारण वाणिज्य बैंकिंग सेवाओं की कमी विदित हुई है । इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने के लिए ग्रामीण तथा अर्ध शहरी केन्द्रों में 1979-81 की अवधि में लगभग 6,500 नये कार्यालय खोलना आवश्यक समझा गया है । समस्त बैंकों को राज्य/जिलावार उन कार्यालयों की सूचियां भेजी गयी हैं जहां बैंक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता है । इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों तथा संबंधित बैंकों के साथ परामर्श कर शाखा विस्तार की जिलावार योजनाएं बना रहा है । विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में केन्द्रों के आबंटन का कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा 30 जून, 1979 तक विभिन्न बैंकों को तीन वर्षों की अवधि में कार्यालय स्थापित करने के लिए लगभग 2,000 ग्रामीण/अर्ध शहरी केन्द्रों का आबंटन किया गया है । इस अवधि में शाखाएं खोलने के लिए किये गये केन्द्रों के कुल आबंटन में वस्तुतः 76 प्रतिशत अंश बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पिछड़े राज्यों का था ।

(2) इस नीति में देश के समस्त सामुदायिक विकास खण्डों के मुख्यालयों को सरकार की विकासात्मक प्रशासन संबंधी योजना में प्राप्त विशेष स्थान को देखते हुए बैंक शाखाएं खोलने के मामले में उन्हें उच्च प्राथमिकता दी गयी है । ऐसे खंडों के मुख्यालयों में जून 1979 के अंत तक बैंक कार्यालय की सुविधाएं उपलब्ध हों—इस उद्देश्य से एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ।

(3) कतिपय जिलों में प्रति बैंक कार्यालय विद्यमान औसत जनसंख्या अक्सर जिले के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंक व्यवसाय का विस्तार करने के लिए पर्याप्त मानदंड सिद्ध नहीं हो सकतीं; क्योंकि शहरी केन्द्रों में बैंक कार्यालयों के संकेन्द्रीकरण से पक्षपातपूर्ण स्थिति पायी जाती है । ऐसे मामलों में असंतुलन को कम करने के निमित्त ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए अतिरिक्त लाइसेन्स प्रदान किये जायेंगे ।

(4) यह स्वीकार कर लिया गया है कि शहरी और महानगरीय केन्द्रों और पत्तन शहरों में शाखा विस्तार के कार्य को पूर्णतः रोकना वांछनीय नहीं होगा । ये केन्द्र ऐसे कारोबार की संभावनाएं प्रस्तुत करेंगे जो विशेष रूप से पिछड़े इलाकों में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर शाखा विस्तार करने से बैंकों की कार्यक्षमता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में सहायता कर सकता है । अतः नयी नीति में अत्यधिक रूप से चुने हुए आधार पर शहरी/महानगरीय क्षेत्रों में कुछ और विस्तार करने का कार्य सम्मिलित किया गया है । इस प्रयोजन के लिए शहरी सहकारी बैंकों के कार्यरत कार्यालयों को भी हिसाब में लिया जाएगा ।

(5) ग्रामीण क्षेत्र के वित्तपोषण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है । नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना तथा कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के विस्तार को प्रोत्साहन दिया जायेगा । जिन क्षेत्रों में नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जा सकती है उनका पता लगाने के उद्देश्य से जिलावार अध्ययन किया जा रहा है तथा ऐसे अध्ययन में उन जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है जहां वाणिज्य और सहकारी बैंकिंग तंत्र विद्यमान हैं । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अब तक केवल वाणिज्य बैंक प्रायोजित करते रहे हैं । शिखर सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच निकटतर संपर्क स्थापित हो—इस उद्देश्य से जहां कहीं संभव हो वहां शिखर बैंकों तथा वाणिज्य बैंकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संयुक्त प्रायोजन को प्रोत्साहन दिया जायगा । उपयुक्त मामलों में केवल शिखर सहकारी बैंकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रायोजन किये जाने पर भी विचार किया जाएगा । संप्रति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वर्तमान विधान के अन्तर्गत गठित किये जाते रहेंगे । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिचालन क्षेत्र का जहां तक संबंध है, कोई कठोर मानदंड निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव नहीं है और इस संदर्भ में लचीला दृष्टिकोण अपनाया जायेगा । ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार के मामले में उन जिलों को, जहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये हैं अथवा स्थापित किये जायेंगे, प्राथमिकता दी जाएगी । जिन मामलों में कृषि के वित्तपोषण की विशेष योजनाएं विद्यमान हैं और जहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तत्काल विस्तार करने की स्थिति में नहीं हैं, जिले के संबंधित अग्रणी बैंक को सामान्यतः शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाएगी । परन्तु इससे वाणिज्य बैंकों पर जहां कहीं आवश्यक समझा जाए वहां नई शाखाएं (कृषि विकास शाखाओं सहित) खोलने अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकार क्षेत्रों में उनकी वर्तमान शाखाओं को जारी रखने के मामले में कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा । जिन क्षेत्रों में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं हैं अथवा उनकी स्थापना करने का प्रस्ताव नहीं है, उन क्षेत्रों में अग्रणी बैंकों को अपने अग्रणी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यालय खोलने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी ।

(6) फिलहाल कतिपय अग्रणी बैंकों ने अपने अग्रणी जिलों में कारगर ढंग से अपने अग्रणी दायित्व को निभाने के लिए पर्याप्त मात्रा में शाखा विस्तार नहीं किया है । भविष्य में केन्द्रों का आबंटन करते समय संबंधित अग्रणी बैंकों से यह कहा जाएगा कि वे पूर्व निर्धारित समग्र उद्देश्य के भीतर अपने अग्रणी जिलों में अधिकाधिक कार्यालय खोलें । बैंकों के क्षेत्रीय स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में अग्रणी दायित्व में अदला-बदली करने की भी अनुमति है ।

---

1 यहां निम्नलिखित के प्रति संकेत हैं :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्य प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए गठित समिति (जेम्स राज समिति), 1977

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित समिति (दांतवाला समिति), 1977

(ग) कृषि के वित्तपोषण में बहु एजेंसी दृष्टिकोण अपनाने से उभरनेवाली समस्याओं का अध्ययन करने के लिए गठित कार्यकारी दल (कामथ कार्यकारी दल), 1976

सारणी 2.2—वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान खोले गये कार्यालयों का बैंक समूहवार ब्यौरा

	वाणिज्य बैंकों द्वारा खोले गये नये कार्यालय						निम्नलिखित तारीखों को बैंक कार्यालय			निम्नलिखित तारीखों को बैंकों की संख्या		
	1977-78			1978-79								
	जुलाई-दिसंबर 1977	जनवरी-जून 1978	जुलाई-जून 1977-78	जुलाई-दिसंबर 1978	जनवरी-जून 1979	जुलाई-जून 1978-79	30 जून 1978	31 दिसम्बर 1978	30 जून 1979	30 जून 1978	31 दिसंबर 1979	30 जन 1979
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. भारतीय स्टेट बैंक	309 (200)	145 (93)	454 (293)	168 (84)	73 (43)	241 (127)	4,813	4,979	5052	1	1	1
2. भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक	142 (92)	51 (22)	193 (114)	105 (69)	38 (22)	143 (91)	2,192	2,297	2335	7	7	7
3 14 राष्ट्रीयकृत बैंक	820 (553)	385 (254)	1,205 (807)	566 (316)	224 (151)	790 (467)	13,745	14,309	14533	14	14	14
4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	394 (346)	233 (214)	627 (560)	318 (298)	343 (226)	561 (524)	1,405	1,723	1965	48	51	56
5. अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक	519 (350)	203 (104)	122 (454)	334 (195)	116 (68)	450 (263)	5,659	6,010	6126	38	39	39
6. विदेशी बैंक	1 (—)	—	1 (—)	—	—	—	129	129	129	14	14	14
7. समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2,185 (1,541)	1,017 (687)	3,202 (2,228)	1,491 (962)	694 (510)	2185 (1472)	27,943	29,447	30140	122	126	131
8. गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक	13 (12)	7 (5)	20 (17)	1 (1)	5 (5)	6 (6)	73	57+	62	6	5	5
9. समस्त वाणिज्य बैंक	2,198 (1,553)	1,024 (692)	3,222 (2,245)	1,492 (963)	699 (518)	2191 (1478)	28,016	29,504	30202	128	131	136

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े उन बैंक रहित केन्द्रों की संख्या है, जहां कार्यालय खोले गये ।

(स्रोत : बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक)

(7) जिन बैंकों का स्वरूप क्षेत्रीय है, उनसे सामान्यतः सुदूर इलाकों में शाखाएं खोलने के लिए नहीं कहा जाएगा ; परन्तु उन्हें अपने ही परिचालन क्षेत्र में प्रयासों को केन्द्रित करने अथवा निकटवर्ती कमी के क्षेत्रों में चुने हुए आधार पर विस्तार करने के लिए कहा जाएगा ।

2.3 वर्ष 1978-79 (जुलाई-जून) के दौरान शाखा विस्तार की नीति का प्रमुख उद्देश्य पहले की तरह यही बना रहा कि जिन क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं उन क्षेत्रों में बैंक कार्यालय खोले जाएं । चूंकि जनवरी 1978 में रिजर्व बैंक ने यह निर्णय किया कि शाखा विस्तार की गति को कम कर वर्तमान विन्यास का समेकन करने एवं उसे मजबूत बनाने पर जोर दिया जाए अतः आलोच्य वर्ष के दौरान खोले गये कार्यालयों की संख्या 2,191 थी जो पिछले वर्ष (3,222) की अपेक्षा कम थी । फिर भी बैंक रहित केन्द्रों में बैंक कार्यालय खोलने के कार्य में तीव्रता लायी गयी और 1,478 कार्यालय (अथवा कुल नये कार्यालयों का 67 प्रतिशत) ऐसे क्षेत्रों में खोले गये । इन नये बैंक रहित केन्द्रों में से अधिकांश केन्द्र (44.2 प्रतिशत) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पिछड़े राज्यों और संघशासित क्षेत्रों—बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में थे ।

सारणी 2.3—वाणिज्य बैंक कार्यालयों का जनसंख्या समूहवार वितरण

(महीने के अंत में बैंक कार्यालयों की संख्या)

	जून 1975	जोड़ में प्रतिशत	दिसम्बर 1975	जोड़ में प्रतिशत	जून 1976	जोड़ में प्रतिशत	दिसम्बर 1976	जोड़ में प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6	7	8
ग्रामीण	6,806	36.3	7,385	36.1	7,687	36.2	8,839	37.4
अर्ध शहरी	5,569	29.7	6,164	30.1	6,387	30.1	7,024	29.7
शहरी	3,267	17.5	3,589	17.6	3,739	17.6	4,135	17.5
महानगरीय/पत्तन शहरी	3,088	16.5	3,308	16.2	3,407	16.1	3,657	15.4
जोड़	18,730	100.0	20,446	100.0	21,220	100.0	23,655	100.0

	जून 1977	जोड़ में प्रतिशत	दिसम्बर 1977	जोड़ में प्रतिशत	जून 1978	जोड़ में प्रतिशत	दिसम्बर 1978	जोड़ में प्रतिशत	जून 1979	जोड़ में प्रतिशत
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ग्रामीण	9,532	38.4	11,092	41.0	11,802	42.1	12,806	43.4	3,333	44.1
अर्ध शहरी	7,211	29.1	7,493	27.8	7,586	27.1	7,778	26.4	7,845	26.0
शहरी	4,263	17.2	4,445	16.5	4,542	16 2	4,668	16.8	4,777	15.6
महानगरीय/पत्तन शहरी	3,796	15.3	3,966	14.7	4,083	14.6	4,252	14.4	4,307	14.3
जोड़	24,802	100.0	26,996	100.0	28,016	100.0	29,504	100.0	30,202	100.0

टिप्पणी : ग्रामीण केन्द्र : 10,000 से अधिक जनसंख्यायुक्त स्थान । अर्ध शहरी केन्द्र : 10,000 से अधिक परन्तु 1,00,000 तक की जनसंख्यायुक्त स्थान । शहरी केन्द्र : 1,00,000 से अधिक परन्तु 10,00,000 तक की जनसंख्यायुक्त स्थान । महानगरीय केन्द्र : 10,00,000 से अधिक जनसंख्यायुक्त स्थान ।

(स्रोत : बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक)

विदेशों में भारतीय वाणिज्य बैंकों के कार्यालय

2.4 आलोच्य वर्ष के दौरान चार भारतीय बैंकों ने विदेशों में निम्न प्रकार 10 कार्यालय खोले : चार कार्यालय ब्रिटेन में, दो कार्यालय अमेरिका में और एक-एक कार्यालय हांगकांग, केमन द्वीप, चैनल द्वीप और बहामास में । विदेशों में भारतीय बैंकों के कार्यालयों की कुल संख्या जून 1979 के अंत में 123 थी । विदेशों में 11 भारतीय बैंकों के कार्यालय कार्यरत थे और इनमें से बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया के क्रमशः 54 और 23 कार्यालय थे । यदि देश-वार देखा जाए तो सर्वाधिक भारतीय बैंक कार्यालयों की संख्या ब्रिटेन में (41) थी ; तदनंतर हांगकांग (14), फिजी द्वीपसमूह (10), केन्या (9), सिंगापुर (7) और मारिशस (6) का स्थान था ।

2.5 विदेश स्थित भारतीय बैंक कार्यालयों की कुल जमाराशियां दिसम्बर 1977 के अंत में 1,226 करोड़ रुपये थीं और वे जून 1978 के अंत में बढ़कर 1,396 करोड़ रुपये हो गयी । इन कार्यालयों द्वारा प्रदत्त ऋणों की राशि जहां दिसम्बर 1977 के अंत में 850 करोड़ रुपये थी वहां जून 1978 के अंत में बढ़कर 977 करोड़ रुपये हो गयी ।

जमा वृद्धि

2.6 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के जमा साधनों में वर्ष 1978-79 (जुलाई-जून) के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई । अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमा राशियों में वर्ष 1978-79 के दौरान 4,556 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी और समग्र रूप से उनकी राशि पिछले वर्ष (24 जून 1977 से 30 जून 1978 तक) हुई वृद्धि (4,410 करोड़ रुपये) के मुकाबले सीमान्त वृद्धि की द्योतक थी (सारणी 2.4) । फिर भी, आलोच्य वर्ष के दौरान जमाराशियों में पायी गयी 19.5 प्रतिशत की वृद्धि दर पिछले वर्ष की दर (23.3 प्रतिशत) के मुकाबले कम ही थी । यदि वर्गवार देखा जाए तो मांग और मीयादी जमा राशियों में 1978-79 के दौरान क्रमशः 1,162 करोड़ रुपयों (12.6 प्रतिशत) और 3394 करोड़ रुपयों (24.1 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई जबकि 1977-78 के दौरान उनमें क्रमशः 1,929 करोड़ रुपयों (26.5 प्रतिशत) और 2,481 करोड़ रुपयों (21.4 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई थी ।

2.7 वृद्धिशील जमाराशियों में मीयादी जमाराशियों का अंश 74.5 प्रतिशत था जब कि पिछले वर्ष उक्त अंश 56.3 प्रतिशत था । मीयादी जमाराशियों में हुई अपेक्षाकृत भारी वृद्धि अंशतः सांख्यिकीय थी क्योंकि बचत जमाराशियों के मांग/मीयादी अंश का निर्धारण करने से संबंधित क्रियाविधि में परिवर्तन किया गया ।[1]

सारणी 2.4—अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़े

(करोड़ रुपये)

	निम्नलिखित तारीखों को बकाया			निम्नलिखित वर्षों के दौरान घट-बढ़*	
	24 जून 1977	30 जून 1978	29 जून 1979*	1977-78 (2-1)	1978-79* (3-2)
	1	2	3	4	5
1. कुल जमाराशियां	18,903	23,313	27,869	+ 4410	+ 4556
(क) मांग जमाराशियां	7,290	9,219	10,381	+ 1929	+ 1162
(ख) मीयादी जमाराशियां	11,613	14,094	17,488	+ 2481	+ 3394
2. कुल बैंक ऋण	13,491	15,694	18,538	+ 2203	+ 2844
(क) उनमें से खाद्यान्नों की वसूली के लिए	2,536	2,525	2,996	— 11	+ 471
(ख) खाद्य ऋण को छोड़कर बैंक ऋण	10,955	13,169	15,542	+ 2214	+ 2373
3. रिजर्व बैंक में पुनः भुनाये गये बिल	116	101	77	— 15	— 24
4. सकल बैंक ऋण (2+3)	13,607	15,795	18,615	+ 2188	+ 2820
5. सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	6,180	7,552	9,418	+ 1372	+ 1866
(क) सरकारी प्रतिभूतियां	4,352	5,497	6,908	+ 1145	+ 1411
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1,828	2,055	2,510	+ 227	+ 455
6. रिजर्व बैंक में नकदी और जमा रकम	1,563	2,755	3,457	+ 1192	+ 702
7. रिजर्व बैंक से लिये गये उधार	563	335	659	— 228	+ 324
8. ऋण-जमा अनुपात	71	67	67		
9. सकल ऋण-जमा अनुपात	72	68	67		
10. ऋण (खाद्य ऋणों को छोड़कर)—जमा अनुपात	58	56	56		
11. सकल ऋण (खाद्य ऋणों को छोड़कर)—जमा अनुपात	59	57	56		
12. निवेश—जमा अनुपात	33	32	34		

[1]क्रियाविधि में हुए परिवर्तन का संकेत 'बैंकिंग विधान और विनियम' खंड में किया गया है ।

*अनंतिम

(स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अधीन प्राप्त विवरणियां)

2.8 दोनों प्रकार की अनिवासी जमाराशियों में उल्लेखनीय वृद्धि पायी गयी (सारणी 2.5) । विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर लागू न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम पांच वर्षों की अवधि की शर्त को 5 जून 1979 से हटा दिया गया है और इस प्रकार ऐसी जमाराशियों को बैंकों द्वारा स्वीकार की जानेवाली अन्य समस्त जमाराशियों की तरह बना दिया गया ।

सारणी 2.5—अनिवासी (विदेशी) रुपया खातों और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों के अधीन विद्यमान खातों की संख्या और बकाया जमा रकम

अनिवासी (विदेशी) रुपया खाते

निम्नलिखित वर्षों के अंत में	खातों की संख्या (1)	राशि (करोड़ रुपयों में) (2)
मार्च 1978	248621	325
मार्च 1979	366574	484

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते

निम्नलिखित वर्षों के अंत में	विदेशी मुद्रा (1)	खातों की संख्या (2)	जमाराशि (हजारों में) (3)
दिसंबर 1978	पौंड स्टार्लिंग	7445	12936
दिसंबर 1977*	पौंड स्टर्लिंग	4496	7296
दिसंबर 1978	अमरिकी डालर	29690	142406
दिसंबर 1977*	अमेरिकी डालर	23048	120705

*संशोधित आंकड़े

(स्रोत : सांख्यिकीय विभाग, और विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग भारतीय रिजर्व बैंक)

ऋण की प्रवृत्तियां

2.9 जमाराशियों के साथ-साथ ऋणों में भी आलोच्य वर्ष के दौरान उच्च वृद्धि दर पायी गयी । परन्तु वृद्धि की गति समान नहीं थी और आलोच्य वर्ष के दौरान ऋण के विस्तार में दो स्पष्ट चरण पाये गये—प्रारंभिक महीनों में कमी पायी गयी और तदनंतर बैंक कर्मचारियों द्वारा चलाये गये आंदोलन के कारण आयी बाधाओं के परिणामस्वरूप ऋणों में काफी अधिक वृद्धि हुई । वर्ष के अंत में प्रतिबन्धक नीति संबंधी उपायों के प्रभाव के कारण वृद्धि की गति में गिरावट आयी ।

2.10 जून के अंत से अक्तूबर 1978 के अंत तक के चार महीनों की अवधि में, जो कि संयोगवश परंपरागत कम कामकाज के समय का परवर्ती भाग भी था, सकल बैंक ऋण में हुई वृद्धि की मात्रा केवल 428 करोड़ रुपये थी । इसमें से लगभग 417 करोड़ रुपयों की वृद्धि अक्तूबर 1978 के महीने के दौरान हुई । इस चरण के दौरान बैंकों ने रिजर्व बैंक से लिये गये अपने ऋण चुका दिये; रिजर्व बैंक में पुनः भुनाये गये बकाया बिलों में भी गिरावट आयी । इस प्रकार चार महीनों की इस अवधि के दौरान हुए ऋण विस्तार की वित्तीय व्यवस्था मुख्य रूप से बैंकों के अपने ही साधनों में से की गयी, इसके बावजूद बैंकिंग तंत्र के पास काफ़ी अधिक चलनिधि विद्यमान थी, जैसा कि अक्तूबर 1978 के अंत में विद्यमान 35 प्रतिशत से अधिक के चलनिधि अनुपात से विदित होता है ।

2.11 अक्तूबर 1978 के अंत और जून 1979 के अंत के बीच हुए सकल बैंक ऋण के विस्तार की मात्रा लगभग 2,392 करोड़ रुपये थी । बैंक कर्मचारियों द्वारा दिसम्बर 1978 के मध्य से जनवरी 1979 के तीसरे सप्ताह तक की लम्बी अवधि के लिए आन्दोलन चलाये जाने के कारण देशभर में समाशोधन संबंधी कार्यकलाप अस्तव्यस्त हो गये और इसका आंशिक परिणाम यह हुआ कि ऋण राशि में असाधारण बढ़ोतरी पायी गयी । इस संकट के समय में बैंकों की सहायता करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने ऋण उपलब्ध कराने की अपनी शर्तों को उदार बनाया ।

2.12 रिजर्व बैंक से बैंकों द्वारा लिये गये उधारों की राशि नवंबर 1978 (अंतिम शुक्रवार) में 247 करोड़ रुपये थी और वह दिसंबर 1978 में बढ़कर 357 करोड़ रुपये और जनवरी 1979 में और बढ़कर 548 करोड़ रुपये हो गयी । रिजर्व बैंक द्वारा पुनः भुनाये गये बकाया बिलों की राशि नवंबर 1978 के 55 करोड़ रुपयों से बढ़कर जनवरी 1979 में 89 करोड़ रुपये हो गयी । पुनर्वित्त संबंधी उच्चतर सीमाओं की उपलब्धता तथा इन सीमाओं के अपेक्षाकृत अधिक उपयोग के कारण इस अवधि के दौरान पुनर्वित्त सहायता में यह तीव्र वृद्धि हुई । उदाहरण के लिए खाद्य ऋणों के स्तर में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप बैंकों की खाद्य ऋणों से संबंधित पुनर्वित्त की पात्रता की राशि नवंबर 1978 में स्थित 146 करोड़ रुपयों से बढ़कर जनवरी 1979 में 225 करोड़ रुपये हो गयी और प्रयुक्त राशि का अनुपात 11 प्रतिशत से बढ़कर 69 प्रतिशत हो गया । "समाशोधन संबंधी असंतुलनों" को संभालने के लिए अस्थायी पुनर्वित्त की सीमा (जिनकी आहरण की तारीख से तीन दिन के भीतर चुकौती करनी पड़ती है) तथा विवेकाधीन पुनर्वित्त की सीमा दोनों में थोड़े समय के लिए बढ़ोतरी करनी पड़ी ताकि समाशोधन संबंधी व्यवस्थाओं के अस्तव्यस्त हो जाने के कारण बैंकों द्वारा अनुभव की जानेवाली कठिनाइयां दूर हो सकें तथा वे निधियों की वास्तविक मौसमी मांग की पूर्ति कर सकें । इस प्रकार, विवेकाधीन पुनर्वित्त की सीमा को नवंबर 1978 के 69 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर जनवरी 1979 में 130 करोड़ रुपये कर दिया गया ।

2.13 बैंकिंग उद्योग में धीरे-धीरे सामान्य स्थिति आने के कारण फ़रवरी 1979 में ऋणों में गिरावट आयी । परंतु तदनंतर ऋणों में पुनः बढ़ोतरी आयी । विवेकाधीन पुनर्वित्त की सीमाओं को जहां मार्च 1979 के दौरान कम कर 56 करोड़ रुपये और जून 1979[1] के दौरान और कम कर 33 करोड़ रुपये कर दिया गया वहां बैंक विशेष रूप से खाद्य और निर्यात के पुनर्वित्त के संबंध में स्वयमेव उपलब्ध पात्रता के संदर्भ में बराबर भारी मात्रा में उधार लेते रहे । 'छोटे कृषकों के लिए सुविधा' के अंतर्गत प्राप्त किये गये पुनर्वित्त की राशि जुलाई से नवंबर 1978 तक की अवधि के दौरान 3 करोड़ रुपयों से बढ़कर 5 करोड़ रुपये हो गयी ; परंतु उक्त राशि मार्च 1979 में बढ़कर 22 करोड़ रुपये और जून 1979 के अंत में और बढ़कर 53 करोड़ रुपये हो गयी । बैंकों के लिए उपलब्ध कुल पुनर्वित्त सीमाओं[2] की राशि जून 1978 के 435 करोड़ रुपयों के मुकाबले जून 1979 के अंत में 751 करोड़ रुपये थी; इसी प्रकार इन सीमाओं के संदर्भ में वास्तव में लिये गये पुनर्वित्त की राशि खाद्यान्न निर्यात और छोटे कृषकों के लिए सुविधा के अंतर्गत पुनर्वित्त की मात्रा में वृद्धि होने के कारण जून 1979 के अंत में 600 करोड़ रुपये थी जो एक वर्ष पूर्व के 187 करोड़ रुपयों के मुकाबले काफ़ी अधिक थी । इसके विपरीत बिलों की पुनर्भुनाई से संबंधित

[1] जून 1979 के अंत तक बकाया पुनर्वित्त/पुनः भुनाये गये बिलों के आंकड़े अनंतिम हैं ।

[2] इसमें पूंजी गत वस्तुओं के आयात के लिए दिया गया पुनर्वित्त, नयी जहाजरानी ऋण योजना के अंतर्गत विदेशों के प्राप्त जहाज, शुष्क वापसी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिया गया पुनर्वित्त शामिल है ।

सीमाओं की जून 1979 में विद्यमान 118 करोड़ रुपयों की राशि जून 1978 की सीमाओं (187 करोड़ रुपये) से कम थी । जून 1979 के अंत में विद्यमान बकाया राशि (77 करोड़ रुपये) भी जून 1978 (101 करोड़ रुपये) की अपेक्षा कुछ कम ही थी । बैंकों द्वारा लिये गये पुनर्वित्त की औसत लागत की मात्रा जून 1979 के अंत में (9.24 प्रतिशत) एक वर्ष पहले (9.06 प्रतिशत) की अपेक्षा थोड़ी सी उच्चतर थी ; क्योंकि इस वर्ष ऋण सीमाओं का अधिक मात्रा में उपयोग किया गया । परंतु रिजर्व बैंक में पुनः भुनाये गये बिलों के मामले में ब्याज की औसत दर जून 1978 के मुकाबले सीमान्त रूप से कम थी।

2.14 पुनर्वित्त सीमाओं का अधिक उपयोग करने के अलावा, दिसंबर 1978 से बैंकों ने अपनी चल आस्तियों को कम कर दिया; इससे चल-निधि अनुपात नवंबर 1978 के 35.7 प्रतिशत से गिरकर जून 1979 में 34.1 प्रतिशत हो गया । इसके अतिरिक्त बैंकों ने ऋण का विस्तार करने के लिए मांग मुद्रा और सहभागिता प्रमाणपत्रों के निर्गम के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का काफी अधिक प्रश्रय लिया ।

2.15 एक वर्ष की अवधि में सकल ऋण में समग्र रूप से हुई वृद्धि की राशि 2,820 करोड़ रुपये (17.9 प्रतिशत) थी जबकि उक्त राशि पिछले वर्ष 2,188 करोड़ रुपये (16.1 प्रतिशत) थी । खाद्यान्नों की वसूली के लिए दिये गये अग्रिमों की राशि में 1978-79 में 471 करोड़ रुपयों (18.7 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई जबकि पिछले वर्ष उसमें 11 करोड़ रुपयों की गिरावट आयी थी । सकल खाद्येतर ऋणों की राशि जून 1978 के अंत में जहां 13,270 करोड़ रुपये थी वहां अगस्त के अंत से दिसंबर के अंत तक की अवधि में उसमें तीव्र वृद्धि पायी गयी और वह 13,082 करोड़ रुपयों से बढ़कर 15,515 करोड़ रुपये हो गयी, परंतु तत्पश्चात् फ़रवरी 1979 के अंत तक उक्त राशि घटकर 15,347 करोड़ रुपये रह गयी । तत्पश्चात् सकल खाद्येतर ऋणों में थोड़ी-सी बढ़ोतरी हुई और उनकी राशि बढ़कर 29 जून 1979 को 15,619 करोड़ रुपये हो गयी जो एक वर्ष की अवधि में हुई 2,349 करोड़ रुपयों (17.7 प्रतिशत) की वृद्धि की द्योतक थी; इसके विपरीत पिछले वर्ष उसमें 2,199 करोड़ रुपयों (19.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी । पहली दिसंबर 1978 से दिसंबर 1978 के अंत तक का वृद्धिशील खाद्येतर (सकल) ऋण-जमा अनुपात 93.9 प्रतिशत था जबकि मार्च 1979 के अंत तथा जून 1979 के अंत में उक्त अनुपात घटकर क्रमशः 73.5 प्रतिशत और 48.9 प्रतिशत हो गया । जून 1979 के अंत में विद्यमान 66.8 प्रतिशत का सकल ऋण-जमा अनुपात एक वर्ष पहले के स्तर (67.8 प्रतिशत) की अपेक्षा एक प्रतिशत न्यून था।

ऋण नीति

2.16 1976-77 तथा 1977-78 के दो क्रमिक वर्षों में मुद्रा उपलब्धि में भारी मात्रा में हुई वृद्धि को देखते हुए तथा 1978-79 में राष्ट्रीय आय में सामान्य वृद्धि होने की संभावना के परिप्रेक्ष्य में 1978-79 के दौरान रिजर्व बैंक की ऋण नीति का उद्देश्य पहले की तरह यही बना रहा कि ऋण विस्तार को रोका जाए और उसे उत्पादन, आर्थिक कार्यकलाप तथा रोजगार के निर्माण में वृद्धि के अनुरूप बनाया जाए। आलोच्य वर्ष के दौरान किये गये प्रतिबन्धक उपायों में निम्नलिखित शामिल थे: सांविधिक चलनिधि अनुपात में वृद्धि की गयी, बैंकों के लिए निर्देशक सिद्धान्त के रूप में सकल वृद्धिशील खाद्येतर ऋण-जमा अनुपात निर्धारित किया गया, सांविधिक चलनिधि अनुपात और प्रारक्षित नकदी अनुपात बनाये रखने में चूक करने पर दंड लागू किया गया तथा बैंकों को रिजर्व बैंक से लिये जानेवाले उधारों, मांग मुद्रा बाजार और सहभागिता प्रमाण-पत्रों के प्रश्रय जैसे बाहरी स्रोतों पर अपनी निर्भरता को न्यूनतम रखने के लिए कहा गया । साथ ही, समाज के कमजोर वर्गों को अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने की नीति का भी पालन किया गया ।

मई 1978 के मध्य में लिए गए उपाय

2.17 अप्रैल 1978 के पूरे महीने में वाणिज्य बैंकों के पास असामान्य रूप से उच्च चलनिधि अनुपात (लगभग 36 प्रतिशत) पाया गया । अतः रिजर्व बैंक ने 15 मई 1978 को 1978 के कम कामकाज के समय के लिए जो ऋण नीति घोषित की उसका उद्देश्य यह था कि बैंकिंग तन्त्र के पास विद्यमान इस अत्यधिक चलनिधि को कम किया जाए । रिजर्व बैंक से उपलब्ध पुनर्वित्त सुविधाओं को सीमित करने के लिए खाद्य ऋण के जिस मूलभूत स्तर पर पुनर्वित्त उपलब्ध होता है, उसे पहली जून 1978 से 1,500 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दिया गया । स्वतः पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत बैंक मार्च 1977 के अंतिम शुक्रवार को विद्यमान अपनी मांग और मीयादी देयताओं के एक प्रतिशत के बराबर की मात्रा तक पुनर्वित्त के लिए पात्र थे बशर्ते कि संबंधित उधार सरकारी अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों पर लिये गये हों; पहली जून 1978 से उक्त सुविधा को भी वापस ले लिया गया । परंतु समाशोधन संबंधी असंतुलनों को दूर करने के निमित्त बैंक दर पर उपलब्ध विवेकाधीन अथवा अस्थायी व्यवस्थाओं के अधीन अस्थायी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी । इसके अलावा अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना के माध्यम से विदेशों से प्राप्त होनेवाले साधनों से मुद्रा उपलब्धि पर होनेवाले प्रभाव को कम करने के लिए बैंकों से यह कहा गया कि वे इन दोनों वर्गों के खातों के अंतर्गत प्रत्येक बैंक में 1 जून 1978 के बाद प्राप्त होनेवाली शुद्ध कुल राशि के आधे अंश को रुपयों में जमा करें[1]। इन विशेष जमाराशियों पर वार्षिक 6.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज देने की व्यवस्था थी । न्यूनतम सांविधिक अनुपात (10 प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित निधि अनुपात के अंतर्गत रखी गयी जमा रकम सहित) के अतिरिक्त रिजर्व बैंक के पास रहने वाली बैंकों की प्रारक्षित नकदी निधियों पर देय ब्याज को भी 1 जून 1978 से 6.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया ।

नवम्बर 1978 के उपाय

2.18 31 मार्च 1978 से 10 नवंबर 1978 तक की अवधि में काफी अधिक मुद्रा विस्तार पाया गया जो पिछले दो वर्षों में पायी गयी भारी वृद्धि के अतिरिक्त था । वस्तुतः 22 सितंबर 1978 से प्रारंभ होने वाले आठ क्रमिक सप्ताहों के दौरान प्रति सप्ताह औसतन 100 करोड़ रुपयों की दर से ऋण विस्तार हुआ । ऋण में हुआ यह तीव्र विस्तार विशेष रूप से इसलिए चिंता का विषय बन गया कि 1978-79 में राष्ट्रीय आय में लगभग 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि प्रत्याशित थी । अतः यह आवश्यक समझा गया कि ऋण विस्तार की संभावनाओं को रोक दिया जाए । इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर नवंबर 1978 में दो अतिरिक्त उपाय किये गये; इनमें से पहला उपाय यह था कि वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात निर्धारित किया गया और दूसरा उपाय यह था कि सांविधिक चलनिधि अनुपात में बढ़ोतरी की गयी । बैंकों को अपने खाद्येतर ऋणों का विस्तार इस प्रकार करने के लिए सूचित किया गया कि पहली दिसंबर 1978 से मार्च 1979 के अंत तक की अवधि के लिए वृद्धिशील सकल खाद्येतर ऋण-जमा अनुपात 40 प्रतिशत के भीतर हो । उनसे यह भी आग्रह किया गया कि उनके द्वारा प्रदान किया जानेवाला ऋण उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक कार्यकलाप और रोजगार निर्माण से संबद्ध हो । दूसरी बात यह है कि पहली दिसंबर 1978 से सांविधिक चलनिधि

[1] इस शर्त को 5 जून 1979 से वापस ले लिया गया ।

अनुपात को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया; इस प्रतिशत को अतिरिक्त जमाराशियों पर कड़ाई से लागू करना था, भले ही पहली दिसम्बर 1978 को किसी विशिष्ट बैंक के सांविधिक चलनिधि संबंधी अनुपात की अतिरिक्त मात्रा कुछ भी क्यों न हो। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि अत्यंत विशेष स्थिति में अथवा अत्यावश्यकता की स्थिति में विवेकाधीन पुनर्वित उपलब्ध होगा और रिज़र्व बैंक से यदा-कदा और अन्तिम उपाय के रूप में प्रश्रय लेना चाहिए । बैंकों को यह भी स्पष्ट किया गया कि जहां प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जुटायी गयी जमाराशियों के काफी अधिक अंश का उसी क्षेत्र में उपयोग करने पर पहले की तरह बल दिया जाता रहेगा वहां यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनके लाभ विशेष रूप से कमजोर अथवा निर्धन वर्गों तक जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग शामिल हैं, पहुंचते हैं । इस बात पर भी बल दिया गया कि ऋणकर्ताओं द्वारा किये जानेवाले बैंक ऋण के उपयोग पर बैंकों को पहले की अपेक्षा अधिक ध्यान देना चाहिए तथा टंडन समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों को कार्यान्वित करना चाहिए । उन्हें विशेष रूप से अपेक्षाकृत बड़े ऋणकर्ताओं को ब्याज दरों में रियायत नहीं देनी चाहिए; क्योंकि इस प्रकार करने से बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । निधियों की चुकौती पर भी उन्हें सावधानी से निगरानी रखनी चाहिए । बैंकों से कहा गया कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय क्षेत्रों को बड़े अथवा छोटे ऋणकर्ताओं से ऋण अंतरित नहीं किये जाते तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से इतर क्षेत्रों के बजाय वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने पर अधिक ध्यान दें।

मार्च 1979 के उपाय

2.19 मार्च 1979 के मध्य में रिज़र्व बैंक ने अर्थ व्यवस्था में निर्मित हो रही मुद्रास्फीतिगत संभावनाओं की ओर बैंकों का ध्यान दिलाया तथा उन्हें यह सूचित किया कि चूंकि 1978-79 में मुद्रा विस्तार में योगदान देनेवाला प्रमुख तत्व वाणिज्य क्षेत्र को दिये गये ऋणों का विस्तार रहा है, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऋणों में की जानेवाली और वृद्धि को कठोरतापूर्वक उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकताओं के साथ संबद्ध किया जाता है । चूंकि खाद्यान्न, चीनी, दाई, चाय और तमाखू जैसे पण्यों के लिए मौसमी मांग बनी रहेगी तथा आगामी महीनों में उनमें वृद्धि भी हो सकती है, यह और भी आवश्यक है कि जिन ऋणकर्ताओं ने बैंकिंग तंत्र से भारी मात्रा में राशि उधार ले ली थी, उन्हें दिये जाने वाले ऋणों को इस प्रकार विनियमित किया जाए कि केवल अत्यावश्यक अपेक्षाओं की पूर्ति हो । इस संदर्भ में बैंकों को निम्नप्रकार सूचित किया गया : (क) आंकड़ों के संकलन तथा उनके विश्लेषण के अपने आंतरिक तंत्र को वे मजबूत बनाये ताकि वे प्रति सप्ताह होनेवाले ऋण विस्तार पर बारीकी से ध्यान रख सकें, (ख) 50 लाख रुपयों तथा उससे अधिक की ऋण सीमाओं का पुनरीक्षण करें तथा जिन पार्टियों के मामलों में वर्तमान नकदी ऋण सीमाओं का 60 से 65 प्रतिशत अंश प्रयुक्त किया जा चुका है, उन मामलों में और ऋण प्रदान करने से पहले अत्यंत कड़ाई से जांच की जानी चाहिए तथा ऐसे ऋणों को अत्यंत सुस्पष्ट प्रयोजनों, जैसे उत्पादन वृद्धि अथवा वर्तमान बायवों की पूर्ति, से संबद्ध करना चाहिए, तथा (ग) मांग मुद्रा बाजार से लिये जानेवाले उधारों तथा सहभागिता प्रमाणपत्रों की बिक्री जैसे बाहरी स्रोतों पर अपनी निर्भरता को वे न्यूनतम रखें ।

2.20 यह भी पाया गया कि बैंकों को पहली दिसम्बर 1978 से सांविधिक चलनिधि अनुपात को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर देने का निदेश दिये जाने के बावजूद बैंकों ने सरकारी निवेशों में अपनी मात्रा में वृद्धि तो नहीं की थी परंतु वे अपने ऋणों में विस्तार करते रहे और इस प्रकार उन्होंने न केवल अपने ही वित्तीय साधनों का पूरा उपयोग किया परंतु मांग मुद्रा बाजार और सहभागिता प्रमाणपत्रों जैसे बाहरी स्रोतों के प्रश्रय को मात्रा में भी वृद्धि की । जिन बैंकों ने निर्धारित सांविधिक चलनिधि अनुपात और प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को बनाये रखने में चूक की थी उन बैंकों से यह कहा गया कि वे ऐसी कमी को पूर्ति करने के लिए तत्काल कदम उठायें । यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक इस प्रकार के कदम उठाते हैं, सांविधिक चलनिधि अनुपात तथा प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात का पालन न करने पर दंड लागू किया गया । 30 मार्च 1979 से जिन बैंकों ने मांग और मीयादी देयताओं के 34 प्रतिशत का सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये नहीं रखा था और/या जिन्होंने निर्धारित प्रारक्षित निधी संबंधी अनुपातों के संदर्भों में चूक की थी, उन्हें उस समय तक पुनर्भुनाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी जाएंगी जब तक उन्होंने ऐसी कमियों की पूर्ति नहीं की । उपर्युक्त प्रकार से चूक करने के अतिरिक्त यदि बैंकों ने 30 मार्च, 1979 तक पुनर्वित/पुनर्भुनाई सुविधाओं का उपयोग किया हो तो सांविधिक चलनिधि अनुपात और प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी के बराबर की पुनर्वित/पुनर्भुनाई सहायता के अंश पर 3 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज लेना था ।

1979 के कम कामकाज के समय के लिए ऋण नीति

2.21 इसके अलावा, मई 1979 में बैंकों को यह सूचित किया गया कि 1979-80 में उनके ऋण विस्तार की मात्रा सापेक्ष तथा समग्र रूप से पूर्व वर्ष के मुकाबले काफ़ी कम होनी चाहिए । चूंकि यह आशा की जाती थी कि आगामी महीनों में खाद्यान्नों की वसूली के लिए वितरित किये जानेवाले ऋणों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होगी, इस बात पर बल दिया गया कि बैंक खाद्येतर ऋणों की मात्रा को सीमित रखें । उन्हें यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि चीनी, वस्त्र उद्योगों जैसे मौसमी उद्योगों द्वारा, जिन्होंने इसके पूर्व भारी मात्रा में उधार लिये थे, निधियों की चुकौती तेजी से की जाती है । शाखा स्तर पर ऋणों पर पर्याप्त नियंत्रण रखने के उद्देश्य से बैंकों से यह कहा गया कि वे निम्नलिखित आधार पर आंतरिक मार्गदर्शी सिद्धांत बनायें : (1) नयी ऋण सीमाएं निर्धारित करते समय अथवा वर्तमान ऋण सीमाओं में वृद्धि करते समय प्रस्तावों की पूरी तथा ब्यौरेवार जांच की जानी चाहिए तथा इस जांच में अतिरिक्त मूल्य वृद्धि की प्रत्याशा के कारण आवेदित ऋण वृद्धि पर विचार नहीं किया जाना चाहिए । यदि ऋण में कोई अतिरिक्त वृद्धि की जाती है तो उसे कड़ाई से उत्पादन में वृद्धि अथवा अनुमत बिलों के साथ संबद्ध किया जाना चाहिए । (2) 50 लाख रुपयों से अधिक की वर्तमान ऋण सीमाओं को संशोधित करने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि बड़े ऋणकर्ता कार्यकारी पूंजीगत प्रयोजनों के लिए बैंक ऋणों पर ही निरंतर काफ़ी अधिक निर्भर रहे तो ऐसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए । (3) संवेदनशील पण्यों के संदर्भ में ऋण मंजूर करते समय तथा उसके उपयोग का अनुशीलन करते समय विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और विशेष रूप से व्यापारियों के संदर्भ में ऐसे ऋण की मात्रा को सीमित रखा जाना चाहिए ।

2.22 बैंकों द्वारा सहभागिता प्रमाणपत्रों का अत्यधिक मात्रा में प्रश्रय लिया जाना कुछ चिंता का विषय था; अतः भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 1979 के प्रारंभ में बैंकों द्वारा लिये जानेवाले सहभागिता प्रमाणपत्रों तथा वित्तीय संस्थाओं से मांग मुद्रा बाजार में लिये जानेवाले उधारों का पुनरीक्षण करने के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया । कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफ़ारिश की कि सह-भागिता प्रमाणपत्रों के माध्यम से जुटायी गयी निधियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपातों और सांविधिक चलनिधि अनुपात की शर्तें लागू की जाएं । उक्त दल की सिफ़ारिशें जहां विचाराधीन हैं वहां रिज़र्व बैंक ने यह निश्चय किया कि वाणिज्य बैंकों को भारी मात्रा में सहभागिता

प्रमाणपत्रों का प्रश्रय लेने से निरुत्साहित करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाए। परंतु यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि इस संबंध में की गयी कार्रवाई से बैंकों के कार्यकलाप प्रभावित नहीं होते तथा इससे अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए अन्य प्रकार के अल्पावधि निवेश करने में कठिनाई नहीं होती, रिज़र्व बैंक ने सहभागिता प्रमाणपत्रों को क्रमिक रूप से सांविधिक चलनिधि अनुपात/प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की शर्तों के अंतर्गत लाने का निश्चय किया ।

2.23 समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 21 जून, 1979 को यह सूचित किया गया कि जुलाई 1979 के अंतिम शुक्रवार से तथा उसके बाद उनके द्वारा जारी किये गये बकाया सहभागिता प्रमाणपत्रों को आकस्मिक देयताओं के रूप में नहीं परंतु जमाराशियों के रूप में माना जाएगा तथा उन पर सांविधिक चलनिधि अनुपात तथा 6 प्रतिशत के प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की शर्तें निम्नलिखित चरणों में लागू होंगी —जुलाई 1970 के अंतिम शुक्रवार से 50 प्रतिशत, अगस्त 1979 के अंतिम शुक्रवार से 75 प्रतिशत और सितम्बर 1979 के अंतिम शुक्रवार से 100 प्रतिशत अर्थात् बकाया सहभागिता प्रमाणपत्रों की पूरी राशि। इसके अतिरिक्त, इन बैंकों से यह भी अपेक्षा की गयी कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जुलाई 1979 के अंतिम शुक्रवार को विद्यमान बकाया जमा स्तर के मुकाबले सहभागिता प्रमाणपत्रों में हुई किसी वृद्धि के 10 प्रतिशत के बराबर से अन्यून राशि की अतिरिक्त औसत दैनिक जमा रकम बनाये रखें । जारी किये गये सहभागिता प्रमाणपत्रों की राशि को अब तक की पद्धति के अनुसार, उनके कुल अग्रिमों की राशि में से कम नहीं करना चाहिए; और खरीदे गये सहभागिता प्रमाणपत्रों की राशि को कुल अग्रिमों की राशि में शामिल नहीं किया जाना चाहिए; परंतु उन्हें बैंकों को दिये गये अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत जाना चाहिए। सहभागिता प्रमाणपत्र जारी करने से जमा होनेवाली राशियों को रिज़र्व बैंक के ब्याज दर संबंधी निदेश से छूट प्राप्त होगी । जिस अधिकतम ब्याज दर पर सहभागिता प्रमाणपत्र जारी किये जा सकते हैं वह पहले की तरह वार्षिक 10 प्रतिशत बनी रहेगी ।

ब्याज दरों में परिवर्तन

2.24 आलोच्य वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंकों का समग्र ब्याज दर विन्यास जहां बिना किसी परिवर्तन के पूर्ववत् बना रहा, वहां उसमें कुछ समायोजन किये गये जिनका उद्देश्य ब्याज दरों को अन्य वित्तीय संस्थाओं की ब्याज दरों के अनुरूप बनाया था ।

2.25 वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सहकारी समितियों को प्रदान किये गये ऋणों पर ली जानेवाली ब्याज दरों को भी संशोधित किया गया जिससे कि उन्हें सहकारी बैंकों द्वारा ली जानेवाली दरों के अनुरूप बनाया जाए । पहली मार्च 1979 से वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह निदेश दिया गया कि वे प्राथमिक समितियों तथा कृषक सेवा समितियों को दिये जानेवाले निर्दिष्ट ऋणों पर 9 प्रतिशत की दर पर ब्याज लें । छोटे कृषकों को लघु सिंचाई भूमि विकास के लिए तथा विविध प्रयोजनों के लिए दिये जानेवाले मीयादी ऋणों के संबंध में ब्याज की दर 15 मार्च 1979 से घटाकर 8 प्रतिशत कर दी गयी । इससे सहकारी समितियां मीयादी ऋणों के मामले में 1/2 प्रतिशत और अल्पावधि ऋणों के मामले में 2 प्रतिशत अथवा अधिक का मार्जिन रख सकेंगी और वे अंतिम ऋणकर्ताओं को उसी दर पर ऋण उपलब्ध करा सकेंगी जिस दर पर कृषक वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सीधे ही उधार लेते हैं ।

2.26 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा अपनी पुनर्वित्त दरों में कमी लाने तथा ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाओं द्वारा अंतिम ऋणकर्ताओं से ली जानेवाली अधिकतम ब्याज दरों में 15 मार्च, 1979 से कमी लाये जाने के परिणामस्वरूप बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे तीन वर्षों से अन्यून अवधियों के ऋणों के लिए कृषकों से निम्नप्रकार ब्याज लें: (i) लघु सिंचाई तथा भूमि विकास के लिए 9.5 प्रतिशत की अनधिक दर पर (इसके पहले की दर 10.5 प्रतिशत थी) और (ii) विविध प्रयोजनों के लिए (क) लघु कृषकों से 9.5 प्रतिशत से अनधिक दर पर तथा (ख) अन्य ऋणकर्ताओं से 10.5 प्रतिशत की दर पर (इसके पहले दोनों के लिए ऐसी दर 11 प्रतिशत थी । कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की पुनर्वित्त दरें (i) और (ii) (क) के लिए 6.5 प्रतिशत तथा (ii) (ख) के लिए 7.5 प्रतिशत होंगी । संशोधित दरें, 15 मार्च 1979 से प्रदान किये गये समस्त नये ऋणों पर लागू हैं भले ही ऐसे ऋण कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए अत्यंत कम हों अथवा नहीं और चाहे संबंधित बैंक ने वास्तव में पुनर्वित्त सुविधा का लाभ उठाया हो अथवा नहीं ।

चयनात्मक ऋण नियंत्रण

2.27 चयनात्मक ऋण नियंत्रण के सामान्य स्वरूप में जहां कोई परिवर्तन नहीं किया गया वहां कतिपय पण्यों की पूर्ति संबंधी स्थिति तथा मूल्यों की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए उन पर दिये जाने वाले अग्रिमों से संबंधित विनियमों में समायोजन किये गये । अग्रिमों की न्यूनतम ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किये गये तथा वे 14 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के बीच अलग-अलग रहीं ।

(i) चीनी

2.28 चीनी के मूल्यों, उसकी आवाजाही तथा उसके वितरण पर से 16 अगस्त 1978 से नियंत्रण हटा दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में तथा सरकार के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि परिवहन की अवधि के दौरान स्टाकों के मूल्यांकन के आधार में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, 29 अगस्त 1978 को बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे चीनी का निर्माण करनेवाली पार्टियों को चीनी के जिन स्टाकों पर अग्रिम प्रदान किये गये हों, उनके मूल्यांकन में कोई परिवर्तन न करें । उन्हें यह भी सूचित किया गया कि लेवी स्टाकों और मुक्त बिक्री के स्टाकों के बीच का अंतर—(क) बिक्री के लिए न निकाली गयी और (ख) बिक्री के लिए निकाली गयी चीनी-काल्पनिक रूप से बना रहेगा तथा अग्रिमों के लिए 15 प्रतिशत अथवा 65 प्रतिशत के संबंधित मार्जिन, यथास्थिति, पहले की तरह लागू किये जाएं । चीनी का निर्माण करने वाली पार्टियों से इतर पार्टियों को चीनी पर दिये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में स्टाकों के मूल्यांकन और मार्जिन संबंधी शर्तें बिना किसी परिवर्तन के जारी रहीं । रुग्ण चीनी मिलों के कार्य पर चीनी के गिरते हुए मूल्यों के प्रभाव तथा चीनी उद्योग की वास्तविक (अस्थायी) ऋण संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए बैंकों को सितम्बर 1978 में यह सूचित किया गया कि वे हर योग्य चीनी मिल को सीमित मात्रा तक कतिपय शर्तों पर 25 लाख रुपयों से अनधिक अस्थायी निर्बाध ऋण प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं । ऐसे ऋण 30 नवम्बर 1978 तक प्रदान किये जा सकते हैं, जिन्हें 1978-79 के मौसम के प्रारम्भ होते ही, परन्तु किसी भी मामले में 31 मई 1979 तक चुकाना होगा ।

2.29 तदनन्तर 14 अक्तूबर, 1978 से चीनी के लेवी स्टाकों और मुक्त बिक्री के स्टाकों के बीच विद्यमान काल्पनिक अंतर को समाप्त कर दिया गया । चीनी की पूर्ति की संतोषजनक स्थिति और 1978-79 के मौसम में गन्ने के उत्पादन की अच्छी संभावनाओं को देखते हुए चीनी का निर्माण करने वाली पार्टियों को चीनी के स्टाकों पर दिये जाने वाले अग्रिमों के न्यूनतम मार्जिन को समान रूप से बैंकों में जमानत के रूप में रखे गये समस्त स्टाकों के मूल्य का 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया और चीनी का निर्माण करने वाली पार्टियों से इतर पार्टियों को प्रदान किये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में न्यूनतम मार्जिन तथा न्यूनतम ब्याज दर पहले की तरह क्रमशः 65 प्रतिशत और 15 प्रतिशत बनी रही । चीनी का उत्पादन करने वाली पार्टियों को चीनी के स्टाक पर दिये जाने वाले अग्रिमों के लिए जहां ब्याज की कोई न्यूनतम दर निर्धारित नहीं

की गयी यहां उन पर अग्रिमों की सामान्य न्यूनतम ब्याज दर (वार्षिक 12-1/2 प्रतिशत) की शर्त लागू की गयी ।

2.30 आमतौर पर मूल्यों में हाल ही में हुई वृद्धि तथा विशेष रूप से कतिपय संवेदनशील पण्यों (चीनी सहित) के मूल्यों में हुई वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में पूर्ति संबंधी स्थिति संतोषजनक होने के बावजूद बैंकों को 29 जून, 1979 को यह सूचित किया गया कि वे इन पण्यों की जमाखोरी के लिए बैंक वित्त का उपयोग करने की किसी प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए ऐसे अग्रिमों पर कड़ाई से ध्यान रखें । तिलहनों, तेलों और वनस्पति तेलों पर दिये जाने वाले अग्रिमों के संदर्भ में जारी किये गये अनुदेश संबंधित खंडों में दिये गये हैं । चीनी पर दिये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में बैंकों को यह सूचित किया गया कि (क) चीनी निर्माता यूनिटों को पहले स्वीकृत 25 लाख रुपयों की निर्बंध सीमाओं को वापस ले लिया जाए तथा ऋणों की शीघ्रतापूर्वक चुकौती की जाए, (ख) चीनी के स्टाक रखने के लिए चीनी कारखानों द्वारा लिये गये ऋणों को कारखानों से निकाले गये स्टाकों के अनुरूप कम किया जाए और (ग) चीनी पर दिये जाने वाले समस्त अग्रिमों के संदर्भ में मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं को बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए । परन्तु सरकार की सार्वजनिक वितरण योजना के अन्तर्गत स्टाक धारित करने वाली उपभोक्ता सहकारी समितियों को इस अपेक्षा से छूट दी गयी ।

(ii) रूई और कपास

2.31 वस्त्र मिलों द्वारा धारित रूई के स्टाकों की सीमाओं में वस्त्र आयुक्त द्वारा हाल ही में घोषित छूट को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने मिलों को कच्ची रूई और कपास पर दिये जाने वाले अग्रिमों से संबंधित ऋण नियंत्रण उपायों में 29 मार्च 1979 को संशोधन किया । स्टाकों के जिन स्तरों के संदर्भ में मिलों को अमल में रहने वाले न्यूनतम मार्जिनों के साथ अग्रिम प्रदान किए जा सकते हैं, उन्हें बम्बई और अहमदाबाद में स्थित मिलों के लिए चार सप्ताहों की खपत से बढ़ाकर तीन महीनों की खपत कर दिया गया तथा बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित मिलों के लिए आठ सप्ताहों की खपत से बढ़ाकर साढे चार महीनों की खपत कर दिया गया, और भारत के अन्य भागों में स्थित मिलों के लिए चार सप्ताहों की खपत से बढ़ाकर छः सप्ताहों की खपत कर दिया गया और केवल धागे की कताई में लगी हुई मिलों के लिए ऐसी खपत की मात्रा को छः सप्ताहों से बढ़ाकर चार महीने कर दिया गया । परन्तु न्यूनतम मार्जिन और न्यूनतम ब्याज बिना किसी परिवर्तन के वही बने रहे; केवल बाद में किये गये परिवर्तन स्टाकों के स्तरों से संबंधित थे, मिलों से इतर पार्टियों को दिये जाने वाले अग्रिमों पर विद्यमान ऋण नियंत्रण में भी कोई परिवर्तन नहीं किया था ; परन्तु ऋण के स्तर को बढ़ाकर किसी पार्टी द्वारा 1975-76, 1974-75 और 1973-74 के बजाय 1977-78 1976-77 और 1975-76 के पिछले तीन वर्षों (नवम्बर-अक्तूबर) में से किसी एक वर्ष में प्रयुक्त ऋण के सर्वोच्च स्तर के 100 प्रतिशत के बराबर कर दिया गया ।

2.32 रिजर्व बैंक ने इस बात पर भी पुनः बल दिया कि उद्योगों के संदर्भ में स्टाकों के स्तर पर ऐसे मानदंड पहले की तरह लागू होते रहेंगे जो बैंक ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसरण में अथवा किसी दूसरे प्रकार से निर्धारित किये जाएं ।

(iii) दालें, तेल और तिलहन

2.33 29 जून, 1979 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से यह कहा गया कि वे अभिसंस्करण यूनिटों तथा अन्यों को दालों पर दिये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में पहले के क्रमशः 35 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के न्यूनतम मार्जिन के बजाय क्रमशः 45 प्रतिशत और 60 प्रतिशत का मार्जिन रखें । गोदाम रसीदों पर दिये जाने वाले अग्रिमों को अभिसंस्करणकर्ताओं के लिए 40 प्रतिशत ही बनाये रखा गया जब कि अन्यों के लिए उसे 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया ।

2.34 बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे सरकारी तथा सरकार से सहायता प्राप्त संगठनों से इतर पार्टियों को वनस्पति तेलों और तिलहनों पर अतिरिक्त ऋण सीमाएं मंजूर न करें ; ऐसे संगठनों के मामले में भी निकाली जाने वाली राशियों के मामले में कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है ।

साख आयोजना

2.35 साख आयोजना का तंत्र पिछले कई वर्षों से क्रमन में है ; इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऋण नीति संबंधी अपेक्षाओं का पालन किया जाता है और राष्ट्रीय विकास योजनाओं के लक्ष्यों के अनुरूप बैंक ऋण प्रदान किये जाते हैं । रिजर्व बैंक समय-समय पर निजी तथा सरकारी क्षेत्र के ऋण के प्रमुख उपयोगकर्ताओं के साथ पहले की तरह विचार-विमर्श करता रहा, ताकि ऋण की मांग के बारे में कुछ अनुमान हो । साख आयोजना संबंधी इन तकनीकों को जहां अल्पावधि साख आयोजना से सीधे संबंधित माना जा सकता है, वहां साख आयोजना संबंधी कतिपय उपायों का स्वरूप इस प्रकार बनाया गया है कि वाणिज्य बैंक के विन्यास में परिवर्तन लाया जाए । ऐसे तीन उपायों अर्थात् प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ऋण प्रदान करने के मामले में राष्ट्रीय लक्ष्यों, ऋण प्राधिकरण योजना और अग्रणी बैंक योजना का हाल ही के वर्षों में उपयोग किया गया है, ताकि वाणिज्य बैंकों के ऋण विन्यास में वांछित परिवर्तन लाये जाएं ।

2.36 कुल बैंक ऋणों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का अंश जहां पिछले वर्षों के मुकाबले मार्च 1979 तक बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया था, वहां इस बढ़ोतरी के साथ-साथ कुल ऋण में बड़े और मझौले उद्योगों के संबंधित अनुपातों में कुछ गिरावट आयी । अतः ऋण के क्षेत्रीय वितरण में लाये गये परिवर्तन की यह क्रमिक प्रक्रिया वाणिज्य बैंक ऋण के स्वरूप में आये परिवर्तन की द्योतक है ।

ऋण का क्षेत्रीय वितरण

2.37 सकल बैंक ऋण के क्षेत्रीय वितरण के संबंध में मई 1979 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं । जून 1978 के अंत से मई 1979 के अंत तक की अवधि के दौरान सकल बैंक ऋण में 2,615 करोड़ रुपयों की वृद्धि (+16.4 प्रतिशत) हुई, जबकि 1977-78 की तदनुरूप अवधि के दौरान उसमें 1,768 करोड़ रुपयों (+13.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी (सारणी 2.6) खाद्यान्नों की सार्वजनिक वसूली के लिए दिये गये ऋणों में 59 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में उनमें 235 करोड़ रुपयों की गिरावट आयी थी । सकल खाद्येतर ऋण की राशि में उक्त अवधि में 2,556 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई, जबकि 1977-78 की उसी अवधि में उसमें 2,003 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी ।

2.38 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों की राशि में 1,188 करोड़ रुपयों (+27.4 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई जबकि उसके पूर्व उसमें 750 करोड़ रुपयों (+21.5 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई थी । मई 1979 के अंत में सकल (शुद्ध) बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों का अंश 30.5 प्रतिशत था, जब कि एक वर्ष पूर्व उक्त अंश 28.0 प्रतिशत था । परन्तु वृद्धिशील (शुद्ध) ऋणों में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों का अंश 48.9 प्रतिशत था, जो एक वर्ष पहले के ऐसे अंश (45.9 प्रतिशत) की अपेक्षा उच्चतर था । प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को प्रदत्त अतिरिक्त अग्रिमों में से कृषि और लघु उद्योगों को क्रमशः 477 करोड़ रुपये और 432 करोड़ रुपये दिये गये, जब कि वर्ष 1977-78 की तदनुरूप अवधि में उन्हें क्रमशः 274 करोड़ रुपयें और 263 करोड़ रुपये दिये गये थे । कृषि को प्रदत्त कुल अग्रिमों की राशि मई 1979 के अंत में 2,203 करोड़ रुपये थी और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को प्राप्त कुल अग्रिमों में उनका अंश 39.9 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 39.1 प्रतिशत) था, जबकि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों की कुल ऋण राशि

में लघु उद्योग क्षेत्र को प्राप्त 2,188 करोड़ रुपयों के अग्रिमों का अंश 39.6 प्रतिशत था और एक वर्ष पूर्व उक्त अंश 40.7 प्रतिशत था ।

2.39 भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को प्रदत्त अग्रिमों की राशि मार्च 1979 तक उनके बकाया ऋणों के एक तिहाई अंश से अन्यून स्तर पर पहुंचनी चाहिए थी । मई 1979 के अंत तक के उपलब्ध आंकड़ों से यह विदित होता है कि इस लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में बैंकों ने उल्लेखनीय प्रगति की थी ।

2.40. बड़े और मझौले उद्योगों को दिये गये अग्रिमों की राशि में जून 1978 के अन्त से मई 1979 के अंत तक की अवधि के दौरान 934 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई, जब कि जून 1977 के अंत से मई 1978 के अन्त तक की अवधि के दौरान उसमें 726 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। मई 1979 के अंत में ऐसे बकाया ऋणों की राशि 7,183 करोड़ रुपये अथवा सकल ऋणों का 38.7 प्रतिशत थी; मई 1978 के अंत में बकाया ऋणों की राशि 6,098 करोड़ रुपये अथवा सकल ऋणों का 39.7 प्रतिशत थी। उद्योग क्षेत्र (बड़े मझौले और लघु उद्योग) को दिये गये कुल ऋणों की राशि में हुई 989 करोड़ रुपयों की वृद्धि के मुकाबले 1,366 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । आलोच्य अवधि के दौरान हुई वृद्धि मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्योगों के संदर्भ में हुई : इंजीनियरी (424 करोड़ रुपये) लोहा और इस्पात (61 करोड़ रुपये) सूती वस्त्र (84 करोड़ रुपये), रसायन (1.38 करोड़ रुपये) तथा नयी योजनाओं के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त जहाज (129 करोड़ रुपये)। थोक व्यापार को दिये गये अग्रिमों में (खाद्यान्नों की वसूली के लिए दिये गये अग्रिमों को छोड़कर) जून 1977 से मई 1978 तक की अवधि में हुई 320 करोड़ रुपयों की वृद्धि के मुकाबले आलोच्य अवधि के दौरान 131 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई। थोक व्यापार के मामले में भारतीय रुई निगम, भारतीय जूट निगम और "अन्य व्यापार" को दिये गये अग्रिमों में क्रमशः 69 करोड़ रुपयों, 28 करोड़ रुपयों और 70 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई, परन्तु भारतीय खाद्य निगम को उर्वरक के लिए दिये गये ऋण में 36 करोड़ रुपयों की गिरावट आने के कारण उक्त वृद्धि अंशतः समायोजित हो गयी ।

ऋण वितरण का क्षेत्रीय और ग्रामीण/शहरी स्वरूप

2.41. ऋण वितरण का अन्य महत्वपूर्ण पहलू ऋण वितरण का क्षेत्रीय और ग्रामीण/शहरी स्वरूप है । जून 1978 के अंतिम शुक्रवार को जनसंख्या समूह के अनुसार बैंक कार्यालयों के राज्यवार ऋण-जमा अनुपात सारणी 2.7 में दर्शाये गये हैं । जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में संकेत किया गया था, विश्लेषणात्मक प्रयोजनों के लिए इन अनुपातों की सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए । केवल इन्हीं आंकड़ों से यह विदित नहीं होता कि किसी राज्य में बैंकों द्वारा जुटायी गयी जमाराशियों को उस राज्य में किस सीमा तक विनियोजित किया गया है; क्योंकि इन जमाराशियों में राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, राज्य स्तर की संस्थाओं के डिबेंचरों आदि में किये गये बैंक निधियों के उन निवेशों को हिसाब में नहीं लिया जाता, जो विकासपरक और मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित परियोजनाओं के वित्तपोषण में योगदान देते हैं । इसके अलावा इस संदर्भ में "ऋण के स्थानांतरण" को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए अर्थात् बैंकों द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में जो ऋण मंजूर किये गये हों तथा उनकी बहियों में बकाया हों और इस कारण उन्हें उस क्षेत्र से संबंधित कुल ऋण के आंकड़ों में शामिल किया गया हो, उनके बारे में इस बात की संभावना हो सकती है कि उस क्षेत्र के कार्यकलापों का वित्तपोषण करने के लिए उसका उपयोग न किया गया हो । इसी प्रकार कतिपय मामलों में हिसाब में ली गयी जमाराशियों की न्यून मात्रा के कारण ऐसे अनुपात काफी अधिक भी हो सकते हैं ।

सारणी 2.6—सकल बैंक ऋण का क्षेत्रीय वितरण

(करोड़ रुपये)

मद	बकाया		घटबढ़	बकाया		घटबढ़
	जून 1977	मार्च 1978	जून 1977 की तुलना में मई 1978 में	जून 1978	मई@ 1979	जून 1978 की तुलना में मई 1979 में
I. खाद्यान्नों की सार्वजनिक वसूली	2,536	2,301	—235	2,525	2,584	+59
II. (क) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	3,486	4,236	+750 (37.4)	4,334	5,522	+1188 (46.5)
(i) कृषि	1,381	1,655	+274 (13.7)	1,726	2,203	+477 (18.7)
(ii) लघु उद्योग	1,460	1,723	+263 (13.1)	1,756	2,188	+432 (16.9)
(iii) अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	645	858	+213 (10.6)	852	1,131	+279 (10.9)
(ख) उद्योग (मझौले और बड़े)	5,372	6,098	+726 (36.3)	6,249	7,183	+934 (36.5)

@ अनंतिम

	1	2	3	4	5	6
(ग) थोक व्यापार (खाद्यान्नों की वसूली से इतर)	1,053	1,373	+ 320 (16.0)	1,424	1,555	+ 131 (5.1)
(1) भारतीय रूई निगम	135	150	+ 15	138	207	+ 69
(2) भारतीय खाद्य निगम (उर्वरक)	75	243	+ 168	250	214	— 36
(3) भारतीय जूट निगम	18	2	— 16	2	30	+ 28
(4) अन्य व्यापार	825	978	+ 153	1,034	1,104	+ 70
(घ) अन्य क्षेत्र	1,160	1,367	+ 207 (10.3)	1,428	1,731	+ 303 (11.9)
III. सकल खाद्येतर बैंक ऋण (क + ख + ग + घ)	11,071	13,074	+ 2003 (100.0)	13,435	15,991	+ 2,556 (100.0)
निर्यात ऋण (मद III के अन्तर्गत शामिल)	1,129	1,206	+ 77	1,142	1,447	+ 305
IV. सकल बैंक ऋण	13,607	15,375	+ 1,768	15,960	18,575	+ 2,615

@अनंतिम

टिप्पणी: 1. आंकड़े उन प्रमुख बैंकों से संबंधित हैं जिनका अंश सकल बैंक ऋण में लगभग 95 प्रतिशत है। इन आंकड़ों में रिजर्व बैंक में पुनः भुनाये गये बिलों को हिसाब में लिये जाने के अलावा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में तथा अन्य अनुमोदित संस्थाओं में पुनः भुनाय गये बिल और सहभागिता प्रमाणपत्र भी शामिल हैं।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े सकल खाद्येतर बैंक ऋण में वृद्धि के प्रतिशत हैं।

(स्रोत: साख आयोजना और बैंकिंग विकास कक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक)

सारणी 2.7—अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों का जन संख्या समूह के अनुसार राज्यवार ऋण-जमा अनुपात

(जून 1978 के अंतिम शुक्रवार को)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी/ महानगरीय	जोड़
	1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र	37.2	47.4	107.9	89.5
हरियाणा	57.3	62.1	62.6	61.4
हिमाचल प्रदेश	25.3	24.3	—	24.8
जम्मू और काश्मीर	18.4	47.7	22.1	23.7
पंजाब	21.9	37.4	46.3	37.0
राजस्थान	84.4	64.5	52.3	60.8
चंडीगढ़	19.4	—	247.4	346.7
दिल्ली	456.6	—	117.2	117.5
पूर्वोत्तर क्षेत्र	29.6	34.5	50.1	38.0
असम	30.9	42.1	51.4	43.4
मणिपुर	42.9	7.1	35.4	36.6
मेघालय	16.6	15.9	—	16.0
नागालैण्ड	3.5	34.7	—	27.9
त्रिपुरा	67.3	34.8	—	41.1
अरुणाचल प्रदेश	6.8	—	—	6.8
मिजोरम	13.3	7.1	—	7.4
सिक्किम	—	6.3	—	6.3

	1	2	3	4
पूर्वी क्षेत्र	52.1	34.1	67.7	58.7
बिहार	70.1	38.0	41.2	43.1
उड़ीसा	72.7	64.7	54.5	60.7
पश्चिम बंगाल	33.3	24.2	72.9	63.9
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	27.9	19.8	—	21.0
मध्यवर्ती क्षेत्र	52.0	52.0	46.4	48.8
मध्य प्रदेश	61.6	55.2	51.3	53.7
उत्तर प्रदेश	49.5	50.8	44.7	47.1
पश्चिमी क्षेत्र	41.0	42.1	73.4	65.9
गुजरात	30.0	34.5	66.3	50.4
महाराष्ट्र	66.9	50.6	74.9	72.5
दादरा और नागर हवेली	83.5	—	—	83.5
गोवा, दमन और दीव	25.3	48.3	—	40.5
दक्षिणी क्षेत्र	76.3	59.7	89.0	79.0
आंध्र प्रदेश	95.5	68.1	64.0	69.0
कर्नाटक	76.9	67.2	88.5	81.8
केरल	48.4	43.2	94.8	61.9
तमिलनाडु	90.5	66.5	104.1	94.2
लक्षद्वीप	6.6	—	—	6.6
पांडिचेरी	91.5	33.9	71.1	68.2
अखिल भारतीय	52.5	47.4	79.9	69.9

(स्रोत : कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण से संबंधित विवरणी)

2.42 ऋण जमा अनुपातों में विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है : जैसे इन अनुपातों की मात्रा सिक्किम के मामले में 6.3 प्रतिशत और चन्डीगढ़ के मामले में 346.7 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न थी। यदि क्षेत्रवार देखा जाए तो उक्त अनुपात उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में 60 प्रतिशत से भी अधिक था। दो क्षेत्रों के बीच का न्यूनतम अधिकतम अन्तर मध्यवर्ती क्षेत्र को छोड़ कर अन्य क्षेत्रों के मामले में उल्लेखनीय था। मध्यवर्ती क्षेत्र में यह अनुपात मध्य प्रदेश के मामले में 53.7 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश के मामले में 47.1 प्रतिशत था। हालांकि यह कहना कठिन है कि क्या बाद में इन अनुपातों में किसी विशिष्ट स्तर तक वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए, परन्तु इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि बैंकों को कई क्षेत्रों में इन अनुपातों को बढ़ाने में काफी प्रयास करने होंगे (सारणी 2.7)।

2.43 ऋण के वितरण का उतना ही महत्वपूर्ण पहलू एक ओर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों और दूसरी ओर शहरी/महानगरीय क्षेत्रों के बीच विद्यमान असंतुलन है। कतिपय ग्रामीण क्षेत्रों में पाये गये असामान्य रूप से ऋण-जमा अनुपात से यह आशंका उभरती है कि वित्तीय साधनों को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अंतरित करने के संदर्भ में ग्रामीण शाखाएं सहायक हो सकती हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सूचित किया गया कि मार्च 1979 तक उनकी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाएं कम से कम 60 प्रतिशत का ऋण जमा-अनुपात बनायें।[1] इस दृष्टिकोण से देखने पर अनुपातों में विद्यमान असंतुलन और भी स्पष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार, जून 1978 के अंत में समग्र देश के संदर्भ में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 52.5 प्रतिशत और 47.4 प्रतिशत का ऋण-जमा अनुपात विद्यमान था। केवल समग्र रूप से दक्षिणी क्षेत्र में ग्रामीण और अर्ध शहरी केन्द्रों में अपेक्षाकृत उच्च ऋण-जमा अनुपात (क्रमशः 76.3 प्रतिशत और 59.7 प्रतिशत) पाया गया। अन्य क्षेत्रों में उक्त अनुपात काफी कम थे। प्रत्येक क्षेत्र के भीतर भी अनुपात की मात्रा में काफी अंतर विद्यमान था। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे इसके पूर्व उल्लिखित राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए कठोर प्रयास करें।

2.44 ग्रामीण और अर्ध शहरी बैंक कार्यालयों के लिए ऋण-जमा अनुपातों के आधार पर जून 1978 में विद्यमान जिलों के वितरण से संबंधित आंकड़े सारणी 2.8 में प्रस्तुत किये गये हैं। इनके अनुसार जून 1978 के अंत में 388 जिलों में से 148 जिलों में ग्रामीण बैंक शाखाओं ने 60 प्रतिशत और उससे अधिक का ऋण-जमा अनुपात प्राप्त किया था। 346 जिलों में से 113 जिलों में अर्ध शहरी शाखाएं जून 1978 के अंत तक 60 प्रतिशत और उससे अधिक का ऋण जमा अनुपात प्राप्त कर सकीं। इस प्रकार, ग्रामीण बैंक शाखाओं तथा अर्ध शहरी बैंक शाखाओं के अन्तर्गत आने वाले क्रमशः 38 प्रतिशत और 33 प्रतिशत जिलों में जून 1978 के अंत में 60 प्रतिशत और उससे अधिक का ऋण-जमा अनुपात पाया गया।

2.45 ग्रामीण और अर्ध शहरी बैंक कार्यालयों के लिए जून 1978 के अंत में ऋण-जमा अनुपातों के आधार पर जिलों के वितरण के राज्यवार आंकड़े क्रमशः सारणी 2.9 और 2.10 में दर्शाये गये हैं। उनसे यह देखा जाएगा कि जिन 148 जिलों में ग्रामीण बैंक कार्यालयों ने 60 प्रतिशत और उससे अधिक का ऋण-जमा अनुपात प्राप्त किया था, उनमें से 19—19 जिले मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में, 18 जिले उत्तर प्रदेश में, 16 जिले राजस्थान में, 13 जिले कर्नाटक में और 11—11 जिले तमिलनाडु और महाराष्ट्र में थे। जिन 113 जिलों में अर्ध शहरी बैंक कार्यालयों ने 60 प्रतिशत और उससे अधिक का ऋण-जमा अनुपात प्राप्त किया, उनमें से 17 जिले आन्ध्र प्रदेश में, 13—13 जिले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 12—12 जिले बिहार और कर्नाटक में, 10 जिले राजस्थान में और 9 और 8 जिले क्रमशः तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में स्थित थे।

1. गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को निर्दिष्ट समय के भीतर लक्ष्य की पूर्ति करनी होगी

सारणी 2.8—ऋण जमा अनुपात के आकार पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी बैंक कार्यालयों में जिलों का वितरण

(जून 1978 के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपयों में)

अनुपात की मात्रा (ऋण-जमा अनुपात)	ग्रामीण			अर्ध-शहरी		
	जिलों की संख्या	जमाराशियां@	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमाराशियां@	अग्रिम
	1	2	3	4	5	6
20 प्रतिशत तक	72	4.45(6)	54	40	5,82(15)	92
20 प्रतिशत—30 प्रतिशत	53	4,91(9)	1,20	57	8,15(15)	1,95
30 प्रतिशत—40 प्रतिशत	49	3,03(6)	1,09	55	10,86(20)	3,73
40 प्रतिशत—50 प्रतिशत	29	1,37(5)	62	46	7,03(15)	3,24
50 प्रतिशत—60 प्रतिशत	37	2,69(7)	1,47	35	5,29(15)	2,80
60 प्रतिशत और उससे अधिक	148	7,34(5)	7,56	113	14,67(13)	11,93
	38.1£			32.7£		
जोड़	388	23,79	12,48	346	51,82	24,57

@कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रत्येक आकार वर्ग के अन्तर्गत प्रति जिला जमाराशियों के द्योतक हैं (राशि करोड़ रुपयों में)।

£जिलों की कुल संख्या में प्रतिशत के रूप में।

(स्रोत : कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण से संबंधित विवरणी)।

पांच कार्यकारी दल

2.46 आलोच्य वर्ष के दौरान जो नीतियां निर्धारित की गयीं उनसे सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति में बैंकों के योगदान में और वृद्धि हुई।

2.47 8 अक्तूबर 1978 को बैंकों और मीयादी ऋण देने वाली संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ हुई प्रधान मंत्री की बैठक के बाद पांच कार्यकारी दलों का गठन किया गया। इनका उद्देश्य (1) विभेदक ब्याज दरों (2) लघु उद्योग (3) कृषि ऋण (4) रोजगार विकास और (5) रुग्ण औद्योगिक यूनिटों की समस्याओं का गहराई से अध्ययन कर सिफारिशें करना था। इन कार्यकारी दलों की अधिकांश सिफारिशें भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं और उन पर जो कार्रवाई की जानी है उसके बारे में बैंकों को निम्नप्रकार सूचना दी गयी :

(1) विभेदक ब्याज दरें

2.48 बैंकों को सूचित किया गया कि (1) इस योजना के अन्तर्गत उत्पादक प्रयासों के लिए समाज के कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले अग्रिमों के स्तर को कुल अग्रिमों के वर्तमाम ½ प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत किया जाए तथा (2) अब तक के 33⅓ प्रतिशत के स्थान पर ऐसे अग्रिमों का कम से कम 40 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को दिया जाए। अनुसूचित जनजातियों को अधिकाधिक निधियां उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को सलाह दी गयी कि वे जनजातीय लोगों के लाभ के लिए विशेष रूप से गठित की गयी सहकारी समितियों/बड़े आकार की बहुउद्देशीय समितियों का उपयोग माध्यम के रूप में करें।

(2) लघु उद्योगों के लिए बैंक ऋण

2.49 बैंकों को सलाह दी गयी थी कि जिन कारीगरों और ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों के यूनिटों की अपनी आवश्यकता 25,000 रुपयों से अधिक नहीं है उनके लिए वे मिश्रित मीयादी ऋणों की योजना बनाएं, जिसमें उपकरण वित्त और कार्यकारी पूंजी दोनों शामिल हों तथा जिनकी चुकौती की अवधि 7 वर्ष से 10 वर्ष तक या इससे अधिक हो। इन मिश्रित ऋणों की ब्याज दर पिछड़े क्षेत्रों में 9.5 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों में 11 प्रतिशत होगी। अत्यन्त लघु क्षेत्र में स्थित यूनिटों तथा अन्य लघु उद्योगों को तीन वर्षों से अन्यून अवधि के लिए प्रदत्त मीयादी ऋणों पर भी इन दरों को लागू किया गया। 'अत्यन्त लघु क्षेत्र' में 1 लाख रुपयों तक की कार्यकारी पूंजी के लिए स्वीकृत ऋण सीमाओं पर 12.5 प्रतिशत से अनधिक ब्याज दर लागू होगी। 25 करोड़ रुपयों से कम देयताओं वाले छोटे बैंक 13.5 प्रतिशत से अनधिक ब्याज दर लगा सकते हैं।

(3) कृषि ऋण

2.50 बैंकों को सलाह दी गयी कि वे राज्य सरकार द्वारा चुने गये 2,000 खंडों में तथा योजना की शेष अवधि के दौरान प्रति वर्ष लिये जाने वाले 300 अतिरिक्त खंडों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में कारगर ढंग से सहयोग दें और यह सुनिश्चित करें कि 1982-83 तक उनके कुल कृषि अग्रिमों का कम से कम 50 प्रतिशत छोटे और सीमांत कृषकों को मिले। नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना में इन खंडों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) रोजगार बढ़ाने में बैंकों की भूमिका

2.51 बैंकों को सलाह दी गयी कि उन्हें प्रति माह प्रति शाखा कम से कम दो अतिरिक्त उधारकर्ताओं को समग्र वार्षिक आधार पर ऋण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि जिन खंडों के लिए विकास योजनाएं तैयार हैं उनमें निजी व्यवसायों की योजनाओं के कार्यान्वयन पर अपना ध्यान केन्द्रित करें और साथ-साथ दूसरे खंडों में अपनी योजनाएं धीरे-धीरे लागू करने का लक्ष्य निर्धारित करें। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निजी व्यवसाय की विशेष योजनाएं बनायी जानी चाहिए।

सारणी 2.9—ग्रामीण केन्द्रों में बैंक कार्यालयों से संबंधित ऋण—जमा

(जून 1978 के

अनुपात की मात्रा

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	20 प्रतिशत तक			20 प्रतिशत—30 प्रतिशत			30 प्रतिशत—40 प्रतिशत		
	जिला की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम	जिला की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I उत्तरी क्षेत्र	**19**	**218,54**	**25,94**	**11**	**93,91**	**21,56**	**5**	**35,61**	**12,79**
हरियाणा	—	—	—	—	—	—	2	18,20	6,66
हिमाचल प्रदेश	1	34,36	4,04	4	16,88	3,86	1	7 02	2,72
जम्मू और काश्मीर	7	20,87	2,53	2	11,12	2,49	—	—	—
पंजाब	1	161,05	19,02	2	63,15	14,51	1	9 15	3,00
राजस्थान	1	1,95	29	3	2,76	70	1	1,24	41
चंडीगढ़	1	31	6	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II पूर्वोत्तर क्षेत्र	**19**	**15,58**	**1,48**	**5**	**26,71**	**6,47**	**1**	**2,61**	**87**
असम	2	5,60	80	4	26,04	6,31	1	2,61	87
मणिपुर	2	29	—	—	—	—	—	—	—
मेघालय	3	2,64	40	—	—	—	—	—	—
नागालैंड	7	2,55	9	—	—	—	—	—	—
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	4	4,35	17	1	67	16	—	—	—
मिजोरम	1	15	2	—	—	—	—	—	—
सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. पूर्वी क्षेत्र	**9**	**69,21**	**8,61**	**11**	**70,70**	**16,60**	**7**	**35,65**	**12,76**
बिहार	5	31,49	3,52	9	28,00	7,22	5	12,04	4,35
उड़ीसा	—	—	—	—	—	—	1	1,64	53
पश्चिम बंगाल	3	37,23	5,03	2	42,70	9,38	1	21,97	7,88
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	49	6	—	—	—	—	—	—
IV. मध्यवर्ती क्षेत्र	**15**	**66,32**	**9,78**	**15**	**100,00**	**25,72**	**20**	**51,84**	**17,91**
मध्य प्रदेश	5	12,32	1,67	1	1,98	45	12	20,44	7,05
उत्तर प्रदेश	10	54,00	8,11	14	98,02	25,27	8	31,40	10,86
V. पश्चिमी क्षेत्र	**8**	**74,19**	**8,25**	**10**	**178,26**	**43,22**	**8**	**74,73**	**27,58**
गुजरात	5	48,74	4,42	6	98,32	21,64	4	43,29	16,10
महाराष्ट्र	2	20,70	3,68	3	15,96	3,37	4	31,44	11,48
दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
गोवा, दमन और दीव	1	4,75	15	1	63,98	17,21	—	—	—
VI. दक्षिणी क्षेत्र	**2**	**85**	**5**	**1**	**21,47**	**6,17**	**8**	**102,50**	**37,37**
आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—	1	2,69	1 08
कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	1	23,29	7,82
केरल	—	—	—	1	21,47	6,17	4	75,18	28,03
तमिलनाडु	1	9	—	—	—	—	—	—	—
लक्षद्वीप	1	76	5	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	2	1,34	47
अखिल भारतीय	**72**	**444,69**	**54,11**	**53**	**491,05**	**119,74**	**49**	**302,94**	**109,28**

(स्रोत : कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण से संबंधित विवरणी)

अनुपातों के आधार पर जिलों का राज्यवार वितरण

अंतिम शुक्रवार को)

(राशि लाख रुपया में)

(ऋण-जमा-अनुपात)

40 प्रतिशत-50 प्रतिशत			50 प्रतिशत—60 प्रतिशत			60 प्रतिशत और अधिक			जोड़		
जिलों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	**44,03**	**20,02**	**6**	**16,89**	**9,32**	**25**	**110,33**	**103,56**	**73**	**519,31**	**193,19**
2	8,66	3,65	3	10,17	5,82	4	28,66	21,49	11	65,69	37,62
—	—	—	—	—	—	2	7,14	5,91	12	65,40	16,53
1	2,97	1,40	—	—	—	—	—	—	10	34,96	6,24
2	25,22	11,88	—	—	—	2	18,06	12,07	12	276,63	60,48
2	7,18	3,00	3	6,72	3,50	16	54,51	55,11	26	74,36	63,13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	31	6
—	—	—	—	—	—	1	1,96	8,95	1	1,96	8,95
3	**69**	**29**	**2**	**1,45**	**74**	**6**	**11,24**	**7,40**	**36**	**58,26**	**17,25**
1	23	10	13	—	—	2	7,50	4,88	10	41,98	12,96
1	31	13	2	1,45	74	1	1	1	6	2,06	88
1	13	6	—	—	—	—	—	—	4	2,77	46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2,55	9
—	—	—	—	—	—	3	3,73	2,51	3	3,73	2,51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5,02	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	**38,52**	**18,07**	**7**	**18,09**	**10,00**	**18**	**62,09**	**87,09**	**61**	**294,26**	**153,13**
4	8,92	3 75	4	12,69	7,14	4	18,07	51,92	31	111,21	77,90
1	3,12	1,36	2	5,09	2,70	9	26,70	21,98	13	36,55	26,57
4	26,48	12,96	—	—	—	5	17,32	13,19	15	145,70	48,44
—	—	—	1	31	16	—	—	—	2	80	22
5	**19,06**	**8,59**	**9**	**30,94**	**16,42**	**37**	**155,26**	**141,55**	**101**	**423,42**	**219,97**
2	5,06	2,34	6	14,24	7,63	19	31,35	33,45	45	85,42	52,59
3	13,97	6,25	3	16,70	8,79	18	123,91	108,10	56	338,00	167,38
2	**5,16**	**2,43**	**5**	**60,78**	**32,42**	**14**	**69,12**	**75,76**	**47**	**462,24**	**189,66**
—	—	—	2	41,02	21,35	2	15,16	10,40	19	246,53	73,91
2	5,16	2,43	3	19,76	11,07	11	53,17	64,70	25	146,19	97,73
—	—	—	—	—	—	1	79	66	1	79	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	68,73	17,36
3	**29,28**	**12,93**	**8**	**140,80**	**77,59**	**48**	**326,47**	**340,20**	**70**	**621,37**	**4,74,33**
1	13,01	5,90	—	—	—	19	123,94	126,35	21	139,64	133,30
1	11,70	4,79	4	86,32	47,38	13	68,36	85,90	19	189,67	145,89
1	4,57	2,26	1	14,62	8,01	4	47,10	34,41	11	162,94	78,88
—	—	—	3	39,86	22,20	11	84,64	90,56	15	124,59	112,76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	76	5
—	—	—	—	—	—	1	2,43	2,98	3	3,77	3,45
29	**136,72**	**62,35**	**37**	**268,95**	**146,49**	**148**	**734,51**	**755,56**	**388**	**2378,86**	**1247,53**

तालिका 2.10—ग्रामीण शहरी केन्द्रों के बैंक कार्यालयों से संबंधित ऋण-जमा—

(जून 1978 के

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	अनुपात की मात्रा								
	20 प्रतिशत तक			20 प्रतिशत 30 प्रतिशत			30 प्रतिशत 40 प्रतिशत		
	जिलों की संख्या	जमाराशियां	ऋण	जिलों की संख्या	जमाराशियां	ऋण	जिलों की संख्या	जमाराशियां	ऋण
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I उत्तरी क्षेत्र	**8**	**136,14**	**1816**	**12**	**157,83**	**39,17**	**7**	**121,24**	**42,22**
हरियाणा	—	—	—	—	—	—	1	21,12	8,39
हिमाचल प्रदेश	1	4,42	51	4	43,43	10,34	—	—	—
जम्मू और कश्मीर	1	1,66	8	1	4,64	1,34	—	—	—
पंजाब	3	125,54	16,80	3	85,24	21,28	2	80,95	27,11
राजस्थान	2	4,46	77	4	24,52	6,21	4	19,17	6,72
चंडीगढ़	1	6	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II पूर्वोत्तर क्षेत्र	**7**	**43,02**	**5,99**	**5**	**42,56**	**11,12**	**5**	**40,24**	**13,87**
असम	1	1,04	8	5	42,56	11,12	1	17,15	5,49
मणिपुर	1	14	1	—	—	—	—	—	—
मेघालय	2	33,06	5,26	—	—	—	—	—	—
नागालैंड	1	1,44	15	—	—	—	1	7,57	2,98
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	3	15,52	5,40
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मिजोरम	1	3,38	24	—	—	—	—	—	—
सिक्किम	1	3,96	25	—	—	—	—	—	—
III पूर्वी क्षेत्र	**7**	**162,42**	**28,59**	**14**	**418,90**	**95,43**	**12**	**142,44**	**46,04**
बिहार	1	3,31	65	6	281,42	61,33	4	40,71	13,00
उड़ीसा	1	1,01	8	2	9,03	2,24	3	8,98	3,34
पश्चिम बंगाल	4	153,61	26,97	6	128,45	31,86	5	92,75	29 70
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	4,49	89	—	—	—	—	—	—
IV मध्यवर्ती क्षेत्र	**10**	**55,76**	**9,59**	**22**	**133,60**	**33,87**	**12**	**128,27**	**46,60**
मध्य प्रदेश	1	2,31	27	9	26,14	6,46	4	23,84	8,38
उत्तर प्रदेश	9	53,45	9,32	13	107,46	27,41	8	104,43	3,822
V पश्चिमी क्षेत्र	**6**	**127,16**	**19,14**	**4**	**62,47**	**15,87**	**12**	**420,82**	**1,44,12**
गुजरात	5	124,38	18,88	3	46,97	11,55	5	285,04	98,13
महाराष्ट्र	—	—	—	1	15,50	4,32	7	135,78	45,99
दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
गोवा दमण और दीव	1	2,78	26	—	—	—	—	—	—
VI दक्षिणी क्षेत्र	**2**	**57,21**	**9,97**	—	—	—	**7**	**232,38**	**79,91**
आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	2	31,70	10,69
केरल	1	57,07	9,95	—	—	—	3	154,20	54,01
तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	1	41,90	13,64
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	1	14	2	—	—	—	1	4,58	1,57
अखिल भारतीय	**40**	**581,71**	**91,44**	**57**	**815,36**	**195,46**	**55**	**1085,39**	**372,76**

(स्रोत: कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण से संबंधित जिलवारी)

अनुपातों के आधार पर जिलों का राज्यवार वितरण

अंतिम शुक्रवार को)

(राशि लाख रुपयों में)

(ऋण-जमा-अनुपात)

40 प्रतिशत 50 प्रतिशत			50 प्रतिशत 60 प्रतिशत			60 प्रतिशत और उससे अधिक			जोड़		
जिलों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम	जिलो की संख्या	जमा राशियां	अग्रिम
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	**65,58**	**30,69**	**10**	**169,68**	**83,89**	**18**	**209,33**	**187,32**	**61**	**859,70**	**407,45**
1	41,07	20,07	4	74,85	40,76	5	73,16	61,24	11	210,20	130,46
1	4,07	1,78	--	--	--	--	--	--	6	51,92	12,63
1	6,40	2,65	1	4,03	2,40	1	2,43	2,67	5	19,16	9,14
--	--	--	2	79 66	40,66	2	62,65	56,32	12	434,04	162,17
3	14,04	6,19	3	11,14	6,07	10	70,99	67,09	26	144,32	93,05
--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	6	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	**3,24**	**1,54**	--	--	--	**1**	**43,51**	**26,98**	**19**	**172,57**	**59,50**
1	3,24	1,54	--	--	--	1	43,51	26,98	9	107,50	45,21
--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	14	1
--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	33,06	5,26
--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	9,01	3,13
--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	15,52	5,40
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	3,38	24
--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	3,96	25
7	**52,69**	**24,56**	**3**	**28,36**	**15,23**	**16**	**105,44**	**100,76**	**59**	**910,25**	**310,61**
4	31,09	14,36	2	22,94	12,46	12	73,64	70,56	29	453,11	172,36
2	21,21	5,67	1	5,42	2,77	4	31,80	30,20	13	68,45	44,30
1	9,39	4,53	--	--	--	--	--	--	16	384,20	93,06
--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	4,49	89
15	**157,41**	**69,89**	**10**	**57,26**	**30,69**	**26**	**232,66**	**207,05**	**95**	**764,26**	**397,69**
8	44,11	19,61	9	48,99	26,45	13	60,30	52,34	44	205,69	113,51
7	113,30	50,28	1	8,27	4,24	13	172,36	154,71	51	559,27	284,18
6	**188,26**	**90,37**	**6**	**137,69**	**72,76**	**11**	**172,60**	**124,42**	**45**	**1109,00**	**466,68**
--	--	--	2	71,58	36,72	3	37,09	29,37	18	565,06	194,65
5	56,46	25,60	4	66,11	36,04	8	135,51	95,05	25	409,36	207,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	131,80	64,77	--	--	--	--	--	--	2	134,58	65,03
11	**235,96**	**107,16**	**6**	**135,86**	**71,59**	**41**	**703,63**	**546,63**	**67**	**1365,04**	**815,21**
3	55,23	23,62	1	18,62	10,00	17	238,63	179,37	21	312,48	212,99
2	52,62	24,68	3	41,19	22,89	12	135,06	116,93	19	260,57	175,19
3	87,82	40,07	1	49,10	24,71	3	72,71	53,21	21	420,90	181,95
3	40,29	18,79	1	26,95	13,99	9	257,23	197,14	14	366,37	243,56
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	4,72	1,59
46	**703,14**	**324,21**	**35**	**528,85**	**280,16**	**113**	**1467,07**	**1193,18**	**346**	**5181,52**	**2457,21**

(5) रुग्ण औद्योगिक यूनिटों की समस्याएं

2.52 रुग्ण औद्योगिक यूनिटों की समस्याओं को हल करने के लिए बैंकों से यह कहा गया कि वे अन्य बातों के साथ-साथ (1) रुग्ण यूनिटों की पुनर्व्यवस्था की संभावनाओं का पता लगाएं तथा यदि वे अपेक्षित सहायता प्रदान करने में असमर्थ हों तो ऐसे मामले को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की विचारार्थ भेजें । उक्त बैंक उस यूनिट को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक सभी उपायों पर विचार करेगा तथा, (2) वे यह सुनिश्चित करें कि रुग्ण यूनिटों की कठिनाइयों को दंडस्वरूप ब्याज लगाकर बढ़ाया नहीं जाता ।

निजी क्षेत्र के बैंक

2.53 रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों को सूचित कर उनसे यह अपेक्षा की है कि वे प्राथमिकता प्राप्त और अपेक्षित क्षेत्रों को क्रमशः अधिक ऋण प्रदान करें जिससे कि 31 मार्च, 1980 तक कुल अग्रिमों का न्यूनतम 33-1/3 प्रतिशत अग्रिम उन्हें प्राप्त हो । ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं में अलग-अलग रूप से न्यूनतम 60 प्रतिशत के ऋण-जमा अनुपात के संबन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू होने वाला लक्ष्य निजी क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू किया गया। निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए लागू किये गये अन्य सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य इस प्रकार हैं :

1. कुल अग्रिम का एक प्रतिशत विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिया जाए और उसका 40 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध हो ।
2. प्रति शाखा प्रति माह कम से कम दो अतिरिक्त उधारकर्ताओं को समग्र वार्षिक आधार पर ऋण प्रदान किया जाए ।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर पहले से लागू होने वाले अनुपात में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पद आरक्षित किये जाएं ।

अग्रणी बैंक योजना

2.54 निरन्तर अग्रणी बैंक योजना की प्रगति की समीक्षा करने तथा उक्त योजना को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए नीति विषयक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक में उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है । इस वर्ष के दौरान उक्त समिति की दो बैठकें हुईं । समिति ने अपनी बैठक में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया वे इस प्रकार हैं :

अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार

2.55 अग्रणी बैंक योजना के अन्तर्गत गोवा, दमन और दीव, तथा दिल्ली और चंडीगढ़ के संघ शासित क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया गया । दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी भारतीय स्टेट बैंक को तथा चंडीगढ़ की जिम्मेदारी पंजाब नेशनल बैंक को सौंपी गयी । देश में स्थित समस्त 390 जिलों (इनमें दिल्ली और चंडीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के 24-परगनों के विभाजित जिले और मणिपुर राज्य में निर्मित छ जिले, जिन्हें पहले एक ही जिले के रूप में समझा गया था, शामिल हैं) के लिए ऋण संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया है ।

जिला ऋण योजनाएं

2.56 यह महसूस किया गया कि ऋण योजनाएं तैयार करने के लिए एक समान पद्धति अमल में लायी जा सकती है और तदनुसार मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये गये । यह निश्चय किया गया कि जो ऋण योजनाएं इस समय प्रचलित हैं उन्हें दिसम्बर 1979 में समाप्त कर दिया जाए । अग्रणी बैंकों से जनवरी 1980 से दिसम्बर 1982 तक की अवधि के लिए नयी ऋण योजनाएं बनाने के लिए कहा गया, ताकि नयी ऋण योजनाओं की अवधि पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के बराबर हो । इसके अतिरिक्त अग्रणी बैंक द्वारा हर वर्ष दिसम्बर में वार्षिक कार्रवाई योजनाएं तैयार की जानी चाहिएं और उनमें कुल ऋण परिव्यय को क्षेत्रवार, योजनावार और संस्थाओं के समूहवार आंकड़े दिये जाने चाहिएं। अग्रणी बैंकों को यह सलाह दी गयी कि वे अपने अग्रणी जिलों में ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन का आवधिक मूल्यांकन करने के लिए अपनी प्रणाली का विकास करें । उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा इन विषयों पर लिये गये निर्णयों के अनुसरण में सभी अग्रणी बैंकों और इतर बैंकों को उपयुक्त अनुदेश/मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये ।

2.57 ग्रामीण क्षेत्रों में बहुएजेंसी पद्धति के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक में "ग्रामीण आयोजना और साख कक्ष" नामक एक कक्ष स्थापित किया गया है । जनवरी 1979 से इस कक्ष ने अपना कार्य प्रारम्भ किया तथा उसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिला और खंड स्तरों की ऋण योजनाओं तथा कृषि ऋण गहन विकास योजना से संबन्धित वे सभी कार्य सौंप दिये गये हैं जो पहले बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग तथा कृषि ऋण विभाग द्वारा किये जाते थे ।

2.58 रिजर्व बैंक के ग्रामीण आयोजना और साख कक्ष ने 1980-82 की अवधि के लिए नयी जिला ऋण योजनाएं तथा 1980 के लिए वार्षिक कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये ताकि सभी अग्रणी बैंक एक समान पद्धति से योजनाएं तैयार करें तथा उन्हें जिला विकास योजनाओं के अनुरूप बनाकर जनवरी 1980 में लागू करें । ये मार्गदर्शी सिद्धांत सभी अग्रणी बैंकों एवं राज्य सरकारों को भेजे गये । अग्रणी बैंकों को सलाह दी गयी कि यदि वर्तमान योजनाएं यथार्थ न मानी गयीं तो 1979 के लिए भी वार्षिक कार्रवाई योजनाएं तैयार करें ।

जिला ऋण योजनाओं का कार्यान्वयन

2.59 जिला परामर्श समिति की बैठकों में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति से ऋण योजनाओं पर कारगर ढंग से तथा तेजी से अमल करने का रास्ता साफ हो जाता है और निर्णय करने में भी सहायता मिलती है, इसलिए अग्रणी बैंकों और इतर बैंकों को सूचित किया गया कि वे जिला परामर्श समिति की बैठकों में, विशेषकर उन बैठकों में जहां ऋण योजनाओं की छमाही और वार्षिक समीक्षा की जाती है तथा वार्षिक कार्रवाई योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाता है, भाग लेने के लिए, जहां तक व्यवहार्य हो, अपने क्षेत्रीय/प्रभागीय/विकास प्रबन्धकों को भेजें ।

2.60 सभी अग्रणी बैंकों का ध्यान भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी 'मार्जिन धन योजना' की ओर दिलाया गया, जिसका उद्देश्य लघु यूनिटों को मार्जिन धन प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था । ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के उद्देश्य से उन्हें बताया गया कि जिला परामर्श समितियों, विकास एजेंसियों और वाणिज्य बैंकों के बीच कारगर समन्वय सुनिश्चित करें तथा समितियों की आवधिक बैठकों में योजना के पहलुओं पर निश्चित रूप से बातचीत हो । बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे संभाव्य उद्यमियों के लिए उपयुक्त स्तरों पर मार्गदर्शन देने के लिए तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित विकास कर्मचारियों की व्यवस्था करें ।

2.61 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सलाह दी गयी कि वे लघु उद्योग, रोजगार विकास योजना, विभेदक ब्याज दर योजना और कृषि वित्त संबंधी कार्यकारी दलों की रिपोर्टों में दी गयी सिफारिशों को कार्यान्वित करें । चूंकि सिफारिशों का मुख्य उद्देश्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा समाज के कमजोर वर्गों को आसानी से तथा उचित ढंग से ऋण उपलब्ध कराना है, इसलिए बैंकों को सूचित किया गया कि जिला परामर्श समिति समान समस्याओं पर विचार करने (मूल वस्तुओं की पूर्ति, बिजली, विपणन व्यवस्थाएं आदि सहित) तथा अनुदेशों के तेजी से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निमित्त उन समस्याओं के समाधान के लिए हल ढूंढ निकालने का उपयुक्त मंच होगा ।

अग्रणी जिलों में ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन का नमूना सर्वेक्षण

2.62 अग्रणी बैंकों तथा अन्य सहभागी संस्थाओं/एजेंसियों द्वारा की गयी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए रिजर्व बैंक ने उन जिलों में मोटे तौर पर नमूना सर्वेक्षण किया जहां ऋण योजनाएं दो वर्षों से अधिक अवधि तक चली थीं। नमूना सर्वेक्षण के लिए विभिन्न अग्रणी बैंकों वाले तीन राज्यों अर्थात् उ० प्र० (फर्रुखाबाद) म० प्र० (सिवनी) और राजस्थान (जैसलमेर) में से एक-एक जिला चुना गया। सर्वेक्षण के लिए क्षेत्रीय जांच की गयी तथा सम्बंधित रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं।

जिला उद्योग केन्द्र

2.63 लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योग के संवर्धन को सर्वाधिक महत्व देने के लिए भारत सरकार ने जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना करने का निश्चय किया। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों तथा निजी क्षेत्र के दो बैंकों, जिन्हें अग्रणी का उत्तरदायित्व सौंपा गया, से कहा कि जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने के लिए चुने गये जिलों में अपने अधिकारियों को प्रबंधक (ऋण) के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त करें।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2.64 इस वर्ष के दौरान और आठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये। इसके साथ जून 1979 के अंत में 17 राज्यों में उनकी कुल संख्या 56 हो गयी। नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से गुजरात में दो, बिहार में तीन और कर्नाटक, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में एक-एक बैंक खोले गये। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल 560 शाखाएं खोली गयीं तथा यह संख्या जून 1978 के अंत में, 1,405 से बढ़कर जून 1979 के अंत में 1,965 हो गयी (सारणी 2.11)।

सारणी 2.11—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के राज्यवार कार्यालय

(जून 1979 के अंत तक)

राज्य	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	शाखाओं की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	3	238
2. असम	1	34
3. बिहार	10	266
4. गुजरात	2	—
5. हरियाणा	2	64
6. हिमाचल प्रदेश	1	21
7. जम्मू और काश्मीर	1	43
8. कर्नाटक	4	156
9. केरल	2	118
10. मध्य प्रदेश	5	149
11. महाराष्ट्र	1	48
12. उड़ीसा	4	155
13. राजस्थान	4	166
14. तमिलनाडु	1	55
15. त्रिपुरा	1	24
16. उत्तर प्रदेश	10	326
17. पश्चिम बंगाल	4	102
जोड़	56	1,965

(स्रोत: ग्रामीण आयोजना और साख कक्ष और बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग भारतीय रिजर्व बैंक)

2.65 51 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार मार्च 1979 के अंतिम शुक्रवार को उनकी कुल जमाराशियां और अग्रिम राशियां क्रमशः 80 करोड़ रुपये तथा 143 करोड़ रुपये थीं। छोटे/सीमान्त किसानों, भूमिहीन श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों को दिये गये अग्रिमों की राशि 134 करोड़ रुपये थी।

2.66 1 अक्तूबर, 1976 को रिजर्व बैंक द्वारा प्रारम्भ की गयी पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त करते रहे। 31 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए मंजूर की गयी ऋण सीमाएं जून 1979 के अंत में 34 करोड़ रुपये थीं। इन सीमाओं से निकाली गयी तथा मार्च 1979 के अंतिम शुक्रवार को बकाया रहने वाली राशि 28 करोड़ रुपये थी।

2.67 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में नकदी आरक्षित निधि आदि रखने के संबन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी गयी रियायतों और छूट का उल्लेख किया गया था। अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर लागू 6 प्रतिशत के मुकाबले उनकी कुल मांग और मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत का नकदी आरक्षित निधि अनुपात जारी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उस निदेश से मिली हुई छूट जारी है जिसके अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को किसी आधारभूत तारीख को विद्यमान वृद्धिशील मांग और मीयादी देयताओं का 10 प्रतिशत जमा रखना होता है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रखी जाने वाली चल आस्तियों का प्रतिशत अन्य बैंकों पर लागू 34 प्रतिशत के मुकाबले पहले की तरह 25 प्रतिशत है।

2.68 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गठित समिति (दांतवाला समिति) की सिफारिश के अनुसरण में रिजर्व बैंक में एक संचालन समिति गठित की गयी और उसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गये। (i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के लिए क्षेत्रों का पता लगाना तथा प्रबंध व्यवस्था में स्थानीय सहभागिता, बोर्डों का गठन, अध्यक्ष की नियुक्ति और कर्मचारियों की भर्ती और उनका प्रशिक्षण आदि संगठन संबंधी विषयों को देखना। (ii) ऋण प्रदान करने की नीतियां आदि परिचालन संबंधी विषय। (iii) चल निधि के मामलों में वर्तमान ढील और छूट की आवधिक समीक्षा करना। (iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति पर निगरानी रखना तथा उसकी समीक्षा करना। (v) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना। (vi) दांतवाला समिति की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों से संबंधित सुझाव देना। इस वर्ष के दौरान संचालन समिति की तीन बैठकें हुईं।

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम/अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के कार्यक्रमों में वाणिज्य बैंकों की सहभागिता

2.69 आलोच्य वर्ष के दौरान कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की सामान्य योजनाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा उक्त निगम के माध्यम से सहायता प्राप्त परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में वाणिज्य बैंकों ने और प्रगति की है। 30 जून 1979 तक निगम ने वाणिज्य बैंकों के लिए 6,147 योजनाएं स्वीकृत कीं, इनके लिए कुल 1,206 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें निगम द्वारा वायदा की गयी सहायता राशि 974 करोड़ रुपये थी। निगम द्वारा वितरित राशियां जून 1978 के अंत में 341 करोड़ रुपयों के मुकाबले जून 1979 के अंत में 491 करोड़ रुपये थीं। योजनाओं में लघु सिंचाई एवं मशीनीकरण की योजनाओं का अंश पहले की तरह अधिक रहा तथा 3,375 योजनाओं के लिए 751 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।

कृषक सेवा समितियां

2.70 वाणिज्य बैंकों, मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा कृषक सेवा समितियों का गठन किया जाता है तथा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन समितियों के कार्य बहुउद्देश्यीय हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे एक सम्पर्क स्थान पर पूर्णतः कृषि ऋण तथा सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करें। जून, 1978 के अन्त तक सार्वजनिक क्षेत्र के 18 तथा निजी क्षेत्र के 2 बैंकों द्वारा 13 राज्यों और दिल्ली के संघ शासित प्रदेश में 213 कृषक सेवा समितियां स्थापित की गयीं।

ग्राम अभिस्वीकरण योजना

2.71 बैंक क्षेत्रीय पद्धति का पालन करते रहे तथा बैंकों ने "ग्राम अभिस्वीकरण योजना" के अन्तर्गत ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के सभी पहलुओं के क्रमशः समेकित विकास के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गांवों को अपनाया। दिसम्बर 1978 के अन्त में बैंकों ने 70,270 गांवों को अपनाया तथा 21 लाख किसानों को 449 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान की, जबकि दिसम्बर, 1977 के अन्त में क्रमशः 55,205 गांवों को अपनाया गया था तथा 15 लाख किसानों को 297 करोड़ रुपयों की सहायता दी गयी थी।

कृषि अग्रिमों की वसूली

2.72 सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये जाने वाले प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों को चुकाने की जो मांग की जाती है, उसमें वसूली गयी राशि का अखिल भारतीय प्रतिशत जून, 1973 से क्रमशः बढ़ता रहा, किन्तु उसमें जून, 1977 के अन्त में गिरावट आयी और वह घटकर 48.8 हो गया था। लेकिन उसमें पुनः सुधार की प्रवृत्ति पायी गयी और वह जून, 1978 के अन्त में थोड़ा-सा बढ़कर 50.2 हो गया। अखिल भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की वसूली की स्थिति जून, 1977 के अन्त में विद्यमान 50.0 प्रतिशत से बढ़कर जून, 1978 के अन्त में 51.2 प्रतिशत हो गयी। 1977-78 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वसूली में जो सुधार आया वह पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में पाया गया।

ऋण प्राधिकरण योजना

2.73 1965 से अमल में रहने वाली ऋण प्राधिकरण योजना मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित करने की बैंक की नीति की पृष्ठभूमि में ऋण विनियमन के सफल साधन के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रही है। बैंक ऋण सम्बन्धी अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने के उद्देश्य से नियुक्त किये गये अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार बैंक ने जो कदम उठाये हैं उनसे ऋणकर्ताओं की उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताओं के आधार पर ऋण वितरण करने का औचित्य सिद्ध हुआ है और इनसे ऋण सम्बन्धी अनुवर्ती कार्रवाई और पर्यवेक्षण में भी बैंकों को सहायता मिली है। ऋण का अध्ययन करने के क्षेत्र में भी बैंकों की प्रगति काफी धीमी रही है।

ऋण प्राधिकरण योजना की कार्यपद्धति

2.74 जुलाई, 1978 से जून, 1979 तक की अवधि के दौरान इस योजना के अधीन आने वाली पार्टियों की संख्या 979 से बढ़कर 1,059 हो गयी। इसमें जून, 1979 के अन्त में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की संख्या 187 थी, जबकि उक्त संख्या जून, 1978 के अन्त में 178 थी। इस योजना के अन्तर्गत आने वाली पार्टियों के नाम विद्यमान कुल ऋण राशि जून, 1979 के अन्त में 11,968 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार उनमें पिछले वर्ष की उसी अवधि में हुई 802 करोड़ रुपयों की वृद्धि के मुकाबले इस वर्ष 1,327 करोड़ रुपयों की काफी अधिक वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की ऋण सीमाओं में 670 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष उनमें 268 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी किन्तु बढ़ते हुए ऋण में निजी क्षेत्र का अंश 1977-78 में स्थित 534 करोड़ रुपयों की तुलना में इस वर्ष 657 करोड़ रुपये था।

2.75 इस वर्ष कुल चालू ऋण सीमाओं के प्रयोजनवार वितरण, के स्वरूप से पिछले वर्ष की उपलब्धि का पता चलता है। इस प्रकार जून, 1979 के अन्त में कुल ऋण सीमाओं का 88.2 प्रतिशत कार्यकारी पूंजी (बैंकिंग ऋण और बिलों सहित), 8.7 प्रतिशत मीयादी वित्त और 3.1 प्रतिशत आस्थगित अदायगी के आधार पर मशीनों की बिक्री के प्रयोजनों के लिए दिया गया था। जून, 1979 के अन्त में 11,968 करोड़ रुपयों की कुल ऋण सीमाएं विद्यमान थीं, उनमें व्यापार क्षेत्र का अंश लगभग 4,501 करोड़ रुपये (37.6 प्रतिशत) था। व्यापार क्षेत्र के अन्तर्गत केवल खाद्यान्नों की वसूली के लिए प्रदत्त ऋणों की राशि 3,151 करोड़ रुपये अथवा कुल ऋण का 26.3 प्रतिशत थी। उद्योग क्षेत्र का अंश 6,640 करोड़ रुपये (55.5 प्रतिशत) था। इसमें से इंजीनियरी वस्तुओं और सूती वस्त्रों के उद्योगों का अंश क्रमशः 1,881 करोड़ रुपये (15.7 प्रतिशत) और 834 करोड़ रुपये (7.0 प्रतिशत) था। सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में 6,447 करोड़ रुपयों की जो ऋण सीमाएं विद्यमान थीं, उनमें व्यापार क्षेत्र का अंश 63.2 प्रतिशत था (जिसमें खाद्यान्नों की वसूली का अंश 48.9 प्रतिशत था)। इंजीनियरी क्षेत्र, बिजली प्रतिष्ठानों तथा मूल धातु और धातु से बनी वस्तुओं (लोहा और इस्पात) का अंश क्रमशः 9.1 प्रतिशत, 5.0 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत था।

योजना में परिवर्तन

2.76 रिजर्व बैंक उक्त योजना की कार्य पद्धति को लचीला बनाने के लिए समय-समय पर उसकी कार्य-प्रणाली का अध्ययन करता रहा है। पिछली रिपोर्ट के बाद योजना की कार्य-प्रणाली में कुछ रियायतें दी गयी हैं और कुछ परिवर्तन भी किये गये हैं। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि क्रियाविधियों को सरल बनाया जाए और बैंकों को अधिक अधिकार दिये जाएं जिससे कि वे ऋण के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय ले सकें। इन परिवर्तनों और वर्तमान अनुदेशों की व्याख्या को संक्षेप में आगे दिया जाता है।

क. रियायतें]

अधिकतम सीमा

2.77 बैंकों द्वारा पूंजीगत आस्तियों के अभिग्रहण के लिए मंजूर किये गये मीयादी ऋणों को ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत ऋण प्रस्तावों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा का हिसाब लगाने के प्रयोजन के लिए शामिल नहीं किया गया है[1] इसके परिणामस्वरूप, कतिपय यूनिटों को योजना के कार्यक्षेत्र के बाहर जाने की अनुमति दी गयी है।

ख. संशोधन

साख पत्र, आस्थगित अदायगी की गारंटियां और स्वीकरण सीमाएं

2.78 (i) पूंजीगत आस्तियों के अभिग्रहण तथा अन्य प्रयोजनों के लिए खोले जाने वाले साख-पत्रों तथा (ii) बैंकों द्वारा ऋणकर्ताओं को पूंजीगत उपकरणों के क्रय के लिए मंजूर की जाने वाली आस्थगित अदायगी सम्बन्धी गारन्टियों तथा उनसे सम्बन्धित स्वीकरण सीमाओं को कतिपय छूट देते हुए योजना के कार्यक्षेत्र के भीतर लाया गया है। परन्तु उक्त सुविधाओं को पहले की तरह अधिकतम सीमा का हिसाब लगाने के प्रयोजन के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

1. सम्प्रति अधिकतम सीमा की राशि गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के लिए क्रमशः 200 लाख रुपये और 300 लाख रुपये है।

स्पष्टीकरण :

1. **गारंटियां**

2.79 वर्तमान अनुदेशों के अन्तर्गत अग्रिम धन की जमाराशि, निष्पादन गारन्टियों आदि के स्थान पर गारन्टियां जारी करने के लिए बैंकों द्वारा मंजूर की गयी सीमाओं को पूर्व प्राधिकरण से छूट प्राप्त है। यह स्पष्ट किया गया कि यदि गारन्टी जारी कर कोई बैंक इस उद्देश्य से वित्तीय दायित्व ग्रहण करे कि उसके घटक पूंजीगत आस्तियों का अभिग्रहण कर सकें, तो उसे कतिपय निर्दिष्ट शर्तों पर रिजर्व बैंक का पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करना होगा।

2. **भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भाऔवि बैंक) की बिल पुनर्भुनाई योजना**

2.80 भाऔवि बैंक की बिल पुनर्भुनाई योजना के अन्तर्गत (तथा योजना के बाहर परन्तु निर्दिष्ट शर्तों पर) देशी बिक्रियों के सन्दर्भ में आस्थगित बिलों का वित्तपोषण करने के लिए बैंकों द्वारा मंजूर की गयी सीमाओं के लिए पूर्व प्राधिकरण अपेक्षित नहीं है। बैंक किसी वर्ष (जुलाई-जून) में 100 लाख रुपयों की निर्दिष्ट सीमा (यह सीमा सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के लिए उच्चतर है) तक किसी खरीदार की ओर से स्वीकरण सीमाएं जारी कर सकते हैं। यह निश्चय किया गया कि भाऔवि बैंक की बिल पुनर्भुनाई योजना के अन्तर्गत तथा योजना के बाहर बैंकों द्वारा मंजूर की जाने वाली स्वीकरण सीमाओं के लिए ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत पूर्व प्राधिकरण अपेक्षित नहीं होगा, बशर्ते कि ऐसी सीमाएं भाऔवि बैंक के नियमों और शर्तों के अनुरूप हों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का सुनिश्चित रूप से पालन किया जाए।

3. **पूंजीगत वस्तुओं के आयातों की सहायता के लिए रुपया वित्त की योजना**

2.81 वर्तमान अनुदेशों के अन्तर्गत पूंजीगत वस्तुओं के आयातों की सहायता के लिए रुपया वित्त की योजना के अधीन बैंकों द्वारा दिये जाने वाले रुपया ऋणों के लिए ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत उस हालत में पूर्व प्राधिकरण अपेक्षित नहीं है जब ऐसे ऋण, मशीनों की कतिपय विशिष्ट मदों के सदर्भ आयात के लिए हों और साथ ही इस प्रकार के आयात बैंक द्वारा वित्तपोषित समग्र परियोजना अथवा विस्तार/आधुनिकीकरण योजना का अंश न हों। बैंकों को यह सूचित किया गया कि उन्हें पहले से प्रदान की गयी छूटों को छोड़कर अन्य मामलों में मीयादी ऋणों के लिए पूर्व प्राधिकरण अपेक्षित होगा।

4. **कार्यकारी पूंजीगत मीयादी ऋण**

2.82 बैंकों द्वारा मंजूर किये गये कार्यकारी पूंजीगत मीयादी ऋणों को ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत अनुशासन के प्रयोजन के लिए 'कार्यकारी पूंजीगत' सीमाओं के रूप में माना जाना चाहिए। इस प्रकार ऋण प्राधिकरण योजना के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली पार्टियों के सन्दर्भ में यदि कार्यकारी पूंजीगत मीयादी ऋणों की राशि रिजर्व बैंक द्वारा पहले से प्राधिकृत वर्तमान कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं में से निकाली जाती है तो रिजर्व बैंक को पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है, भले ही कार्यकारी पूंजीगत मीयादी ऋण की राशि और/या उसकी चुकौती की अवधि कुछ भी क्यों न हो। यदि कार्यकारी पूंजीगत मीयादी ऋण के लिए वर्तमान कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं की मंजूरी/वृद्धि अपेक्षित हो तो पूर्व प्राधिकरण आवश्यक होगा। ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत आने वाली पार्टियों से इतर पार्टियों के मामले में केवल उन्हीं सन्दर्भों में बैंक को लिखने की आवश्यकता होगी, जहां किसी कार्यकारी पूंजीगत मीयादी ऋण (टण्डन अध्ययन दल द्वारा निर्धारित किये गये निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार निकाले गये) की मंजूरी से ऋणकर्ता द्वारा समस्त बैंकिंग तन्त्र से प्राप्त कुल कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं की राशि 2 करोड़ रुपये अथवा अधिक (सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के लिए 3 करोड़ रुपये) हो जाए। चयनात्मक ऋण नियंत्रण सम्बन्धी उपायों के अन्तर्गत आने वाले पण्यों पर दिये जाने वाले अग्रिमों के लिए उक्त रियायत लागू नहीं होगी।

5. **सीमाओं की सूचना देने के लिए अधिकतम सीमा**

2.83 ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत आने वाले ऋणकर्ताओं से इतर ऋणकर्ताओं को मंजूर की जाने वाली ऐसी सीमाओं की सूचना रिजर्व बैंक को देने समय, जिनसे बैंकिंग तन्त्र से उपलब्ध कुल ऋण सीमाओं की राशि निजी क्षेत्र के मामले में 1 करोड़ रुपये और अधिकतम 2 करोड़ रुपयों तक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में 3 करोड़ रुपये हो जाए, ऐसे ऋणकर्ताओं को पूंजीगत आस्तियों के अभिग्रहण के प्रयोजन के लिए मंजूर किये गये मीयादी ऋणों की कुल ऋण सीमाओं का हिसाब लगाने के निमित्त शामिल न किया जाए। दूसरे शब्दों में रिजर्व बैंक को सूचना देने के उद्देश्य से 1 करोड़ रुपयों की अधिकतम सीमा का हिसाब लगाने के लिए ऋणकर्ताओं को मंजूर की गयी केवल कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं (कार्यकारी पूंजीगत मीयादी ऋणों सहित) पर ध्यान देना चाहिए।

वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदत्त मीयादी ऋण

2.84 रिजर्व बैंक द्वारा लागू किये गये कतिपय नीतिगत उपायों के परिणामस्वरूप मीयादी ऋण प्रदान करने के संदर्भ में वाणिज्य बैंक क्रमिक रूप से अधिकाधिक योगदान दे रहे हैं। वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदत्त मीयादी ऋणों से संबंधित आंकड़े केवल जून 1977 के अंत तक ही उपलब्ध हैं। मीयादी ऋण खातों की कुल संख्या जून 1976 के अंत में 196 हजार से बढ़कर जून 1977 के अंत में 237 हजार हो गयी और इस प्रकार समस्त खातों की कुल संख्या में उसका अनुपात 30.5 प्रतिशत से बढ़कर 32.5 प्रतिशत हो गया (सारणी 2.12)। मीयादी ऋणों के संदर्भ में स्वीकृत कुल सीमाओं की राशि उसी अवधि के दौरान 1,840 करोड़ रुपयों से बढ़कर 2,337 करोड़ रुपये हो गयी अर्थात् उसमें पूर्व वर्ष में हुई 18.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 27.0 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी। बकाया मीयादी ऋणों की राशि में भी जून 1976 के अंत में स्थित, 1,516 करोड़ रुपयों से बढ़कर जून 1977 के अंत में 1,964 करोड़ रुपये हो गयी, जो पूर्व वर्ष हुई 32.1 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 29.6 प्रतिशत की वृद्धि की द्योतक थी। कुल बैंक ऋणों में जून 1977 के अंत में विद्यमान बकाया मीयादी ऋणों का अंश 16.3 प्रतिशत था, जबकि एक वर्ष पूर्व उक्त अंश 14.4 प्रतिशत था।

चीनी उद्योग को ऋण

2.85 जैसा कि चयनात्मक ऋण नियंत्रण के खंड में उल्लेख किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति लिये बिना प्रति ऋण-कर्ता 25 लाख रुपयों तक की अवधि निर्बाध ऋण सुविधा कतिपय शर्तों पर 30 नवंबर 1978 तक जारी रखी गयी। यह अभिवेदन किया गया कि बैंक ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार मंजूर किये गये 25 लाख रुपयों के निर्बाध ऋणों का उपयोग चीनी कारखानों को मौसम के बाद मरम्मत करने अथवा अन्य अत्यावश्यक प्रयोजनों के लिये किये गये व्यय की पूर्ति करने के निमित्त उपलब्ध कराने के बजाय ऋण खातों में विद्यमान अनियमितताओं में सुधार लाने के लिए कर रहे थे। रिजर्व बैंक ने दिसंबर 1978 में बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि निर्बाध ऋणों का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाता है जिसके लिये वे प्रदान किये गये हों। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे ऐसी चीनी मिलों की सहायता करें जो गन्ना उत्पादकों को देय राशियों की पूर्ति करने में असमर्थ हैं और चुने हुए आधार पर कतिपय शर्तों पर कार्यकारी पूंजीगत मीयादी ऋण प्रदान करते हुए उनके नकदी ऋण खातों में विद्यमान मार्जिन संबंधी कमी की पूर्ति करें। ऐसे ऋणों के लिए अचल आस्तियों और/अथवा राज्य सरकार/कंपनी/फर्म के निदेशकों/स्वामियों की गारंटियों द्वारा जमानत प्रदान करने की आवश्यकता थी।

2.86. 1978-79 के पेराई के मौसम में चीनी मिलों का वित्तपोषण करने के उद्देश्य से बैंकों को नवंबर 1978 में यह सूचित किया गया कि वे अलग-अलग चीनी मिलों को पिछले दो पेराई के मौसमों अर्थात् 1976-77 और 1978-79 की पूर्व प्राधिकरण के बिना मंजूर की गयी नियमित सीमाओं (इनमें नियमित सीमाओं के अतिरिक्त निकाली गयी राशि, यदि कोई हो, तथा अस्थायी आधार पर मंजूर की गयी सीमाएं शामिल नहीं है) के अंतर्गत अधिक बकाया राशि के औसत के बराबर की राशि तक परिस्थिति के अनुसार ऋण सीमाएं मंजूर कर सकते हैं । यदि बैंक किसी चीनी मिल के मामले में ऊपर उल्लिखित सीमा से अधिक ऋण सीमाएं मंजूर करना आवश्यक समझे और यदि ऋणकर्ता की वर्तमान कुल तथा प्रस्तावित अतिरिक्त सीमाओं की राशि ऋण प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत आये, तो बैंक ऐसी सीमा रिजर्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद ही मंजूर कर सकता है ।

2.87 चीनी पर से नियंत्रण हटा दिये जाने के फलस्वरूप चीनी यूनिटों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चीनी संबंधी नीति की और समीक्षा की गयी । पहले के अनुदेशों में संशोधन करते हुए फरवरी 1979 में बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे 1978-79 के पेराई मौसम के लिए पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किये बिना केवल पिछले पेराई मौसम अर्थात् (1977-78 के लिए यदि नियमित सीमाओं से अधिक कोई राशि निकाली गयी हो तो उसे और अस्थायी आधार पर प्रदत्त सीमाओं को छोड़कर) नियमित सीमाओं के अधीन बकाया अधिकतम राशि की सीमा तक अलग-अलग चीनी मिलों को योग्यता के आधार पर ऋण सीमाएं मंजूर कर सकते हैं ।

रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों का वित्तपोषण

2.88. रिजर्व बैंक का रुग्ण औद्योगिक उपक्रम कक्ष रुग्ण यूनिटों का पता लगाने और आवश्यक मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई करने में बैंकों की भूमिका का अध्ययन पूर्ववत् करता रहा । इस कक्ष ने रुग्ण यूनिटों की पुनर्व्यवस्था के संबंध में सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रयासों के बीच समन्वयन लाने का प्रयास किया । औद्योगिक पुनर्व्यवस्था में संस्थागत प्रयासों पर निगरानी रखते हुए जब कभी अलग-अलग मामलों में हस्तक्षेप करना या मार्गदर्शन देना आवश्यक हुआ, तब उक्त कक्ष ने कदम उठाये और चुने हुए रुग्ण यूनिटों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने, उनका हल निकालने और उनमें समन्वयन लाने के लिए वित्तपोषक संस्थाओं की बैठकें आयोजित की । उक्त कक्ष ने ऐसी पांच बैठकें आयोजित कीं । इसके अलावा कक्ष के प्रतिनिधियों ने अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा संबंधित बैंकों/संस्थाओं के प्रयासों को समन्वित करने के लिए आयोजित पन्द्रह बैठकों में भी भाग लिया ।

सारणी 2.12—अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मीयादी ऋण (बकाया) 1972-77

(राशि करोड़ रुपयों में)

निम्नलिखित महीने के अंतिम शुक्रवार को	खातों की संख्या		ऋण सीमा		बकाया राशि		खातों की बसूली के लिए दिये गये अग्रिमों को छोड़कर कुल बैंक ऋण
	मीयादी ऋण	समस्त खातों का जोड़	मीयादी ऋण	कुल बैंक ऋण	मीयादी ऋण	कुल बैंक ऋण	
	1	2	3	4	5	6	7
दिसम्बर 1972	89,231	416,567	839	9702	601	5,051	4,892
	(21.4)		(8.6)		(11.9)		(12.3)
जून 1973	103,340	460,384	974	10,428	706	5,771	5,303
	(22.3)		(9.3)		(12.2)		(13.3)
दिसम्बर, 1973	119,385	509,424	1,067	11,370	832	6,396	6,044
	(23.4)		(9.4)		(13.0)		(13.8)
जून, 1974	129,894	535,204	1,280	12,881	924	7,289	6,766
	(24.3)		(9.9)		(12.7)		(13.7)
दिसम्बर 1974	141,701	550,330	1,354	12,362	1,021	7,359	7,150
	(25.7)		(11.0)		(13.9)		(14.3)
जून 1975	152,999	572,306	1,555	13,589	1,148	8,180	7,385
	(26.7)		(11.4)		(14.0)		(15.5)
दिसम्बर 1975	171,536	605,046	1,612	14,468	1,307	9,030	8,094
	(28.4)		(11.1)		(14.5)		(16.1)
जून 1976	196,123	643,382	1,840	16,740	1,516	1,0568	8,383
	(30.5)		(11.0)		(14.4)		(18.1)
दिसम्बर 1976	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
जून 1977	237,278	733,578	2,337	18,503	1,964	12,064	9,528
	(32.4)		(12.6)		(16.3)		(20.6)

अनु०—अनुपलब्ध

टिप्पणी:— 1. ये आंकड़े रु. 10,000 से अधिक की ऋण सीमाओं से युक्त खातों से संबंधित हैं ।

2. स्तंभ 1, 3 और 5 के अंतर्गत कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े क्रमशः स्तंभ 2, 4 और 6 में सूचित जोड़ में मीयादी ऋणों के प्रतिशत को दर्शाते हैं ।

3 स्तंभ 7 के अंतर्गत कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े स्तंभ 7 के जोड़ में स्तंभ 5 के अंतर्गत दिये गये मीयादी ऋणों के प्रतिशत को दर्शाते हैं ।

(स्रोत : मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां)

2.89. रुग्ण यूनिटों की पुनर्व्यवस्था में बैंकों की भूमिका में सुधार लाने के उद्देश्य से जब कभी आवश्यक हुआ, उक्त कक्ष ने रुग्ण यूनिटों के संबंध में बैंकों को अनुदेश/मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये । जब इस बात का प्रतिवेदन किया गया कि बैंक मार्जिन संबंधी आवश्यकताओं में छूट देने से कतराते हैं तब सितम्बर 1978 में बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे मार्जिनों के प्रति लचीला दृष्टिकोण अपनायें और आवश्यक होने पर पात्र मामलों मे मार्जिनों मे संबंधित तब रिजर्व बैंक के निर्देशों से छूट देने के लिए उसे लिखें । साथ ही स्टाकों में सम्मिलित अप्रचलित और अनुपयोगी स्टाकों के संबंध में कुछ रियायतें देते समय बैंकों को रुग्ण यूनिटों के संदर्भ में स्टाकों/बिलों मे संबंधित उचित अनुशासन बनाये रखने की आवश्यकता के बारे में भी सूचित किया गया । उच्च अधिकार प्राप्त समिति (केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में) के निर्णयों के अनुसरण दिसम्बर 1978 मे बैंकों को निम्नलिखित बातों की सूचना दी गयी ।

(1) रुग्ण यूनिटों के लिए स्थापित विशेष कक्षों की कार्य-प्रणाली की समीक्षा करना और नियंत्रण व्यवस्थाओं को मजबूत बनाना,

(2) वाणिज्य बैंकों द्वारा भा. औ. वि. बैंक को रुग्ण यूनिटों के संदर्भ में भेजे गये मामलों में विभिन्न कार्रवाइयां करना,

(3) रुग्ण लघु यूनिटों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए बैंकों में उच्च स्तर पर एक अलग कक्ष स्थापित करना, ताकि उनकी समस्याओं को अधिक सावधानी और समझदारी से निबटाया जा सके,

(4) लघु यूनिटों को परामर्श सेवा प्रदान करना, और

(5) इस बात को सुनिश्चित करना कि रुग्ण यूनिटों की समस्याएं दंडस्वरूप ब्याज दर वसूल करने से जटिल नहीं हैं ।

2.90. जनवरी 1979 में बैंकों से यह भी कहा गया कि ऊपर लिखित उच्च अधिकार-प्राप्त समिति के विभिन्न निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में वे प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

2.91 रुग्ण यूनिटों के रूप में सूचित किये गये 334 यूनिटों के संदर्भ में बैंकों द्वारा सितम्बर 1978 के अन्त तक किये गये अध्ययनों से 137 सक्षम यूनिटों का पता लगा । पता लगा है कि इनमें से 8 यूनिट बैंकों द्वारा किये गए पुनर्व्यवस्था प्रयासों के कारण सक्षम हुए हैं । यह भी पता चला है कि वस्त्र भारी इंजीनियरी और लोहे व इस्पात के उद्योगों में अनुकूल प्रवृत्तियों के संकेत विद्यमान थे ।

2.92. रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र से एक करोड़ रुपये और उससे अधिक राशि के कुल ऋण प्राप्त करने वाली सभी रुग्ण यूनिटों के संक्षिप्त विवरण देते हुए बैंक त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं । त्रैमासिक विवरणों में दी गयी जानकारी से यह स्पष्ट हुआ है कि सितंबर 1978 के अंत में बैंकों द्वारा पता लगाये गये बड़े रुग्ण यूनिटों (एक करोड़ रुपये या उससे अधिक राशि के कुल बैंक ऋण प्राप्त) की संख्या बढ़कर 334 हो गयी और उनके संदर्भ में बैंकों द्वारा दिये गये वित्त की राशि 983 करोड़ रुपये थी, जबकि सितंबर 1977 के अंत में इस प्रकार के 270 यूनिटों के मामलों में बैंक वित्त की राशि 774 करोड़ रुपये थी (इनमें राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अपने अधिकार में लिये गये यूनिट शामिल नहीं हैं) ।

प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित लोगों की सहायता

2.93. देश के किसी भी भाग मे जब कभी बड़े पैमाने पर तूफान, बाढ़ आदि प्राकृतिक विपत्तियां आती रही हैं भारतीय रिजर्व बैंक व वाणिज्य बैंकों को यह सूचित करता रहा है कि वे रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रभावित पार्टियों को सत्काल सहानुभूतिपूर्वक वित्तीय सहायता प्रदान करें । जब सितंबर 1978 में पश्चिम बंगाल में तथा मई 1979 में आंध्र प्रदेश में अभूतपूर्व बाढ़ आयी थी तब इन अनुदेशों पर पुनः जोर दिया गया । बैंकों को जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सारांश निम्न प्रकार है :

(क) संबंधित राज्य सरकार/प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के साथ निकट संपर्क स्थापित किया जाए और विपत्ति से पीड़ित लोगों के आर्थिक पुनर्वास के लिए उनके सहयोग के साथ उपयुक्त योजनाएं बनायी जाएं ।

(ख) वर्तमान फसल ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित किया जाए तथा उनकी चुनौती के लिए 3 से 5 वर्षों तक की अवधि निर्धारित की जाए । इसके अलावा प्राथमिकता के आधार पर नये नकदी ऋण प्रदान करने पर विचार किया जाए ।

(ग) प्रत्येक जिले में दिये जाने वाले वित्त की मात्रा यथासंभव एक समान हो और उनमें ऋणकर्ता की उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को भी विचार में लिया जाए ।

(घ) स्थिति के संबंध में बैंक के मूल्यांकन के आधार पर ऐसी सहायता गैर जमानती आधार पर अथवा तीसरी पार्टी की गारंटी पर जोर दिये बिना ही प्रदान की जाए । साझेदारी के साथ फसल उगाने वाले कृषकों के मामले में ऐसी सहायता सामूहिक गारंटी के आधार पर प्रदान की जाए ।

(ङ) प्रभावित क्षेत्रों में क्षेत्र कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाए और यदि आवश्यक हो तो दूसरे क्षेत्रों से अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को वहां नियोजित किया जाए ।

2.94. भारतीय बैंक संघ और कृषि वित्त निगम प्रभावित क्षेत्रों में हानि का अनुमान लगाने के लिए और अपेक्षित राहत संबंधी उपायों पर विचार करने के लिए अध्ययन कर रहे हैं । प्रभावित व्यक्तियों/यूनिटों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के संदर्भ में बैंकों के लिए उन्होंने कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये हैं । पश्चिम बंगाल में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों/यूनिटों को बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋणों के विवरण नीचे दिये गये हैं :

सारणी 2.13—प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में बकाया बैंक ऋण

31 मार्च 1979

(राशि लाख रुपयों में)

श्रेणी	खाता की संख्या	बकाया राशि
1. कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलाप	46,049	795.59
2. व्यापार और स्वनियोजित व्यक्ति	42	6.11
3. कुटीर और अत्यंत लघु क्षेत्र	26	1.30
4. मझोले और बड़े उद्योग	15	179.32
5. अन्य (लघु उद्योग)	375	140.33
जोड़	46,507	1,122.65

(स्रोत : बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक)

2.95 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने विशेष पुनर्वास योजना, 1978 के अंतर्गत विभिन्न बैंकों से 98 लाख रुपयों के लिए प्राप्त 49 आवेदन पत्रों का निबटान किया और 15 मार्च 1979 तक 38.78 लाख रुपयों की राशि वितरित की ।

विभेदक ब्याज दर योजना

2.96 विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन ऋण प्रदान करने में जनवरी 1978 से दिसम्बर 1978 तक की अवधि के दौरान और प्रगति

हुई। ऋण खातों में 2,28,096 की वृद्धि हुई और उनकी संख्या 13,91,440 से बढ़कर 16,19,536 हो गयी। बकाया ऋणों की राशि 68 करोड़ रुपयों से बढ़कर 90 करोड़ रुपये हो गयी अर्थात् उसमें 22 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी। प्रति खाता ऋण की औसत राशि दिसम्बर 1977 के अंत में स्थित रु० 487 से बढ़कर दिसम्बर 1978 के अंत में रु० 556 हो गयी।

शुल्क वापसी ऋण योजना, 1976

2.97 उक्त योजना शुल्क वापसी के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अनंतिम रूप से प्रमाणित जहाजरानी बिलों पर बैंकों से 90 दिन तक ब्याजमुक्त वित्त प्राप्त करने वाले निर्यातकों के लाभ के लिए है। इसके बदले में वित्तपोषक बैंक निर्यातकों के शुल्क वापसी दावों के अंतिम निपटान तक रिजर्व बैंक से ब्याजमुक्त वित्त प्राप्त करने के पात्र हैं। पहली नवंबर 1978 से 30 जून 1979 तक की अवधि के दौरान 29 बैंकों को कुल 19 करोड़ रुपयों की सीमा मंजूर की गयी, जिन्होंने 25 मई 1979 तक 14 करोड़ रुपयों तक का पुनर्वित्त प्राप्त किया।

2.98 बैंकों और निर्यातकों दोनों द्वारा अनुभव की गयी कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिए हाल ही में लेखा पद्धति को संशोधित किया गया। नयी पद्धति के अंतर्गत, जो मई 1979 से अमल में आयी, सीमा-शुल्क अधिकारी संबंधित बैंकों को अंतिम शुल्क वापसी की अदायगी चेक द्वारा करेंगे और उक्त बैंकों को बदले में इस योजना के अधीन उनके द्वारा लिये गये पुनर्वित्त के बराबर की राशि रिजर्व बैंक को सीमाशुल्क अधिकारियों से चेक प्राप्त होने के दिन से पांच दिन के भीतर चुकानी होगी। रिजर्व बैंक वाणिज्य मंत्रालय के साथ मिलकर इस योजना को बंगला देश को किये जाने वाले निर्यातों और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की ऋण व्यवस्था के अधीन वित्तपोषित निर्यातों पर लागू करने की संभाव्यता का अध्ययन कर रहा है।

निर्यात बिल

2.99 निर्यात वित्त से संबंधित सभी मामलों पर नीतियां बनाने के लिए 1975 में रिजर्व बैंक द्वारा गठित निर्यात वित्त से संबंधित स्थायी समिति की 1978-79 के दौरान दो बार बैठकें हुईं। निर्यातों को अधिक लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से और विशेष रूप से पश्चिमी गोलार्ध के देशों के लिए लगनेवाली अधिक पोतलदान अवधि को देखते हुए यह निश्चय किया गया कि निर्यात के लिए पोतलदानोत्तर ऋण (एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए आस्थगित अदायगी पर दिये जानेवाले ऋणों से भिन्न) की अवधि को 1 फरवरी 1979 से इस समय प्रचलित 128 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया जाए। कांडला मुक्त व्यापार अंचल और बंबई में सांताक्रुज इलेक्ट्रोनिक्स निर्यात अभिसंस्करण अंचल में कार्यरत यूनिटों को अपने समस्त उत्पादन का निर्यात करना होगा और इस प्रयोजन के लिए यह निश्चय किया गया कि ऐसे यूनिटों को उच्चतम रियायती ब्याज दर पर कार्यकारी पूंजीगत वित्त प्रदान किया जाए और बैंकों से पोतलदान पूर्व ऋण प्राप्त करते समय निर्यात के लिए साख पत्र या ठोस आदेश प्रस्तुत करने से इन यूनिटों को छूट दी जाए।

2.100 आस्थगित अदायगी की शर्तों पर इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यातकों को 1975 में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों को संशोधित करने के लिए आलोच्य वर्ष में एक समिति स्थापित की गयी। निर्यात क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों और परियोजना निर्यातों और महत्वपूर्ण ठेकों से संबंधित कई प्रस्तावों की जांच से प्राप्त अनुभव के आधार पर उक्त संशोधन आवश्यक हो गया था। समिति ने हाल ही में अपना कार्य पूरा किया है और भारत सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त होते ही संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये जाएंगे।

निर्यात ऋण संबंधी उपाय

2.101 अमेरिका तथा कतिपय अन्य देशों में हीरे के बाजार में पायी गयी गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में हीरों के निर्यातक हाल ही में भारत से हीरों का निर्यात करने में मंदी की प्रवृत्ति का सामना कर रहे हैं। अतः हीरों के कुल क्रय में गिरावट आयी है जिसके परिणामस्वरूप निर्यातकों/हीरों की पालिश करने वाले यूनिटों के पास तैयार वस्तुयें संचित हो गयी हैं। इस स्थिति के कारण निर्यातकों के समक्ष चलनिधि संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और हीरों को तराशने तथा उनकी पालिश करने के उद्योग में कार्यरत सारी संख्या के कामगार इससे प्रभावित हुए हैं।

2.102 सामाजिक-आर्थिक प्रतिक्रियाओं के कारण तथा निर्यात व्यापार के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने के निमित्त उसे अधिक ठोस आधार प्रस्तुत करने की आवश्यकता को देखते हुए बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे हीरों के निर्यातकों को प्रदान किये गये पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर वित्त की स्वीकृत सीमाओं का पुनरीक्षण करें और यह सुनिश्चित कर लें कि जहां कहीं आवश्यक हो, वे उनकी ऋण संबंधी वास्तविक अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए अधिक मात्रा में वित्त प्रदान करते हैं। बैंकों को न केवल पोतलदानोत्तर ऋण की अधिक लंबी अवधि (अधिकतम 180 दिनों की अवधि की शर्त पर) स्वीकार करने के लिए सूचित किया गया है, परन्तु उनसे यह भी कहा गया है कि वे छोटे हीरे-निर्यातकों को बंधक-सुविधाएं (25 लाख रुपयों से कम निर्यात-कारोबार वाले परोक्ष धारक) प्रदान करें तथा इस प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दें।

2.103 इसके अलावा, कतिपय देशों, अर्थात् नाइजीरिया, घाना, इजराइल, सूडान, सीरिया, ताईवान, तुर्की, वियतनाम, यमन अरब गणतंत्र, जैरे और जाम्बिया को वस्तुओं का पोतलदान करने वाले निर्यातक उन देशों में विद्यमान सुदागत कठिनाइयों के कारण निर्यात संबंधी राशि को इस देश में प्राप्त करने में विलंब का अनुभव कर रहे थे। उपर्युक्त समस्या को सुलझाने तथा ऐसे मामलों में निर्यातकों पर पड़नेवाले ब्याज के भार को कम करने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त देशों पर आहरित निर्यात बिलों (मांग अथवा मीयादी) के मामले में ऋण प्रदान करने वाला बैंक बिल के रुपए/भुनाये जाने/वसूली के लिए भेजे गये बिल पर अग्रिम प्रदान करने की तारीख से भारत में उसकी राशि प्राप्त होने अथवा निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम द्वारा अदायगी किये जाने की तारीख तक (इनमें से जो भी पहले हो) अधिकतम 180 दिनों के लिए ब्याज उपदान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि नियत तारीख को स्थानीय मुद्रा में बिल की अदायगी की जाए; इस संबंध में कतिपय अन्य शर्तों की भी पूर्ति की जानी चाहिए।

निर्यात ऋण (ब्याज उपदान) योजना

2.104 निर्यात ऋण (ब्याज उपदान) योजना, 1968 में निर्यात ऋण प्रदान करनेवाले बैंकों को उनकी ब्याज प्राप्ति में होनेवाली हानि की आंशिक पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है। यह योजना 10 वर्षों से भी अधिक समय से अमल में है। उपदान की राशि एक वर्ष में 12 करोड़ रुपये के आसपास रहती है। यह विदित हुआ कि बैंकों के समक्ष आनेवाली कुछ परिचालनगत समस्याओं को ध्यान में रखना होगा। अतः योजना की उपयोगिता में सुधार लाने के लिए भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ और भारतीय बैंक संघ के परामर्श से अब उसकी समीक्षा की जा रही है।

2.105 पहली जुलाई 1978 से 30 जून 1979 तक की अवधि के दौरान 58 बैंकों को 13 करोड़ रुपयों की राशि ब्याज उपदान के रूप में दी गयी। इस राशि में से 7 करोड़ रुपये पोतलदान पूर्व ऋण के संदर्भ में और 6 करोड़ रुपये पोतलदानोत्तर ऋण के संदर्भ में थे। योजना के प्रारंभ से 30 जून 1979 तक इस योजना के अंतर्गत कुल 72 करोड़ रुपयों का उपदान वितरित किया गया।

2.106 वाणिज्य मंत्रालय की विपणन विकास सहायता निधि से वार्षिक 1.5 प्रतिशत और विदेश मंत्रालय द्वारा आवंटित निधि से 3.0 प्रतिशत की दर पर भारतीय बैंक, वि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को ब्याज उपदान अदा किया जा रहा है। आलोच्य अवधि के दौरान उक्त तीनों संस्थाओं को 90 लाख रुपयों के कुल उपदान

वितरित किये गये। इसके अलावा भाग्रौवि बैंक और पंजाब नैशनल बैंक द्वारा बंगला देश को दिये गये क्रमशः 4 करोड़ रुपयों और 1 करोड़ रुपयों के वाणिज्य ऋण पर विपणन विकास सहायता निधि और विदेश मंत्रालय द्वारा आबंटित निधि में से हरेक में 1.5 प्रतिशत की दर पर 6 लाख रुपयों का ब्याज उपदान अदा किया गया।

निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम लिमिटेड में डेटा बैंक

2.107 यह निश्चय किया गया है कि निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम लिमिटेड को एक डेटा बैंक स्थापित करना चाहिए जो विभिन्न निर्यातकों और विदेशों में महत्वपूर्ण खरीदारों के संबंध में अद्यतन जानकारी एकत्र करेगा और जब कभी बैंकों को जरूरत हो तब उन्हें आंकड़े उपलब्ध करायेगा।

वायदा विनिमय दर संबंधी उतार-चढ़ाव के जोखिम से रक्षा

2.108 अब तक रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय दर संबंधी उतार-चढ़ाव के जोखिम से लंबी अवधि तक रक्षा प्रदान की जाती थी और उससे यदि कोई हानि होती थी तो उसे वाणिज्य मंत्रालय की विपणन विकास सहायता निधि से वसूल किया जाता था। अब यह निश्चय किया गया है कि निर्यात ऋण संगठनों द्वारा विदेशों में चलायी जानेवाली इसी प्रकार की योजनाओं की तरह ही निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम लिमिटेड आवश्यक रक्षा प्रदान करेगा और रिजर्व बैंक द्वारा चलायी जानेवाली वर्तमान योजना को हटाने के लिए एक योजना बनाएगा। रिजर्व बैंक अल्प अवधियों के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय दर संबंधी उतार-चढ़ाव के जोखिम से रक्षा प्रदान करता रहेगा।

पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए रुपया वित्त की योजना

2.109 भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1978 में पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए रुपया वित्त की जो योजना शुरू की गयी थी, उसे विशेष रूप से राज्य बिजली बोर्डों को गैस टर्बाइन जेनरेटिंग सेटों के आयात के लिए भी लागू किया गया। किन्तु यह ही सुविधा एक बार अपवाद स्वरूप दी गयी है और राज्य बिजली बोर्डों को दिये जानेवाले बैंक वित्त के संबंध में पहले ही लागू रिजर्व बैंक के नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों में अन्यथा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बैंक उक्त योजना के अधीन राज्य बिजली बोर्डों को दिये जानेवाले ऋणों के संदर्भ में रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त के पात्र रहेंगे।

2.110 सरकारी क्षेत्र के चौदह बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार योजना के अधीन उनके द्वारा मार्च 1979 के अंत तक मंजूर की गयी सहायता की राशि 1,332 लाख रुपये थी।

बैंकिंग विधान/विनियमन

बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 1978

2.111 बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 लोकसभा में उसके शीतकालीन अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया। बैंकिंग आयोग द्वारा की गयी और सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों को वैधानिक रूप प्रदान करना उक्त विधेयक का उद्देश्य है। उक्त विधेयक में निम्नलिखित बातों में संशोधनों की व्यवस्था है: बैंकर्स बुक्स एवीडेंस एक्ट, 1891, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970।

भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंक विनियमावली, 1951 के विनियम 7 में संशोधन

2.112 भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंक विनियमावली, 1951 के विनियम 7 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अधीन रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली साप्ताहिक विवरणी के प्रयोजन के लिए बचत बैंक खातों की जमा रकम को 'मांग' और 'मीयादी' देयताओं में अनुभाजित करना होता है। उक्त विनियम में दी गयी क्रियाविधि के अनुसार यदि बैंक के बचत बैंक नियम किसी समय बिना पूर्व सूचना के खाते से अधिकतम राशि निकालने के लिए निर्दिष्ट करते हैं ऐसी प्रत्येक राशि के संदर्भ में, ऐसी अधिकतम राशि, या जहां खाते में जमा रकम इस अधिकतम राशि से अधिक नहीं है, संपूर्ण जमा रकम को मांग देयता के रूप में और अधिकतम राशि से अधिक राशि को मीयादी देयता के रूप में माना जाना चाहिए।

2.113 यह विदित हुआ कि उक्त क्रियाविधि इन जमाराशियों के 'मांग' देयता अंश का वास्तविक अनुमान नहीं दर्शाती, जिसके फलस्वरूप 'जनता के पास मुद्रा उपलब्धि' के आंकड़े उस सीमा तक काल्पनिक बन जाते हैं। अतः 'मीयादी' और 'मांग' देयताओं में बचत बैंक जमाराशि के वास्तविक अनुभाजन को दर्शाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 58 की उप धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1978 में रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक विनियमावली, 1951 के विनियम 7 के उपबंधों को संशोधित किया, ताकि बचत खाते में मासिक न्यूनतम जमा रकम, जिस पर खाते में ब्याज जमा किया जाता है, के औसत को मीयादी देयता के रूप में और उक्त राशि से अधिक राशि को मांग देयता के रूप में माना जा सके। यह संशोधन 16 अगस्त 1978 से अमल में आया।

बैंकों का निरीक्षण

2.114 वाणिज्य बैंकों का समय-समय पर निरीक्षण करने के रिजर्व बैंक के कार्यक्रम के अनुसरण में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अधीन आलोच्य वर्ष के दौरान 19 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, एक गैर अनुसूचित बैंक और 31 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय स्वरूप का निरीक्षण कार्य हाथ में लिया गया। पिछले तीन वर्षों (जुलाई-जून) में निरीक्षण किये गये बैंकों और बैंक कार्यालयों की संख्या की तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शायी गयी है।

सारणी 2.14—वाणिज्य बैंकों का निरीक्षण

	1976-77	1977-78	1978-79
	1	2	3
वित्तीय निरीक्षण			
निरीक्षण किये गये/निरीक्षण के लिए लिये गये बैंकों की संख्या	26	37*	51*
निरीक्षण किये गये कार्यालयों की संख्या	825	978*	1363*
केन्द्रवार निरीक्षण			
केन्द्रों की संख्या	1,476	1,058	750
कार्यालयों की संख्या	2,362	1,759	1264

*इनमें वार्षिक मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए निरीक्षण किये गये बैंक/कार्यालय शामिल नहीं हैं।

(स्रोत : बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक)

2.115 आलोच्य अवधि के दौरान विदेश स्थित भारतीय बैंकों के संदर्भ में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा की क्रमशः पश्चिम जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम में स्थित एक-एक शाखा का निरीक्षण किया गया।

सारणी 2.15—अनुसूचित व निजी बैंक

	स्टेट बैंक समूह			राष्ट्रीयकृत बैंक		
	1976	1977	1978	1976	1977	1978
	1	2	3	4	5	6
I. कुल आय	543.38	675.49	801.56	1064.94	1263.59	1444.02
	(20.3)	(25.3)	(18.7)	(24.7)	(18.7)	(14.3)
उसमें से—						
ब्याज और बट्टा	449.24	563.41	668.30	946.31	1132.8	1299.68
	(21.3)	(24.4)	(18.6)	(24.1)	(19.7)	(14.7)
II. कुल व्यय	534.59	666.13	791.89	1045.34	1248.30	1428.16
	(20.4)	(24.7)	(18 8)	(24.7)	(19.4)	(14.4)
उसमें से—						
(क) जमाराशियों, उधारों आदि पर अदा किया गया ब्याज	317.77	409.84	490.88	684 18	829 81	938.24
	(37.5)	(28.9)	(19.8)	(37.9)	(21 3)	(13.1)
(ख) कर्मचारियों को वेतन, भत्ते, भविष्य निधि और बोनस/ अनुग्रह राशि की अदायगी	165.41	196.19	226.43	261 11	301.13	352.98
	(—2.7)	(18.6)	(15.4)	(—0.7)	(15.3)	(17.2)
III. कराधान और कर्मचारियों को देय बोनस/अनुग्रह राशि की अदायगी के लिए व्यवस्था करने के बाद विद्यमान लाभ	8.79	8.86	9.87	19.60	15.29	15.86
	(18.0)	(0.8)	(9.1)	(27.3)	(—22.0)	(3.7)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ को दर्शाते हैं; 1977 के आंकड़े संशोधित हैं।

@ ये आंकड़े 10 करोड़ रुपयों की और उससे अधिक जमाराशियुक्त गैर-सरकारी क्षेत्र के 28 तुलनीय भारतीय वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं।

(स्रोत : बैंकों के लाभ-हानि लेखे)

के कार्य परिणाम

(राशि करोड़ रुपयों में)

अन्य भारतीय अनुसूचित बैंक (6			विदेशी बैंक			जोड़		
1976	1977	1978	1976	1977	1978	1976	1977	1978
7	8	9	10	11	12	13	14	15
165.35 (30.6)	213.13 (28.9)	260 8 (2?.4)	125.75 (5 2)	130.16 (3.5)	137.07 (5.3)	1899.42 (22.4)	2282.37 (20.2)	2643.4 (15.9)
143.01 (29.3)	185.67 (29.8)	231.90 (24.9)	98 59 (1 9)	101.40 (2.9)	106.16 (4.7)	1637.16 (22.2)	1983.35 (22.11)	2306.04 (16.3)
161.35 (30.6)	209.92 (30.1)	256.76 (22.3)	118.36 (3 6)	126.87 (7.2)	131.29 (3.5)	1859.64 (22.3)	2251.72 (21.1)	2608.10 (15.9)
93.35 (39.5)	123.84 (32.7)	154.20 (24.5)	53.43 (7.9)	56.65 (6.0)	60.15 (6.2)	1148.78 (33.2)	1420.14 (23.6)	1643.47 (15.8)
44.34 (12.5)	56.06 (26.4)	67.87 (21.1)	23.22 (—1.8)	27.99 (20.5)	28.52 (1.9)	494.08 (—0.4)	581.37 (17.7)	675.80 (16.2)
4 (29 0)	3.21 (—19.8)	4.05 (26.2)	7.39 (40.3)	3.29 (—55.5)	5.78 (75.7)	39.78 (27.5)	30.65 (—23.0)	35.36 (15.4)

बैंकों का विलयन और परिसमापन

समामेलन

2.116 जैसा कि पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, भारत सरकार ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के अंतर्गत 49 बैंकों के संबंध में समामेलन की योजनाएं मंजूर की थीं। संबंधित योजनाओं की व्यवस्थाओं के अनुसार हस्तांतरी बैंकों को 6/12 वर्ष की अवधि के बाद या भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श करके मंजूर की गयी उससे पहले की अवधि के बाद हस्तांतरक बैंकों की आस्तियों का अंतिम मूल्यांकन करना था। 31 बैंकों की आस्तियों का अंतिम मूल्यांकन पूरा किया गया और 9 बैंकों के मामले में रिपोर्टें विचाराधीन हैं। शेष नौ बैंकों के में पांच बैंकों के संबंध में अंतिम मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा था।

परिसमापन

2.117 आलोच्य अवधि के दौरान नौ बैंकों को विघटित किया गया, जिनमें छः बैंक ऐसे थे जिनका विघटन तो पिछली अवधियों के दौरान ही हो चुका था, किन्तु जिनके संबंध में सूचनाएं 1978-79 की अवधि के दौरान प्राप्त हुईं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44(1) के अधीन एक बैंक को स्वैच्छिक परिसमापन के लिए प्रमाण-पत्र जारी किया गया।

वाणिज्य बैंकों का लाइसेंसीकरण

2.118 जुलाई 1978 से 30 जून 1979 तक की अवधि के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अधीन निम्न-लिखित दो बैंकों को लाइसेंस दिये गये: नैनीताल बैंक लिमिटेड, नैनीताल और यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता। इस प्रकार, लाइसेंसी-कृत वाणिज्य बैंकों की संख्या बढ़कर 50 हो गयी (इसमें नैशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान शामिल है, जो शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक के अधिकार में है)। नैनीताल बैंक लिमिटेड, नैनीताल का नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया गया है।

2.119 30 जून 1979 को आठ बैंक (इनमें गैर सरकारी क्षेत्र के तीन भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक और एक विदेशी अनुसूचित बैंक अर्थात हबीब बैंक लिमिटेड जो शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक के अधिकार में है, शामिल हैं) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अधीन बिना लाइसेंस के कार्य कर रहे थे। सरकारी क्षेत्र के 22 बैंकों को लाइसेंसों की आवश्यकता नहीं है।

समाशोधन गृह सुविधाएं

2.120 आलोच्य वर्ष के दौरान 47 नये समाशोधन गृहों की स्थापना की गयी, जिससे 30 जून 1979 तक समाशोधन गृहों की कुल संख्या बढ़कर 651 हो गयी, जबकि 30 जून 1978 को यह संख्या 604 थी। इनमें 11, 515, 124 और 1 समाशोधन गृहों का प्रबंध क्रमशः भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है।

ऋण सूचना

2.121 भारतीय रिजर्व बैंक का बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग अलग-अलग ऋणकर्त्ताओं को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं से संबंधित जानकारी बैंकों और दूसरी अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं को उपलब्ध कराकर उनकी सहायता करता रहा। जुलाई 1978 से जून 1979 तक के वर्ष के दौरान 1,049 आवेदन-पत्रों पर संबंधित आवेदक बैंकों/अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं को ऋण सूचना प्रदान की गयी जबकि पिछले वर्ष के दौरान 890 आवेदन-पत्रों पर ऐसी सूचना प्रदान की गयी थी।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्य परिणाम

2.122 62 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के वर्ष 1978 के लिए प्रकाशित लाभ-हानि लेखों से उनके जो कार्य परिणाम उपलब्ध है, उन्हें 1977 और 1976 के कार्य परिणाम के साथ सारणी 2.14 में दर्शाया गया है। 1978 के दौरान बैंक अपने लाभ-हानि लेखों में कर्मचारियों के लिए बोनस की व्यवस्था करने के संबंध में विभिन्न पद्धतियां अपनाते रहे। कुछ बैंकों ने इसको स्थापना व्यय की एक मद के रूप में माना है और इसे वेतन, पारिश्रमिक आदि के अधीन दर्शाया है, जबकि कुछ अन्य बैंकों ने यह सूचित किया कि जब बोनस वितरित किया जाएगा तब उस राशि को आकस्मिक निधियों में से दिया जायेगा, जिसके लिए वर्ष की लाभ राशि में व्यवस्था की गयी है। पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि इस वर्ग की प्रारक्षित निधियों का एक अंश बोनस के भुगतान के सिवाय दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हो सकता है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्य परिणामों के विश्लेषण हेतु, ऐसी सूचना के अभाव में, यह मान लिया गया है कि इस वर्ष के दौरान समस्त आकस्मिक प्रारक्षित निधि की व्यवस्था बोनस देने के लिए ही की गयी। 1978 के दौरान कर और स्टाफ को बोनस/अनुग्रह राशि की अदायगी की व्यवस्था करने के बाद बैंकों के लाभ 5 करोड़ रुपये से बढ़कर 35 करोड़ रुपये हो गये (अथवा 15.4 प्रतिशत बढ़े) जबकि वे 1976 के 40 करोड़ रुपयों से कम होकर 1977 में 30 करोड़ रुपये हो गये थे।

2.123 1978 के दौरान आय और व्यय दोनों में वृद्धि हुई। 1978 के दौरान बैंकों की कुल आय में 361 करोड़ रुपयों (+15.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि 1977 में उसमें 383 करोड़ रुपयों (+20.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। आलोच्य वर्ष के दौरान बैंकों के कुल व्यय में भी 356 करोड़ रुपयों (+15.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि गत वर्ष के दौरान कुल व्यय में 392 करोड़ रुपयों (+21.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। वर्ष 1977 के विपरीत 1978 में बैंकों की आय में व्यय की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई, जिससे बैंकों के लाभ बढ़ गये। जमाराशियों, उधारों आदि से संबंधित ब्याज की अदायगी 1977 के 23.6 प्रतिशत से कम होकर 1978 में 15.7 प्रतिशत और स्थापना व्यय 17.7 प्रतिशत से कम होकर 16.2 प्रतिशत हो जाने के कारण 1978 में बैंकों के व्यय में न्यून वृद्धि हुई। 5 वर्ष और उससे अधिक की सावधि जमाराशियों और अन्य अवधियों की दूसरी जमाराशियों की ब्याज दरों को कम कर देने से संभवतः ब्याज की अदायगियों (वृद्धि दर) में कमी आयी।

2.124 1978 के दौरान सभी बैंक समूहों के लाभ में वृद्धि हुई। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों के लाभ में 9.1 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि 1977 में उक्त वृद्धि दर 0.8 प्रतिशत थी। राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ भी वर्ष 1978 के दौरान 3.7 प्रतिशत बढ़ गये, जबकि पिछले वर्ष उनके लाभ में 22.0 प्रतिशत की गिरावट आयी थी।

समितियां और कार्यकारी दल: नियुक्ति, सिफारिशें और अनुवर्ती कार्रवाई

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्यपद्धति का अध्ययन करने के लिए समिति (जेम्स राज समिति)

2.125 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्यपद्धति का अध्ययन करने के लिए जेम्स एम० राज की अध्यक्षता में जून 1977 में नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने शाखा विस्तार

की गति और दिशा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका, भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों के विन्यास तथा पूर्वोत्तर, पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में तीन नये बैंकों के गठन के संबंध में कई सिफारिशें कीं ।

2.126 समिति ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तीव्र वृद्धि के कारण उनके प्रबन्ध तन्त्र पर अत्यधिक भार पड़ा है और इसके परिणामस्वरूप पर्यवेक्षी नियंत्रण ढीले पड़ गये हैं और इससे लागत पर प्रभाव पड़ने के कारण उनकी लाभप्रदता में भी बाधा पड़ी है । अतः अधिक संख्या की शाखाओं वाले बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि तीन से पांच वर्ष की अवधि तक वे अपनी स्थिति को मजबूत बनायें । अतः उन्हें निर्दिष्ट सीमा से अधिक विस्तार की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए । इसके अतिरिक्त किसी भी बैंक को उसके मुख्य कार्यक्षेत्रों से दूर शाखाएं खोलने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए तथा इस प्रकार की शाखाओं का स्वैच्छिक आदान-प्रदान हो जाना चाहिए । इस तरह, समिति के अनुसार वाणिज्य बैंकों को केवल जिला मुख्यालय/मंडी स्तर पर शाखाएं खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण क्षेत्र का वित्तपोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्रमशः वाणिज्य बैंकों की वर्तमान ग्रामीण शाखाओं को अभिस्वीकार कर लेना चाहिए ।

2.127 जैसा कि पैराग्राफ 2.2 में उल्लेख किया जा चुका है, 1979—81 के लिए शाखा लाइसेन्सीकरण की नयी नीति निर्धारित करते समय जेम्स राज समिति तथा कामथ कार्यकारी दल और वांतवाला समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है ।

2.128 भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों को पुनर्गठित करने तथा पूर्वोत्तर, पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में तीन नये बैंक गठित करने से संबंधित सिफारिश बैंकिंग तन्त्र के स्वरूप से अभिप्राय रखती है और ये सिफारिशें रिजर्व बैंक के विचाराधीन हैं।

2.129 आंतरिक संगठन, शक्तियों के प्रत्यायोजन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने की शर्तों आदि से संबंधित अन्य सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए बैंकों को सूचित किया जा चुका है ।

गृह निर्माण योजनाओं के वित्तपोषण में

वाणिज्य बैंकिंग तंत्र की भूमिका से संबंधित अध्ययन के लिए कार्यकारी दल

2.130 गृह निर्माण योजनाओं के वित्तपोषण में बैंकिंग तंत्र की भूमिका का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यकारी दल की रिपोर्ट प्रस्तुत होने का उल्लेख पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था । इस कार्यकारी दल की सिफारिशों पर आधारित निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को जारी किये गये ।

2.131 गृह निर्माण कार्यों के वित्तपोषण में बैंकिंग तंत्र का सीमित योगदान ही हो सकता है और यह 75 करोड़ रुपये वार्षिक हो सकता है । दिसम्बर 1978 के अन्त तक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये कुल अग्रिमों के लगभग 0.5 प्रतिशत के बराबर यह राशि होगी और बैंकों के अपने कर्मचारियों को प्रदत्त आवास ऋण इसमें शामिल नहीं होंगे समय-समय पर इस अनुपात की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता का पुनरीक्षण किया जायेगा ।

2.132 निर्धारित राशि के भीतर प्रदान किये जाने वाले प्रत्यक्ष और परोक्ष वित्त का अनुपात बैंकों के विवेक पर निर्भर करता है । तथापि बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अतिरिक्त वित्त का बड़ा भाग आवास और शहरी विकास निगम और राज्य आवास मण्डलों के गारण्टीकृत बांडों और डिबेंचरों के अभिदान के रूप में दिया जाता है । आवास योजनाओं का प्रत्यक्ष वित्तपोषण मुख्यतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्गों और मध्यम आय वर्गों के लाभ हेतु होना चाहिए । सामान्यतः आवास ऋण परियोजना की कुल लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा ब्याज दर 12 प्रतिशत होनी चाहिए जिसमें किस्तों के नियमित भुगतान पर 1/2 प्रतिशत छूट दी जाये । फिर भी, बैंक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों को कुल लागत के 80 प्रतिशत तक आवास ऋण प्रदान कर सकता है और अनुसूचित जातियों/जनजातियों से 2,500 रुपये से अनधिक ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज ले सकते हैं । वसूली की अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । अग्रिम के लिए जमानत के रूप में सम्पत्ति का बंधक अथवा सरकारी गारण्टी रखनी चाहिए ।

2.133 यद्यपि अग्रिमों का हिसाब वाणिज्य बैंकों की बहियों में रहेगा, फिर भी वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ग्रामीण सहकारी समिति और स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से आवास ऋण प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं तथा उचित ऋणकर्ताओं का पता लगाने और ऐसे अग्रिमों के वितरण तथा वसूली के लिए इन संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं ।

2.134 कार्यकारी दल ने कुछ निर्माण प्रक्रियाओं को बैंक ऋण के पात्र के रूप में वर्गीकृत किया है न कि आवास ऋण के पात्र के रूप में । ऐसी प्रक्रियाओं का वित्तपोषण वाणिज्यिक सिद्धांतों पर ही किया जाना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त सिद्धांतों को अत्यधिक महत्व दिया जाए । ऋण के लिए आवेदन पत्रों का निबटान करते समय अर्जित आय, नकद प्राप्ति, चुकौती के साधन और अन्य संबंधित आंकड़ों की ध्यानपूर्वक संवीक्षा करना आवश्यक है जिससे यह निश्चित हो जाए कि परियोजना वाणिज्यिक दृष्टि से सक्षम है तथा अर्जित अतिरिक्त नकदी आय ऐसे अग्रिमों के अधीन देय किस्तें चुकाने के लिए पर्याप्त होगी । आवास ऋण के सिवाय निर्माण कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त दिया जाए; पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के मामले में बैंक ऋण का प्रयोग मूलभूत सुविधाओं (सार्वजनिक सड़कों, पुलों, पत्तन, बांधों आदि) के निर्माण के लिए न हो; क्योंकि इन कार्यों के लिए उनके बजटों में व्यवस्था की जानी चाहिए । ऐसे वित्त के लिए निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए :

2.135 बैंकों को योजना की कुल लागत के 40 प्रतिशत और अपवादात्मक मामले में 50 प्रतिशत से अधिक अग्रिम प्रदान नहीं करने चाहिए । इन पर वाणिज्यिक अग्रिमों पर लागू ब्याज दर ली जानी चाहिए । सामान्यतः 7 वर्षों में ऋण की अदायगी हो जानी चाहिए ; परन्तु किसी भी हालत में यह अवधि 10 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए । जमानत स्वरूप सम्पत्ति बंधक के रूप में रखी जा सकती है और/अथवा ऐसे प्रयोजनों के लिए साधारणतः उपलब्ध कोई अन्य जमानत हो सकती है ।

2.136 बैंकों को यह निदेश दिया गया था कि मूलभूत सुविधाओं और सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यालयों, जिनमें नगरपालिका तथा पंचायत के कार्यालय शामिल हैं, के लिए भवन निर्माण हेतु वे प्रत्यक्ष ऋण के रूप में आगे से कोई भी वित्त प्रदान न करें । फिर भी, उन कार्यों के लिए ऋण प्रदान किये जा सकते हैं, जिन पर कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम जैसी संस्थाओं से पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त हो; उन कम्पनियों अथवा अलग अलग व्यक्तियों को भी ऋण प्रदान किया जा सकता है जो मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कार्य करने का वायदा करें । धर्मार्थ अथवा धार्मिक संगठनों को विशेष महत्व देना आवश्यक नहीं है जब तक कि उनकी योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले लोग कमजोर वर्गों के न हों ।

2.137 वाणिज्य बैंकों, आवास और शहरी विकास निगम आवास मंडलों, जीवन बीमा निगम आदि की संघीय व्यवस्था को, जहां भी संभव हो, योजना के स्वरूप के आधार पर अपनाया जाना चाहिए; यह व्यवस्था विशेषकर उन परियोजनाओं में अपनायी जानी चाहिए जिनमें पूंजीगत परिव्यय अधिक हो । ऐसी संघीय ऋण व्यवस्था में बैंकों

के मामले में अदायगी की अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा किस्मत की राशि आनुपातिक आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। आवास और शहरी विकास निगम, आवास मंडलों, जीवन बीमा निगम जैसी विशेषीकृत एजेंसियों के लिए अदायगी की लम्बी अवधि निर्धारित करने में कोई आपत्ति नहीं है, आनुपातिक आधार पर निर्धारित किस्तों की अदायगी साथ-साथ प्रारम्भ होगी ।

बैंक ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित अध्ययन दल—तंडन समिति

2.138 1975 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति नयी ऋण नीतियों के परिचालन में लचीलापन बनाये रखने के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है; बैंक ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित अध्ययन दल की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर ये ऋण नीतियां बनायी गयी थीं । रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग में स्थापित कक्ष द्वारा समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

2.139 आलोच्य वर्ष के दौरान इस समिति की तीन बैठकें हुई तथा बैंकों, उद्योगों और उनके प्रतिनिधि संघों, वाणिज्य और उद्योग मण्डलों द्वारा ऋण आवेदन/मानदंडों में परिशोधन से संबंधित और अन्य विषयों, जिन पर समिति के विचार प्राप्त किये जा सकते हैं, पर उठायी गयी बातों पर उन बैठकों में विचार किया गया । भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न विषयों पर समिति के विचारों का परीक्षण किया और बैंकों को उनके अनुसार निदेश दिये जिससे वे परिचालन के लचीलेपन में और अधिक सुधार करें और नये उधार तन्त्र को बेहतर ढंग से समझ सकें । समिति ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की, उन पर निर्णय लिये और बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत अनुदेश जारी किये :

(i) उधार देने की पद्धतियों (अध्ययन दल द्वारा संस्तुत) को और अधिक लचीला बनाने के लिए बैंकों को जुलाई 1978 में यह सूचित किया गया कि वे, विशेष मामले के तौर पर, उन औद्योगिक इकाइयों को, जिनका पिछला कार्यकलाप अच्छा रहा है और जिन्होंने काफी समय से एक मजबूत चालू अनुपात बनाये रखा है, कुछ प्रयोजनों के लिए एक निश्चित सीमा तक चालू अनुपात में कमी करने की अनुमति देने पर विचार करें । फिर भी, इस बात पर बल दिया गया कि बैंकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कम से कम 1.33 : 1 का चालू अनुपात रखा जाता है । बैंकों को यह भी निदेश दिया गया कि ऐसे ऋणकर्ताओं को, जिनपर अध्ययन दल द्वारा संस्तुत उधार देने की पहली पद्धति लागू की जाती है, अतिरिक्त सामान्य शेयर अथवा मीयादी ऋण जुटाये बिना अपने कार्यों में विस्तार की अनुमति सामान्यतः नहीं मिलनी चाहिए ताकि विस्तार के परिणामस्वरूप उनका वित्तीय ढांचा कमजोर न हो जाए ।

(ii) ऋण प्राधिकरण योजना के अधीन अधिकतम सीमा के प्रयोजन के लिए मीयादी ऋणों को शामिल करने के प्रश्न और साख पत्रों एवं गारंटियों को योजना के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित करने के प्रश्न पर विचार किया गया और अगस्त 1978 में बैंकों को उचित अनुदेश जारी किये गये ।

(iii) बैंक ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित अध्ययन दल की विभिन्न सिफारिशों को लघु इकाइयों पर लागू करने के प्रश्न पर समिति ने विचार किया । समिति का यह विचार था कि चूंकि 90 प्रतिशत से अधिक इकाइयां 2 लाख रुपये से कम ऋण सीमाओं का उपयोग करती है और अध्ययन दल द्वारा संस्तुत स्टाकों के मानदंड केवल उन इकाइयों पर लागू होते हैं जो बैंकिंग तंत्र से 10 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमाओं का उपयोग करती हैं, अतः अधिकतर लघु उद्योग इकाइयां उक्त मानदंड के कार्यक्षेत्र के बाहर हैं । उनमें से कुछ बड़ी इकाइयां ही इस नियम के अन्तर्गत आती हैं और चूंकि वे सम्भाव्य मध्यम/बड़े पैमाने के उद्योग हैं इसलिए धीरे-धीरे उन्हें श्रेष्ठ प्रबंध व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए ।

(iv) बड़ी इकाइयों द्वारा छोटी इकाइयों को बिलों के भुगतान में विलम्ब की समस्या पर समिति ने विचार-विमर्श किया । इस विषय का और अधिक परीक्षण किया गया और अगस्त 1978 में बैंकों को यह निदेश दिया गया कि अन्य बातों के साथ-साथ वे समग्र ऋण सीमाओं के अन्तर्गत स्वीकारण/साख-पत्र सुविधाओं के लिए अलग उप-सीमाएं निर्धारित करें जिनका प्रयोग केवल लघु उद्योगों से खरीदों के सम्बन्ध में ही किया जाये; लघु उद्योगों से की जाने वाली खरीदों के अनुपात और अन्य संबद्ध तत्वों को ध्यान में रखकर उप-सीमाएं निर्धारित की जाए । बैंकों को यह भी कहा गया कि वे लघु इकाइयों को देय राशि के विवरण अपने मध्यम और बड़े ऋणकर्ताओं से प्रत्येक तिमाही में प्राप्त करें और उक्त विषय पर ऋणकर्ता के साथ समुचित ढंग से विचार विमर्श करें जिससे लघु इकाइयों को अविलम्ब अदायगियां सुनिश्चित हों ।

(v) समिति ने इस बात पर चर्चा की कि बैंकों को कुछ ऐसी इकाइयों से, जो निर्माण कार्य नहीं करती, किस प्रकार की त्रैमासिक सूचना प्राप्त करनी है और समिति के निर्णयानुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने एक उप-दल गठित किया है जो निर्माण-कार्य न करने वाली इकाइयों (जैसे परिवहन, निर्माण कम्पनियां, बिजली बोर्ड, व्यापारिक इकाइयां, होटल, नागरिक आपूर्ति निगम आदि) से प्राप्त होने वाली सूचना का विस्तृत विवेचन करेगा और बैंकों द्वारा ऐसी इकाइयों को दिये जाने वाले ऋण पर नियंत्रण रखने की कार्यवाहियों और तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई पर विचार करेगा । इस उप-दल की पहली बैठक 17 अप्रैल 1979 को हुई ।

(vi) टायर बनाने वाले उद्योगों को स्टाकों/बिलों के मानदंडों में ढील देने की अनुमति के संबंध में समिति ने यह महसूस किया कि रबड़ उत्पादों पर लागू होने वाले स्टाकों/बिलों के मानदंडों में सामान्य परिशोधन के लिए कोई भी आधार नहीं है ।

(vii) मानदंडों में पारस्परिक परिवर्तनशीलता के संबंध में समिति ने अनुभव किया कि अध्ययन दल द्वारा विहित कुछ उद्योगों में बिलों और तैयार वस्तुओं से संबंधित मानदंडों में पहले से ही पारस्परिक परिवर्तनशीलता है । इसके अलावा, स्टाक के अलग-अलग घटकों (अर्थात् कच्चे माल, निर्माणाधीन स्टाक और तैयार वस्तुएं) के संदर्भ में अलग-अलग मानदंड हैं क्योंकि उनकी आवश्यकता का निर्धारण करने वाले तत्व भिन्न हैं तथा पारस्परिक परिवर्तनशीलता मानदंडों के औचित्य के अनुरूप भी नहीं होगी ।

(viii) संघीय व्यवस्थाओं के अधीन स्वीकृतियां आदि प्राप्त करने में ऋणकर्ताओं को होने वाली कठिनाइयों/असुविधाओं और समन्वय के अभाव तथा अन्य कार्य संबंधी समस्याओं पर निदेश समिति में चर्चा की गई । इन चर्चाओं के आधार पर नवम्बर 1978 में बैंकों को कुछ स्थूल मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये । उनके अन्तर्गत निम्नलिखित विभिन्न पहलुओं को लिया गया : संघीय व्यवस्था के लिए अपेक्षित बैंकों की संख्या, सदस्य बैंकों का न्यूनतम हिस्सा निर्धारित करने की आवश्यकता, संघीय व्यवस्था के सदस्यों का सक्रिय योगदान कार्यपद्धति जिससे मूल्यांकन के चरण और अन्य चरणों पर अनुचित विलम्ब समाप्त/कम किया जा सके, सूचना का आदान प्रदान, अग्रिमों के लिए जमानत का निरीक्षण सत्यापन आदि ।

(ix) चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् के अभिवेदन के उत्तर में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निदेश दिया कि हालांकि टण्डन समिति ने चमड़ा उद्योग के लिए कोई भी मानदंड निर्धारित नहीं किये हैं फिर भी पिछली प्रवृत्तियों, प्रक्रिया/परिचालन समय, व्यापार प्रणालियों आदि को ध्यान में रखकर बैंक स्टाकों/बिलों के मामले में उचित स्तर निर्धारित कर सकते हैं। बैंकों को यह भी निदेश दिया गया कि आयोजनाओं के औचित्य पर विचार करते समय वे इस तथ्य को भी ध्यान में रखें कि पहले जहां आधे तैयार चमड़े का निर्यात होता था वहां अब तैयार चमड़े और चमड़े के उत्पादनों के निर्यात पर अधिक बल दिया जाता है, अतः प्रक्रिया-समय बढ़ जायेगा और इकाइयों को अधिक स्टाक रखने होंगे। इसके अलावा, चूंकि बहुत सी इकाइयां स्वामित्व साझेदारीवाली लघु इकाइयां थीं अतः वे कार्यकारी पूंजी में विद्यमान अन्तर को 25 प्रतिशत की पूर्ति करने के लिए पहली ऋण पद्धति के आधार पर सामान्य शेयर और मीयादी ऋण जुटाने की स्थिति में न हों। बैंकों से यह कहा गया कि वे उपयुक्त मामलों में उचित ढील दें जिससे कि उद्योग निर्यात बाजार का लाभ उठा सके, परन्तु वे समय-समय पर इसका पुनरीक्षण करें और अपेक्षित मशीनें खरीदने के लिए इन इकाइयों की मीयादी ऋणों की प्रार्थना पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सहायता प्राप्त इकाइयां लाभों के पुनः प्रयोग जैसे उपायों से अपने वित्तीय स्वरूप को सुधारें।

(x) रूई कताई मिलों और उर्वरक उद्योग के लिये स्टाकों/बिलों के मानदंडों में ढीलें जारी रखने या उन्हें हटा देने के संबंध में निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :

(क) रूई कताई मिलें : रूई कताई मिलों की स्थिति में सुधार हो जाने के कारण और समय तक ढीलें देने की आवश्यकता नहीं थी।

(ख) उर्वरक उद्योग : इस उद्योग को प्रदत्त वर्तमान ढीलों में कोई परिशोधन करने से पहले इस विषय पर भारतीय उर्वरक संघ के साथ विचार विमर्श कर लिया जाये। समिति को और कई बातों पर लिखा गया था, उन पर भी उसने विचार विमर्श किया। तत्संबंधी वितरण निम्न प्रकार हैं :

(i) बैंक ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई पर अध्ययन दल की विभिन्न सिफारिशों का कार्यान्वयन और इस संबंध में बैंकों द्वारा अनुभव की गयी कठिनाइयां;

(ii) सूचना तंत्र के अधीन ऋणकर्ताओं द्वारा बैंकों को प्रस्तुत किये गये विवरणों की समीक्षा;

(iii) उधार लेनेवाली इकाइयों के प्रबंध की लेखा परीक्षा; और

(iv) क्या औद्योगिक इकाइयों के वित्तीय कुप्रबंध का पता लगाने/उसे रोकने के लिये बड़े ऋणकर्ताओं के संबंध में बैंकों द्वारा बनाये गये सूचना तंत्र का प्रयोग किया जा सकता है; यदि हां, तो किस सीमा तक; अथवा इस प्रयोजन की प्राप्ति के लिये क्या बैंकिंग तंत्र लेखा परीक्षकों की शक्ति बढ़ाने जैसे किसी अन्य उपाय का प्रयोग कर सकता है।

उधार कार्यों पर अन्तर संस्थागत दल

2.140 मीयादी उधार देनेवाली संस्थाओं और वाणिज्य बैंकों के उधार कार्यों के समन्वयन से संबंधित अंतर संस्थागत दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उल्लेख पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था। बैंकों और मीयादी उधार देनेवाली संस्थाओं के बीच समन्वयन से संबंधित सभी पहलुओं पर दल ने सिफारिशें की है ; उक्त संस्थाओं के बीच मीयादी ऋणों के अंश विभाजन के मानदंड निर्धारित करना; मूल्यांकन, अनुवर्ती कार्रवाई, सूचना के आदान-प्रदान आदि के परिप्रेक्ष्य में मीयादी उधार देनेवाली संस्थाओं की भूमिका निश्चित करना; मीयादी ऋण मंजूर करने और परियोजना की स्वीकृति के संबंध में माथ पत्र खोलने और कार्यकारी पूंजीगत सीमाएं स्वीकार करने के समय का संकेत करना; प्रतिभूतियों के विभाजन, दस्तावेजों की संवीक्षा, नकद प्राप्तियों में अंश निर्धारण आदि से संबंधित सुझाव देना और रुग्ण इकाइयों का उपचार करना। दल की सिफारिशों के अनुसरण में औद्योगिक परियोजनाओं के वित्तपोषण के कार्य में मीयादी उधार प्रदान करनेवाली संस्थाओं और बैंकों के समन्वित प्रयास के दौरान उत्पन्न होने वाले विभिन्न नीतिगत प्रश्नों का अध्ययन करने के लिये स्थायी समन्वयन समिति स्थापित की गयी है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंकों और मीयादी उधार देनेवाली संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। रुग्ण इकाइयों को दी जानेवाली पुनर्वास सहायता में मीयादी ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाओं की सहभागिता से संबंधित सिफारिशें उक्त दल के विचाराधीन हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ परिशोधनों/स्पष्टीकरणों के साथ अन्य सिफारिशों को मंजूर कर लिया।

बैंकों की परिचालन क्षमता और लाभप्रदता से संबंधित कार्यकारी दल

2.141 रिजर्व बैंक ने कार्यकारी दल की सिफारिशों पर विचार किया और लागत नियंत्रण, नकदी प्रबंध, शाखाओं के लिए स्टाफ स्वरूप, ग्राहक सेवा, शाखाओं की लाभप्रदता, सेवाओं की लागत का निर्धारण, विवेकाधीन शक्तियां आदि से संबंधित कतिपय पहलुओं पर बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये।

बैंकों की ग्राहक सेवा के संबंध में कार्यकारी दल

2.142 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि बैंकों की ग्राहक सेवा संबंधी कार्यकारी दल की सिफारिशों की जांच करने के लिये एक दल (कार्य दल) गठित किया गया है ताकि उक्त सिफारिशों का कार्यान्वयन जल्दी हो सके। उक्त दल ने नियमित रूप से बैठकें बुलाई तथा सिफारिशों के कार्यान्वयन में बैंकों की प्रगति का पुनरीक्षण किया। इस वर्ष के दौरान सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ और सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे सितम्बर 1978[1] से उन्हें अमल में लायें। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि सरकारी क्षेत्र के कई बैंकों ने इन सिफारिशों के कार्यान्वयन में काफी प्रगति की है, जो कि केवल उन्हीं के द्वारा कार्यान्वित की जानी थीं। बैंकों द्वारा भेजी जाने वाली त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों के आधार पर रिजर्व बैंक अपने पास इस संबंध में जानकारी रखता है। ऐसे सात क्षेत्रों में, जहां कार्यकारी दल ने यह महसूस किया था कि बैंकों की ग्राहक सेवा में सुधार लाने की तत्काल आवश्यकता है, बैंकों द्वारा की गयी प्रगति का विवरण नीचे दिया जाता है :

सारणी 2.16—ग्राहक सेवा से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन में की गयी प्रगति

सेवा क्षेत्र	सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों की कुल संख्या	50 प्रतिशत से अधिक बैंकों द्वारा कार्यान्वित सिफारिशों की कुल संख्या
1. जमा खाते . . .	14	8
2. प्रेषण और वसूली . . .	12	8
3. ऋण और अग्रिम . . .	8	6
4. विदेशी मुद्रा कारोबार . .	5	1
5. सरकारी कारोबार . .	1	1
6. अनुशासन और अभिरुचि . .	7	3
7. सामान्य . . .	4	4

[1]कार्यकारी दल की अंतिम रिपोर्ट में ये सिफारिशें सं० 28 और 30 के अंतर्गत आती हैं। ये सिफारिशें खातों और पास बुकों के विवरण प्रदान करने के मामलें में ग्राहकों को दी जानेवाली सेवा से संबंधित हैं।

वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिये जाने वाले ऋणों से संबंधित राज्य अधिनियमों के संबंध में विशेषज्ञ

2.143 वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि के लिये दिये जानेवाले ऋणो से संबंधित राज्य अधिनियमों के संबंध में विशेषज्ञ दल (तलवार समिति) की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति पिछले वर्ष की रिपोर्ट में दी गयी थी। तलवार समिति द्वारा सिफारिश किये गये नमूना विधेयक के आधार पर 16 राज्यों ने आवश्यक विधान पारित कर लिये हैं।

वाणिज्य बैंकों की कृषि ऋण योजनाओं के संबंध में विशेषज्ञ दल

2.144 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि वाणिज्य बैंकों की कृषि ऋण योजनाओं से संबंधित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। दल ने वाणिज्य बैंकों की कृषि ऋण योजनाओं को विकासात्मक प्रयासों के अनुरूप बनाने और कृषकों को दिये जानेवाले ऋणों के लाभों में वृद्धि करने वाली अन्य सहायक गतिविधियों के लिये बनायी गयी ऋण योजनाओं के अनुरूप बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जब तक यह नहीं होगा तब तक सभी वर्गों के कृषि ऋणकर्ताओं के मामले में बढ़ती हुई ऋण राशि से अधिक आय नहीं होगी। दल का यह विचार है कि कृषि क्षेत्र को वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की राशि में विशेष वृद्धि करने तथा काश्तकारों को अधिकाधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिये की गयी व्यवस्थाओं में हुई प्रगति के बावजूद कृषि ऋण योजनाओं के निर्माण, उनसे संबंधित विषय तथा उनके कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं में कई त्रुटियां विद्यमान हैं। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उक्त दल ने कई सिफ़ारिशें की हैं तथा इस बात पर जोर दिया है कि उनमें से कई सिफारिशें उपयुक्त होंगी चाहे बैंक अपने आप कृषकों को सीधे ऋण वितरित करें या वे प्राथमिक कृषि ऋण समितियों तथा कृषक सेवा समितियों जैसी बिचौली संस्थाओं के माध्यम से ऋण वितरित करवायें। बैंकों को दल की अधिकांश सिफ़ारिशें कार्यान्वित करने के लिये कहा गया है।

पुरी समिति की रिपोर्ट

2.145 लघु उद्योगों की बैंक ऋण संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री आई० सी० पुरी की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने उक्त क्षेत्र को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिये जुलाई 1978 में बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये। बैंकों को यह सूचित किया गया कि केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा विशेष रोजगार योजनाओं के अंतर्गत प्रवर्तित जो छोटे यूनिट विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र के और तकनीकी योग्यता प्राप्त तथा दूसरे उद्यमियों के हैं उनके मामले में मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं में वे लचीला दृष्टिकोण अपनायें तथा परियोजनाओं की क्षमता का ध्यान रखें। साथ ही समर्थक जमानत/गारंटी के अभाव में किसी भी उपयुक्त प्रस्ताव को अस्वीकार न करें।

हथकरघों के लिए ऋण की आवश्यकताओं के मूल्यांकन से संबंधित अध्ययन दल

2.146 भारत सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सहकारी क्षेत्र से बाहर रहनेवाले हथकरघा बुनकरों और राज्य हथकरघा विकास निगमों का वित्तपोषण करने की समीक्षा करने के लिये एक अध्ययन दल गठित किया। दल से यह कहा गया था कि वह अगले पांच वर्षों में निगमों की ऋण आवश्यकताओं का अनुमान लगायें तथा आसानी से बैंक वित्त उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक उपाय एवं संस्थागत क्रियाविधियां सुझायें। दल से यह भी कहा गया था कि वह हथकरघा बुनकरों/हथकरघा विकास निगमों का वित्तपोषण करने में राष्ट्रीयकृत बैंकों की वर्तमान भूमिका का अध्ययन करें, ऐसे उपाय सुझायें जिनसे इन निगमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच कार्यगत संबंध निरंतर स्थापित हो सके, और हथकरघा क्षेत्र को ऋण की सहकारी प्रणालियों एवं वाणिज्य बैंकों द्वारा किये जानेवाले वित्तपोषण की तुलनात्मक लाभ-हानि का मूल्यांकन करे। अध्ययन दल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

सहभागिता प्रमाणपत्रों से संबंधित कार्यकारी दल

2.147 15 मार्च 1979 को कुछ प्रमुख बैंकों के अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने दो कार्यकारी दल गठित किये। उनमें से एक दल सहभागिता प्रमाणपत्रों के रूप में और वित्तीय संस्थाओं से मांग मुद्रा बाजार में उधारों के रूप में बैंकों द्वारा ली जानेवाली सहायता का अध्ययन करेगा तथा दूसरा दल बैंकों की नकदी ऋण प्रणाली के सभी पहलुओं का पुनरीक्षण करेगा।

2.148 सहभागिता प्रमाणपत्रों से संबंधित कार्यकारी दल के विचारणीय विषय निम्न प्रकार हैं: (i) मांग मुद्रा बाजार और सहभागिता प्रमाणपत्रों के आकार और स्वरूप का अध्ययन करना तथा मुद्रा और ऋण नीतियों के मामले में उनके प्रभाव की व्याख्या करना, (ii) उस आधार का सुझाव करना जिस पर वाणिज्य बैंकों और पुनर्वित्त एजेंसियों (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम जैसी) से भिन्न स्रोतों से बैंकों को उपलब्ध होनेवाले वित्तीय साधनों की स्थूल मात्रा का मूल्यांकन किया जाए, (iii) मांग मुद्रा बाजारों और सहभागिता प्रमाणपत्रों से संबंधित व्यवस्थाओं में भाग लेनेवाली गैर बैंकिंग संस्थाओं से ऐसी निधियों के उपलब्ध होने में किसी प्रतिबंध के कारण पड़नेवाले असर की जांच करना तथा ऐसी निधियों के उत्पादक प्रयोग के लिये वैकल्पिक क्षेत्रों का सुझाव देना और (iv) किसी दूसरे संबंधित विषय पर सिफारिशें करना। कार्यकारी दल ने मई 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यकारी दल द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों पर विचार करते हुए यह निर्णय किया गया कि प्रारंभ में सहभागिता प्रमाणपत्रों का अधिकाधिक सहारा लेने की बैंकों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कार्रवाइयां की जाएं। इन कार्रवाइयों पर ऋण नीति से संबंधित पैराग्राफों में पहले ही विचार किया जा चुका है।

नकदी ऋण पर कार्यकारी दल

2.149 नकदी ऋण से संबंधित कार्यकारी दल को निम्नलिखित बातों की समीक्षा करनी है : हाल ही के वर्षों में पायी गयी नकदी ऋण प्रणाली की कार्य पद्धति का, विशेष रूप से मंजूर की गयी ऋण सीमाओं और उनके प्रयोग की मात्रा के बीच विद्यमान खाई के संदर्भ में अध्ययन करना; इस अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रणाली में संशोधनों का सुझाव देना ताकि इस प्रणाली को वाणिज्य बैंकों के औचित्यपूर्ण निधि प्रबंध के अनुरूप बनाया जाए और/या ऐसी वैकल्पिक ऋण सुविधाएं सुझाना जिनसे ऋण के मामले में अधिकाधिक अनुशासन का पालन हो और बैंक ऋण सीमाओं को उत्पादन अथवा अन्य उत्पादक कार्यों से संबद्ध कर सकें और ऐसे दूसरे संबंधित विषयों पर सिफ़ारिशें करना जो दल के विचार में उपयुक्त हों। कार्यकारी दल ने एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है।

लघु उद्योग के लिए वित्तीय एजेंसी पर कार्यकारी दल

2.150 उद्योग के लघु तथा विकेन्द्रित क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शीर्ष वित्तीय संस्था गठन के प्रश्न की जांच करने के लिये रिज़र्व बैंक ने मई 1979 में एक कार्यकारी दल गठित किया। इस कार्यकारी दल के विचारणीय विषय निम्न प्रकार हैं : (1) उद्योग के लघु और विकेन्द्रित क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ऋण की वृद्धि के उपाय सुझाना तथा इस परिप्रेक्ष्य में इस उद्देश्य के लिये अलग वित्तीय एजेंसी स्थापित करने की संभावना का मूल्यांकन करना; (2) नयी वित्तीय एजेंसी की वास्तविक स्थापना के पूर्व आवश्यक वैधानिक एवं प्रशासनिक स्वरूप पर विचार करना; (3) इस बात की जांच करना कि क्या ऐसी कोई एजेंसी लघु उद्योग क्षेत्र की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी या लघु उद्योग क्षेत्र और ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों के लिये अलग-अलग एजेंसियां स्थापित करना आवश्यक है; (4) नयी वित्तीय एजेंसी को सौंपे जाने वाले पुनर्वित्तपोषण के कार्य और विपणन कार्य आदि की व्यापकता का निर्धारण करना; और (5) प्रस्तावित वित्तीय एजेंसी तथा वाणिज्य बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों जैसी वर्तमान ऋण संस्थाओं के बीच पारस्परिक संबंध निर्धारित करना।

बैंकों को प्रभावित करने वाली और उनसे संबंधित विधि की समीक्षा—बैंकिंग विधि समिति की रिपोर्ट

2.151 भारत सरकार ने 1972 में डा० पी० वी० राजमन्नार की अध्यक्षता में एक-सदस्यीय बैंकिंग विधि समिति गठित की थी। समिति ने सरकार तथा रिज़र्व बैंक के विचारार्थ निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं:

(i) परकाम्य लिखत विधि पर रिपोर्ट

यह रिपोर्ट परकाम्य लिखतों के सन्दर्भ में भारत तथा अन्य देशों में विद्यमान विधि तथा पद्धति के तुलनात्मक अध्ययन का फल है। समिति ने परकाम्य लिखतों से सम्बन्धित सामान्य विधि के सभी पहलुओं, विशेषकर विनिमय बिलों, चेकों तथा नोटों का गहन अध्ययन किया है और 1881 में देश में लागू वर्तमान परकाम्य लिखत अधिनियम में संशोधन के लिए विनिर्दिष्ट सिफारिशें की हैं।

(ii) स्थावर सम्पत्ति सुरक्षा विधि पर रिपोर्ट

इस रिपोर्ट में सामान्यतः (प्रमुखतः हमारी बन्धक विधि में दी गई) स्थावर सम्पत्ति सुरक्षा विधि और व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा स्थावर सम्पत्ति दोनों पर संस्थागत एजेन्सियों द्वारा ग्रामीण ऋण प्रदान किये जाने से सम्बन्धित विशेष विधि की समीक्षा की गयी है।

(iii) व्यक्तिगत संपत्ति सुरक्षा विधि पर रिपोर्ट

इस रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत सम्पत्ति जिसे संस्थागत तथा अन्य ऋणदाता के पास जमानत के रूप में रखा जा सकता है, के सन्दर्भ में वाणिज्य तथा सहकारी ऋण प्रदान करने से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचार किया गया है।

(iv) माल के अधिकार-प्रलेखों पर रिपोर्ट

इस रिपोर्ट में बैंक अग्रिमों के लिये पात्र रेलवे रसीदों, लॉरी रसीदों, लदान बिलों, भाण्डागार रसीदों और अन्य प्रलेखों से सम्बन्धित कानूनी रूपरेखा, की समीक्षा की गयी है। साथ ही इस रिपोर्ट और में जूट व्यापार क्षेत्र में प्रचलित पक्का दानि आदेश की समीक्षा भी दी गयी है।

(v) देशी परकाम्य लिखत (हुंडी) पर रिपोर्ट

इस रिपोर्ट में देशी लिखत अर्थात हुंडी से सम्बन्धित पद्धति तथा परम्परा को संहिताबद्ध करने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त रिपोर्टें रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

सांविधिक लेखा परीक्षक पैनल

(सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए) के विस्तार पर समिति

2.152 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नियुक्त किए जाने के लिए लेखा परीक्षकों का पैनल तैयार करने के निमित्त आवश्यक मानदंड तथा मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने अक्टूबर 1978 में उपर्युक्त समिति का गठन किया। समिति कतिपय अन्य विषयों पर भी सिफारिशें करेगी। इस समिति में रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय, भारतीय बैंक संघ, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान तथा बैंक लेखा परीक्षकों की स्थायी परामर्श समिति के प्रतिनिधि सदस्य हैं।

अन्य समितियां

2.153 चयनात्मक ऋण नियन्त्रण पर एक-सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा उनकी सिफारिशें बैंक के विचाराधीन हैं।

शिक्षा और प्रशिक्षण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2.154 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों तथा शाखा प्रबन्धकों को पुणे स्थित कृषि बैंकिंग महाविद्यालय में प्रशिक्षण दिया जाता है। यह निश्चय किया गया है कि जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों तथा शाखा प्रबन्धकों के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा तब लेखाकारों क्षेत्र अधिकारियों एवं लिपिकों जैसे अन्य कर्मचारियों के लिए सम्बन्धित प्रयोजक बैंक के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा जो कि कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे के सम्पूर्ण नियन्त्रण में होगा।

2.155 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित संचालन समिति ने अपनी दूसरी बैठक में शिक्षण व्यवस्थाओं को संशोधित किया है। यह निश्चय किया गया है कि कृषि बैंकिंग महाविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले 12 सप्ताह के पाठ्यक्रम को समाप्त किया जाए। इसके स्थान पर महाविद्यालय द्वारा चार सप्ताह का अभिस्थापन कार्यक्रम चलाया जाए। ऐसे पाठ्यक्रमों की संख्या को वर्ष में दो तक सीमित न किया जाए बल्कि 3 से 4 वर्षों की उचित अवधि में शेष अप्रशिक्षित शाखा प्रबन्धकों को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जाएं। प्रयोजक बैंकों को सूचित किया जाएगा कि वे अपने प्रशिक्षण महाविद्यालयों या संस्थाओं में आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए व्यवस्था करें।

अग्रणी बैंक योजना

2.156 अग्रणी बैंक योजना के उद्देश्यों तथा उसके अभिप्रायों को बेहतर रूप में समझने की दृष्टि से योजना में सम्बद्ध उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने यह निर्णय किया था कि राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान राज्य सरकारों तथा वाणिज्य बैंकों के अधिकारियों के लिए जिला स्तर तथा साथ ही राज्य स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित करे। तदनुसार संस्थान ने उत्तर प्रदेश के सात जिलों तथा पश्चिम बंगाल के तीन जिलों में कार्यशालाएं आयोजित कीं। इस विषय पर उच्च अधिकार-प्राप्त समिति ने जुलाई, 1978 में हुई अपनी चौथी बैठक में पुनः विचार किया और यह निर्णय किया गया कि इस सम्बन्ध में एक नीति तैयार की जानी चाहिये जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के सभी जिले यथाशीघ्र सम्मिलित किये जा सकें। राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान ने बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, बम्बई में दिसम्बर, 1978 में चार सेमीनार आयोजित किये। ये सेमीनार तीन-तीन दिन के लिये थे और इनमें अग्रणी बैंकों के प्रधान/क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रतिनिधियों तथा उनके प्रशिक्षण महाविद्यालयों के संकाय सदस्यों ने और राज्य सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। इनका यह उद्देश्य है कि विभिन्न अग्रणी बैंकों के अधिकारी, जिन्होंने सेमीनार में भाग लिया है, राज्य/जिले के कार्यालयों के समन्वयन के साथ जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित करें ताकि देश के विभिन्न जिले यथाशीघ्र इनमें सम्मिलित किये जा सकें। तदनुसार, इस दिशा में पहले चरण के रूप में अधिकांश अग्रणी बैंकों ने जून, 1979 में समाप्त छमाही के दौरान जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित करने के लिये कार्यक्रम बना लिया है।

2.157 राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान ने बंगाल, उत्तर प्रदेश और असम के लिए भी राज्य स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की हैं। इनके अलावा भारतीय स्टेट बैंक तथा राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान ने आन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के लिए राज्य स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की हैं। राज्य स्तरीय बैंकर समितियों के संयोजकों के साथ अन्य सभी राज्यों में भी राज्यस्तरीय कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रस्ताव है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हिन्दी का प्रयोग

2.158 आलोच्य अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक ने अपने तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए सतत प्रयास किये। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करने के लिए बैंक में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छठी बैठक 22 जनवरी, 1979 को हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों से सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अवगत करा दिया गया है।

2.159 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर निगरानी रखने की दृष्टि से बैंक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टें तथा प्रत्येक बैंक द्वारा गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के कार्य विवरणों की प्रतिलिपियां पूर्ववत् प्राप्त करता रहा। इस विषय पर बैंकों से जानकारी एकत्र कर वह भारत सरकार को भेजी जाती रही।

अध्याय 3

सहकारी बैंक व्यवसाय

3.1 कृषि और कृष्येतर उपक्षेत्र दोनों को और विशेषकर ग्रामीण आबादी के कमजोर वर्गों को अधिक ऋण प्रदान करने के लिए इस वर्ष के दौरान ग्रामीण ऋण की संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करने के और प्रयास किये गये । इस क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा की गयी प्रगति की समीक्षा अध्याय 2 में पहले ही की जा चुकी है । सहकारी ऋण के ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए की गयी कार्रवाइयों तथा अधिकाधिक मात्रा में कृषि/कृष्येतर और अल्पावधि/दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में की गयी प्रगति का विवरण इस अध्याय में दिया गया है ।

3.2 जून, 1978 में समाप्त तीन वर्षों के दौरान सहकारी ऋण की प्रगति के आंकड़े तथा रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी ऋण सुविधाओं और पुनर्वित पर ब्याज की दरों के ब्यौरे क्रमशः सारणी 3.1 तथा 3.2 में दिये गये हैं । सहकारी विन्यास के विभिन्न स्तरों पर लगायी गयी ब्याज दरों की वर्तमान स्थिति सारणी 3.3 में दर्शायी गयी है ।

3.3 सहकारी समितियों ने जमाराशि जुटाने में और प्रगति की । जून, 1977 के अन्त में जहां राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की जमाराशियां क्रमशः 835 करोड़ रुपये तथा 1154 करोड़ रुपये थीं वहां प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के पास 142 करोड़ रुपयों की जमाराशियां थीं । जून, 1978 के अन्त तक उक्त जमाराशियां बढ़कर क्रमशः 1002 करोड़ रुपये, 1373 करोड़ रुपये तथा 165 करोड़ रुपये हो गयीं; इनकी वृद्धि दर 1976-77 के क्रमशः 15.3 प्रतिशत, 17.2 प्रतिशत तथा 25.7 प्रतिशत से बढ़कर 1977-88 में क्रमशः 20.0 प्रतिशत, 19.0 प्रतिशत तथा 16.2 प्रतिशत हो गयी । प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में सदस्यों की संख्या 1975-76 के अन्त में स्थित 395 लाख से बढ़कर 1976-77 के अन्त में 448 लाख तथा 1977-78 के अन्त में और बढ़कर 610 लाख हो गयी । 1976-77 के दौरान प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा दिये गये अल्पावधि तथा मध्यावधि ऋणों की राशि 1,211 करोड़ रुपये थी जबकि 1977-78 के दौरान उक्त राशि 1,257 करोड़ रुपये थी ।

3.4 वाणिज्य बैंकों के लिए निर्धारित दरों की तुलना में अपने विवेकानुसार जमाराशियों पर उच्चतर दरों (एक सीमा तक) पर ब्याज अदा करने की जो अनुमति सहकारी बैंकों को दी गयी थी, वह इस वर्ष भी जारी रही ।

ऋणों पर ब्याज दरें

3.5 रिजर्व बैंक द्वारा शिखर सहकारी बैंकों को (राज्य सहकारी बैंक) दी जाने वाली अल्पावधि ऋण सुविधाओं की ब्याज दरें 1977-78 के दौरान कम कर दी गयी थीं और उन्हें मध्यावधि ऋणों के मामले में और कम कर दिया गया । पहली जनवरी, 1979 से कृषि उद्देश्यों के लिए दिये जाने वाले मध्यावधि ऋण तथा परिवर्तन ऋणों की संशोधित दर बैंक दर से 3 प्रतिशत कम है जबकि पुरानी दर बैंक दर से 2½ प्रतिशत कम थी । जिन प्रयोजनों के लिए दिये जाने वाले अल्पावधि ऋण रिजर्व बैंक से पुनर्वित प्राप्त के पात्र थे उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया और मध्यावधि प्रयोजनों के मामले में कुछ गौण परिवर्तन किये गये ।

सारणी 3.1 भारत में सहकारी ऋण आंदोलन की प्रगति

(राशि करोड़ रुपयों में)

संस्थाओं के प्रकार	सहकारी वर्ष		
	1975-76	1976-77	1977-78प
	1	2	3
(क) राज्य सहकारी बैंक			
(i) संख्या (वास्तविक)	126	26	26
(ii) स्वाधिकृत निधियां	159	184	213
(iii) जमाराशियां	724	835	1,002*
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये उधार	247	375	468
(v) उनमें से अल्पावधि कृषि ऋण	147	229	289
(vi) कार्यकारी पूंजी	1,287	1,526	1,814
(vii) जारी किये गये ऋण	1,515	1,899	2,005
(viii) बकाया ऋण	894	1,089	1,321
(ख) मध्यवर्ती सहकारी बैंक			
(i) संख्या (वास्तविक)	344	344	338
(ii) स्वाधिकृत निधियां	360	423	484
(iii) जमाराशियां	985	1,154	1,373††
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक/शिखर बैंकों से लिये गये उधार	513	699	767
(v) कार्यकारी पूंजी	2,048	2,514	2,774
(vi) जारी किये गये ऋण	1,722	1,988	2,130
(vii) बकाया ऋण	1,428	1,796	2,111
(ग) राज्य मध्यवर्ती/भूमि विकास बैंक			
(i) संख्या (वास्तविक)	19	19	19
(ii) स्वाधिकृत निधियां	154	164	208
(iii) बकाया डिबेंचर	1,384	1,591	1,559
(iv) कार्यकारी पूंजी	1,667	1,918	2,082
(v) जारी किये गये ऋण	205	249	239
(vi) बकाया ऋण	1,069	1,211	1,305

(स्रोत : कृषि ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक)

*मई 1979 तक 1,059 करोड़ रुपये ।

††मई 1979 तक 1,526 करोड़ रुपये, जिसमें 9 औद्योगिक सहकारी बैंक शामिल हैं ।

(ब) प्राथमिक कृषि ऋण समितियां			
(i) संख्या (हजारों में)	135	124	122
(ii) सदस्य (हजारों में)	39,521	44,832	61,003
(iii) स्वाधिकृत निधियां	437	499	554
(iv) जमाराशियां	113	142	165
(v) उधार	1,154	1,426	1,614
(vi) जारी किये गये ऋण	1,023	1,211	1,257
(vii) कृषि प्रयोजनों के लिए कुल ऋण	971	1,152	1,203
उनमें से मध्यावधि ऋण	90	136	149
(viii) बकाया ऋण	1,299	1,599	1,203

अ-अनंतिम

सारणी 3.2—1977-78 और 1978-79 के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी संस्थाओं, राज्य सरकारों और कृषिपुनर्वित्त और विकास निगम को दिया गया ऋण

(राशि करोड़ रुपयों में)

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा	वित्त का प्रयोजन	1977-78†				1977-79†			
		मंजूर की गयी सीमाएं	निकाली गयी राशियां	चुकायी गयी राशियां	बकाया राशियां	मंजूर की गयी सीमाएं	निकाली गयी राशियां	चुकायी गयी राशियां	बकाया राशियां
		1	2	3	4	5	6	7	8
I. अल्पावधि जोड़		845	1228	1163	325	946	1218	1283	259
धारा 17(4) (ग) के साथ पठित 17 (2) (ख) / 17 (4) (ग)	(i) मौसमी कृषि कार्य (बैंक दर से 3 प्रतिशत कम दर पर)[1]	749	994	934	289	795	1066*	1121*	234*
धारा 17 (4) (ग) के साथ पठित 17 (2) (ख) या 17 (4) (ग)	(ii) कई और कपास को छोड़कर अन्य फसलों का विपणन (जून 1978 से बैंक दर पर)	1	—	—	—	3	—	—	—
17 (4) (ग)	(iii) कई और कपास का विपणन[2] (जून 1978 से बैंक दर पर)	14	1	1	—	66	4	4	—
धारा 17 (4) (ग) के साथ पठित 17 (2) (ख) या 17 (4) (ग)	(iv) उर्वरकों की खरीद और वितरण (जून 1978 से बैंक दर से 1 प्रतिशत अधिक दर पर)[3]	13	24	31	3	6	8	10	1
धारा 17 (4) (ग) के साथ पठित 17 (2) (ख) या 17 (4) (ग)	(v) हथकरघे से बनी वस्तुओं का उत्पादन और विपणन (मार्च 1978 से बैंक दर 2-1/2 प्रतिशत कम दर पर)[4]	44	167	159	24	51	126	134	16
17 (4) (ग) के साथ पठित 17 (2) (खख)	(vi) अन्य कुटीर और लघु उद्योगों का वित्तपोषण (मार्च 1978 से बैंक दर से 3 प्रतिशत कम दर पर)[4]	7	5	4	5	6	12	9	8

			1	2	3	4	5	6	7	8
17 (4ङ)	(vii)	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को ऋण (बैंक दर पर)	10	—	—	—	10	—	—	—
17 (4) (ग)	(viii)	सूत की खरीद और बिक्री (बैंक दर पर)[4]	2	1	1	—	3	1	1	—
17 (4) (ग)	(ix)	चीनी के बंधक पर (बैंक दर से 3 प्रतिशत अधिक दर पर)	8	36	34	3	6	1	4	—
II. मध्यावधि जोड़††			121 सं०	115	89	161	66	38	75	125
46क (2) (ख) के साथ पठित 17 (4कक)	(i)	कृषि प्रयोजनों के लिए (1 जनवरी 1979 से बैंक दर से 3 प्रतिशत कम दर पर)[3]	21	12	7	22	28	16	11	28
46ख (2) के साथ पठित 17 (4कक)	(ii)	अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करना (जनवरी 1979 से बैंक दर से 3 प्रतिशत कम दर पर)[5]	98 सं०	103	81	138	37	22*	64*	97*
17 (4कक) जैसा कि धारा 46क (2) (ख) के अधीन निश्चय किया गया है	(iv)	सहकारी चीनी कारखानों/अभिसंस्करण समितियों के शेयरों की खरीद (बैंक दर पर)[6]	1	—	—	—	1	—	—	—
III. दीर्घावधि जोड़			86	86	29	328	94	94	38	385
धारा 46क (2) (क) जैसा कि धारा 46क (2) (क) के अधीन निश्चय किया गया है	(i)	सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को दिये गये ऋण (वार्षिक 6 प्रतिशत की दर पर)[4]	21	21	8	111	19@	19@	10	121
धारा 46क (2) (ङ) के साथ पठित 17 (4कक)	(ii)	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को ऋण (वार्षिक 6 प्रतिशत की दर पर)	65	65	21	217	75	75	28	264
कुल ऋण (I+II+III)			1052 सं०	1429	1281	814	1106	1350	1396	769

1. फरवरी 1978 तक बैंक दर से 2 प्रतिशत कम दर पर; मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार जमाराशियां जुटाने से रियायती दर पर पुनर्वित्त को संबद्ध करने की योजना के अनुसार 1-1/2 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज वसूल करने की शर्त पर 1 मार्च 1978 से बैंक दर से 3 प्रतिशत कम दर पर।

2. रुई की एकाधिकार वसूली शामिल है।

3. स्तंभ 1–4 और स्तंभ 5–8 के संदर्भ में आंकड़े क्रमशः कैलेण्डर वर्ष 1977 और 1978 से संबंधित है।

4. आंकड़े वित्तीय वर्ष से संबंधित हैं।

5. इन ऋणों की पुनर्व्यवस्था और उनकी अवधियों का पुनर्निर्धारण शामिल है।

@जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए, आंकड़े जुलाई-जून से संबंधित हैं।

@पिछले वर्षों की निकाली गई राशियां।

सं० संशोधित

* 31-5-1979 को विद्यमान स्थिति।

†† अल्पावधि और मध्यावधि ऋणों की विभिन्न मदों के जोड़ तथा समूह के जोड़ में पाये जाने वाले नाम मात्र के अंतर का कारण आंकड़ों को पूर्णांकित करना है।

— कुछ नहीं अथवा नगण्य

सारणी 3.3 सहकारी विन्यास के विभिन्न स्तरों पर ली जाने वाली वर्तमान ब्याज दरें

राज्य	शिखर बैंक		मध्यवर्ती सहकारी बैंक		प्राथमिक कृषि ऋण समितियां	
	अल्पावधि	मध्यावधि	अल्पावधि	मध्यावधि	अल्पावधि	मध्यावधि
	1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	6.75	7.25	8.75	9.25	11.00	11.50
बिहार	6.75	अनु.	8.75	अनु.	11.25	अनु०
गुजरात	6.00से	6.50से	6.50से	8.00से	8.00से	9.50से
	6.50	7.00	11.00	12.75	13.50	15.00
हरियाणा	6.40	7.50	8.50	9.00	11.00	11.00
कर्नाटक	6.75	6.25	9.00	9.25	11.50	12.25
ल. कृ.				8.25		11.00
केरल	6.75	अनु.	8.50	अनु.	11.00	अनु.
मध्य प्रदेश	7.00	7.50	9.50	9.00से	12.50	11.00
ल. कृ.	6.50		8.00	13.00	10.00	10.00
महाराष्ट्र	6.25		8.00से		11.00से	
			10.00		13.00	
उड़ीसा	6.75	7.25	8.75	9.25	11.00	11.50
पंजाब	6 30	6.75	8.00	8.50	10.50	10.50
राजस्थान	7.55	7.00	9.75	8.50	12.00	10.50
ल. कृ.	6.50		8.50		10.50	
तमिलनाडु	6.66	7.50	8.75	10.00	12.00	12.50
ल. कृ.					10.50	
उत्तर प्रदेश	7.10		9.50		12.00	
ल. कृ.	6.25		8.50		11.00	
पश्चिम बंगाल	6.75		9.00		11.25से	
					11.50	
असम	10.50	10.50			13.00	13.00
गोवा, दमण और दीव	7.00				9.00	
हिमाचल प्रदेश	10.00	10.50			12.50	13.00
जम्मू और काश्मीर	6.75		8.50		11.00	
अंदमान और निकोबार	9.25	12.00			11.50	14.00
चंडीगढ़	11.00	11.00			12.50	12.50
मणिपुर	10.00	10.50			13.00	13.00
त्रिपुरा	10.00	11.00			13.00	14.00
नागालैंड	11.00	11.00			13.00	13.00
मेघालय	11.00	11.50			13.50	14.50
दिल्ली	9.50	10.00			11.50	12.00
ल. कृ.	9.00				11.00	
पांडिचेरी	8.50	9.00			11.00	11.00
ल. कृ.	8.00				10.00	

(स्रोत : कृषि ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक)

ल. कृ.—लघु कृषक

अनु.—अनुपलब्ध

3.6 रिजर्व बैंक ने सहकारी समितियों के ब्याज दर विन्यास से सम्बन्धित अध्ययन दल की सिफारिशों को स्वीकार किया तथा उन्हें कार्यान्वित किया । उक्त अध्ययन दल ने जून, 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कहा गया था । अध्ययन दल ने अल्पावधि और मध्यावधि कृषि ऋण की ब्याज दरों के औचित्य तथा कृषि ऋण प्रदान करने वाली अन्य संस्थागत एजेंसियों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरों में समानता लाने के लिए कई सिफारिशें की हैं । इन सिफारिशों पर उचित खण्डों में विचार किया गया है । साथ ही पात्र संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त सहायता में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा दी गयी रियायतों के परिणामस्वरूप सहकारी समितियों द्वारा वितरित दीर्घावधि ऋण की ब्याज दरों में भी कमी कर दी गयी है ।

कृषि ऋण

अ. अल्पावधि ऋण

(क) मौसमी कृषि कार्यों के लिए अल्पावधि ऋण]

3.7 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले ऋणों को जमा राशि जुटाने के प्रयासों से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को रियायती ब्याज दर की सुविधा केवल उस सीमा तक उपलब्ध होगी जहां तक वे जमाराशियों के लक्ष्य की पूर्ति करेंगे । यह योजना आलोच्य वर्ष के दौरान जारी रही । वर्ष 1977-78 के दौरान 36 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को ब्याज की इस रियायती दर का पूरा लाभ उपलब्ध नहीं था जबकि 1976-77 तथा 1975-76 में ऐसे बैंकों की संख्या क्रमशः 29 और 32 थी । इस योजना के अन्तर्गत 1976-77 के अन्त में जहां 246 मध्यवर्ती सहकारी बैंक और 3 राज्य सहकारी बैंक आते थे वहां 1977-78 के अन्त में उक्त बैंकों की संख्या क्रमशः 290 और 6 थी ।

3.8 चालू वर्ष के लिए मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा ऋण लेने से पहले खरीफ तथा रबी फसलों के लिए दिये गये अग्रिमों के निर्दिष्ट अंश की वसूली करने की शर्त द्वारा ऋण देने तथा वसूली के कार्यों में आवधिकता को सुनिश्चित करने के लिए पहले जारी किये गये अनुदेश इस वर्ष भी अमल में रहे । फिर भी, सहकारी बैंकों के ब्याज दर विन्यास से सम्बन्धित अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार इन शर्तों में छूट दी गयी तथा राज्य सहकारी बैंकों को मध्यवर्ती सहकारी बैंक की ओर से रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर की गयी अल्पावधि ऋण सीमा से (अप्रैल, 1979 से) ऋण लेने की अनुमति दी गयी । किन्तु शर्त यह थी कि वर्तमान खरीफ 'मांग'[1] का 40 प्रतिशत (पहले के अल्पावधि कृषि अग्रिमों की कुल 'मांग' के 40 प्रतिशत की शर्त के मुकाबले) या कुल 'मांग' (अतिदेय राशियों सहित) का 30 प्रतिशत वसूल किया जाना चाहिए तथा उसे 31 मार्च, 1979 के पहले शिखर बैंक में जमा किया जाना चाहिए । साथ ही, सहकारी वर्ष के समाप्त होने से पहले मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने अल्पावधि ऋणों की कुल 'मांग' का न्यूनतम 40 प्रतिशत वसूल कर लिया है, अन्यथा आगामी सहकारी वर्ष में वे ऋण के पात्र नहीं होंगे । कुल मांग में पिछले वर्ष के 30 जून तक अल्पावधि ऋणों के अन्तर्गत विद्यमान अतिदेय राशियां तथा सम्बन्धित सहकारी वर्ष के लिए की गयी खरीफ और रबी अग्रिमों की 'मांग' शामिल होगी । हालांकि राज्य सहकारी बैंक अपने स्रोतों से ऐसे मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को ऋण देने के लिए स्वतन्त्र थे जो निर्धारित मौसमी अनुशासन का पालन नहीं करते, फिर भी रिजर्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों को यह सूचित किया कि वह उनसे मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को अपने स्रोतों से वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामले में भी उसी शर्त का पालन करने की अपेक्षा करता है ।

3.9 वर्ष 1977-78 के दौरान मौसमी कृषि कार्यों के वित्तपोषण के लिए रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को मंजूर की गयी अल्पावधि ऋण सीमाओं में जहां 53 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई और वे बढ़कर 749 करोड़ रुपये हो गयी, वर्ष 1978-79 के दौरान 46 करोड़ रुपयों की और वृद्धि हुई तथा उक्त ऋण सीमायें 795 करोड़ रुपये हो गयीं । इस वृद्धि का कारण यह भी कहा जा सकता है कि सहकारिता आन्दोलन के विन्यासगत तथा परिचालनगत पहलुओं में और सुधार हुए ।

(ख) कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता

3.10 भारतीय रिजर्व बैंक मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ऋण नीतियों एवं प्रक्रियाओं को छोटे किसानों के अनुकूल बनाने की दिशा में सदा प्रयत्नशील रहा है । उदाहरण के तौर पर रिजर्व बैंक द्वारा मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए स्वीकृत ऋण सीमा के 70 प्रतिशत से अधिक राशि लेने की अनुमति किसी राज्य सहकारी बैंक को तब तक नहीं दी गयी जब तक उससे सम्बद्ध छोटे किसानों को दिये गये ऋण का अनुपात प्राथमिक समितियों को दिये गये कुल अल्पावधि ऋणों के निर्दिष्ट प्रतिशत (सामान्यतः 20 प्रतिशत) तक नहीं पहुंच गया हो । सहकारी बैंकों के ब्याज दर विन्यास से सम्बन्धित अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार इस शर्त में संशोधन किया गया था ताकि यदि बैंक निर्धारित स्तर तक नहीं पहुंच पाये हों तो भी वे ऋण सीमा से राशि निकाल सकें । किन्तु शर्त यह होगी कि इस प्रकार के ऋण छोटे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने तक ही सीमित रहेंगे । वर्ष 1977-78 के दौरान कुल 339 बैंकों में से 292 बैंकों ने छोटे किसानों को दिये जाने वाले ऋण के निर्धारित अंश से अधिक ऋण दिया जबकि 1976-77 में 334 बैंकों में से 260 बैंकों ने ऐसे ऋण दिये थे । कमजोर वर्गों के लिए बनायी गयी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले ऋणकर्ता सहकारी बैंकों से स्वीकृत कृषि तथा सम्बन्धित कार्यों के लिए मध्यावधि वित्त-पोषण सुविधा प्राप्त कर सकें—इस उद्देश्य से मध्यावधि वित्तपोषण के लिए अपेक्षित जमानत से सम्बन्धित वर्तमान मानदण्डों में रियायत की गयी । इसके परिणामस्वरूप सहकारी बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि वे उस ऋण लेने वाले की व्यक्तिगत जमानत पर, जिसके पास देने के लिए प्रत्यक्ष जमानत न हो, कम खर्च वाले एक यूनिट की लागत तक दुधारू पशु, मुर्गी, भेड़ आदि खरीदने के लिए ऋण मंजूर कर सकते हैं ।

(ग) चयनात्मक ऋण नियंत्रण और फसलों के विपणन के लिए अल्पावधि ऋण

3.11 मूंगफली, सरसों/तोरिया, एरण्ड और अलसी के बीज तथा उनके तेल, वनस्पति, चीनी, गुड़, खाण्डसारी और रूई तथा कपास जैसी संवेदनशील वस्तुओं की जमानत पर दिये जाने वाले ऋण पर न्यूनतम मार्जिन तथा ब्याज दर के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के पहले के निदेश लागू थे ।

3.12 16 अगस्त, 1978 से चीनी के मूल्यों, आवाजाही और वितरण पर से नियंत्रण हटा दिया गया था । अतः 8 सितम्बर, 1978 को राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को यह सूचित किया गया कि नियंत्रण हट जाने के बावजूद लेवी स्टाक और मुक्त बिक्री के स्टाकों—(क) बिक्री के लिए नहीं दिये गये और (ख) बिक्री के लिए दिये गये—के बीच अन्तर सम्भवतः काल्पनिक रूप से बना रहे तथा चीनी उत्पादकों को दिये गये ऐसे अग्रिमों के मामले में फरवरी 1977 के निदेश में निर्धारित मार्जिन रखे जाएं । तथापि बैंकों से यह कहा गया कि चीनी उद्योग को दिये जाने वाले ऋण का अनुचित विस्तार न होने दिया जाए तथा पहले मंजूर की गयी निधियों को जबरदस्ती वापस न लिया जाए । चीनी की पूर्ति सम्बन्धी सन्तोषजनक स्थिति तथा 1978-79 के उत्पादन के सन्दर्भ में बेहतर सम्भावनाओं को देखते हुए चीनी की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिमों के लिए राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को 1 नवम्बर, 1978 को एक नया निदेश जारी किया गया । चीनी के लेवी स्टाकों तथा मुक्त बिक्री के स्टाकों के बीच के काल्पनिक अन्तर को समाप्त कर दिया गया और बैंकों से जमानत के रूप में लिये जाने वाले चीनी के स्टाकों का नियमित वाणिज्यिक सिद्धान्तों के आधार पर मूल्यांकन किया जाना था । अतः मुक्त बिक्री की चीनी पर (चीनी बनाने वाली सहकारी समितियों को) दिये गये अग्रिमों के लिए रखा जाने वाला 65 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन समाप्त हो गया । इन पाटियों को चीनी पर दिये गये अग्रिमों के मामले में

[1] अतिदेयों को छोड़कर

संशोधित न्यूनतम मार्जिन 15 प्रतिशत था । फिर भी चीनी के उत्पादकों से भिन्न चीनी व्यापारियों के मामले में उक्त मार्जिन स्टॉकों और उनसे सम्बन्धित गोदाम रसीदों पर क्रमशः 65 प्रतिशत और 55 प्रतिशत ही रहा । चीनी के उत्पादकों से भिन्न दूसरी पार्टियों को चीनी की जमानत पर दिये गये ऋणों/अग्रिमों/नकदी ऋणों/ओवरड्राफटों पर लगाया गया न्यूनतम ब्याज 15 प्रतिशत ही था । फिर भी, चीनी के उत्पादकों को दिये गये ऋणों के मामले में कोई न्यूनतम दर निश्चित नहीं की गयी थी; ये अग्रिम वार्षिक 12 1/2 प्रतिशत की सामान्य न्यूनतम ब्याज दर पर दिये गये । कच्ची रूई और कपास पर सूती मिलों को राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन तथा ब्याज दर की पहले की शर्तें ही लागू रहीं । फिर भी, 19 अप्रैल, 1979 से रूई के स्टाकों पर दिये गये अग्रिमों पर अपेक्षित न्यूनतम मार्जिन निम्न प्रकार है—चार महीनों की खपत के बराबर के स्टाकों पर दिये गये ऋण के लिए न्यूनतम मार्जिन 25 प्रतिशत तथा उससे अधिक के स्टाकों पर दिये गये ऋणों के लिए मार्जिन 45 प्रतिशत । राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतः गारन्टीकृत अग्रिमों के मामले में 20 प्रतिशत का एक समान मार्जिन लागू किया गया । इससे पहले निर्धारित न्यूनतम मार्जिन 9 सप्ताहों की खपत के बराबर के स्टाकों पर दिये गये ऋणों पर 25 प्रतिशत तथा उससे अधिक के स्टाकों पर दिये गये ऋणों पर 45 प्रतिशत था । निर्माताओं से इतर पार्टियों को रूई और कपास पर दिये गये अग्रिमों के मामले में न्यूनतम मार्जिन (50 प्रतिशत) तथा न्यूनतम ब्याज दर (15 प्रतिशत) में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

3.13 जनवरी, 1979 में शहरी सहकारी बैंकों को एक निदेश जारी किया गया जिसमें चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली संवेदनशील वस्तुओं के क्रय-विक्रय से उत्पन्न मीयादी बिलों पर उनके द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों की स्थिति को स्पष्ट किया गया था । तदनुसार संवेदनशील वस्तुओं पर दिये गये अग्रिमों पर लागू होने वाली शर्तों के अधीन ऐसे ऋण मंजूर करने की अनुमति दी गयी । अलग-अलग ऋणकर्ताओं को मीयादी बिलों पर दिये जाने वाले अग्रिमों की उच्चतम सीमा 25 प्रतिशत के न्यूनतम मार्जिन के साथ एक लाख रुपये (जैसा कि पिछले वर्ष उल्लेखित वस्तुओं पर दिये गये ऋणों के मामले में रखी जाती है) रखी गयी । फिर भी, रूई और कपास की बिक्री से उत्पन्न होने वाले मीयादी बिलों पर दिये जाने वाले ऋणों को छोड़ दिया गया है । माल की आन्तरिक आवाजाही में सहायता करने के उद्देश्य से शहरी सहकारी बैंकों को यह अनुमति भी दी गयी कि वे चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन आने वाली वस्तुओं की आवाजाही के सन्दर्भ में मांग प्रलेखी बिलों की खरीद द्वारा ऋण सुविधाएं दें; किन्तु शर्त यह है कि उन्हें इस बात को सुनिश्चित कर लेना होगा कि इस सुविधा का प्रयोग माल की वास्तविक आवाजाही के लिए किया गया था तथा खरीदे हुए बिलों की वसूली तुरन्त कर ली गयी थी ।

3.14 फसलों के विपणन के लिए दी गयी ऋण सीमाओं में काफी वृद्धि हुई । वर्ष 1977-78 के 15 करोड़ रुपयों से बढ़कर वर्ष 1978-79 में उक्त सीमा 69 करोड़ रुपये हो गयी । 1977-78 में रूई और कपास के विपणन के लिए मंजूर की गयी ऋण सीमा 14 करोड़ रुपये थी । 1978-79 में उक्त सीमा बढ़कर 66 करोड़ रुपयों से अधिक हो गयी । इस वृद्धि का प्रमुख कारण यह था कि महाराष्ट्र सरकार की एकाधिकार रूई क्रय योजना को रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधा (45 करोड़ रुपये) उपलब्ध थी ।

(घ) उर्वरकों का वितरण

3.15 चयनात्मक आधार पर उर्वरकों के वितरण को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामले में उन क्षेत्रों में जहां वाणिज्य बैंक सहायता प्रदान करने में असमर्थ हैं, रिजर्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों के लिए अल्पावधि ऋण सीमाएं मंजूर की । कैलेण्डर वर्ष 1978 के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा तीन राज्य सहकारी बैंकों के लिए मंजूर की गयी कुल ऋण सीमाएं 6 करोड़ रुपये थीं जबकि वर्ष 1977 के दौरान पांच राज्य सहकारी बैंकों के लिए 13 करोड़ रुपये की ऋण सीमायें मंजूर की गयी थीं ।

(ङ) मध्यावधि ऋण

3.16 कैलेण्डर वर्ष 1979 के दौरान रिजर्व बैंक ने कृषि उद्देश्यों तथा ऋण परिवर्तन के उद्देश्यों के लिए दिये गये मध्यावधि ऋणों के लिए पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने की पहले की नीति जारी रखी ।

3.17 अतिदेय राशियों को समाप्त करने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि वर्ष 1979 में पुनर्वित्त सुविधा केवल उन्हीं बैंकों को प्राप्त होगी जिनकी कुल अतिदेय राशियां 1977-78 की कुल 'मांग' के 60 प्रतिशत से कम हैं तथा जिनके लिए 1978-79 के दौरान अल्पावधि ऋण सीमाएं अस्वीकार नहीं की गयी थीं । वर्ष 1978 तक ऐसे बैंक, जिनकी अतिदेय राशियां कुल मांग के 60 प्रतिशत तथा मध्यावधि अग्रिमों के मामले में 50 प्रतिशत से अधिक थीं, रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधा पाने के पात्र नहीं थे । फिर भी लघु कृषक विकास एजेंसी तथा सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के बैंक पुनर्वित्त सुविधा पाने के पात्र थे यद्यपि मध्यावधि ऋणों के सन्दर्भ में उनकी अतिदेय राशियां 'मांग' के 50 प्रतिशत से अधिक हो गयी हों ।

3.18 दुधारू पशु, भेड़, मुर्गी, बैल और बैलगाड़ी आदि खरीदने के लिए दिये जाने वाले ऋणों के पुनर्वित्त के मामले में रिजर्व बैंक की नीति अगस्त, 1978 में संशोधित की गयी ताकि विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाले तथा प्रमुख रूप से कमजोर वर्गों के ऋणकर्ताओं को लाभ पहुंचे । ये संशोधन कम लागत वाले यूनिट के आकार, दी गयी जमानत आदि पर निर्भर करेंगे तथा इनका छोटे से छोटा यूनिट भी मध्यावधि अग्रिम पा सकेगा ।

3.19 कैलेण्डर वर्ष 1978 के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए मंजूर किये गये 28 करोड़ रुपयों के मध्यावधि ऋणों में से 16 करोड़ रुपयों की राशि राज्य सहकारी बैंकों द्वारा निकाली गयी थी । 1977 के दौरान 21 करोड़ रुपयों के मध्यावधि ऋण मंजूर किये गये थे जिनमें से 12 करोड़ रुपयों की राशि निकाली गयी थी ।

परिवर्तन ऋण और शेयर पूंजीगत अभिदान के लिए ऋण

3.20 रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि में से मध्यावधि परिवर्तन ऋण सीमाएं मंजूर करना जारी रखा ताकि राज्य सहकारी बैंक/मध्यवर्ती सहकारी बैंक प्राकृतिक विपत्तियों से ग्रस्त क्षेत्रों के मामले में रिजर्व बैंक को अल्पावधि कृषि ऋण चुका सकें । वर्ष 1977-78 के 98 करोड़ रुपयों के मुकाबले वर्ष 1978-79 में (मई 1979 तक) 37 करोड़ रुपयों की ऋण सीमाएं मंजूर की गयी थीं । कृषि ऋण मण्डल की सिफारिश पर यह निश्चय किया गया है कि राज्य सरकारों को 1978-79 के रबी मौसम तथा उसके बाद जारी किये गये अल्पावधि उत्पादन ऋणों के सन्दर्भ में मंजूर किये गये परिवर्तन ऋणों के 15 प्रतिशत का अपना अंश वहन करना पड़ेगा । इस प्रकार, निधि से दी जाने वाली पुनर्वित्त सहायता ऐसे परिवर्तन ऋणों के केवल 60 प्रतिशत तक ही सीमित होगी । शेष की पूर्ति निम्न प्रकार होगी :

राज्य सरकार—15 प्रतिशत, राज्य सहकारी बैंक—10 प्रतिशत और मध्यवर्ती सहकारी बैंक—15 प्रतिशत

वर्ष 1978-79 के दौरान सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अभिदान करने के लिए राज्य सरकारों को राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घ-कालीन प्रवर्तन) निधि में से 19 करोड़ रुपयों के ऋण मंजूर किये गये । ये ऋण पूर्ण रूप से ले लिये गये । तीन वर्षों से अधिक अवधि तक कार्यरत कृषक सेवा समितियों तथा कमजोर प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के संदर्भ में ऐसे ऋण मंजूर करने से संबंधित शर्तों में वर्ष 1978-79 के लिए छूट दी गयी । कृषक सेवा समितियों के मामले में मंजूरी की यह शर्त थी कि उनकी अतिदेय राशि 1977-78 की मांग राशि के 50

प्रतिशत से अधिक न हो। जहां तक कमजोर प्राथमिक भूमि विकास बैंकों का संबंध है, लघु कृषक विकास एजेन्सी/अभिसूचित क्षेत्रों में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के संदर्भ में विद्यमान शर्तें पुनर्गठन कार्यक्रम के अंतर्गत लाये गये कमजोर प्राथमिक भूमि विकास बैंकों पर भी लागू कर दी गयीं।

ङ. दीर्घावधि ऋण

3.21 सामान्य और विशेष विकास डिबेंचर जारी करने के लिए एक समान नियमावली निर्धारित करने के लिए सितंबर 1975 में रिजर्व बैंक ने डिबेंचर के मानदंडों पर एक स्थायी समिति गठित की थी। उक्त स्थायी समिति ने अग्रिमों को विनियमित करने वाले मानदंडों में कुछ संशोधनों की सिफारिश की जो कि बाद में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा भी अनुमोदित की गयी। संशोधित मानदण्ड जनवरी 1979 में भूमि विकास बैंकों को सूचित किये गये हैं और यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही उनके ऋण देने के कार्यों में वृद्धि होगी। इन मानदंडों द्वारा प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखाएं विशेष विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत अपने छोटे/सीमान्त कृषकों की निवेश ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगी तथा बायदा व्यय की पूरी राशि तक के लिए ऋण वितरित किये जायेंगे। उसी समय वे नये ऋणों की कुछ मात्रा के लिए भी पात्र होंगे। उक्त सुविधा पहले के मानदंडों के अधीन उपलब्ध नहीं थीं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक भूमि विकास बैंक/राज्य भूमि विकास बैंक की शाखा की पात्रता पिछले जून के अंत में उसके अपने वसूली कार्यों पर निर्भर करेगी; लेकिन इसके लिए संशोधित सीमा प्रणाली लागू होगी, जो कि पिछली प्रणाली से काफी अधिक लचीली है। संशोधित और पुराने मानदंड इस प्रकार हैं:

पुराने मानदंड		संशोधित मानदंड	
जून 1978 के अंत में प्राथमिक शाखा स्तर पर अतिदेय राशियों की सीमा	पिछले वर्ष जारी किये गये ऋणों के प्रतिशत या पिछले 3 वर्षों में जारी किये गये ऋणों के औसत—इनमें से जो भी अधिक हो—के रूप में पात्र ऋण कार्यक्रम	सहकारी वर्ष के अंत में पिछले तीन वर्षों की अतिदेय राशियों के औसत के आधार पर प्राथमिक शाखा स्तर की अतिदेय राशियों की सीमा या पिछले वर्ष की अतिदेय राशियां इनमें से जो भी कम हो—	पिछले वर्ष जारी किये गये ऋणों के प्रतिशत या पिछले वर्षों में जारी किये गये ऋणों के औसत—इनमें से जो भी अधिक हो—के रूप में पात्र ऋण कार्यक्रम
0–25	कोई प्रतिबंध नहीं	0–25	कोई प्रतिबंध नहीं
26–35	80	26–30	100
36–45	70	31–35	90
46–55	60	36–40	80
56–60	50	41–45	75
61–100	कुछ नहीं	46–50	70
		51–55	65
		56–100	कुछ नहीं

इसके साथ ही, संशोधित मानदंडों के अंतर्गत प्राथमिक भूमि विकास बैंक/राज्य भूमि विकास बैंक की शाखा की ऋण पात्रता निश्चित करने के लिए अतिदेय राशियों का अंत सहकारी वर्ष के अंत में पिछले तीन वर्षों की अतिदेय राशियों के औसत या पिछले वर्ष की अतिदेय राशियों पर—इनमें से जो भी कम हो—आधारित होगा। संशोधित मानदंडों के अनुसार भूमि विकास बैंक चाहे उनकी पात्रता कुछ भी क्यों न हो, अपने द्वारा स्वीकृत प्यारे व्यय की पूर्ति करेंगे बशर्ते कि वे निर्धारित शर्तों का अनुपालन करें।

प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखाओं द्वारा जारी किये गये

दीर्घावधि ऋण—ब्याज दर

3.22 जुलाई 1978 में भूमि विकास बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे साधारण ऋणों पर निम्न प्रकार ब्याज की दर लगायें (क) लघु सिंचाई तथा भूमि विकास उद्देश्यों के लिए दिये गये अग्रिमों पर अंतिम ऋणकर्ता से वार्षिक 10.5 प्रतिशत से अनधिक (ख) अन्य उद्देश्यों के लिये दिये गये अग्रिमों पर 11 प्रतिशत से अनधिक। साथ ही, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा दी गयी पुनर्वित्त सहायता पर ब्याज की दर में एक प्रतिशत की कटौती होने के कारण भूमि विकास बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे लघु सिंचाई तथा भूमि विकास के लिए अंतिम ऋणकर्ताओं से 9.5 प्रतिशत की दर पर 15 मार्च 1979 से ब्याज वसूल करें। अन्य प्रयोजनों के लिए उक्त दर छोटे किसानों के लिए 9.5 प्रतिशत तथा दूसरों के लिए 10.5 प्रतिशत है।

भूमि विकास बैंक—सामान्य डिबेंचर कार्यक्रम

3.23 1978-79 के वित्तीय वर्ष के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों के ऋण कार्यक्रम की राशि 419 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी (1977-78 में यह राशि 328 करोड़ रुपये थी) जिसमें कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की पुनर्वित्त योजनाओं के लिए 271 करोड़ रुपये तथा साधारण ऋण कार्यक्रमों के लिए 148 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह उम्मीद है कि वर्ष 1978-79 के साधारण ऋण कार्यक्रमों के लिए निर्धारित 148 करोड़ रुपयों में से 23 करोड़ रुपये उनके आंतरिक स्रोतों से तथा शेष 125 करोड़ रुपये सामान्य डिबेंचर जारी करके जुटाये जायेंगे। उपरोक्त कार्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 1979 तक 93 करोड़ रुपयों की कुल राशि के सामान्य डिबेंचर जारी करने के प्रस्तावों को रिजर्व बैंक ने मंजूर किया था; यह राशि कार्यक्रम के कुल 125 करोड़ रुपयों का 74.3 प्रतिशत थी।

3.24 वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों के ऋण कार्यक्रम के लिए अस्थायी रूप से कुल 434 करोड़ रुपयों की राशि निर्धारित की गयी है। यह प्रस्ताव है कि 136 करोड़ रुपयों के परिकल्पित सामान्य ऋण कार्यक्रम के लिए उक्त बैंक अपने आंतरिक स्रोतों से 11 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे तथा 125 करोड़ रुपये सामान्य डिबेंचर जारी कर जुटाये जायेंगे। आशा है कि इस सामान्य डिबेंचर कार्यक्रम में निम्नलिखित एजेंसियों का सहयोग प्राप्त होगा:

	(करोड़ रुपये)
(i) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें	16
(ii) जमा बीमा निगम	38
(iii) वाणिज्य बैंक (भारतीय बैंक संघ के माध्यम से)	10
(iv) भारतीय स्टेट बैंक समूह	7
(v) पारस्परिक सहयोग और निधी सहायता	54
	125

ग्रामीण डिबेंचर जारी करना

3.25 वित्तीय वर्ष 1978-79 के दौरान डिबेंचरों की ब्याज दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया; ऐसे डिबेंचर जारी करने से संबंधित अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। किन्तु उक्त योजना के अधीन किसी भी बैंक ने ग्रामीण डिबेंचर जारी नहीं किये।

कृष्येतर ऋण

औद्योगिक वित्त

सहकारी चीनी कारखानों की कार्यकारी पूंजीगत वित्त

3.26 1977-78 के दौरान रिजर्व बैंक ने सहकारी चीनी मिलों की कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के निमित्त कुल 8 करोड़ रुपयों की अल्पावधि ऋण सीमाएं मंजूर की थीं। वर्ष 1978-79 में मई 1979 तक 6 करोड़ रुपयों की ऋण सीमा मंजूर की गयी।

बुनकर समितियों के लिए वित्त

3.27 वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए ऋण सीमा संबंधी आवेदन पत्रों में दी गयी समेकित जानकारी और आलोच्य वर्ष के ऋण कार्यक्रमों की संभाव्यता के आधार पर बुनकर समितियों के वित्तपोषक के लिए रिजर्व बैंक द्वारा मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को ऋण सीमाएँ मंजूर की गयी। यह सुविधा उचित पर्यवेक्षण व्यवस्थाओं वाले मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और सक्षम प्राथमिक समितियों तक ही सीमित रही। इस प्रकार, मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के प्रति 60 प्रतिशत से अधिक अतिदेय राशियुक्त समितियां, लेखा परीक्षा के अंतर्गत श्रेणी 'घ' में रखी गयी समितियां या ऐसी समितियां जिनकी तीन साल से अधिक समय से लेखा परीक्षा नहीं हुई है और ऐसी समितियां जिनके खाते मध्यवर्ती सहकारी बैंक के पास निष्क्रिय पड़े रहे हैं, उक्त ऋण सीमाओं की पात्र नहीं थीं।

3.28 वर्ष 1977-78 के दौरान हथकरघा वस्तुओं के उत्पादन और विपणन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर की गयी 44 करोड़ रुपयों की ऋण सीमा के मुकाबले 1978-79 के दौरान 51 करोड़ रुपयों की उच्चतर सीमा मंजूर की गयी। 31 मार्च 1979 को अग्रिमों की बकाया राशि 16 करोड़ रुपये थी जबकि 31 मार्च 1978 को वह 24 करोड़ रुपये थी।

अन्य कुटीर और लघु उद्योगों का वित्तपोषण

3.29 वर्ष 1978-79 के लिए 31 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और 33 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों की ओर से 8 राज्य सहकारी बैंकों को 6 करोड़ रुपयों की ऋण सीमाएँ मंजूर की गयीं जबकि 1977-78 के दौरान 7 करोड़ रुपयों की ऋण सीमाएँ मंजूर की गयीं थीं।

स्वर्ण बुलियन, सोने और चांदी के आभूषणों की जमानत पर सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिम

3.30 रिजर्व बैंक द्वारा की गयी स्वर्ण नीलामियों के परिप्रेक्ष्य में सोने के आभूषणों पर सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिम देने की नीति का और अध्ययन किया गया। 22 जुलाई 1978 को सहकारी समितियों के पंजीयकों से यह कहा गया कि वे मध्यवर्ती और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को उचित अनुदेश जारी करें जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वर्ण बुलियन पर कोई अग्रिम प्रदान नहीं किये गये हैं तथा स्वर्ण बुलियन पर दिये गये बकाया अग्रिमों, यदि कोई हों, को यथाशीघ्र, किन्तु 30 सितम्बर 1978 के पहले वसूल कर लिया जाएगा। सोने के आभूषणों पर दिये गये अग्रिमों के मामले में बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि ऐसे अग्रिम सट्टेबाजी के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त नहीं किये जाते।

सहकारी संगठन को मजबूत बनाना

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का पुनर्गठन

3.31 सहकारी ऋण के विस्तार के लिए पूर्व अपेक्षा के रूप में ऋण वितरण के आधार स्तर पर मजबूत और सक्षम संस्थाओं की आवश्यकता को काफ़ी अच्छी तरह समझ लिया गया है। समितियों के समामेलन की क्रियाविधि को व्यवस्थित बनाने के फलस्वरूप और साथ ही भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के पुनर्गठन के कार्य को तेज करने के लिए अनुरोध किये जाने के परिणामस्वरूप कई राज्यों में कार्यक्षमता के आधार पर समितियों के पुनर्गठन की दिशा में काफी प्रगति हुई है।

3.32 आशा है कि देश में समितियों की कुल संख्या 1976-77 के अंत में 1,24,000 से घटकर पुनर्गठन का कार्य पूरा होने पर 90,000 हो जाएगी। आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को कार्यक्षम बनाने के लिए उनका पुनर्गठन कार्य लगभग पूरा हो गया है। अन्य राज्यों में पुनर्गठन की दिशा में प्रयास जारी हैं। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी कुछ राज्य पहले ही सहमत पद्धति पर कार्यक्रम को पूरा करने की दिशा में केवल विचार कर रहे हैं।

मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों की पुनर्व्यवस्था

3.33 इस वर्ष कुछ मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों की पुनर्व्यवस्था करने के प्रयास जारी रहे। पुनर्व्यवस्था के अंतर्गत आनेवाले 180 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से 146 बैंकों को केन्द्रीय क्षेत्र योजना कार्यक्रम के अधीन लाया गया। भारत सरकार ने अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिए अपने अंश के रूप में 842 लाख रुपये मंजूर किये और 775 लाख रुपये जारी किये। यद्यपि इन बैंकों में से अधिकांश बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार पाया गया है तथापि कुछ और समय के लिए उन पर निगरानी रखी जाएगी। सहकारिता के दो स्तरों के वित्यास वाले राज्यों में पांच राज्य सहकारी बैंकों को पुनर्व्यवस्था के अधीन रखा गया। 30 जून 1977 को 54 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर पुनर्व्यवस्था कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया।

सहकारी ऋण संस्थाओं का समेकन

3.34 तीन राज्य सरकारों अर्थात् पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने सहकारी ऋण वित्यास के दो पक्षों (अल्पावधि/मध्यावधि और दीर्घावधि) के समेकन के लिए स्वयं कार्यवाई प्रारंभ कर दी है। पंजाब और राजस्थान राज्यों का जिला स्तरीय संस्थाओं अर्थात् अल्पावधि ऋण के पक्ष में मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और दीर्घावधि ऋण के पक्ष में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को समाप्त करने का प्रस्ताव है और प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और जिला स्तर पर राज्य सहकारी विकास बैंकों की शाखाओं सहित शिखर स्तर पर राज्य सहकारी विकास बैंकों के पुनर्गठन के साथ एक द्वि-स्तरीय वित्यास स्थापित करने की इन राज्यों की परिकल्पना है। पंजाब के मामले में कृषि ऋण मंडल का यह विचार था कि इस विषय पर विचार करने से पहले अतिरिक्त विवरण प्राप्त करना जरूरी है और राजस्थान के मामले में प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जा रहा था। मध्य प्रदेश के मामले में योजना में द्विस्तरीय वित्यास के विभिन्न स्तरों पर दो स्तरों के मात्र समेकन की परिकल्पना की गयी है। उक्त मंडल ने इस प्रस्ताव का सामान्यतः समर्थन नहीं किया है। उसने यह राय दी है कि राज्य सरकार को इस मामले में बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। किन्तु यदि राज्य सरकार उक्त समेकन प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए बहुत उत्सुक है तो उसे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऋण की उपलब्धता में बाधा नहीं आती और उसे कुछ निर्दिष्ट शर्तों का पालन करना होगा जिसमें वित्तीय और प्रशासनिक बायदे शामिल हैं।

कृषि ऋण सघन विकास

3.35 कृषि ऋण सघन विकास कार्यक्रम को 41 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा था। उसकी प्रगति जारी रही। आलोच्य वर्ष के दौरान नौ और जिलों में ऋण योजनाएं और कार्रवाई संबंधी कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से क्षेत्र अध्ययन पूरे किये गये; इससे जिन जिलों में ऐसे अध्ययन चलाये गये उनकी संख्या बढ़कर कृषि ऋण सघन विकास योजना के अंतर्गत चुने हुए 41 जिलों में से 32 जिले हो गयी। इसके अलावा सात जिलों के लिए ऋण और कार्रवाई संबंधी कार्यक्रम निर्धारित किये गये; इससे जिन जिलों में ऐसे कार्यक्रम निर्धारित करने का कार्यक्रम पूरा किया गया था उनकी संख्या बढ़कर 25 हो गयी।

3.36 कृषि ऋण सघन विकास योजना की प्रमुख उपलब्धियों में से एक थी विकास योजनाएं बनाने तथा उनके कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न एजेंसियों और जिले में कार्यरत ऋण संस्थाओं के बीच क्रियाशील समन्वय लाना। उक्त योजना के अंतर्गत कुछ जिलों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के पुनर्गठन, नये सदस्य बनाने और कृषि तथा संबंधित

कार्यों के वित्तपोषण के लिए ऋण उपलब्ध कराने जैसे क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हुई। पहली अप्रैल 1977 से 31 मार्च 1978 तक छः और जिलों में पुनर्गठन से संबंधित कार्य पूरा किया गया; इस प्रकार जिन जिलों में पुनर्गठन-कार्य पूरा किया गया उनकी संख्या बढ़कर 24 हो गयी। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में विशेष रूप से कई लघु और सीमांत कृषक सदस्य हुए। चुने गये 41 जिलों में से 37 जिलों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की कुल सदस्य संख्या में लगभग 7 लाख की वृद्धि हुई। पर्याप्त मात्रा में समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने और ऋण के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के स्तर पर ऋण की प्राप्ति को प्रभावित करने वाली ऋण नीतियों और क्रियाविधियों में सुधार किया गया। अधिकाधिक ऋण प्रदान करने का लाभ अन्यों की तुलना में लघु और सीमांत कृषकों को अधिक पहुँचा है।

3.37 कृषि ऋण सघन विकास योजना के प्रारंभ से अब तक की गतिविधियों में से कुछ गतिविधियों के कारण योजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता है। अग्रणी बैंकों से यह कहा गया है कि दिसम्बर 1979 तक वे अपनी वर्तमान ऋण योजनाओं को समाप्त कर दें और जनवरी 1980 से दिसम्बर 1982 तक की अवधि के लिए अपने अग्रणी जिलों के निमित्त नयी जिला ऋण योजनाएं और हर वर्ष दिसम्बर में वार्षिक कार्यवाई योजना बनाये। जिला ऋण योजना जिले के लिए एक व्यापक ऋण योजना होगी और उसमें बैंकों द्वारा उत्पादन के वित्तपोषण और निवेशों के लिए तकनीकी रूप से सक्षम और आर्थिक संभाव्यतायुक्त योजनाओं के क्षेत्रवार, खंडवार, योजनावार तथा संस्थावार कुल ऋण परिव्यय की राशियां दर्शायी जाएंगी। अन्य वित्तीय संस्थाओं में से सहकारी संस्थायें भी योजनायें बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने में सहयोग देनेवाली एजेंसियां हैं। इन गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में यह निश्चय किया गया है कि कृषि ऋण सघन विकास कार्यक्रम को 1980 के बाद जिला ऋण योजना से कारगर ढंग से संबद्ध कर दिया जाए।

दूसरी गतिविधियां

ऋण प्राधिकरण योजना

3.38 सहकारी ब्याज दर विन्यास से संबंधित अध्ययन दल द्वारा की गयी सिफ़ारिशों के अनुसरण में प्राथमिक समितियों को दिये गये अग्रिमों के संदर्भ में कुछ संशोधनों की घोषणा की गयी। निर्माण/अभिसंस्करण समितियों तथा उभोक्ता समितियों को दिये जाने वाले निम्नलिखित अग्रिमों के मामले में रिज़र्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण की अपेक्षा करने वाले योजना के उपबंध 1978-79 के दौरान जारी रहे:

(1) नयी चीनी मिलों के मामले में थोक पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए अग्रिम प्रदान करने के सभी मामले;

(2) निर्माण/अभिसंस्करण यूनिटों के मामले में 25 लाख रुपयों से अधिक थोक पूंजीगत आवश्यकताओं का वित्त पोषण;

(3) सहकारी विपणन/अभिसंस्करण समितियों और उपभोक्ता भंडारों/समितियों को सहकारी बैंकों के मामले में 2 करोड़ रुपये और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मामले में 1 करोड़ रुपये से अधिक कार्यकारी पूंजी प्रदान करना।

साथ ही, राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किये बिना सहकारी विपणन एवं अभिसंस्करण समितियों को कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए उच्चतर निर्बंध ऋण सीमाएं मंजूर करने की भी अनुमति दी गयी। संशोधित सीमा 10 लाख रुपये या संबंधित समिति की स्वाधिकृत निधियां, इनमें से जो भी कम हो, है, जबकि पहले यह सीमा 5 लाख रुपये थी। जून 1979 में समाप्त वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा थोक पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए 11 करोड़ रुपयों और कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए 585 करोड़ रुपयों का प्राधिकरण दिया गया। उक्त पूंजी से संबंधित प्रस्तावों की संख्या क्रमशः 26 और 148 थी।

3.39 16 अगस्त 1978 से चीनी पर से नियंत्रण हटा लिये जाने के बाद और स्टाकों के काफ़ी अधिक जमा हो जाने से चीनी के मूल्यों में आयी गिरावट के फलस्वरूप सहकारी चीनी मिलों की चलनिधि संबंधी स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा और इससे वे अपने द्वारा लिये गये बंधक ऋणों के संदर्भ में निर्धारित मार्जिन को बनाये रखने में असमर्थ रहीं। मार्जिन के घाटे को पूरा करने के लिए सहकारी चीनी मिलों को कार्यकारी पूंजीगत मीयादी ऋण मंजूर करने के निमित्त रिज़र्व बैंक के पूर्व प्राधिकरण के संबंध में जनवरी 1979 में राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था। उक्त प्रयोजन के लिए 3 राज्य सहकारी बैंकों और 11 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को 48 सहकारी चीनी मिलों के लिए 21 करोड़ रुपयों के कार्यकारी पूंजीगत मीयादी ऋण प्रदान करने का प्राधिकरण दिया गया।

वाणिज्य बैंकों द्वारा समितियों का वित्तपोषण

3.40 वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के वित्तपोषण की योजना जून 1970 में शुरू की गयी थी। 31 दिसम्बर 1978 को 12 राज्यों में उक्त योजना अमल में थी जहां 24 वाणिज्य बैंकों की 623 शाखाओं ने 122 जिलों की 2,894 समितियों को अपने हाथ में लिया। प्रति शाखा समितियों की औसत संख्या लगभग 5 थी जबकि कार्यगत संभाव्यता और क्षमता के लिए दस समितियों का मानदंड निर्धारित था। 1977–78 के दौरान वाणिज्य बैंकों ने कुल 22 करोड़ रुपयों के अल्पावधि कृषि ऋण प्रदान कर 2,170 समितियों का वित्तपोषण किया। इसके अलावा 556 समितियों को 3 करोड़ रुपयों के मध्यावधि ऋण भी आबंटित किये गये जबकि 1976–77 में 646 समितियों को 3 करोड़ रुपये दिये गये थे। 31 दिसम्बर, 1978 को प्रति समिति औसत ऋण कारोबार की राशि सक्षमता के औसत मानदंड तक पहुंच गयी थी जो कि एक समिति के लिए 2 लाख रुपये परिकल्पित थी। 31 दिसम्बर, 1978 का कुल बकाया (अल्पावधि और मध्यावधि) ऋणों की राशि 47 करोड़ रुपये थी, इसमें से 29 करोड़ रुपयों की राशि (62 प्रतिशत) अतिदेय थी। वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को दिये गये ऋणों के 65 प्रतिशत अंश की 1977–78 में वसूली की गयी जबकि 1976–77 में 44 प्रतिशत राशि वसूल की गयी थी। योजना के प्रारम्भ से दिसम्बर 1978 तक वाणिज्य बैंकों द्वारा भी गयी समितियों में 405 हजार नये सदस्य शामिल किये गये। ऋण लेने वाले सदस्यों की संख्या 31 दिसम्बर, 1977 के 432 हजार से बढ़कर 549 हजार हो गयी और 31 दिसम्बर 1978 को कुल सदस्य संख्या में उनका अंश 37 प्रतिशत था।

3.41 ऊपर उल्लिखित योजना की धीमी प्रगति को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने योजना की समीक्षा के लिए एक दल गठित किया है जो उसकी प्रगति में बाधक तत्वों का पता लगाएगा और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएगा।

दंडस्वरूप ब्याज दर

3.42 धारा 17 (4) (ग) के साथ पठित धारा 17 (2) (ख) के अधीन (1 मार्च 1978 से) अग्रिमों पर दिये जाने वाले पुनर्वित्त की दर में 1 प्रतिशत की कमी किये जाने के फलस्वरूप रिज़र्व बैंक ने नियत तारीखों पर ऋण/ऋण की किस्तों की चुकौती करने में चूक करने वाले राज्य सहकारी बैंकों से वसूल की जाने वाली दंडस्वरूप ब्याज दर का पुनरीक्षण किया। इस प्रकार 11 जुलाई 1978 से ऋण की समग्र अवधि के लिए इन बैंकों से बैंक दर पर ब्याज वसूल किया जाता है जबकि पहले चूक की अवधि के लिए, सामान्य ब्याज दर से 1 प्रतिशत अधिक ब्याज वसूल किया जाता था।

जमाराशियों पर दिये जाने वाले अग्रिमों से संबंधित ब्याज दर

3.43 फरवरी 1979 में रिज़र्व बैंक ने सभी राज्य, मध्यवर्ती और प्राथमिक सहकारी बैंकों को यह सूचित किया गया कि जब किसी

जमा रकम को समय से पहले निकालने पर जमाकर्ता का देय ब्याज में कमी की जाती है तब उन पर दिये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में लिये जाने वाले ब्याज को इस प्रकार तय किया जाना चाहिए कि उन दोनों ब्याज दरों के बीच 2 प्रतिशत का अंतर बना रहे।

बैंककारी विनियमन और निरीक्षण

3.44 30 जून, 1978 को लाइसेंस प्राप्त सहकारी बैंकों की कुल संख्या 130 थी और 31 मार्च 1979 को वह बढ़कर 148 हो गयी। 18 बैंकों की यह वृद्धि केवल प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (109 में से 127) के संदर्भ में हुई, राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या क्रमशः 7 और 14 ही बनी रही।

3.45 सहकारी बैंकों के कार्यालयों की जो संख्या 31 दिसम्बर, 1977 को 8309 थी वह 31 दिसम्बर, 1978 को बढ़कर 8894 हो गयी। इसमें राज्य सहकारी बैंकों के 363, मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के 6,659 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के 1,675 और प्राथमिक (वेतन भोगी) सहकारी बैंकों के 197 कार्यालय शामिल हैं। वर्ष 1978-79 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी बैंकों को नये कार्यालय खोलने के लिए 98 लाइसेंस जारी किये गये जबकि 1977-78 में 131 लाइसेंस जारी किये गये थे।

3.46 30 जून, 1979 को बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत आनेवाले 1,568 सहकारी बैंक थे जिनमें 29 राज्य, 347 मध्यवर्ती और 1,192 प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल है जबकि 30 जून 1978 को सहकारी बैंकों की संख्या 1,568 थी।

3.47 6 जून, 1978 की अधिसूचना के अनुसार रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को 24 जून 1978 से और दो वर्षों की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप धारा (1) के उपबंधों से उस सीमा तक छूट दी है जहां तक उक्त उपबंधों के अनुसार अनुसूचित बैंकों से उनकी अपनी कुल मांग और मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत से अधिक राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास औसत दैनिक शेष के रूप में बनाये रखना अपेक्षित है।

3.48 इस वर्ष के दौरान भी रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों का निरीक्षण करता रहा और निरीक्षणों के दौरान पायी गयी महत्वपूर्ण त्रुटियों से उन्हें अवगत कराता रहा। आलोच्य वर्ष के दौरान जिन बैंकों का निरीक्षण किया गया उनमें 413 प्राथमिक सहकारी बैंक, 136 मध्यवर्ती सहकारी बैंक, 11 राज्य सहकारी बैंक और 8 दूसरी संस्थाएं थी।

3.49 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों की एक संशोधित नियम पुस्तक 'मेन्युअल आंन एडवांसेस बाय को-आपरेटिव बैंक्स' मार्च 1978 में जारी की गयी।

अध्ययन दल

जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश

3.50 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में और जम्मू और कश्मीर के लिए कृषि ऋण संस्थाओं से संबंधित अध्ययन दल की जिस रिपोर्ट का उल्लेख किया गया था उसे अन्तिम रूप दिया गया है और हिमाचल प्रदेश से संबंधित अध्ययन दल की रिपोर्ट का कार्य समाप्ति के चरण में है।

हथकरघा वित्त पर अध्ययन दल

(भारत सरकार द्वारा नियुक्त)

3.51 इस दल ने जून 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उसकी कतिपय महत्वपूर्ण सिफारिशें नीचे दी जाती है :—

(1) विपणन और उत्पादन के कार्यों के लिए ऋण सीमाएं मंजूर करते समय रिजर्व बैंक शिखर बुनकर समितियों की निर्यात संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखे।

(2) यदि भारी बकाया राशियों के कारण कृषि उत्पादन के लिए अल्पावधि ऋण सीमाएं स्वीकार करने से इन्कार किया जाता है तो भी बुनकर समितियों के उत्पादन और विपणन कार्यों के वित्तपोषण के लिए मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को ऋण मंजूर किए जा सकते हैं।

(3) रिजर्व बैंक सहकारी कताई मिलों की ओर से हथकरघा बुनकर समितियों के लिए धारा 17(4)(ग) के साथ पठित धारा 17(2)(खख) के अधीन ऋण व्यवस्था कर सकता है।

(4) केन्द्रीय/राज्य सरकारों की सहायता की शर्त पर रिजर्व बैंक बुनकर और हथकरघा बुनकर समितियों को सहकारी कताई मिलों के शेयर प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक मध्यावधि ऋण प्रदान कर सकता है।

(5) बुनकर समितियों के मामले में प्रति करघा वित्त के मान की तीन वर्ष में एक बार समीक्षा की जाए और उसमें परिवर्तन किया जाए। इसी प्रकार शिखर बुनकर समितियों के मामले में बिक्री में कार्यकारी पूंजी के अनुपात का अध्ययन भी किया जाए ताकि कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं के वित्तपोषण के मानदंडों में संशोधन किया जा सके। बैंक ने इन सिफारिशों का अध्ययन कर इस वर्ष आवश्यक कार्यवाई शुरू की।

शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित समिति

3.52 इस समिति ने सितम्बर 1978 में रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट पेश की। कृषि ऋण विभाग ने इस रिपोर्ट का अध्ययन पूरा कर लिया है और आवश्यक कार्यवाही भी शुरू कर दी है।

सहकारी बैंकों के ब्याज दर विन्यास पर अध्ययन दल

3.53 इस दल ने जून 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की और उसमें कई सिफारिशें भी की, जिनमें निम्नलिखित शामिल थीं : (1) सहकारी बैंकों द्वारा लघु कृषकों के दिये जाने वाले अग्रिमों पर जो ब्याज लिया जाता है उसकी दरों में कमी की जाए, (2) मध्यावधि कृषि प्रयोजनों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा दिये जानेवाले पुनर्वित्त की ब्याज दर में जो रियायत की जाती है उसमें ½ प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसे अल्पावधि कृषि ऋण के पुनर्वित्त की ब्याज दर के बराबर लाया जा सके, (3) अल्पावधि कृषि ऋणों की पुनर्वित्त सुविधाओं के सम्बन्ध में जो अनुशासन निर्धारित किया गया है उसके पालन का रिजर्व बैंक अध्ययन करे ताकि यह सुनिश्चित हो कि ऐसे अनुशासन से सुविधाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता। उक्त अनुशासन में अवधिकता का पालन, लघु कृषकों को ऋण प्रदान करना आदि शामिल है, और (4) सहकारी बैंकों/वाणिज्य बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि ऋणों पर अंतिम ऋणकर्ताओं से ली जाने वाली ब्याज दरों में एकरूपता लायी जाए। सहकारी बैंकों के संदर्भ में इन सिफारिशों को रिजर्व बैंक ने स्वीकार कर लिया है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों और सहकारी बैंकों को सूचित किया है।

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण

व्यवस्था के संबंध में समिति

3.54 रिजर्व बैंक ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की वर्तमान व्यवस्थाओं में सुधारों के संबंध में सुझाव देने के लिए मार्च 1979 के अन्त में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। अन्य बातों के साथ-साथ समिति से यह भी कहा गया है कि वह (1) कृषि और संबंधित प्रयोजनों के लिए मीयादी ऋण की बढ़ती हुई मांग के परिप्रेक्ष्य में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के स्वरूप और कार्यकलापों की समीक्षा करे (2) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की तीव्रता के संदर्भ में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्रामीण स्तरों पर अल्पावधि और मध्यावधि ऋण विन्यास को दीर्घावधि ऋण विन्यास के साथ समन्वित करने की आवश्यकता और संभाव्यता का अध्ययन करे, (3) सहकारी वित्तपोषक

संस्थाओं के तीन स्तरोंवाले और दो-स्तरोंवाले तंत्र की सापेक्ष गुणवत्ता का मूल्यांकन करे और उनमें आवश्यक सुधारों के सुझाव दें, (4) कृषि वित्त निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी परामर्श सेवाओं का अध्ययन करे और उनमें आवश्यक सुधारों के लिए सुझाव दे तथा (5) ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में रिजर्व बैंक की भूमिका का अध्ययन करे।

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम

3.55 कृषि के लिए शिखर विकास बैंक के रूप में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (कृपुवि निगम) विभिन्न राज्यों में कृषि तथा संबंधित कार्यों में निवेशों को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है तथा इस बात पर जोर दे रहा है कि कमजोर वर्गों की सहायता की जाए और साधन स्रोतों के विकास के संबंध में विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलनों को कम किया जाए। विश्व बैंक की सहायता प्राप्त कृषि विकास कार्यक्रमों के संदर्भ में निगम ने 1974 से अपने कार्यों के स्तर को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये है। निगम की स्थापना से जून, 1979 के अंत तक कृपुवि निगम द्वारा मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या कुल 8,655 थी जिनमें निगम द्वारा किये गये कुल 2,303 करोड़ रुपयों के वायदे शामिल हैं। उक्त राशि में से 1,334 करोड़ रुपये या 58 प्रतिशत की राशि पुनर्वित्त सहायता के रूप में वितरित की गयी।

3.56 आलोच्य वर्ष के दौरान (जुलाई 1978—जून, 1979) कृपुवि निगम द्वारा मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या तथा उसके वायदों की राशि क्रमशः 2505 और 573 करोड़ रुपये थी जबकि 1977-78 (जुलाई, -जून) के दौरान उक्त आंकड़े 1836 तथा 330 करोड़ रुपये थे। निगम ने हमेशा की तरह इस बार भी ऋणों के व्यापक भौगोलिक विस्तार तथा उद्देश्यों की विविधता पर जोर दिया। लघु सिंचाई को छोड़कर दूसरे उद्देश्यों के लिए 226 करोड़ रुपयों (कुल वायदों का 40 प्रतिशत) के वायदों सहित कुल 1470 योजनाएं (कुल संख्या का 59 प्रतिशत) मंजूर की गयीं। पिछले वर्षों के दौरान लघु सिंचाई के लिए दिये जाने वाले ऋणों का अंश सर्वाधिक रहता था। 1978-79 के दौरान 285 करोड़ रुपयों के कुल वितरणों में से भूमि विकास बैंकों, वाणिज्य बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों द्वारा ली गयी राशियां क्रमशः 131 करोड़ रुपये (36 प्रतिशत), 150 करोड़ रुपये (53 प्रतिशत) तथा 4 करोड़ रुपये (1 प्रतिशत) हैं। पिछले वर्ष (जुलाई–जून) से संबंधित अनुपात क्रमशः 47.8 प्रतिशत, 51.3 प्रतिशत और 0.9 प्रतिशत थे।

3.57 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने कृषि के विकास में क्षेत्रों के भीतर और विभिन्न क्षेत्रों के बीच विद्यमान असमानताओं को कम करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा। निगम ने कम विकसित/बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, में अधिक ऋण उपलब्ध कराकर उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। जम्मू और काश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता द्वारा सेब अभिसंस्करण और विपणन की योजना मंजूर की गयी है। राजस्थान में कृपुवि निगम ने 'अन्त्योदय' कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुपालन तथा अन्य योजनाओं में निवेश की परिकल्पना करते हुए एक योजना मंजूर की है जिससे गांवों में रहने वाले निर्धनतम परिवार लाभान्वित होंगे। उड़ीसा और राजस्थान के लिए अध्ययन दलों का गठन किया गया है जो चालू योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का पुनरीक्षण करेंगे तथा योजनाओं को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों का सुझाव देंगे। भूमि विकास, बागान फसलों आदि की बैंक सहायता के लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार करने में मणिपुर सरकार का मार्गदर्शन देने के लिए निगम के तकनीकी अधिकारियों के एक दल ने नवम्बर 1978 में मणिपुर का दौरा किया। निगम के पुनर्वित्त का 28.2 प्रतिशत अंश दक्षिणी क्षेत्र को मिला और उसके बाद मध्यवर्ती क्षेत्र (23.0 प्रतिशत), उत्तरी क्षेत्र (19.0 प्रतिशत), पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (15.7 प्रतिशत), तथा पश्चिमी क्षेत्र (14.1 प्रतिशत) का स्थान था। पिछले वर्ष क्षेत्रों के अनुपात क्रमशः निम्नप्रकार थे: 27.5 प्रतिशत, 25.5 प्रतिशत, 15.6 प्रतिशत, 17.1 प्रतिशत और 14.3 प्रतिशत।

3.58 निगम ने अपनी योजनाओं के अंतर्गत अधिकाधिक लघु कृषकों को लाभ पहुंचाने के अपने प्रयासों को इस वर्ष चालू रखा। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता के साथ निगम की जो ऋण परियोजनाएं I और II कार्यान्वित की जा रही थीं उनके अन्तर्गत निधियों का 50 प्रतिशत से अधिक अंश लघु कृषकों की निवेश संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के काम में लाया गया है। निगम लघु कृषक विकास एजेंसी के तत्वाधान में और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत प्रायोजित योजनाओं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित के लिए बनायी गयी विशेष योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता रहा। यह सुविधा पहले 31 मार्च, 1979 तक उपलब्ध थी परंतु अब उसे अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया है। जून, 1979 के अंत तक लघु कृषक विकास एजेंसी के लिए 534 योजनाओं को मंजूरी दी गयी जिनमें कुल वायदे की राशि 90 करोड़ रुपये थी। उक्त राशि में से जून, 1979 के अंत तक वित्तपोषक संस्थाओं ने 47 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त प्राप्त किया।

3.59 इस वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने जुलाई, 1979 में 2500 लाख डालरों की पंजाब सिंचाई परियोजना और तृतीय कृपुवि निगम ऋण परियोजना को मंजूरी दी। इसके अलावा उक्त संघ के मिशन ने दो परियोजनाओं का मूल्यांकन किया; उनमें से एक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा में काजू के बागान के विकास से संबंधित थी और दूसरी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के आंतरिक क्षेत्रों में मत्स्यपालन के विकास की परियोजना थी। अब तक 1,765 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायतायुक्त सैंतीस परियोजनाओं को, जिनमें तृतीय कृपुवि निगम ऋण परियोजना शामिल है, विश्व बैंक (4 परियोजनाएं) और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (33 परियोजनाएं) ने अनुमोदित किया है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 11,660 लाख डालर का ऋण निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

3.60 विश्व बैंक समूह द्वारा जिन विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया था उनमें निगम के सफल योगदान को देखते हुए अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी निगम को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हो गयी हैं। इस वर्ष के दौरान कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 150 लाख कैनेडियन डालरों का ऋण मंजूर किया। यूनाइटेड किंगडम के स्थानीय व्यय अनुदान, 1979 के अंतर्गत 150 लाख पौंड का ऋण मंजूर किया गया है।

3.61 इस वर्ष के दौरान कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने कृषि के काम आनेवाले पंपसेटों के विद्युतीकरण के लिए राज्य बिजली बोर्डों को उपलब्ध करायी जानेवाली पुनर्वित्त सहायता की मात्रा को उदार बनाया। यह केवल बोरिंग पंपों के लिए दिये जाने वाले ऋणों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए भी सहमत हुआ। लेकिन यह उन संदर्भों में लागू होगा जहां बोरिंग पम्प लगाना तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त होगा और साथ ही जहां किराये पर लिये गये पंप सेटों की सहायता से बोरिंग का काम किया जा सकता है। मात्र प्रतिशत ऋण की वसूली करने में राज्य भूमि विकास बैंकों को होनेवाली कठिनाइयों को देखते हुए निगम ने उन बैंकों को 1 जुलाई, 1978 से विकास डिबेंचर जारी करने की अनुमति देने का निश्चय किया। इन डिबेंचरों की अवधि अंतिम ऋणकर्ताओं को दिये गए तदनुरूप ऋणों की अवधि के अतिरिक्त 2 वर्षों से अधिक नहीं होगी; इस संबंध में कुछ और शर्तें भी निर्धारित की गयीं। राज्य भूमि विकास बैंकों के ऋण कार्यक्रमों को विनियमित करने के लिए रिजर्व बैंक तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा लागू किये गये नियमित मानदंडों में जनवरी 1979 में ढील दी गयी ताकि ऐसे प्राथमिक भूमि विकास बैंक/शाखाएं जिनकी काफी अधिक समय से बकाया रहने वाली राशियां 'मांग' राशि के 26 प्रतिशत और 55 प्रतिशत के बीच में हैं, अधिकाधिक ऋण के लिए पात्र हों।

3.62 मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या में काफी अधिक वृद्धि और अपने कार्यों के संभावित विस्तार को देखते हुए निगम ने प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधकों और वरिष्ठ निदेशकों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी निदेशकों को कुछ ऐसी विशिष्ट योजनाओं के लिए मंजूरी प्रदान करने की शक्ति दी है जिनमें 10 लाख रुपये और 40 लाख रुपयों के बीच पुनर्वित्त सहायता देनी होती है।

3.63 चालू वर्ष में पांच वर्षों तक निगम को कंपनी कर अदा करने में छूट दी गयी और भारत सरकार ने कृषि निगम की प्रदत्त ऋणों की ब्याज दरों में 0.5 प्रतिशत का कटौती करने का निश्चय किया। अतः निगम ने 15 मार्च, 1979 से लघु सिंचाई और भूमि विकास योजनाओं के लिए पुनर्वित्त की ब्याज दर को वार्षिक 7.5 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत और दूसरे विभिन्न प्रयोजनों की योजनाओं के लिए वार्षिक 8.0 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है। अंतिम ऋणकर्ता से लिए जाने वाले ब्याज की दरें उक्त संदर्भों में क्रमशः 9.5 प्रतिशत और 10.5 प्रतिशत होंगी। तरह-तरह के कार्यों के लिए लघु कृषकों को दिये जाने वाले ऋणों से संबंधित पुनर्वित्त की ब्याज दरों को घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया है किन्तु शर्त यह है कि वित्तपोषक बैंक लघु कृषकों को पहले की 11 प्रतिशत की ब्याज दर के बदले 9.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण प्रदान करें।

3.64 राज्य भूमि विकास बैंकों को लघु सिंचाई योजनाओं के लिए उनके विशेष विकास डिबेंचरों में अंशदान के रूप में 90 प्रतिशत पुनर्वित्त की सुविधा पहले 30 जून, 1979 तक ही उपलब्ध थी; परंतु अब उसे न केवल राज्य भूमि विकास बैंकों के लिए, बल्कि वाणिज्य बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी लघु सिंचाई निवेशों के संदर्भ में तथा उनके द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की योजनाओं के अंतर्गत कृषि के पंपसेटों को बिजली चालित करने के लिए दिये गये ऋणों के संदर्भ में भी अनिश्चित अवधि के लिए लागू कर दिया गया।

3.65 राज्य सरकारों द्वारा स्थापना से 1 प्रतिशत का बाजार शुल्क वसूल करने में अनुभव की गयी कठिनाइयों को देखते हुए निगम ने यह स्वीकार किया है कि कम से कम आधे प्रतिशत के बाजार शुल्क के साथ मंडी क्षेत्रों के विकास से संबंधित योजनाओं के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की जाएं बशर्ते कि संबंधित अधिनियम में बाद के दो अथवा तीन वर्षों की अवधि के भीतर उक्त शुल्क को बढ़ाकर एक प्रतिशत कर देने की व्यवस्था की जाए।

अध्याय 4

अन्य विशिष्ट संस्थाएं

4.1 इस अध्याय में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक की गतिविधियों और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भाऔवि बैंक), राज्य वित्तीय निगमों (राविनिगम), निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसी अन्य वित्तीय संस्थाओं का पुनरीक्षण किया गया है। इस पुनरीक्षण से यह विदित होता है कि औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र को अधिकाधिक ऋण प्रदान करने के प्रयासों में आलोच्य वर्ष के दौरान और प्रगति हुई।

मियादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को रिज़र्व बैंक की सहायता

4.2 रिज़र्व बैंक ऋण सुविधाओं की व्यवस्था और ऋण गारंटी योजना के माध्यम से औद्योगिक विकास हेतु मियादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को पहले की तरह मजबूत बनाता रहा। 1978-79 (जुलाई–जून) के दौरान रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में भाऔवि बैंक को 200 करोड़ रुपयों का ऋण मंजूर किया जबकि पिछले वर्ष 180 करोड़ रुपयों का ऋण मंजूर किया गया था। भाऔवि बैंक द्वारा उक्त निधि से लिये गये ऋणों की बकाया राशि जून, 1979 के अंत में 871 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष के दौरान भाऔवि बैंक द्वारा पुनः भुनाये गये योग्य बिलों की जमानत पर उसे 90 करोड़ रुपयों की अल्पावधि ऋण-सीमा भी मंजूर की गयी। रिज़र्व बैंक ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को मंजूर की गयी 3 करोड़ रुपयों की ऋण सीमा को और एक वर्ष के लिए पुनः नवीकृत किया। इसके साथ ही जुलाई 1978 से जून 1979 तक की अवधि के दौरान 7 राज्य वित्तीय निगमों को उनके तदर्थ बांडों की जमानत पर रिज़र्व बैंक ने कुल 13 करोड़ रुपयों की नयी ऋण सीमाएं मंजूर कीं। जून 1979 के अंत में 9 राज्य वित्तीय निगमों के संदर्भ में विद्यमान कुल ऋण सीमा 17 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा 17 राविनिगमों (अर्थात दिल्ली वित्तीय निगम को छोड़कर सभी राविनिगम) को यह अनुमति दी गयी कि वे वर्ष 1978-79 (अप्रैल–मार्च) के दौरान बांड जारी कर बाजार से कुल 46 करोड़ रुपयों (परिपूरित) की राशि का ऋण प्राप्त कर सकते हैं जबकि पिछले वर्ष उक्त राशि 41 करोड़ रुपये थी। लघु उद्योगों को अधिक मात्रा में संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने और इस कार्य में विद्यमान जोखिम को किसी अन्य एजेंसी के साथ बांटने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जुलाई, 1960 में एक ऋण गारंटी योजना बनायी थी; इसके अंतर्गत बैंकों और अन्य ऋण संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को प्रदान किये जाने वाले अग्रिमों का गारंटी प्रदान की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17 (11क) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को केन्द्रीय सरकार के एजेंट के रूप में उक्त योजना को चलाने का कार्य सौंपा गया है और इस प्रयोजन के लिए उसे 'गारंटी संगठन' के नाम से अभिहित किया गया है।

ऋण गारंटी योजना की प्रगति

4.3 उक्त योजना के अधीन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र ऋण संस्थाओं की संख्या मार्च 1979 के अंत में 748 थी जब कि मार्च 1978 के अंत में उक्त संख्या 706 थी। आलोच्य अवधि के दौरान इस योजना में भाग लेने वाली संस्थाओं की संख्या में 11 की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 291 हो गयी। मार्च, 1977 के अंत में बकाया गारंटियों की जो राशि 2,147 करोड़ रुपये थी वह मार्च 1978 के अंत में बढ़कर 2,440 करोड़ रुपये और 1979 के अंत में और बढ़कर 2,874 करोड़ रुपये हो गयी। इससे यह विदित होता है कि योजना में दी गयी प्राथमिकता के अनुसार लघु उद्योग यूनिटों को दिये जाने वाले संस्थागत ऋण में निरंतर वृद्धि होती रही है।

जून 1977 के अंत में बकाया गारंटियों की राशि के उद्योगवार विश्लेषण से यह परिलक्षित होता है कि खाद्य उत्पादक उद्योग (पेय पदार्थों को छोड़कर) का अंश (अपेक्षाकृत) अधिक (12.3 प्रतिशत) बना रहा तथा उसके पश्चात् वस्त्र (11.1 प्रतिशत), धातु से बनी वस्तुओं (10.6 प्रतिशत), रासायनिक उत्पादों (8.4 प्रतिशत), बिजली की मशीनों को छोड़कर अन्य मशीनों के निर्माण (6.7 प्रतिशत), बिजली की मशीनों और उपकरणों (6.5 प्रतिशत) और मूल धातुओं (5.2 प्रतिशत) के उद्योगों का स्थान आता है। इन उद्योगों के संबंधित अंश पिछले वर्ष के लगभग समान ही थे। मार्च, 1978 के अंत तक चूककर्ता यूनिटों की संख्या 18,926 और संबंधित राशि 117 करोड़ रुपये था जो मार्च 1979 के अंत तक बढ़कर क्रमशः 22,443 यूनिट और 150 करोड़ रुपये हो गया। (अप्रैल 1978 से मार्च 1979 तक की अवधि के दौरान चूककर्ता यूनिटों की संख्या में 3,517 की और संबंधित राशि में 33 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई। प्रति चूककर्ता यूनिट की औसत राशि 61,800 रुपयों से बढ़कर 63,800 रुपये हो गयी तथा बकाया गारंटियों में चूक की राशि का प्रतिशत 4.8 से थोड़ा-सा बढ़कर 5.2 हो गया। अप्रैल 1978 से मार्च 1979 तक की अवधि के दौरान 1,347 यूनिटों के संदर्भ में 173 लाख रुपयों के दावे अदा किये गये; इससे 1960 में इस योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक 3,955 यूनिटों के संदर्भ में अदा किये गये कुल दावों की राशि 489 लाख रुपये हो गयी। दावों के लिए अदा की गई कुल राशि में से 77 लाख रुपयों की राशि वसूल कर ली गई है तथा मार्च 1979 के अंत तक अदा किये गए दावों की शुद्ध राशि 411 लाख रुपये थी।

4.4 अप्रैल 1978 से मार्च 1979 तक की अवधि के दौरान गारंटी शुल्कों के रूप में 250 लाख रुपये प्राप्त हुए और उन्हें केन्द्रीय सरकार को अंतरित कर दिया गया।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा निम्नलिखित को प्रदत्त अग्रिम[1] :

(क) लघु उद्योग, (ख) छोटे सड़क और जल परिवहन चालक और

(ग) औद्योगिक बस्तियों की स्थापना

(क) लघु उद्योग

4.5 जुलाई-दिसम्बर 1978 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को मंजूर की गयी ऋण सीमाओं (कारीगरों और अन्य योग्यता-प्राप्त उद्यमियों को दिये गये मीयादी ऋणों और अग्रिमों सहित) की राशि 329 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में उक्त राशि 240 करोड़ रुपये थी। मंजूर की गयी ऋण सीमाओं की कुल राशि दिसम्बर 1978 के अंतिम शुक्रवार को 2,766 करोड़ रुपये थी। बैंकों द्वारा सहायताप्राप्त यूनिटों की संख्या इस अवधि के दौरान 5.13 लाख से बढ़कर 5.58 लाख हो गयी। प्रति यूनिट मंजूर की गयी ऋण सीमाओं की जो औसत राशि जून 1969 में 1.03 लाख रुपये थी वह धीरे-धीरे कम होकर दिसम्बर 1977 में 0.48 लाख रुपये हो गयी परन्तु वह पुनः सीमान्त रूप से बढ़कर दिसम्बर 1978 में 0.50 लाख हो गयी। उक्त अवधि में इस औसत में आयी गिरावट बैंकों द्वारा लघु यूनिटों के वित्तपोषण के लिए निरन्तर किये गये प्रयासों की द्योतक है। कुल बकाया बैंक ऋणों (खाद्यान्नों की वसूली के लिए दिये गये अग्रिमों को छोड़कर) में लघु उद्योगों का जो अंश बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद धीरे-धीरे बढ़ता हुआ जून 1974 में 13.4 प्रतिशत हो गया था और जून 1975 में गिरकर 12.9 प्रतिशत हो गया था, उसमें पुनः वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी और दिसम्बर 1978 के अन्त में वह 14.9 प्रतिशत हो गया। दिसम्बर 1978 के अन्त में बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये कुल बकाया ऋण में से सरकारी क्षेत्र के बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का अंश 88.5 प्रतिशत था। स्टेट बैंक समूह ने अपने कुल ऋणों का 35.6 प्रतिशत और 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 52.9 प्रतिशत अंश लघु उद्योगों को प्रदान किया। यदि राज्यवार देखा जाए तो लघु उद्योगों को दिये गये ऋण की कुल बकाया राशि में दिसम्बर 1978 के अन्त में महाराष्ट्र का अंश लगभग 18.7 प्रतिशत (या 403 करोड़ रुपये) था; परन्तु ऐसे वित्तपोषित यूनिटों की अधिकतम संख्या (88,076 या 15.8 प्रतिशत) तमिलनाडु में थी। दिसम्बर 1978 में समाप्त हुई छमाही के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को मंजूर किये गये मीयादी ऋणों (किस्ती ऋणों सहित) में 65 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई और वे बढ़कर 425 करोड़ रुपये हो गये; वित्तपोषित यूनिटों की संख्या 1.01 लाख से बढ़कर 1.08 लाख हो गयी। जुलाई-दिसम्बर 1978 के दौरान 360 करोड़ रुपयों के ऋण बकाया थे जो 51 करोड़ रुपयों की वृद्धि के द्योतक थे। लघु उद्योगों को दिये गये ऋण की कुल बकाया राशि में दिसम्बर 1978 के अन्त में बकाया मीयादी ऋणों का अंश 16.7 प्रतिशत था।

सारणी 4.1—जून 1976 से लेकर मार्च 1979 तक लघु उद्योगों से संबंधित ऋण गारन्टी योजना की प्रगति

(राशि करोड़ रुपयों में)

निम्नलिखित वर्ष के अंत में	चुकाये न गये अग्रिम			गारंटी के प्रयोग के कारण अदा किये गये दावे		दावों के संबंध में वसूल की गयी राशि में गारंटी संगठन का अंश
	बकाया गारंटियां	यूनिटों की संख्या	राशि	यूनिटों की संख्या	राशि	
	1	2	3	4	5	6
जून 1976	1,949.8	12,439	60.0	1,201	1.7	0.3
जून 1977	2,195.1	16,275	91.4	2,239	2.5	0.4
जून 1978	2,526.4	19,887	125.8	2,711	3.3	0.6
मार्च 1979	2,874.0	22,443	150.0	3,955	4.9	0.8

(स्रोत : औद्योगिक वित्त विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक)

4.6 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को मंजूर की गयी 2,766 करोड़ रुपयों की कुल ऋण सीमा में से कारीगरों और अन्य योग्यताप्राप्त उद्यमियों का अंश 95 हजार यूनिटों के सन्दर्भ में 116 करोड़ रुपये या 4.2 प्रतिशत था। दिसम्बर 1978 के अन्त में इन खातों में बकाया रकम 95 करोड़ रुपये थी, जो 1978 की पहली छमाही की तुलना में 14 करोड़ रुपयों की शुद्ध वृद्धि की द्योतक थी; इसके विपरीत पूर्व वर्ष की तदनुरूप अवधि में उसमें 12 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। इन वर्गों के उधारकर्ताओं के कुल बकाया ऋण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों का अंश दिसम्बर 1978 में बढ़कर 99.0 प्रतिशत हो गया; स्टेट बैंक समूह और राष्ट्रीयकृत बैंकों का अंश क्रमशः 35.3 प्रतिशत 63.7 प्रतिशत था। इस समूह में प्रति यूनिट मंजूर की गयी औसत ऋण राशि जून 1978 के 11,313 रुपयों से सीमांत रूप से बढ़कर दिसम्बर 1978 में 12,246 रुपये हो गयी।

(ख) छोटे सड़क और जल परिवहन चालक

4.7 2 लाख 35 हजार छोटे सड़क और जल परिवहन चालकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से दिसम्बर 1978 के अन्त में कुल 512 करोड़ रुपयों के ऋण प्राप्त हुए जो जून 1978 में प्राप्त ऋणों से 40 करोड़ रुपये अधिक थे। बकाया राशि में भी उक्त अवधि के दौरान 56 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई और वह 415 करोड़ रुपये हो गयी। इस श्रेणी में वित्तपोषित यूनिटों की संख्या में जुलाई-दिसम्बर 1978 की अवधि के दौरान 26 हजार की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 2 लाख 35 हजार हो गयी।

(ग) औद्योगिक बस्तियां

4.8 दिसंबर 1978 के अंतिम शुक्रवार तक 23 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने, जिनमें सरकारी क्षेत्र के 15 बैंक भी शामिल हैं, औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए 261 यूनिटों के संदर्भ में 30 करोड़ रुपयों की ऋण सीमाएं मंजूर कीं। संबंधित खातों में बकाया राशि 27 करोड़ रुपये थी जबकि जून 1978 में ऐसी राशि 23 करोड़ रुपये थी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

भाऔवि बैंक के कार्यकलाप

4.9 वर्ष 1978-79 (जुलाई-जून) के दौरान गारंटियों को छोड़कर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भाऔवि बैंक) द्वारा मंजूर की गयी कुल सहायता (प्रभावी) की राशि 1061 करोड़ रुपये (30,555 आवेदन पत्रों के संदर्भ में) थी जो पिछले वर्ष के दौरान मंजूर की गयी 710 करोड़ रुपयों की सहायता राशि (14,212 आवेदकों को) के मुकाबले 49.4 प्रतिशत अधिक थी। उक्त अवधि के दौरान कुल वितरणों की राशि 680 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष के दौरान वितरित 474 करोड़ रुपयों के मुकाबले 43.5 प्रतिशत अधिक थी (सारणी 4.2)।

4.10 भाऔवि बैंक की स्थापना से जून 1979 के अंत तक 82,292 आवेदन पत्रों के संदर्भ में कुल 4131 करोड़ रुपये मंजूर किये गये। इसके मुकाबले वितरणों की राशि 2777 करोड़ रुपये थी।

सारणी 4.2—अपनी स्थापना से लेकर तथा 1977-78 और 1978-79 (जुलाई-जून) के दौरान भारतीय बैंक द्वारा स्वीकृत सहायता एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रयुक्त सहायता

(राशि करोड़ रुपयों में)

सहायता का स्वरूप	स्वीकृतियां						वितरण		
	1977-78 (जुलाई-जून)		1978-79 (जुलाई-जून)		स्थापना से लेकर जून 1979 तक कुल स्वीकृतियां		1977-78 (जुलाई-जून)	1978-79 (जुलाई-जून)	स्थापना से लेकर जून 1979 के अंत तक कुल वितरण
	आवेदन पत्रों की संख्या	राशि	आवेदन पत्रों की संख्या	राशि	आवेदन पत्रों की संख्या	राशि	राशि	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. प्रत्यक्ष औद्योगिक सहायता		225	271.9	320	402.0	1413	1420.6	181.4	257.9	836.6
(क) औद्योगिक संस्थाओं को प्रत्यक्ष ऋण (निर्यात ऋण को छोड़कर)		189	251.8	260	374.6	987	1274.5	169.9	251.6	770.5
(i) सामान्य		105	202.3	116	255.9	705	1072.1	157.6	214.0	719.7
(ii) सुलभ ऋण सहायता		55	46.0	98	112.3	189	190.0	9.5	33.7	44.2
(iii) तकनीकी विकास निधि		29	3.5	46	6.4	93	12.4	2.8	3.9	6.6
(ख) औद्योगिक संस्थाओं के शेयरों और डिबेंचरों की हामीदारी और उनमें प्रत्यक्ष अभिदान		36	20.1	60	27.4	426	146.1	11.5	6.3	86.1
2. औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त		13031	224.2	29233	417.3	76925	1318.6	145.5	255.5	892.1
3. बिलों की पुनर्भुनाई		920	133.4	951	139.3	3672	920.5	99.6	104.1	721.8
4. वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में अभिदान		18	32.7	20	39.0	31	154.4	28.4	41.3	151.4
कुल परियोजना सहायता (1 से 4 तक)		14194	662.2	30524	997.6	82041	3814.1	454.9	658.8	2601.9
5. निर्यात वित्त		18	47.3	31	63.6	251	316.6	19.3	21.2	175.1
(क) निर्यातों के लिए प्रत्यक्ष ऋण		8	18.1	16	12.5	104	132.0	11.0	12.4	95.4
(ख) निर्यात ऋणों के लिए पुनर्वित्त		7	6.6	10	8.9	123	67.9	4.0	4.6	54.2
(ग) विदेशी खरीदार ऋण		1	3.1	1	2.9	9	25.1	3.6	2.0	11.1
(घ) विदेशी ऋण व्यवस्था		2	19.5	3	36.7	14	89.0	0.7	2.8	14.4
(ङ) विदेशी निवेश वित्त		—	—	1	2.6	1	2.6	—	—	—
1 से 5 तक का जोड़		14212	709.5	30555	1061.2	82292	4130.7	474.2	680.0	2769.9
6. ऋणों और आस्थगित अदायगियों के लिए गारंटियां		—	—	—	—	15	26.7	—	—	19.6
7. निर्यात गारंटियां		42	50.0	107	64.9	174	161.5	51.5@	60.5@	141.8@

@निष्पादित गारंटियां

टिप्पणी : 1. बिलों की पुनर्भुनाई (मद 3) के संदर्भ में आवेदन पत्रों की संख्या खरीदार/उपयोगकर्ता की संख्या से संबंधित है और वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में अभिदान (मद 4) के सामने में आवेदन पत्रों की संख्या वित्तीय संस्थाओं की संख्या से संबंधित है ।

2. बिलों की पुनर्भुनाई के संबंध में स्वीकृत सहायता की राशि पुनः भुनाये गये बिलों के अंकित मूल्य की द्योतक है और सहायता की प्रयुक्त राशि अंकित राशि में से बट्टे की राशि को काटने के बाद किये गये शुद्ध वितरण को दर्शाते हैं ।

(स्रोत : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक)

सारणी 4.3—1978-79 (जुलाई-जून) के दौरान भाऔवि बैंक द्वारा स्वीकृत सहायता का प्रयोजनवार वर्गीकरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

	प्रयोजन									
	नवीन		विस्तार/विविधीकरण		आधुनिकीकरण/पुनःस्थापन		पूरक सहायता		जोड़	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. परियोजनागत प्रत्यक्ष सहायता	77	185.5	24	64.9	9	16.4	24	16.5	134	283.3
	(50)	(136.9)	(34)	(58.9)	(8)	(10.7)	(20)	(15.9)	(112)	(222.4)
2. बिलों की पुनर्भुनाई	38	0.7	—	—	916	138.6	—	—	951	139.3
	(52)	(2.5)			(876)	(130.9)			(920)	(133.4)
जोड़	155	186.2	24	64.9	925	155.0	24	16.5	30318	839.9
	(102)	(139.4)	(34)	(58.9)	(884)	(141.6)	(20)	(15.9)	(14063)	(580.0)

*अर्थात् निम्नलिखित के लिए दी गयी सहायता : (i) परियोजना की लागत में हुई वृद्धि कार्यान्वयन में हुए विलंब के कारण हुई लागत, मशीनों और निर्माण कार्य की सामग्री की लागत में हुई वृद्धि, अनुमानित नकदी साधनों में आयी कमी आदि (ii) जिन कम्पनियों ने पहले अचल आस्तियों के अधिग्रहण के लिए कार्यकारी पूंजीगत निधियों का उपयोग किया था उनके नकदी साधनों पर पड़ने वाले दबाव को दूर करना, (iii) वित्तीय पुनर्गठन, आदि

टिप्पणी : 1. मद 1 के संदर्भ में आंकड़े परियोजनाओं की संख्या और मद 2 के संदर्भ में खरीदार-उपयोगकर्ताओं की संख्या को दर्शाते हैं ।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि से संबंधित हैं ।

3. मद 2 के संदर्भ में अलग-अलग आंकड़े जोड़ में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि कतिपय नये यूनिटों ने भी सहायता का उपयोग किया है ।

(स्रोत : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक)

परियोजनागत प्रत्यक्ष सहायता योजना

4.11 वर्ष 1978-79 के दौरान भाऔवि बैंक ने 134 परियोजनाओं के संदर्भ में 283 करोड़ रुपयों की परियोजनागत प्रत्यक्ष सहायता मंजूर की; इसमें 116 परियोजनाओं के लिए ऋणों के रूप में दिए गये 256 करोड़ रुपये और 60 कंपनियों की शेयर पूंजी की हामीदारी तथा उनमें प्रत्यक्ष अभिदान के रूप में दिये गये 27 करोड़ रुपये शामिल हैं । आलोच्य अवधि के दौरान वितरित 220 करोड़ रुपयों की राशि 1977-78 के दौरान वितरित 169 करोड़ रुपयों के मुकाबले काफी अधिक थी । यदि प्रयोजनवार देखा जाए तो मंजूर की गयी सहायता का 88 प्रतिशत अंश नयी परियोजनाओं के रूप में नयी क्षमता स्थापित करने तथा वर्तमान यूनिटों के विशालतरण और उनके विस्तार के लिए दिया गया था (सारणी 4.3) । यदि क्षेत्रवार देखा जाए तो सहायता का 40 प्रतिशत अंश सरकारी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र को प्राप्त हुआ जब कि शेष 60 प्रतिशत अंश गैर सरकारी क्षेत्र को प्राप्त हुआ । उद्योगवार वितरणों से यह विदित होता है कि सहायता का 69 प्रतिशत अंश मूलभूत उद्योग समूह से संबंधित परियोजनाओं का था । परियोजनागत प्रत्यक्ष सहायता योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित यूनिटों के लिए मंजूर की गयी सहायता की राशि 134 करोड़ रुपये थी और उसमें से रियायती सहायता की राशि 113 करोड़ रुपये थी ।

सहायता की अन्य योजनाएं

4.12 परियोजनागत प्रत्यक्ष सहायता के अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनायी गयी सहायता की अन्य बहुत-सी योजनाएं कार्यान्वित की जाती रहीं ।

(क) सुलभ ऋण सहायता

4.13 1978-79 के दौरान सुलभ ऋण योजना के अधीन भाऔवि बैंक द्वारा 98 आवेदकों को 112.3 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गयी जो 1977-78 के दौरान 55 आवेदकों को मंजूर की गयी 46 करोड़ रुपयों की राशि की तुलना में 113.5 प्रतिशत अधिक थी । सुलभ ऋण योजना के प्रारंभ से जून 1979 के अंत तक 189 यूनिटों के संदर्भ में कुल 190 करोड़ रुपयों की सहायता मंजूर की गयी । योजना के अधीन सहायता के वितरणों की राशि में आलोच्य अवधि के दौरान लगभग 240.0 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि परिलक्षित हुई; वितरित राशि 1977-78 के 10 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1978-79 में 34 करोड़ रुपये हो गई । योजना के अधीन 30 जून 1979 को बकाया सहायता राशि 44 करोड़ रुपये थी ।

(ख) तकनीकी विकास निधि योजना

4.14 1978-79 के दौरान तकनीकी विकास निधि योजना के अधीन भा० औ० वि० बैंक ने 46 यूनिटों को 6 करोड़ रुपयों के प्रत्यक्ष रुपया ऋण मंजूर किये जबकि पिछले वर्ष के दौरान 29 यूनिटों को 4 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे । योजना के अधीन जून 1979 तक 93 यूनिटों को 12 करोड़ रुपये मंजूर किये गये । मंजूरियों के संदर्भ में हुई 50.0 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले उक्त योजना के अधीन वितरणों की राशि में 33.3 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई और वह 3 करोड़ रुपये से बढ़कर 4 करोड़ रुपये हो गयी ।

(ग) औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त

4.15 स्वतः पुनर्वित्त योजना को 1 जुलाई 1978 से अमल में लाये जाने तथा योजना के अंतर्गत 1978-79 के दौरान दी गयी अन्य

छूटों के परिणाम स्वरूप पुनर्वित्त संबंधी स्वीकृतियों में भारी मात्रा में बढ़ोत्तरी हुई है । आलोच्य अवधि के दौरान 29,233 आवेदनपत्रों के संदर्भ में 417 करोड़ रुपयों की राशि मंजूर की गयी जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान 13,031 आवेदनपत्रों के संदर्भ में 224 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे अर्थात् उनमें 86.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई । आलोच्य अवधि के दौरान योजना के अधीन 25 करोड़ रुपयों की राशि वितरित की गयी जो 1977-78 की इसी अवधि के दौरान वितरित 14 करोड़ रुपयों की तुलना में 75.3 प्रतिशत अधिक थी । आलोच्य वर्ष के दौरान स्वतः पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत दी गई स्वीकृतियों की राशि 23,796 आवेदनपत्रों के संदर्भ में 210 करोड़ रुपये थी जबकि ऐसी सहायता की प्रयुक्त राशि 79 करोड़ रुपये थी । वर्ष 1978-79 के दौरान 28,243 आवेदनपत्रों के संदर्भ में 293 करोड़ रुपयों की पुनर्वित्त सहायता लघु उद्योग क्षेत्र के लिए मंजूर की गयी जिसमें छोटे सड़क परिवहन चालक भी शामिल हैं । निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित यूनिटों के लिए रियायती दरों पर मंजूर की गयी पुनर्वित्त सहायता की राशि 160 करोड़ रुपये थी ।

(घ) बिल पुनर्भुनाई योजना

4.16. 1978-79 (जुलाई-जून) के दौरान बिल पुनर्भुनाई योजना के अधीन 951 खरीदार-उपयोक्ताओं के संदर्भ में 139 करोड़ रुपये मंजूर किये गये जो 1977-78 के दौरान 920 खरीदार-उपयोगकर्ताओं के संदर्भ में मंजूर किये गये 133 करोड़ रुपयों के मुकाबले सीमांत वृद्धि द्योतक हैं । 104 करोड़ रुपयों के वितरणों की राशि भी पिछले वर्ष के दौरान वितरित 100 करोड़ रुपयों के मुकाबले सीमान्त रूप से अधिक थी ।

(ङ) मूल पूंजी योजना

4.17. संप्रति मूल पूंजी योजना उन 24 राज्य औद्योगिक विकास निगमों/राज्य औद्योगिक निवेश निगमों द्वारा चलायी जा रही हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने "वित्तीय संस्थाओं" के रूप में अधिसूचित किया है और इन निगमों को भा०औ०वि० बैंक की पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध है । योजना के प्रारम्भ से लेकर जून 1979 के अंत तक 5 करोड़ रुपयों की मूल पूंजी सहायता के लिए भा०औ०वि० बैंक को 90 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 2 करोड़ रुपयों की राशि के 63 प्रस्ताव मंजूर किये गये और इन संदर्भ में कुल वितरणों की राशि 1 करोड़ रुपये थी ।

(च) निर्यात बिल योजना

4.18. निर्यात वित्त योजनाओं (गारंटियों को छोड़कर) के अधीन मंजूर की गयी कुल सहायता में 36.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 1977-78 (जुलाई-जून) के 18 आवेदकों के संदर्भ में 47.3 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1978-79 के दौरान 31 आवेदकों के संदर्भ में 64 करोड़ रुपये हो गयी । विदेशी ऋण व्यवस्था योजनाओं और निर्यात ऋण योजनाओं के पुनर्वित्त के अधीन दी गयी मंजूरियों में क्रमशः 85.0 प्रतिशत (20 करोड़ रुपयों से बढ़कर 37 करोड़ रुपये) और 28.6 प्रतिशत (7 करोड़ रुपयों से बढ़कर 9 करोड़ रुपये) की वृद्धि परिलक्षित हुई जबकि निर्यातों के लिए प्रत्यक्ष ऋणों की योजना के अंतर्गत मंजूरियों की राशि उक्त अवधि के दौरान 18 करोड़ रुपयों से घटकर 13 करोड़ रुपये हो गयी । निर्यात वित्त की समस्त योजनाओं के अधीन कुल वितरणों की राशि 21 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान वितरित 19 करोड़ रुपयों की राशि से 10.5 प्रतिशत अधिक थी ।

(छ) पिछड़े क्षेत्रों को सहायता

4.19. आलोच्य वर्ष के दौरान निर्दिष्ट पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के लिए भा०औ०वि० बैंक द्वारा मंजूर की गयी सहायता की कुल राशि 377 करोड़ रुपये थी (सारणी 4.4) । हालांकि मंजूर की गयी राशि में 79 करोड़ रुपयों की बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी परन्तु भा० औ० वि० बैंक द्वारा मंजूर की गयी कुल सहायता में पिछड़े क्षेत्रों का अंश 1977-78 के 47.5 प्रतिशत से घटकर 1978-79 में 39.4 प्रतिशत हो गया । आलोच्य वर्ष के दौरान 314 करोड़ रुपये के वितरणों की राशि भी पूर्व वर्ष की अपेक्षा 93 करोड़ रुपये अधिक थी परन्तु कुल वितरणों में परिमाण के रूप में पिछड़े क्षेत्रों का अंश 50.6 प्रतिशत था जो पिछले वर्ष के 51.6 प्रतिशत के मुकाबले सीमान्त रूप से न्यून था । इन यूनिटों के संदर्भ में कुल स्वीकृतियों और वितरणों की राशि क्रमशः 1,491 करोड़ रुपये तथा 980 करोड़ रुपये थी जो कुल स्वीकृतियों और वितरणों का क्रमशः 40.7 प्रतिशत और 39.9 प्रतिशत थी ।

(ज) शेयरों और बांडों में अभिदान

4.20 आलोच्य वर्ष के दौरान भा०औ०वि० बैंक ने 18 राज्य वित्तीय निगमों की शेयर पूंजी में 660 करोड़ रुपयों (950 हजार शेयरों की विशेष पूंजी सहित) का अभिदान किया । भा०औ०वि० बैंक ने भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के बांड निर्गमों में 15-15 करोड़ रुपयों का भी अभिदान किया ; सुलभ ऋण योजना के अंतर्गत उनकी सहबद्धिता के लिए समर्थन के रूप में भा०औ०वि० बैंक ने यह अभिदान किया । भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को 350 लाख रुपयों की राशि भी वितरित की गयी जो कि ब्रिटेन की ऋण व्यवस्था के संदर्भ में प्राप्त निधियों की रुपया राशि की अंतिम किश्त की द्योतक थी । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 5 करोड़ रुपयों के अधिकार शेयरों में भा०औ०व० बैंक ने 120 लाख रुपयों की विनियोग राशि का अभिदान किया । अन्य वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में जून 1979 के अंत तक किये गये कुल अभिदानों की राशि 151 करोड़ रुपये थी ।

(झ) आयातों के लिए ऋण व्यवस्था

4.21 अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/विश्व बैंक से भा०औ०वि० बैंक को अब तक चार ऋण प्राप्त हुए हैं। इनमें से क्रमशः 250 लाख अमेरिकी डालर और 400 लाख अमेरिकी डालर के ऋण राज्य वित्तीय निगमों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए थे और 280 लाख अमेरिकी डालर का तीसरा ऋण गैर सरकारी क्षेत्र की विशिष्ट उर्वरक परियोजनाओं को प्रबंधन नियंत्रण योजना और उर्वरक संयंत्रों की कठिनाइयों को दूर करने में सहायता पहुंचाने के लिए था। विश्व बैंक से प्राप्त होने वाले 250 लाख अमेरिकी डालर का चौथा ऋण सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र की मझौली परियोजनाओं की सहायता के लिए था। इन चार ऋण व्यवस्थाओं के अंतर्गत जून, 1979 के अंत तक विश्व बैंक की मंजूरियों और वितरणों की कुल राशि क्रमशः 88 करोड़ रुपये और 45 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा विश्व बैंक समूह भारत सरकार को दी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की अपनी ऋण व्यवस्था (140 लाख अमेरिकी डालर) के एक अंश (22 लाख अमेरिकी डालर) को जम्मू और काश्मीर की बागवानी परियोजना के संदर्भ में भा०औ०वि० बैंक के माध्यम से प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। यह ऋण 26 जनवरी, 1979 से प्रभावी हुआ है।

(ञ) विकास परक कार्य

4.22 1978-79 के दौरान मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में क्रमशः भारतीय औद्योगिक वित्त, निगम भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नेतृत्व में तीन और तकनीकी परामर्श संगठन गठित किये गये। इन तीन संगठनों को मिलाकर देशभर में कार्यरत तकनीकी परामर्श संगठनों की संख्या 12 हो गयी, जिनमें से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा क्रमशः 8, 3 और 1 संगठन प्रायोजित किये गये थे। तकनीकी सहायता निधि

सारणी : 4.4—निर्दिष्ट पिछड़े जिलों के यूनिटों भा०औ०वि० बैंक द्वारा स्वीकृत (प्रभावी) तथा वितरित सहायता@

(राशि करोड़ रुपयों में)

वर्ष	स्वीकृत सहायता			वितरित सहायता		
	कुल	पिछड़े जिले	2 की तुलना में 3 का प्रतिशत	कुल	पिछड़े जिले	5 की तुलना में 6 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
स्थापना से लेकर जून 1970 के अंत तक	276.3	44.7 (—)	16 2	250.2	36.1 (—)	14.4
1970-71	84.9	21.0 (0.3)	24.7	54.2	9.4 (0.1)	17.3
1971-72	135.0	44.9 (17.5)	33.2	73.7	15.1 (1.5)	20.5
1972-73	121.6	40.8 (13.8)	33.6	97.6	23.5 (8.6)	24.1
1973-74	164.9	58.6 (42.3)	35.6	143.0	49.4 (18.3)	34.5
1974-75	268.7	94.7 (52.5)	35.2	186.8	68.8 (25.7)	36.8
1975-76	386.9	172.3 (115.9)	44.5	249.6	98.7 (53.2)	39.5
1976-77	633.2	337.7 (187.9)	53.3	351.5	145.4 (98.8)	41.1
1977-78	629.4	298.4 (149.6)	47.5	426.4	220.2 (127.4)	51.6
1978-79	958.7	377.4 (272.8)	39.4	617.5	313.5 (176.0)	50.6
जोड़	3659.6	1490.5 (852.6)	40.7	2450.5	980.1 (509.6)	39.9

@इसमें प्रत्यक्ष ऋण, सुलभ ऋण, तकनीकी विकास निधि, हामीदारी/प्रत्यक्ष अभिदान, पुनर्वित्त और बिलों की पुनर्भुनाई शामिल हैं ।

टिप्पणी : स्तंभ 3 और 6 में कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े रियायती शर्तों पर वितरित राशि को दर्शाते हैं ।

(स्रोत : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक)

में से राज्य स्तरीय निगमों और तकनीकी परामर्श संगठनों के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा तकनीकी परामर्श संगठनों द्वारा आयोजित निम्नलिखित उद्यमी विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गयी; अर्थात् (i) केरल में केरल औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन द्वारा आयोजित 9 उद्यमी विकास कार्यक्रम (इनमें से 3 कार्यक्रम मात्र हरिजनों के लिये थे), (ii) उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश औद्योगिक परामर्श संगठन द्वारा आयोजित 4 उद्यमी विकास कार्यक्रम और (iii) गौहाटी में उत्तर पूर्व औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन द्वारा चलाया गया एक उद्यमी विकास कार्यक्रम ।

राज्य वित्तीय निगमों के कार्यकलाप

4.23 राज्य वित्तीय निगमों (राकि निगमों) के कार्यकलापों में 1978-79 (अप्रैल—मार्च) के दौरान—उल्लेखनीय सुधार पाया गया । 18 राकि निगमों (तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम सहित) द्वारा मंजूर तथा वितरित की गयी कुल वित्तीय सहायता की राशि क्रमशः 195 करोड़ रुपये और 135 करोड़ रुपये थी जब कि पिछले वर्ष के दौरान यह क्रमशः 166 करोड़ रुपये और 107 करोड़ रुपये थी। (सारणी 4.5) 1978-79 के दौरान मंजूरियों और वितरणों में हुई वृद्धि की मात्रा क्रमशः 17.5 प्रतिशत और 26.2 प्रतिशत थी जो 1977-78 के दौरान परिलक्षित क्रमशः 1.7 प्रतिशत और 2.0 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले काफ़ी अधिक थी । कुल बकाया ऋणों की राशि मार्च, 1978 के अन्त में स्थित 539 करोड़ रुपयों के मुकाबले मार्च, 1979 के अन्त में 643 करोड़ रुपये थी ।

सारणी 4.5—राज्य वित्तीय निगमों के कार्यकलाप

(करोड़ रुपयों में)

	1977-78 (अप्रैल—मार्च)	1978-79 (अप्रैल—मार्च)
मंजूर किये गये ऋण (प्रभावी) .	166.1	195.3
वितरित ऋण . .	107.4	135.2
बकाया ऋण (मार्च के अन्त में)	539.3	643.9

(स्रोत : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक)

4.24 राकि निगमों द्वारा मंजूर की गयी तथा वितरित की गयी कुल सहायता में अधिकांश भाग पहले की तरह लघु उद्यमों, जिनमें सड़क परिवहन चालक भी शामिल हैं, को प्रदत्त सहायता का था। 1978-79 के दौरान सहायता प्राप्त कुल यूनिटों, मंजूर की गयी कुल सहायता और वितरित कुल सहायता में लघु उद्योग क्षेत्र का अंश क्रमशः 98.6 प्रतिशत, 78.2 प्रतिशत और 71.0 प्रतिशत था।

4.25 निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित यूनिटों को प्रदत्त राकि निगमों की सहायता में भी आलोच्य वर्ष के दौरान बढ़ोतरी पायी गयी । ऐसे क्षेत्रों में स्थित 5,401 यूनिटों के मामले में वित्तीय सहायता की राशि 114 करोड़ रुपये अथवा 1978-79 के दौरान मंजूर की गयी कुल सहायता का 58.5 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष के दौरान उक्त राशि 4,057 यूनिटों के संदर्भ में 87 करोड़ रुपये, (52.4) प्रतिशत) थी।

4.26 सत्रह राकि निगमों (हरियाणा को छोड़कर) ने मार्च, 1979 के अन्त तक कुल 580 लाख रुपयों की विशेष पूंजी जुटायी । विशेष पूंजी योजना के अन्तर्गत मार्च, 1979 के अन्त तक मंजूर की गयी राशि 419 यूनिटों के संदर्भ में 140 लाख रुपये और वितरणों की राशि 40 लाख रुपये थी। मार्च, 1979 के अन्त में 98 करोड़ रुपयों की कुल सहायता के लिए 3,556 आवेदन पत्र राकि निगमों के पास अनिर्णीत पड़े थे।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

4.27 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम जमाकर्त्ताओं, विशेष रूप से छोटे जमाकर्त्ताओं को बीमाकृत बैंकों द्वारा अपनी देयताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होने पर उनकी जमाराशियों को हानि के जोखिम से संरक्षण प्रदान करता है तथा पात्र ऋण संस्थाओं को उनके द्वारा समाज के कमजोर वर्गों की कुछ निर्दिष्ट श्रेणियों के ऋणकर्त्ताओं को दी गयी ऋण सुविधाओं के संदर्भ में रक्षा प्रदान करता है। 15 जुलाई, 1978 से भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड को जमा बीमा निगम में विलीन कर देने और जमा बीमा निगम का नाम बदलकर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम कर देने से जमा बीमा और ऋण गारंटी से संबंधित कार्य नये निगम द्वारा किये जाते हैं। भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड की सभी देयताएं और आस्तियां तथा अधिकार और दायित्व अब निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम में निहित है। उक्त निगम द्वारा संयुक्त यूनिट के स्थापना व्यय तथा अन्य व्यय को पूरा करने के लिए उसकी पूंजी को 2 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया। उक्त पूंजी की समस्त राशि का अभिदान रिज़र्व बैंक ने किया है और रिज़र्व बैंक निगम का एकमात्र शेयरधारक है।

जमा बीमा कार्य

4.28 बीमाकृत वाणिज्य बैंकों की संख्या बिना परिवर्तन के 78 ही रही, जबकि बीमाकृत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या बढ़कर 30 जून, 1979 को 56 हो गयी। सहकारी बैंकों के मामले में बीमाकृत बैंकों की कुल संख्या उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों में क्रमशः 27 और 71 पात्र सहकारी बैंकों का पंजीकरण करने से बढ़कर जून, 1979 के अन्त में 978 हो गयी। जून 1979 के अन्त तक उक्त योजना में 11 राज्यों और तीन संघशासित क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गोवा, दमण और दीव तथा पांडिचेरी के सहकारी बैंक शामिल थे। शेष राज्यों में इस योजना को लागू करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ऐसे आवश्यक विधान पारित करने की प्रतीक्षा की जा रही है जिनसे इस योजना को लागू किया जा सकेगा। प्रति सौ रुपये के लिए वार्षिक 4 पैसे की बीमा प्रीमियम दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बीमाकृत जमाराशियों के आवश्यक विवरण इकट्ठे करने में बैंकों पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के उद्देश्य से 1979 के प्रारम्भ से बीमा प्रीमियम की अदायगी की अवधि को त्रैमासिक से बदलकर अर्धवार्षिक कर दिया गया है। 1978 के अंत में 21,659 करोड़ रुपयों की बैंकों की कुल कर योग्य जमाराशियों में वर्ष के दौरान 1,767 करोड़ रुपयों की वृद्धि परिलक्षित हुई। जमा खातों की कुल संख्या में पूर्णतः संरक्षित खातों का प्रतिशत 98.2 से थोड़ा सा बढ़कर 98.3 हो गया जबकि कुल कर योग्य जमाराशियों में बीमाकृत जमाराशियों का प्रतिशत 71.1 से घटकर 71.0 हो गया।

4.29 निगम द्वारा (जमा बीमा निगम की) स्थापना से लेकर अब तक जिन दावों के लिए अदायगी की गयी या अदायगी की व्यवस्था की गई उनकी राशि 179 लाख रुपये थी । ये दावे 14 वाणिज्य बैंकों और 6 सहकारी बैंकों के संदर्भ में थे। निगम को वाणिज्य बैंकों के संदर्भ में चुकाये गये 73 लाख रुपये प्राप्त हुए जबकि सहकारी बैंकों के मामले में इस प्रकार कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

ऋण गारंटी कार्य

4.30 भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड के सभी अधिकार और दायित्व लेने के बाद निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम पिछले निगम द्वारा निर्मित और कार्यान्वित की गयी तीनों ऋण गारंटी योजनाओं अर्थात् लघु ऋण गारंटी योजना, वित्तीय निगम गारंटी योजना और सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना को चला रहा है । आलोच्य वर्ष के दौरान निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा इन योजनाओं में कतिपय संशोधन किये गये ताकि छोटे ऋणकर्त्ताओं को अधिकाधिक लाभ मिल सके। बाढ़ पीड़ितों को उदार शर्तों पर पुनर्वास वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित ऋणकर्त्ताओं को दिये गये काफ़ी समय से बकाया रहने वाले फसल ऋणों को मीयादी ऋणों में परिवर्तित कर देने के कारण, प्राप्त होने वाले दावों के संबंध में निगम की देयता को रु० 5,000 से बढ़कर

रु० 7,500 कर दिया गया है ताकि 1977 के खरीफ़ मौसम से शुरू होने वाले तीन कृषि मौसमों के संदर्भ में देय राशि को रक्षा प्रदान की जा सके, अब तक उक्त अवधि दो कृषि मौसम थी । यह ऋणकर्ता को दिये जाने वाले नये फसल ऋणों के मामले में विद्यमान निगम की अधिकतम रु० 2,500 की देयता के अतिरिक्त है । साथ ही, भारत सरकार द्वारा विभेदक ब्याज दर योजना के संबंध में गठित कार्यकारी दल की सिफ़ारिशों के अनुसरण में 1 जनवरी, 1979 को या उसके बाद उक्त योजना के अंतर्गत प्रदान किये गये अग्रिमों के संबंध में निगम की गारंटी रक्षा को चूक की राशि के 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है । इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जो विशेष भूमिका अदा करनी पड़ती है, उसको देखते हुए, उन्हें अस्थायी राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उनके गारंटीकृत अग्रिमों के संदर्भ में गारंटी शुल्क की दर को पहली जुलाई, 1979 अथवा संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख, इनमें से जो भी परवर्ती तारीख हो, से तीन वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक $\frac{1}{2}$ प्रतिशत से कम कर वार्षिक $\frac{1}{4}$ प्रतिशत कर दिया गया है । अप्रैल, 1979 से लघु ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत हर ऋणकर्ता के संबंध में निगम के मुद्रागत दायित्व की अधिकतम सीमाएँ समस्त बैंकिंग तन्त्र के बजाय प्रत्येक बैंक द्वारा उसे प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं पर लागू है । दिसम्बर, 1978 के अंत में तीनों योजनाओं के अंतर्गत आने वाली 1,716 करोड़ रुपये की राशि पिछले वर्ष के मुकाबले 13.1 प्रतिशत की वृद्धि की द्योतक थी । लघु उद्योगों को दिया गया ऋण संप्रति एक अलग गारंटी योजना के अंतर्गत आता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनायी गयी है और रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित है । सभी ऋण गारंटी योजनाओं को एक संगठन के अधीन लाने के उद्देश्य से लघु उद्योग क्षेत्र के संदर्भ में ऋण गारंटी कार्यों को भी निगम द्वारा अधिकार में लिये जाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

4.31 लघु ऋण गारंटी योजना में पचहत्तर वाणिज्य बैंक और (49 में से) 47 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं और निगम द्वारा गारंटीकृत कुल अग्रिमों में अकेले इनका अंश 99.5 प्रतिशत है । वित्तीय निगम गारंटी योजना में भाग लेनेवाली संस्थाओं की संख्या बिना किसी परिवर्तन के 18 ही बनी रही । सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना जिसमें जमा बीमा रक्षा के लिए पात्र सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक (प्राथमिक सहकारी बैंकों से इतर) भाग ले सकते हैं, में (24 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) 85 वाणिज्य बैंक और 30 सहकारी बैंक शामिल हो गये हैं ।

4.32 योजना में भाग लेने वाली ऋण संस्थाओं द्वारा माँगी जाने वाली गारंटी, जो 1973 से प्रारम्भ हुई थी, में 1975 से तेजी से वृद्धि हो रही है । 1978 के दौरान प्राप्त दावों से यह प्रवृत्ति काफ़ी स्पष्ट थी । 1978 के दौरान 29,925 दावे प्राप्त हुए और उनकी राशि 876 लाख रुपये थी । जबकि पिछले सभी वर्षों में प्राप्त दावों की संख्या 21,638 और उनकी राशि 669 लाख रुपये थी । जनवरी-अप्रैल, 1979 के दौरान 386 लाख रुपयों के लिए 12,314 दावे प्राप्त हुए, उनमें से 5,514 दावों का निबटान किया जा चुका है । बड़ी संख्या में प्राप्त होने वाले दावों की पूर्ति के लिए निगम ने कई कदम उठाये हैं । जांच पड़ताल की कियाविधियों और विषयों को अत्यंत सरल कर दिया गया है; नवम्बर, 1978 से दावे का एक अपेक्षाकृत सरल फार्म अमल में लाया गया है तथा रु० 1,000 या उससे कम राशि के दावों को निपटाने के लिए एक सरल कियाविधि और दावा संबंधी सरल फार्म अमल में लाये जा रहे हैं । दिसम्बर, 1978 के अन्त में कुल 51,563 दावों में से 664 लाख रुपयों के 27,033 दावे निबटाये गये ।

4.33 अदा किये गये दावों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के कारण निगम अदा किये गये दावा खातों की जांच और संबंधित ऋणकर्त्ताओं से प्राप्य राशियों की वसूली पर विशेष ध्यान दे रहा है । 1978 के दौरान निगम ने वसूलियों के अपने अंश के रूप में 3,284 हजार रुपयों की राशि प्राप्त की जबकि पिछले सभी वर्षों के दौरान कुल 1,173 हजार रुपये प्राप्त हुए थे ।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

4.34 भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य समाज के मध्यम-आय वर्गों के लघु निवेशकों को अधिक और बढ़ती हुई संख्या के लिए शेयरों के बराबर प्रकार के निवेश (जिसमें जोखिम कम हो और उचित लाभ हो) की सुविधा प्रदान करना है । ये सुविधाएँ प्रदान करते हुए ट्रस्ट साधन जुटाने और उनका निवेश करने तथा उसके द्वारा पूंजी की समग्र उत्पादकता को बढ़ाने और अर्थ-व्यवस्था के विकास में भी सहायता पहुंचाता है । बचत राशि जुटाने के लिए ट्रस्ट जनता को 'यूनिटों' की बिक्री करता है ।

4.35 1978-79 (जुलाई—जून) के दौरान ट्रस्ट की तीन योजनाओं के अधीन यूनिटों की बिक्री की कुल राशि 102 करोड़ रुपये थी और वह पिछले वर्ष की तुलना में 38.6 प्रतिशत अधिक थी । यह वृद्धि पिछले वर्ष पायी गयी 112 प्रतिशत की वृद्धि के अतिरिक्त है । ट्रस्ट द्वारा पुनः खरीदे गये 10 करोड़ रुपयों के यूनिटों की राशि पिछले वर्ष के दौरान पुनः खरीदे गये 11 करोड़ रुपयों के यूनिटों के मुकाबले कम थी । इस प्रकार सभी योजनाओं के अंतर्गत यूनिटों की शुद्ध बिक्री की राशि में इस वर्ष 92 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष उसमें 62 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । (सारणी 4.6) ।

सारणी 4.6—भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों की बिक्री, पुनःक्रय और बकाया राशि—योजनावार

(राशि करोड़ रुपयों में)

	बिक्री		पुनः क्रय		30 जून, 1979 को
योजनाएँ	1977-78	1978-79	1977-78	1978-79	बकाया राशि
यूनिट योजना 1964	70.86	96.08	10.86	9.13	330.31
यूनिट योजना 1971 (यूनिट संबद्ध बीमा योजना)	2.41	5.45	0.05	0.11	10.43
यूनिट योजना 1976	(a)	(a)	0.32	0.22	6.73
जोड़	73.27	101.53	11.23	9.46	347.47

(a) बिक्री रोक दी गयी ।

टिप्पणी : 1978-79 के आंकड़े अनंतिम हैं ।

(स्रोत : भारतीय यूनिट ट्रस्ट)

4.36 पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष के अधिकांश भाग में यूनिटों की रिकार्ड बिक्री का प्रमुख कारण यह था कि बिक्री से प्राप्त राशि को यूनिटों में पुनः लगाने के फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले पूंजीगत लाभ को कर से छूट दे दी गयी थी । फ़रवरी महीने के दौरान इस छूट को हटाये जाने के भय से यूनिटों की बिक्री में भारी वृद्धि हुई । यूनिटों की बिक्री की उक्त वृद्धि के दूसरे कई कारण थे; उनमें गहन और सुव्यवस्थित बिक्री और प्रचार की भूमिका महत्वपूर्ण थी । पूंजीगत लाभों को कर से दी गयी छूट को पहली मार्च 1979 से हटा लिये जाने से बचत के अन्य माध्यमों के मुकाबले यूनिटों के प्रति विद्यमान आकर्षण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है । तीनों योजनाओं अर्थात् यूनिट योजना 1964, यूनिट योजना 1971 और यूनिट योजना 1976 के अधीन वर्ष 1978-79 के लिए

दिये जाने वाले लाभांश को क्रमशः 9 प्रतिशत, 8 प्रतिशत और 3 प्रतिशत बनाये रखा गया।

4.37 30 जून 1979 को जनता को बेचे गये और जनता पर बकाया यूनिटों की राशि 317 करोड़ रुपये थी; इसमें से लगभग 330 करोड़ रुपये यूनिट योजना 1964 के अंतर्गत थे (यूनिटधारी खातों की संख्या लगभग 9 लाख थी)। यूनिट योजना 1976 (पूंजीगत यूनिट) के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री पहले की तरह निलंबित रही।

निवेश

4.38 31 मई 1979 को ट्रस्ट की कुल निवेश योग्य निधियां 402 करोड़ रुपये थीं। इनमें से सामान्य शेयरों की राशि 120 करोड़ रुपये या 29.9 प्रतिशत, डिबेंचरों की राशि 83 करोड़ रुपये या 20.6 प्रतिशत और अधिमान शेयरों की राशि 17 करोड़ रुपये या 4.1 प्रतिशत थी। शेष राशि (अर्थात् 182 करोड़ रुपये) का निवेश प्रमुखतः बैंकों में मांग जमा राशियों, निवेश-बाण्डों पर अग्रिम जमाराशियों और सावधि जमा राशियों के रूप में किया गया।

[सं० एफ० 10/2/79-बी० ओ०-1]

जे० सी० राय, निदेशक

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 29th October, 1979

S.O. 1597.—In accordance with section 53(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Governor, Reserve Bank of India has submitted to the Government of India the following Annual Report on Trend and Progress of Banking in India for the year ended June 30, 1979

CHAPTER 1
INTRODUCTION

Three features of the banking scene in 1978-79 deserve to be highlighted : the sustained growth in deposits and credit, enlargement of banks' involvement in lending to the weaker sections, and the initiation of a three-year branch expansion policy specifically directed towards reduction of regional imbalances. Two national targets had been set earlier for public sector banks to be reached by March 1979 : firstly, banks should strive to reach a level of not less than one-third of their outstanding credit to priority sectors. And secondly, banks were required to deploy 60 per cent of their total deposit mobilisation from rural and semi-urban areas in the respective areas. Considerable progress was achieved in 1978-79 in these matters also.

1.2 Aggregate deposits of scheduled commercial banks recorded a rise of Rs. 4,556 crores in 1978-79 (July-June), which was, marginally larger than the rise of Rs. 4,410 crores witnessed in 1977-78. In terms of rates of growth, however, aggregate deposits growth decelerated from 23.3 per cent in 1977-78 to 19.5 per cent. This was partly for the reason that national income, which had risen by as much as 7.2 per cent in 1977-78, rose in 1978-79 by only 4 to 4.5 per cent.

1.3 The trends in credit during 1978-79 showed two distinct phases, the first one, during the early part of the year of a rapid build-up in liquidity followed by a period of rapid expansion in credit. In particular, the expansion in non-food gross bank credit during the eight successive weeks ended November 17, 1978 was at an unusually high rate of about Rs. 100 crores per week. In terms of incremental credit-deposit ratios, the ratio for these eight weeks worked out to nearly 100 per cent. Following this extraordinary spurt in bank credit the Reserve Bank of India (RBI) prescribed a policy of limiting the incremental (gross) non-food credit-deposit ratio to 40 per cent for the period December 1, 1978 to end-March 1979. In actual fact, however, expansion in such credit up until the last week of January 1979 continued to be very large. For the year 1978-79 as a whole non-food (gross) bank credit recorded an increase of 17.7 per cent ; this was on top of an increase of nearly 20 per cent witnessed during the previous year. Even making allowance for a relatively higher industrial growth of about 7.6 per cent in 1978-79 as against 3.0 per cent in 1977-78 and the need for supporting larger inventories in some sectors like sugar, the expansion in non-food (gross) bank credit in 1978-79 was much greater than warranted. The credit policy measures taken during this period has to be viewed against this background.

1.4 The experience of the last year has brought into sharp relief the deficiencies in the existing system of monitoring data/information on credit or banking indicators generally. Credit planning at the macro level has to be adequately supported by an information system at the individual bank's level which enables it to monitor the functioning of its branches promptly and effectively. Measures to streamline the monitoring system at the individual bank's level to achieve this objective have already been initiated.

1.5 According to the targets laid down by the Government of India (GOI) advances to priority sectors like agriculture, small-scale industries and small borrowers by public sector commercial banks should reach a level of not less than one-third of their outstanding credit by March 1979. At the end of March 1979 advances to priority sectors by 50 banks which account for about 95 per cent of the total bank credit formed 30.5 per cent of their total (net) bank credit as compared with the level of 28.2 per cent a year ago. The share of priority sector in the total incremental (net) credit was lower at 43.0 per cent in 1978-79 (April-March) than the corresponding share of 46.9 per cent in 1977-78.

1.6 In respect of the target relating to rural lending, however, the banking system has a long way to go. Public sector banks were expected to achieve by March 1979 a credit-deposit ratio of at least 60 per cent in respect of their rural and semi-urban branches separately. For the country as a whole, the ratios for the rural and semi-urban areas were 52.5 and 47.4, respectively, at the end of June 1978. The fact that the all-India ratios were low does not mean that all regions/districts have remained well below the target. In fact the Southern Regional as a whole has exceeded the target in respect of rural areas with the ratio of 76.3 per cent and has nearly reached the target for semi-urban areas with the ratio of 59.7 per cent. Similarly, 38 per cent of districts covered by rural bank branches and 33 per cent of districts covered by semi-urban bank branches showed credit-deposit ratios of 60 per cent or above. This underlines the uneven progress in this respect, both region-wise and even district-wise.

1.7 Such an approach to the lending pattern of commercial banks, implicit in these national targets has brought about, over the years, a significant structural transformation in the composition of credit. The share of large and medium industries in total bank credit, for instance, has declined over the years, at the same time as the relative share of priority sectors like agriculture has gone up. The pace at which such a transformation is taking place may perhaps receive further impetus from some of the guidelines recently issued to banks following the recommendations of the Five Working Groups constituted by the GOI in October 1978. Furthermore, banks are being increasingly involved in block development plans and more recently in the District Industries Centres (DICs). The success of the banking system in tackling these somewhat new and complex tasks would depend upon the speed with which they could adapt their lending attitudes, procedures and skills to the new tasks.

1.8 A comprehensive branch expansion policy for the three years 1979-81, formulated in the broader framework of a reduction in regional imbalances and strengthening of a multi-agency approach to rural credit, was announced in September 1978. The basic objective of the multi-agency approach is to facilitate greater effectiveness of all the agencies involved in rural credit—commercial banks, regional rural banks (RRBs) and co-operative banks—an avoidance of disparate policies and enlargement of the total available of institutional finance to the rural sector. The branch licensing policy is basically guided by considerations of evolving a well-differentiated structure of the banking system and reducing regional imbalances in banking development. The programme envisages the opening of about 6,500 branches in the rural and semi-urban areas during the three

years 1979-81. For this purpose, district-wise plans are being chalked out. Special efforts are being made to facilitate the establishment of RRBs wherever the situation warrants them.

CHAPTER 2

COMMERCIAL BANKING

Branch Expansion : Policy and Progress

2.1 In the first decade after the nationalisation of the 14 major commercial banks, over 21,900 new bank offices were opened throughout the country, raising the total number of functioning offices from 8,262 in June 1969 to 30,202, at the end of June 1979. Of the new offices, over half (11,476) were opened in centres where there had previously been no commercial bank office. The average population per bank office declined from 65,000 in June 1969 to about 18,000 in June 1979. This remarkable progress notwithstanding deficiencies in the availability of banking infrastructure persist in some areas. At the end of June 1979, the population per bank office was above average in 13 States/Union Territories (Table 2.1).

2.2 An important development during the year was the formulation, in September 1978, of a new branch licensing policy for the three year period 1979-81. While the overall objective of the policy continues to be the expansion of banking facilities in deficit areas and the reduction of inter-State and inter-district disparities in this regard, other factors such as the emphasis given to rural development, the support necessary for developmental activities and the recommendations of the Dantwala Committee, the James Raj Committee and the Kamath Working Group, have also been taken into account.[1] The policy is based on the multi-agency approach with emphasis on coordination between financial institutions viz., commercial banks, co-operatives and RRBs to avoid wasteful competition and duplication of effort. An outline of the policy is given below :—

(i) The areas—States and districts—which are deficit in commercial banking services, as indicated by population per office that is higher than the national average of 20,000 at the end of June 1978 have been identified. To bring these areas on a par with the national average, it is considered necessary to open about 6,500 new offices in rural and semi-urban centres in the period 1979-81. State/district-wise lists of offices that are required to be opened have been issued to all banks. Further, district-wise plans of expansion are being drawn up by the RBI in consultation with the State Governments and the concerned banks. The allotment of centres in the various States/Union Territories has been taken up and up to 30th June 1979, about 2,000 rural/semi-urban centres have been allotted to various banks for establishing offices in the three year period. Of the total allotments made during the period for opening of branches, 76 per cent were accounted for by backward States of Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Orissa and West Bengal.

(ii) The policy accords top priority to the opening of bank branches in all the community development block headquarters in the country in view of the special position they occupy in the Government's scheme of developmental administration. A time-bound programme has been drawn up so as to ensure that such block headquarters are provided with a bank office by end-June 1979.

[1]. The reference is to :

(a) Committee to study Functioning of Public Sector Banks (James Raj Committee), 1977.

(b) Committee on Regional Rural Banks (Danwala Committee), 1977.

(c) Working Group to Study Problems Arising Out of the Adoption of Multi-Agency Approach in Agricultural Financing (Kamath Working Group), 1976.

TABLE 2.1—STATE-WISE DISTRIBUTION OF BANK OFFICES AS AT THE END OF JUNE 1977, JUNE 1978, DECEMBER 1978 AND JUNE 1979

State/Union Territory	No. of offices as at the end of				Opened during 1977-78 (July 1977 to June 1978)	Of which at unbanked centres	Opened during 1978-79 (July 1978 to June 1979)	Of which at unbanked centres	Population per bank office (in thousands) as at the end of		
	June 1977	June 1978	Dec. 1978	June 1979					June 1978	Dec. 1978	June 1979
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Andhra Pradesh	1,844	2,134	2,314	2,366	289	218	232	162	20	19	18
Assam	354	414	347	446	60	44	32	24	35	33	33
Bihar	1,176	1,397	1,498	1,594	222	162	198	151	40	38	35
Gujarat	1,883	2,077	2,143	2,162	194	143	85	43	13	12	12
Haryana	604	674	695	720	71	50	46	32	15	14	14
Himachal Pradesh	253	292	311	313	39	32	21	14	12	11	11
Jammu & Kashmir	285	337	256	371	52	41	34	30	14	13	12
Karnataka	2,138	2,339	2,480	2,531	204	135	193	132	13	12	12
Kerala	1,705	2,011	2,059	2,098	306	238	87	59	11	10	10
Madhya Pradesh	1,247	1,465	1,578	1,626	218	175	162	122	28	26	26
Maharashtra	2,671	2,913	3,062	3,113	243	123	200	98	17	16	16
Manipur	23	32	33	35	9	9	3	1	34	33	31
Meghalaya	41	49	53	53	8	6	4	4	21	19	19
Nagaland	22	29	32	33	7	5	4	3	18	16	16
Orissa	529	660	698	718	131	104	59	46	33	31	31
Punjab	1,271	1,425	1,461	1,469	154	118	44	22	10	9	9
Rajasthan	1,022	1,150	1,277	1,317	128	94	167	136	22	20	20

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tamil Nadu	2,307	2,552	2,635	2,675	246	181	123	87	16	16	15
Tripura	49	67	69	69	17	11	2	2	23	23	23
Uttar Pradesh	2,714	3,055	3,246	3,369	342	221	313	239	29	27	26
West Bengal	1,626	1,804	1,866	1,910	179	97	106	52	25	24	23
Andaman & Nicobar Islands	7	12	12	12	5	4	—	—	10	10	10
Arunachal Pradesh	11	13	17	17	2	2	4	3	36	28	28
Chandigarh	71	74	75	76	3	1	2	1	3	3	3
Dadra & Nagar Haveli	4	4	4	4	—	—	—	—	19	19	19
Delhi	709	768	810	820	60	7	54	2	5	5	5
Goa, Daman & Diu	190	216	223	225	26	21	9	7	4	4	4
Lakshadweep	5	5	5	5	—	—	—	—	6	6	6
Mizoram	4	6	12	12	2	—	6	6	55	28	28
Pondicherry	37	42	43	43	5	3	1	—	11	11	11
TOTAL	**24,802**	**28,016**	**29,504**	**30,202**	**3,222**	**2,245**	**2,191**	**1,478**	**20**	**19**	**18**

Note : (1) 8 Offices were closed during the period July 1977 to June 1978.
(2) 5 Offices were closed during the period July 1978 to June 1979.
(3) Data for Sikkim are not readily available.

(*Source:* Department of Banking Operations and Development, R.B.I.)

TABLE 2.2—BANK GROUP-WISE DISTRIBUTION OF OFFICES OPENED DURING 1977-78 AND 1978-79

Bank Group	New offices opened by commercial banks						Bank offices as on			Number of banks as on		
	1977-78			1978-79								
	July-December 1977	January-June 1978	July-June 1977-78	July-December 1978	January-June 1979	July-June 1978-79	June 30, 1978	December 31, 1978	June 30, 1979	June 30, 1978	December 31, 1978	June 30, 1979
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. State Bank of India	309 (200)	145 (93)	454 (293)	168 (84)	73 (43)	241 (127)	4,813	4,979	5,052	1	1	1
2. Associate Banks of State Bank of India	142 (92)	51 (22)	193 (114)	105 (69)	38 (22)	143 (91)	2,192	2,297	2,335	7	7	7
3. 14 Nationalised Banks	820 (553)	385 (254)	1,205 (807)	566 (316)	224 (151)	790 (467)	13,745	14,309	14,533	14	14	14
4. Regional Rural Banks	394 (346)	233 (214)	627 (560)	318 (298)	243 (226)	561 (524)	1,405	1,723	1,965	48	51	56
5. Other Scheduled Commercial Banks	519 (350)	203 (104)	722 (454)	334 (195)	116 (68)	450 (263)	5,659	6,010	6,126	38	39	39
6. Foreign Banks	1 (—)	—	1 (—)	—	—	—	129	129	129	14	14	14
7. All Scheduled Commercial Banks	2,185 (1,541)	1,017 (687)	3,202 (2,228)	1,491 (962)	694 (510)	2,185 (1,472)	27,943	29,447	30,140	122	126	131
8. Non-Scheduled Commercial Banks	13 (12)	7 (5)	20 (17)	1 (1)	5 (5)	6 (6)	73	57	62	6	5	5
9. All Commercial Banks	2,198 (1,553)	1,024 (692)	3,222 (2,245)	1,492 (963)	699 (515)	2,191 (1,478)	28,016	29,504	30,202	128	131	136

Note : Figures in brackets are numbers of unbanked centres in which offices were opened.

(*Source :* Department of Banking Operations and Development, R. B. I.)

TABLE 2.3—POPULATION GROUP-WISE DISTRIBUTION OF COMMERCIAL BANKS, OFFICES

(Number of offices as at the end of the month)

	June 1975	% to total	December 1975	% to total	June 1976	% to total	December 1976	% to total
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rural	6,806	36.3	7,385	36.1	7,687	36.2	8,839	37.4
Semi-urban	5,569	29.7	6,164	30.1	6,387	30.1	7,024	29.7
Urban	3,267	17.5	3,589	17.6	3,739	17.6	4,135	17.5
Metropolitan/Port town	3,088	16.5	3,308	16.2	3,407	16.1	3,657	15.4
Total	**18,730**	**100.0**	**20,446**	**100.0**	**21,220**	**100.0**	**23,655**	**100.0**

	June 1977	%to total	December 1977	% to total	June 1978	% to total	December 1978	% to total	June 1979	% to total
	9	10	11	12	13	14	15	17	17	18
Rural	9,532	38.4	11,092	41.0	11,802	42.1	12,806	43.4	13,333	44.1
Semi-urban	7,211	29.1	7,493	27.8	7,586	27.1	7,778	26.4	7,845	26.0
Urban	4,263	17.2	4,445	16.5	4,542	16.2	4,668	15.8	4,717	15.6
Metropolitan/Port town	3,796	15.3	3,966	14.7	4,086	14.6	4,252	14.4	4,307	14.3
Total	**24,802**	**100.0**	**26,996**	**100.0**	**28,016**	**100.0**	**29,504**	**100.0**	**30,202**	**100.0**

Note : Rural Centres : Places with population up to 10,000. Semi-Urban Centres : Places with population over 10,000 and up to 1,00,000. Urban Centres : Places with population over 1,00,000 and up to 10,00,000. Metropolitan Centres : Places with population over 10,00,000.

(*Source* : Department of Banking Operations and Development, R. B. I.)

(iii) The average population per bank office in certain districts may not always constitute an adequate criterion for the spread of banking in rural and semi-urban areas of the district, because of the bias brought in by concentration of bank offices in urban centres. In such cases, additional licences for branches in rural and semi-urban areas will be granted for reducing the imbalance.

(iv) It is recognised that it would not be desirable to completely stop further expansion in urban and metropolitan centres and port towns. These centres still offer scope for business which could help offset the impact that large-scale expansion in rural and semi-urban areas, particularly in backward areas, will have on the viability of banks. The new policy hence permits some further expansion in urban/metropolitan areas, on a highly selective basis. For this purpose, the existence of offices of urban co-operative banks (UCBs) will also be taken into account.

(v) RRBs have a significant role to play in the financing of the rural sector. The establishment of new RRBs and the expansion of the branches of existing RRBs will be encouraged. In order to identify the areas where new RRBs could be established, a district-wise study is being conducted, priority being given to districts having weak commercial and cooperative banking structure. RRBs have so far been sponsored only by commercial banks. In order to develop a closer linkage between apex cooperative banks and RRBs, wherever possible, joint sponsorship of RRBs by apex banks and commercial banks will be encouraged. In appropriate cases, sponsorship of RRBs by apex co-operative banks singly could also be considered. For the present, RRBs will continue to be organised under the existing statute. As regards the area of operations of RRBs, no rigid norms are proposed to be prescribed and a flexible approach will be adopted. In the matter of branch expansion in rural areas, in the districts where RRBs have been established or will be established hereafter, they will be accorded priority. In cass where there are special schemes of financing agriculture and where RRBs are not in a position to expand immediately, the concerned lead bank of the district will be generally allowed to open branches. However, this does not preclude commercial banks from opening new branches (including Agricultural Development Branches), whereever considered essential, or continuing their existing branches in the command areas of RRBs. In areas where no RRBs are functioning or are planned to be established, preference will be given to lead banks in their lead districts for opening offices in rural areas.

(vi) At present, some of the lead banks do not have an adequate branch coverage in their lead districts for effectively discharging their lead responsibility. In the future allocations of centres, the concerned lead banks will be asked to open more branches in their lead districts, within the overall objective set out earlier. Swapping of lead responsibility among the banks in the context of their regional character is also permitted.

(vii) Banks which have a regional character, will not be generally asked to open branches in far-flung areas but will be asked to concentrate on their own areas of operation or expand in the adjoining deficit areas on a selective basis.

2.3 During the year 1978-79 (July-June) the principal aim of branch expansion policy continued to be that of establishing bank offices in areas inadequately served by such services. However, in accordance with the decision taken by the RBI in January 1978 to slow down the pace of expansion and to place emphasis on consolidation and strengthening of the existing structure, the total number of offices opened during the year, at 2,191, was lower than that for the previous year (3,222). However, the emphasis on the thrust into unbanked areas quickened and 1,478 offices (or 67 per cent of the total new offices) were opened in such areas. The bulk of three newly banked centres (4.42 per cent) were in the backward States and Territories of the North Eastern Region, Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, Uttar Pradesh and West Bengal.

Offices of Indian Commercial Banks in Foreign Countries

2.4 During the year under review, four Indian banks opened 10 offices in foreign countries; of these four were in U.K., two in U.S.A. and one each in Hong Kong, Cayman Islands, Channel Island and Bahamas. The total number of Indian bank offices abroad at the end of June 1979 was 123. Of the 11 Indian banks having offices abroad, Bank of Baroda accounted for 54 offices and Bank of India for 23 offices. Country-wise the largest concentration of Indian bank offices was in U.K. (41) followed by Hong Kong (14), Fiji Islands (10), Kenya (9), Singapore (7) and Mauritius (6).

2.5 The aggregate deposits of the Indian banks' offices abroad increased from Rs. 1,226 crores, as at the end of December 1977, to Rs. 1,396 crores, as at the end of June 1978. Credit extended by these offices increased from Rs. 850 crores as at the end of December 1977 to Rs. 977 crores as at the end of June 1978.

Deposits Growth

2.6 The deposit resources of scheduled commercial banks increased substantially during 1978-79 (July-June). Aggregate deposits of scheduled commercial banks showed a rise of Rs. 4,556 crores during the year 1978-79 which was, in absolute amount, marginally larger than the rise (Rs. 4,410 crores) in the previous year (June 24, 1977 to June 30, 1978) (Table 2.4). However, the rate of growth of deposits at 19.5 per cent during the year was lower than in the previous year (23.3 per cent). Category-wise, demand and time deposits went up by Rs. 1,162 crores (12.6 per cent) and Rs. 3,394 crores 24.1 per cent) during 1978-79, as compared with Rs. 1,929 crores (26.5 per cent) and Rs. 2,481 crores (21.4 per cent), respectively, during 1977-78.

2.7 Time deposits accounted for 74.5 per cent of the incremental deposits as against 56.3 per cent in the previous year; the relatively larger increase in time deposits was partly statistical, because of a change in procedure for determining demand/time portion of savings deposits[1]

1. The change in procedure is indicated in the section on "Banking Legislation/Regulation."

TABLE 2.4—SCHEDULED COMMERCIAL BANKS' DATA

(Rs. Crores)

	Outstanding as on			Variations during	
	June 24, 1977	June 30, 1978	June 29, 1979*	1977-78 (2-1)	1978-79* (3-2)
	1	2	3	4	5
1. Aggregate Deposits	**18,903**	**23,313**	**27,869**	**+4,410**	**+4,556**
(*a*) Demand Deposits	7,290	9,219	10,381	+1,929	+1,162
(*b*) Time Deposits	11,613	14,094	17,488	+2,481	+3,394
2. Total Bank Credit	**13,491**	**15,694**	**18,538**	**+2,203**	**+2,844**
Of which					
(*a*) Food procurement advances	2,536	2,525	2,996	—11	+471
(*b*) Bank credit excluding food advances	10,955	13,169	15,542	+2,214	+2,373
3. Bills rediscounted with the R. B. I.	116	101	77	—15	—24
4. Gross Bank Credit (2+3)	**13,607**	**15,795**	**18,615**	**+2,188**	**+2,820**
5. Investments in Government and other approved securities	6,180	7,552	9,418	+1,372	+1,866
(*a*) Government securities	4,352	5,497	6,908	+1,145	+1,411
(*b*) Other approved securities	1,828	2,055	2,510	+227	+455
6. Cash and Balances with the R. B. I.	1,563	2,755	3,457	+1,192	+702
7. Borrowings from the R. B. I.	563	335	659	—228	+324
8. Credit-Deposit Ratio	71	67	67		
9. Gross Credit-Deposit Ratio	72	68	67		
10. Credit (excluding food credit) — Deposit Ratio	58	56	56		
11. Gross Credit (excluding food credit) —Deposit Ratio	59	57	56		
12. Investment-Deposit Ratio	33	32	34		

*Provisional.

(Source : Returned received under Section 42(2) of the RBI Act, 1934)

2.8 Both the categories of non-resident deposits recorded significant increases (Table 2.5). The stipulation about the minimum period of one year and the maximum period of five years applicable to deposits under the Foreign Currency (Non-Resident) Accounts Scheme was discontinued, effective June 5, 1979, thus bringing such deposits on a par with all other deposits accepted by banks.

TABLE 2.5—NUMBER OF ACCOUNTS AND OUTSTANDING BALANCES UNDER NON-RESIDENT (EXTERNAL) RUPEE ACCOUNTS AND FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS

Non-resident (External) Rupee Accounts

As at the end of	No. of accounts	Amount (In Crores of Rupees)
March 1978	2,48,621	325
March 1979	3,66,574	484

Foreign Currency (Non-resident) Accounts

As at the end of	Foreign Currency	No. of accounts	Amount of deposits ('000)
December 1978	£ Stg.	7,445	129,36
December 1977*	£ Stg.	4,496	72,96
December 1978	U. S. $	29,690	14,24,06
December 1977*	U. S. $	23,048	12,07,05

*Revised figures.

(*Source* : Department of Statistics and Exchange Control Department, R. B. I.)

Credit Trends

2.9 Alongside deposits, credit also recorded a high rate of growth during the year. However, the pace of increase was not uniform and two separate phases can be distinguished in the credit expansion during the year—a slackness in the early months followed by a pronouncedly rapid growth in credit, accentuated by the disruptions on account of the agitation by bank employees. Towards the end of the year the pace of increase abated under the influence of restrictive policy measures.

2.10 Over the four-month period end-June-end-October 1978, coinciding with the latter part of the conventional slack season, the expansion in gross bank credit was only Rs. 428 crores. Of this, as much as Rs. 417 crores was the expansion during the month of October 1978. During this phase, banks repaid their borrowings from the RBI; the outstandings of bills rediscounted with the RBI also declined. Credit expansion in this four-month period was thus financed mainly with banks' own resources, despite which there was so much excess liquidity in the system as indicated by the liquidity ratio of over 35 per cent at the end of October 1978.

2.11 The gross bank credit expansion between end-October 1978 and end-June 1979 was of the order of Rs. 2,392 crores. The prolonged agitation by bank employees from mid-December 1978 to the third week of January 1979 resulted in dislocation of clearing operations throughout the country and contributed in part to an abnormal inflation of credit figures. To assist banks in this period of stress, the RBI liberalised the conditions of access to it.

2.12 Banks' borrowings from the RBI went up from Rs. 247 crores in November 1978 (last Friday) to Rs. 357 crores in December 1978 and further to Rs. 548 crores in January 1979. The outstanding bills rediscounted by the RBI also rose from Rs. 55 crores in November 1978 to Rs. 89 crores in January 1979. This sharp increase in refinance accommodation during this period was the result both of availability of higher refinance limits as well as larger utilisation of these limits. For instance, with the increase in the level of food credit, food refinance entitlement of banks went up from Rs. 146 crores in November 1978 to Rs. 225 crores in January 1979 and the utilisation ratio went up from 11 per cent to 69 per cent. The stand-by refinance limit for meeting "clearing imbalances" (which are to be repaid within three days from the date of drawal), as well as discretionary refinance limits, had to be temporarily stepped up in order to mitigate the difficulties faced by banks on account of dislocation of clearing arrangements and also to enable them to meet the genuine seasonal demand for funds. Thus, discretionary refinance limits were enhanced from Rs. 69 crores in November 1978 to Rs. 130 crores in January 1979.

2.13 With the gradual restoration of normalcy in the banking industry, there was a decline in credit in February 1979. But thereafter, there was a renewed spurt in credit. While limits of discretionary refinance were brought down to Rs. 56 crores during March 1979 and further to Rs. 33 crores by end of June 1979[1], banks continued to draw heavily on their automatic entitlements particularly in respect of food and export refinance. The availment of refinance under the "small farmers' window" ranged between Rs. 3 crores and Rs. 5 crores during July to November 1978 but went up to Rs. 22 crores in March 1979 and further to Rs. 53 crores by the end of June 1979. The total refinance limtis[2] of banks at the end of June 1979 were higher at Rs. 751 crores as against Rs. 435 crores in June 1978; similarly the availment of refinance against these limits as at the end of June 1979 was higher at Rs. 600 crores as against Rs. 187 crores a year ago due to increase in refinance for food, exports and small farmers' window. The bill rediscounting limits at Rs. 118 crores were, on the other hand, lower in June 1979 as compared with those in June 1978 (Rs. 187 crores). The outstanding amount, as at the end of June 1979 (Rs. 77 crores), was also somewhat lower than in June 1978 (Rs. 101 crores). The average cost of refinance availed of by banks, as at the end of June 1979 (9.24 per cent), was slightly higher than that a year ago (9.06 per cent) due to the higher utilisation of limits this year. In the case of bills rediscounted with the RBI the average rate of interest was, however, marginally lower than in June 1978.

2.14 Apart from higher utilisation of refinance limits since December 1978 banks depleted their liquid assets, the liquidity ratio coming down from 35.7 per cent in November 1978 to 34.1 per cent in June 1979. Besides this, substantial recourse by banks to non-banking financial institutions in the form of call money and issue of Participation Certificates (PCs) was also made for expansion of credit.

2.15 The increase in gross credit over the year as a whole was Rs. 2,820 crores (17.9 per cent) as compared with a rise of Rs. 2,188 crores (16.1 per cent) in the last year. Advances for food procurement rose by Rs. 471 crores (18.7 per cent) in 1978-79, in contrast to a decline of Rs. 11 crores in the previous year. Gross non-food credit which stood at Rs. 13,270 crores at the end of June 1978, showed a steep increase between end-August and end-December from Rs. 13,082 crores to Rs. 15,515 crores, but declined thereafter to Rs. 15,347 crores by end-February 1979. Gross non-food credit moved narrowly thereafter and stood at Rs. 15,619 crores on June 29, 1979 showing an increase of Rs. 2,349 crores (17.7 per cent) over the year, as against Rs. 2,199 crores (19.9 per cent) in the previous year. The incremental non-food (gross) credit-deposit ratio since December 1, 1978, which worked out to 93.9 per cent at the end of December 1978, fell to 73.5 per cent by end-March 1979 and to 48.9 per cent by end-June 1979. The gross credit-deposit ratio at 66.8 per cent at end-June 1979 was lower by one percentage point over the level a year ago (67.8 per cent).

Credit Policy

2.16 In view of the sizeable expansion in money supply in two successive years 1976-77 and 1977-78 and in the light of prospects of a moderate growth of national income in 1978-79, the objective of Reserve Bank's credit policy during 1978-79 continued to be to restrain credit expansion and relate it to increases in output, economic activity and employment creation. The restrictive measures taken during the year included the raising of the Statutory Liquidity Ratio (SLR), stipulation of an incremental non-food gross credit-deposit ratio as a guideline to banks, imposition of penalty for default in maintaining SLR and Cash Reserve Ratio (CRR) and exhortation to banks to keep, at a minimum, their reliance on external resources, such as borrowings from the RBI and call money market and recourse to PCs. Simultaneously, the policy of accelerating the flow of credit to weaker sections of society was also pursued.

Measures taken in Mid-May 1978

2.17 The credit policy for the 1978 slack season announced by the RBI on May 15, 1978 was directed towards siphoning off of the excess liquidity prevailing in the banking system which was reflected in the unusually high liquidity ratio of commercial banks (around 36 per cent) throughout April 1978. To restrict the refinance facilities available from the Reserve Bank, the Bank raised the basic level at which refinance for food credit became available from Rs. 1,500 crores to Rs. 2,000 crores, effective June 1, 1978. The automatic refinance facility under which banks were entitled to refinance to the extent of one per cent of their demand and time liabilities, as on the last Friday of March 1977, provided the borrowings were against the Government or other approved securities, was also withdrawn as from June 1, 1978. However, for meeting clearing imbalances, temporary accommodation was provided under discretionary or stand-by arrangements at the Bank Rate. Further, for neutralising the impact on money supply of the inflow of resources from abroad, through Non-Resident (External) Rupee Accounts and Foreign Currency (Non-Resident) Accounts Scheme, banks were asked to deposit in terms of rupees, the equivalent of one-half of the net aggregate amount accruing after June 1, 1978 to each

1. Figures of outstanding refinance/bills rediscounted as at the end of June 1979 are provisional.

2. Excluding refinance for import of capital goods, shipping loans(SAFAUNS), duty drawback and refinance to Rigional Rural Banks

banks under these two categories of accounts[1]. These special deposits were to carry interest at 6.5 per cent per annum. The interest on cash reserves of banks with the Bank above the statutory minimum (including the balances kept under the 10 per cent incremental reserve ratio) was also raised from 6.0 per cent to 6.5 per cent, effective June 1, 1978.

November 1978 Measures

2.18 The period March 31, 1978 to November 10, 1978 witnessed sizeable monetary expansion, which came on top of a substantial increase in the preceding two years. In fact the rate of expansion of credit exceeded, on an average, Rs. 100 crores per week during successive eight weeks beginning from September 22, 1978. Such a rapid expansion in credit became a matter of concern particularly because the growth in national income in 1978-79 was expected to be about 3 to 4 per cent. It was, therefore, considered imperative to contain credit expansion potential. With this objective two additional measures were taken in November 1978 ; the first was the stipulation of an incremental credit-deposit ratio and the second the raising of S.L.R. Banks were advised to so plan their non-food credit expansion that the incremental gross non-food credit-deposit ratio for the period December 1, 1978 to end-March 1979 would be well within 40 per cent. It was impressed on them that the credit provided by them should be related to increases in output, economic activity and employment creation. Secondly, the SLR was raised from 33 per cent to 34 per cent with effect from December 1, 1978 ; this percentage was to be strictly applied to additional deposits, regardless of any excess in SLR that any particular bank might have as on December 1, 1978. Banks were also advised that discretionary refinance would be limited to very special situations or situations of extreme need and recourse to Reserve Bank should be sparing and as a last resort. It was also clarified that, while the earlier emphasis on priority sectors and on utilising a substantial proportion of deposits mobilised in rural areas in those areas remained valid, it should be ensured that, even in priority sectors and in rural areas, they reached out particularly to the weaker or poorer sections including members of scheduled castes and scheduled tribes. It was also emphasised that banks should monitor the utilisation of bank credit by borrowers more closely than before and implement the norms set by the Tandon Committee. They should not extend concessions in interest charges, in particular to relatively large borrowers, as such a policy would have adverse effects on banks' profitability, and should keep a careful watch on the return flow of funds. Banks were further asked to ensure that there was no leakage of credit from large or small borrowers to socially undesirable sectors and to pay greater attention to diverting credit away from non-priority areas to priority areas.

March 1979 Measures

2.19 In mid-March 1979, the Reserve Bank pointed out to banks the inflationary potential being built up in the economy and advised them that, as credit extension to the commercial sector had been the dominant factor contributing to the monetary expansion in 1978-79, it was necessary to ensure that any further increase in credit was related strictly to the needs of increase in production. As the seasonal demand in respect of commodities like foodgrains, sugar, cotton, tea and tobacco would continue and even increase in the ensuing months, it was all the more necessary that credit to other borrowers, who had already drawn heavily on the banking system, should be carefully regulated to meet only the most essential requirements. The banks were therefore asked (a) to strengthen their internal machinery of data collection and monitoring to enable them to keep a close watch over credit expansion from week to week (b) to review credit limits of Rs. 50 lakhs and above and also wherever 60 to 65 per cent of the existing cash credit limit to any party was already utilised, grant of further credit should be subject to greater scrutiny and related to clearly identifiable purposes such as increase in production or existing commitments, and (c) to keep to the minimum their reliance on external resources such as borrowings from call money market and sale of PCs.

2.20 It was also observed that in spite of the directive to banks raising the SLR from 33 per cent to 34 per cent from December 1, 1978, banks had not increased their investments in Government securities but continued to expand credit and thus used up not only their own resources but also increased their resource to outside sources, such as call money and issue of PCs. The banks which defaulted in maintaining the stipulated SLR and CRR were asked to take immediate steps to make good the deficiency. To ensure that this was done, penalty on the non-observance of SLR and CRR was introduced. With effect from March 30, 1979, in respect of banks which did not maintain the SLR of 34 per cent of demand and time liabilities, and/or defaulted in respect of stipulated reserve ratios, access to refinance/rediscount facilities was not to be made available until such deficiencies were made good. In addition to defaulting as above, if banks had as on March 30, 1979 utilised refinance/rediscount facilities, an additional interest of 3 per cent was to be charged on the portion of refinance/rediscount accommodation equivalent to the shortfall in SLR and CRR.

Credit Policy for Slack Season, 1979

2.21 Further in May 1979, banks were advised that their non-food credit expansion in 1979-80 should be significantly less than in the previous year, in both relative and absolute terms. As disbursement of credit for financing food procurement operations was expected to be larger in the following months, it was emphasised that banks should restrict non-food credit. They were also asked to ensure that the return flow of funds from seasonal industries, such as sugar, textiles, etc., which had borrowed heavily in the past, was accelerated. For exercising adequate control on credit at the branch level, banks were asked to evolve a set of internal guidelines on the following lines. (1) While fixing new credit limits or considering enhancement of existing credit limits, a full and detailed scrutiny of the proposals should be made and in this scrutiny, increases sought on expectations of further price rises should be disregarded. Any additional accommodation should be related strictly to increase in output or in permitted inventories. (2) For revising existing credit limits above Rs. 50 lakhs, great discretion should be exercised. The continuous and extensive dependence of large borrowers on bank credit for working capital purposes should be discouraged. (3) Special care should be exercised in sanctioning credit and monitoring its use in respect of sensitive commodities and such credit should be restricted particularly in respect of traders.

2.22 The excessive recourse by banks to PCs was the cause of some concern and the RBI constituted, in early April 1979, a Working Group to review the banks' recourse to PCs and borrowings in the call money market from financial institutions. The Working Group recommended, *inter alia*, that the funds raised through PCs be brought under the purview of the CRR and SLR. While the recommendations of the Group were under consideration, the Reserve Bank decided, to begin with, to initiate action to discourage commercial banks from excessive recourse to PCs. However with a view to ensuring that action in this regard does not disput the operations of banks and also does not make it difficult for other financial institutions to shift to alternative avenues short-term investment, the bank decided to place out the process of bringing PCs under SLR/CRR in stages.

2.23 All scheduled commercial banks were advised on June 21, 1979, that, with effect from the last Friday of July 1979, and thereafter, the outstanding PCs issued by them would cease to be treated as contingent liabilities, but would be treated as deposits and should be subject to SLR and 6 per cent CRR requirements in phases—50 per cent from last Friday of July 1979, 75 per cent from last Friday of August 1979 and 100 per cent i.e. the entire amount of outstanding PCs from the last Friday of September 1979. Further, these banks were required to maintain with the RBI an additional average daily balance equivalent to not less than 10 per cent of any increase in PCs over the outstanding level as on the last Friday of July 1979. The amount of PCs issued should not be deducted, as was the practice so far, from the figure

of their total advances; and the amount of PCs purchased is not to be included in total advances, but should be shown as advances to banks. Deposits arising from the issue of PCs will be exempt from the purview of the Reserve Bank's directive on interest rates. The maximum rate of interest at which PCs can be issued will continue to be 10 per cent per annum.

Changes in Interest Rates

2.24 While the overall interest rates structure of commercial banks continued unchanged during the year, some adjustments were made to bring lending rates in line with those of other financial institutions.

2.25 Interest rates charged by commercial banks and RRBs on loans granted by them to co-operatives were also revised to bring them in line with the rates charged by co-operative banks. Commercial banks and RRBs were directed to charge, with effect from March 1, 1979, interest at 9 per cent on specified loans granted to primary societies and farmers' service societies (FSS). The rate of interest was reduced to 8 per cent with effect from March 15, 1979, in respect of term loans for minor irrigation/ land development and for diversified purposes to small farmers. This would enable the co-operatives to retain a margin of 1¼ per cent in the case of term loans and 2 per cent or more in the case of short-term loans and make credit available to the ultimate borrower at the same rate as those charged to agriculturists borrowing directly from commercial banks and RRBs.

2.26 Consequent to the Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC) reducing is refinance rates and also the maximum rates chargeable by the lending institutions to the ultimate borrowers, effective March 15, 1979, banks were advised to charge interest on loans of not less than three years to farmers (i) for minor irrigation and land development at a rate not exceeding 9.5 per cent (as against the earlier rate of 10.5 per cent) and (ii) for diversified purposes (a) at a rate not exceeding 9.5 per cent to small farmers and (b) not exceeding 10.5 per cent to other farmers (as against the earlier rate of 11 per cent for both). The refinance rates of ARDC would be 6.5 per cent for (i) and (ii)(a) and 7.5 per cent for (ii)(b). The revised rates are applicable to all new loans granted from March 15, 1979, irrespective of whether such loans are too small to be eligible for refinance from ARDC or not, and irrespective of whether the bank concerned actually utilised the refinance facility.

Selective Credit Control

2.27 While the general framework of Selective Credit Control continued to remain unchanged adjustments were made in the regulations governing advances against some of the commodities keeping in view the supply position and trends in prices. No changes were made in the minimum lending rates of interest which varied between 14 and 15 per cent.

(i) Sugar

2.28 In the context of the removal of control on prices, movement and distribution of sugar, effective August 16, 1978, and in view of Government's decision that the basis for the valuation of stocks need not be changed during the transition period, scheduled commercial banks were advised on August 29, 1978 not to make any change in the valuation of stocks against which advances had been granted to parties manufacturing sugar. They were further advised that the distinction between levy sotcks and free-sale stocks—(a) not released for sale and (b) released for sale—would be continued notinally, and the respective margins 15 per cent or 65 per cent, as the case may be, for advances might continue to be applied. The valuation of stocks and margin stipulations govering advances against sugar to parties other than those manufacturing sugar remained unchanged. Further, taking into account the impact of falling sugar prices on the working of sick sugar mills and the genuine (temporary) credit needs of the sugar industry banks were advised in September 1978 to consider granting temporary clean loans to deserving sugar mills to a limited extent, not exceeding Rs. 25 lakhs, in the case of each borrower without prior reference to the RBI, subject to certain stipulations. Such loans could be granted up to November 30, 1978 to be repaid as soon as possible after the commencement of the 1978-79 season but in any case not later than May 31, 1979.

2.29 Subsequently, effective October 14, 1978, the national distinction between levy stocks and free-sale stocks of sugar was dispensed with. In view of the comfortable supply position of sugar and good prospects of sugarcane production in the 1978-79 season the minimum margin on advances granted against stocks of sugar to parties manufacturing sugar was stipulated uniformly at 15 per cent of the value of all the stocks charged to the banks as security; the minimum margin and the minimum rate of interest in respect of advances granted to parties other than those manufacturing sugar continued to be 65 per cent and 15 per cent per annum, respectively. While no minimum rate of interest was prescribed for advances against stocks of sugar to parties manufacturing sugar, they were subject to the general minimum lending rate on advances (12½ per cent per annum).

2.30 In the context of the recent rise in prices in general and in prices of some of the sensitive commodities (including sugar) in particular, despite comfortable supply position, banks were advised on June 29, 1979 to keep a strict vigilance on advances to check any tendency to utilise bank finance for hoarding those commodities. Instructions issued in relation to advances against pulses, oilseeds and vegetable oils are given in the respective sections. On sugar advances banks were advised that (a) clean limits of Rs. 25 lakhs permitted earlier, to sugar manufacturing units should be withdrawn and loans should be repaid expeditiously (b) credit drawn by sugar factories for holding stocks of sugar should be reduced in line with the release of stocks from the factories and (c) margin requirements on all advances against sugar should be raised by 10 per cent. Consumers' co-operatives holding stocks under scheme of public distribution organised by Government were, however, exempt from this requirement.

(ii) Cotton and Kapas

2.31 Taking into account the recent relaxation announced by the Textile Commissioner in the limits for cotton stocks held by textile mills, the Bank modified on March 29, 1979 credit control measures relating to advances to mills against raw cotton and kapas. Inventory levels in respect of which bank advances to mills might be made with minimum margins then in force were raised from four weeks' to three months' consumption for mills located in Bombay and Ahmedabad, from eight weeks' to four and half months' consumption for mills in Bihar and West Bengal, from six weeks' to four months' consumption for mills in other parts of India, and from six weeks' to four months' consumption for mills solely engaged in spinning yarn. The minimum margins and interest rate, however, remained unchanged except for consequential changes related to level of stocks. Credit control on adavnces to parties other than mills also remained unchanged with the exception that the level of credit would be 100 per cent of the peak level of credit utilised by a party with the bank in any of the three preceeding years (November to October) viz., 1977-78, 1976-77 and 1975-76, instead of 1975-76, 1974-75 and 1973-74.

2.32 The Bank also reiterated that the level of inventories in respect of industries would continue to be governed by such norms as laid down, whether in pursuance of the recommendations of Study Group on Follow-up of Bank Credit, or otherwise.

(iii) Pulses, Oils and Oilseeds

2.33 On June 29, 1979 scheduled commercial banks were advised to keep minimum margins of not less than 45 per cent (as against 35 per cent earlier) on advances against pulses for processing units and of not less than 60 per cent for others as against 50 per cent earlier. The minimum margin on advances against warehouse receipts was retained at 40 per cent for processors and raised to 50 per cent from 40 per cent for others.

2.34 Banks were also advised to refrain from granting additional limits against vegetable oils and oilseeds to parties other than Government and Government supported organisations; even in the case of such organisations strict security drawals was required to be maintained

Credit Planning

2.35 The mechanism of credit planning has been in operation for several years now to ensure adherence to credit policy requirements and alignment of flows of bank credit with

objectives of the national development plans. The RBI has continued to hold discussions from time to time with major users of credit in the private and public sectors and commercial banks in order to get an idea of the demand for credit. While these techniques of credit planning may be regarded as more directly relevant for short-term credit planning, there are certain instruments of credit planning which are designed to bring about a structural change in commercial bank credit. Three such instruments, viz., national targets for bank lending to priority sectors and in rural areas, Credit Authorisation Scheme (CAS) and Lead Bank Scheme have been used in more recent years to bring about the desired changes in the structure of commercial bank credit.

2.36 While the share of priority sectors in total bank credit had risen to 30 per cent by March 1979 over the years this rise has been accompanied by some reduction in the relative share of large and medium industries in total credit. This gradual process of shift in sectoral distribution of credit, therefore, represents a structural change in the composition of commercial bank credit.

TABLE 2.6—SECTORAL DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT

(Rs. Crores

Items	Outstandings		Variations	Outstandings		Variations
	June 1977	May 1978	May 1978 over June 1977	June 1978	May @ 1979	May 1979 over June 1978
	1	2	3	4	5	6
I. Public Food Procurement	2,536	2,701	—235	2,525	2,584	+59
II. (a) Priority Sectors	3,486	4,236	+750 (37.4)	4,334	5,522	+1,188 (46.5)
(i) Agriculture	1,381	1,655	+274 (13.7)	1,726	2,203	+477 (18.7)
(ii) Small-Scale Industries	1,460	1,723	+263 (13.1)	1,756	2,188	+432 (16.9)
(iii) Other Priority Sectors	645	858	+213 (10.6)	852	1,131	+279 (10.9)
(b) Industry (medium and large)	5,372	6,098	+726 (36.3)	6,249	7,183	+934 (36.5)
(c) Wholesale Trade (Other than food procurement)	1,053	1,373	+320 (16.0)	1,424	1,555	+131 (5.1)
(i) Cotton Corporation India	135	150	+15	138	227	+69
(ii) Food Corporation of India (Fertiliser)	75	243	+168	250	214	—36
(iii) Jute Corporation of India	18	2	—16	2	30	+28
(iv) Other Trade	825	978	+153	1,034	1,104	+70
(d) Other Sectors	1,160	1,367	+207 (10.3)	1,428	1,731	+303 (11.9)
III. Non-food Gross Bank Credit (a+b+c+d)	11,071	13,074	+2,003 (100.0)	13,435	15,991	+2,556 (100.0)
Export Credit (included under item III)	1,129	1,206	+77	1,142	1,447	+305
IV. Gross Bank Credit	13,607	15,375	+1,768	15,960	18,575	+2,615

@ Provisional

Note : 1 Data relate to major banks which account or about 95 per cent of gross bank credit. Further, these data, besides taking into account the bills rediscounted with the RBI, also include bills rediscounted with the IDBI and other approved institutions and participation certificates.

2 Figures in brackets are percentages to the increase in non-food gross bank credit.

(*Source:* Credit Planning and Banking Development Cell, R. B. I.).

Sectoral Development of Credit

2.37 Data on sectoral deployment of gross bank credit are available up to end-May 1979. During the period end-June 1978 to end-May 1979 gross bank credit increased by Rs. 2,615 crores (+16.4 per cent) as compared with a rise of Rs. 1,768 crores (+13.0 per cent) during the corresponding period of 1977-78 (Table 2.6). There was a rise of Rs. 59 crores in public food procurement credit in contrast to a decline of Rs. 235 crores during the same period in the previous year. Non-food gross credit rose by Rs. 2,556 crores during the period as compared with an increase of Rs. 2,003 crores in the same period in 1977-78.

2.38 Advances to priority sectors increased by Rs. 1,188 crores (+27.4 per cent) as against a rise of Rs. 750 crores (+21.5 per cent) earlier. At the end of May 1979, priority sector advances constituted 30.5 per cent of the total (net) bank credit as against 28.0 per cent a year ago. Advances to priority sectors, however, constituted 48.9 per cent of the incremental (net) credit, which was higher than the position (45.9 per cent) recorded a year earlier. Of the additional advances to priority sectors, agriculture and small-scale industries accounted for Rs. 477 crores and Rs. 432 crores, respectively, compared with Rs. 274 crores and Rs. 263 crores, respectively, in the corresponding period of 1977-78. Total advances to agriculture at the end of May 1979 amounted to Rs. 2,203 crores and formed 39.9

per cent of total priority sector advances as against 39.1 per cent a year ago while advances to small-scale industries at Rs. 2,188 crores accounted for 39.6 per cent of total as against 40.7 per cent a year earlier.

2.39 Under the target laid down by the GOI priority sector advances of commercial banks in public sector should have reached a level of not less than one third of their outstanding credit by March 1979. Data available up to end-May 1979 reveal that the banks had made considerable progress towards achieving this target.

2.40 Advances to medium and large industry increased by Rs. 934 crores during end-June 1978 to end-May 1979 as against Rs. 726 crores during end-June 1977 to end-May 1978. The outstandings at the end of May, 1979 stood at Rs. 7,183 crores or 38.7 per cent of gross credit; at end-May 1978 the outstanding were Rs. 6.098 crores or 39.7 per cent of gross credit. Total credit to industry (large, medium and small-scale industry) increased by Rs. 1,366 crores as compared with Rs. 989 crores in 1977-78. The increase during the period was chiefly accounted for by Engineering (Rs. 424 crores), Iron and Steel (Rs. 61 crores), Cotton Textiles (Rs. 84 crores), Chemicals (Rs. 138 crores) and SAFAUNS (Ships Acquired From Abroad Under New Schemes) (Rs. 129 crores). There was an increase of Rs. 131 crores in advances to wholesale trade (other than food procurement) during the period as compared with Rs. 320 crores during June 1977 to May 1978. In the case of wholesale trade, the advances to Cotton Corporation of India, Jute Corporation of India and 'Other Trade' went up by Rs. 69 crores, Rs. 28 crores and Rs. 70 crores, respectively, which was offset to some extent by a decline of Rs. 36 crores in fertilizer credit for Food Corporation of India.

Regional and Rural/Urban Pattern of Credit Development

2.41 Another aspect of credit disbursal which has acquired significance is the regional and rural/urban pattern of credit deployment. Data on statewise credit-deposit ratios of bank offices according to population group, as on the last Friday of June 1978, are presented in Table 2.7. As pointed out in the last year's Report the limitations of these ratios for analytical purposes should be borne in mind. They do not by themselves reflect the extent to which resources mobilised by banks in a State are deployed therein since they do not take into account investment of bank funds in securities of State Governments, debentures of State-level institutions, etc., which contribute to the financing of developmental and infrastructural projects. Further, one should take a note of what is known as "Migration of Credit", that is, loans sanctioned by banks in a given area and outstanding in their books and hence included in the figure of total credit for that area may not, in all cases, relate to the financing of activities in that area. Also such ratios may tend to be high in some cases because of the low magnitudes of deposits on which they are worked out.

2.42 Credit-deposit ratios show a wide range of variations among different regions : for instance the ratios varied from 6.3 per cent in Sikkim to 346.7 per cent in Chandigarh. Region-wise the ratio exceeded 60 per cent for the Northern Region, Western Region and Southern Region. The intra-regional variations were marked except in the Central Region where the ratio was 53.7 per cent in Madhya Pradesh and 47.1 per cent in Uttar Pradesh. Although it is difficult to say whether the eventual objective should be to facilitate the raising of these ratios to a particular level, it cannot be denied that a large leeway has to be made up by banks in raising the ratios in many areas (Table 2.7).

2.43 An equally important aspect of deployment of credit is the imbalance between rural and semi-urban areas, on the one hand, and urban/metropolitan areas, on the other. The unusually low credit-deposit ratios in certain rural areas have given rise to the apprehension that rural branches might become the conduit for the flow of resources from the rural to the urban areas. In view of this factor, public sector banks were advised that by March 1979 their rural and semi-urban branches separately should achieve a credit- deposit ratio of at least 60 per cent.[1] Looked at from this point of view, the imbalances in the ratios are glaring. Thus, at the end of June 1978, for the country as a whole the credit-deposit ratios for the rural and semi-urban areas were 52 5 and 47.4 respectively. Only the Southern Region as a whole reported relatively a high credit-deposit ratio for rural (76.3 per cent) and semi-urban (59.7 per cent) areas. In the remaining regions the ratios were much lower. There were marked variations even within each region also. Banks need to make intensive efforts in realising the national target referred to earlier.

1. The private sector banks should reach the target within a specified time.

TABLE 2.7—STATE-WISE CREDIT-DEPOSIT RATIOS OF OFFICES OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS ACCORDING TO POPULATION GROUPS

(As on the last Friday of June 1978)

Region/State/Union Territory	Rural	Semi-urban	Urban/ Metropolitan	Total
	1	2	3	4
Northern Region	**37.2**	**47.4**	**107.9**	**89.5**
Haryana	57.3	62.1	62.6	61.4
Himachal Pradesh	25.3	24.3	—	24.8
Jammu & Kashmir	18.4	47.7	22.1	23.7
Punjab	21.9	37.4	46.3	37.0
Rajasthan	84.4	64.5	52.3	60.8
Chandigarh	19.4	—	247.4	346.7
Delhi	456.6	—	117.2	117.5
North-Eastern Region	**29.6**	**34.5**	**50.1**	**38.0**
Assam	30.9	42.1	51.4	43.4
Manipur	42.9	7.1	35.4	36.6
Meghalaya	16.6	15.9	—	16.0
Nagaland	3.5	34.7	—	27.9
Tripura	67.3	34.8	—	41.1
Arunachal Pradesh	6.8	-	—	6.8
Mizoram	13.3	7.1	—	7.4
Sikkim	—	6.3	—	6.3

	1	2	3	4
Eastern Region	**52.1**	**34.1**	**67.7**	**58.7**
Bihar	70.1	38.0	41.2	43.1
Orissa	72.7	64.7	54.5	60.7
West Bengal	33.3	24.2	72.9	63.9
Andaman & Nicobar Islands	27.9	19.8	—	21.0
Central Region	**52.0**	**52.0**	**46.4**	**48.8**
Madhya Pradesh	61.6	55.2	51.3	53.7
Uttar Pradesh	49.5	50.8	44.7	47.1
Western Region	**41.0**	**42.1**	**73.4**	**65.9**
Gujarat	30.0	34.5	66.3	50.4
Maharashtra	66.9	50.6	74.9	72.5
Dadra & Nagar Haveli	83.5	—	—	83.5
Goa, Daman & Diu	25.3	48.3	—	40.5
Southern Region	**76.3**	**59.7**	**89.0**	**79.0**
Andhra Pradesh	95.5	68.1	64.0	69.0
Karnataka	76.9	67.2	88.5	81.8
Kerala	48.4	43.2	94.8	61.9
Tamil Nadu	90.5	66.5	104.1	94.2
Lakshadweep	6.6	—	—	6.6
Pondicherry	91.5	33.9	71.1	68.2
ALL INDIA	**52.5**	**47.4**	**79.9**	**69.9**

(*Source* : Returns on Aggregate Deposits and Gross Bank Credit).

2.44 Data on frequency distribution of districts based on credit-deposit ratios for rural and semi-urban bank offices for June 1978 are presented in Table 2.8. According to this, rural bank branches had achieved 60 per cent and above credit-deposit ratio in 148 out of 388 districts as at end-June 1978. Semi-urban branches could achieve 60 per cent and above credit-deposit ratio in 113 out of 346 districts at the end of June 1978. Thus, 38 per cent of district covered by rural bank braches and 33 per cent of districts covered by semi-urban bank branches showed a credit-deposit ratio of 60 per cent and above at the end of June 1978.

TABLE 2.8—FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRICTS BASED ON CREDIT DEPOSIT RATIOS FOR RURAL AND SEMI-URBAN BANK OFFICES

(As on the last Friday of June 1978)

(Amount in Rupees Crores)

Frequency (Credit-Deposit Ratio)	Rural			Semi-Urban		
	No. of Districts	Deposits @	Advances	No. of Districts	Deposits @	Advances
	1	2	3	4	5	6
Up to 20%	72	445 (6)	54	40	582 (15)	92
20%— 30%	53	491 (9)	120	57	815 (14)	195
30%— 40%	49	303 (6)	109	55	1,086 (20)	373
40%— 50%	29	137 (5)	62	46	703 (15)	324
50%— 60%	37	269 (7)	147	35	529 (15)	280
60% and above	148 (38.1)£	374 (5)	756	113 (32.7)£	1,467 (13)	1,193
Total	**388**	**2,379**	**1,248**	**346**	**5,182**	**2,457**

@Figures in brackets represent amount of deposits per district under each size class (in crores of rupees).

£ As percentage of total number of districts.

(*Source:* Return on Aggregate Deposits and Gross Bank Credit).

2.45 Data on state-wise frequency distribution of districts based on credit-deposit ratios as at end-June 1978 for rural and semi-urban bank offices are presented in Table Nos. 2.9 and 2.10, respectively. It may be seen therefrom that out of 148 districts in which rural bank offices achieved credit-deposit ratio of 60 per cent and over, 19 districts were each from Madhya Pradesh and Andhra Pradesh, 18 from Uttar Pradesh, 16 from Rajasthan, 13 from Karnataka and 11 each from Tamil Nadu and Maharashtra. Of the 113 districts in which semi-urban bank offices reached credit-deposit ratio of 60 per cent and above, 17 districts were from Andhra Pradesh, 13 each from Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, 12 each from Bihar and Karnataka, 10 from Rajasthan, 9 from Tamil Nadu and 8 from Maharashtra.

TABLE 2.9—STATE-WISE FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRICTS BASED

(As on the last Friday

Region/State/Union Territory	Frequency (Credit-Deposit Ratio)								
	Up to 20%			20% — 30%			30% — 40 %		
	No. of Districts	Deposits	Advances	No. of Districts	Deposits	Advances	No. of Districts	Deposits	Advance
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Northern Region	**19**	**218,54**	**25,94**	**11**	**93,91**	**21,56**	**5**	**35,61**	**12,79**
Haryana	..	..	..	..	..	..	2	18,20	6,66
Himachal Pradesh	5	34,36	4,04	4	16,88	3,86	1	7,02	2,72
Jammu & Kashmir	7	20,87	2,53	2	11,12	2,49	..	..	..
Punjab	5	161,05	19,02	2	63,15	14,51	1	9,15	3,00
Rajasthan	1	1,95	29	3	2,76	70	1	1,24	41
Chandigarh	1	31	6	..	..	..	..	..	..
Delhi	..	..	..	..	..	..	..	..	..
II. North-Eastern Region	**19**	**15,58**	**1,48**	**5**	**26,71**	**6,47**	**1**	**2,61**	**87**
Assam	2	5,60	80	4	26,04	6,31	1	2,61	87
Manipur	2	29	..	..	..	..	..	..	..
Meghalaya	3	2,64	40	..	..	..	..	..	..
Nagaland	7	2,55	9	..	..	..	..	..	..
Tripura	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Arunachal Pradesh	4	4,35	17	1	67	16	..	..	..
Mizoram	1	15	2	..	..	..	..	..	..
Sikkim	..	..	..	..	..	..	..	..	..
III. Eastern Region	**9**	**69,21**	**8,61**	**11**	**70,70**	**16,60**	**7**	**35,65**	**12,76**
Bihar	5	31,49	3,52	9	28,00	7,22	5	12,04	4,35
Orissa	..	..	..	..	..	..	1	1,64	53
West Bengal	3	37,23	5,03	2	42,70	9,38	1	21,97	7,88
Andaman & Nicobar Islands	1	49	6	..	..	..	..	..	..
IV. Central Region	**15**	**66,32**	**9,78**	**15**	**100,00**	**25,72**	**20**	**51,84**	**17,91**
Madhya Pradesh	5	12,32	1,67	1	1,98	45	12	20,44	7,05
Uttar Pradesh	10	54,00	8,11	14	98,02	25,27	8	31,40	10,86
V. Western Region	**8**	**74,19**	**8,25**	**10**	**178,26**	**43,22**	**8**	**74,73**	**27,58**
Gujarat	5	48,74	4,42	6	98,32	21,64	4	43,29	16,10
Maharashtra	2	20,70	3,68	3	15,96	4,37	4	31,44	11,48
Dadra & Nagar Haveli	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Goa, Daman & Diu	1	4,75	15	1	63,98	17,21	..	..	..
VI. Southern Region	**2**	**85**	**5**	**1**	**21,47**	**6,17**	**8**	**102,50**	**37,37**
Andhra Pradesh	..	..	..	..	..	..	1	2,69	1,05
Karnataka	..	..	..	..	..	..	1	23,29	7,82
Kerala	..	..	..	1	21,47	6,17	4	75,18	28,03
Tamil Nadu	1	9	..	..	..	..	..	..	..
Lakshadweep	1	76	5	..	..	..	..	..	..
Pondicherry	..	..	..	..	..	..	2	1,34	47
ALL INDIA	**72**	**444,69**	**54,11**	**53**	**491,05**	**119,74**	**49**	**392,94**	**109,28**

(*Source:* Return on Aggregate Deposits and Gross Bank Credit).

ON CREDIT-DEPOSIT RATIOS FOR BANK OFFICES IN RURAL CENTRES
of June 1978)

(Amount in lakhs of rupees)

Region/State/Union Territory	Frequency (Credit-Deposit Ratio)											
	40%—50%			50%—60%			60% and above			Total		
	No. of Districts	Deposits	Advances	No. of Districts	Deposits	Advances	No. of Districts	Deposits	Advances	No. of Districts	Deposits	Advances
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Northern Region	**7**	**44,03**	**20,02**	6	**16,89**	**9,32**	**25**	**110,33**	**103,56**	**73**	**519,31**	**193,19**
Haryana	2	8,66	3,65	3	10,17	5,82	4	28,66	21,49	11	65,69	37,62
Himachal Pradesh	..	..	..	..	..	..	2	7,14	5,91	12	65,40	16,53
Jammu & Kashmir	1	2,97	1,40	..	..	..	..	..	..	10	34,96	6,42
Punjab	2	25,22	11,88	..	..	..	2	18,06	12,07	12	276,63	60 48
Rajasthan	2	7,18	3,09	3	6,72	3,50	16	54,51	55,14	26	74,36	63,13
Chandigarh	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	31	6
Delhi	..	..	..	..	..	..	1	1,96	8,95	1	1,96	8,95
II. North-Eastern Region	**3**	**67**	**29**	2	**1,45**	**74**	**6**	**11,24**	**7,40**	**36**	**58,26**	**17,25**
Assam	1	23	10	..	..	..	2	7,50	4,88	10	41,98	12.96
Manipur	1	31	13	2	1,45	74	1	1	1	6	2,06	88
Meghalaya	1	13	6	..	..	..	..	..	..	4	2,77	46
Nagaland	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	2,55	9
Tripura	..	..	..	..	..	..	3	3,73	2,51	3	3,73	2,51
Arunachal Pradesh	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	5,02	33
Mizoram	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	15	2
Sikkim	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
III. Eastern Region	**9**	**38,52**	**18,07**	**7**	**18,09**	**10,00**	**18**	**62,09**	**87,09**	**61**	**294,26**	**153,13**
Bihar	4	8,92	3,75	4	12,69	7,14	4	18,07	51,92	31	111,21	77.90
Orissa	1	3,12	1,36	2	5,09	2,70	9	26,70	21,98	13	36,55	26,57
West Bengal	4	26,48	12,96	..	..	..	5	17,32	13,19	15	145,70	48,44
Andaman & Nicobar Islands	..	..	..	1	31	16	..	..	..	2	80	22
IV. Central Region	**5**	**19,06**	**8,59**	**9**	**30,94**	**16,42**	**37**	**155,26**	**141,55**	**101**	**423,42**	**219,97**
Madhya Pradesh	2	5,09	2,34	6	14,24	7,63	19	31,35	33,45	45	85,42	52,59
Uttar Pradesh	3	13,97	6,25	3	16,70	8,79	18	123,91	108,10	56	338,00	167,38
V. Western Region	**2**	**5,16**	**2,43**	**5**	**60,78**	**32,42**	**14**	**69,12**	**75,76**	**47**	**462,24**	**189,66**
Gujarat	..	..	..	2	41,02	21,35	2	15,16	10,40	19	246,53	73,91
Maharashtra	2	5,16	2,43	3	19,76	11,07	11	53,17	64,70	25	146,19	97,73
Dadra & Nagar Haveli	..	..	..	..	..	..	1	79	66	1	79	66
Goa, Daman & Diu	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	68,73	17,36
VI. Southern Region	**3**	**29,28**	**12,95**	**8**	**140,80**	**77,59**	**48**	**326,47**	**340,20**	**70**	**621,37**	**474,33**
Andhra Pradesh	1	13,01	5,90	..	..	..	19	123,94	126,35	21	139,64	133,30
Karnataka	1	11,70	4,79	4	86,32	47,38	13	68,36	85,90	19	189,67	145,89
Kerala	1	4,57	2,26	1	14,62	8,01	4	47,10	34,41	11	162,94	78,88
Tamil Nadu	..	..	..	3	39,86	22,20	11	84,64	90,56	15	124,59	112,76
Lakshadweep	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	76	5
Pondicherry	..	..	..	..	..	..	1	2,43	2,98	3	3,77	3,45
ALL INDIA	**29**	**136,72**	**62,35**	**37**	**268,95**	**146,49**	**148**	**734,51**	**755,56**	**388**	**2378,86**	**1 247.5 ?**

TABLE 2.10—STATE-WISE FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRICTS BASED

(As on the last Friday

Region/State/Union Territory	Frequency (Credit-Deposit Ratio)								
	Up to 20%			20%—30%			30%—40%		
	No. of Districts	Deposits	Advances	No. of Districts	Deposits	Advances	No. of Districts	Deposits	Advances
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Northern Region	**8**	**136,14**	**18,16**	**12**	**157,83**	**39,17**	**7**	**121,24**	**42,22**
Haryana	..	..	..	..	..	..	1	21,12	8,39
Himachal Pradesh	1	4,42	51	4	43,43	10,34	..	..	..
Jammu & Kashmir	1	1,66	8	1	4,64	1,34	..	..	..
Punjab	3	125,54	16,80	3	85,24	21,28	2	80,95	27,11
Rajasthan	2	4,46	77	4	24,52	6,21	4	19,17	6,72
Chandigarh	1	6	..	..	..	..	..	..	..
Delhi	..	..	..	..	..	..	..	..	..
II. North-Eastern Region	**7**	**43,02**	**5,99**	**5**	**42,56**	**11,12**	**5**	**40,24**	**13,87**
Assam	1	1,04	8	5	42,56	11,12	1	17,15	5,49
Manipur	1	14	1	..	..	..	..	..	..
Meghalaya	2	33,06	5,26	..	..	..	..	..	..
Nagaland	1	1,44	15	..	..	..	1	7,57	2,98
Tripura	..	..	..	..	..	..	3	15,52	5,40
Arunachal Pradesh	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Mizoram	1	3,38	24	..	..	..	..	..	..
Sikkim	1	3,96	25	..	..	..	..	..	..
III. Eastern Region	**7**	**162,42**	**28,59**	**14**	**418,90**	**95,43**	**12**	**142,44**	**46,04**
Bihar	1	3,31	65	6	281,42	61,33	4	40,71	13,00
Orissa	1	1,01	8	2	9,03	2,24	3	8,98	3,34
West Bengal	4	153,61	26,97	6	128,45	31,86	5	92,75	29,70
Andaman & Nicobar Islands	1	4,49	89	..	..	..	..	..	..
IV. Central Region	**10**	**55,76**	**9,59**	**22**	**133,60**	**33,87**	12	**128,27**	**46,60**
Madhya Pradesh	1	2,31	27	9	26,14	6,46	4	23,84	8,38
Uttar Pradesh	9	53,45	9,32	13	107,46	27,41	8	104,43	38,22
V. Western Region	**6**	**127,16**	**19,14**	**4**	**62,47**	**15,87**	**12**	**420,82**	**144,12**
Gujarat	5	124,38	18,88	3	46,97	11,55	5	285,04	98,13
Maharashtra	..	..	..	1	15,50	4,32	7	135,78	45,99
Dadra & Nagar Haveli	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Goa, Daman & Diu	1	2,78	26	..	..	..	..	..	..
VI. Southern Region	**2**	**57,21**	**9,97**	..	..	..	**7**	**232,38**	**79,91**
Andhra Pradesh	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Karnataka	..	..	..	..	..	..	2	31,70	10,69
Kerala	1	57,07	9,95	..	..	..	3	154,20	54,01
Tamil Nadu	..	..	..	..	..	..	1	41,90	13,64
Lakshadweep	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Pondicherry	1	14	2	..	..	..	1	4,58	1,57
ALL INDIA	**40**	**581,71**	**91,44**	**57**	**815,36**	**195,46**	**55**	**1085,39**	**372,76**

(*Source:* Return on Aggregate Deposits and Gross Bank Credit)

ON CREDIT-DEPOSIT RATIOS FOR SEMI-URBAN BANK OFFICES
of June 1978)

(Amount in lakhs of rupees)

Region /State/Union Territory	Frequency (Credit-Deposit Ratio)											
	40%—50%			50%—60%			60% and above			Total		
	No. of Dis-tricts	De-posits	Advan-ces	No. of Dis-tricts	Depo-sits	Advan-ces	No. of Dis-tricts	Depo-sits	Advan-ces	No. of Dis-tricts	Depo-sits	Advan-ces
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Northern Region	**6**	**65,58**	**30,69**	**10**	**169,68**	**89,89**	**18**	**209,23**	**187,32**	**61**	**859,70**	**407,45**
Haryana	1	41,07	20,07	4	74,85	40,76	5	73,16	61,24	11	210,20	130,46
Himachal Pradesh	1	4,07	1,78	..	..	..	..	..	..	6	51,92	12,63
Jammu & Kashmir	1	6,40	2,65	1	4,03	2,40	1	2,43	2,67	5	19,16	9,14
Punjab	..	..	..	2	79,66	40,66	2	62,65	56,32	12	434,04	162,17
Rajasthan	3	14,04	6,19	3	11,14	6,07	10	70,99	67,09	26	144,32	93,05
Chandigarh	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	..
Delhi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
II. North-Eastern Region	**1**	**3,24**	**1,54**	..	..	..	**1**	**43,51**	**26,98**	**19**	**172,57**	**59,50**
Assam	1	3,24	1,54	..	..	..	1	43,51	26,98	9	107,50	45,21
Manipur	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	14	1
Meghalaya	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	33,06	5,26
Nagaland	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	9,01	3,13
Tripura	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	15,52	5,40
Arunachal Pradesh	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Mizoram	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3,38	24
Sikkim	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3,96	25
III. Eastern Region	**7**	**52,69**	**24,56**	**3**	**28,36**	**15,23**	**16**	**105,44**	**100,76**	**59**	**910,25**	**310,61**
Binar	4	31,09	14,36	2	22,94	12,46	12	73,64	70,56	29	453,11	172,36
Orissa	2	12,21	5,67	1	5,42	2,77	4	31,80	30,20	13	68,45	44,30
West Bengal	1	9,39	4,53	..	..	..	..	..	..	16	384,20	93,06
Andaman & Nicobar Islands	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4,49	09
IV. Central Region	**15**	**157,41**	**69,89**	**10**	**57,26**	**30,69**	**26**	**232,66**	**207,05**	**95**	**764,96**	**397,69**
Madhya Pradesh	8	44,11	19,61	9	48,99	26,45	13	60,30	52,34	44	205,69	113,51
Uttar Pradesh	7	113,30	50,28	1	8,27	4,24	13	172,36	154,51	51	559,27	284,18
V. Western Region	**6**	**188,26**	**90,37**	**6**	**137,69**	**72,76**	**11**	**172,60**	**124,42**	**45**	**1109,00**	**466,68**
Gujarat	..	..	..	2	71,58	36,72	3	37,09	29,37	18	565,06	194,65
Maharashtra	5	56,46	25,60	4	66,11	36,04	8	135,51	95,05	25	409,36	207,00
Dadra & Nagar Haveli	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Goa, Daman & Diu	1	131,80	64,77	..	..	..	..	..	..	2	134,58	65,03
VI. Southern Region	**11**	**235,96**	**107,16**	**6**	**135,86**	**71,59**	**41**	**703,63**	**545,65**	**67**	**1365,04**	**815,28**
Andhra Pradesh	3	55,23	23,62	1	18,62	10,00	17	238,63	179,37	21	312,48	212,99
Karnataka	2	52,62	24,68	3	41,19	22,89	12	135,06	116,93	19	260,57	175,19
Kerala	3	87,82	40,07	1	49,10	24,71	3	72,71	53,21	11	420,90	181,95
Tamil Nadu	3	40,29	18,79	1	26,95	13,99	9	257,23	197,14	14	366,37	243,56
Lakshadweep	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Pondicherry	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4,72	1,59
ALL INDIA	**46**	**703,14**	**324,21**	**35**	**528,85**	**280,16**	**113**	**1467,07**	**1193,18**	**346**	**5181,52**	**2457,21**

Five Working Groups

2.46 Policy formulations during the year gave further impetus to the involvement of banks in the achievement of socio-economic objectives

2.47 As a sequel to the Prime Minister's meeting with the Chief Executives of banks and term-lending institutions on October 8, 1978 five Working Groups were constituted to study in depth and make recommendations on (1) Differential Rates of Interest, (2) Small-Scale Industries, (3) Agricultural Credit, (4) Promotion of Employment and (5) Problems of Sick Industrial Units. Most of the recommendations of these Working Groups have been accepted by the GOI and the RBI and banks were advised as under regarding the action to be taken.

(1) Differential Rates of Interest

2.48 Banks were advised (a) to increase the level of advances under this scheme to weaker sections of the society for productive ventures from the existing ½ per cent of total advances to 1 per cent and (b) to give minimum 40 per cent of such advances to persons belonging to scheduled castes and scheduled tribes as against 33⅓ per cent hitherto. In order to facilitate the flow of funds to scheduled tribes, banks were advised to use the medium of co-operative societies/large sized multi-purpose societies (LAMPS) organised specically for the benefit of tribal population.

(2) Bank Credit for Small-Scale Industries

2.49 Banks were asked to establish a scheme of composite term loans covering both equipment finance and working capital with repayment period of 7 to 10 years or even more, for artisans and village and cottage units, whose individual requirement does not exceed Rs. 25,000/-. The rate of interest on these composite loans in backward areas would be 9.5 per cent and in other areas 11 per c These rates were also made applicable to term loans fo ot less than three years granted to units in the tiny s and other small-scale industries. In the case of the tiny sector credit limits for working capital up to Rs. 1 lakh will carry interest at a rate not exceeding 12.5 per cent. Small banks with liabilities of less than Rs. 25 crores may charge interest not exceeding 13.5 per cent.

(3) Agricultural Credit

2.50 Banks were advised to participate effectively in the Integrated Rural Development Programmes in 2,000 blocks selected by State Governments and in 300 additional blocks to be taken up annually during the remaining period of the Plan, and to ensure that at least 50 per cent of their total agricultural advances go to the small and marginal farmers by 1982-83. Priority would be given to these blocks in the establishment of new RRBs.

(4) Role of Banks in Promoting Employment

2.51 Banks were advised that they should aim at providing credit on aggregative annual basis to at least two additional borrowers per branch per month. They should concentrate on implementation of self-employment schemes in blocks for which development plans are ready and simultaneously aim at extending gradually their schemes to other blocks. Special schemes of self-employment for scheduled castes and scheduled tribes have to be drawn up.

(5) Problems of Sick Industrial Units

2.52 In order to tackle the problems of sick industrial units, banks were asked, among other things, (1) to explore possibilities of rehabilitating sick units, and in case they are not able to provide the assistance required, they should refer the case to the IDBI which would consider the package of measures necessary for rehabilitating the unit, and (2) to ensure that the difficulties of sick units are not compounded by the charging of penal rate of interest.

Private Sector Banks

2.53 The RBI informed commercial banks in the private sector that they were expected to progressively enlarge their credit to priority and neglected sectors to reach a minimum of 33⅓ per cent of total advances by March 31, 1980. The target applicable to public sector banks in respect of credit-deposit ratio of at least 60 per cent to be achieved separately in rural and semi-urban branches was also extended to private sector banks. The other socio-economic objectives extended to private sector banks were :

1. Lending 1 per cent of total advances under the differential interest rate scheme of which 40 per cent should go to the scheduled castes and scheduled tribes.
2. Providing credit on an aggregative annual basis to at least two additional borrowers per branch per month.
3. Reserving posts for scheduled castes/scheduled tribes on the same proportion as already applicable to public sector banks.

Lead Bank Scheme

2.54 The High Power Committee (HPC) constituted in the RBI for the purpose of keeping the progress of the Lead Bank Scheme under constant review and for issuing policy guidelines for its effective implementation met twice during the year. The important issues considered by the Committee at these meetings are indicated below.

Extension of Areas Covered Under Lead Bank Scheme

2.55 The Union Territories of Goa, Daman and Diu, as also the rural areas of the Union Territories of Delhi and Chandigarh were brought within the purview of the Lead Bank Scheme. The lead responsibility in respect of the rural areas of Delhi was entrusted to State Bank of India and that of Chandigarh to Punjab National Bank. The credit plans for all 390 districts (including rural areas of Delhi and Chandigarh, bifurcated districts of 24 Parganas in West Bengal and the 6 districts created in the Manipur State which was earlier deemed as one district) in the country have been launched for implementation.

District Credit Plans

2.56 It was felt that substantial uniformity could be effected in the methodology adopted for preparation and implementation of the credit plans and guidelines were evolved in this behalf. It was decided that the credit plans in operation should be terminated in December 1979 and the lead banks asked to formulate fresh plans for the period January 1980 to December 1982 so that the new plans would synchronize more or less with the Five Year Plan. Further, annual action plans are required to be prepared by the lead bank in December each year indicating sectoral, scheme-wise and institution group-wise break-up of the total credit outlays. Lead banks were advised to develop their own system for carrying out periodical evaluation studies of the implementation of credit plans of their lead districts. Suitable instructions/guidelines were issued to all the lead and non-lead banks pursuant to the decisions taken on these subjects by the HPC.

2.57 With a view to ensuring the proper implementation of multi-agency approach to credit in rural areas a new Cell called the "Rural Planning and Credit Cell" was set up in the RBI. The Cell which began functioning from January 1979 has been entrusted with all the items of work relating to RRBs, credit plans at district and block levels and Agricultural Credit Intensive Development (ACID) Scheme which were earlier handled by the Department of Banking Operations and Development and Agricultural Credit Department of the Bank.

2.58 The Rural Planning and Credit Cell in the RBI formulated further guidelines for the preparation of the new district credit plans for the period 1980—82 and annual action plan for 1980 so as to ensure that all lead banks prepare the plans in a uniform manner, dovetailing them properly into district development plans and launch them for implementation in January 1980. These guidelines were conveyed to all lead banks and State Governments. The lead banks were advised regarding the preparation of annual action plans for 1979 also, in case the existing plans were not considered as realistic.

Implementation of District Credit Plans

2.59 As the presence of senior officials helps in the formulation of decisions at the District Consultative Committee (DCC) meetings paving way for the effective and expeditious

implementation of credit plans, the lead banks and non-lead banks were advised to depute their Regional/Divisional/Development Managers to attend DCC meetings as far as practicable, particularly for the meetings where half-yearly and annual review of credit plans and finalisation of annual action plans are taken up.

2.60 Attention of all lead banks was drawn to the "Margin Money Scheme" formulated by GOI for financial assistance to State Governments/Union Territories to provide margin money to small-scale units. In order to successfully implement the scheme for the development of the rural areas they were advised that DCCs should ensure effective co-ordination between development agencies and commercial banks and that the aspects of the Scheme should be invariably discussed at the periodical meetings of the DCCs. It was also indicated to banks that they should provide technically trained development officials at appropriate levels to give guidance to prospective entrepreneurs.

2.61 The scheduled commercial banks were advised to implement the recommendations contained in the Reports of Working Groups on Small-Scale Industries, Employment Promotion Scheme, Differential Rates of Interest Scheme and Agricultural Finance. The main objective of the recommendations being to ensure smooth and adequate flow of credit to priority sectors and weaker sections of the society, banks were advised that DCC would be the appropriate forum to discuss common problems (including supply of inputs, power, marketing arrangements, etc.), and evolve ways and means to overcome them to ensure speedy implementation of instructions.

Samples Surveys of Implementation of Credit Plans in Lead Districts

2.62 In order to assess the progress made by the lead banks and other participating institutions/agencies, the RBI undertook random sample surveys of the districts where credit plans had been in operation for more than two years. One district each from three states, *viz.*, Farrukhabad (UP) Seoni (MP), and Jaisalmer (Rajasthan) with different lead banks was selected for the sample survey. The field investigations for the survey were carried out and the relative reports were under preparation.

District Industries Centres (DICs)

2.63 In order to give the highest importance to the promotion of smallscale, cottage and village industries and to maximise employment potential, the GOI decided to set up DICs. All the public sector banks and two private sector banks entrusted with lead responsibility were advised by Government to depute their officers to function as Managers (Credit) in th districts chosen for setting up the DICs.

Regional Rural Banks

2.64 During the year, eight more RRBs were set up, bringing their total number to 56 in 17 States as at the end of June 1979. Of the new RRBs, two were established in Gujarat, three in Bihar and one each in Karnataka, Rajasthan and Madhya Pradesh. The total number of branches of the RRBs rose by 560 from 1,405 at the end of June 1978 to 1,965 at the end of June 1979 (Table 2.11).

TABLE 2-11—STATE-WISE OFFICES OF REGIONAL RURAL BANKS

(As on June 30, 1979)

States	No. of RRBs	No. of Branches
	1	2
1. Andhra Pradesh	3	238
2. Assam	1	34
3. Bihar	10	266
4. Gujarat	2	..
5. Haryana	2	64
6. Himachal Pradesh	1	21
7. Jammu & Kashmir	1	43
8. Karnataka	4	156
9. Kerala	2	118
10. Madhya Pradesh	5	149
11. Maharashtra	1	48
12. Orissa	4	155
13. Rajasthan	4	166
14. Tamil Nadu	1	55
15. Tripura	1	24
16. Uttar Pradesh	10	326
17. West Bengal	4	102
Total	**56**	**1,965**

(*Source* : Rural Planning and Credit Cell and D.B.O.D., R.B.I.)

2.65 According to the progress reports received from 51 RRBs, their deposits and advances totalled Rs. 80 crores and Rs. 143 crores, respectively, as on the last Friday of March 1979. The advances granted to small/marginal farmers, landless labourers and rural artisans amounted to Rs. 134 crores.

2.66 The RRBs continued to avail of the refinance facility under the Refinance Scheme introduced by the RBI on October 1, 1976. Limits sanctioned to 31 RRBs aggregated to Rs. 34 crores, as at the end of June 1979. The total amount drawn against these limits and outstanding as on the last Friday of March 1979 was Rs. 28 crores.

2.67 A reference was made in the last year's Report of the concessions and exemptions granted to RRBs by the RBI in regard to maintenance of cash reserves, etc. The CRR continues to be 3 per cent of it's total demand and time liabilities as against 6 per cent applicable to other scheduled commercial banks. The RRBs also continue to get exemption from the directive requiring the scheduled commercial banks to deposit 10 per cent of incremental demand and time liabilities with reference to a base date. The liquid assets to be maintained by the RRBs under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act, 1949) continue to be 25 per cent as against 34 per cent applicable to other banks.

2.68 In pursuance of a recommendation of the Committee on Regional Rural Banks (Dantwala Committee), a Steering Committee was constituted in the RBI and entrusted with the following functions : (i) to identify areas for location of RRBs and look after organisational matters such as local participation in management, composition of boards, appointment of chairman, recruitment and training of staff, etc., (ii) operational matters such as loaning policies etc., (iii) periodical review of existing relaxation and concessions in the matter of liquidity, (iv) monitoring and review of the progress of RRBs, (v) supervision over the functioning of RRBs and (vi) to suggest guidelines on the follow-up action on Dantawala Committee Report. The Steering Committee met thrice during the year.

Commercial Banks' Participation in ARDC/IDA/IBRD Programmes

2.69 The involvement of commercial banks in the implementation of normal ARDC schemes and projects assisted by

IDA/IDRD through ARDC showed further strides during the year. As on June 30, 1979, the Corporation sanctioned 6,147 schemes to commercial banks involving total financial assistance of Rs. 1,206 crores of which the Corporation's commitment was Rs. 974 crores. The disbursements made by the Corporation amounted to Rs. 491 crores as at end-June 1979 as against Rs. 341 crores at the end of June 1978. Minor irrigation and farm mechanisation schemes continued to account for a major share in the schemes and the financial assistance involved was Rs. 751 crores, covering 3,375 schemes.

Farmers' Service Societies (FSS)

2.70 Farmers' Service Societies, which have multi-purpose functions and are expected to provide a package of agricultural credit and related services at a single contact point are organised and financed by commercial banks, Central Co-operative Banks and RRBs. By the end of June 1978, 213 FSS had been set up in 13 States and in the Union Territory of Delhi by 18 public sector banks and two private sector banks.

Village Adoption Scheme

2.71 Banks continued to follow the area approach and adopted villages under the 'Village Adoption Scheme' for extending financial assistance for the integrated development of village economy in all its aspects in a phased manner. As at the end of December 1978, banks had adopted 72,270 villages and financed 2.1 million farmers to the extent of Rs. 449 crores as against 55,205 villages, 1.5 million farmers and Rs. 297 crores, respectively, at the end of December 1977.

Recovery of Agricultural Advances

2.72 The all-India percentage of recovery to amount demanded for repayment in respect of direct agricultural advances granted by public sector banks, which had shown progressive improvement since June 1973, showed a deterioration and declined to 48.8 at the end of June 1977 but improved slightly to 50.2 as at the end of June 1978. The recovery position of all Indian scheduled commercial banks also rose from 50.0 per cent at the end of June 1977 to 51.2 per cent at the end of June 1978. The improvement in recovery performance of the public sector banks during 1977-78 was shared by all regions except the Eastern and Central Regions.

Credit Authorisation Scheme

2.73 The Credit Authorisation Scheme (CAS), which has been in operation since 1965, continues to play a significant role as an effective instrument of credit regulation particularly in the background of the Bank's policy to keep the inflationary pressures under check. The steps taken by the Bank in pursuing the recommendations of the Study Group appointed to frame guidelines for follow-up of bank credit have gone a long way in ensuring a certain degree of optimality in the allocation of credit based on the borrowers' production requirements and have also helped banks in the follow-up and supervision of funds lent. The progress made by banks in monitoring credit has been rather slow.

Working of CAS

2.74 During the period from July 1978 to June 1979 the number of parties covered under the Scheme increased from 970 to 1,059 inclusive of public sector undertakings numbering 187 at end-June 1979 as against 178 at end-June 1978. The total limits in force relating to the parties covered under the Scheme at Rs. 11,968 crores at the end of June 1979 showed a substantial increase of Rs. 1,327 crores during the period as against an increase of Rs. 802 crores in the corresponding period of the previous year. The credit limits in respect of public sector undertakings rose by Rs. 670 crores as against an increase of Rs. 268 crores in the earlier year while the share of private sector in the incremental credit amounted to Rs. 657 crores compared with Rs. 534 crores in the same period in 1977-78.

2.75 The pattern of purpose-wise distribution of the total limits in force continued to reflect the position recorded in the previous year. Thus, at the end of June 1979, 88.2 per cent of total limits were for working capital purposes (including packing credit and bills), 8.7 per cent for term finance and 3.1 per cent for sale of machinery on deferred payment basis. Activity-wise, of the total limits in force of Rs. 11,968 crores at the end of June 1979, trading accounted for about Rs. 4,501 crores (37.6 per cent). Under trading, food procurement alone claimed Rs. 3,151 crores or 26.3 per cent of the total. Industry accounted for Rs. 6,640 crores (55.5 per cent), of which engineering and cotton textiles claimed limits of Rs. 1,881 crores (15.7 per cent) and Rs. 834 crores (7.0 per cent), respectively. Of the total credit limits in force of Rs. 6,447 crores relating to public sector, trading accounted for about 63.2 per cent (the share of food procurement being 48.9 per cent), engineering 9.1 per cent, electricity undertakings 5.0 per cent and basic metal and metal products (iron and steel) 3.2 per cent.

Changes in the Scheme

2.76 The Bank has been reviewing the working of the Scheme from time to time in order to introduce flexibility in its operations. Subsequent to the last Report certain relaxations and modifications have been effected in the working of the Scheme mainly with a view to further streamlining the procedures as also delegating more authority to the banks themselves for facilitating quick credit decisions. These changes as also clarifications of the existing instructions are summarised below.

A. RELAXATIONS

Cut-off point

2.77 Terms loans granted by banks for acquisition of capital assets have been excluded for the purpose of computing the cut-off points fixed for loan proposals under the Credit Authorisation Scheme.[1] As a result, a few units have been allowed to go out of the purview of the Scheme.

B. MODIFICATIONS

Letters of credit, deferred payment guarantees and acceptance limits

2.78 (i) Letters of credit for acquisition of capital assets as also for other purposes, and (ii) deferred payment guarantees for purchase of capital equipment and acceptance limits in connection therewith, sanctioned by banks to borrowers covered by CAS, have been brought within the purview of the Scheme, subject to certain exemptions. However, the above facilities will continue to be excluded for the purpose of computing the cut-off point.

Clarifications

1. Guarantees

2.79 Under the existing instructions, limits sanctioned by banks for issue of guarantees, e.g., in lieu of earnest money deposits, performance guarantees, etc., are exempt from prior authorisation. It was clarified that if by issue of any guarantee a bank undertook financial obligation to enable its constituents to acquire capital assets, it would require the Bank's prior authorisation subject to certain stipulated conditions.

2. IDBI Bills Rediscounting Scheme

2.80 Limits sanctioned by banks for financing of deferred receivables in regard to domestic sales under the IDBI Bills Rediscounting Scheme (and also outside the scheme subject to stipulated conditions) do not require prior authorisation. Banks can issue acceptances on behalf of buyers under the above Scheme up to the prescribed limit of Rs. 100 lakhs (limit for public sector borrowers being higher) in a year (July-June). It was decided that sanction of such acceptance limits by banks under the IDBI Bills Rediscounting Scheme and also those outside the Scheme will not require prior authorisation under CAS provided conformity with the terms and conditions of IDBI's Scheme and compliance with the RBI instructions are duly ensured.

3. Scheme for Rupee Finance to cover Import of Capital Goods

2.81 Under the existing instructions term loans allowed by banks under the Scheme for rupee finance to cover import

1. At present the cut-off point is Rs. 200 lakhs for private sector and Rs. 300 lakhs for public sector.

of capital goods do not require our prior authorisation under CAS if the loans are for an ad-hoc import of certain specific items of machinery and not part of an overall project or expansion/modernisation scheme financed by the bank. Banks were advised that the term loans would require prior authorisation except to the extent exemptions were already granted in regard to them.

4. Working Capital Term Loans

2.82 Working Capital Term Loans (WCTL) sanctioned by banks should be treated as 'Working Capital' limits for the purpose of discipline under the CAS. Thus, in respect of parties coming under the purview of CAS, if WCTL is carved out of the existing working capital limits already authorised by the Bank, further reference is not necessary irrespective of the amount of WCTL and/or the period of its repayment. Prior authorisation will, however, be required if the WCTL involved sanction/enhancement in the existing working capital limits. In the case of non-CAS parties, reference to the Bank would be necessary only in cases where sanction of any WCTL (worked out as per the guidelines provided by the Tandon Study Group) would take the total working capital limits enjoyed by the borrower from the entire banking system to Rs. 2 crores or more (Rs. 3 crores for public sector borrowers). This relaxation will not apply to advances against commodities covered by selective credit control measures.

5. Cut-off Point for Reporting of Limits

2.83 For the purpose of reporting to the Bank the limits sanctioned to non-CAS borrowers which would take the total credit limits available from the banking system to Rs. 1 crore and upto Rs. 2 crores for private sector and Rs. 3 crores for public sector borrowers, term loans sanctioned to such borrowers for the purpose of acquisition of capital assets may be excluded for the purpose of computation of total credit limits. In other words, for computing the cut-off point of Rs. 1 crore for the purpose of reporting to the Bank, only working capital limits (including working capital term loans) sanctioned to the borrowers should be taken into account.

Term Lending by Commercial Banks

2.84 As a result of certain policy measures instituted by the RBI there has been a progressive involvement of comercial banks in term lending. Data on term lending of commercial banks are available for the period ended June 1977. The total number of term loan accounts increased from 196 thousands at the end of June 1976 to 237 thousands at the end of June 1977 recording a rise from 30.5 per cent to 32.4 per cent of the total number of all accounts (Table 2.12). Total credit limits sanctioned in respect of term loans increased from Rs. 1,840 crores to Rs. 2,337 crores during the same period—an increase of 27.0 per cent as compared to an increase of 18.3 per cent in the previous year. The outstanding term loans also went up from Rs. 1,516 crores at the end of June 1976 to Rs. 1,964 crores at the end of June 1977, amounting to an increase of 29.6 per cent over the year as compared to an increase of 32.1 per cent in the earlier year. Outstanding term loans at the end of June 1977 constituted 16.3 per cent of the total bank credit as against 14.4 per cent a year ago.

Credit to Sugar Industry

2.85 As stated in the section on Selective Credit Control, a temporary clean loan facility up to Rs. 25 lakhs per borrower without prior reference to the RBI, subject to certain conditions, was allowed up to November 30, 1978. It was represented that banks were adjusting the clean loans of Rs. 25 lakhs sanctioned in terms of the above mentioned instructions for correcting the irregularity in the cash credit account instead of making them available to factories to cover expenses incurred for off-season repairs and other essential purposes. The RBI asked banks in December 1978 to ensure that the clean loans were used for the purpose for which they were intended. They were further advised to assist sugar mills, which were unable to meet the dues of the cane growers and to adjust the margin deficit in their cash credit accounts, by allowing working capital term loans on a selective basis, subject to certain conditions. Such loans were to be secured by a charge on fixed assets and/or guarantee of State Government/directors or proprietors of the company/firm.

TABLE 2.12—SCHEDULED COMMERCIAL BANKS' TERM LOANS (OUTSTANDING) 1972-77

(Amount in Crores of Rupees)

As on last Friday	No. of Accounts		Credit Limit		Amount Outstanding		Total Bank Credit excluding food procurement advances
	Term Loans	Total of all accounts	Term Loans	Total Bank Credit	Term Loans	Total Bank Credit	
December 1972	89,231	416,567	839	9,702	601	5,051	4,892
	(21.4)		(8.6)		(11.9)		(12.3)
June 1973	103,340	460,384	974	10,428	706	5,771	5,303
	(22.4)		(9.3)		(12.2)		(13.3)
December 1973	119,385	509,424	1,076	11,370	832	6,396	6,044
	(23.4)		(9.4)		(13.0)		(13.8)
June 1974	129,894	535,204	1,280	12,881	924	7,289	6,766
	(24.3)		(9.9)		(12.7)		(13.7)
December 1974	141,701	550,330	1,354	12,362	1,021	7,359	7,150
	(25.7)		(11.0)		(13.9)		(14.3)
June 1975	152,999	572,306	1,555	13,589	1,148	8,180	7,385
	(26.7)		(11.4)		(14.0)		(15.5)
December 1975	171,536	605,046	1,612	14,468	1,307	9,030	8,094
	(28.4)		(11.1)		(14.5)		(16.1)
June 1976	196,123	643,382	1,840	16,740	1,516	10,568	8,383
	(30.5)		(11.0)		(14.4)		(18.1)
December 1976	N.A.	N.A.	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A.
June 1977	237,278	733,578	2,337	18,503	1,964	12,064	9,528
	(32.4)		(12.6)		(16.3)		(20.6)

Note : 1. Data relate to accounts with credit limit over Rs. 10,000.

2. Figures in brackets given under cols. 1,3 and 5 indicate percentages of term loans to totals reported in cols. 2, 4 and 6 respectively.

3. Figures in brackets under col. 7 indicate percentage of term loans under col. 5 to total in col. 7

(*Source* : Basic Statistical Returns).

2.86 For financing sugar mills during the 1978-79 crushing season, banks were advised in November 1978 that they might sanction credit limits on merits to individual sugar mills to the extent of the average of maximum outsanding under the regular limits for the earlier two crushing seasons, viz., 1976-77 and 1977-78 (exclusive of drawings, if any, over and above the regular limits, as also limits granted on a temporary basis) sanctioned to them without prior authorisation. In case a bank considered it necessary to sanction credit limits to any sugar mill in excess of those indicated above and the total of the existing and the proposed additional limits of the borrower came within the purview of credit authorisation, it could release such limits only after obtaining prior authorisation from the Bank.

2.87 Keeping in view the credit requirements of sugar units consequent on decontrol of sugar, the sugar policy was further reviewed. In modification of the earlier instructions, banks were advised in February 1979 that they might sanction for the 1978-79 crushing season, credit limits on merits to individual sugar mills to the extent of the maximum outstandings under the regular limits for the last crushing season only i.e., 1977-78 (exclusive of drawings, if any over and above the regular limits, as also the limits granted on a temporary basis) without obtaining prior authorsation.

Financing of Sick Industrial Undertakings

2.88 The Sick Industrial Undertakings Cell in the RBI continued to monitor banks' performance in identifying sick units and taking remedial action, wherever necessary. It tried to bring about co-ordination in the efforts of Government, banks and financial institutions in the rehabilitation of sick units. While overseeing the institutional efforts in industrial rehabilitation, whenever it became necessary to intervene and guide in individual cases, the Cell took initiative and convened meetings of financing institutions to discuss the problems of select sick units, find solution and secure co-ordination. The Cell convened five such meetings. Besides, the Cell's representatives also participated in fifteen meetings arranged by other financial institutions for co-ordinating the efforts of concerned banks/institutions.

2.89. With a view to bringing about improvement in the banks' performance in rehabilitating the sick units, the Cell issued instructions/guidelines to banks as and when necessary in regard to sick units. When it was represented that banks were reluctant to relax margin requirements, banks were advised in September 1978 to adopt a flexible approach in margins and to apply to the RBI in deserving cases for grant of exemption from its directives relating to margins, if necessary. At the same time, while allowing certain relaxations about obsolete and unusable stocks included in the inventories, banks were advised about the need to maintain proper discipline in regard to inventory/receivable norms in respect of sick units. In accordance with the decisions of the High Power Committee (under the Chairmanship of the Union Finance Minister), banks were advised in December 1978 about :

(i) reviewing the functioning of special cells for sick units and strengthening of monitoring arrangements,

(ii) preparing a package of measures by the IDBI in respect of cases of sick units referred to it by commercial banks,

(iii) establishing a separate cell at the top level in banks for looking into complaints of small-scale sick units in order to tackle their problems with greater awareness and understanding,

(iv) providing consultancy services to small-scale units, and

(v) ensuring that the difficulties of the sick units are not compounded by charging of penal rate of interest

2.90 Banks were also told in January 1979 to submit a progress report in regard to the implementation of the various decisions of the above mentioned High Power Committee.

2.91 The studies conducted by banks, up to the end of September 1978, of some of the 334 units reported to be sick, revealed 137 units to be viable. Of these, eight units were reported to have turned the corner due to the rehabilitation efforts made by banks. It was also reported that there were indications of favourable trends prevailing in textile, heavy engineering and iron and steel industries.

2.92. In terms of RBI instructions, banks have been submitting quarterly statements giving brief particulars of all sick units enjoying aggregate credit of Rs. 1 crore and above from the banking system. The information contained in the quarterly statements as at the end of September 1978, revealed that the number of large sick units (i.e., those enjoying aggregate bank credit of Rs. 1 crore and above) identified by banks increased to 334 involving bank finance of Rs. 983 crores as against 270 units involving bank fiance of Rs. 774 crores, as at the end of September 1977. (These exclude the units taken over by National Textile Corporation.)

Assistance to people affected by Natural Calamities

2.93 Whenever there has been occurrence of natural calamities such as cyclones, floods, etc. on a large scale in any part of the country, the RBI has been advising the commercial banks to extend financial assistance to the affected parties expeditiously and sympathetically on the basis of a constructive approach. When there were unprecedented floods in West Bengal in September 1978 and in Andhra Pradesh in May 1979, these instructions were reiterated. The gist of the guidelines issued to banks are as under :

(a) They should be in close touch with the State Government/local authorities in the affected areas and in collaboration with them evolve suitable schemes for the economic rehabilitation of the victims.

(b) Existing crop loans may be converted into medium-term loans with a repayment schedule ranging from 3 to 5 years. Besides, fresh crop loans should be considered on a priority basis.

(c) Scale of finance followed in each district should be, as far as possible, uniform and also it should take into consideration the consumption needs of the borrowers.

(d) Depending on the bank's assessment of the situation, assistance may even be on an unsecured basis or without insisting on third party guarantee. In the case of share croppers assistance may be on a group guarantee basis.

(e) Field staff in the affected regions should be augmented and, if necessary, experienced persons from other regions be deployed there.

2.94 The Indian Bank's Association and the Agricultural Finance Corporation have been carrying out studies in the affected regions assessing the damage and consider the type of relief measures needed. They have evolved certain guidelines to be followed by banks for extending financial assistance for the rehabilitation of affected persons/units. Details of credit extended by banks to the flood affected persons/units in West Bengal are given below.

TABLE 2.13—OUTSTANDING BANK CREDIT FOR PERSONS AFFECTED BY NATURAL CALAMITIES, (AS ON MARCH 31, 1979)

(In lakhs of Rupees)

Category	Number of Accounts	Amount outstanding
1. Agriculture and allied activities	46,049	795.59
2. Trade and self-employed	42	6.11
3. Cottage and tiny sector	26	1.30
4. Medium and large-scale industries	15	179.32
5. Others (Small-scale industries)	375	140.33
Total	46,507	1,122.65

(*Source* : Department of Banking Operations and Development, RBI).

2.95 The IDBI disposed of 49 applications for Rs. 98 lakhs from various banks under Special Refinance Scheme 1978 and disbursed a sum of Rs. 38.78 lakhs up to May 15, 1979.

Differential Rates of Interest Scheme

2.96 Lending under the Differential Rates of Interest Scheme made further progress during the period January 1978 to December 1978. There was an increase of 2,28,096 in the number of borrowal accounts which rose from 13,91,440 to 16,19,536. The amount of loans outstanding went up from Rs. 68 crores to Rs. 90 crores recording an increase of Rs. 22 crores. The average amount of loan per account increased from Rs. 487 at the end of December 1977 to Rs. 556 at the end of December 1978.

Duty Drawback Credit Scheme, 1976

2.97 The Scheme is intended to benefit exporters who avail of interest-free finance from banks up to 90 days against shipping bills provisionally certified by the Customs authorities towards refund of duty. The financing banks in turn are eligible to avail of interest-free refinance from the RBI pending final settlement of duty drawback claims of the exporters. During the period November 1, 1978 to June 30, 1979 limits aggregating to Rs. 19 crores were sanctioned to 29 banks which availed of refinance to the extent of Rs. 14 crores, as on May 25, 1979.

2.98 The accounting procedure was revised recently to remove certain difficulties experienced by both banks and exporters. Under the new procedure, which became effective from May 1979, Customs authorities are to make payment of final duty drawback by cheques direct to the bank concerned, which in turn, should repay to the RBI the corresponding amount of refinance availed of by them under the Scheme within five working days after receipt of the cheque from the Customs authorities. The RBI together with Ministry of Commerce is examining the possibility of extending the Scheme to cover exports to Bangladesh as well as those financed under IDA credit.

Export Finance

2.99 The Standing Committee on Export Finance constituted in the RBI in 1975 to formulate policies on all matters relating to export finance met twice during 1978-79. With a view to making exports more competitive and taking into account the larger shipment period required for countries particularly in the Western Hemisphere, it was decided to increase the period of post-shipment credit for export (other than those on deferred payment basis for periods exceeding one year) from the then existing 128 days to 180 days, with effect from February 1, 1979. The units functioning in Kandla Free Trade Zone and Santa Cruz Electronics Export Processing Zone at Bombay are required to export their entire production and for this purpose it was decided to extend the working capital finance to such units at the concessive ceiling rates of interest and also to exempt the units from production of letters of credit or firm orders for export at the time of availment of pre-shipment credit from banks.

2.100 A Committee was set up during the year to revise the 'Guidelines to exporters of engineering goods on the deferred payment basis' issued in 1975. The revision was necessitated by various developments on the export front and also in the light of the experience gained in processing a large number of proposals on project exports and turn key contracts. The Committee completed its task recently and the revised guidelines will be issued on receiving the necessary clearance from GOI.

Export Credit Measures

2.101 The exporters of diamonds have been, of late, facing recessionary trends in the export of diamonds from India in the wake of developments in the diamond market in U.S.A. and some other countries. The export off-take of diamonds has, therefore, fallen resulting in accumulation of finished products with the exporters/diamond polishing units. This situation has posed serious liquidity problems to exporters and has affected a large number of workers in the diamond cutting and polishing industry.

2.102 In view of the socio-economic repercussions and the need for putting the export trade on a firmer footing to ensure its continued growth, the banks have been advised to review the limits sanctioned for pre-shipment and post shipment finance extended to diamond exporters and ensure that, wherever necessary, banks should extend increased finance to meet their genuine credit requirement. The banks have been advised not only to extend longer periods of post-shipment credit (subject to the maximum of 180 days) but also consider extending pledge facility to small diamond exporters (on-sight holders with export turnover of less than Rs. 25 lakhs) and pay special attention to the genuine needs of this priority sector.

2.103 Further, the exporters shipping goods to certain countries viz. Nigeria, Ghana, Israel, Sudan, Syria, Taiwan, Turkey, Vietnam, Yemen, Arab Republic, Zaire and Zambia, were experiencing delays in obtaining repatriation of export proceeds owing to foreign exchange difficulties prevalent there. To tide over the above problem of the exporters as also to reduce the interest burden on the exporters in such cases, it has been decided that in the case of export bills (demand or usance) drawn on the aforesaid countries, the lending banks will be eligible for interest subsidy from the date of purchase/discount of a bill/making an advance against export bill sent for collection till the date of receipt of proceeds thereof in India on payment by ECGC, whichever is earlier, subject to the maximum period of 180 days, the bill being paid on due date in local currency and certain conditions being fulfilled.

Export Credit (Interest Subsidy) Scheme

2.104 The Export Credit (Interest Subsidy) Scheme, 1968 provides for compensating banks extending export credit to make up partially for their losses in interest earnings. The Scheme has been in operation for over ten years. The amount of subsidy ranges around Rs. 12 crores a year. It was observed that certain operational difficulties faced by Banks required to be taken into account. The Scheme is hence being reviewed for improving its utility in consultation with the Foreign Exchange Dealers' Association of India and the Indian Banks' Association.

2.105 During the period from July 1, 1978 to June 30, 1979 interest subsidy amounting to Rs. 13 crores was paid to 58 banks. Of this amount, subsidy in respect of pre-shipment credit amounting to Rs. 7 crores and that on post-shipment credit Rs. 6 crores. The total amount of subsidy disbursed since the inception of the Scheme up to June 30, 1979 amounted to Rs. 72 crores.

2.106 Interest subsidy at 1.5 per cent per annum from the Marketing Development Assistance Fund of the Commerce Ministry at 3.0 per cent from the funds allotted by the Ministry of External Affairs is being paid to the IDBI, the United Commercial Bank and United Bank of India. The total subsidy disbursed to the three institutions during the period under review amounted to Rs. 90 lakhs. Besides interest subsidy amounting to Rs. 6 lakhs at 1.5 per cent each from the Marketing Development Assistance Fund as also the funds released by the Ministry of External Affairs has been paid on the commercial credit of Rs. 4 crores and Rs. 1 crore extended to Bangladesh by the IDBI and Punjab National Bank, respectively.

Data Bank in ECGC

2.107 It has been decided that ECGC should set up a data bank to compile up-to-date information on the various exporters, as also important buyers abroad and to make available the data to banks, as and when required by them.

Forward Exchange Fluctuations Risk Cover

2.108 Long term foreign exchange fluctuations risk cover was hitherto being provided by the RBI and any losses arising therefrom were being charged to the Marketing Development Assistance Fund of the Ministry of Commerce. It has now been decided that in keeping with similar schemes operated abroad by export credit organisations, ECGC will provide the necessary cover and formulate a scheme to supersede the one being presently operated by the RBI. The latter will continue to extend exchange risk fluctuation cover for short periods.

Scheme for Rupee Finance to Cover Import of Capital Goods

2.109 The scheme of rupee finance to cover import of capital goods introduced by the GOI in April 1978, has, as a special case, been made available to State Electricity Boards for import of gas turbine generating sets. However, this facility has been allowed as a one-time exception and

the RBI's policy guidelines already in force in regard to bank finance to State Electricity Boards remain otherwise unchanged. Banks will be entitled to refinance from the RBI in respect of the loans granted by them under the Scheme to State Electricity Boards

2.110 According to data furnished by fourteen public sector banks, the assistance sanctioned under the Scheme by them up to end-March 1979 aggregated Rs. 1332 lakhs.

BANKING LEGISLATION/REGULATION

Banking Laws (Amendment) Bill, 1978

2.111 The Banking Laws (Amendment) Bill, 1978 was introduced in the Lok Sabha during its winter session. The Bill sought to give legislative effect mainly to such of the recommendations of the Banking Commission as had been accepted by the Government. It contains amendments to the Bankers' Books Evidence Act, 1891, Reserve Bank of India Act, 1934, BR Act, 1949, State Bank of India Act, 1955, State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 and Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

Amendment to Regulation 7 of the Reserve Bank of India Scheduled Banks' Regulations, 1951

2.112 In terms of Regulation 7 of the Reserve Bank of India Scheduled Banks' Regulations, 1951, scheduled banks are required to apportion the balances in the saving banks accounts into 'demand' and 'time' liabilities for the purpose of the weekly return to be submitted to the Reserve Bank under Section 42(2) of the RBI Act, 1934. According to the procedure outlined in the above Regulation, if the Savings Bank Rules of the bank specify a maximum amount that may, at any time, be withdrawn from an account without previous notice, then in respect of each amount, such maximum amount, or where the balance in the account was not more than this maximum, the whole of the balance, should be regarded as a demand liability and the excess over the maximum amount, as a time liability.

2.113 It was observed that the aforesaid procedure did not give a realistic estimate of the 'demand' liability portion of these deposits with the result that data on 'money supply with the public' to that exent became notional. So as to indicate the realistic apportionment of savings bank deposits into 'time' and 'demand' liabilities, the provisions of Regulation 7 of the Scheduled Banks' Regulations, 1951, were amended by the Bank in 1978, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) to the effect that the average of the monthly minimum balances in a savings account on which interest is being credited to the account shall be regarded as a time liability and the excess over the said amount, as a demand liability. This amendment came into force with effect from August 16, 1978.

TABLE 2.14—INSPECTION OF COMMERCIAL BANKS

	1976-77	1977-78	1978-79
	1	2	3
Financial Inspection			
Number of banks inspected/ taken up for inspection	26	37**	51**
Number of offices (in India) inspected	823	978**	1,363**
Centre-wise Inspection			
Number of centres	1,476	1,058	750
Number of offices	2,362	1,759	1,264

**Excludes banks/offices inspected for the purpose of annual appraisal.

(*Source* : Department of Banking Operations and Development, RBI).

Inspection of Banks

2.114 In pursuance of the RBI's programme of periodical inspections of commercial banks the financial type of inspection of 19 scheduled commercial banks, one non-scheduled bank and 31 RRBs was taken up under Section 35 of the BR Act, 1949 during the year under report. The comparative position in regard to the number of banks and the offices inspected for the last three years (July-June) is indicated below.

2.115 As regards overseas branches of India banks a branch each of State Bank of India, Bank of India, and Bank of Baroda in West Germany, France and Belgium, respectively, was inspected during the period.

BANK MERGERS AND LIQUIDATIONS

Amalgamations

2.116 As mentioned in the last Report the GOI had sanctioned schemes of amalgamations under Section 45 of the BR Act, 1949 in respect of 49 banks. In terms of the provisions of the relative scheme the transferee banks were required to make final valuation of the assets of the transferor banks after a period of 6/12 years or such earlier period as might be sanctioned by the GOI in consultation with the RBI. The final valuation of the assets of 31 banks was completed and, in the case of 9 banks, the reports are under considera ion. Of the remaining nine banks final valuation in respect of five banks is being pursued.

Liquidations

2.117 Nine banks were dissolved during the period under review including six banks which were dissolved during the earlier periods but the advices in respect of which were received during the period 1978-79. A certificate under Section 44(1) of the BR Act, 1949 was issued to one bank to enable it to go into voluntary liquidation

Licensing of Commercial Banks

2.118 During the period July 1978 to June 30, 1979, licences under Section 22 of the BR Act, 1949, were granted to two banks, viz., Naini Tal Bank Ltd., Naini Tal and United Industrial Bank Ltd., Calcutta, raising the number of licensed commercial banks to 50 (including National Bank of Pakistan, which is under the Custodian of Enemy Property). The name of the Naini Tal Bank Ltd., Naini Tal, was included in the Second Schedule to the RBI Act, 1934.

2.119 As on June 30, 1979, eight banks (including three Indian scheduled commercial banks in private sector and a foreign scheduled bank, viz., Habib Bank Ltd. which is under Custodian of Enemy Property) were functioning without a licence under Section 22 of the BR Act, 1949. Public sector banks, numbering 22, do not require licences.

Clearing House Facilities

2.120 During the period under review, 47 new clearing houses were set up, bringing up the total number to 651 as on June 30, 1979 from 604 as on June 30, 1978. Of these, 11 are managed by the RBI, 515 by State Bank of India and 124 by the Associate Banks of State Bank of India, and 1 by Bank of India.

Credit Information

2.121 The Department of Banking Operations and Development of RBI continued to render assistance to banks and other notified financial institutions by furnishing information on credit facilities allowed to individual borrowers. During the year July 1978 to June 1979 credit information in respect of 1,049 applications was furnished to the applicant bank/notified financial institutions, as against 890 applications during the previous year.

Working Results of Scheduled Commercial Banks

2.122 The working results of 62 scheduled commercial banks based on their published profit and loss accounts for

TABLE 2.15—WORKING RESULTS OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

(Amount in Rupees Crores)

	State Bank Group			Nationalised Banks		
	1976	1977	1978	1976	1977	1978
	1	2	3	4	5	6
I. Total Earnings	**543.38**	**675.49**	**801.56**	**1,064.94**	**1,263.59**	**1,444.02**
	(20.3)	**(24.3)**	**(18.7)**	**(24.7)**	**(18.7)**	**(14.3)**
Of which:						
Interest and discount	449.24	563.47	668.30	946.32	1,132.81	1,299.68
	(21.3)	(25.4)	(18.6)	(24.1)	(19.7)	(14.7)
II. Total Expenditure	**534.59**	**666.63**	**791.89**	**1,045.34**	**1,248.30**	**1,428.16**
	(20.4)	**(24.7)**	**(18.8)**	**(24.7)**	**(19.4)**	**(14.4)**
Of which:						
(a) Interest paid on deposits, borrowings etc.	317.77	409.84	490.88	684.18	829.81	938.24
	(37.5)	(28.9)	(19.8)	(37.9)	(21.3)	(13.1)
(b) Salaries, allowances, provident fund and bonus/ex-gratia payment to staff	165.41	196.19	226.43	261.11	301.13	352.98
	(—2.7)	(18.6)	(15.4)	(—0.7)	(15.3)	(17.2)
III. Profits after provision for taxation and bonus/ex-gratia payment to staff	**8.79**	**8.86**	**9.67**	**19.60**	**15.29**	**15.86**
	(18.0)	**(0.8)**	**(9.1)**	**(27.3)**	**(—22.0)**	**(3.7)**

(Amount in Rupees Crores)

	Other Indian Scheduled Commercial Banks@			Foreign Banks			Total		
	1976	1977	1978	1976	1977	1978	1976	1977	1978
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Total Earnings	**165.35**	**213.13**	**260.81**	**125.75**	**130.16**	**137.07**	**1,899.42**	**2,282.37**	**2,643.46**
	(30.6)	**(28.9)**	**(22.4)**	**(5.2)**	**(3.5)**	**(5.3)**	**(22.4)**	**(20.2)**	**(15.8)**
Of which:									
Interest and discount	143.01	185.67	231.90	98.59	101.40	106.16	1,637.16	1,983.35	2,306.0
	(29.3)	(29.8)	(24.9)	(1.9)	(2.9)	(4.7)	(22.2)	(21.1)	(16.3)
II. Total Expenditure	**161.35**	**209.92**	**256.76**	**118.36**	**126.87**	**131.29**	**1,859.64**	**2,251.72**	**2,693.19**
	(30.6)	**(30.1)**	**(22.3)**	**(3.6)**	**(7.2)**	**(3.5)**	**(22.3)**	**(21.1)**	**(15.8)**
Of which:									
(a) Interest paid on deposits, borrowings etc.	93.35	123.84	154.20	53.43	56.65	60.15	1,148.73	1,420.14	1,643.47
	(39.5)	(32.7)	(24.5)	(7.9)	(6.0)	(6.2)	(36.2)	(23.6)	(15.7)
(b) Salaries, allowances, provident fund and bonus/ex-gratia payment to staff	44.34	56.06	67.87	23.22	27.99	28.52	494.08	581.37	675.80
	(12.5)	(26.4)	(21.1)	(—1.8)	(20.5)	(1.9)	(—0.4)	(17.7)	(16.2)
III. Profits after provision for taxation and bonus/ex-gratia payment to staff	**4.00**	**3.21**	**4.05**	**7.39**	**3.29**	**5.78**	**39.78**	**30.65**	**35.36**
	29.0)	**(—19.8)**	**(26.2)**	**(40.5)**	**(—55.5)**	**(75.7)**	**(27.5)**	**(—23.0)**	**(15.4)**

Note : Figures in brackets indicate percentage variation over the previous year; figures for 1977 are revised.

@ Figures relate to 28 comparable Indian commercial banks in the private sector with deposits of Rs. 10 crores and over.

(*Source* : Profit and loss accounts of banks)

the calendar year 1978 are presented along with those for 1977 and 1976 in Table 2.15. During 1978, banks continued to adopt different accounting procedures with regard to providing bonus to staff in their profit and loss accounts. A few banks treated it as a part of establishment expenditure and showed it under salaries, wages etc., while some others stated that the amount payable as bonus when disbursed would be paid out of contingency reserves for which provision is made in the profit for the year. As observed in the last year's Report, it is possible that a part of this category of reserves could be for purposes other than for bonus payments. In the absence of such information, it is assumed for the purpose of analysing the working results of the scheduled commercial banks that the entire provision for the contingency reserves made during the year was for bonus payments. During 1978, the profits of banks, after making provision for taxation and bonus/ex-gratia payment to staff, increased by Rs. 5 crores to Rs. 35 crores (or by 15.4 per cent) in contrast to a setback in 1977, when they declined from Rs. 40 crores in 1976 to Rs. 30 crores in 1977.

2.123 Both earnings and expenditures increased during 1978. Total earnings of banks increased during 1978 by Rs. 361 crores (+15.8 per cent) as compared with a rise of Rs. 383 crores (+20.2 per cent) in 1977. Total expenditure of banks also rose during the year by Rs. 356 crores (+15.8 per cent) compared with an increase of Rs. 392 crores (+21.1 per cent) during the previous year. Unlike in 1977, the rise in earnings was higher than that of expenditure during 1978 which enabled the banks to improve their profits in 1978. The lower growth rates in banks' expenditure in 1978 was mainly attributable to a slow-down in the pace of interest payments on deposits, borrowings, etc., from 23.6 per cent in 1977 to 15.7 per cent in 1978 and in establishment expenses from 17.7 per cent to 16.2 per cent. The decline in interest payments (growth rate) was probably due to downward revision in interest rates on fixed deposits of 5 years and above and in respect of most other term deposit categories.

2.124 The increase in profits during 1978 was shared by all the bank-groups. Among the public sector banks, State Bank and its associates improved their profits by 9.1 per cent as compared with a rise of 0.8 per cent attained in 1977. In the case of nationalised banks also, their profits rose by 3.7 per cent during 1978 in sharp contrast to a decline of 22.0 per cent in the previous year.

Committees and working Groups : Appointment, Recommendations and Follow-up

Committee to Study Functioning of Public Sector Banks (James Raj Committee)

2.125 A reference was made in the last year's Report of the submission of the Report by the Committee appointed to study the functioning of public sector banks constituted by the RBI under the Chairmanship of James S. Raj in June 1977. The Committee made several recommendations bearing on the tempo and direction of branch expansion, role of RRBs, structure of State Bank of India and its subsidiaries, and setting up of there new banks in the North Eastern, Eastern and Central regions.

2.126 It was emphasised by the Committee that the rapid growth of public sector banks cast a severe strain on their management resulting in dilution of supervisory controls and also affected their profitability due to the impact on cost structure. Hence banks having a large number of branches should consolidate their position for a period of three to five years. They should not, therefore, be allowed to expand beyond specified limits. Further, no bank should be forced to open branches remote from the main areas of its operation and the existing branches of this type should be exchanged voluntarily. Thus according to the Committee, commercial banks should be allowed to open branches only up to district headquarters/mandi block level and RRBs should play a significant role in the financing of the rural sector. RRBs should gradually take over the existing rural branches of commercial banks.

2.127 As mentioned earlier in para 2.2, in the formulation of the new branch licensing policy for 1979-81 the recommendations of the James Raj Committee and those made by the Kamath Working Group and Dantwala Committee have been taken into account.

2.128 The suggestions relating to restructuring of SBI and its subsidiaries and setting up of three new banks in the North Eastern, Eastern and Central Regions, which have a bearing on the structure of the banking system, are being examined by the Bank.

2.129 Other recommendations relating to internal organisation, delegation of powers, terms and conditions of lending to the priority sectors, etc., have been conveyed to banks for implementation.

Working Group to study the Role of Commercial Banking System in providing Finance for Housing Schemes

2.130 A reference was made in the last years' Report about the submission of the report by the Working Group, constituted by the RBI, to examine the role of banking system in providing finance for housing schemes. Based on the recommendations made by the Working Group the following guidelines were issued by the RBI to commercial banks.

2.131 The contribution of the banking system in providing finance for house construction activities can only be modest and be of the order of Rs. 75 crores per annum. This amount would constitute approximately 0.5 per cent of total advances of all scheduled commercial banks, as at the end of December 1978, and would be exclusive of housing loans meant for banks' own employees. The adequacy or otherwise of this proportion will be reviewed from time to time.

2.132 Within the amount earmarked the proportion of direct and indirect finance to be provided is at the discretion of the banks. However, banks should ensure that the major portion of the additional finance is provided as subscription to the guaranteed bonds and debentures of Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) and State Housing Boards. Direct finance for housing projects should, in the main, be for the benefit of scheduled castes and scheduled tribes, economically weaker sections, low-income groups and middle-income groups. Housing finance should not normally exceed 50 per cent of the total cost of project and the rate of interest should be 12 per cent, with half a percentage rebate for regular payment of instalments. Banks may, however, provide housing loans up to 80 per cent of the total cost to scheduled castes and scheduled tribes, economically weaker sections and low-income groups and charge an interest of four per cent to scheduled castes/tribes on loans not exceeding Rs. 2,500. The repayment period should not be more than 10 years. The security for the advance should be either mortgage of the properties or Government guarantee.

2.133 While the advances may remain in the books of banks, they may consider channelising housing finance through RRBs, village co-operative and voluntary agencies and avail of the services of these institutions for identifying suitable borrowers and for disbursement and recovery of such advances.

2.134 The Working Group has categorised certain construction activities eligible for bank finance but not as housing finance. Such activities should be financed strictly on commercial priciples, with utmost importance given to considerations of national priority. While dealing with applications for finance income generated, cash flow, sources of repayment and other relevant data need to be scrutinised carefully to ensure that the project is commercially viable and that the additional cash generated will be adequate to meet the instalments due under such loans. Finance for construction activities other than housing finance may be granted to both public and private sector undertakings, but it should be ensured that, in the case of public sector units, bank finance is not substituted for usual budgetary allocations for construction of infrastructural facilities (public roads, bridges, harbours, dams, etc). The terms and conditions governing such finance should be as follows :

2.135 Banks should not advance more than 40 per cent, and in exceptional cases, 50 percent of the cost of the project. Interest should be at the rate usually applicable to commercial advances. Loans should normally be repaid within seven years, but in no case should the repayment period exceed ten years. Security may comprise mortgage of properties and/or other security normally available for such purposes.

2.136 Banks were advised that no finance in the form of direct loans should hereafter be provided by them for infrastructural facilities and construction of buildings meant purely for government/semi-government offices, including municipal and panchayat offices. Loans may, however, be granted for activities which will be refinanced by institutions like the ARDC, as well as to companies or individuals who

contract to undertake infrastructural construction. It is not necessary to give any special consideration to charitable or religious organisations unless the beneficiaries under the scheme belong exclusively to the weaker sections.

2.137 Wherever possible, and particularly for projects involving capital outlay of large amounts, consortium approach should be adopted—involving commercial banks, HUDCO, Housing Boards, LIC, etc., depending upon the nature of the scheme. In such consortium lending, repayment period in the case of banks should not be more than ten years, the amount of instalment being on a *pro rata* basis. There is no objection to fixing longer repayment period for specialised agencies like HUDCO, Housing Boards, LIC, the repayment being on a *pro rata* basis starting simultaneously.

Study Group on Follow-up of Bank Credit—Tandon Committee

2.138 The Committee of Direction constituted by the RBI in 1975 has been serving as a useful means to maintain flexibility in the operation of the new lending policies, formulated in the light of the recommendations of the Report of the Study Group on Follow-up of Bank Credit. The suggestions of the Committee are being followed up by the Cell set up in the Department of Banking Operations and Development of the Bank.

2.139 During the period under report the Committee held three meetings and examined a number of issues raised by banks, industries and their representative associations, as also Chambers of Commerce and Industry, in regard to application/modification of lending norms as also other matters on which the Committee's views could be obtained with advantage before taking a decision. The RBI examined the views given by the Committee on the various issues referred to it and advised banks suitably to enable them to further improve the operational flexibility and develop better understanding of the new lending system. Some of the major issues discussed by the Committee, decision taken and guidline/instructions issued to banks are given below.

(i) In order to make the lending methods (recommended by the Study Group) more flexible, banks were informed in July 1978 that they might, as a special case, consider permitting slip-back in current ratio to a limited extent for certain purposes to industrial units which have good past performance record and which have built up a sound current ratio over a period of time. However, it was emphasised that banks should ensure that the current ratio of at least 1.33 : 1 is maintained. Banks were also advised that the borrowers to whom the first method of lending recommended by the Study Group is applied should not normally be allowed to expand their activities without bringing in additional equity or raising term loans so that their financial structure is not weakened as a result of expansion.

(ii) The questions whether term loans should continue to be included for the purpose of cut-off points under the CAS and whether letters of credit and guarantees should be brought within the purview of the Scheme, were considered and suitable instructions were issued to banks in August 1978.

(iii) The question of application of various recommendations of the Study Group on Follow-up of Bank Credit to small-scale units was considered by the Committee. It was of the view that as over 90 per cent of the small-scale units enjoy credit limits of less than Rs. 2 lakhs and as the inventory norms recommended by the Study Group are applicable only to units enjoying credit limits of over Rs. 10 lakhs from the banking system, most of the SSI units would be outside the purview of the norm. It is only the large units among them, that are covered by the discipline and as they are potential medium/large industries, it is advisable to gradually expose them to better management practices.

(iv) The problem of delayed payment of bills of small-scale industries by large units was discussed in the Committee. The matter was further examined and banks were advised in August 1978, *inter alia* that they might fix up separate sub-limits for acceptance/letters of credit facilities within the overall credit limits, which should be utilised only in respect of their purchases from small-scale industries ; the quantum of sub-limits might be decided after taking into account the proportion of purchases from the SSIs and other relevant factors. Banks were also asked to obtain each quarter the particulars of the amount due to small-scale units by their medium and large borrowers and discuss the matter appropriately with the borrower to ensure that payments to small-scale units would be made without delay.

(v) The matter relating to the type of quarterly information to be obtained by the banks from certain non-manufacturing units was discussed by the Committee and in pursuance of the decision taken, a Sub-Group has been constituted by RBI for examining in detail the type of information to be obtained from non-manufacturing units (*viz.*, transport, construction companies, electricity boards, trading units, hotels, civil supplies corporation etc.) and to consider other measures to ensure control and proper follow-up of bank finance to such units. The Sub-Group held its first meeting on April 17, 1979.

(vi) Regarding the relaxations in the norms of inventory/receivables to be allowed to tyre manufacturing industries the Committee felt that there was no case for a general modification in the inventory/receivable norms, as applicable to rubber products.

(vii) As regards, interchangeability in the norms, the Committee felt that there is already an in-built interchangeability in the norms in respect of finished goods and receivables in certain industries, which have been prescribed by the Study Group itself. Secondly, the norms have been stipulated separately in respect of individual components of inventory (i.e., raw-materials, stocks-in-process and finished goods) as the factors governing their needs vary and that further interchangeability will not be in line with the rationale of norms.

(viii) The difficulties/inconveniences experienced by borrowers in obtaining sanctions, etc., under the consortium arrangements and lack of co-ordination and certain other operational problems experienced, were discussed in the Committee of Direction. In the light of the discussions, certain broad guidelines were issued to banks in November 1978, covering various aspects, such as number of banks that may form consortium, the need for prescribing minimum share of member banks, operational involvement of members of the consortium, procedure by which undue delay in appraisal as well as at other stages could be obviated/minimised, exchange of information, inspection/verification of the security held for advances, etc.

(ix) In response to a representation received from the Leather Export Promotion Council, the RBI advised banks that though the Tandon Committee had not prescribed any norms for leather industry, banks might determine the reasonable levels in respect of inventory/receivables in this regard, keeping in view the past trends, process/lead time, trade practices, etc. Banks were also told that, while considering the reasonableness of the projections, they might also take into account the fact that, with the shift in the emphasis from export of semi-finished leather to finished leather and leather products, the process time would be elongated and that the units would have to carry higher inventory. Further, since most of the units were stated to be small proprietary/partnership concerns, they might not be in a position to raise equity and term loans to provide 25 per cent of the working capital gap, even on the basis of the first method of lending. In order to enable the industry to take advantage of the export market, banks were asked to permit suitable relaxations in deserving cases, subject to periodical review and also consider request of these units for term loan; sympathetically for purchase of the requisite machinery. Banks should also ensure that the assisted units improved their financial structure by such measures as plough-back of profits.

(x) As regards the continuance or otherwise of the relaxations in inventory/receivable norms for cotton spinning mills and fertiliser industry, the following decisions were taken.

(a) Cotton Spinning Mills.—There was no need for continuing the relaxations as the position of the cotton spinning mills had improved.

(b) Fertiliser Industry.—Before considering any modifications in the existing relaxations allowed to the industry, the matter might be discussed further with the Fertiliser Association of India.

The Committee also discussed various other issues referred to it, such as—

(i) Implementation of various recommendations of the Study Group on Follow-up of Bank Credit and the difficulties experienced by banks in the implementation;

(ii) Scrutiny of the statements submitted to banks by the borrowers under the Information System;

(iii) Management audit of borrowing units; and

(iv) The question whether, and if so, to what extent the Information System built up by banks in respect of their large borrowers can be used for detecting/preventing the financial mismangement of the industrial units or whether the banking system can resort to any other measures, such as strengthening the hands of the auditors, etc., to achieve this purpose.

Inter-Institutional Group on Lending Operations

2.140 A reference was made in the last year's Report of the submission of the Report by the Inter-Institutional Group on Co-ordination of the Lending Operations of Term-lending Institutions and Commercial Banks. The Group has made recommendations on all aspects of co-ordination between term-lending institutions and banks : spelling out the criteria for sharing term-loans; indicating the role of term-lending institutions and banks in regard to appraisal, follow-up, sharing of information etc.; indicating the timing of sanctioning working capital limits and the opening of letters of credit in relation to the clearance of the project and the sanction of term-loans; suggesting operational details of sharing of securities, scrutiny of documents, sharing of each flows, etc., and the nursing of sick units. In terms of the recommendations of the Group, a Standing Co-ordination Committee consisting of representatives of the RBI, commercial banks and term-lending institutions has been set up for considering various policy issues that may arise in the course of term-lending institutions and banks acting in co-ordination in financing industrial projects. The recommendations relating to participation of term-lending institutions in rehabilitation assistance to sick units were under the examination of the said Group. The other recommendations were accepted by the RBI subject to certain modification/clarifications.

Working Group on Operational Efficiency and Profitability of Banks

2.141 The RBI considered the recommendations of the Working Group and issued guidelines to banks on certain aspects of cost control, cash management, staffing pattern, customer service, branch profitability pricing of services, discretionary powers, etc.

Working Group on Customer Service in Banks

2.142 A mention was made in the last year's report regarding constitution of a Group (Task Force) to examine the recommendations of the Working Group on Customer Service in Banks with a view to implementing them expenditiously. The Group held meetings regularly and review the progress made by banks in the implementation of the recommendations. During the year two more recommendations were accepted by the Government with certain modifications and the banks were advised to implement them in September 1978[1]. Besides, it may be stated that many banks in the public sector have made considerable progress in the implementation of those recommendations which could be implemented unilaterally by them. The RBI maintains information in this regard on the basis of the quarterly progress reports submitted by banks. The progress made by the banks in the seven areas in which the Working Group had felt an urgent need for achieving improvement in the customer service in banks is given below :

TABLE 2.16—PROGRESS IN IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS RELATING TO CUSTOMER SERVICE

Service Area	Total Number of recommendations accepted by the Government	Total number of recommendations implemented by more than 50% of banks
1. Deposit accounts	14	8
2. Remittances and collections	12	8
3. Loans and advances	8	6
4. Foreign Exchange business	5	1
5. Government business	1	1
6. Discipline and attitude	7	3
7. General	4	4

Export Group on State Enactments having a bearing on Commercial Banks' Lending to Agriculture

2.143 The progress in the implemen ation of the recommendations of the Expert Group on State Enactments having a bearing on Commercial Banks' Lending to Agriculture (Talwar Committee) was covered in the last year's Report. 16 States have passed necessary legislation on the lines of the Model Bill recommended by the Talwar Committee.

Export Group on Agricultural Credit Schemes of Commercial Banks

2.144 A reference was made in the last year's Report on the submission of the Report by the Expert Group on Agricultural Credit Schemes of Commercial Banks. The Group has emphasised the need for effectively dovetailing the agricultural credit schemes of commercial banks with developmental efforts and also with credit schemes for other supporting activities which enhance the benefits of loans given to cultivators. Unless this is done, it will not be possible to ensure that increasing amounts of credit generate incremental incomes for all categories of agricultural borrowers. The Group finds, that, notwithstanding the impressive increase in the flow of commercial banks' credit to agricultural sector and the progress made in evolving arrangements to provide increasing quantum of credit to agriculturists, there are still a number of short-comings in the modalities of formulation, content and implementation of agricultural credit schemes. It has made a series of recommendations designed to achieve the desired objectives and emphasised that many of them would be valid irrespective of whether the banks themselves directly disburse loans to agriculturists or do so through intermediaries such as PACS and FSS. Most of the recommendations of the Group have been commended to the banks for implementation.

Puri Committee's Report

2.145 On the basis of the recommendations of the High Power Committee appointed by the Central Government with Shri L. C. Puri as Chairman, to examine bank credit problems of small-scale industries, the RBI issued guidelines to banks in July 1978 to facilitate flow of credit to that sector. Banks were advised to adopt a flexible approach towards

1. These are Recommendations No. 28 & No. 30 in the Final Report of the Working Group. They relate to customer service in such areas as furnishing of statement of accounts and passbooks.

margin requirements particularly in regard to smaller units of the small-scale industries and the technically qualified and other entrepreneurs sponsored under special employment schemes of Central/State Governments, be guided by the viability of projects and not to turn down any worthwhile proposal for want of collateral security/guarantee.

Study Group to Assess Credit Needs of Handlooms

2.146 The GOI constituted a Study Group to review the financing of handloom weavers outside the fold of co-operatives and state handloom development corporations by the nationalised banks. The Group was asked to estimate the credit requirements of the corporations over the next five years and suggest measures and institutional procedures which will help in securing smooth flow of bank finance. It was also asked to make a study of the present role of nationalised banks in financing the handloom weaver/handloom development corporations to suggest methods by which working relationship between these corporations and nationalised banks could be increasingly established, and to assess the comparative advantages and disadvantages of co-operative channels of credit and commercial banks financing the handloom sector. The Study Group has since submitted its Reports to the GOI.

Working Group on Participation Certificates

2.147 In pursuance of the decision taken at the meeting which the RBI had with the Chairmen of some of the major banks on March 15, 1979, the RBI constituted two Working Groups, one to review banks' recourse to participation certificates and borrowings in call money market from financial institutions and another to review the system of cash credit by banks in all its aspects.

2.148 The terms of reference of the Working Group on Participation Certificates are (i) to examine the size and pattern of operations in call money market and in respect of participation certificates and clarify the implications for monetary and credit policies, (ii) to indicate the basis on which the broad magnitude of resources available to banks from sources other than commercial banks and refinance agencies (such as IDBI and ARDC) may be asessed, (iii) to examine the implications of any limitations on supplies of such funds from the non-banking institutions participating in the call money markets and participation certificate arrangements and suggest alternative avenues for the productive use of such funds, and (iv) to make recommendations on any other related matter. The Working Group submitted its Report in May 1979. While considering the various suggestions made by the Working Group, it was decided to begin with to initiate measures to discourage banks from excessive resources to PCs These measures have been discussed earlier in the paras on credit policy.

Working Group on Cash Credit

2.149 The Working Group on cash credit has been asked to review the operation of cash credit system in recent years, particularly with reference to the gap between sanctioned credit limits and extent of their utilisation; to suggest, in the light of this review, modifications in the system with a view to making the system more amenable to rational management of funds by commercial banks and/or alternative types of credit facilities, which would ensure greater credit discipline and also enable banks to relate credit limits to increase in output or other productive activities, and to make recommendations on any other related matter as the Group may consider germane to the subject. The Working Group has submitted an interim report which is under consideration.

Working Group on Financial Agency for Small Industry

2.150 In May 1979, the RBI constituted a Working Group to examine the question of setting up an apex financial institution for meeting the credit requirements of the small and decentralised sector of industry. The terms of reference of the Working Group are (1) to suggest ways and means for increasing the credit flow to meet the requirements of the small and decentralised sector of industry and, in this context, to assess the possibility of setting up a separate financial agency for this purpose; (2) to consider matters of both legislative and administrative character which will need to be sorted out prior to the actual establishment of a new financial agency; (3) to examine whether any such agency should cover the entire gamut of the small-scale sector, or agencies need to be established to meet the credit requirements of the small-scale sector and village and cottage industries separately; (4) to determine the scope of activities such as refinancing operations and marketing operations to be entrusted to the new financial agency; and (5) to determine the linkage between the proposed financial agency and the existing credit channel such as commercial banks and State Financial Corporations (SFCs).

Review of Laws affecting and concerning Banks—Report of the Banking Laws Committee

2.151 In 1972 the GOI constituted the Banking Laws Committee as a One-man Committee under the Chairmanship of Dr. P. V. Rajamannar. The Committee submitted the following reports to the Government and the RBI for consideration.

(i) Report on Negotiable Instruments Law

The report is the product of a comparative study of the law and practice in India and in other countries with reference to negotiable instruments. The Committee has made a comprehensive review of all aspects of the general law relating to negotiable instruments, particularly bills, cheques and notes and has made certain recommendations for amending the present Negotiable Instruments Act which has been in operation in the country since 1881.

(ii) Report on Real Property Security Law

The report reviews the real property security law in general (embodied mainly in our mortgage law) and the special law relating to the extension of rural credit by institutional agencies against both personal property and real property.

(iii) Report on Personal Property Security Law

The report considers all the aspects relating to commercial and business credit with reference to the different types of available personal property which may be offered as security to the institutional and other lenders.

(iv) Report on Documents of Title to Goods

The report provides a review of the legal framework governing railway receipts, lorry receipts, bills of lading, warehouse receipts and other documents eligible for bank advances. The report also contains a review of Pucca Delivery Order (PDO) System prevailing in jute trade.

(v) Report on Indigenous Negotiable Instruments (Hundies)

The report proposes to codify the practices and usages relating to indigenous instruments, viz., hundi. The above reports are under consideration of the RBI and GOI.

Committee for Enlargement of Statutory Auditors Panel (for Public Sector Banks)

2.152 In October 1978, the RBI constituted the above Committee to evolve norms and guidelines for empanelment of auditors for being considered for appointment to the public sector banks. The committee will also make recommendations on certain other allied issues. The committee is composed of members representing RBI, GOI, Comptroller and Auditor General's Office, Indian Banks' Association, SBI, Institute of Chartered Accountants of India and Standing Advisory Committee of Bank Auditors.

Other Committees

2.153 The One-Man Committee on Selective Credit Controls submitted its Report and its recommendations are under consideration of the Bank.

EDUCATION AND TRAINING

Regional Rural Banks

2.154 The Chairman and branch managers of RRBs are imparted training at the College of Agricultural Banking (CAB) in Pune. It was decided that while the training of chairman and branch managers of RRBs would be conducted at the CAB, Pune, the training of other staff such as Accountants, Field Officers and Clerks would be at the training centres of the respective sponsor banks under the overall supervision of the CAB, Pune.

2.155 The Steering Committee on RRBs, in its second meeting, modified the training arrangements. It was decided to discontinue the 12 weeks' course conducted by the CAB. The latter may instead conduct a four weeks' orientation programme. Such course need not be limited to two courses in a year but as many number of courses as may be required to cover all the remaining untrained branch managers within a reasonable period of 3 to 4 years. The sponsor banks would be advised to arrange for a basic training programme in their own training colleges or institutions.

Lead Bank Scheme

2.156 With a view to having better understanding and appreciation of the objectives and implications of the Lead Bank Scheme, the High Power Committee on the Scheme had decided that the National Institute of Bank Management (NIBM) should organise workshops for officials of the State Governments and commercial banks at district levels as also at the State level. The NIBM accordingly arranged workshops in seven districts of Uttar Pradesh and in three districts of West Bengal. The matter was again considered by the High Power Committee in its fourth meeting held in July 1978 and it was decided that a strategy should be evolved whereby all the districts in the country could be covered by the training programme as quickly as possible. The NIBM organised four seminars in December 1978, at Banker's Training College, Bombay, each of three days' duration, at which representatives from the Head/Regional Offices of lead banks and faculty members from their training colleges, as also State Government officials, participated. It is the intention that the participants of the various lead banks who attended the seminars will, in turn, in co-ordination with the State/district functionaries, arrange to organise district level workshops, so as to cover the various districts in the country as quickly as possible. Accordingly as a first step, most of the lead banks drew up programmes for holding district level workshops during the half-year ended June, 1979.

2.157 The NIBM also organised State level workshops for West Bengal, Uttar Pradesh and Assam. Further SBI/NIBM have organised State level workshops for Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. It is proposed to organise State level workshops in all the other States, by involving the conveners of the State Level Bankers' Committees.

Use of Hindi in Public Sector Banks

2.158 During the period under review, the RBI continued its efforts for the progressive use of Hindi in its working as well in the working of public sector banks. The Official Languages Implementation Committee set up in the Bank for monitoring the progress made in the use of Hindi in the public sector banks held its sixth meeting on January 22, 1979. The decisions taken in the meeting were conveyed to all the public sector banks.

2.159 With a view to watching the progressive use of Hindi by the public sector banks, quarterly progress reports, annual assessment reports and copies of the proceedings of Official Languages Implementation Committees constituted by individual banks continued to be obtained by the Bank. The information on the subject was also being collected from the banks and forwarded to the GOI.

CHAPTER 3

CO-OPERATIVE BANKING

3.1 Further efforts were made during the year to strengthen the institutional arrangements for rural credit with a view to facilitating larger flow of credit to both the agricultural and non-agricultural sub-sectors and, particularly, to the weaker sections of the rural population. The progress achieved by commercial banks and RRBs in this sphere has already been reviewed in Chapter 2. The measures taken to strengthen the co-operative credit structure and the progress achieved in respect of enlarging the flow of credit—agricultural/non-agricultural and short-term/medium-term/long-term—are discussed in this Chapter.

3.2 Data on the progress of co-operative credit during the three years ended June 1978 and credit facilities provided by the RBI and rates of interest on refinance are presented in Tables 3.1 and 3.2, respectively. The present position of interest rates charged at various levels of co-operative structure is indicated in Table 3.3.

3.3 Co-operatives made further progress in deposit mobilisation. While deposits with SCBs and CCBs amounted to Rs. 835 crores and Rs. 1,154 crores, respectively, at the end of June 1977, those with PACS were Rs. 142 crores. By the end of June 1978 the deposits increased to Rs. 1,002 crores, Rs. 1,373 crores and Rs. 165 crores, respectively; the growth rates were 20.0 per cent, 19.0 per cent and 16.2 per cent, respectively, in 1977-78 as against 15.3 per cent, 17.2 per cent, and 25.7 per cent, respectively, in 1976-77. As on May 1979, deposits of SCBs and CCBs rose to Rs. 1,059 crores and Rs. 1,526 crores, respectively. Membership in PACS increased from 395 lakhs at the end of 1975-76 to 448 lakhs at the end of 1976-77 and further to 610 lakhs at the end of 1977-78. Short and medium-term loans issued by PACS during 1977-78 amounted to Rs. 1,257 crores as against Rs. 1,211 crores in 1976-77.

3.4 The discretion given to co-operative banks to pay interest on deposits at rate higher (subject to a limit) than that paid by commercial banks was continued during the year.

Lending Rates

3.5 The rates of interest on short-term credit facilities from the Bank to the apex co-operative banks (SCBs), which were lowered during 1977-78, were further reduced in the case of medium-term loans. Effective January 1, 1979, the revised rate for medium-term loans for agricultural purposes and for conversion loans is 3 per cent below the Bank Rate, as against the old rate of 2½ per cent below the Bank Rate. The purposes for which short-term loans were eligible for refinance from the RBI remained unchanged and minor additions were made in medium-term purposes.

3.6 The Bank accepted and implemented the recommendations of the Study Group on Interest Rates Structure of Co-operatives, which submitted its report in June 1978, as mentioned in the last year's Report. The Study Group had made several recommendations for rationalisation of interest rates on short-term and medium-term agricultural credit and bringing about parity in the rates charged by other institutional agencies dispensing agricultural credit. These are discussed in the appropriate sections. Further, consequent upon the concessions announced by the ARDC in its refinance to elibible institutions, rates of interest on long-term credit disbursed by co-operatives were suitably lowered.

AGRICULTURAL CREDIT

A. SHORT-TERM CREDIT

(a) Short-term Credit for Seasonal Agricultural Operations

3.7 Under the scheme of linking borrowings from the RBI with efforts at deposit mobilisation by CCBs, the concessional rate of interest is available to CCBs only to the extent that they fulfil the deposit targets. This scheme was continued during the year under review. During 1977-78, the full benefit of concessional rate of interest was not available to 36 CCBs as against 29 CCBs in 1976-77 and 32 CCBs in 1975-76. The number of banks covered by the scheme increased from 246 CCBs and 3 SCBs, at the end of 1976-77 to 290 CCBs and 6 SCBs at the end of 1977-78.

TABLE 3.1—PROGRESS OF CO-OPERATIVE CREDIT MOVEMENT IN INDIA

(Amount in Rupees Crores)

Type of Institutions	Co-operative Years		
	1975-76	1976-77	1977-78 P
	1	2	3
(a) State Co-operative Banks			
(i) Number (actuals)	26	26	26
(ii) Owned Funds	159	184	213
(iii) Deposits	724	835	1,002@
(iv) Borrowings from the RBI	247	375	468
Of which : S.T. Agricultural	147	229	289
(v) Working capital	1,287	1,526	1,814
(vi) Loans issued	1,515	1,899	2,005
(vii) Loans Outstanding	894	1,089	1,321
(b) Central Co-Operative Banks			
(i) Number (actuals)	344	344	338
(ii) Owned Funds	360	423	484
(iii) Deposits	985	1,154	1,373
(iv) Borrowings from the RBI/apex banks	513	699	767
(v) Working capital	2,048	2,514	2,774
(vi) Loans issued	1,722	1,988	2,130
(vii) Loans outstanding	1,428	1,796	2,111
(c) State/Central Land Development Banks			
(i) Number (actuals)	19	19	19
(ii) Owned Funds	154	164	208
(iii) Debentures outstanding	1,384	1,591	1,559
(iv) Working capital	1,667	1,918	2,082
(v) Loans issued	205	249	239
(vi) Loans outstanding	1,069	1,211	1,305
(vii) Loans to individuals by CLDBs/PLDBs	215	278	217
(d) Primary Agricultural Credit Societies			
(i) Number (in thousands)	135	124	122
(ii) Membership (in thousands)	39,521	44,832	61,003
(iii) Owned Funds	457	499	554
(iv) Deposits	113	142	165
(v) Borrowings	1,154	1,426	1,614
(vi) Total Loans issued	1,023	1,211	1,257
(vii) Total loans for agricultural purposes	971	1,152	1,203
of which Medium-term loans	90	136	149
(viii) Loans outstanding	1,299	1,599	1,758

(*Source* : Agricultural Credit Department, RBI). P=Provisional

@ Rs. 1,059 crores as on end-May 1979.

@@ Rs. 1,526 crores as on end-May 1979, inclusive of 9 Industrial Co-operative Banks.

TABLE 3.2 –RESERVE BANK CREDIT TO CO-OPERATIVES, STATE GOVERNMENTS AND ARDC DURING 1977-78 AND 1978-79

(Rupees in Crores)

Section of the RBI ACT, 1934	Purpose of finance	1977-78 ā				1978-79 ā			
		Limits sanctioned	Drawals	Repayments	Outstandings	Limits sanctioned	Drawals	Repayments	Outstandings
		1	2	3	4	5	6	7	8
I. Short-term Total††		**845**	**1,228**	**1,163**	**325**	**946**	**1,218**	**1,283**	**259**
17(2)(b) read with 17(4)(c)/Section 17(4)(c)	(i) Seasonal agricultural operations (at 3% below Bank Rate)[1]	749	994	934	289	795	1,066*	1,121*	234*
-do-	(ii) Marketing of crops other than cotton and *kapas* (at Bank Rate from June 1978)	1	—	—	—	3	—	—	—
17(4)(c)	(iii) Marketing of cotton and *kapas* (at Bank Rate from June 1978)[2]	14	1	1	..	66	4	4	—
-do-	(iv) Purchase and distribution of fertilisers (at 1% above Bank Rate from June 1978)[3]	13	24	31	3	6	8	10	1
17(2)(bb) read with 17(4)(c)	(v) Production and marketing of handloom products (at 2-1/2% below Bank Rate from March 1978)[4]	44	167	159	24	51	126	134	16
-do-	(vi) Financing of other cottage and small scale industries (3% below Bank Rate from March 1978)[4]	7	5	4	5	6	12	9	8
17(4F)	(vii) Loans to ARDC (at Bank Rate)	10	—	—	—	10	—	—	—
17(4)(c)	(viii) Purchase and sale of yarn (at Bank Rate)[4]	2	1	1	—	3	1	1	—
-do-	(ix) Against pledge of sugar (at 3% above Bank Rate)	8	36	34	3	6*	1	4	—
II. Medium-term Total††		**121**	**115**	**89**	**161**	**66**	**38**	**75**	**125**
17(4AA) read with 46A(2)(b)	(i) Agricultural purposes (at 3% below Bank Rate from January 1, 1979)[5]	21	12	7	22	28	16	11	28
17(4AA) read with 46B(2)	(ii) Conversion of short-term loans into medium-term loans in scarcity affected areas (3% below Bank Rate from January 1979)[5]	98R	103	81	138	37	22*	64*	97*
17(4AA) as determined under Section 46A(2)(B)	(iii) Purchase of shares in co-operative sugar factories/ processing societies (at Bank Rate)[5]	1	—	—	—	1	—	—	—
III. Long-term Total		**86**	**86**	**29**	**328**	**94**	**94**	**38**	**385**
17(4AA) as determined under Section 46A(2)(a)	(i) Loans to State Governments for contribution to share capital of co-operative credit institutions (at 6% per annum)[4]	21	21	8	111	19	19 ā ā	10	121
17(4AA) read with Section 46A.(2)(e)	(ii) Loans to ARDC (at 6% per annum)	65	65	21	217	75	75	28	264
Total Credit (I+II+III)		**1,052R**	**1,429**	**1,281**	**814**	**1,106**	**1,350**	**1,396**	**769**

1. At 2% below Bank Rate up to February 1978; from March 1, 1978 at 3% below Bank Rate subject to recovery of an additional interest of 1-1/2% accordng to the scheme linking refinance at concessional rate with mobilisation of targeted deposits by CCBs.
2. Including monopoly procurement of cotton.
3. Data relate to calendar year 1977 for cols. 1 to 4 and to 1978 for cols. 5 to 8.
4. Data relate to financial years.
5. Including rephasement and reschedulement.

ā Refer to July-June unless otherwise mentioned.

ā ā Farlier year's drawals.

* Position as on 31-5-1979

††Marginal differences in the totals of various items in Short and Medium-term loans and group totals are due to rounding up of figures.

R Revised.

— Nil or Negligible.

TABLE 3.3—RATES OF INTEREST CURRENTLY CHARGED AT VARIOUS LEVELS OF THE CO-OPERATIVE STRUCTURE

(Per cent per annum)

States/Union Territories	Apex Banks		Central Co-operative Banks		Primary Credit	Agricultural Societies
	Short-term	Medium-term	Short-term	Medium-term	Short-term	Medium-term
	1	2	3	4	5	6
Andhra Pradesh	6.75	7.25	8.75	9.25	11.00	11.50
Bihar	6.75	N.A.	8.75	N.A.	11.25	N.A.
Gujarat	6.00 to 6.50	6.50 to 7.00	7.75 to 11.00	8.00 to 12.75	8.00 to 13.50	9.50 to 15.00
Haryana	6.40	7.50	8.50	9.00	11.00	11.00
Karnataka	6.75	6.25	9.00	9.25	11.50	12.25
SF				8.25		11.00
Kerala	6.75	N.A.	8.50	N.A.	11.00	N.A.
Madhya Pradesh	7.00	7.50	9.50	9.00 to 13.00	12.50	11.00 to 16.00
SF	6.50		8.00		10.00	
Maharashtra	6.25		8.00 to 10.00		11.00 to 13.00	
Orissa	6.75	7.25	8.75	9.25	11.00	11.50
Punjab	6.30	6.75	8.00	8.50	10.50	10.50
Rajasthan	7.75	7.00	9.75	8.50	12.00	10.50
SF	6.50		8.50		10.50	
Tamil Nadu	6.66	7.50	8.75	10.00	12.00	12.50
SF					10.50	
Uttar Pradesh	7.10		9.50		12.00	
SF	6.25		8.50		11.00	
West Bengal	6.75		9.00		11.25 to 11.50	
Assam	10.50	10.50			13.00	13.00
Goa, Daman & Diu	7.00				9.00	
Himachal Pradesh	10.00	10.50			12.50	13.00
Jammu & Kashmir	6.75		8.50		11.00	
Andaman & Nicobar	9.25	12.00			11.50	14.00
Chandigarh	11.00	11.00			12.50	12.50
Manipur	10.00	10.50			13.00	13.00
Tripura	10.00	11.00			13.00	14.00
Nagaland	11.00	11.00			13.00	13.00
Meghalaya	11.00	11.50			13.50	14.50
Delhi	9.50	10.00			11.50	12.00
SF	9.00				11.00	
Pondicherry	8.50	9.00			11.00	11.00
SF	8.00				10.00	

SF—Small Farmers

(*Source* : Agricultural Credit Department, RBI)

3.8 The instructions issued earlier to ensure seasonality discipline in lending and recovery operations through requirement of specified recoveries of kharif and rabi advances before drawals by CCBs for the current year, were continued. However, as recommended by the Study Group on Interest Rates Structure of Co-operatives, the stipulations were relaxed and SCBs were allowed (with effect from April 1979) to draw on short-term credit limits sanctioned by the RBI on behalf of CCBs provided 40 per cent of current kharif 'demand'[1] (as against the earlier stipulation of 40 per cent of total 'demand' of short-term aricultural advances) or 30 per cent of the total 'demand' (including overdues) is recovered and remitted to the apex bank before March 31, 1979. Further before the close of co-operaive year, CCBs have to ensure a minimum recovery of 40 per cent of total 'demand' of short-term advances without which they will not be eligible for drawals in the next co-operative year. The total 'demand' will comprise overdues under short-term loans, as on June 30 of the previous year, and the **kharif** and **rabi** 'demands' for the concerned co-operative year. Though SCBs were free to lend from their own resources to such of the CCBs which did not comply with the prescribed seasonality discipline, the RBI advised SCBs that it expects them to adhere to the same stipulation in the case of financing of CCBs from their own funds also.

1. Excluding overdues.

3.9 During the year 1977-78, short-term credit limits sanctioned by the RBI to SCBs for financing seasonal agricultural operations had increased by Rs. 53 crores to Rs. 749 crores; a further rise of Rs. 46 crores was noticed during 1978-79 and credit limits reached Rs. 795 crores. This increase could be attributed to further strides made in structural and operational aspects of the co-operative movement.

(b) Financing of Weaker Sections

3.10 The Bank continued its efforts at reorienting the lending policies and procedure of CCBs in favour of small farmers. For instance, SCBs were not allowed to draw in excess of 70 per cent of the limits sanctioned to CCBs by the RBI unless the proportion of advances to small farmers was maintained at a specified percentage (usually 20 per cent) of their total short term advances to the affiliated primary Societies in accordance with the recommendations of the Study Group on Interest Rates Structure of Co-operatives, this condition was modified so as to enable a bank to draw on the limit even if it has not reached the prescribed level, provided such drawals are restricted to the extent of finance provided to small farmers. During 1977-78, 292 banks out of a total of 339 banks exceeded the stipulated share of advances to small farmers as against 260 out of 334 in 1976-77. With a view to enabling borrowers covered under the various schemes for weaker sections to avail themselves of medium-term finance for approved agricultural and allied purposes from co-operative banks, the existing norms in respect of security for medium-term finance were relaxed. Consequently, co-operative banks were permitted to sanction loans for purchase of milch cattle, poultry birds, sheep, etc., up to the cost of one economic unit against personal surety of a borrower, who has no tangible security to offer.

(c) Selective Credit Controls and Short-term Credit for Marketing of Crops

3.11 Advances against the security of sensitive commodities, viz., groundnut, mustard seed/rapeseed, castorseed, linseed and oils thereof, vanaspati, sugar, gur, khandsari and cotton and kapas were continued to be governed by the Bank's directives in regard to the minimum margin to be maintained and the rate of interest charged.

3.12 In view of the decontrol on prices, movement and distribution of sugar with effect from August 16, 1978, SCBs and CCBs were advised on September 8, 1978 that despite decontrol, the distinction between levy stocks and free stocks—(a) not released for sale and (b) released for sale—might be notionally continued and the respective margins laid down in the directive of February 1977 observed in respect of such advances for manufacturers of sugar. The banks were, however, asked to avoid undue expansion of credit to sugar industry as well as to avoid any forced withdrawal of funds already granted. In view of the comfortable supply position of sugar and better prospects for 1978-79 production, new directive was issued on November 1, 1978 to SCBs/CCBs for advances against security of sugar. The notional distinction between levy stocks and free-sale stocks of sugar was dispensed with and sugar stocks charged to the banks as security were to be valued on usual commercial principles. Consequently, the minimum margin of 65 per cent for advances (to co-operative societies manufacturing sugar) against free-sale sugar became inoperative. The revised minimum margin on advances against sugar to these parties was 15 per cent. In the case of non-manufacturers, the margin was, however, continued at 65 per cent and 55 per cent against stocks and warehouse receipts covering stocks, respectively. The minimum interest to be chargd on loans/advances/cash credits/overdrafts against the security of sugar to parties other than those manufacturing sugar was continued at 15 per cent. However, no minimum rate was fixed in the case of advances to manufactures of sugar; these advances were allowed subject to the general minimum lending rate of 12½ per cent per anum. The earlier stipulations on minimum margin and minimum rate of interest regarding advances made by SCBs and CCBs to cotton mills against raw cotton and kapas continued. However, from April 19, 1979, advances against stocks of cotton require a minimum margine of 25 per cent for loans against stocks equivalent to 4 months' consumption and 45 per ceint for loans against stocks n excess thereof. A uniform minimum margin of 20 per cent was permitted in case of limits fully guaranteed by the State Governments. The earlier stipulation was a minimum margin of 25 per cent on loans against stocks of 9 weeks' consumption and 45 per cent for loans against stocks in excess thereof. In the case of advances against cotton and kapas to parties other than manuafcturers, there was no change in the minimum margin 50 per cent) and the minimum rate of interest (15 per cent).

3.13 A directive was issued in January 1979 to Urban Co-operative Banks (UCBs) clarifying the position in regard to their advances against usance bills arising out of sale and purchase of sensitive commodities covered by selective credit controls. Accordingly, such advances were permitted within stipulated conditions applicable to the advances against sensitive commodities. The ceiling limit on advances against usance bills to individual borrowers was maintained at Rs. 1 lakh (as in the case of advances against commodities mentioned last year) with a minimum margin of 25 per cent. Advances against usance bills arising out of sales of cotton and kapas, however, were excluded. With a view to assisting internal movement of goods. UCBs were also permitted to give credit facilities by way of purchase of demand documentary bills in connection with movement of commodities covered under selective credit control, provided they ensured that the facilities were utilised for genuine movement of goods and the bills purchased were promptly realised.

3.14 The limits for marketing of crops showed a sizeable increase from Rs. 15 crores in 1977-78 to Rs. 69 crores in 1978-79. In 1977-78, a credit limit of Rs. 14 crores was sanctioned for marketing of cotton and kapas. In 1978-79, the limit rose to over Rs. 66 crores. The increase was mainly due to RBI refinance (Rs. 45 crores) available for the monopoly cotton purchase scheme of the Government of Maharashtra.

Distribution of Fertilisers

3.15 The RBI continued to sanction short-term credit limits to SCBs for financing distribution of fertilisers on a selective basis, wherever commercial banks were not able to do so. During the calendar year 1978, the Bank sanctioned credit limits aggregating Rs. 6 crores to three SCBs as against Rs. 13 crores in 1977 to five SCBs.

B. MEDIUM-TERM CREDIT

3.16 During the calender year 1979, the Bank continued its earlier policy of granting refinance facilities for medium-term loans in respect of agricultural purposes and also for conversion purposes.

3.17 With a view to curbing overdues it was, however, decided that for the year 1979, the refinance facility would be available only to those banks, which had total overdues less than 60 per cent of total demand for 1977-78 and for which short-term credit limits were not denied during 1978-79. Till the year 1978, banks having overdues above 60 per cent of the total demand and over 50 per cent in respect of their medium-term advances were not eligible for refinance from the Bank. However, banks in the areas covered by SFDAs and MFALs were eligible for refinance even though their overdues in respect of medium-term loans exceeded 50 per cent of the demand'.

3.18 The Bank's policy in regard to the refinancing of loans for the purchase of milch cattle, sheep, poultry birds, bullocks and bullock carts, etc., was modified with effect from August 1978 so as to benefit those covered by special programmes and more particularly the weaker sections of the borrowers. These changes, depending on the size of the economic units, security offered, etc., will enable even smaller units to obtain medium term advances.

3.19 Out of Rs. 28 crores of medium-term credit for agricultural purposes sanctioned by the RBI for the calendar year 1978, an amount of Rs. 16 crores was drawn by SCBs. During 1977, Rs. 21 crores of medium-term credit had been sanctioned against which Rs. 12 crores was drawn.

Conversion Loans and Loans for Share Capital Contribution

3.20 The RBI continued to sanction medium-term conversion limits from the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund for enabling SCBs/CCBs to repay short-term agricultural loans due to the RBI in respect of areas affected by natural calamities. During 1978-79 (upto May 1979) limits amounting to Rs. 37 crores were sanctioned as against Rs 98 crores in 1977-78. On the recommendation of the Agricultural Credit Board, it has been decided that the State Governments

will have to bear their share of 15 per cent of conversions sanctioned in respect of short-term production loans issued for 1978-79 rabi season and the thereafter. Thus the refinance from the Fund would be confined to only 60 pre cent of such conversion. The balance would be met as below :

State Government—15 per cent, SCB—10 per cent and CCB—15 per cent. During the year 1978-79, loans amounting to Rs. 19 crores were sanctioned from NAC (LTO) Fund to the State Governments for contributing to share capital of co-operative credit institutions; the loans were fully drawn. For 1978-79, conditions for sancton of such loans in respect of FSS functioning for over 3 years and in respect of weak PLDBs were modified. In the case of the former, the sanction was subjected to over dues not exceeding 50 per cent of the demand during 1977-78, while in the case of the latter, the conditions applicable to PLDBs functioning in SFDA notified areas were extended to week PLDBs brought under rehabilitation programme.

C. LONG-TERM CREDIT

3.21 The Standing Committee on Debenture Norms constituted by the RBI in September 1975 for evolving uniform procedures for floatation of ordinary and special development debentures recommended some changes in the norms relating to the regulation of advances which were subsequently approved by the International Development Association (IDA). The revised norms which have been communicated to Land Development Banks (LDBs) in January 1979 are expected to enable them to step up their loaning operations. They would also enable Primary Land Development Banks (PLDBs)/branches of State Land Development Banks (SLDBs) to meet fully the investment credit needs of small/marginal farmers under special development programme and to disburse loans to the full extent of committed expenditure, at the same time making them eligible for some quantum of fresh loaning, which was not admissible under the previous norms. It may, however, be added that the eligibility of a PLDB/branch of SLDB will continue to depend on its recovery performance, as at the end of the preceding June but, under a revised slab system, which is more liberal than the earlier one, as indicated below :

Moreover under the revised criteria the consideration of overdues of a PLDB/branch of SLDB for deciding loan eligibility will be on the basis of the average of the last three years'

Earlier Norms		Revised Norms	
Range @ of overdues at the primary/branch level as at the end of June 1978	Eligible loaning programme as percentage of loans issued in the previous year or average of loans issued in preceding 3 years, whichever in higher	Range @ of overdues at the primary/branch level on the basis of the average of last three years' overdues at the end of co-operative year or previous year's overdues whichever is less	Eligible loaning programme as percentage of loans issued in the previous year or average of loans issued in preceding 3 years, whichever is higher
0—25	Unrestricted	0—25	Unrestricted
26—35	80	26—30	100
36—45	70	31—35	90
46—55	60	36—40	80
56—60	50	41—45	75
61—100	Nil	46—50	70
		51—55	65
		56—100	Nil

@Range refers to percentage of overdues to demand.

overdues, as at the end of the co-operative year, or overdues of the previous year, whichever is less. The revised norms also permit LDBs to meet their committed expenditure in full, irrespective of their eligibility, subject to their compliance with stipulated conditions.

Issue of Long-term Loans by PLDBs/Branches of SLDBs

Rate of Interest

3.22 The LDBs were advised in July 1978, to charge a rate of interest on ordinary loans (a) not exceeding 10.5 per cent per annum to the ultimate borrowers on advances for minor irrigation and land development purposes, and (b) not exceeding 11 per cent on advances for other purposes. Further, following the one per cent reduction in the rate of interest effected by the ARDC on the refinance provided by it, LDBs were advised to charge, with effect from March 15, 1979, a rate of interest to the ultimate borrowers at 9.5 per cent for minor irrigation and land development. For other purposes, the rate is 9.5 per cent for small farmers and 10.5 per cent for others.

Land Development Banks—Ordinary Debenture Programme

3.23 The lending programme of SLDBs for the financial year 1978-79 had been fixed at Rs. 119 crores (as against Rs. 328 crores for 1977-78) comprising Rs. 271 crores for ARDC refinance schemes and Rs. 148 crores under ordinary lending programmes. Of the ordinary lending programme of Rs. 148 crores for 1978-79, an amount of Rs. 23 crores was expected to come out of their internal resources and the balance of Rs. 125 crores was to be raised by way of floatation of ordinary debentures. Against the above programme, ordinary debenture floatation proposals for a total of Rs. 93 crores were approved by the RBI till March 31, 1979, which worked out to 74.3 per cent of the total programme of Rs. 125 crores.

3.24 The total lending programme of SLDBs for the financial year 1979-80 has been tentatively fixed at Rs. 434 crores. The ordinary lending programme, envisaged at Rs. 136 crores, is proposed to be financed to the extent of Rs. 11 crores from internal resources by the SLDBs and Rs. 125 crores is to be raised by way of floatation of ordinary debentures. The ordinary debenture programme is expected to be supported by the following agencies :

	(Rs. Crores)
(i) Central and State Governments . . .	16
(ii) Life Insurance Corporation	38
(iii) Commercial Banks through IBA . . .	10
(iv) State Bank of India Group . . .	7
(v) Mutual support and self help . . .	54
	125

Floatation of Rural Debentures

3.25 During the financial year 1978-79, the rate of interest on rural debentures was raised from 10 per cent to 12 per cent, the other existing terms and conditions for floatation of such debentures remaining the same. No bank had, however, floated rural debentures under the scheme.

NON-AGRICULTURAL CREDIT

INDUSTRIAL FINANCE

Working Capital Finance to Co-operative Sugar Factories

3.26 During 1977-78, the Bank had sanctioned short-term credit limits aggregating Rs. 8 crores for financing working capital requirements of co-operative sugar factories. For the year 1978-79 (up to May 1979), a credit limit of Rs. 6 crores was sanctioned.

Finance for Weavers' Societies

3.27 For the financial year 1979-80 credit limits to SCBs on behalf of CCBs for financing weavers societies were sanctioned by the Bank on the basis of the consolidated information furnished in the credit limit applications and the feasibility of lending programmes for the year. This facility was restricted to CCBs with proper supervision arrangements and in respect of viable primary societies. Thus, societies with overdues of over 60 per cent to CCB, societies placed in D class in audit or those which are not audited for over three years and those whose accounts with the bank have remained inoperative were not eligible for these limits.

3.28 As against the limit of Rs. 44 crores sanctioned by the RBI during the financial year 1977-78 for production and marketing of handloom products, a higher limit of Rs. 51 crores was sanctioned during 1978-79. The outstanding amount of advances was Rs. 13 crores as on March 31, 1979, as compared to Rs. 24 crores as on March 31, 1978.

Financing of Other Cottage and Small-Scale Industries

3.29 For the year 1978-79, credit limits of Rs. 6 crores were sanctioned to 8 SCBs on behalf of 31 CCBs and 33 Primary UCBs, as against Rs. 7 crores sanctioned during 1977-78.

Advances against the security of gold bullion, gold and silver ornaments by co-operative banks

3.30 In the context of gold auctions then undertaken by the RBI, the policy towards advances by co-operative banks against gold ornaments was further reviewed. The Registrars of Co-operative Societies were advised on July 22, 1978 to issue suitable instructions to the CCBs and Primary UCBs, to ensure that no advances were granted against gold bullion, and the outstanding advances, if any, against gold bullion should be recovered as early as possible, but not later than September 30, 1978. As regards advances against gold ornaments, the banks were asked to ensure that such advances were not utilised for speculative purposes.

STRENGTHENING OF CO-OPERATIVE STRUCTURE

Reorganisation of PACS

3.31 The need for having strong and viable institutions at the base level of the credit structure as a pre-requisite for expansion of co-operative credit has been well recognised. Following the streamlining of the procedures for amalgamation of societies and also as a result of the efforts made by the GOI and the RBI to persuade State Governments to speed up the reorganisation of PACS, considerable progress has been made in the reorganisation of societies on a viable basis in several States.

3.32 The total number of societies in the country is expected to decline from 1,24,000 at the end of 1976-77 to about 90,000 after the process of reorganisation is completed. The reorganisation of PACS on a viable basis is more or less complete in Andhra Pradesh, Assam, Haryana, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal. Efforts towards reorganisation are being made in other States. However, some States seem to be still having reservations in completing the programmes on the lines already agreed to.

Rehabilitation of CCBs/SCBs

3.33 Efforts to rehabilitate certain CCBs and SCBs continued during the year. Of the 180 CCBs under rehabilitation, 146 CCBs were brought under the Central Sector Plan Scheme. The GOI sanctioned Rs. 842 lakhs as its share to write off bad debts and released Rs. 775 lakhs. Though a large number of these banks have shown improvement in their financial position, they would continue to be under surveillance for some more time. Five SCBs in the States having the two-tier structure continued to be under rehabilitation. Based on their financial position, as on June 30, 1977, 54 Primary UCBs were brought under the rehabilitation programme.

Integration of Co-operative Credit Institutions

3.34 Three State Governments, viz., Punjab, Madhya Pradesh and Rajasthan have initiated, on their own, action to bring about integration of the two wings (short/medium-term and long-term) of the co-operative credit structure. The States of Punjab and Rajasthan purpose abolition of the district level institutions, viz., CCBs in short-term wing and the PLDBs in the long-term wing and envisage a two-tier structure with reorganised PACS at the primary level and the State Co-operative Development Bank (SCDB) at the apex level with branches of the SCDB at the district level. In the case of Punjab, the Agricultural Credit Board felt it necessary to call for additional particulars before considering the issue and the proposals for Rajasthan are still under discussion. In the case of Madhya Pradesh the scheme envisaged merely integration of the two wings at different levels of the three-tier structure. The Board has not generally favoured the proposal. It has opined that the State Government should proceed in the matter very cautiously. However, in case the State Government is very keen on implementing the integration proposal, it should ensure that the credit flow is not interrupted and it should agree to fulfil certain specified conditions involving financial and administrative commitments.

Agricultural Credit Intensive Development (ACID)

3.35 The Agricultural Credit Intensive Development Programme which was under implementation in 41 districts continued to show progress. During the year, field studies were completed in 9 more districts raising the number of districts where such studies were conducted to 32 out of 41 districts selected under the ACID Scheme. Further, credit and action programmes were formulated for seven districts raising the number of districts where the formulation of such programmes was completed to 25.

3.36 One of the major achievements of the ACID Scheme has been the bringing about of a functional co-ordination between various agencies concerned with the formulation and implementation of development schemes and the credit institutions operating in the district. The Scheme recorded good progress in some districts. In matters such as re-organisation of PACS, enrolment of new members and flow of credit for financing agriculture and allied activities. During the year April 1, 1977 to March 31, 1978, the work relating to re-organisation was completed in six more districts thus raising the total number of districts where the reorganisation was completed to 24. The coverage of PACS had increased especially with reference to small and marginal farmers. In 37 out of 41 selected districts, the total membership of PACS increased by about 7 lakhs. At the CCBs level, the restrictive loaning policies and procedures affecting the flow of credit were streamlined to ensure adequate and timely financing and better end-use of credit. The benefits of increased lendings had accrued more to the small and marginal farmers than to others.

3.37 Since the introduction of the ACID Scheme, there have been certain developments requiring a review of the Scheme. The lead banks have been advised to terminate their existing plans by December 1979 and formulate fresh District Credit Plans (DCPs) for their lead district for the period from January 1980 to December 1982 and Annual Action Plan by December each year. The DCP would be a comprehensive credit plan for the district and would indicate total credit outlays (sector-wise, block-wise, scheme-wise and institution-wise) for technically feasible and economically viable schemes for financing production and investments by the banks, Co-operative, among other financial institutions, are also participating agencies in the formulation and implementation of the plans. In the context of these developments it has been decided to effectively integrate the ACID Programme with DCP from 1980 onwards.

OTHER DEVELOPMENTS

Credit Authorisation Scheme

3.38 In accordance with the recommendations of the Study Group on Interest Rates Structure of Co-operatives some modifications were announced in respect of advances to primary societies. The provisions of the scheme requiring prior authorisation from the RBI in respect of the advances to manufacturing/processing societies and consumers' societies as mentioned below were continued during 1978-79 :

(i) all cases of granting advances for block capital requirements in the case of new sugar factories ;

(ii) financing of block capital requirements above Rs. 25 lakhs in the case of manufacturing/processing units ;

(iii) granting of working capital to co-operative marketing/processing societies and consumers' stores/societies—above Rs. 2 crores in case of SCBs and above Rs. 1 crore in case of CCBs.

Further, SCBs/CCBs were also allowed to sanction higher clean credit limits for working capital requirements to a co-operative marketing-cum-processing society without obtaining prior authorisation from the RBI. The revised limit is Rs. 10 lakhs or the owned funds of the concerned society, whichever is less, as against the earlier limit of Rs. 5 lakhs. During the year ended June 1979, authorisation was granted by the RBI for Rs. 11 crores for block capital requirements and Rs. 585 crores for working capital requirements. The number of proposals involved were 26 and 148, respectively.

3.39 Consequent upon the fall in prices of sugar after its decontrol from August 16, 1978 and increasing accumulation of stocks, the liquidity position of the co-operative sugar factories was affected and they were unable to maintain the stipulated margin in respect of pledge loans taken by them. The SCBs and CCBs were advised in January 1979 about the RBI's prior authorisation for sanction of working capital term loan to the co-operative sugar factories to meet the deficit in the margin. Authrisation aggregating Rs. 12 crores was granted for the said purpose to 3 SCBs and 11 CCBs in respect of 48 co-operative sugar factories.

Financing of Societies by Commercial Banks

3.40 As on December 31, 1978, the scheme of financing of PACS by commercial banks introduced in June 1970 was in operation in 12 States where 623 branches of 24 commercial banks had taken over 2,894 societies in 122 districts. The average number of societies per branch as such continued at around 5 as against the norm of ten societies for operational viability and efficiency. During 1977-78, commercial banks had financed 2,170 societies providing aggregate short-term agricultural loans of Rs. 22 crores. Besides, medium-term loans of Rs. 3 crores were also disbursed to 556 societies, as against Rs. 3 crores advanced to 646 societies in 1976-77. As on December 31, 1978, the average loan business per society reached the average viability norm of Rs. 2 lakhs envisaged for a society. The total (short and medium-term) loans outstanding as on December 31, 1978, were Rs. 47 crores of which Rs. 29 crores (62 per cent) were overdue. The recoveries of loans granted to PACS by commercial banks were 65 per cent in 1977-78 as against 44 per cent in 1976-77. Since the introduction of the scheme till December 1978, 405 thousand new members were admitted in the societies taken over by commercial banks. The borrowing membership which was 432 thousands as on December 31, 1977, increased to 549 thousands as on December 31, 1978, and formed 37 per cent of total membership.

3.41 In view of the slow progress of the scheme mentioned above, the RBI has constituted a Group for reviewing the scheme, identifying the factors inhibiting its progress and suggesting remedial measures.

Penal Rate Interest

3.42 Consequent upon the lowering refinance rate by 1 per cent on advances under Section 17(2)(bb) read with 17(4)(c) (from March 1, 1978), the RBI reviewed the penal rate of interest to be charged to defaulting SCBs in repayment of loan/loan instalments on due dates. Thus, from July 11, 1978, these banks are charged interest at the Bank Rate for the entire period of loan as against the earlier rate of 1 per cent above the normal lending rate for the period of default.

Interest on Advances against Deposits

3.43 In February 1979, the RBI advised all SCBs, CCBs and PCBs that whenever the interest payable to a depositor on premature withdrawal of a deposit is reduced, the interest charged on advances thereagainst should be correspondingly reduced to keep a differential of two per cent between the two rates.

Banking Rgulation and Inspection

3.44 As on March 31, 1979, the total number of licenced co-operative banks rose to 148 from 130 as on June 30, 1978. The rise of 18 banks was only under Primary UCBs (from 109 to 127), the number of SCBs and CCBs continuing at 7 and 14, respectively.

3.45 As on December 31, 1978, the number of offices of co-operative banks rose to 8,894 from 8,309 as on December 31, 1977. This consisted of 363 offices of SCBs, 6,659 of CCBs, 1,675 of Primary UCBs and 197 of Primary (salary earners' type) Co-operative Banks. During the year 1978-79, 98 licences were issued to SCBs and PCBs for opening of new offices, as against 131 licences issued in 1977-78.

3.46 As on June 30, 1979, there were 1,568 co-operative banks coming under the purview of BR Act, 1949 comprising 29 State, 347 central and 1,192 primary co-operative banks, as compared with the respective figures of 29, 353 and 1,187 co-operative banks, as on June 30, 1978.

3.47 In terms of notification dated June 6, 1978, the RBI exempted for a further period of two years from June 24, 1978 all the scheduled SCBs from the provisions of Sub-section (i) of Section 42 of the RBI Act, 1934 in so far as the said provision required the scheduled banks to maintain with RBI an average daily balance in excess of 3 per cent of their total demand and time liabilities.

3.48 During the year, the Bank continued to undertake inspections of co-operative banks and bring to their notice the important defects observed during the inspections. The number of banks inspected during the year were 413 PCBs, 136 CCBs, 11 SCBs and 8 other institutions.

3.49 A revised manual entitled "Manual on Advances by Co-operative Banks" covering guidelines for advances granted by CCBs and UCBs was issued in March 1978.

STUDY TEAMS

Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh

3.50 The report of the study team on agricultural credit institution for Jammu and Kashmir referred to in the last year's Report, was finalised during the year and that of Himachal Pradesh was nearing completion.

Study Group on Handloom Finance (appointed by GOI)

3.51 The Group submitted its report in June 1978. Some of the important recommendations of the Study Group are given below :

(i) The RBI may take into account export credit needs of apex weavers' societies while sanctioning credit limits for marketing and production activities.

(ii) Even if short-term credt limits for agricultural operations are denied on account of heavy overdues, such CCBs may be sanctioned limits for financing production and marketing activities of the weavers' societies.

(iii) The RBI may open a line of credit under Section 17(2)(bb) read with Section 17(4)(c) to handloom weavers' societies on behalf of co-operative spinning mills.

(iv) Subject to subsidy from Central/State Governments, the Bank may provide medium-term loans to weavers' and handloom weavers' societies for the acquisition of shares in co-operative spinning mills.

(v) The scale of finance per loom in case of weavers' societies may be reviewed and revised once in three years. Similarly, in the case of apex weavers' societies, the ratio of working capital to sales may be studied so as to revise the norms for financing of working capital needs. These recommendations were examined by the Bank and necessary action was initiated during the year.

Committee on Urban Co-operative Banks

3.52 The Committee submitted its report to the Bank in September 1978. The examination of the report by the Agricultural Credit Department has since been completed and suitable action has been taken in the matter.

Study Group on Interest Rates Structure of Co-operatives

3.53 The Group submitted its report in June 1978 and recommended, among others, (1) reduction in rates of interest charged by co-operatives on advances to small farmers, (2) increase of ½ per cent in the concessional rate of interest on the RBI's refinance for medium-term agricultural purposes so as to bring it on par with that on refinance for short-term agricultural loans, (3) review by the RBI of discipline governing refinance facilities for short-term agricultural loans such as seasonality discipline, loans to small farmers, etc., so as to ensure that these do not become restrictive and (4) introduction of unformity in lending rates charged to ultimate borrowers on agricultural loans by co-operatives/commercial banks and RRBs. These recommendnations in so far as they relate to co-operative banks, have been accepted by the RBI and have been communicated to State Governments and co-operative banks for implementation.

Committee on Credit for Farm and Rural Development

3.54 The Bank constituted a High-Level Committee in March 1979 to suggest improvements in the existing arrangements for institutional credit for agricultural and rural development. The Committee has been asked, among others, (i) to review the structure and operations of the ARDC in the light of the growing needs for term loans for agricultural and allied purposes, (ii) to examine the need for and the feasibility of integration of short-term and medium-term credit structures with long-term credit structures at national, state, district and village levels in the context of the intensification of rural development programmes, (iii) to assess the relative merits of three-tier and two-tier structures of co-operative financing institutions and suggest improvements, (iv) to study the consultancy services provided by the Agricultural Finance Corporation and suggest improvements and (v) to review the role of the RBI in the field of rural credit.

AGRICULTURAL REFINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION (ARDC)

3.55 As the apex development bank for agriculture, the ARDC is actively engaged in promoting investment in agriculture and allied activities in different States with emphasis on helping the weaker sections and reducing regional imbalances in resource development. The Corporation has stepped up the level of its operations notably since 1974 in the context of World Bank-assisted programmes for agricultural development. The number of schemes sanctioned by the ARDC since inception up to end-June 1979 totalled 8,655 with the Corporation's commitments aggregating Rs. 2,303 crores, of which Rs. 1,334 crores or 58 per cent were disbursed by way of refinance assistance.

3.56 The number of schemes sanctioned by the ARDC during the year (July 1978-June 1979) and its commitments thereof were 2505 and Rs. 573 crores, respectively, as against 1,836 and Rs. 330 crores during 1977-78 (July-June). The Corporation continued its emphasis on wider geographical spread and diversification of purposes of lending. As many as 1,470 schemes (59 per cent of total number) with commitments aggregating Rs. 226 crores (40 per cent of the aggregate commitment) were sanctioned for purposes other than minor irrigation, which used to predominate in lending in earlier years. During 1978-79, of the total disbursement of Rs. 285 crores, amounts availed of by LDBs, commercial banks and SCBs were Rs. 131 crores (46 per cent), Rs. 150 crores (53 per cent) and Rs. 4 crores (1 per cent), respectively. The corresponding proportions in the provious year (July-June) were 47.8 per cent, 51.3 per cent and 0.9 per cent, respectively.

3.57 The ARDC stepped up its efforts to reduce inter-regional and intra-regional disparties in agricultural development by trying to increase the flow of credit to the less developed/under-banked areas, particularly in the North-Eastern Region. In Jammu and ashmir, a project for apple processing and marketing has been sanctioned with the IDA assistance. In Rajasthan, the ARDC has sanctioned a scheme under 'Antyodaya' programme envisaging investment in animal husbandry and other schemes, which will benefit the poorest families in the villages. Study teams have been set up for Orissa and Rajasthan to review the progress of implementation of on-going schemes and to suggest measures for quick implementation of the schemes. A team of technical officers of the Corporation visited Manipur in November 1978 to guide the Government in the formulation of bankable schemes for land development, plantation crops, etc. Region-wise the Southern Region absorbed (28.2 per cent) of the ARDC refinance, followed by the Central Region (23.0 per cent), Northern Region (19.0 per cent), Eastern and North-Eastern Region (15.7 per cent) and Western Region (14.1 per cent); the corresponding proportions in the previous year were 27.5 per cent 25.5 per cent, 15.6 per cent, 17.1 per cent and 14.3 per cent, respectively.

3.58. The Corporation's efforts to benefit the maximum number of small farmers under its schemes continued during the year. Under the ARDC Credit Project I and II, implemented with assistance from the IDA, more than 50 per cent of the funds have been utilised for meeting the investment needs of small farmers. The Corporation continued to provide 90 per cent refinance facility for schemes sponsored under the aegis of SFDA, Drought Prone Areas Programme (DPAP) and for special schemes intended for the benefit of scheduled castes and scheduled tribes. The facility which was available upto March 31, 1979 has been extended indefinitely. At the end of June 1979, 534 schemes were sanctioned to SFDA involving an aggregate commitment of Rs. 90 crores. Of these, financing institutions availed themselves of refinance of Rs. 47 crores as at the end of June 1979.

3.59. During the year, the IDA sanctioned Punjab Irrigation Project and the Third ARDC Credit Project for $ 250 million in July 1979. Besides, the IDA mission appraised two projects—one for the development of cashew plantation in Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Orissa and the other for development of inland fisheries in Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal, Orissa and Madhya Pradesh. Thirty seven projects including the Third ARDC Credit Project involving financial assistance of Rs. 1,765 crores have so far been approved by the World Bank (4 projects) and IDA (33 projects). A credit of $ 1,166 million in the aggregate is to be routed through the ARDC under these projects.

3.60. In view of the successful involvement of the ARDC in the various agricultural development programmes finalised by the World Bank Group, other international agencies have also come forward to extend financial assistance to the ARDC. During the year, the Canadian International Development Association sanctioned a credit of 15 million Canadian dollars. A credit of £15 million has been sanctioned under the United Kingdom Local Costs Grant, 1979.

3.61. During the year, the ARDC liberalised the scale of refinance assistance to be made available to State Electricity Boards for the energisation of agricultural pumpsets. It agreed to refinance loans given for boring alone where it is technically feasible and where borings could be worked with pumpsets on hire. In view of the difficulties experienced by SLDBs in effecting cent per cent recoveries, the ARDC decided to allow SLDBs to float development debentures with effect from July 1, 1978 carrying a maturity of not more than 2 years in excess of the period of the corresponing loans given to the ultimate borrowers, subject to certain conditions. The common norms applied by the RBI and the ARDC for regulating the lending programmes of SLDBs were considerably liberalised in January 1979 to provide for larger eligibility for the PLDBs branches having overdues between 26 and 55 per cent of 'demand'.

3.62. In view of the considerable increase in the number of schemes sanctioned and contemplated expansion of its activities, the ARDC has delegated powers to its general managers and senior directors in head office and directors in charge of regional offices to sanction certain types of schemes involving refinance assistance varying between Rs. 10 lakhs and Rs. 40 lakhs.

3.63. As a sequel to the exemption granted to the ARDC from payment of corporate tax for a period of five years from the current year, and the decision of GOI to effect 0.5 per cent reduction in the rates of interest on its loan to ARDC, the Corporation reduced, from March 15, 1979, interest on its refinance from 7.5 per cent to 6.5 per cent per annum for minor irrigation and land development schemes and from 8 per cent to 7.5 per cent per annum for schemes for diversified purposes. The rates to be charged to the ultimate borrowers

will be 9.5 per cent and 10.5 per cent, respectively. Refinance rate on loans to small farmers for diversified activities was reduced to 6.5 per cent provided the financing banks lend to small farmers at 9.5 per cent as against the earlier rate of 11 per cent.

3.64. The facility of 90 per cent refinance to the SLDBs by way of subscription to their special development debentures for minor irrigation schemes, which was available upto June 30, 1979, has been extended indefinitely not only to SLDBs but also to commercial banks, SCBs and RRBs in respect of minor irrigation investments and the loans given by them to State Electricity Boards for energisation of agricultural pumpsets under ARDC schemes.

3.65. In view of the difficulties experienced by State Governments to charge the market fee of 1 per cent from inception, the Corporation has agreed to extend refinance facilities to the schemes for development of market yards with market fee at 1/2 per cent minimum provided an enabling provision is made in the relevant Act to raise the fee to 1 per cent in the subsequent two or three years.

CHAPTER 4

OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS

4.1 The activities of the RBI in the sphere of industrial finance and those of other financial institutions, viz., Industrial Development Bank of India (IDBI), State Financial Corporations (SFCs), Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) and Unit Trust of India (UTI) are reviewed in this Chapter. The review indicates that efforts to provide larger credit to the industrial sector, particularly to the small-scale sector, made further progress during the year.

RBI Assistance to Term Lending Institutions

4.2 The RBI continued to strengthen the term-lending institutions involved in industrial finance through provision of credit facilities and through the Credit Guarantee Scheme. During 1978-79 (July-June) the RBI sanctioned a loan of Rs. 200 crores to the IDBI out of the National Industrial Credit (Long-term Operations) Fund as against Rs. 180 crores sanctioned in the previous year. The outstanding amount of the IDBI's borrowings from the Fund stood at Rs. 871 crores, as at the end of June 1979. A short-term borrowing limit of Rs. 90 crores was also sanctioned to the IDBI during the year against the security of eligible bills rediscounted by it. The RBI renewed the borrowing limit of Rs. 3 crores sanctioned to the IFCI, for a further period of one year. In addition, the RBI sanctioned fresh limits aggregating Rs. 13 crores to 7 SFCs against the security of their ad hoc bonds during the period July 1978 to June 1979. The total borrowing limits in force, as at the end of June 1979 aggregated Rs. 17 crores in respect of 9 SFCs. Besides, 17 SFCs (i.e., all SFCs except Delhi Financial Corporation) were allowed to float market bonds for an aggregate amount of Rs. 46 crores (notified) during the year 1978-79 (April-March) as against Rs. 41 crores allowed in the previous year. In order to enlarge the flow of institutional lending to small industries by enabling them to share the risks involved with some other agency, the GOI formulated a Credit Guarantee Scheme in July 1960 for the guarantee of advances granted by banks and other credit institutions to small-scale industries. The RBI has been entrusted with the administration of the Scheme as the agent of the Central Government under Section 17(11A) of the RBI Act, 1934 and has been designated as the 'Guarantee Organisation' for the purpose.

Progress of Credit Guarantee Scheme

4.3 The number of institutions eligible for facilities under the Scheme stood at 748 at the end of March 1979, as against 706 at the end of March 1978. The number of institutions participating in the Scheme increased by 11 to 291 during the period. The amount of outstanding guarantees rose from Rs. 2,147 crores, at the end of March 1977, to Rs. 2.44, crores at the end of March 1978, and further to Rs. 2,874 crores at the end of March 1979, reflecting a steady flow of institutional credit to the small scale industrial units in line with Plan Priorities (Table 4.1).

An industry-wise analysis of the amount of guarantees outstanding at the end of June 1977 shows that the food manufacturing industry (except beverages) continued to account for (relatively) a large share (12.3 per cent) followed by textiles (11.1 per cent), metal products (10.6 per cent), chemical products (8.4 per cent), manufacture of machinery except electrical machinery (6.7 per cent), electrical machinery and equipments (6.5 per cent) and basic metals (5.2 per cent). The respective shares were more or less the same in the previous year. The number of defaulting units, which stood at 18,926 involving Rs. 117 crores, as at the end of March 1978, increased to 22,443 involving Rs. 150 crores at end-March 1979. During the period April 1978 to March 1979, the number of defaulting units increased by 3,517 and the amount involved went up by Rs. 33 crores. The average amount per defaulting unit rose from Rs. 61,800 to Rs. 66,800 and the percentage of the amount involved in defaults to total outstanding guarantees rose from 4.8 per cent to 5.2 per cent. The claims amounting to Rs. 173 lakhs were paid in respect of 1,347 units during the period April 1978 to March 1979, bringing the aggregate claims paid, since the inception of the Scheme in 1960, to Rs. 489 lakhs in respect of 3,955 units. Out of the aggregate amount paid as claims, a sum of Rs. 77 lakhs has been recovered and the net amount of claims paid till the end of March 1979 stood at Rs. 411 lakhs.

4.4 During the period April 1978 to March 1979, a sum of Rs. 250 lakhs was received as guarantee fees and transferred to the Central Government.

Scheduled commercial banks advanced to (a) small-scale industries (b) small road and water-transport operators and (c) for setting up of industrial estates :

(a) Small-scale Industries

4.5 During the period July-December 1978 the additional credit limits (including term loans and advances granted to craftsmen and other qualified, entrepreneurs),

TABLE 4.1—PROGRESS OF CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR SMALL-SCALE INDUSTRIES FROM JUNE 1976 TO MARCH 1979

(Amount in Rupees Crores)

As at the end of	Guarantees Outstanding	Advances under default[1]		Claims paid on account of invocation of guarantee		Guarantee Organisation's share of recoveries in respect of claims
		No. of Units	Amount	No. of Units	Amount	
	1	2	3	4	5	6
June 1976	1,949.8	12,439	60.0	1,201	1.7	0.3
June 1977	2,195.1	16,275	91.4	2,239	2.5	0.4
June 1978	2,526.4	19,887	125.8	2,711	3.3	0.6
March 1979	2,874.0	22,443	150.0	3,955	4.9	0.8

(*Source* : Industrial Finance Department, R.B.I.)

[1]Data are provisional.

tioned by scheduled commercial banks to small-scale industries amounted to Rs. 329 crores as against Rs. 240 crores during the corresponding period of the preceding year; as on the last Friday of December 1978 the total sanctioned credit limit amounted to Rs. 2,766 crores. The number of units assisted by the banks increased from 513 thousands to 558 thousands during this period. The average amount of credit limits sanctioned per unit, which was Rs. 103 thousands in June 1969, gradually came down to Rs. 48 thousands in December 1977, but marginally went up to Rs. 50 thousands in December 1978. The decline in this average over the period indicates a sustained effort towards financing of small units by banks The share of small-scale industries in the total outstanding bank credit (excluding food procurement advances) which went up steadily since the nationalisation of banks to 13.4 per cent in June 1974 and fell to 12.9 per cent in June 1975, again picked up the upward trend and was 14.9 per cent at the end of December 1978. Of the total outstanding bank credit to small-scale industries, as at the end of December 1978, the public sector banks (excluding RRBs) accounted for 88.5 per cent; the SBI Group provided 35.6 per cent and 14 nationalised banks 52.9 per cent. State-wise, Maharashtra accounted for 18.7 per cent (or Rs. 403 crores) of the total outstanding credit to small-scale industries, as at the end of December 1978. The largest number of such units financed was, however, in Tamil Nadu (88.076 or 15.8 per cent). During the half year ended December 1978, the term loans (including instalment credits) sanctioned by scheduled commercial banks to small-scale industries recorded a rise of Rs. 65 crores to Rs. 425 crores; the number of units financed increased from 101 thousands to 108 thousands. The amount of loans outstanding at Rs. 360 crores also recorded an increase of 51 crores durin July—December 1978. The outstanding term loans constituted 16.7 per cent of the total outstanding bank credit to small-scale industries at end-December 1978.

4.6 Out of the total credit limit of Rs. 2,766 crores sanctioned by the scheduled commercial banks to small-scale industry sector, Rs. 116 crores or 4.2 per cent went to crafts-men and other qualified entrepreneurs spread over 95 thousand units. The balance outstanding in these accounts at Rs. 95 crores, as at the end of December 1978, showed a net rise of Rs. 14 crores over the first half-year of 1978 as against a rise of Rs. 12 crores in the corresponding period of the previous year. The share of the public sector banks excluding RRBs in the total outstanding credit to these categories of borrowers increased to 99.0 per cent in December 1978, with the share of the SBI Group and the nationalised banks being 35.3 per cent and 63.7 per cent, respectively. The average amount of limits sanctioned per unit in this group went up marginally from Rs. 11,313 in June 1978 to Rs. 12,246 in December 1978.

(b) Small Road and Water Transport Operators

4.7 Small road and water transport operators numbering 235 thousands had a total credit limit of Rs. 512 crores from the scheduled commercial banks as at the end of December 1978, which was higher by Rs. 40 crores over June 1978 level. The amount outstanding also went up during the period by Rs. 56 crores and stood at Rs. 415 crores. The number of units financed in this category rose by 26 thousands to 235 thousands during the period July—December 1978.

(c) Industrial Estates

4.8 As at the end-December 1978, 23 scheduled commercial banks including 15 public sector banks sanctioned credit limits of Rs. 30 crores covering 261 units for the setting up of industrial estates. The amount outstanding in the relative accounts was Rs. 27 crores as against Rs. 23 crores in June 1978.

Industrial Development Bank of India

IDBI's Operations

4.9 The total assistance sanctioned (effective) excluding guarantees by the Industrial Development Bank of India (IDBI) during the year 1978-79 (July-June) at Rs. 1061 crores (covering 30,555 applications) was higher by 49.4 per cent as compared with Rs. 710 crores (to 14,212 applicants) during the previous year. The total disbursements during the same period at Rs. 680 crores were 43 5 per cent higher than the amount of Rs. 474 crores disbursed during the previous year (Table 4.2).

4.10 Total effective sanctions, since inception of the IDBI upto the end of June 1979, aggregated Rs. 4131 crores in respect of 82,292 applications. The disbursements against this amounted to Rs. 2777 crores.

Project Direct Assistance Scheme

4.11 During the year 1978-79, IDBI sanctioned project direct assistance of Rs. 285 crores in respect of 134 projects; this consisted of Rs. 256 crores by way of loans to 116 projects and Rs. 27 crores by way of underwriting of and direct subscriptions to the share capital of 60 companies. Disbursements during the period under review, at Rs. 220 crores were substantially higher as compared with Rs. 169 crores disbursed during 1977-78. Purpose-wise, 88 per cent of the assistance sanctioned was for setting up of fresh capacities by way of new projects and diversification and expansion of existing units (Table 4.3). Sector-wise, public, joint and co-operative sectors accounted for 40 per cent of the assistance and the balance 60 per cent going to private sector. Industrywise distribution shows that 69 per cent of assistanee was in respect of projects belonging to basic indutries group. Under project direct assistance scheme, the amount sanctioned to units in the specified backward areas was Rs. 134 crores, the concessional quantum being Rs. 113 crores.

Other Schemes of Assistance

4.12 Apart from project direct assistance, various other schemes of assistance designed to meet special requirements of different sectors, continued to be in operation.

(a) Soft Loan Assistance

4.13 Sanctions by the IDBI under the Soft Loan Scheme at Rs. 112 crores to 98 applicants were higher by 143.5 per cent during 1978-79 as compared to Rs. 46 crores to 55 applicants during 1977-78. The total assistance sanctioned since the beginning of the Soft Loan Scheme upto the end of June 1979 amounted to Rs. 190 crores in respect of 189 units. The disbursements of the assistance under the Scheme have shown a sharp increase of about 240.0 per cent during the period under review, amount disbursed having increased to Rs. 34 crores in 1978-79 from Rs. 10 crores in 1977-78. The cumulative disbursements under the Scheme amounted to Rs. 44 crores as on June 30, 1979.

(b) Technical Development Fund (TDF) Scheme

4.14 Under Technical Development Fund (TDF) Scheme, the IDBI sanctioned direct rupee loans of Rs. 6 crores to 46 units during 1978-79 as against Rs. 4 crores sanctioned to 29 units during the previous year. Total sanctions under the Scheme upto end of June 1979 amounted to Rs. 12 crores to 93 units. As against the increase of 50.0 per cent in sanctions, the disbursements under the TDF Schemes showed a smaller increase of 33.3 per cent rising from Rs. 3 crores to Rs. 4 crores.

(c) Refinance of Industrial Loans

4.15 As a result of introduction of Automatic Reference Scheme (ARS) with effect from July 1, 1978, and other liberalisations effected under the Scheme during 1978-79, refinance sanctions have picked up substantially. During the period under review sanctions amounted to Rs. 417 crores covering 29,233 applications as against Rs 224 crores covering 13,031 applications during the corresponding period of the preceding year, recording an increase of 86.2 per cent. Disbursements under the Scheme during the period under review amounted to Rs. 2.56 crores which were 75.3 per cent higher than the amount of Rs. 146 crores disbursed during the corresponding period of 1977-78. Sanctions under ARS during the year amounted to Rs. 210 crores in respect of 23,796 applications against which utilisation of assistance amounted to Rs. 79 crores. Refinance assistance of Rs. 293 crores covering 28,243 applications was sanctioned during 1978-79 to small-scale sector including small road transport operators. Refinance assistance at concessional rates to units in the specified backward districts amounted to Rs. 160 crores.

TABLE 4.2—ASSISTANCE SANCTIONED BY THE IDBI AND UTILISED BY THE ASSISTED CONCERNS DURING 1977-78 AND 1978-79 (JULY-JUNE) AND SINCE INCEPTION

(Rupees in Crores)

Type of Assistance	Sanctions (Effective)						Disbursals		
	1977-78 (July-June)		1978-79 (July- June)		Cumulative sanction since inception up to end-June 1979		1977-78 (July-June)	1978-79 (July-June)	Cumulative disbursements since inception up to end June 1979
	No. of applications	Amount	No. of applications	Amount	No. of applications	Amount	Amount	Amount	
1. Direct Industrial Assistance .	225	271.9	320	402.0	1413	1420.6	181.4	257.9	836.6
(a) Direct loans to industrial concerns (other than for exports)	189	251.8	260	374.6	987	1274.5	169.9	251.6	770.5
(i) Normal . . .	105	202.3	176	255.9	705	1072.1	157.6	214.0	719.7
(ii) Soft loan assistance .	55	46.0	98	112.3	189	190.0	9.5	33.7	44.2
(iii) Technical Development Fund . . .	29	3.5	46	6.4	93	12.4	2.8	3.9	6.6
(b) Underwriting of and direct subscriptions to shares and debentures of industrial concerns . .	36	20.1	60	27.4	426	146.1	11.5	6.3	66.1
2. Refinance of industrial loans .	13,031	224.2	29,233	417.3	76,925	1318.6	145.5	255.5	892.1
3. Rediscounting of Bills . .	920	133.4	951	139.3	3672	920.5	99.6	104.1	721.8
4. Subscriptions to shares and bonds of financial institutions .	18	32.7	20	39.0	31	154.4	28.4	41.3	151.4
Total Project Assistance (1 to 4)	**14,194**	**662.2**	**30,524**	**997.6**	**82,041**	**3814.1**	**454.9**	**658.8**	**2601.9**
5. Export Finance . . .	18	47.3	31	63.6	251	316.6	19.3	21.2	175.1
(a) Direct loans for exports .	8	18.1	16	12.5	104	132.0	11.0	12.4	95.4
(b) Refinance of export credit	7	6.6	10	8.9	123	67.9	4.0	4.0	54.2
(c) Overseas buyer's credit .	1	3.1	1	2.9	9	25.1	3.6	2.0	11.1
(d) Foreign lines of credit .	2	19.5	3	36.7	14	89.0	0.7	2.8	14.4
(e) Overseas investment finance	..	..	1	2.6	1	2.6	..	..	..
Total of 1 to 5	**14,212**	**709.5**	**30,555**	**1061.2**	**82,292**	**4130.7**	**474.2**	**680.0**	**2769.9**
6. Guarantees for loans and deferred payments . . .	..	..	..	..	15	26.7	..	..	19.6
7. Export guarantees . . .	42	50.0	107	64.9	174	161.5	51.5	60.5@	141.8@

@ Guarantee executed

Notes : 1. The number of applications in respect of Rediscounting of Bills (item 3) relates to the number of purchaser/user and in the case of subscriptions to shares and bonds of financial institutions (items 4) to the number of financial institutions.

2. In case of Rediscounting of Bills, amount sanctioned represents face value of bills rediscounted and amount utilised indicates the net disbursals after deduction of rediscount charges from the face value.

(*Sourse* : Industrial Development Bank of India.)

TABLE 4.3—PURPOSE-WISE CLASSIFICATION OF IDBI's ASSISTANCE SANCTIONED DURING 1978-79 (JULY-JUNE)

(Rupees in Crores)

Schemes	Purpose									
	New		Expansion/Diversification		Modernisation/ Rehabilitation		Supplementary Assistance*		Total	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Project direct assistance .	77 (50)	185.5 (136.9)	24 (34)	64.9 (58.9)	9 (8)	16.4 (10.7)	24 (20)	16.5 (15.9)	134 (112)	283.3 (222.4)
2. Rediscounting of bills . .	38 (52)	0.7 (2.5)	..	..	916 (876)	138.6 (130.9)	..	..	951 (920)	139.3 (133.4)
Total	**115** (102)	**186.2** (139.4)	**24** (34)	**64.9** (58.9)	**925** (884)	**155.0** (141.6)	**24** (20)	**16.5** (15.9)	**1085** (1032)	**422.6** (355.8)

*That is, assistance for (i) meeting overruns in projects—costs arising from delays in implementation, rise in cost of machinery and building materials, shortfall in estimated cash resources, etc. (ii) relieving strain on cash resources of companies which had earlier utilised working capital funds for acquisition of fixed assets, (iii) financial re-organisation, etc.

Note : 1. Number in respect of item 1 indicate the number of projects and in respect of item 2 number of purchaser-user.

2. Figures in brackets relate to corresponding period of the previous year.

3. Break-up in respect of item 2 may not add up to total as some of the existing units have also utilised assistance.

(*Source* : Industrial Development Bank of India.)

(d) Bills Rediscounting Scheme

4.16 Under the Bills Rediscounting Scheme, sanctions during 1978-79 (July-June) amounted to Rs. 139 crores in respect of 951 purchaser-users showing a marginal increase in amount over Rs. 133 crores sanctioned to 920 purchaser-users during 1977-78. Disbursements were also marginally higher at Rs. 104 crores than Rs. 100 crores disbursed during the previous year.

(e) Seed Capital Scheme

4.17 At present the Seed Capital Scheme is being administered through 24 SIDCs/SIICs which have been notified by the Central Government as 'financial institutions' and they have been extended refinance facility from the IDBI. Since inception of the Scheme upto the end of June 1979, 90 applications for Seed Capital assistance of Rs. 5 crores were received by the IDBI. Of these, 63 proposals for a sum of Rs. 2 crores were sanctioned and the total disbursements amounted to Rs. 1 crore.

(f) Export Finance Scheme

4.18 Total assistance sanctioned under the Export Finance Schemes (excluding guarantees) increased by 36.2 per cent from Rs. 47 crores to 18 applicants in 1977-78 (July-June) to Rs. 64 crores to 31 applicants during 1978-79. Under the foreign lines of credit and the refinance of export credit schemes, the sanctions showed increases of 85.0 per cent (from Rs. 20 crores to Rs. 37 crores) and 28.6 per cent (from Rs. 7 crores to Rs. 9 crores), respectively, while that under the scheme of direct loans for exports declined from Rs. 18 crores to Rs. 13 crores during the period. The total disbursements under all the schemes of export finance amounted to Rs. 21 crores; 10.5 per cent higher than Rs. 19 crores disbursed during last year.

(g) Assistance to Backward Areas

4.19 During the year under review, the assistance sanctioned by the IDBI to the projects located in the specified backward districts/areas aggregated Rs. 377 crores (Table 4.4). Though the amount sanctioned showed an increase of Rs. 79 crores, the share of backward areas in the total assistance sanctioned by the IDBI came down from 47.5 per cent in 1977-78 to 39.4 per cent during 1978-79. The disbursements at Rs. 314 crores were higher by Rs. 93 crores during the year, but in terms of percentage to the total disbursements, the share of backward area is marginally lower at 50.6 per cent as compared to 51.6 per cent during the preceding year. The cumulative sanctions and disbursements to these units aggregated Rs. 1491 crores and Rs. 980 crores forming 40.7 per cent and 39.9 per cent, respectively, of the total sanctions and disbursements.

(h) Subscriptions to Shares and Bonds

4.20 During the year, IDBI subscribed Rs. 660 lakhs (including special capital of Rs. 950 thousands) to the share capital of 18 State Financial Corporations. The IDBI also subscribed Rs. 15 crores each to the bonds issues of the ICICI and the IFCI as support for their participation under the Soft Loan Scheme. A sum of Rs. 350 lakhs was also disbursed to the ICICI representing balance instalment of the rupee counterpart funds against the U. K. line of credit. Application money of Rs. 120 lakhs was subscribed to IFCI's rights issue of shares for Rs. 5 crores. The total subscriptions to shares and bonds of other financial institutions as at the end of June 1979 amounted to Rs. 151 crores.

(i) Line of Credit for Imports

4.21 The IDBI has so far obtained four lines of credit from IDA/World Bank. Of these, two lines of credit of US $25 million and US $40 million, respectively, were for on-lending to SFCs and the third line of credit of US $28 million was for assisting specific private sector fertiliser projects for their schemes of pollution control and debottlenecking of the fertiliser plants. The fourth line of credit of US $25 million from the World Bank was for assisting medium sized projects in the State, public and joint sectors. Total sanctions and disbursals under these four lines of credit by the World Bank upto the end of June 1979 amounted to Rs. 88 crores and Rs. 45 crores, respectively. Besides the World Bank group has also agreed to route a portion (US $2.2 million) of their IDA Credit Line (US $14 million) to the Government of India in respect of J & K Horticulture project through the IDBI. This credit became effective from January 26, 1979.

(j) Developmental Activities

4.22 During 1978-79, three more Technical Consultancy Organisations (TCOs), one each in Madhya Pradesh, Gujarat and West Bengal were set up under the leadership of IFCI, ICICI and IDBI, respectively. With these three

TABLE 4.4—ASSISTANCE SANCTIONED (EFFECTIVE) AND DISBURSED BY THE IDBI TO UNITS IN THE SPECIFIED BACKWARD DISTRICTS@

(Rupees in Crores)

Year	Assistance sanctioned			Assistance disbursed		
	Total	Backward districts	% of Col. 3 to 2	Total	Backward districts	% of Col. 6 to 5
1	2	3	4	5	6	7
Since inception up to the end of June 1970 . .	276.3	44.7 (—)	16.2	250.2	36.1 (—)	14.4
1970-71	84.9	21.0 (0.3)	24.7	54.2	9.4 (0.1)	17.3
1971-72	135.0	44.9 (17.5)	33.3	73.7	15.1 (1.5)	20.5
1972-73	121.6	40.8 (13.8)	33.6	97.6	23.5 (8.6)	24.1
1973-74	164.9	58.6 (42.3)	35.5	143.0	49.4 (18.3)	34.5
1974-75	268.7	94.7 (52.5)	35.2	186.8	68.8 (25.7)	36.8
1975-76	386.9	172.3 (115.9)	44.5	249.6	98.7 (53.2)	39.5
1976-77	633.2	337.7 (187.9)	53.3	351.5	145.4 (98.8)	41.1
1977-78	629.4	298.4 (149.6)	47.5	426.4	220.2 (127.4)	51.6
1978-79	958.7	377.4 (272.8)	39.4	617.5	313.5 (176.0)	50.6
Total	**3659.6**	**1490.5** (852.6)	**40.7**	**2450.5**	**980.1** (509.6)	**39.9**

@ Comprise of direct loans, soft loans, TDF, underwriting/direct subscription, refinance and bills rediscounting.

Note: Figures in brackets in cols. 3 and 6 refer to the amount disbursed on concessional terms.

(*Source :* Industrial Development Bank of India).

TABLE 4.5—OPERATIONS OF STATE FINANCIAL CORPORATIONS

(Rupees in Crores)

	1977-78 (April-March)	1978-79 (April-March)
Loans Sanctioned (effective)	166.1	195.3
Loans Disbursed	107.4	135.2
Loans Outstanding (as at the end of March)	539.3	643.0

(*Source :* Industrial Development Bank of India).

are 12 TCOs functioning in the country, 8 sponsored by IDBI, 3 by IFCI and one by ICICI. Out of the Technical Assistance Fund (TAF) financial assistance was provided to training programmes of officials of state level corporations and TCOs and Entrepreneurial Development Programmes (EDPs) organised by TCOs; viz., (i) 9 EDPs organised by KITCO in Kerla (3 of which were exclusively for Harijans), (ii) 4 EDPs organised by UPICO in Uttar Pradesh and (iii) one EDP conducted by NEITCO in Gauhati.

OPERATIONS OF STATE FINANCIAL CORPORATIONS

4.23 The operations of State Financial Corporations (SFCs) showed marked improvement during 1978-79 (April-March). The total financial assistance sanctioned and dispursed by the 18 SFCs (including the TUC) aggrgated Rs. 195 crores and Rs. 135 crores as against Rs. 166 crores and Rs. 107 crores, respectively during the preceding year (Table 4.5). The increases in sanctions and disbursement during 1978-79 were of the order of 17.5 per cent and 26.2 per cent, respectively, which are much higher than the rise of 1.7 per cent and 2.0 per cent respectively recorded during 1977-78. Total loans outstanding as at the end of March 1979 stood at Rs. 643 crores as compared with Rs. 539 crores at the end of March 1978.

4.24 Assistance to small scale enterprises including road transport operators continued to account for a major portion

in the total assistance sanctioned and disbursed by the SFCs. The small scale sector accounted for 98.6 per cent of the total number of units assisted, 78.2 per cent of the total assistance sanctioned and 71.0 per cent of the total assistance disbursed during 1978-79.

4.25 The SFCs' assistance to units located in the specified backward areas also showed increase during the year under review. The concessional assistance in case of 5,401 units located in such areas amounted to Rs. 114 crores or 58.5 per cent of the total assistance sanctioned during 1978-79 as against Rs. 87 crores (52.4 per cent) in respect of 4,057 units during the preceding year.

4.26 Seventeen SFCs (excluding Haryana) raised special capital aggregating Rs. 580 lakhs as at the end of March 1979. Under the special capital scheme, at the end of March 1979, sanctions amounted to Rs. 140 lakhs in respect of 419 units and disbursements to Rs. 40 lakhs. As at the end of March 1979, 3,556 applications for total assistance of Rs. 98 crores were pending with the SFCs.

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

4.27 The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation provides protection to depositors, particularly the small depositors, from the risk of loss of their deposits in the event of an insured bank's inability to meet its liabilities and also provides cover to eligible credit institutions in respect of credit facilities extended by them to certain specified categories of borrowers belonging to the weaker sections of the community. With the merger of the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (CGCI) in the Deposit Insurance Corporation, (DIC) with effect from July 15, 1978 and the latter having been renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC), the deposit insurance and credit guarantee functions are performed by the new Corporation. All the liabilities and assets of the CGCI as also its rights and obligations now vest in the DICGC. To enable the DICGC to meet the establishment and other expenses of the combined units, its capital was increased from Rs. 2 crores to Rs. 10 crores. The entire amount of capital has been subscribed to by the RBI, the sole shareholder in the Corporation.

Deposit Insurance Function

4.28 The number of insured commercial banks remained unchanged at 78, while the total number of insured RRBs. increased to 56 as on 30th June 1979. As regards co-operative banks, the total number of insured banks increased to 978, as at the end of June 1979, with the registration of 27 and 71 eligible co-operative banks from the States of Orissa and Uttar Pradesh, respectively. Till the end of June 1979 the scheme covered co-operative banks in 11 States and three Union Territories, viz., Andhra Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal, Delhi, Goa, Damon and Diu and Pondicherry. The extension of the scheme to the remaining States awaits the passing of necessary enabling legislation by the concerned State Governments. The rate of insurance premium at 4 paise per hundred rupees per annum remained unchanged. With a view to reducing the workload on banks in compiling the necessary statements of insured deposits, the periodicity of payment of the insurance premium has been changed from quarterly to half yearly intervals since the beginning of 1979. The total assessable deposits of the banks at Rs. 21,659 crores, as at the end of 1978 showed an increase of Rs. 1,767 crores during the year. The percentage of fully protected accounts to the total number of deposit accounts slightly increased from 98.2 to 98.3 while the percentage of insured deposits to total assessable deposits decreased from 71.1 to 71.0.

4.29 The total amount of claims paid or provided for by the Corporation since the inception (of the DIC) stood at Rs. 179 lakhs. These claims relate to 14 commercial banks and 6 co-operative banks. The Corporation has also received repayments to the extent of Rs. 73 lakhs in respect of commercial banks while there have been no repayments in regard to co-operative banks.

Credit Guarantee Function

4.30 The DICGC, after the taking over of all the rights and obligations of the CGCI, is continuing the three credit guarantee schemes formulated and operated by the latter, viz., the Small Loan Guarantee Scheme, the Financial Corporation Guarantee Scheme and the Service Co-operative Societies Guarantee Scheme. During the year under review, certain amendments were effected in these schemes by the DICGC so as to enlarge the benefits to small borrowers. With a view to facilitating liberal grant of rehabilitation finance to flood victims, the claims liability of the Corporation for overdue crop loans to borrowers affected by natural calamities, converted into term loans, has been raised from Rs. 5,000 to Rs. 7,500 so as to cover dues in respect of three agricultural seasons, commencing from 1977 kharif, instead of two seasons as hitherto. This is in addition to the liability up to a maximum of Rs. 2,500 for the fresh crop loan that may be granted to the borrower. Further, in pursuance of the recommendations of the Working Group on Differential Rates of Interest Scheme set up by the GOI, the guarantee cover of the Corporation in regard to advances granted under that scheme, on or after January 1, 1979, has been enhanced from 75 per cent to 90 per cent of the amount in default. Further, with a view to giving some temporary relief to the RRBs in view of the special role they are required to play in extending credit to priority sectors in rural areas, the rate of guarantee fee in respect of their guaranteed advances was lowered from 1/2 per cent to 1/4 per cent per annum for a period of three years from July 1, 1979 or from the date of joining the Scheme by the RRB concerned, whichever is later. With effect from April 1979, the overall monetary ceilings under the Small Loan Guarantee Scheme on the Corporation's liability per borrower are applicable in relation to credit facilities granted to him by each bank instead of by the entire banking system. The total advances covered by the three schemes at Rs. 1,716 crores, as at the end of December 1978 recorded a rise of 13.1 per cent over the previous year. Credit extended to small-scale industries is presently covered by a separate guarantee scheme formulated by the Central Government and administered by the RBI. A proposal for the Corporation to undertake credit guarantee functions in respect of this sector also with a view to integrating all credit guarantee schemes under one organisation is under consideration.

4.31 Seventy five commercial banks and 47 (out of 49) RRBs are participating in the Small Loans Guarantee Scheme, which alone accounts for 99.5 per cent of the total advances guaranteed by the Corporation. The number of institutions participating in the Financial Corporation Guarantee Scheme remained unchanged at 18. As regards the Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, participation in which is open to all all scheduled commercial banks, RRBs and to co-operative banks (other than primary co-operative banks) which are eligible for deposit insurance cover, 85 commercial banks (including 24 RRBs) and 30 co-operative banks have joined the Scheme.

4.32 Invocation of guarantee by the participating credit institutions, which commenced in 1973, has been rising rapidly since 1975. During 1978, the trend in the inflow of claims was very much pronounced. Claims numbering 29,925 for Rs. 876 lakhs were received during 1978 as against 21,638 claims for Rs. 669 lakhs received in all the previous years. During January-April 1979, 12,314 claims for Rs. 386 lakhs were received. Of these, 5,514 claims have already been settled. The Corporation has taken several measurer to meet the increasingly large number of claims. The scrutiny procedure and content have been considerably simplified, a simpler claim format has been introduced since November 1978 and an easier settlement procedure and a claim format are being introduced for claims for an amount of Rs. 1,000 or less. Of the total number of 51,563 claims received, 27,033 claims for Rs. 664 lakhs have been disposed of as at the end of December 1978.

4.33 With the pronounced increase in the claims paid, the Corporation is devoting particular attention to verification of claim paid accounts and recovery of the amounts due from the borrowers concerned. The Corporation realised a sum of Rs. 3,284 thousands as its share of recoveries during 1978, as against an aggregate amount of Rs. 1,173 thousands realised during all the previous years.

UNIT TRUST OF INDIA

4.34 The object of the UTI is to extend facilities for an equity type of investment ((which combines the advantages of minimum risk and a reasonable return) to the large and growing number of small investors in the middle income groups of the community. hile providing these facilities, the UTI helps, at the same time, in the mobilisation of resources and their channelling into investments, thereby increasing the overall productivity of capital and facilitating the growth of the economy. To mobilise savings, the UTI sells 'Units' to the public.

4.35 During 1978-79 (July-June), sales of units under the three schemes of UTI aggregated Rs. 102 crores and was higher by 38.6 per cent on top of a record increase of 112 per cent in the preceding year. Repurchases of units by the Trust around Rs. 10 crores were lower compared to repurchases of Rs. 11 crores during the previous year. Thus, the net sales under all the schemes increased by Rs. 92 crores during the year as against Rs. 62 crores last year (Table 4.6).

4.36 As in the last year, the major thrust in record sales of units was provided by the operation, during the major part of the year, of the tax exemption of capital gains on re-investments of sale proceeds in units. The sales during the month of February were substantially boosted on fears of removal of this exemption. Among other factors, intensive and systematic sales promotion and publicity also played a significant role in increasing the sales of units. With the withdrawal of tax exemption on capital gains from March 1, 1979, the competitive attraction of units over the other media of savings has been affected. The dividend

TABLE 4.6—SCHEME-WISE SALES REPURCHASES AND OUTSTANDING UNITS OF UNIT TRUST OF INDIA

(Rupees in Crores)

Schemes	Sales		Repurchases		Outstanding as on June 30,
	1977-78	1978-79	1977-78	1978-79	1979
Unit Scheme 1964	70.86	96.08	10.86	9.13	330.31
Unit Scheme 1971	2.41	5.45	0.05	0.11	10.43
(Unit Linked Insurance Plan)					
Unit Scheme 1976	@	@	0.32	0.22	6.73
Total	**73.27**	**101.53**	**11.23**	**9.46**	**347.47**

@Sales suspended.

Note : The data for 1978-79 are provisional.

(*Source* : Unit Trust of India.)

for the year 1978-79 under all the three schemes, viz. Unit Scheme 1964, Unit Scheme 1971 and Unit Scheme 1976, was maintained at 9 per cent, 8 per cent and 3 per cent respectively.

4.37 As on June 30, 1979, units sold and outstanding with the public amounted to Rs. 347 crores, of which about Rs. 330 crores were under Unit Scheme 1964 (unit holding accounts being about 9 lakhs). Sales of units under Unit Scheme 1976 (Capital Units) continued to remain suspended.

Investments

4.38 As on May 31, 1979, total investible funds of the Trust amounted to Rs. 402 crores. Of this, equity shares accounted for Rs. 120 crores or 29.9 per cent, debentures for Rs. 83 crores or 20.6 per cent and preference shares for Rs. 17 crores or 4.1 per cent. The remaining amount (i.e. Rs. 182 crores) was invested mainly in call deposits with banks, advance deposits against investment commitments and

[No. F. 10/2/79-BO-I]

[No. F. 10/2/79-BO-I]

J. C. ROY, Director

(आर्थिक कार्य विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1978

बैंकिंग प्रभाग

का०आ० 1598. भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3(ii) में प्रकाशनार्थ, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की दिनांक 29 सितम्बर 1978 की अधिसूचना संख्या 8-9/78-ए० सी० में शब्द "रोड" से पहले "समा जो राव" शब्द के स्थान पर "सया जी राव" शब्द प्रतिस्थापित समझा जाये।

[संख्या 8-9/78-ए० सी०]

एम० पी० वर्मा, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 18th Nov., 1978

(ERRATA)

BANKING DIVISION

S.O. 1598.—In the notification of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) No. F.8-9/78-AC, dated the 29th September 1978 to be published in Part II-Section 3(ii) of the Gazette of India, for the words "of", the word "to" may be substituted, before the words "31st March, 1979".

[No. 8-9/78 AC]

M.P. VARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 मई, 1980

का०आ० 1599. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री जनार्दन सिंह को मगध ग्रामीण बैंक, गया का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 8 मई, 1980 से प्रारम्भ होकर 7 मई, 1983 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री जनार्दन सिंह, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-1/79 आर० आर० बी०-खंड-II)]

इन्द्रानी सेन, अवर सचिव

New Delhi, the 15th May, 1980

S.O. 1599.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Janardhan Singh as the Chairman of the Magadh Gramin Bank, Gaya and specifies the period commencing on the 8th May, 1980 and ending with the 7th May, 1983 as the period for which the said Shri Janardhan Singh shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-1/79-RRB-Vol. II]

INDRANI SEN, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 मई, 1980

का० आ० 1600.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची में फार्म 'क' के साथ संलग्न टिप्पणी (च) के उपबंध, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया पर 31 दिसम्बर, 1979 की स्थिति के उसके तुलनपत्र के संबंध में लागू नहीं होंगे जिसमें कि उक्त फार्म की सम्पत्ति एवं परिसम्पत्ति पक्ष की मद संख्या 4 के किसी उपशीर्ष (2), (3), (4) तथा (5) के सामने अन्दर के कालम में दिखाये गये मूल्यों के उक्त उपशीर्ष के अंतर्गत किये गये निवेशों के बाजार मूल्यों से अधिक हो जाते हैं पर इस उपशीर्ष के अंतर्गत किये गये निवेशों के बाजार मूल्यों को अलग से कोष्ठकों में दिखलाया जाता है।

[संख्या-15(8)/80-बी० ओ०-3]

New Delhi, the 29th May, 1980

S.O. 1600.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Note (f) appended to the Form 'A' in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the United Bank of India in respect of its balance sheet as on the 31st December 1979, which when the value shown in the inner column against any of the sub-heads (ii), (iii), (iv) and (v) of the item 4 of the Poperty and Assets side of the said Form exceeds the market value of the investments under that sub-head, shows separately within brackets the market value of the investments under that sub-head.

[No. 15(8)/80-B.O. III]

नई दिल्ली, 30 मई, 1980

का० आ० 1601.—गोवा, दमन और दीव (बैंक पुनर्निर्माण), विनियम, 1962 की धारा 4(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 29-7-1978 की अधिसूचना संख्या 22(6)/बी०ओ०-3/78 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि बैंको नेशनल अल्ट्रामेरिनो एण्ड कैक्सा इकोनोमिका डी गोवा के वर्तमान अभिरक्षक (कस्टोडियन) श्री वी० एन० नादकर्णी जब कभी छुट्टी पर या शहर से बाहर जायेंगे तो श्री एलेक्सो मारसेलिनो डी मेलो, प्रबंधक, कार्मिक बैंकिंग प्रभाग, भारतीय स्टेट बैंक, पणजी (गोवा), श्री वी० एन० नादकर्णी की अनुपस्थिति में, अभिरक्षक (कस्टोडियन) के कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे।

[संख्या 22(2)/80-बी० ओ०-3]

New Delhi, the 30th May, 1980

S.O. 1601.—In exercise of the powers conferred under Regulation 4(1) of the Goa, Daman and Diu (Banks Reconstruction) Regulation 1962, and in supersession of Notification No. 22(6)-B.O. III/78 dated 29-7-1978, the Central Government hereby directs that whenever Shri V. N. Nadkarni, the present Custodian of Banco National Ultramarino and Caixa Economica De Goa, proceeds on leave or goes out of station, Shri Aleixo Marcelino de Melo, the Manager, Personal Banking Division, State Bank of India, Panaji (Goa) shall discharge the duties of the Custodian in the absence of Shri V. N. Nadkarni.

[No. 22(2)/80-B.O. III]

का०आ० 1602. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10ख की उपधारा (1) तथा (2) के उपबंध, रत्नाकर बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर पर, 7 मई, 1980 से 3 महीने तक अर्थात् 6 अगस्त, 1980 तक या इस बैंक में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति तक, इनमें से जो भी पहले हो तब तक के लिए लागू नहीं होंगे।

[संख्या 15(37)-बी०ओ०-3/79]

S.O. 1602.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 10B of the said Act, shall not apply to Ratnakar Bank Ltd. Kolhapur, for 3 months with effect from 7th May, 1980 *i.e.* upto 6th August, 1980 or till the appointment of the next whole-time Chairman of that bank, whichever is earlier.

[No. 15(37)-B.O. III/79]

नई दिल्ली, 31 मई, 1980

का०आ 1603.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबंध, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया पर, इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 2 वर्ष तक की अवधि के लिए उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक इनका संबंध, बैंक द्वारा मैसर्स भारत शीट एण्ड मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 51 प्रतिशत चुकता शेयर पूंजी की, प्लैज़ी के रूप में धारिता से है ।

[संख्या. 15(19)/80-बी०ओ०-3]
एन० डी० बत्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 31st May, 1980

S.O. 1603.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Sub-section (2) of the Section 19 of the said Act shall not apply to the United Bank of India, Calcutta for a period of two years from the date of issue of this notification in respect of its holding 51 per cent of the paid-up share capital of M/s. Bharat Sheet Metal Industries Ltd., as pledgee.

[No. 15(19)/80-B.O. III]
N. D. BATRA, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1980

आयकर

का०आ० 1604.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना सं० 679 (फा० सं० 187/2/79-आई टी(ए-1) तारीख 20 जुलाई, 1974 से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

(1) क्रम सं० 21, 21क, 21ख, 21ग, 21घ और 21ङ के सामने स्तंभ (1), (2) और (3) के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी ।

अनुसूची

क्रम सं०	सी ई टी सं०	मुख्यालय	अधिकारिता
1	2	3	4
21	तमिलनाडु-I	मद्रास	(1) कम्पनी सर्किल-I, मद्रास (2) सिटी सर्किल-I, मद्रास (3) विशेष सर्वेक्षण सर्किल, मद्रास (4) विदेश अनुभाग, मद्रास
21क	तमिलनाडु-II	मद्रास	(1) सम्पदा शुल्क और आ० क० सर्किल मद्रास (2) स० शु० और आ० क० सर्किल, तन्जावुर (3) स० शु० और आ० क० सर्किल, मद्रास (4) कम्पनी सर्किल-II, मद्रास (5) सिटी सर्किल,-III, मद्रास (6) सिटी सर्किल-IV, मद्रास
21ख.	तमिलनाडु-III	मद्रास	(1) सिटी सर्किल-I, मद्रास (2) सिटी सर्किल-III, मद्रास (3) विशेष अन्वेषण सर्किल-I, मद्रास (4) विशेष अन्वेषण सर्किल-II, मद्रास (5) हुण्डी सर्किल-I, मद्रास (6) वित्तपुरम सर्किल (7) पांडिचेरी सर्किल (8) कुड्डालौर सर्किल (9) नागपट्टिनम् सर्किल (10) कुंभाकोनम् सर्किल (11) तन्जावुर सर्किल
21ग.	तमिलनाडु-IV	मद्रास	(1) वेतन सर्किल-I, मद्रास (2) वेतन सर्किल-II, मद्रास (3) प्रतिशय सर्किल, मद्रास (4) सिटी सर्किल-V, मद्रास (5) सिटी सर्किल-IV, मद्रास (6) तांम्बरम् सर्किल (7) कांचीपुरम सर्किल (8) वेल्लोर सर्किल (9) विशेष अन्वेषण सर्किल-III मद्रास
21घ.	मदुरई	मदुरई	(1) कम्पनी सर्किल, तिरूचिरापल्ली (2) सिटी सर्किल-I, तिरूचिरापल्ली (3) सिटी सर्किल-II, तिरूचिरापल्ली (4) कनूर सर्किल (5) पुडुक्कोट्टाई सर्किल (6) करैकुडी सर्किल (7) कम्पनी सर्किल, मदुरई (8) मदुरई सर्किल (9) विशेष सर्वेक्षण सर्किल, मदुरई (10) विशेष सर्किल, मदुरई (11) डिंडीगुल सर्किल (12) तिरुनेलवेली सर्किल (13) तूतीकोरिन सर्किल (14) विरूधुनगर सर्किल (15) नगरकोइल सर्किल
21ङ.	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	(1) कम्पनी सर्किल-I कोयम्बटूर (2) कम्पनी सर्किल-II, कोयम्बटूर (3) कम्पनी सर्किल-III, कोयम्बटूर (4) कम्पनी सर्किल-IV, कोयम्बटूर (5) कम्पनी सर्किल-V, कोयम्बटूर (6) सिटी सर्किल-I, कोयम्बटूर (7) सिटी सर्किल-II, कोयम्बटूर (8) सिटी सर्किल-III, कोयम्बटूर (9) वेतन सर्किल, कोयम्बटूर (10) विशेष सर्वेक्षण सर्किल, कोयम्बटूर (11) ऊटकामंड सर्किल (12) मोल्लाची सर्किल (13) तिरूप्पुर सर्किल (14) इरोड सर्किल (15) कृष्णागिरि सर्किल (16) कम्पनी सर्किल, सालेम (17) सर्किल-I, सालेम (18) सर्किल-II, सालेम (19) स० शु० और आ० क० सर्किल, कोयम्बटूर

यह अधिसूचना 1-5-1980 से प्रवृत्त होगी ।

[सं० 3244--फा.सं० 187/5/80-आई टी (ए-I)]
बी० एम० सिंह, अवर सचिव,

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 10th Aprli, 1980

INCOME TAX

S.O. 1604.—In exercise of th powers conferred by sub-section (1) of section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Schedule appended to its Notification No. 679 [F. No. 187/2/74-IT(AI)] Dated 20th July, 1974 as amended from time to time :—

(i) Existing entries under columns (1), (2) and (3) against S. No. 21, 21A, 21B, 21C, 21D, 21E shall be substituted by the following entries.

SCHEDULE

Sl. No.	CIT	H. Qrs.	Jurisdiction
1	2	3	4
21.	Tamil Nadu-I	Madras	1. Companies Circle-I, Madras. 2. City Circle-I, Madras. 3. Special Survey Circle, Madras. 4. Foreign Section, Madras.
21A.	Tamil-Nadu-II	Madras	1. ED-cum-IT Circle, Madras 2. ED-cum-IT Circle, Thanjavur 3. ED-cum-IT Circle, Madura. 4. Companies Circle-II, Madras. 5. City Circle-III, Madras. 6. City Circle-IV, Madras.
21B.	Tamil-Nadu-III	Madras	1. City Circle-II, Madras. 2 City Circle-VII, Madras. 3. Special Investigation circle-I, Madras. 4. Special investigation circle-II, Madras. 5. Hundi Circle-I, Madras. 6. Villupuram Circle. 7. Pondichery Circle. 8. Cuddalore Circle. 9. Nagapattinam Circle. 10. Kumbakonam Circle. 11. Thanjavur Circle.
21C.	Tamil-Nadu-IV	Madras	1. Salaries Circle-I, Madras. 2. Salaries Circle-II, Madras. 3. Refund Circle, Madras. 4. City Circle-V, Madras. 5. Cty Circle-VI, Madras. 6. Tambaram Circle. 7. Kancheepuram Circle. 8. Vellore Circle. 9. Special Investigation Circle-III, Madras.
21D.	Madurai	Madurai	1. Company Circle, Tiruchirapalli. 2. City Circle-I, Tiruchirapalli. 3. City Circle-II, Tiruchirapalli. 4. Kanur Circle. 5. Pudukottai Circle. 6. Karaikudi Circle. 7. Company Circle, Madurai. 8. Madurai Circle 9. Special Survey Circle, Madurai. 10. Special Circle, Madurai. 11. Dindigul Circle. 12. Tirunelveli Circle. 13. Tuticorn Circle. 14. Virudhunagar Circle. 15. Nagercoil Circle.
21E.	Coimbatore	Coimbatore	1. Company Circle-I, Coimbatore. 2. Company Circle-II, Coimbatore. 3. Company Circle-III, Coimbatore. 4. Company Circle-IV, Coimbatore. 5. Company Circle-V, Coimbatore. 6. City Circle-I, Coimbatore. 7. City Circle-II, Coimbatore. 8. City Circle-III, Coimbatore. 9. Salary Circle, Coimbatore. 10. Special Survey Circle, Coimbatore. 11. Ootacamund Circle 12. Pollachi Circle. 13. Tiruppur Circle. 14. Erode Circle. 15. Krishnagiri Circle. 16. Company Circle, Salem 17. Circle-I, Salem. 18. Circle-II, Salem. 19. ED-cum-IT Circle, Coimbatore.

This notification shall take effect from 1-5-1980.

[No. 3244—F. No. 187/5/80-IT (AI)]

B. M. SINGH, Under Secy.

वाणिज्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1980

का० आ० 1605.—कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स, वेस्टर्न रेलवे, चर्चगेट, बम्बई को लाइसेंस अवधि अप्रैल, 75, मार्च-76 के लिए यू० के० से बी एम० ए० सी० कोच डोलकस ट्रेन आदि के लिए कैपैसिटी कंट्रोल वाल्व के आयात के लिए 26,280/— रुपये (छब्बीस हजार दो सौ अस्सी रुपये मात्र) मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं० जी०/आर०/3200052/आर/एम जी/62/ए/च०/41-42 दिनांक 16-2-77 प्रदान किया गया था, जो 31-7-79 तक वैध था। अब लाइसेंसधारी ने इस कार्यालय को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा

विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति बम्बई पत्तन के पास पंजीकृत करार बिना और उसका बिल्कुल उपयोग किए बिना ही खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने स्टाम्प कागज पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस सं० जी/आर/3200052/आर/एम जी/62/एच/41-42 दिनांक 16-2-77 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति आवेदक से खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता है कि उन्हें 26,280/- रुपये मात्र के उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति जारी की जाए। आयात लाइसेंस सं० जी/आर/3200052/आर/एमजी/62/एच/41-42 दिनांक 16-2-77 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

[सं० 284-सी/रेलवे/76-77/जी एल एस/पीटी]

के० आर० धीर,
उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE & CIVIL SUPPLIES

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1980

S.O. 1605.—Controller of Stores, Western Railway, Church Gate, Bombay was granted an import licence No. G/R/3200052/R/MG/62/H/41-42 dated 16-2-77 valid upto 31-7-79 for the import of Capacity control valve for EMAL Coaches Deluxe train etc. from U. K. for the licensing period April 75-March 76 for the value Rs. 26,280 (Rupees twenty six thousand two hundred and eighty only). Now the licensee has requested this office for the issue of duplicate Exchange Control purpose copy of the said licence on the ground that the original Exchange Control Purposes copy of the said licence has been lost/Misplaced without registering at Bombay port and has not been utilised at all.

2. In support of his contention, the applicant has filed an affidavit on a stamped paper. The undersigned is satisfied that the original Exchange Control Purpose copy of licence No. G/R/3200052/R/MG/62/H/41-42 dated 16-2-77 has been lost/misplaced by the applicant and directs that duplicate Exchange Control Purpose copy of the said licence for Rs. 26,280 only should be issued to him. The original Exchange Control Purpose copy of import licence No. G/R/3200052/R/MG/62/H/41-42 dated 16-2-77 is hereby cancelled.

[No. 284-C/Rly/76-77/GLS/Pt.]

K. R. DHERR, Dy. Chief Controller of Imports & Exports,
for Chief Controller of Imports & Exports

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 1980-05-19

भारतीय मानक संस्था

का० आ० 1606.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के नियम 3 के उपविनियम 2 तथा विनियम 3 के उपविनियम (2) और (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्योरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 1977-11-30 को निर्धारित किए गए हैं :

अनुसूची

क्रम संख्या	निर्धारित भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	नए मानकों द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक/मानकों की पद संख्या और शीर्षक	विवरण
1	2	3	4
1.	IS : 803–1976 मृदु इस्पात की वेलनाकार वैल्डकृत ऊर्ध्व तेल भंडार टंकियों की डिजाइन गढ़ाई और खड़े करने की रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण)	IS : 803–1962 मृदु स्पात की वेलनाकार वैल्डकृत ऊर्ध्व तेल भंडार टंकियों की रीति संहिता	—
2.	IS : 1224 (भाग 1)–1977 गरबर पद्धति द्वारा दूध में वसा की मात्रा ज्ञात करना भाग 1 दूध (पहला पुनरीक्षण)	IS : 1224–1958 गरबर पद्धति द्वारा संपूर्ण दूध, वाष्पित दूध (मीठा रहित) क्रीम निकले दूध, मखनिया दूध, छाछ और क्रीम में वसा की मात्रा ज्ञात करना	—
3.	IS : 1224 (भाग 2)–1977 गरबर पद्धति द्वारा वसा की मात्रा ज्ञात करना भाग 2 दूध उत्पाद (पहला पुनरीक्षण)	,,	—
4.	IS : 1359–1977 बंग विद्युत लेपनों की (विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 1359–1966 बंग विद्युतलेपनों की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	—

1 2	3	4
5. IS : 1856–1977 ढुलाई कार्यों के लिए इस्पात के तार के रस्सों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 1856–1970 खानों में ढुलाई कार्यों के लिए इस्पात के तार के रस्सों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	1977-09-30 को निर्धारित
6. IS : 1855 (भाग 38)—1977 विद्युत तकनीकी शब्दावली भाग 38 ट्रांसफार्मर (पहला पुनरीक्षण)	IS : 1885 (भाग 38)–1973 विद्युत तकनीकी शब्दावली भाग 38 ट्रांसफार्मर	—
7. IS : 2032 (भाग 19)–1977 विद्युत प्रोद्योगिकी में प्रयुक्त लेखी प्रतीक भाग 19 चिकित्सा व्यवसाय में प्रयुक्त उपकरण	—	1977-10-31 को निर्धारित
8. IS : 2032 (भाग 21)–1977 विद्युत प्रोद्योगिकी में प्रयुक्त लेखी प्रतीक भाग 21 विद्युत वैल्डिंग उपकरण	—	—
9. IS : 2107–1977 व्हाइटहार्ट घातवर्ध्य लोहे की ढली वस्तुओं की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2107–1962 व्हाइटहार्ट घात वर्ध्य लोहे की ढली वस्तुओं की विशिष्टि	1977-05-31 को निर्धारित
10. IS : 2365–1977 लिफ्टों, एस्केलेटरों और हविसों में प्रयुक्त इस्पात के तार के निलम्बन रस्सों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2365–1963 लिफ्टों और हविसों के लिए इस्पात के तार के निलम्बन की विशिष्टि	1977-09-30 को निर्धारित
11. IS : 3390–1977 पारे वाले रुधिर दाब मापियों की विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3390–1965 पारे वाले रुधिर दाब मापियों की विशिष्ट	भा मा संस्था प्रमाणन चिन्ह योजना के लिए IS : 3390–1965 IS : 3390–1977 के साथ 1978-06-30 तक लागू होगा।
12. IS : 3634–1977 बिलों में दवा डालने के लिए हस्तचालित यंत्रों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3634–1966 बिलों में दवा डालने के लिए यंत्रों की विशिष्टि	—
13. IS : 3717–1977 परिष्कृत पुराने सीसे की विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3717–1966 परिष्कृत पुराने सीसे की विशिष्टि	—
14. IS : 3842 (भाग 9)–1977 ए सी प्रणालियों के लिए रिले की उपयोग संदर्शिका भाग 9 बसबार सुरक्षा के लिए रिले	—	1977-10-31 को निर्धारित
15. IS : 3885 (भाग 1)–1977 परतदार कमानियां (रेल के डिब्बों के लिए) बनाने के लिए इस्पात की विशिष्ट भाग 1 चपटे सेक्शन (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3885 (भाग 1)–1966 परतदार कमानियां (रेल के डिब्बों के लिए) बनाने के लिए इस्पात की विशिष्टि भाग 1 चपटे सैक्शन	1979-10-31 को निर्धारित भा मा संस्था प्रमाणन चिन्ह योजना के लिए IS : 3885 (भाग 1) 1966 IS : 3885 (भाग 1) 1977 के साथ 1978-02-28 तक लागू रहेगा।
16. IS : 3907 (भाग 1)—1977 प्रयोगशाला में प्रयुक्त पशुओं के परिवहन की रीति संहिता भाग 1 चूहों, बड़े चूहों, खरगोशों, गिनी पिग, सफेद चूहों और हेमस्टर्स का परिवहन (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3907 (भाग 1)—1966 प्रयोगाला में प्रयुक्त पशुओं के परिवहन की रीति संहिता चूहों, बड़े चूहों, खरगोशों, गिनी पिग और सफेद चूहों का परिवहन	1977-10-31 को निर्धारित
17. IS : 4103–1977 धातु की नेस्टिंग कुर्सियों की विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)	IS : 4103–1967 नेस्टिंग धातु की कुर्सियों की विशिष्ट	—
18. IS : 4236–1977 प्रसाधन उद्योग के लिए ग्लिसरायल मोनोस्टियरेट की विशिष्ट	IS : 4236–1967 प्रसाधन उद्योग के लिए ग्लिसराइल मोनोस्टियरेट की विशिष्टि	1977-10-31 को निर्धारित
19. IS : 4236–1977 आग प्रतिरोधी कैंटिस कपड़े की विशिष्ट	IS : 4355–1967 आग प्रतिरोधी कैंविस कपड़े की विशिष्टि	—

1	2	3	4
20.	IS : 4519–1977 तांबे की कम्प्यूटेटर पत्तियों के माप (पहला पुनरीक्षण)	IS : 4519–1968 कम्प्यूटेटर पत्तियों के लिए तांबा	—
21.	IS : 4569 (भाग 6)–1977 नेत्र कैंचियां भाग 6 पुतली (पहला पुनरीक्षण)	IS : 4569–1969 नेत्र कैंचियां की विशिष्ट	—
22.	IS : 5120–1977 विशेष कार्यों के लिए घूर्णन गतिशील पम्पों की तकनीकी अपेक्षाएं (पहला पुनरीक्षण)	IS : 5120–1968 विशेष कार्यों के लिए घूर्णन गतिशील पम्पकी तकनीकी अपेक्षाए	1977-10-31 को निर्धारित
23.	IS : 5438–1977 नाइट्रोबेंजीन-3 सल्फोनिक अम्ल, सोडियम लवण की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 5438–1969 नाइट्रोबेंजीन एम सल्फोनिक अम्ल सोयडयम लवण की विशिष्टि	—
24.	IS : 5500–1977 कम्पन रोलर (बेलेन) की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 5500–1969 कम्पन रोलर की विशिष्टि	—
25.	IS : 6873 (भाग 1)–1977 विद्युत चुम्बकीय अवबाधा की मापन पद्धतियां भाग 1 मोटर गाड़ियों और अन्य सामान साधनों के दहन तंत्र से (पहला पुनरीक्षण)	IS : 6873 (भाग 1)–1972 रेडियो अवबाधा मापन पद्धतियां भाग 1 चिंगारी दहन वाले अन्तर्दहन इंजनों से	—
26.	IS : 7160 (भाग 5)—1977 पाठ्य पुस्तकों के लिए मुद्रण क्षेत्र हाशिए और टाइप साइज की संदर्शिका	—	—
27.	IS : 7595 (भाग 3)–1977 मोटर बोर्डों की सामान्य अपेक्षाएं भाग 3 संकाकर मोटर बोर्ड	—	—
28.	IS : 8414–1977 मिट्टी और शैल भराई वाले बांधों में निचले रिसाव की डिजाइन सम्बन्धी संदर्शिका	—	—
29.	IS : 8422 (भाग 2)–1977 अंतर्दाही इंजनों के पिस्टन रिंग भाग 2,30 से 200 मि०मी० सांकेतिक व्यास के एम रिंगों के गाववुम सतह वाले संबीड़न रिंग।	—	—
30.	IS : 8466–1977 खोई वाहक चेनों की विशिष्टि	—	—
31.	IS: 8471 (भाग 4)–1977 एसीटिलीन जनित्रों सम्बन्धी अपेक्षाएं भाग 4 मध्यम दाब, अचल जल से कार्बाइड और कार्बाइड से जल टाइप	—	—
32.	IS: 8471 (भाग 5)–1977 एसीटिलीन जनित्रों सम्बन्धी अपेक्षाएं भाग 5 मध्यम दाब वाले, सुवाह्य जल मे कार्बाइड और कार्बाइड से जल टाइप	—	—
33.	IS : 8472–1977 ठंडे साफ और ताजे पानी के लिए स्वतः पनियाने वाले पुनरुत्पादक पम्पों की विशिष्टि	—	—
34.	IS : 8473–1977खानों में प्रयुक्त कड़ीदार छड़ों की विशिष्ट	—	—
35.	IS : 8479 (भाग 2)–1977 दूध और दूध उत्पादों में फॉस्फेटेज सक्रियता को ज्ञात करने की पद्धतियां भाग 2 संवर्ध पद्धतियां	—	—

1	2	3	4
36.	IS : 8481–1977 तरल आक्सीकरण केश रंजकों की विशिष्टि	—	—
37.	IS : 8506–1977 प्रयोगशाला की विद्युत प्रतिरोधी भट्टियों की विशिष्टि	—	1977-10-31 के निर्धारित
38.	IS : 8512–1977 मक्खिया कैलोसा शहद की विशिष्टि	—	—
39.	IS : 8513–1977 वायुयान कार्यों के लिए ठंडे गढ़े रिवेटों के एलुमिनियम (मिश्रधातु 55000) मिश्र तार की विशिष्टि	—	—
40.	IS : 8521 (भाग 1)–1977 औद्योगिक मुख रक्षकों (शील्ड) की विशिष्टि भाग 1 प्लास्टिक के वाइजर	—	—
41.	IS : 8524–1977 सौर मोम निष्कर्षक की विशिष्टि	—	—
42.	IS : 8540–1977 कांच साफ करने के तरल की विशिष्टि	—	—
43.	IS : 8542–1977 लकड़ी के फर्नीचर की पेस्टनुमा पालिश की विशिष्टि	—	—
44.	IS : 8543 (भाग 1/अनुभाग 1)–1977 प्लास्टिक की परीक्षण पद्धतियां भाग II गढ़ाई से पहले सामग्रियों के परीक्षण अनुभाग 1 कीप से उड़ेलने योग्य गढ़ाई सामग्रियों का आभासी घनत्व ज्ञात करना	—	—
45.	IS : 8543 (भाग 2 अनुभाग 2)–1977 प्लास्टिक की परीक्षण पद्धतियां भाग 2 गढ़ाई से पहले सामग्री के परीक्षण अनुभाग 2 कीप से न उड़ेलने योग्य गढ़ाई सामग्रियों का आभासी घनत्व मालूम करना।	—	—
46.	IS : 8543 (भाग II/अनुभाग 3)–1977 प्लास्टिक की परीक्षण पद्धतियों भाग II गढ़ाई से पहले सामग्री परीक्षण अनुभाग 3 गढ़ाई सामग्रियो के राशि अनुपात (बल्क फैक्टर) ज्ञात करना		
47.	IS : 8551–1977 1–(4 सल्फोफिनाइल)–3 मिथाइल–5 पाइराजोलोन की विशिष्टि	—	—
48.	IS : 8552–1977 1–(4 सल्फोफिनाइल)–3—कार्बोक्सी–5 पाइराजोलोन की विशिष्टि		
49.	IS : 8554–1977 लेप टूटन विभव माप द्वारा एनोडीकृत लेपों का रोधन जांच पद्धतियां	—	—
50.	IS : 8563– 977 स्प्लिट पिनें बनाने के लिए अर्धगोल मृदु इस्पात के तार की विशिष्टि	—	—
51.	IS : 8564–1977 तीलियां की बुंडियों के लिए इस्पात के तार की विशिष्टि	—	—
52.	IS : 8565–1977 हील्ड तारो की विशिष्टि	—	—
53.	IS : 9000 (भाग 3/अनुभाग 1 से 5)–1977 इलैक्ट्रोनिक और बिजली की वस्तुओं की मूल वातावरणीय परीक्षण विधियां भाग 3 शुष्क ताप परीक्षण	—	—

इन भारतीय मानकों की प्रतियां भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफरमार्ग, नई दिल्ली 110002 और अहमदाबाद, बंगलोर, बम्बई, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चण्डीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, पटना और त्रिवेन्द्रम स्थित शाखा कार्यालयों में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

[सं० सी एम डी/13 2]

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, 1980-05-19

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

S.O.1606.—In pursuance of Sub-rule (2) of Rule 3 and Sub-regulations (2) and (3) of regulation 3 of Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules and Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Indian Standard(s), particulars of which are given in the Schedule hereto annexed, have been established on 1977-11-30 :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of the Indian Standards Established	No. and Title of the Indian Standard or Standards, if any, superseded by the new Indian Standard	Remarks, if any
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 803–1976 Code of practice for design, fabrication and erection of vertical mild steel cylindrical welded oil storage tanks (First revision).	IS : 803–1962 Code of practice for design, fabrication and erection of vertical mild steel cylinderical welded oil storage tanks.	—
2.	IS : 1224 (Part I)–1977 Determination of fat by the gerber method Part I milk (First revision).	IS : 1224–1958 Determination of fat in whole milk, evaporated (unsweetened) milk, separated milk, skim milk, butter milk and cream by the gerber method.	—
3.	IS : 1224 (Part II)–1977 Determination of fat by the Gerber method Part II milk products (First revision).	-do-	—
4.	IS : 1359–1977 Specification for electroplated coatings of tin /Second Revision).	IS : 1359–1966 Specification for electroplated coatings of tin (revised).	—
5.	IS : 1856–1977 Specification for steel wire ropes for haulage purposes (Second revision)	IS : 1856–1970 Specification for steel wire ropes for haulage purposes in mines (First revision).	Established on 1977-09-30.
6.	IS : 1855 (Part XXXVIII)–1977 Electrotechnical Vocabulary Part XXXVIII transformers (First revision).	IS : 1885 (Part XXXVIII)–1973 Electrotechnical vocabulary Part XXXVIII transformers.	—
7.	IS : 2032 (Part XIX)–1977 Graphical Symbols used in electrotechnology Part XIX electrical equipment used in medical practice.	—	Established on 1977-10-31.
8.	IS : 2032 (Part XXI)–1977 Graphical symbols used in electrotechnology Part XXI electric welding equipment	—	—
9.	IS : 2107–1977 Specification for whiteheart malleable iron castings (First revision).	IS : 2107–1962 Specification for whiteheart malleable iron castings.	Established on 1977-05-31.
10.	IS : 2365–1977 Specification for Steel wire suspension ropes for lifts, elevators and hoists (First revision).	IS : 2365–1963 Specification for steel wire suspension ropes for lifts and hoists.	Established on 1977-09-30.
11.	IS : 3390–1977 Specification for sphygmomanometers, mercurial (First revision).	*IS : 3390–1965 Specification for sphygmomanometers, mercurical.	For purposes of ISI Certification Marks Scheme, IS : 3390–1965 shall run concurrently with IS : 3390–1977 upto 1978-06-30.
12.	IS : 3634–1977 Specification for hand-operated dust applicator for burrows (First revision).	IS : 3634–1966 Specification for dust applicator for burrows.	—
13.	IS : 3717–1977 Specification for refined secondary lead (First revision).	IS : 3717–1966 Specification for refined secondary lead.	—
14.	IS : 3842 (Part IX)–1977 Application guide for Electrical relays for AC systems Part IX relays for bus bar protection.	—	Established on 1977-10-31.

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	IS : 3885 (Part I)-1977 Specification for steel for the manufacture of laminated springs (Railway rolling stock) Part I flat sections (First revision).	*IS : 3885 (Part I)-1966 Specification for steel for the manufacture of laminated springs (Railway rolling stock) Part I flat sections.	Established on 1977-10-31. *For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS : 3885 (Part I)-1966 shall run concurrently with IS : 3885 (Part I)-1977 upto 1978-02-28.
16.	IS : 3907 (Part I)-1977 Code of practice for transport of laboratory animals Part I transport of mice, rats, rabbits, guinea pigs, cotton rats and hamsters (First revision).	IS : 3907 (Part I)-1966 Code for the transport of laboratory animals : Part I transport of mice, rats, rabbits, guinea pigs and cotton rats.	Established on 1977-10-31.
17.	IS : 4103-1977 Specification for metal nesting chairs (First revision).	IS : 4103-1967 Specification for metal nesting chairs.	—
18.	IS : 4236-1977 Specification for glyceryl monostearate for cosmetic industry (First revision).	IS : 4236-1967 Specification for glyceryl monostearate for cosmetic industry.	Established on 1977-10-31.
19.	IS : 4355-1977 Specification for fire-resistant brattice cloth (First revision).	IS : 4355-1967 Specification for fire-resistant brattice cloth.	—
20.	IS : 4519-1977 Dimensions for copper commutator bars (First revision).	IS : 4519-1968 Copper for commutator bars.	—
21.	IS : 4569 (Part VI)-1977 Specification for scissors, Eye Part VI IRIS (First revision).	IS : 4569-1968 Specification for scissors, eye.	—
22.	IS : 5120-1977 Technical requirement for rotodynamic special purpose pumps (First revision).	IS : 5120-1968 Technical requirements for rotodynamic special purpose pumps.	Established on 1977-10-31
23.	IS : 5438-1977 Specification for nitrobenzene-3-sulphonic acid, sodium salt (First revision).	IS : 5438-1969 Specification for nitrobenzene-m-sulphonic acid, sodium salt.	—
24.	IS : 5500-1977 Specification for vibratory roller (First revision).	IS : 5500-1969 Specification for vibratory-roller.	—
25.	IS : 6873 (Part I)-1977 Methods of measurement of electromagnetic interference Part I from ignition systems of motor vehicles and other similar devices (First revision).	IS : 6873 (Part I)-1972 Methods of measurement of radio interference: Part I from internal combustion engines using spark ignition.	—
26.	IS : 7160 (Part V)-1977 Guide for print area, margins and type sizes for textbooks Part V textbooks in Kannada.	—	—
27.	IS : 7595 (Part III)-1977, General requirements for other boards Part III oval otter boards.	—	—
28.	IS : 8414-1977 Guidelines for design of under-seepage control measures for earth and rockfill dams.	—	—
29.	IS : 8422 (Part II)-1977 Specification for piston rings for IC engines Part II taper faced compression rings from 30 up to 200 mm Nominal diameter M-rings.	—	Established on 1977-10-31.
30.	IS : 8466-1977 Specification for bagasse carrier chains.	—	—
31.	IS : 8471 (Part IV)-1977 Requirements for acetylene generators Part IV medium pressure, stationary, of water-to-carbide and carbide-to-water type.	—	—
32.	IS : 8471 (Part V)-1977 Requirements for acetylene generators Part V medium pressure, portable, of water-to-carbide and carbide-to-water type.	—	—
33.	IS : 8472-1977 Specification for regenerative self-priming pumps for clear, cold, fresh water.	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)
34.	IS : 8473–1977 Specification for link bars used in mines.	—	—
35.	IS : 8479 (Part II)–1977 Methods for determination of phosphatase activity in milk and milk products Part II reference method.	—	—
36.	IS : 8481–1977 Specification for oxidation hair dyes, liquid.	—	—
37.	IS : 8506–1977 Specification for laboratory electrical resistance furnaces.	—	Established on 1977-10-31.
38.	IS : 8512–1977 Specification for carvia callosa honey.	—	—
39.	IS : 8513–1977 Specification for aluminium alloy wire for cold forged rivets for aircraft purposes (Alloy 55000).	—	—
40.	IS : 8521 (Part I)–1977 Specification for industrial safety faceshields Part I with plastic visor.	—	—
41.	IS : 8524–1977 Specification for solar wax extractor.	—	—
42.	IS : 8540–1977 Specification for glass cleaner, liquid.	—	—
43.	IS : 8542–1977 Specification for polish for wooden furniture, paste.	—	—
44.	IS : 8543 (Part II/Sec. I)–1977 Methods of testing plastics Part II Testing of materials before moulding Section I Determination of Apparent Density of Moulding Materials that can be poured from a funnel.	—	—
45.	IS : 8543 (Part II/Sec. 2)–1977 Methods of testing plastics Part II Testing of materials before moulding Section 2 Determination of Apparent density of moulding materials that cannot be poured from a funnel.	—	—
46.	IS : 8543 (Part II/Sec. 3)–1977 Methods of testing plastics Part II testing of materials before moulding Section 3 Determination of bulk factor of moulding materials.	—	—
47.	IS : 8551–1977 Specification for 1-(4-sulphophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone.	—	—
48.	IS : 8552–1977 Specification for 1-(4'-sulphophenyl)-3-carboxy-5-pyrazolone.	—	—
49.	IS : 8554–1977 Method of checking insulation of anodized coating by measurement of breakdown potential.	—	—
50.	IS : 8563–1977 Specification for half round mild steel wire for the manufacture of split pins.	—	—
51.	IS : 8564–1977 Specification for steel wire for nipples for spokes.	—	—
52.	IS : 8565–1977 Specification for heald wire.	—	—
53.	IS : 9000 (Pat-III Sec. 1 to 5)-1977 Basic environmental testing procedures for electronic and electrical items Part III dry heat test.	—	—

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution, Manak Bhawan, 9-Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and also from its branch offices at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Bhubaneswar, Calcutta, Chandigarh, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Patna and Trivandram.

229 GI/80—15 [No. CMD/13 : 2]

का० आ० 1607.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) के विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय मानक जिनके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं रद्द कर दिए गए हैं और अब उन्हें वापस माना जाए।

अनुसूची

क्रम संख्या	रद्द किये गए भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	राजपत्र अधिसूचना की एस० ओ० संख्या और तिथि जिसमें भारतीय मानक की स्थापना छपी थी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 1885 (भाग 5), 1965 विद्युत तकनीकी शब्दावली भाग 5 स्फटिक क्रिस्टल	भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) मे दिनांक 1965-08-28 में एस ओ संख्या 2673 दिनांक 1965-08-13 के अधीन प्रकाशित	स्फटिक क्रिस्टल और दाब विद्युत छन्ना की विद्युत तकनीकी शब्दावली के IS : 1885 (भाग 54) 1978 विद्युत तकनीकी शब्दावली भाग 54 दाब विद्युत साधन में सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप
2.	IS : 1885 (भाग 33)—1972 विद्युत तकनीकी शब्दावली भाग 33 दाब विद्युत छन्ना	भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) मे दिनांक 1974-04-06 मे एस ओ संख्या 889, दिनांक 1974-03-21 के अधीन प्रकाशित	

[संख्या सी एम डी/13 : 7]

S.O. 1607.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 as amended from time to time, it is, hereby, notified that the Indian Standard(s), particular to which are mentioned in the Schedule given hereafter, have been cancelled and stands withdrawn:

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Title of the Indian Standard Cancelled	S.O. No. & Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was Notified.	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS: 1885 (Part V)—1965 Electrotechnical vocabulary: Part V Quartz crystal.	S.O. 2673 dated 1965-08-13 published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1965-08-28.	As the electrotechnical vocabulary on quartz crystals and piezoelectric filter have now been covered under IS: 1885 (Part XLIV)—1978 Electrotechnical vocabulary: Part XLIV Piezoelectric device
2.	IS: 1885 (Part XXXIII)—1972 Electrotechnical vocabulary: Part XXXIII Piezoelectric filters.	S.O. 889 dated 1974-03-21 published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1974-04-06.	

[No. CMD/13:7]

का० आ० 1608.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि जिस मानक चिह्न का डिजाइन, उसके शाब्दिक विवरण तथा तत्संबंधी भारतीय मानक के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दिया गया है वह भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों और विनियमों के निमित्त यह मानक चिह्न 1979-10-01 से लागू होगा।

अनुसूची

क्रम सं०	मानक चिह्न का डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक	मानक चिह्न के डिजाइन का शाब्दिक विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		कारबेरिल, तकनीकी	IS : 7539-1975 कारबेरिल तकनीकी की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें "ISI" शब्द होते है, स्तम्भ (2) मे दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन मे दिखाया गया है मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या दी गई है।

[संख्या सी एम डी/13 : 8]

S.O. 1608.— In pursuance of sub-rules (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the India Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark, design of which together with the verbal description of the design and the title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed, has been specified.

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1979-10-01:

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS 7539 ISI	Carbaryl, technical	IS: 7539—1975 Specification for carbaryl, technical.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13:9

का० आ० 1609.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) के विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कारबेरिल तकनीकी की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस नीचे अनुसूची में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निर्धारित की गई है और यह फीस 1979-10-01 से लागू होगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कारबेरिल, तकनीकी	IS : 7539—1975 कारबेरिल, तकनीकी की विशिष्टि	100 कि० ग्रा०	1. रु० 10.00 प्रति इकाई पहली 500 इकाइयों के लिए, 2. रु० 5.00 प्रति इकाई 501वीं से 1000 इकाइयों के लिए, और 3 रु० 1.00 प्रति इकाई 1001वीं इकाई और अगली इकाइयों के लिए

[संख्या सी० एम डी/13 : 10]

S.O.1609—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee per unit for Carbaryl technical details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been determined and the fee shall come into force with effect from 1979-10-01 :

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Carbaryl, technical	IS: 7539—1975 Specification for carbaryl, technical.	100 kg	(i) Rs. 10.00 per unit for the first 500 units; (ii) Rs. 5.00 per unit for the 501st to 1000 units; and (iii) Re 1.00 per unit for the 1001st unit and above.

[No. CMD/13:10]

का० आ० 1610.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) के विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि पालीइथाइलीन फ्लोटों की प्रति हजार इकाई मुहर लगाने की फीस नीचे अनुसूची में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निर्धारित की गई है और यह फीस 1980-04-01 से लागू होगी :

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	केवल पालीइथाइलीन फ्लोट	IS : 1703–1977 जल वितरण कार्यों के लिए फ्लोट (क्षैतिज प्लंजरयुक्त) गोलों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक अदद	(i) 4 पैसे प्रति इकाई पहली 50000 इकाइयों के लिए, और (ii) 2 पैसे प्रति इकाई 50001वीं इकाई और अगली इकाईयों के लिए

[संख्या सी एम डी/13 : 10]
ए० पी० बनर्जी, अपर महानिदेशक

S.O. 1610—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee per unit for polythelene floats only details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been determined and the fee shall come into force with effect from 1980-04-01;

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Polythelene floats only.	IS : 1703—1977 Specification for ball valves (horizontal plunger type) including floats for water supply purposes (second revision).	One Piece	(i) 4 Paise per unit for the first 50000 units and (ii) 2 Paise per unit for the 50001st unit and above.

[No. CMD/13:10]
A.P. BANERJI, Addl. Director General

योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 17 मई, 1980

का० आ० 1611.—इस विभाग की दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 की अधिसूचना सं० एम-12011/6/79-स्था० 2 के क्रम में उसके अन्तर्गत गठित समिति को अपनी मुख्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 15 मार्च, 1980 तक समय की स्वीकृति दी गई थी।

[सं० एम०-12011/6/79-स्था०-2]
आर० एन० सक्सेना, उप सचिव

MINISTRY OF PLANNING

(Department of Statistics)

New Delhi, the 17th May, 1980

S.O. 1611.—In continuation of this Department Notification M-12011/6/79-Estt. II dated the 30th October 1979, the Committee set up thereunder was allowed time upto the 15th March, 1980 for the submission of its main report.

[No. M-12011/6/79 Estt. II]
R. N. SAXENA, Dy. Secy.

पेट्रोलियम एवायम और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 24 मई, 1980

का० आ० 1612—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप न० एस० एन० टी० से जी० जी० एस० सन्थाल-1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस

तथा आयोग, निर्माण और देख भाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करनेवाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कूप नं० एम० एन० टी० से जी० जी० एस० सनथाल-1 तक पाइप लाईन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात	जिला : मेहसाना	तालुका : मेहसाना		
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एकारई	सेन्टीयर
सनथल	849/2	0	06	00
	850	0	10	80
	851/1	0	04	68
	851/2	0	05	64
	852	0	10	80
	864/1	0	12	24
	865	0	10	32
	866/1	0	05	52
	सी०टी०	0	02	00

[सं० 12016/26/80-प्रो०]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILISER

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 24th May, 1980

S.O. 1612.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNT to GGS Supthal-I in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390 009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Well No SNT to GGS Santhal-I

State Gujrat Distt. Mehsana Taluka-Mehsana.

Village	Survey No.	Hect.	Are	Centiare
Santhal . .	849/2	0	06	00
	850	0	10	80
	851/1	0	04	68
	851/2	0	05	64
	852	0	10	80
	864/1	0	12	24
	865	0	10	32
	866/1	0	05	52
	CT.	0	02	00

[No. 12016/26/-80-Prod.]

का० आ० 1613.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० एन० के० बी० ओ० से जी० जी० एस० कम सी० टी० एफ० कड़ी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एसद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस तथा आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एन० के० बी० ओ० से जी० जी० एस०/सी० टी० एफ० कड़ी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात	जिला : मेहसाना	तालुका : कड़ी		
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ए०आर० ई०	सेन्टीयर
चालासन	128	0	09	84
	130	0	07	20
	127	0	05	28
	134	0	06	36
	135	0	12	60
	137/2	0	09	12
	119/2/के	0	08	76
	109/2	0	09	96
	कार्टट्रेक	0	00	60
	110/1	0	13	44
	87	0	12	90

[सं० 12016/26/80-प्रो० 2]

S.O. 1613.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKBO to GGS Cum CTF Kadi in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent

Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390 009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

NKBO to GGS Cum CTF Kadi

State—Gujarat Distt—Mehsana Taluka—Kadi.

Village	Survey No.	Hect.	Are	Centiare
Chalasan . .	128	0	09	84
	130	0	07	20
	127	0	05	28
	134	0	06	36
	135	0	12	60
	137/2	0	09	12
	119/2/K	0	08	76
	109/2	0	09	96
	C.T.	0	00	60
	110/1	0	13	44
	87	0	12	90

[No. 12016/26/80-Prod.(II)]

का० आ० 1614.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० सी० बी० बी० से डी० एस० 24 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस तथा आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

डी० एस० सी० बी० बी० से डी० एस०-24 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : खंभात

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ए० आर० सेन्टीयर ई०	
1	2	3	4	5
नेजा	288	0	57	64
	सरकारी जमीन	0	05	20
,,	109	0	16	96
	110	0	11	33
	112	0	18	39
	कार्ट ट्रेक	0	00	52
	86	0	14	00
	87	0	16	25
	89	0	35	54

[सं० 12016/28/80-प्रो०]

S.O. 1614.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from CBB to D.S. 24 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390 009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

R.O.U. FOR LAYING PIPELINE FROM

D. S. CBB TO DS-24

State : Gujarat District : Kaira Taluka : Cambay

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Neja . . .	288	0	57	64
	Govt. land	0	05	20
	109	0	16	96
	110	0	11	33
	112	0	18	39
	101	0	35	35
	Cart-track	0	00	52
	86	0	14	00
	87	0	16	25
	89	0	35	54

[No. 12016/28/80-Prod.]

नई दिल्ली, 26 मई, 1980

का० आ० 1615.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० के० जे० एक्स से जी० जी० एस० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस तथा आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़ वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कूप सं० के० जे० एक्स से जी० जी० एस० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	ब्लाक सं०	हेक्टेयर	ए० आर० ई०	सेन्टीयर
पानसर	925	0	03	00
	924	0	11	40
	924	0	01	80
	923	0	09	45

[सं० 12016/25/80-प्रो० I]

New Delhi, the 26th May, 1980

S.O. 1615.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from KJX to GGS Pansar in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390 009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

R.O.U. FOR LAYING PIPELINE FROM WELL NO. KJX TO GGS.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Pansar . .	925	0	03	00
	924	0	11	40
	924	0	01	80
	923	0	09	45

[No. 12016/25/80-Prod. I.]

का० आ० 1616—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप सं० पानसर II से जी० जी० एस० पानसर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस तथा आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करनेवाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

पानसर-2 से जी० जी० एस० पानसर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	ब्लाक सं०	हेक्टेयर	ए० आर० ई०	सेन्टीयर
पानसर	1652	0	07	50
	1313	0	10	50
	1312	0	06	90
	1309	0	12	00
	1308	0	12	30
	1306	0	01	00
	कार्ट ट्रेक	0	00	90
	1270	0	11	40
	1273	0	10	05
	1263	0	09	00
	कार्ट ट्रेक	0	01	50
	1086	0	16	80
	1087	0	16	95
	1079	0	08	85
	1078	0	34	65
	948	0	15	00
	939	0	16	05
	935	0	13	50
	934	0	05	10
	933	0	01	80
	932	0	19	80
	925	0	10	55
	924	0	14	55
	923	0	08	70

[सं० 12016/25/80-प्रो० II]

S.O. 1616.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Pansar-2 to GGS Pansar in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390 009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM PANSAR-2 TO GGS PANSAR

State : Gujarat District : Mehsana Taluka -: Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Pansar . .	1652	0	07	50
	1313	0	10	50
	1312	0	06	90
	1309	0	12	00
	1308	0	12	30
	1306	0	01	00
	Cart track	0	00	90
	1270	0	11	40
	1273	0	10	05
	1263	0	09	00
	Cart track	0	01	50
	1086	0	16	
	1087	0	16	80
	1079	0	08	95
	1078	0	34	85
	948	0	15	65
	939	0	16	00
	935	0	13	05
	934	0	05	50
	933	0	01	80
	932	0	19	80
	925	0	10	55
	924	0	14	55
	923	0	08	70

[No. 12016/25/80-Prod. II]

का०आ० 1617.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० एन०के०सी०पी० से एस०के०बी०जे० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस तथा आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कूप नं० एन० के० सी० पी० से एन०के०बी० जे० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगाम

गांव	सर्वे नं०	हैक्टेयर	एआर ई	सेन्टीयर
तेलावी	77	0	22	08
	कार्ट ट्रेक	0	01	56
	85	0	02	40
	76	0	18	48
	75	0	23	28

[संख्या 12016/27/80-प्रो०]

S.O. 1617.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKCR to NKBJ in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390 009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

ACQUISITION OF ROU FROM WELL NO. NKCP TO NKBJ

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Telavi . .	77	0	22	08
	Track	0	01	56
	85	0	02	40
	76	0	18	48
	75	0	23	28

[No. 12016/27/80-Prod. I]

का०आ० 1618.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० एन०के०सी० आर० से एस०के०बी०जे० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप सं० एन०के०सी०आर० और एन०के०बी०जे० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगाम

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
तेलारी	83	0	02	40
	84	0	16	21
	92	0	15	12
	87	0	09	00
	86	0	11	64
	कार्ट ट्रैक	0	00	60
	75	0	25	24

[सं० 12016/27/80-प्रो०-II]

किरन चड्ढा, अवर सचिव

S.O. 1618.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKCR to NKBJ in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra-390 009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

NKCR TO NKBJ

State : Gujarat Distt : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hect.	Are	Centiare
Telari	83	0	02	40
	84	0	16	21
	92	0	15	12
	87	0	09	00
	86	0	11	64
	C.T.	0	00	60
	75	0	25	24

[No. 12016/27/80-Prod. II]

KIRAN CHADHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 मई, 1980

का०आ० 1619.—यतः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए गुजरात राज्य के सलाया से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया गया है।

और यतः इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को अनुसूची में निर्दिष्ट गांव के नाम के सामने दिखाई गई तिथि से पर्यवसित कर दिया है।

अब अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया पर्यवसान के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

व्यपन क्षेत्र सलाया से मथुरा तक पाइप लाइन संक्रिया पर्यवसान

तहसील : मालपुरा जिला : टौंक राज्य : राजस्थान

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	संक्रिया पर्यवसान की तिथि
पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग)	1 अटोली	3784	10-12-77	3-3-80
	2 लक्षी	3784	10-12-77	3-3-80
	3 देहूनी	3784	10-12-77	3-3-80
	4 कुराड़	3784	10-12-77	3-3-80
	5 स्याह	3784	10-12-77	3-3-80
	6 बरोल	3784	10-12-77	3-3-80
	7 पचेवर	3784	10-12-77	3-3-80
	8 मिलकपुर	3784	10-12-77	3-3-80
	9 किराबल	3784	10-12-77	3-3-80
		3711	10-11-79	
	10 जावलिया	3784	10-12-77	3-3-80
	11 अरन्या बस्सी	3784	10-12-77	3-3-80

[सं० 12020/11/80-प्रो०]

New Delhi, the 26th May, 1980

S.O. 1619.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the Indian Oil Corporation Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar Pradesh;

And whereas the Indian Oil Corporation Limited has terminated the operation referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on the date shown against the name of village in the schedule;

Now, therefore, under rule 4 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisiton of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of the said operation.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from Salaya to Mathura

Tehsil : Malpura District : Tonk State : Rajasthan

Name of the Ministry	Name of the Village	S.O. No.	Date of Publication in the Gazette of India	Date of Termination
1	2	3	4	5
Petroleum, Chemicals & Fertiliser (Department of Petroleum)	1 Atoli	3784	10-12-77	3-3-80
	2 Lari	3784	10-12-77	3-3-80
	3 Dedhani	3784	10-12-77	3-3-80
	4 Kurad	3784	10-12-77	3-3-80
	5 Syah	3784	10-12-77	3-3-80
	6 Barol	3784	10-12-77	3-3-80
	7 Pachewar	3784	10-12-77	3-3-80
	8 Milakpur	3784	10-12-77	3-3-80
	9 Kirawal	3784	10-12-77	3;3-80
		3711	10-11-79	
	10 Chawandiya	3784	10-12-77	3-3-80
	11 Aranya Bassi	3784	10-12-77	3-3-80

[No. 12020/11/80-Prod.]

का०आ० 1620.—यतः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के लिए गुजरात राज्य के सलाया से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया गया है ।

और यतः इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को अनुसूची में निर्दिष्ट गांव के नाम के सामने दिखाई गई तिथि से पर्यवसित कर दिया है ।

अब यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया पर्यवसान के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

व्यधन क्षेत्र सलाया मथुरा तक पाइप लाइन संक्रिया पर्यवसान

तहसील : चाकसू जिला : जयपुर राज्य : राजस्थान

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	संक्रिया पर्यवसान की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)	1 कृपारामपुरा	3033	1-1 -77	20-2-80
	2 कीरतपुरा	3033	1-10-77	20-2-80
	3 खेजड़ीबुजर्ग	3033	1-1 -77	20-2-80
	4 श्री जयदेव पुरा	3033	1-10-77	19-2-80
	5 चादेड़ा	3033	1-10-77	19-2-80
	6 जयपुरा	3033	1-10-77	18-2-80
	7 बाड़ बागपुरा	3033	1-10-77	14-2-80
	8 रसूलपुरा	3033	1-10-77	14-2-80
	9 चाकसू	3033	1-10-77	13-2-80
		3361	25-11-78	
	10 भगवानपुरा	3033	1-10-77	12-2-80
	11 बीडपिनारपुरा	3033	1-10-77	12-2-80
	12 गुड़ला (निमोड़िया)	3033	1-10-77	11-2-80
	13 रामसिंहपुरा (गणेशपुरा)	3033	1-10-77	11-2-80
	14 रुपाहेड़ी खुर्द मय बापूगांव	3033	1-10-77	8-2-80
	15 सवाई जयसिंह पुरा	3033	1-10-77	7-2-80
	16 भगवतपुरा	3033	1-10-77	7-2-80
	17 बोदिया का बाड़ (बल्लूपुरा)	3033	1-10-77	7-2-80
	18 रमजानी पुरा	3033	1-10-77	7-2-80
	19 बांड खांद पुरा	3033	1-10-77	7-2-80
	20 रुपाहेड़ी कला	3033	1-10-77	31-1-80
	21 हरिनारायणपुरा	3033	1-10-77	31-1-80
	22 माधोपुरा	3033	1-1 -77	30-1-80
	23 महादेव पुरा	3033	1-10-77	30-1-80
	24 हिंगोटी	3033	1-10-77	30-1-80

[सं० 12020/1/80-प्रो० 1]

S.O. 1620.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act,

1962, the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the Indian Oil Corporation Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar Pradesh;

And whereas the Indian Oil Corporation Limited has terminated the operation referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on the date shown against the name of village in the schedule;

Now, therefore, under rule 4 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of the said operation.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from Salaya to Mathura

Tehsil : Chaksu District : Jaipur State : Rajasthan

Name of the Ministry	Name of the Village	S.O. No.	Date of Publication in the Gazette of India	Date of Termination
1	2	3	4	
Petroleum, Chemicals & Fertiliser (Department of Petroleum)	1 Kirparampura	3033	1-10-77	20-2-80
	2 Kiratpura	3033	1-10-77	20-2-80
	3 Khejari Bujurg	3033	1-10-77	20-2-80
	4 Shri Jaidevpura	3033	1-10-77	19-2-80
	5 Kodera	3033	1-10-77	19-2-80
	6 Jaipura	3033	1-10-77	18-2-80
	7 Barh Bagpura	3033	1-10-77	14-2-80
	8 Rasoolpura	3033	1-01-77	14-2-80
	9 Chaksu	3033	1-10-77	13-2-80
		3361	25-11-78	
	10 Bhagwanpura	3033	1-10-77	12-2-80
	11 Bid Panarpura	3033	1-10-77	12-2-80
	12 Gudala (Nimodiya)	3033	1-10-77	11-2-80
	13 Ramsinghpura (Ganeshpura)	3033	1-10-77	11-2-80
	14 Roopaheri Khurd Including Bapu Gaon	3033	1-10-77	8-2-80
	15 Sawai Jaisinghpura	3033	1-10-77	7-2-80
	16 Bhagwatpura	3033	1-10-77	7-2-80
	17 Badya Ka Barh (Ballupura)	3033	1-10-77	7-2-70
	18 Ramzanipura	3033	1-10-77	7-2-80
	19 Barh Chandpura	3033	1-10-77	7-2-80
	20 Roopahari Kalan	3033	1-10-77	31-1-80
	21 Harinarayanpura	3033	1-10-77	31-1-80
	22 Madhopura	3033	1-10-77	30-1-80
	23 Mahadeopura	3033	1-10-77	30-1-80
	24 Hingoti	3033	1-10-77	30-1-80

[No. 12020/1/80-Prod-I]

का० आ० 1621.—यतः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के लिए गुजरात राज्य के सलाया से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया गया है।

और यतः इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को अनुसूची में निर्दिष्ट गांव के नाम के सामने दिखाई गई तिथि से पर्यवसित कर दिया है।

अब यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों की अर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया पर्यवसान के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

व्यधन क्षेत्र सलाया से मथुरा तक पाइप लाइन संक्रिया पर्यवसान

तहसील : फागी जिला : जयपुर राज्य : राजस्थान

मंत्रालय का नाम	गांव	का० आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	संक्रिया पर्यवसान की तिथि
1	2	3	4	5
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)	1. मेन्दवास	3602	26-11-77	3-3-80
	2 नांगड़ा	3602	28-11-77	3-3-80
	3 केरिया	3602	26-11-77	1-3-80
	4 कर्बरपुरा	3602	26-11-77	29-2-80
	5 रतनपुरा	3602	26-11-77	28-2-80
	6 मान्दो	3602	26-11-77	28-2-80

1	2	3	4	5
	7 नथमलपुरा	3602	26-11-77	28-2-80
	8 हथेली	3602	26-11-77	28-2-80
	9 खेड़ा हनु-मानजी	3602	26-11-77	27-2-80
	10 माधोराज-पुरा	3602	26-11-77	27-2-80
	11 झरना	3602	27-11-77	27-2-80
	12 जुगलकिशोर-पुरा	3602	26-11-77	27-2-80
	13 बीची	3602	26-11-77	27-2-80
	14 भांकरोटा	3602	26-11-77	27-2-80
	15 गोपालपुरा	3602	26-11 77	23-2-80
	16 डाबिष	3602	26-11-77	22-2-80
	17 श्रीरामजीपुरा	3602	26-11-77	22-2-80 और 16-3-80

[सं० 12020/1/80-प्रो०-II)]

नरेन्द्र सिंह, सक्षम प्राधिकारी

अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए

S.O. 1621.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the Indian Oil Corporation Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar Pradesh;

And whereas the Indian Oil Corporation Limited has terminated the operation referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on the date shown against the name of village in the schedule;

Now, therefore, under rule 4 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of the said operation.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from Salaya to Mathura

Tehsil : Phagi District : Jaipur State : Rajasthan

Name of the Ministry	Name of the Village	S.O. No.	Date of Publication in the Gazette of India	Date of Termination
1	2	3	4	5
Petroleum, Chemicals & Fertiliser (Department of Petroleum)	1 Mendwas	3602	26-11-77	3-3-80
	2 Neemera	3602	26-11-77	3-3-80
	3 Keria	3602	26-11-77	1-3-80
	4 Kanwarpura	3602	26-11-77	29-2-80
	5 Ratanpura	3602	26-11-77	28-2-80
	6 Mandi	3602	26-11-77	28-2-80
	7 Nathmalpura	3602	26-11-77	28-2-80
	8 Hatheli	3602	26-11-77	28-2-80
	9 Khera Hanumanjai	3602	26-11-77	27-2-80
	10 Madhorajpura	3602	26-11-77	27-2-80
	11 Jharana	3602	26-11-77	27-2-80
	12 Jugalkishorpura	3602	26-11-77	27-2-80
	13 Beechi	3602	26-11-77	27-2-80
	14 Bhankrota	3602	26-11-77	27-2-80
	15 Goplapura	3602	26-11-77	23-2-80
	16 Davich	3602	26-11-77	22-2-80
	17 Shri Ramjipura	3602	26-11-77	22-2-80 & 16-3-80

[No. 12020/1/80-Prod-II]

NARENDRA SINGH, Competent Authority,

Under the Act for Rajasthan and Uttar Pradesh

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 2 जून, 1980

का० आ० 1622.—कोल इंडिया लिमिटेड ने जिसके अंतर्गत उसके मुख्यालय, यूनिट और सहायक कंपनियां भी हैं, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11ग की उपधारा (1) के अधीन छूट के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी कोई पृथक अंशदान या प्रीमियम का भुगतान किए बिना, उक्त स्थापन द्वारा जीवन बीमा के रूप में अपने कर्मचारियों के लिए प्रारंभ की गई लाइफ कवर स्कीम के अधीन उन फायदों का उपभोग कर रहे हैं जो ऐसे कर्मचारियों के लिए कोयला खान निक्षेप युक्त बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें आगे उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय फायदों से अधिक अनुकूल है :

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 1 जनवरी, 1979 से उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. नियोजक उक्त स्थापन के संबंध में कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद को ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा, ऐसा लेखा रखेगा और निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक प्रत्येक मास की समाप्ति से 15 दिन के भीतर ऐसे निरीक्षण प्रभारों का भुगतान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर उक्त अधिनियम की धारा 11ग की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन निर्दिष्ट करे ।

3. लाइफ कवर स्कीम के प्रशासन में हुए सभी व्यय जिनके अंतर्गत लेखा रखने, विवरणियां प्रस्तुत करने, लेखा अंकेक्षित करने, निरीक्षण प्रभारों का भुगतान आदि भी है, नियोजन द्वारा वहन किए जाएंगे ।

4. नियोजक स्थापन के सूचना बोर्ड पर (केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित) और जिस प्रकार या जैसे ही वह संशोधित की जाए, लाइफ कवर स्कीम की एक प्रति और कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी प्रमुख बातों का अनुवाद संप्रदर्शित करेगा ।

5. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक लाइफ कवर स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए लाइफ कवर स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

6. केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना लाइफ कवर स्कीम के उपबंधों का ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा जिससे कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 11ग की उपधारा (1) केन्द्र सरकार को यह अधिकार देती है कि वह कोयला खान निक्षेप युक्त बीमा स्कीम, 1976 के सभी या किसी उपबंध के प्रवर्तन से किसी खान को उस स्थिति में छूट दे जबकि वह इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी कोयला खान के कर्मचारी, कोई पृथक अंशदान या प्रीमियम का भुगतान किए बिना, उनकी भविष्य निधि की राशि से जुड़े अथवा बिना जुड़े हुए जीवन बीमा जैसे लाभ उठा रहे हैं और ऐसे लाभ उन कर्मचारियों के लिए बीमा योजना के अधीन स्वीकार्य लाभों की तुलना में अधिक अनुकूल है । कोयला खान निक्षेप युक्त बीमा योजना, 1976 के अधीन, कोयला खान भविष्य निधि के सदस्य कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर, उसकी भविष्य निधि पाने का हकदार, व्यक्ति भविष्य निधि की राशि के अलावा, उतनी राशि और पाने का हकदार होगा जो मृत व्यक्ति के भविष्य निधि खाते में पिछले तीन वर्षों में रहे औसत शेष के बराबर हो किन्तु शर्त यह है कि ऐसी राशि अधिकतम रु० 10,000 हो सकती है और साथ में यह शर्त भी है कि मृत व्यक्ति के भविष्य निधि खाते का औसत शेष रु० 1,000 से कम न हो । कोल इंडिया लि० में मालिकों और कर्मचारियों के बीच राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता (ii) 11 अगस्त, 1979 को हुआ जिसमें, अन्य बातों के साथ साथ, कोयला खान निक्षेप युक्त बीमा स्कीम के स्थान पर 1-1-1979 से कर्मचारियों के लिए लाइफ कवर स्कीम लागू करने की व्यवस्था है । उक्त स्कीम के अधीन, किसी ऐसे कर्मचारी की मृत्यु होने पर जो कोयला खान भविष्य निधि या कम्पनी की किसी अंशदायी भविष्य निधि स्कीम का सदस्य है, उसके द्वारा नामित व्यक्ति को उतनी धनराशि मिलेगी जो उसे आनुतोषिक भुगतान अधिनियम के अधीन देय राशि के साथ मिलकर उसके 20 महीने के वेतन (मूल वेतन जमा मंहगाई भत्ता) के बराबर हो—मासिक वेतन की राशि मृत सदस्य-कर्मचारी को मृत्यु के तुरंत पहले देय दर से आंकी जाएगी—किन्तु शर्त यह है कि सामान्य आनुतोषिक के अतिरिक्त देय राशि किसी भी हालत में रु० 11,000/- से कम नहीं होगी । अतः कोल इंडिया लि० ने सांविधिक निक्षेप युक्त बीमा स्कीम के प्रवर्तन से 1-1-1979 से छूट दिए जाने का अनुरोध किया है । चूंकि लाइफ कवर स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभ, निक्षेप युक्त बीमा स्कीम के लाभों की तुलना में, अधिक अनुकूल हैं इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 11ग के अधीन पिछले प्रभाव यानी 1-1-1979 से ऐसी छूट देना कोयला खान भविष्य निधि के सदस्यों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

[सं० 13(1)/80-सी० एम० डब्ल्यू० (पीएफ)]

ए० एस० देशपान्डे, उप सचिव

MINISTRY OF STEEL, MINES & COAL

(Department of Coal)

New Delhi, the 2nd June, 1980

S.O. 1622.—Whereas the Coal India Ltd. (which includes its Headquarters, units and subsidiaries) (herein-after referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (1) of section 11C of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948, (46 of 1948) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Life Cover Scheme introduced by the said establishment for its employees in the nature of life assurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11C of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme, with effect from the Ist January, 1979.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Coal Mines Provident Fund Commissioner, Dhanbad, maintain such account and provide for such facilities for inspections, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3) of Section 11C of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Life Cover Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Life Cover Scheme (as approved by the Central Government) and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Life Cover Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Life Cover Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

6. No amendment of the provisions of the Life Cover Scheme will be made, which is likely to affect adversely the interests of the employees, without approval of the Central Government.

EXPLANATORY MEMORANDUM

Sub-section (1) of Section 11C of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 empowers the Central Government to grant exemption to any coal mine from the operation of all or any of the provisions of the Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 if it is satisfied that the employees of such coal mine are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits in the nature of life assurance whether linked to their deposits in provident fund or not, and such benefits are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Insurance Scheme. Under the Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, on the death of an employee, who is the member of the Coal Mines Provident Fund, the person entitled to receive the provident Fund is also entitled to get in addition to amount of provident fund, an amount equal to the average balance in the Provident Fund account of the deceased during the preceding three years subject to a maximum of Rs. 10,000 and also subject to the condition that the average balance in the Provident Fund account of the deceased should not be less than Rs. 1000. The National Coal Wage Agreement (II) was concluded on the 11th August, 1979 between the employees and the employers of the Coal India Limited providing, inter alia, for a Life Cover Scheme for the employees in lieu of the Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme w.e.f. 1-1-79. Under the said scheme, in the event of death of any employee covered by the Coal Mines Provident Fund or any of the Company's Contributory Provident Fund Schemes, his nominee shall be paid a sum which together with the payment due to him under the Payment of Gratuity Act will be equal to 20 month's salary (Basic plus Dearness Allowance) at the rates payable immediately before the death of the member provided that the amount to be paid in addition to the normal gratuity shall not in any event be less than Rs. 11,000. The Coal India Limited has, therefore, made a request for grant of exemption from the operation of the statutory DLI Scheme w.e.f. 1-1-1979. Since the benefits available under the Life Cover Scheme are more favourable than those under the statutory Deposit Linked Insurance Scheme, grant of exemption under section 11C(1) of the Act from a retrospective date i.e. 1-1-1979 will not have any adverse effect on the members of the Coal Mines Provident Fund.

[No. 13(1)/80-CMW (PF)]
A. S. DESHPANDE, Dy. Secy.

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 मई, 1980

का० आ० 1623—बीज रहित इमली श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नियमों के उक्त प्रारूप पर उस तारीख से 45 दिन के पश्चात विचार किया जाएगा जिस तारीख को भारत के उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आपत्ति या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

(1) इन नियमों का नाम बीजरहित इमली श्रेणीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम, 1980 है।

(2) बीज रहित इमली श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1971 में :—

नियम 3 में "अनुसूची" शब्द के स्थान पर "अनुसूची 1 और 2" शब्द और अंक रखे जायेंगे।

नियम 4 में, "अनुसूची के स्तम्भ 2 से 8 तक" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "अनुसूची 1 और 2 के स्तम्भ 2 से 6 तक" शब्द और अंक रखे जायेंगे।

(3) नियम 7 में, उप नियम (1) में, खण्ड (4) के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात :

(5) कृषि विपणन सलाहकार या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्वानुमोदन से किसी अन्य किस्म के आधान में और/या आकारों में की जाएगी।

(6) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां रखी जाएंगी, अर्थात :—

अनुसूची 1

(नियम 3 और 4 देखिए)

हलके लाल से चमकीले भूरे रंग की बीजरहित इमली का श्रेणी नाम और क्वालिटी परिभाषा

श्रेणी अभिधान	विशेष लक्षण (छूट की अधिकतम सीमा)				साधारण लक्षण
	आर्द्रता प्रतिशत (भार के अनुसार)	बीजा तत्व (प्रतिशत भार के अनुसार)†	विजातीय पदार्थ प्रतिशत भार के अनुसार		
			कार्बनिक*	अकार्बनिक**	
1	2	3	4	5	6
विशेष	17.0	7.0	4.0	1.00	1. इमली का गुदा टेमेरिन्डस इंडिका के परिपक्व फल से पहले छिलके को और फिर गुदा और बीज के ऊपर की तन्तु भय झिल्ली को उतारने के बाद प्राप्त किया जाए।
क. श्रेणी	20.0	10.0	6.5	1.5	2. गुदा अच्छी तरह सुखाया जाएगा और केक के रूप में संपीडित किया जाएगा।
ख. श्रेणी	25.0	15.0	10.0	2.0	3. गुदा कीट प्रभाव से या जीवित कीट और फफूंदी से मुक्त होगा।
ग. श्रेणी	30.0	25.0	13.0	2.0	4. केक हलके लाल से चमकीले भूरे रंग का होगा।
अविनिर्दिष्ट	—	—	—	—	5. गुदे में इमली का ही विशिष्ट स्वाद और गंध होगी और वह किसी भी प्रकार की दुर्गन्ध से मुक्त होगा।

*कार्बनिक—विजातीय पदार्थ के अंतर्गत फल के अन्य भाग, जैसे—रेशे, तन्तु और छिलके होंगे।

**अकार्बनिक—विजातीय पदार्थ से पत्थर, गर्द, धूल और अकार्बनिक प्रकृति का कोई अन्य विजातीय पदार्थ अभिप्रेत है।

†अविनिर्दिष्ट श्रेणी किसी विदेशी क्रेता द्वारा वांछित उपज की मात्रा और क्वालिटी उपदर्शित करते हुए उसके "विनिर्दिष्ट आदेश" के लिए ही अनुज्ञात की जाएगी।

नमक : बीज रहित इमली में यदि नमक तत्व मौजूद है तो वह 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

अनुसूची 2

काले रंग की बीज रहित इमली का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी परिभाषा

श्रेणी अभिधान	विशेष लक्षण (छूट की अधिकतम सीमा)				साधारण लक्षण
	नमी (प्रतिशत भार के अनुसार)	बीज तत्व (प्रतिशत भार के अनुसार)†	विजातीय पदार्थ (प्रतिशत भार के अनुसार)		
			कार्बनिक*	अकार्बनिक**	
1	2	3	4	5	6
विशेष काली	17.0	7.0	4.0	1.0	1. इमली का गुदा टेमेरिंडस इंडिका के परिपक्व फल से पहले छिलके को और फिर गुदे और बीज के ऊपर की तन्तु भय झिल्ली को उतारने के बाद प्राप्त किया जाएगा।
क. श्रेणी काली	20.0	10.0	6.5	1.5	2. गुदा अच्छी तरह सुखाया जाएगा और केक के रूप में संपीडित किया जाएगा।
ख. श्रेणी काली	25.0	15.0	10.0	2.0	3. गुदा कीट प्रभाव से या जीवित कीट और फफूंदी से मुक्त होगा।
ग. श्रेणी काली	30.0	25.0	13.0	2.0	4. केक हलके से गाढ़े काले रंग का होगा।
					5. गुदे में इमली का ही विशिष्ट स्वाद और गंध होगी और वह किसी भी प्रकार की दुर्गन्ध से मुक्त होगा।

*कार्बनिक–विजातीय पदार्थ के अंतर्गत फल के अन्य भाग, जैसे, रेशे, तन्तु और छिलके होंगे।

**अकार्बनिक–विजातीय पदार्थ से पत्थर, गर्द, धूल और अकार्बनिक प्रकृति का कोई अन्य विजातीय पदार्थ अभिप्रेत है।

†अविनिर्दिष्ट श्रेणी किसी विदेशी क्रेता द्वारा वांछित उपज की मात्रा और क्वालिटी उपदर्शित करते हुए उसके "विनिर्दिष्ट आदेश" के लिए ही अनुज्ञात की जाएगी।

बीज रहित इमली में यदि नमक तत्व मौजूद है तो वह 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।"

[सं० 10-3/79-ए एम]

के०एल० गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION

New Delhi, the 29th May, 1980

S O **1623**.—The following draft rules, further to amend the Seedless Tarmarind Grading and MarkingRules, 1971, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), are hereby published, as required by the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after 45 days from the date on which the copies of Gazette of India in which this notification is published are made available to the public.

Any objections or suggestions received from any person with respect to the said draft rules, before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1 These rules may be called the Seedless Tamarind Grading and Marking (Amendment) Rules, 1980

2 In the Seedless Tamarind Grading and Marking Rules, 1971—

(i) in rule 3, for the word "Schedule" the words and figures,— Schedule I and II" shall be substituted

(ii) in rule 4, the words and figures "2 to 8 of the schedule" the words and figures "2 to 6 of the Schedules I and II" shall be substituted

(iii) in rule 7, in sub-rule (1) , after clause (iv) the following shall be added , namely —

"(v) in any other types of container and/or sizes with the prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this regard "

(iv) for the Schedule, the following Schedules shall be substituted, namely —

SCHEDULE I

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of Seedless Tamarind, Light Red to Tinged Brown Colour

Grade designation	Special Characteristics (Maximum limit of tolerance)				General Characteristics
	Moisture (per cent by weight)	Seed content (per cent by weight)	Foreign matter (per cent by weight)		
			*Organic	Inorganic**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Special	17 0	7 0	4 0	1 0	1 The Tamarind pulp shall have been obtained from the mature fruits of Tamarindus Indica, by removing first the rind and then the fibrous skeleton enclosing the pulp and the seeds.
A Grade	20 0	10 0	6 5	1 5	
B Grade	25 0	15 0	10 0	2 0	
C Grade	30 0	25 0	13 0	2 0	
Non-specified	.				2 The pulp shall be well dried and compressed into cakes.
					3. The pulp shall be free from insect infestation or live insects and mould.
					4. The colour of the cake shall be light red to tinged brown
					5 The pulp shall have the characteristic taste and flavour and shall be free from any obnoxious odour.

Organic—Foreign matter will consist of other parts of fruit such as fibre strand and rind

Inorganic—Foreign matter means stones, dust, dirt and any other foreign material of inorganic nature.

Non-specified Grade shall be allowed only against a "specific order" from the foreign buyer indicating the quantity and quality of the produce desired.

Salt : Salt content in seedless Tamarind, if present, shall not exceed 2%

SCHEDULE II

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of Seedless Tamarind, Black colour

Grade designation	Special Characteristics (Maximum limit of tolerance)				General characteristics
	Moisture (per cent by weight)	Seed content (per cent by weight)	Foreign matter (per cent by weight)		
			Organic*	Inorganic**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Special Black	17.0	7.0	4.0	1.0	1. The Tamarind pulp shall have been obtained from the mature fruits of Tamarindus Indica, by removing first the rind and then the fibrous skeleton enclosing the pulp and the seeds.
A Grade-Black	20.0	10.0	6.5	1.5	
B Grade-Black	25.0	15.0	10.0	2.0	
C Grade-Black	30.0	25.0	13.0	2.0	
Non-Specified†	..	..	..	..	2. The pulp shall be well dried and compressed into cakes.
					3. The pulp shall be free from infestaion or live insects and mould.
					4. The colour of cake shall be light to Dark black.
					5. The pulp shall have the characteristic taste and flavour and shall be free from any obnoxious odour.

*Organic—Foreign matter will consist of other parts of the fruit such as fibre strand and rind.

**Inorganic—Foreign matter means stones, dust, dirt and any other foreign material of inorganic nature.

†Non-specified Grade shall be allowed only against a specific order from the foreign buyer indicating the quality and quantity of the produce desired.

Salt: The salt content in seedless tamarind, if present, shall not exceed 2%.

[No. F-10-3/79-AM]
K.L. GUPTA, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 28 मई, 1980

का० आ० 1624—चूंकि यह समझा जाता है कि श्री पी० डी० गांधी ने जिन्हें भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का० आ० 2100, दिनांक 21 जून, 1975 के तहत कांडला डाक लेबर बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया था, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1962 के नियम 4 के उप नियम (5) के खंड (iv) के अधीन उक्त पद को छोड़ दिया है,

और चूंकि, इसके परिणामस्वरूप उक्त डाक लेबर में एक पद रिक्त हो गया है,

इसलिए, अब, उक्त नियमों के नियम 4 में दी गई व्यवस्था के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना द्वारा उक्त रिक्त पद को अधिसूचित करती है।

[फा० संख्या-एल० डी० के०/4/80-एल० 3]
एस० एन० ककड़, निदेशक

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 28th May, 1980

S.O. 1624.—Whereas Shri P. D. Gandhi was appointed as a member of the Kandla Dock Labour Board by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2100, dated the 21st June, 1975;

And whereas he is deemed to have vacated his office under clause (iv) of sub-rule (5) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962;

And whereas a vacancy has consequently occurred in the said Dock Labour Board;

Now, therefore, in pursuance of the provision of rule 4 of the said rules, the Central Government hereby notifies the said vacancy.

[F. No. LDK/4/80-LIII]
S. N. KAKAR, Director

नई दिल्ली, 4 जून, 1980

का० आ० 1625—दिल्ली परिवहन निगम (सदस्य) नियम, 1973 के नियम 3 के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम,

1950 (1950 का 64) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के द्वारा श्री यशवन्त सिन्हा, संयुक्त सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय को 4 जून, 1980 से दिल्ली परिवहन निगम का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का० आ० 258(अ) दिनांक 1 मई, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में मद संख्या (iii) में निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी :—

"श्री यशवन्त सिन्हा

संयुक्त सचिव,

नौवहन और परिवहन मंत्रालय"

[फा० सं० टी जी डी (9)/79]

सुदर्शन वसुदेव, उप सचिव

New Delhi, the 4th June, 1980

S.O. 1625.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), read with rule 3 of the Delhi Transport Corporation (Members) Rules, 1973, the Central Government hereby appoints Shri Yashwant Sinha, Joint Secretary, Ministry of Shipping and Transport as a member of the Delhi Transport Corporation with effect from 4th June, 1980 and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport wing) No. S.O. 258(E) dated the 1st May, 1979, namely :—

In the said notifications in para 1 against the item (iii), the following shall be inserted :

"Shri Yashwant Sinha, Joint Secretary, Ministry of Shippingn and Transport"

[F. No. TGD(9)/79]

S. VASUDEV, Dy. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 मई, 1980

का०आ० 1626—चलचित्र (सेंसर) नियमावली, 1958 के नियम 10 साथ पठित चलचित्र अधिनियम 1952 (1952 का 37वां) की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी अनुभाग अधिकारी और ग्रेड -1 के स्थानापन्न अधिकारी श्री एस० रामास्वामी की स्थानापन्न अपर प्रादेशिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, मद्रास, के रूप में नियुक्ति की अवधि को 18-7-79 से अगले आदेश तक प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर बढ़ाती है।

[फा० सं० 802/18/79/एफ० सी०]

के०एस० वेंकटरामन, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 31st May, 1980

S.O. 1626.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), read with rule 10 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government is pleased to extend the appointment of Shri S. Ramaswamy, a permanent Section Officer and officiating Grade I officer of the Central Secretariat Service, as officiating Additional Regional Officer, Central Board of Film Censors, Madras, on usual deputation terms with effect from 18-7-79 until further orders.

[F. No. 802/18/79-FC]

K. S. VENKATARAMAN, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1980

का० का० 1627.—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस०ओ० 3792, दिनांक 2 दिसम्बर 1968 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबंध के अंतर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद एतद्द्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम सं०	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई (मीटरों मे)	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार या सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाक्युमेंट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1638 (राष्ट्रीय)	206.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई-26		"समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)
2.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1638 (उत्तर)	272.00	-तदेव-		"समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)
3.	भारतीय समाचार चित्र समाचार मैगजीन संख्या 3 (डे आफ दि डार्क सन) (रंगीन)	299.00	-तदेव-		"समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म। (सामान्य प्रदर्शन के लिए)

1 2	3	4	5	6
4. कंठमाला	219.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई-26		"शिक्षा संबंधी" फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)
5. महाराष्ट्र समाचार संख्या 342	246.28	सूचना महानिदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेंटर, 68, तारदेव रोड, बम्बई 400034		"समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म (महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
6. मध्य प्रदेश समाचार वर्णन संख्या 23	250.00	सूचना और प्रचार सहायक निदेशक, मध्य प्रदेश सरकार भोपाल		"सहायक और सामयिक घटनाओं" की फिल्म। (मध्य प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन के लिए)।
7. अनमोल पानी	365.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24, पैडर रोड, बम्बई-400026		"शिक्षा संबंधी" फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)।
8. भारतीय समाचार चित्र संख्या 1639 (राष्ट्रीय)	212.00	-तदेव-		"समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)
9. भारतीय समाचार चित्र संख्या 1639 (पूर्वी)	264.00	-तदेव-		तदेव (पूर्वी सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
10. काम के बदले अनाज	210.05	-तदेव-		"डाक्युमेंट्री" फिल्म (सामान्य प्रदर्शन ले लिए।
11. जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा	218.00	-तदेव-		-तदेव-
12. आफ हिल्स फ्रूटस एण्ड मैल्लो फ्रूटफुलनेस मैल्लो फूट लैस	336.00	-तदेव- श्रीमती द्वारका देव	फिल्म प्रभाग 4, टालस्टाय मार्क नई दिल्ली 1	-तदेव-
13. औशन पर्ल्ज	312.12	नवीन फिल्मस फिल्मालय सीजर रोड, एन्धोली, अंधेरी, बम्बई, 400058		
14. कापर		मैसर्स सोनिको 16/35ए, घोरे-श्वर धोले लैन, 52-6194 (कलकत्ता 35)	फिल्म प्रभाग, 24, पैडर रोड, बम्बई 26	-तदेव-
15. भारतीय समाचार चित्र संख्या 1640 (राष्ट्रीय)	245.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई-26		"समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)
16. तदेव (दक्षिण)	293.00	-तदेव-		-तदेव- (दक्षिण सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
17. रूप का गहना (रंगीन)	45.00	-तदेव-		राष्ट्रीय (सामान्य प्रदर्शन के लिए)
18. दलदल	560.50	फिल्म प्रभाग, 24, पैडर रोड, बम्बई-26	मैसर्स दुर्गा खोटे प्रोडक्शंस, बम्बई	"डाक्युमेंट्री" फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)
19. फोल्क डांसिज आफ गोवा (रंगीन)	448.66	-तदेव-	श्री जे०एस० भाण्डेकर, बम्बई	-तदेव-
20. समाचार-72	288.04	श्री धीरेन्द्र पाण्डे, समाचार चित्र निर्माता, सूचना और जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।		"समाचार और सामयिक घटनाओं" का फिल्म (उत्तर प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
21. माहिती चित्र संख्या 320	237.74	सूचना सहायक निदेशक, गुजरात सरकार, धनराज महल छत्रपति शिवाजी मार्ग, बम्बई-29	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, सचिवालय, ब्लाक नं० 7, गांधी नगर-382010	-तदेव- (गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
22. हौम्योपैथी दि ह्यूमन मैडीसन (रंगीन)	294.50	हरीश कुमार पी० पटेल, डी/5, लैनसे काटेज, बोरी-वाली (पूर्व) बम्बई-400066		"डाक्युमेंट्री" फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)
23. *दे काल मी चमार	511.00	फिल्म प्रभाग, 24, पैडर रोड, बम्बई-400026		"डाक्युमेंट्री" फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)

1	2	3	4	5	6
24.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1641 (राष्ट्रीय)	201.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई-26		"समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)
25.	भारतीय समाचार चित्र सं० 1641 (पश्चिम)	301.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई-26		"समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म (पश्चिम सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
26.	शहर पहियों पर	267.00	-तथैव-		"डाकुमेंट्री" फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)
27.	नई बस्तियां	399.00	-तथैव-		-तथैव-
28.	उनके विकास के लिए	267.00	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-400026	मैसर्स विदेश सरकार प्रोडक्शन, कलकत्ता	"डाकुमेंट्री" फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)
29.	फार दि गुड श्राफ श्रस श्राल	260.00	फिल्म प्रभाग, 24, पैडर रोड, बम्बई-400026	श्री सुरेन्द्र सिंह, बम्बई	-तथैव-
30.	हमारे टेंक मैन (रंगीन)	384.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई-26		-तथैव-
31.	बचत का आनन्द (रंगीन)	185.00	-तथैव-		-तथैव-
32.	धन दिन दिन बढ़ता जाए (रंगीन)	148.00	-तथैव-		-तथैव-
33.	उनके लिए ..... (रंगीन)	122.00	-तथैव-		-तथैव-
34.	माहिती चित्र संख्या 321	274.32	सूचना सहायक निदेशक, गुजरात सरकार, धनराज महल, भूमितल, छत्रपति शिवाजी मार्ग, बम्बई-20	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, सचिवालय, गांधी नगर	"समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म (गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
35.	उत्तर प्रदेश समाचार 73	286.51	धीरेन्द्र पाण्डे मार्फत बम्बई फिल्म लेबा० (प्रा०) लि० दादर, बम्बई-400028	धीरेन्द्र पाण्डे समाचार चित्र निर्माता सूचना और जन संपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	
36.	महाराष्ट्र समाचार संख्या 343	270.00	सूचना महानिदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेंटर, 68, तारदेव रोड, बम्बई-34		"समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म (महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
37.	हमारा पंचायत	335.28	-तथैव- .		"डाकुमेंट्री" फिल्म (महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
38.	आदत बुरी बला	257.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई-26		"डाकुमेंट्री" फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)
39.	बवधू	442.57	-तथैव-		-तथैव-
40.	परजीवी	373.00	-तथैव-		-तथैव-
41.	मौन प्रहरी (रंगीन)	285.00	-तथैव-		-तथैव-
42.	पापी का वरदान	197.00	-तथैव-		-तथैव-
43.	विश्व व्यापार आकर्षण	259.00	-तथैव-		-तथैव-
44.	छत्तीसगढ़	350.00	-तथैव-		-तथैव-
45.	जो आग से लड़ते हैं		-तथैव-		-तथैव-
46.	आपका डाक टिकट	363.00	फिल्म प्रभाग, 24, पैडर रोड, बम्बई-26	फिल्म प्रभाग 4, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली	तथैव-
47.	पोषण से स्वास्थ्य	262.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई-26		-तथैव-
48.	बिन्दु में सिन्धु (रंगीन)	355.00	फिल्म प्रभाग, 24, पैडर रोड, बम्बई-26	श्री श्रोम प्रकाश अरोड़ा, अरोड़ा फिल्म्स, बम्बई	-तथैव-
49.	कलैवर पीपल	116.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई-26		-तथैव-
50.	काम भी बचत भी	198.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, पैडर रोड बम्बई-26		"डाकुमेंट्री" फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)
51.	मझधार की मीन	504.00	-तथैव-		-तथैव-
52.	बाल विकासयोजना	327.00	-तथैव-		-तथैव-
53.	चार चेहरे	356.00	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-26	मैसर्स सरैया प्रोडक्शंस, बम्बई	-तथैव-

1	2	3	4	5	6
54.	संत और शिल्पकार	300.00	श्री सुनील घोष ई-5 कुर्ला राजनरोड, हम्बल होम, बांदरा, बम्बई	श्री ए.बी मरन, के०वी०आई० सी०, इर्ना, बम्बई	"डाकुमेंट्री" फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)
55.	भारत समाचार चित्र संख्या 1642 (राष्ट्रीय)	238.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26		"समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)
56.	-तथैव- (उत्तरी)	296.00	-तथैव-		"समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म (उत्तरी सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
57.	दि मैजिक आफ फेथ (रंगीन)	303.58	सूचना और जनसंपर्क महा-निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेंटर, 68-तारदेव रोड, बम्बई-34		"डाकुमेंट्री" फिल्म (महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
58.	सूखे का सामना	274.32	धीरेन्द्र पाण्डे, समाचार चित्र निर्माता, सूचना और जन-संपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ-1		"डाकुमेंट्री" फिल्म (उत्तर प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
59.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1643 (राष्ट्रीय)	213.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई-26		"समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म (पूर्वी सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
60.	-तथैव- (पूर्वी)	302.00	-तथैव-		-तथैव-
61.	ए लैम्प अनटू आर्ट	584.91	सूचना और जन संपर्क महा-निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेंटर, 68, तारदेव रोड, बम्बई-400034		"डाकुमेंट्री" फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)
62.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1644 (राष्ट्रीय)	192.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26		"समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)
63.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1644 (दक्षिण)	264.00	-तथैव-		"समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म (दक्षिण सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
64.	माहिती चित्र संख्या 322	192.02	सूचना सहायक निदेशक, मार्फत रमनों आर० लेबा० लि० 77, ऐनी बीसेंट रोड, वर्ली, बम्बई-18	सूचना निदेशक गुजरात सरकार, सचिवालय, गांधी नगर	"समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म (गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
65.	**दि मैजिक आफ फेथ (रंगीन)	303.58	सूचना और जनसंपर्क महा-निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेंटर, 68 तारदेव रोड, बम्बई-400034		"डाकुमेंट्री" फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)
66.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1645 (राष्ट्रीय)	287.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई-26		"समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)
67.	उत्तर प्रदेश समाचार 74	288.32	धीरेन्द्र पाण्डे, समाचार चित्र निर्माता, सूचना और जन संपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ		-तथैव- (उत्तर प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
68.	बिजली के प्रयोग में साव-धानी (रंगीन)	299.31	बालकृष्ण कुलकर्णी, 7, सी फेस, 126-ए, वीर सावरकार मार्ग, महिम, बम्बई 400016		"शिक्षा संबंधी" फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)
69.	शिवाजी महाराज की 300वीं पुण्य तिथि	298.00	सूचना और जनसंपर्क महानि-देशालय, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेंटर, 68, तारदेव रोड, बम्बई-34		"समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म (महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिए)।
70.	कोका वाजतो वाजतो	303.58	-तथैव-		"डाकुमेंट्री" फिल्म (महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिए)

1 2	3	4	5	6
71. मधुमेह से बचिए	228.60	श्री पी० किशोर, मालिक, किशोर पिक्चर्स, नटराज स्टूडियो अंधेरी (पूर्व), बम्बई-400069		शिक्षा संबंधी" फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)
72. स्टाप क्राइम		श्री अनिल बाजपेयी, 50, सोनबाई सदन, बाजार रोड, बांदरा, बम्बई-400050		"डाकुमेंट्री" फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)
73. एक बहन (रंगीन)	255.42	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई-26		-तथैव-
74. फारगेट अस नाट (रंगीन)	273.00	-तथैव-	फिल्म प्रभाग, 4, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली	-तथैव-
75. पूर्वश्री (रंगीन)	447.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26		-तथैव-
76. जरा धीमे (रंगीन)	143.00	-तथैव-		-तथैव-
77. हुसेन (रंगीन)	475.00	-तथैव-		-तथैव-
78. खुजली	212.00	-तथैव-		-तथैव-

[फा०सं० 315/1/80-एफ (पी)]
अर्जुन देव मलिक, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 3rd June, 1980

ORDER

S.O.1627 —In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information & Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length of the Film (in metres)	Name of the applicant	Name of the Producer	Brief whether a Synopsis Scientific Film or for Educational purpose or a film dealing with news current events or documentary fil .
1	2	3	4	5	6
1.	Indian News Review No. 1638 (National)	206.00	Films Division, Govt. of India 24-Peddar Road, Bombay-26.		News and Current Events (General Release)
2.	Indian News Review No. 1638 (North)	272.00	-do-		News and Current Events (General Release).
3.	Inr News Magazine No. 3 (Day of the Dark Sun) (Colour)	299.00	-do-		News and Current Events (General Release)
4.	Prevention of Goitre .	219.00	-do-		Educational (General Release).
5.	Maharashtra News No. 342.	246.28	Directorate General of Information Govt. of Maharashtra, film Centre, 68-Tardeo Road Bombay-34.		News and Current Events (Release in Maharashtra circuit.
6.	Madhya Pradesh Samachar Darshan No. 23.	250.00	Asstt. Director Information & Publicity, Govt., of M.P., Bhopal.		News and Current Events' (Release in Madhya Pradesh circuit.
7.	Precious Water . .	365.00	Films Division, Govt. of India 24-Peddar Road, Bombay-400026.		Educational General release.

1	2	3	4	5	6
8.	Indian News Review No. 1639 (National).	212.00	Films Division, Govt. of India	24-Peddar Road, Bombay-26.	News and Current Events (General release).
9.	Indian News Review No. 1639 (Eastern).	264.00	-do-		News and Current Events (Release in Eastern Circuit
10.	Food for Work . .	210.05	-do-		Documentary (General) release.
11.	Reading the World .	218.00	-do-		Documentary General release.
12.	Of Hills Fruits & Mellow Fruitfulness.	336.00	Films Div. 24-Peddar Road, Bombay-26.	Films Div. 4-Tolstoy Marg, New Delhi.	Documentary General release.
13.	Ocean Pearls	312.12	Smt. Dwarka Deo, Naveen Films Filmalay, Censor Road, Amboli, Andheri, Bombay-400058.		'Documentary' General release.
14.	Copper		M/s Sceneco 16/3-A Bireswar Dhole Lane 52-6194 (Calcutta 35).	Films Div. 24-Peddar Road Bomay-26.	'Documentary' General release.
15.	Indian News Review No. 1640 (National).	245.00	Films Div. Govt. of India	24-Peddar Road, Bombay-26.	News & Current Events (General Release)
16.	Indian News Review No. 1640 (Southern)	293.00	-do-		News and Current Events (Release in Southern circuit.)
17.	Roop Ka Gahana (colour)	45.00	-do-		Educational (General) release.
18	Quicksand	560.50	Films Div. 24-Peddar Road Bombay-26.	M/s. Durgakhote Productions, Bombay.	Documentary (General) Release.
19.	Folk Dances of Goa (Colour).	448.66	do.	Shri J. S. Bhandekar Bombay.	Documentary (General) Release.
20.	Uttar Pradesh Samachar 72.	288.04	Shri Dhirendra Pande, Pro- & Public Relations Deptt.	ducer Newsreels Information Uttar Pradesh, Lucknow.	'News and Current Events (Release in U.P. circuit) .
21.	Mahitichitra No. 320	237.74	Asstt. Director of Information, Govt. of Gujarat Dhanraj Mahal, Ground Floor, Chh. Shivaji Marg, Bombay-29.	Director of Information Govt. of Gujarat Sachivalaya Block No. 7 Ghandinagar-382010.	'News and Current Events, (Release in Gujarat circuit.)
22.	Homoeopathy the Humane Medicine (colour)	294.00	Harish Kumar P. Patel, (East) Bombay-400 066.	D/5 Nensey Cottage, Borivali	'Documentary' Genera Release.
23.	*They Call me Chamar	511.00	Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-400 006.		'Documentary' General Release.
24.	Indian News Review No. 1641 (National)	201.00	Films Division, Govt. of India,	24-Peddar Road, Bombay-26.	News and Current Events (General Release).
25.	Indian News Review No. 1641 (Western)	301.00	-do-		News and Current Events (Release in Western circuit).
26.	A city on wheels	267.00	-do-		Documentary General Release.
27	Better Homes	399.00	-do-		Documentary General Release.
28.	For them to Bloom	267.00	Films Division 24-Peddar Road, Bombay-400026.	M/s. Bidesh Sarkar Productions, Calcutta.	Documentary General Release.
29.	For the Good of us all	260.00	-do-	Shri Surender Singh, Bombay.	Documentary General Release.
30.	Our Tankmen (Colour)	384.00	Films Div. Govt. of India,	24-Peddar Road, Bombay-26.	Documentary General Release.
31.	Joy in Saving (Colour)	185.00	-do-		Documentary General Release.
32.	Fortune Maker (Colour)	148.00	-do-		Documentary General Release.
33.	His.....(Colour)	122.00	-do-		Documentary General Release.
34.	Mahitichitra No. 321	274.32	Asstt. Director of Information, Govt. of Gujarat Dhanraj Mahal, Ground Floor, Chh. Shivaji Marg, Maharaj, Bombay-20.	Director of Information, Govt. of Gujarat Sachivalaya, Gandhi Nagar.	News and Current Events (Release in Gujarat circuit)

1	2	3	4	5
35.	Uttar Pradesh Samachar 73	286.51	Dhirendra Pande C/o Bombay Film Law (P) Ltd. Dadar, Bombay-400 028.	Dhirendra Pande Producer Newsreels Information & Public Relations Deptt. U. P.	News and Currents Events (Release Lucknow).
36.	Maharashtra News No. 343	270.00	Directorate General of Information, Government of Maharashtra, Film Centre, 68-Tardeo Road, Bombay-34.		News and Current Events (Release in Maharashtra circuit).
37.	Hamal Panchayat	335.28	Directorate General of Information Government of Maharashtra, Film Centre, 68-Tardeo Road, Bombay-34.		Documentary Release in Maharashtra circuit.
38.	Habits Die Hard	257.00	Films Div., Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Documentary General Release.
39.	Stinking Story	442.57	-do-		-do-
40.	The Parasities	373.00	-do-		Documentary General Release.
41.	The Silent Arm (Colour)	285.00	-do-		-do-
42.	Harnessing the Tapi	197.00	-do-		-do-
43.	Shop Window to the World.	259.00	-do-		-do-
44.	Chhatisgarh	350.00	-do-		-do-
45.	The Fire Fighters		-do-		-do-
46.	Your Postage Stamp	363.00	Films Division 24-Paddar Road Bombay-26.	Films Div. 4-Tolstoy Marg, New Delhi.	-do-
47.	Nutrition for Health	262.00	Films Div. Govt. of India 24-Peddar Road, Bombay-26.		-do-
48.	The Drop That Counts (Colour)	355.00	Films Div. 24-Peddar, Bombay.	Shri Prakash Arora, Arora Films, Bombay.	-do-
49.	Clever People	116.00	Films Div., Govt. of India 24-Peddar Road, Bombay-26.		-do-
50.	They Serve, They Save	198.00	-do-		do-
51.	Waves and Shores	504.00	-do-		-do-
52.	For Mother and Child	327.00	-do-		-do-
53.	Four Faces	356.00	Films Div. 24-Peddar Road Bombay.	M/s. Saraiya Productions Bombay.	-do-
54.	Saints and Craftsman	300.00	Shri Sunil Ghose, E-5 Hurly Rajan Road, Humble Home Bandra, Bombay.	Shri A. B. Saran KVIC. IRLA Bombay.	Documentary General Release.
55.	Indian News Review No. 1642 (National)	238.00	Films Div. Govt. of India 24-Peddar Road, Bombay-26.		News and Current Events (General Release).
56.	Indian News Review No. 1642 (Northern)	296.00	-do-		News and Currente Events (Release in Northern circuit.
57.	The Magic of Faith (Colour)	303.58	Directorate General of Inf. & Public Relations, Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68-Tardeo Road, Bombay-400 034.		Documentary Release in Maharashtra circuit.
58.	Sookhe-Ka-Saamna	274.32	Dhirendra Pande, Producer Newsreels, Information and Public Relations Deptt., U. P. Lucknow.		Documentary Release in U. P. circuit.
59.	Indian News Review No. 1643 (National)	213.00	Films Div. of Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		News and Current Events (Release in Eastern circuit).
60.	Indian News Review No. 1643 (Eastern)	302.00	-do-		News and Current Events (Release in Eastern circuit).
61.	A Lamp Unto Art	584.91	Directorate General of Inf. & Public Relations, Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68-Tardeo Road, Bombay-400 034.		Documentary General Release.
62.	Indlan News Review No. 1644 (National)	192.00	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		News and Current Events (General Release).
63.	Indian News Review No. 1644 (Southern)	264.00	Films Division, Govt. of India 24-Peddar Road Bombay-400 026.		News and Currents Events (Release in Sourthern Circuit)
64.	Mahitichitra No. 322	192.02	Asstt. Director of Information C/o Ramnor R. Lab. Ltd., M77, Annie Besant Road, Worl Bombay-18.	Director of Information Govt. of Gujarat Sachivalaya, Gandhi Nagar-10.	News and Current Events. Release in Gujarat Circuit.)
65.*	*Magic of Faith (Colour)	303.58	Directorate General of Inf. & Public Relations, Govt. of Maharashtra Film Centre, 68 Tardeo Road, Bombay-400 034.		Documentary General Release.

1	2	3	4	5	6
66.	Indian News Review No. 1645 (National)	287 00	Films Division, Govt. of India, 24-P oddar Road, Bombay-26.		'News and Current Events' (General Release).
67.	Uttar Pradesh Samachar 74	288.32	Dhirendra Pande, Producer Newsreels, Information & Public Relations Deptt. U. P. Lucknow.		'News and Current Events' (Release in U. P. circuit).
68.	Safety in the Use of Electricity (colour)	299.31	Balkrishna Kulkarani, 7 Seaface 126-A, Veer Savarkar Marg, Mahim, Bombay-400016.		Educational (General Release).
69.	Shivrayachi Aathvava Pratap	298.00	Directorate General of Inf. & Public Relations, Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68 Tardeo Road, Bombay-34.		'News and Current Events' (Release in Maharashtra circuit)
70.	Yoka Wajto Wajto	303.58	-do-		'Documentary' (Release in Maharashtra circuit).
71.	Madhu Meh Se Bachiye	228 60	Shri P. Krishore, Prop. Kishore Pictures, Natraj Studio Andheri (East) Bombay-400069.		'Educational' General Release.
72.	Stop Crime		Shri Anil Bajpai 50, Sonbai Sadan, Bazar Road, Bandra Bombay-400050.		'Documentary' General Release.
73.	Ek Bahen (Colour)	255.42	Film Div., Govt. of India, 24-Poddar Road, Bombay-26.		'Documentary' General Release.
74.	Forget us not (Colour)	273.00	-do-	Films Div. 4-Tolstoy Marg, New Delhi.	'Documentary' General Release.
75.	Rhythms of Eastern Region (Colour)	447.00	Films Div., Govt. of India, 24-Poddar Road, Bombay-26.		'Documentary' General Release.
76.	Go Slow (Colour)	143.00	-do-		'Documentary' General Release.
77.	Husain (Colour)	475.00	-do-		'Documentary' General Release.
78.	Scabies	212.00	-do-		'Documentary' General Release.

[File No. 315/1/80-F(P)]

A. D. MALIK, Desk Officer.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 19 मई, 1980

का०आ० 1628.— निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 55 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 16 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग हरियाणा राज्य में स्थित निष्क्रान्त सम्पत्तियों तथा भूमियों के संबंध में श्री वी० पी० जोहर, वित्त आयुक्त, राजस्व, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ द्वारा भी किया जाएगा और उन्हें धारा 16 के अधीन आवेदन स्वीकार करने तथा उनके निपटान के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है।

2. जहां तक हरियाणा राज्य का संबंध है, इसके द्वारा का०आ० 55, दिनांक 10/14 दिसम्बर, 1970 द्वारा जारी की गई अधिसूचना का अतिक्रमण किया जाता है।

[संख्या 1(14)/विशेष सेल/75-एस०एस० II]

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 19th May, 1980

S.O. 1628.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 55 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under Section 16 of the said Act, shall be exercised also by Shri V. P. Johar, Financial Commissioner, Revenue, Government of Haryana, Chandigarh in respect of evacuee properties and lands situated in the State and he shall also be authorised to admit and dispose of application under Section 16.

2. This supersedes the Notification issued vide S.O. 55 dated 10th/14th December, 1970, in so far as Haryana State is concerned.

[No. 1(14)/Spl. Cell/75-SS.II]

नई दिल्ली, 28 मई, 1980

का०आ० 1629.—निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) अधिनियम, 1951 (1951 का LXIV) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा दिल्ली के वरिष्ठ उपन्यायाधीश श्री के०पी० वर्मा को, उनके कार्यभार के अतिरिक्त, उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिए गए कार्यों का निष्पादन तथा शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० 14(6)/77-एस०एस० II]

एन० एम० वाधवानी, अवर सचिव

New Delhi, the 28th May, 1980

S.O. 1629.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 4 of the Evacuee Interest (Separation) Act, 1951 (LXIV of 1951), the Central Government hereby appoints Shri K. P. Verma, Senior Sub-Judge, Delhi, as Competent Officer for the Union Territory of Delhi for the purpose of performing, in addition to his own duties, the functions and exercising the powers assigned to him under the said Act.

[No. 14(6)/77-SS. II]

N. M. WADHWANI, Under Secy.

संचार मंत्रालय
(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 30 मई, 1980

का० आ० 1630—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 34 के साथ पठित नियम 9 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खंड (ख) और नियम 29 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के संचार मंत्रालय (डाक तार) की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 620, तारीख 28 फरवरी, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, भाग-II साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग III में, "टेलीफोन जिले और टेलीफोन जिलों के उप प्रभाग" शीर्षक के अधीन स्तंभ 1 में वर्णित "कार्यालय अधीक्षक" प्रविष्टि के सामने स्तंभ 3, 4 और 5 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

3	4	5
"टेलीफोन जिले का प्रधान	सभी	सदस्य, डाकतार बोर्ड
उप महाप्रबंधक	(1) से (4) तक	टेलीफोन जिले का प्रधान"

[सं० 152/11/77-डिस० II]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(P&T Board)

New Delhi, the 30th May, 1980

S.O. 1630.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12, and sub-rule (1) of rule 24 read with rule 34 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following further amendment in the notification of the Govt. of India in the Ministry of Communications (Posts and Telegraphs) No. S.R.O. 620 dated the 28th February, 1976, namely:—

In the Schedule to the said notification in Part-II General Central Service, Class III, under the heading "Telephone Districts and Sub-Division of Telephone Districts" against Office Supdt. appearing in column 1, for the entries in columns 3, 4 and 5, the following entries shall be substituted, namely :—

3	4	5
"Head of the Telephone District.	All	Member, Posts and Telegraphs Board.
Deputy General Manager.	(i) to (iv)	Head of Telephone District"

[No. 152/11/77-Disc.II]

आदेश

नई दिल्ली, 31 मई, 1980

का०आ० 1631.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधीक्षक, केन्द्रीय तारघर, सिकन्दराबाद द्वारा पारित दण्डादेशों के सम्बन्ध में निदेशक, दूर संचार को अपील प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करते हैं।

[सं० 201-57/76 डिस्क II/पी० टी०]

के० एल० कपूर, सहायक महानिदेशक (डिस्क II)

ORDER

New Delhi, the 31st May, 1980

S.O. 1631.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby specifies the Director of Telecommunications as the Appellate Authority in respect of punishment order passed by the Superintendent of Central Telegraph Office, Secunderabad.

[No. 201/57/76-Disc. II/Pt.]

K. L. KAPUR, Asstt. Director General (Disc. II)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून, 1980

का० आ० 1632.—जबकि मद्रास मुख्य टेलीफोन एक्सचेंज के स्थानीय क्षेत्र में बदली किए जाने के बारे में जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक सार्वजनिक सूचना, जैसा कि भारतीय तार नियमावली 1951, के नियम 434 (III) (बी० बी०) में अपेक्षित है, मद्रास में प्रचलित समाचार पत्रों में छपवाया गया था जिसमें उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव है तो वे इस नोटिस के प्रभावित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें।

और जबकि उक्त नोटिस सर्वसाधारण की जानकारी के लिये 22-1-80 को अंग्रेजी दैनिक "दि हिन्दू", 17-1-1980 को तमिल दैनिक "थीनाथानथी", 17-1-80 को तमिल दैनिक "थीनामानी", 17-1-80 को तमिल दैनिक "मक्कल कुरल" और 16-1-80 को अंग्रेजी दैनिक "दि मेल" में निकाला गया था।

और जबकि उक्त नोटिस पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है।

इसलिये अब उक्त नियमावली के नियम 434 (III) (बी०बी०) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक डाकतार ने घोषणा की है कि 16-6-1980 से मद्रास मुख्य का स्थानीय संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा :—

मद्रास मुख्य टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था

मद्रास मुख्य टेलीफोन एक्सचेंज का क्षेत्र वह होगा जो मद्रास नगर निगम के क्षेत्राधिकार में पड़ता है, कार्यावक्कम टाउनशिप, तिरुवोट्टियूर नगर पालिका, मनाली नगर पंचायत, चित्लाकुट्टु नगर पंचायत, मधवारम टाउनशिप, मदुरोवियल नगर पंचायत, पालासरवक्कम नगर पंचायत, पोरूर नगर पंचायत, नन्दमवक्कम नगर पंचायत, सं० थामस मांउट छावनी, अलन्दूर नगर पालिका, पालावरम छावनी (अधिसूचना की तारीख को मौजूद सीमायें) और किसी भी एक्सचेंज से 5 कि० मी० की अरीय दूरी तक का क्षेत्र समाहित है।

टिप्पणी :—

1. मधवारम एक्सचेंज से 5 कि० मी० की अरीय दूरी की सीमा उत्तर में पालल नगर पंचायत को छोड़कर तथा पश्चिम में अम्बात्तूर टाउनशिप (को छोड़कर) तथा मधवारम टाउनशिप (को शामिल करके) तक सीमित है।

2. कोडम्बाक्कम एक्सचेंज से 5 कि० मी० की अरीय दूरी उत्तर पश्चिम में कूयम नदी तक सीमित है।

3. सं० थामस मांउट एक्सचेंज से 5 कि० मी० की अरीय दूरी दक्षिण पश्चिम में पल्लावरम नगर पालिका (को छोड़कर) तक सीमित है।

[संख्या 3-20/74- पी० एच० बी०]

New Delhi, the 3rd June, 1980

S.O. 1632.—Whereas a public notice for revising the local area of Madras Main Telephone Exchange System was published as required by rule 434(III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Madras, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 22-1-1980 in English Daily "The Hindu", on 17-1-80 in Tamil Daily "Dhina Thanthy" on 17-1-1980 in Tamil Daily "Dhinamani", on 17-1-1980, in Tamil Daily "Makkal Kural" and on 16-1-1980 in English Daily "The Mail".

And whereas objections and suggestions received from the public on the said notice have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434(III)(bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 16-6-1980 the revised local area of Madras Main shall be as under:

Madras Main Telephone Exchange System :—

The Local Area of Madras Main Telephone Exchange system shall cover an area falling under the jurisdiction of Madras Corporation, Kathivakkam Township, Tiruvothiyur Municipality, Manali Town Panchayat, Chinnasekkadu Town Panchayat, Madhavaram Township, Madurovoyal Town Panchayat, Valasarawakkam Town Panchayat, Porur Town Panchayat, Nandambakkam Town Panchayat, St. Thomas Mount Cantonment, Alandur Municipality, Pallavaram Cantonment, (Boundaries as existing on the date of notification) and area within 5 KM Radial Distance from any of the Exchanges in the Systems.

Notes:

1. The limit of 5 KM. Radial Distance from Madhavaram Exchange is restricted to Polal Town Panchayat (excluding) on the North and Ambattur Township, (excluding) and Madhavaram Township (including) on the West.

2. The limit of 5 KM Radial Distance from Kodambakkam Exchange is restricted to Cooum River on the North West.

3. The limit of 5 KM. Radial Distance from St. Thomas Mount Exchange is restricted to Pallavaram Municipality (excluding) on the South West.

[No. 3-20/74-PHB]

का०आ० 1633.—जबकि मद्रास दक्षिण टेलीफोन एक्सचेंज के स्थानीय क्षेत्र में बदली किये जाने के बारे में जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक सार्वजनिक सूचना, जैसा कि भारतीय तार नियमावली 1951, के नियम 434(III) (बी०बी०) में अपेक्षित है, मद्रास के मशहूर समाचार पत्रों में छपवाया गया था जिसमें उससे कहा गया था कि इस बारे में यदि कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव है तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें।

और जबकि उक्त नोटिस सर्व साधारण की जानकारी के लिए 22-1-1980 को अंग्रेजी दैनिक 'दि हिन्दू' में, 17-1-80 को तमिल दैनिक "धीनाथामयी", 17-1-80 को तमिल दैनिक "धीनामानी", 17-1-80 तमिल दैनिक "मक्कल कुरील" तथा 16-1-80 को अंग्रेजी दैनिक "दिमेल" में निकाला गया था।

और जबकि उक्त नोटिस पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है।

इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 434 (III) (बी०बी०) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक डाक तार ने घोषणा की है कि 6-6-1980 से मद्रास दक्षिण का स्थानीय संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा :—

मद्रास दक्षिण टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था :—

मद्रास दक्षिण टेलीफोन एक्सचेंज का क्षेत्र वह होगा जो पल्लावरम नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में पड़ता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अनकपुथूर नगर पंचायत, पम्मल नगर पंचायत, तिरूनीरमलाई नगर पंचायत, चितलापक्कम नगर पंचायत, तम्बा राम, नगर पालिका, पेरुंगलाथूर नगर पंचायत (अधिसूचना की तारीख को मौजूद सीमाएं) और तम्बाराम एवं क्रोमपेट एक्सचेंजों से 5 कि०मी० की अरीय दूरी तक के क्षेत्र समाहित है।

टिप्पणी :

क्रोमपेट एक्सचेंज की 5 कि०मी० की अरीय दूरी के क्षेत्र के अंतर्गत पल्लावरम नगर को शामिल करने एवं पल्लावरम छावनी को छोड़कर उत्तर पश्चिम में उत्तर और अदयार नदी तक का क्षेत्र सीमित होगा।

[सं० 3-20/74 पी०एच०बी०]

S.O. 1633.—Whereas a public notice for revising the local area of Madras South Telephone Exchange System was published as required by rule 434(III)(bb) of the Indian Telegraphs Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Madras, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 22-1-1980 in English Daily "The Hindu", on 17-1-1980 in Tamil Daily, "Dhine Thanthy", 17-1-1980 in Tamil Daily "Dhinaman", on 17-1-1980 in Tamil Daily "Makkal Kural" and on 16-1-1980 in English Daily "The Mail".

And whereas objections and suggestions received from the public on the said notice have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434(III)(bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 16-6-1980 the revised local area of Madras South shall be as Under:

Madras South Telephone Exchange System :—

The Local Area of Madras South Telephone Exchange System shall cover an area falling under the jurisdiction of Pallavaram Municipality, Anakaputhur Town Panchayat, Pammal Town Panchayat, Tiruneermalai Town Panchayat, Chitlapakkam Town Panchayat, Tamberam Municipality, Perungalathur Town Panchayat, (Boundaries as existing on the date of Notification) and 5 KMs. Radial Distance from Tamgaram and Chromepet Exchanges.

Notes :

1. The limit of 5 KM Radial Distance from Chromepet Exchange will be restricted to Pallavaram Municipality (including) and Pallavaram Cantonment (Excluding) on the North and Adyar River on the North West.

[No. 3-20/74-PHB]

का०आ० 1634.—जबकि मद्रास पश्चिम टेलीफोन एक्सचेंज के स्थानीय क्षेत्र में बदली किये जाने के बारे में जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक सार्वजनिक सूचना, जैसा कि भारतीय तार नियमावली 1951 के नियम 434 (III) (बी०बी०) में अपेक्षित है मद्रास में प्रचलित समाचार पत्रों में छपाया गया था जिसमें उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव है तो वे इस नोटिस के प्रभावी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें।

और जबकि उक्त नोटिस सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 22-1-80 को अंग्रेजी दैनिक "दि हिन्दू" 17-1-80 को तमिल दैनिक "धीनाथानथी" 17-1-80 को तमिल दैनिक "धीनाभानी", 17-1-80 को तमिल दैनिक "मक्कलकुरील" और 16-1-80 को अंग्रेजी दैनिक "दि मेल" में निकाला गया था ।

और जबकि उक्त नोटिस पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ।

इस लिए अब उक्त नियमावली के नियम 434 (III) (बी०बी०) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक डाक-तार ने घोषणा की है कि 16-6-1980 से मद्रास पश्चिम का संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा :

मद्रास पश्चिम टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था

मद्रास पश्चिम टेलीफोन एक्सचेंज का क्षेत्र वह होगा जो मंगादू नगर पंचायत, पूनामल्ली नगर पंचायत, थीरुमाझीसाई नगर पंचायत, आवादी टाउनशिप, अम्बत्तूर टाउन नत्तरीकुप्पम नगर पंचायत, पोलल नगर पंचायत, ग्राम कादिरवेदु और सुरामदु (आम सूचना की तारीख को मौजूद सीमायें) और चोलावरम टैंक के क्षेत्राधिकार में पड़ता है तथा वह क्षेत्र जो किसी भी एक्सचेंज के 5 कि०मी० की अरीय दूरी के क्षेत्र में पड़ता है ।

टिप्पणी :

1. पूनामल्ली एक्सचेंज से 5 कि०मी० की अरीय दूरी की सीमा दक्षिण पश्चिम में चेंबरमबक्कम टैंक (को छोड़कर) तक सीमित होगी ।

2. अम्बातूर एक्सचेंज से 5 कि०मी० की अरीय दूरी दक्षिण में कुयुम नदी तक और पूर्व में अम्बातूर टाउनशिप (को शामिल करके) तक सीमित होगी ।

[सं० 3-20/74 पी एण्ड बी]

एम० बी० रामामूर्ति, टेलीफोन निदेशक (ई)

S.O. 1634.—Whereas a public notice for revising the local area of Madras West Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Madras, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 22-1-1980 in English Daily "The Hindu" on 17-1-1980 in Tamil Daily "Dhina Thanthy" on 17-1-1980 in Tamil Daily "Dhinamani" on 17-1-1980 in Tamil Daily "Makkal Kural" and on 16-1-1980 in English Daily "The Mail".

And whereas objections and suggestions received from the public on the said notice have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434(III)(bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 16-6-1980 the revised local area of Madras West shall be as under :

Madras West Telephone Exchange System

The Local Area of Madras West Telephone Exchange System shall cover an area falling under the jurisdiction of Mangadu Town Panchayat, Poonamallee Town Panchayat, Thirumabhisai Town Panchayat, Avadi Township, Ambattur Township, Naravarikuppam Town Panchayat, Polal Town Panchayat, Villages Kadirvedu and Surapatu (Boundaries as existing on the date of Notification) Red Hills Lake, and Cholavaram Tank and area falling within 5 KMs Radial Distance from any of the Exchanges in the system.

Notes :

1. The limit of 5 KM Radial Distance from Poonamallee Exchange is restricted to Chembarambakkam Tank (excluding) in the South West.

2. The limit of 5 KM Radial Distance from Ambattur Exchange is restricted to Cooum River in the South and Ambattur Township (including) in the East.

[No. 3-20/74-PHB]

M. B. RAMAMURTHY, Director of Phones(E)

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 मई, 1980

का०आ० 1635.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में यूनाइटिड इण्डिया फायर जनरल इन्श्योरेंस कं० लिमिटेड, कोचीन-682016 के प्रबन्ध से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० सुन्दरसनम डेनियल होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या यूनाइटिड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कोचीन के प्रबन्धतंत्र की, कुमारी डी०आर० चित्राभाई, टाइपिस्ट की सेवाओं को 24 अक्तूबर, 1974 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-17012(17)/79-डी० 4(ए)]

नन्द लाल, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 3rd May, 1980

S.O. 1635.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of United India Fire and General Insurance Company Limited, Cochin-682016 and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed :

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Sudarsanam Daniel shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of United India Fire and General Insurance Company Limited, Cochin in terminating the services of Kumari D. R. Chitrabhai, Typist, with effect from the 24th October, 1974 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?

[No. L-17012(17)/79-D.IV(A)]

NAND LAL, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 17 मई, 1980

का०आ० 1636—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में ओरियण्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेंस कं० लिमिटेड, मद्रास के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० सुदरसनम डेनियल होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या ओरियण्टल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कं० लिमिटेड, मद्रास के प्रबंधतंत्र की निम्नलिखित कर्मकारों का पुनःवर्गीकरण न करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?

क्रम सं०	नाम	पद
1.	श्री एस० आर० मोठ	सहायक
2.	श्री एस०जे० गांधी	,,
3.	श्री एम० वेंकटकृष्णा राव	,,
4.	श्री पी० आर० राजाराम	,,
5.	श्री पी० डी बेंजामीण	,,
6.	श्री एस० शंकरामूर्थी	,,
7.	श्री एम० थंगास्वामी	,,
8.	श्री एम०के० साह	,,
9.	श्री टी०के० बालासुब्राह्मनियम	,,
10.	श्री एस० दुराइस्वामी	,,
11.	श्री आर० श्री निवासन	,,
12.	श्री जे० अम्बरोस	,,
13.	श्री पी०एस०के० पाणिकेर	वरिष्ठ सहायक, सब स्टाफ
14.	श्री एस० नारायण स्वामी	-यथोक्त-
15.	श्री डी० पेरासुरामन	-यथोक्त-

[सं० एल-17012/19/79-डी 4(ए)]
एस० एस० मेहता, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 17th May, 1980

S.O. 1636.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Oriental Fire and General Insurance Company Limited, Madras and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Sudarsanam Daniel shall be the Presiding Officer with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Oriental Fire and General Insurance Company Limited, Madras in not recategorising the undermentioned workmen is justified? If not, to what relief are the concerned workmen entitled?

S. No.	Name	Designation
1.	Shri S. R. Mothi	Assistant
2.	Shri C. J. Gandhi	Assistant
3.	Shri N. Venkatakrishna Rao	Assistant
4.	Shri P. R. Rajaram	Assistant
5.	Shri P. D. Benjamin	Assistant
6.	Shri S. Sankaramurthy	Assistant
7.	Shri M. Thangaswamy	Assistant
8.	Shri M. K. Shah	Assistant
9.	Shri T. K. Balasubramanian	Assistant
10.	Shri S. Duraiswamy	Assistant
11.	Shri R. Srinivasan	Assistant
12.	Shri J. Ambrose	Assistant
13.	Shri P. R. K. Panicker	Senior Assistant Sub-Staff
14.	Shri S. Narayanaswamy	-do-
15.	Shri D. Parasuraman	-do-

[No. L-17012/19/79-D.IV(A)]
S. S. MEHTA, Desk Officer

New Delhi, the 29th May, 1980

S.O. 1637.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal Madras, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India, Madras and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd May, 1980.

BEFORE PRESIDING OFFICER, THIRU T. SUDARSANAM DANIEL, B.A., B.L., INDUSTRIAL TRIBUNAL MADRAS

(Constituted by the Government of India)

Tuesday, the 13th day of May, 1980

Industrial Dispute No. 24 of 1979

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Dispute Act, 1947 between the workmen and the Management of State Bank of India, Madras.)

BETWEEN

Thiruvalargal
1. M. V. Sarma,
2. G. Munuswamy,
3. G. Palani,
4. K. Jayapal,
5. M. Prasad,
6. S. Alaudeen,
7. V. Sankaran,
8. P. Periaswamy,
9. V. Tagore,
10. K. S. Narayanan,
11. N. Manickam,
12. S. V. Adimoolam,
13. Chandran,
14. A. Susainathan and
15. S. K. Vaithyanathan.

} No. 135, Moore Street, Madras-600001.

AND

The Chief General Manager, State Bank of India, L.H.O., Madras-1.

REFERENCE

Order No. L-12011/49/78-D.II.A, dated 24th May, 1979 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on for final hearing on Tuesday, the 18th day of March, 1980, upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru K. Chandru for Thiruvalargal Row and Reddy and K. Chandru, Advocates for the workmen and of Thiruvalargal T. S. Gopalan, P. Ibrahim Kalifulla and P. Raghunathan, Advocates for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration this Tribunal made the following :

AWARD

This is an Industrial Dispute between the workmen and the Management of State Bank of India, Madras-1 referred to this Tribunal for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in Order No. L-12011/49/78-D.II.A, dated 24-5-1979 of the Ministry of Labour, in respect of he following issue :

"Wheher the action of the management of State Bank of India, Madras in terminating the services of the undermentioned workers with effect from 13-11-1973 is justified ?"

1. S/Shri M. V. Sarma,
2. G. Munuswamy,
3. G. Palani,
4. K. Jayapal,
5. M. Prasad,
6. S. Allaudeen,
7. V. Sankaran,
8. P. Periaswamy,
9. V. Tagore,
10. K. S. Narayanan,
11. N. Manickam,
12. S. V. Adimoolam,
13. Chandran,
14. A. Susainathan.
15. S. K. Vaithyanathan.

If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

(2) Facts leading upto the reference are as follows : The Respondent is the State Bank of India, Madras represented by its Chief General Manager, Local Head Office, Madras-1. The reference relates to 15 employees. Petitioners 1 to 5, 10, 11, 13 to 15 have filed a joint claim statement. Petitioners 6, 7, 8, 9 and 12 have filed a separate joint claim statement treating the claim statement jointly filed by Petitioners 1 to 5, 10, 11 and 13 to 15. In the Annexure to the claim statement filed by Petitioners 1 to 5, 10, 11, 13 to 15, the names of all the 15 employees covered by the issue and the designation last enjoyed by them and the total years of service and the salary paid to them had been mentioned. As I have already pointed out the Respondent-Management is State Bank of India, Madras represented by its Chief General Manager, Local Head Office, Madras-1. This Bank has been constituted under the State Bank of India Act, 1955. Section 43 of the said Act empowers the Central Board of the Bank to appoint such number of Officers, employees and staff as it considered necessary or desirable for the efficient performance of its functions and determine their terms and conditions of service. The workmen of the Respondent-Bank are represented by recognised trade union and the terms and conditions of service are governed by the awards and settlements made under the provisions of the Industrial Disputes Act. In the year 1963, the Respondent-Bank and the All India State Bank of India Staff Federation, the recognised trade union for workmen in the Bank entered into an agreement which inter alia provided for organisation and conduct of welfare activities for the Bank staff and utilisation of the staff welfare fund. The staff welfare fund is a fund created by the Central Board of the State Bank of India by transfer of funds from the annual profits for providing certain amenities to the staff and carried out welfare activities for the employees of the Bank as a whole. One of the primary object of the creation of the staff welfare fund was to provide staff canteen facilities at centres where the staff complement is above 60 and top priority was given for the formation of such canteens. There are nine such centres within the area of operation of the Bank in this country. On the basis of this scheme Circle Welfare Committees were constituted to organise, conduct and supervise the welfare activities of the circle as such. This Circle Welfare Committee was made responsible for supervising the utilisation of the funds for purpose intended. The Circle Welfare Committee in turn allots funds for Local Head Office for the Local Implementation Committee to look after the utilisation of funds allotted by the Bank. In terms of the aforesaid agreement, the Circle Welfare Committee was constituted at the Madras Local Head Office of the State Bank of India in August, 1963. It is common ground that the Local Implementation Committee should be run on no profit no loss basis, while the Bank would provide accommodation for the canteen, the cost of non-recurring expenditure has to be met out of the Staff Welfare Fund. The Agent or the Chief General Manager as the case may be has been made as Ex-Officio President of the Local Implementation Committee. The other office bearers and members of the Committee were all employees of the Bank and no outsider is permitted to hold any office in the Local Implementation Committee or in the Circle Welfare Committee. In carrying out the above said objectives, the Respondent-Bank provided allocation of suitable amounts to various Circle Welfare Committees to be used for the welfare activities in the Circle. This amount is created by the Central Board of the Respondent-Bank by transfer of funds from annual profits which is declared to be appropriated by the Bank but it was earmarked for providing certain amenities to the staff and carrying out other welfare activities for the employees of the Bank as a whole. After the constitution of the Canteens by the Management, the Respondent-Bank gave large sums of money towards the salaries to be paid to the employees engaged in the Canteens. Such amounts were passed through the Local Implementation Committee. Kitchen utensils and furniture to be used in the Canteen are supplied by the Respondent-Bank. The Canteen is also situated within the premises of the Bank. The Canteen also works during the working hours of the Bank. The accounts of the Canteen were audited by the Bank and inspection is also made by the Inspecting Officials of the Bank. Moreover, cost of additions and alterations to the building, furniture, electricity, water charges etc. were borne by the Respondent-Bank alone. That apart, the Bank also gave subsidies in order to meet the wages to be paid for the Canteen employees. Therefore, in 1966, the Respondent-Bank sent a circular Ex. W-19 that they will provide subsidies from the Bank's charges account in order to pay uniform scales of wages to the employees of the canteen and they also prescribed the scales of pay detailed therein. Moreover, on the representation of the All India State Bank of India Staff Federation, in 1972 the Respondent-Management increased the revised subsidies to meet the revision of wages to the employees of the Canteen—vide Ex. W-20. The funds of the Local Implementation Committee were deposited in the branch of the Bank in the name of the Staff Welfare Account and the cheques were drawn on Staff Welfare Account signed by the President and Secretary of the Local Implementation Committee. But the Salaries of the employees engaged in the staff canteen were paid through the Local Implementation Committee. Such a canteen had been maintained in the Respondent-Bank for the past 15 years.

(3) While so on 7-6-1973, State Bank Cooperatives' Employees' Union, Madras-1 a registered body presented a charter of demands under Ex. W-1 with the Respondent-Management relating to the staff working in the State Bank of India Staff Mess, Madras. There was no response on the part of the Respondent-Management and thereafter this said Union issued a strike notice in August, 1973. At this stage in November, 1973, Petitioners who were employed in the State Bank of India Staff Mess were denied employment from 13-11-1973—vide Ex. W-2. When the Union approached the concerned Labour Officer on 14-11-1973—vide Ex. W-3, and this Labour Officer sought for the remarks of the Management, the Management sent a reply Ex. W-4 that to the effect that canteen is not an 'industry' within the meaning of relevant section of the Industrial Disputes Act. Ex. M-3 is another letter of the Respondent-Management dated 22-10-73 explaining their stand with regard to the canteen employees. Ex. W-5 is the further letter of the Union to the Labour Officer dated 6-12-1973 giving their view of the Management's explanation under Ex. M-3. Ex. W-6 is the Conciliation Failure Report submitted on 29-1-1974. The

Government of Tamil Nadu declined to make any reference-vide Ex. W-7. Meanwhile, almost on identical facts, Central Government Industrial Tribunal, Calcutta rendered an award in Reference No. 63 of 1975 on 30-11-1976, copy of which is produced as Ex. W-9. Thereafter, the State Bank Cooperatives' Employees' Union, Madras again took up the cause of these 20 employees who were thrown out of employment with effect from 13-11-1973—vide Exs. W-10, W-11, W-12 and W-13. Ex. W-15 is the explanation offered by the Management. Ex. W-17 is the Conciliation Failure Report submitted by the Assistant Labour Commissioner (Central), Madras. Acting on this Report, the Government of India has made the present reference.

(4) Before proceeding further, it will be pertinent for me to set out the nature and extent of the employment and work extracted from these 15 petitioners and others. Out of these 15 employees, Thiru M. V. Sarma was working as Head Cook while Thiru M. Prasad was Assistant Cook. Thiruvalargal G. Munuswamy, G. Palani, K. Jayapal, V. Tagore, S. V. Adimoolam were working as Cleaners and Thiruvalargal S. Alaudeen, V. Sankaran, K. S. Narayanan, M. Manickam were working as Servers and Thiru S. K. Vaithyanathan was working as Head Server. Thiru P. Perinsamy was employed as Grinder, Thiru Chandran as Crush Maker and Thiru A Susainathan as Assistant Cashier. The total years of service put in by these employees and the salary paid to them are mentioned in Annexure to the Claim Statement filed by the Petitioners 1 to 5, 10, 11, 13 to 15. Thus it would appear that these 15 Petitioners and others who were working in the State Bank of India Staff Mess, Madras-1 in different assignment were denied employment with effect from 13-11-1973. But one important aspect that can be gathered from the stand of the Management under Ex. M-3 on 22-10-1973, Ex. W-15 on 27-1-1978 and the counter statement filed before this Tribunal is that they never specifically deny the fact that these workmen were employed in the State Bank of India Staff Mess upto 13-11-1973. On the other hand, the unmistakable stand of the Management with regard to these employees culled out from the remarks offered by the Management under Ex. W-15 on 27-1-1978. In pararaph (4) of Ex. W-15, the Respondent-Management has clearly stated as follows :

> "The petitioners were not employees of the Bank and hence this dispute is not maintainable against the Bank. Admittedly they were employed in the Staff Mess managed by the Local Implementation Committee—a body of employees of the Bank constituted under its scheme for the welfare of the staff".

Thus in as much as the definite case of the Respondent-Management is that none of these Petitioners had been employed by the Respondent Bank it is obvious that no charges had been framed by the Respondent-Bank against any of these workmen and no enquiry had been held prior to the denial of employment from 13-11-1973. I have earlier pointed out how even from June, 1973, the employees of State Bank of India Staff Mess, Madras were agitating for certain rights as can be gathered from Ex. W-1, the charter of demands dated 7-6-1973. According to the Petitioners they have even issued a strike notice to the Management in August, 1973. However, Thiru N. Manickam-Petitioner No. 11 was denied employment from 9-11-1973 while the rest were denied employment from 14-11-1973. These facts are borne out by Ex. W-2 dated 13-11-1973, a communication sent by these 20 workmen by registered post to the Respondent-Management and also Ex. W-3, a communication sent through the Union on 14-11-1973 Ex. W-4 is a communication of the Management dated 17-11-1973 offering their remarks. Significantly, in Ex. W-4, the Management does not dispute any of the facts mentioned in Ex. W-2 or Ex. W-3. But on the other hand, as the State Bank of India Staff Mess is not an 'Industry' under the Industrial Disputes Act and as such the workers employed by such Mess would not come within the purview of Industrial Disputes Act. To a similar effect it is also the stand of the Management under Exs. M-3, W-15 and also before this Tribunal. In as much as according to the Respondent-Management, Petitioners were never employed by them, the question of framing any charge against the Petitioners or holding any enquiry against them did not at all arise. In the circumstances, the one and the only crucial point that has to be determined is whether the employees of the State Bank of India Saff Mess are the employees of the Respondent-Bank and once the issue is found in favour of the Petitioners, it must follow that the termination is unjustified with effect from 13-11-1973.

(5) It remains to be considered whether these Petitioners were employees of the Respondent-Bank in 1974-I-L.L.J.-Page 367 (Mangalore Ganesh Beedi Works and others vs. Union of India and others) five judges of the Supreme Court at page 379, paragraph 41, have laid down several tests to determine the relationship between the employee and the employer. The Supreme Court has pointed out that in recent years, the control test as traditionally formulated has not been treated as an exclusive test although control is an important facor. As I have already mentioned there is absolutely no controversy on facts about the constitution of the Staff Mess and its working and its relationship with Bank as such. It is unnecessary for me to reiterate those facts once over. suffice for me to point out specific contention on the following facts, Ex. W-18 is the Circular issued by the Deputy Secretary and Treasurer of the Respondent-Management to its Agent enclosing the text of the arrangement agreed to between the representatives of the State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation wth regard to the organisation and conduct of welfare activities for the Bank's staff and the utilisation of the Staff Welfare Fund. From Ex. W-18, it can be gathered that the Bank sets apart a specified amount to the Staff Welfare activities. Providing a canteen facility is one of the measure welfare scheme for the staff. No dout, in order to implement the scheme, the Management and the Staff Federation have entered into working arrangement resulting in formation of Circle Welfare Committees and Local Welfare Committees to carry out the welfare activities intended for the employees of the Bank. The Bank has naturally involved its employees in carrying out the activities instead of entrusting it to any outside agency or leasing out. It is in that view it must be remembered that equal representation is provided for the Officers and the staff to constitute the class of employees for whom the facilities are to be provided. Merely because the Management has involved the staff also in the working out the facilities, it does not necessarily follow that the Management has little or no control over the canteen. Either the Agent or the Chief General Manager of the Local Head Office are appointed Ex-officio Presidents of the Local Implementation Committee and even if the said officers wished they could not be allowed to draw from the post of the President. As admitted even by M.W 1. the canteen accounts are audited by internal auditors and also by the Inspector of the Bank. The very fact that Bank Officers are auditing the accounts of the Mess demonstrates that the Mess is an undertaking of the Respondent-Bank. It is also common ground that the Bank alone meets the wage bill of the canteen workers albeit under the nomenclature of subsidies. The wage bill of the canteen workers has also been revised as will be evident from Exs. W-20 and W-21. Ex. W-22 also indicates that the Branch Manager who is Ex-officio President of the Local Implementation Committee cannot resign from the Committee and if he resigns disciplinary action will be taken against him by the Bank. Ex. W-23 is the Bank's direction with regard to the expenditure of the Mess. Ex. W-8 is the direction of the Bank with regard to timings during which the canteen should function. Ex. M-13 (at page 57) is Local Committee's resolution asking for Imprest cash. Page 41 of Ex. M-13 clearly points out that the canteen sub-committee is not competent to take any decisions regarding the instructions issued by the Bank. Even the captions in the Minutes Books Exs. M-12 and M-13 indicate the writ (viz.) State Bank of India. Therefore, these several circumstances would easily demonstrate that the control is always exercised by the Respondent-Bank.

(6) The second test laid down by the Supreme Court is organisation test. Kitchen utensils and furniture to be used in the canteen are supplied by the Respondent-Bank. The canteen is also constituted within the premises of the Bank. The working hours of the canteen is the same as that of the Bank. According to the claim of the Petitioners, even

Uniforms were given to the canteen employees by the Respondent-Bank. Cost of additions and alterations to the building furniture and electricity charges are borne by the Respondent-Bank. Therefore on the facts of the case it can easily be held that the organisation test also is satisfied. As the Supreme Court has pointed out in the ultimate analysis it would depend on all the facts and circumstances of each case in determining the relationship of master and servant. No doubt it is not the business of the Respondent-Bank to run canteens. But in view of Ex. W-18, subsidised canteen has become part of service conditions of the State Bank of India employees. In 1973—II—L.L.J page 130 (The Saras pur Mills Co., Ltd., vs. Ramanlal Chimanlal and others) the Supreme Court has held that the workers employed in the canteen which was being run by the Cooperative Society are the employees of the Mills. It is true that in that case under the Factories Act it was the duty of the Mills to run and maintain the canteen for use of its employees. But as much as subsidised canteen has become part of the service condition of the employees of the State Bank of India, the employees of such canteen should also be deemed to be employees of the Respondent-Bank. To a similar effect it is also the decision of our High Court in the unreported decision in WP. No. 4755 of 1976 dated 24-11-1978, a true copy of which is placed before this Tribunal. In that decision, the High Court has held the canteen employees to be employees of the factory. Therefore it has to be held that the employees of the State Bank of India Staff Mess are the employees of the Respondent-Bank.

(7) On behalf of the Petitioners, it is also pointed out that the Respondent-Bank having implemented the Award of the Calcutta Tribunal, it is not open to them to come forward with the different stand at Madras and that the Respondent-Management cannot discriminate which will be violative of Article 14 of the Constitution. There is no controversy that the Respondent-Bank is a "STATE" within the maening of Article 12 of the Constitution. Ex. W-9 is the Award rendered by the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in Reference No. 63 of 1975. The reference related to the demand of workmen of the State Bank of India represented by the State Bank of India Employees' Association, Bengal Cricle, for treating the staff of such canteens which are run by the Local Implementation Committees, as workmen of State Bank of India for giving them the same status, pay and facilities as are available to other Class IV employees of the Bank. The claim was resisted by the Management. However, on merits the Tribunal held that the canteen employees are workmen of the Respondent-Bank. This decision was rendered on 30-11-1976. The Respondent-Management did not challenge the Award Ex. W-9 but has implemented the Award. Therefore, the learned counsel for the Petitioners Thiru K. Chandru quite rightly points out that the same Management having the status of the "STATE" under the Constitution cannot discriminate its employees merely because the issue has arisen for consideration in Madras and not Calcutta. In 1979—II L.L.J.—Page 217 (Ramana Dayaram Shetty vs. International Airport Authority of India and others) the Supreme Court held that having regard to the Constitutional mandate of Article 14. the Management is not entitled to act arbitrarily. A Division Bench of our High Court in the unreported decision in W.P. No. 64 of 1971 and other Writ Petition dated 9-1-1974 has pointed out that although they did not agree with the Andhra Pradesh High Court's view of the matter. nevertheless allowed the Writ Petition on the ground that the Andhra Pradesh High Court's view became final because to hold otherwise would result in discrimination between Station Masters serving within the jurisdiction of Andhra Pradesh and those serving within the territory of Tamil Nadu. A copy of this decision was also placed at the disposal of the Tribunal for perusal. Therefore for this reason also the Respondent-Management would not be entitled to flout the Award of the Calcutta Tribunal which has been implemented by the RespondentBank in so far as it relates to Tamil Nadu Hence I also hold that the Petitioners must be deemed to be employees of the Respondent-Bank.

(8) The Madras City Hotel Workers Association raised a reference on behalf of the State Bank of India Staff Mess Workmen against the Management of State Bank of India Staff Mess in I. D. No. 76 of 1966 on the file of the Additional Labour Court, Madras, Ex. M-1 is the Award, wherein the Labour Court held that the Staff Mess is not an industry within the meaning of Section 2(j) of the Industrial Disputes Act, 1947, Learned Counsel for the Respondent-Bank Thiru Gopalan submits that in as much as the Award had not been terminated the workmen are not entitled to put forward their claim that they are the employees of the Respondent-Bank. But it must be pointed out that the Award under Ex. M-1 was not rendered against the Respondent-Bank. The professed employer under the Award is the Management of State Bank of India Staff Mess, First Line Beach, Madras-1. The Respondent-Bank was not at all a party. Moreover, the dispute had been raised by Madras City Hotel Workers Association. But the present dispute is only an Industrial Dispute raised by the aggrieved workmen in their individual capacity. Further more, the Award under Ex. M-1 held that the workers are not employed by the State Bank of India. It may incidentally be noted that even without impleading the State Bank of India as a party to that reference the Labour Court came to the conclusion that the State Bank of India Staff Mess is not a department of the Bank. Therefore, the finding of the Labour Court that those workmen were not employees of the Bank was not rendered on merit. If so, as pointed out by the Supreme Court in 1977—I—L.L.J—Page 471 (Cox and Kings (Agents) Limited vs. workmen), the order of the Additional Labour Court under Ex. M-1 did not have any attributes of an "Award" because even on the preliminarily jurisdictional fact there was no industrial dispute as such in accordance with law and therefore any observation found in Ex. M1 is neither decisive nor binding and so it cannot be held that in view of Ex. M-1, the present claim of the workmen should be held to operate as resjudicata. Secondly, the appropriate Government to refer cases in respect of Banking Industry under section 2(a) of the Industrial Disputes Act is only the Central Government and therefore any reference by the State Government and any consequent Award thereof as is evidenced from Ex. M-1 cannot be held to be with jurisdiction. Further more, since Labour Court under Ex. M-1 decided that the canteen was not an industry any further finding would be invalid and so the basis for any industrial dispute does not exist. Finally, it is also stated assuming that the Award under Ex. M-1 is valid and with jurisdiction, even then it cannot be held to be good in law in the light of the latest decision of the Supreme Court in 1978—II.L.J.—Page 349 (Bangalore Water Supply Sewerage Board, etc., vs. A. Rajappa and others, etc.). For these reasons I am unable to accept the contention of the learned counsel for the Respondent-Bank that the decision rendered under Ex. M-1 would disentitle the Petitioners from raising their present claim. Learned counsel for the Respondent-Bank also sought to rely on the decision of the Supreme Court reported in 1978—I—L.L.J.—Page 312 (employers in relation to Punjab National Bank vs. Ghulam Dastagir). That decision has after all held that the direction and control are telling factors to decide as to whether a "workman" (driver) in that case is an employee of the Bank. But decision does not exclude other factors also and as the Supreme Court points out the question in each case turns on its own circumstances and decisions in other cases are rather illustrative than determinative. In the aforesaid decision, the Supreme Court also points out:

> "We have no doubt that if in this case there was evidence to show any colourable device resorted to by the Bank, our conclusion would have been adverse to the Management."

In the circumstances that decision does not very much advance the stannd taken up by the Respondent-Management. As a later decision by larger bench of Supreme Court in 1978—II—L.L.J.—Page 397 (Hussainbhai, Calicut vs. Alath Factory Thozhilali Union, Calicut and others) has pointed out one has to discern the naked truth on lifting the veil or looking at the conspectus of factors governing employment through draped in different perfect paper arrangement to find out if the real employment is the Management-Bank. The Supreme Court has also cautioned that the court must be astute to avoid the mischief and achieve the purpose of the law and not be misled by the maya of legal appearances. Looked at from any angle either on facts or on law, it is well nigh impossible to

accept the contention of the Management that the Petitioners are not workmen of the Respondent-Bank. In the ultimate analysis I hold that these 15 Petitioners were employed by Respondent-Bank.

(9) In view of my finding in paragraphs supra, it has to be seen the nature and extent of relief that can be granted to these Petitioners. On behalf of the Management, it is stated that Petitioners present attempt to rejuvenate their lost battle after a lapse of 5 years is hopelessly delayed and the matter has become stale and therefore the Petitioners are not entitled to any relief on grounds of even delay. In 1979—I—L.L.J.—Page 1 (Avon Services (Production Agencies) Pvt. Ltd., vs. Industrial Tribunal, Haryana, Faridabad and others), the Supreme Court has held that the delay in making a reference cannot form the subject matter of consideration by the Tribunal and so long as issues referred to a Tribunal it is for the Tribunal to adjudicate the issue. It is true that the Petitioners were non-employed by the State Bank of India Staff Mess from 13-11-1973 and the attempt of Petitioners to vindicate their right did not meet with any success till 1974—vide Ex. W-7. However, the complexion of the claim was dramatically changed in the light of the decision of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta Ex. W-9 rendered on 30-11-1976. Thereafter, the Petitioners have again started to agitate their right and have eventually succeeded in impressing the appropriate Government to make the present reference. However, although Petitioners claim cannot be rejected yet time lag that has taken place since their termination on 13-11-1973 can be taken into consideration as to whether reinstatement can be ordered with effect from the date of termination on 13-11-1973. In this context, the nature of the employment of these workmen must be borne in mind. As I have already pointed out that most of them were Cleaners, Servers and two of them were Head Cook and Assistant Cook while the remaining were Grinders, Crush Maker and Assistant Cashier. Therefore it is obvious that all these Petitioners are adept in the hotel industry which is a growing and essential and ever containing industry. Therefore it is not surprising that although 20 employees were terminated on 13-11-1973 eventually only 15 of them, the present Petitioners have sought to enforce their right against the Respondent-Bank. No doubt in paragraph (25) of the claim statement, it is stated that the Petitioners are suffering without employment for more than 5 years and they have gone to their native places and struggling hard due to acute economic crisis to maintain themselves and their families. Great weight cannot be attached to this part of the claim. Another important factor that has weighed with the Petitioners is the Award rendered by the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta on 30-11-1976 which Award has been implemented by the Respondent-Bank. After implementing this Award under Ex. W-9, naturally, the Respondent-Management wanted to regularise the employees in the Staff Mess and at the same time to save their own face. It is not as though the Mess was closed from 13-11-1973. But the Mess was continued even thereafter till date and therefore the Mess had to be run with the employees similar to Petitioners 1 to 15 from 14-11-1973 onwards. That being so when the Respondent-Management implemented the decision of the Industrial Tribunal, Calcutta, the Respondent-Management entered into a dialogue with the workers of the Mess. Hence an agreement was entered into on 31-10-1977—vide Ex. W-24 between the State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation with regard to the employees in the canteen. As per the terms of settlement under Ex. W-24, the Bank has agreed to take over the concerned Local Implementation Committee and conduct the same in the manner provided under the scheme attached to the agreement and that the Bank will also provide the canteen staff, who will be appointed and paid by the Bank instead of by way of subsidy as at present and such persons having been employed in the canteen at the said branches and offices immediately before the coming into force of the Agreement will be considered for employment by the Bank. Therefore it is manifest that ignoring the claim of the present Petitioners, the Respondent-Bank has entered into a settlement with the workmen of the Mess employed after 13-11-73 to regularise them. This Settlement was to take effect from 2-1-1978. Therefore in the light of this Settlement under Ex. W-24, Petitioners should be given relief at any rate from 2-1-1978. These Petitioners cannot claim better terms than those embodied in the Settlement under Ex. W-24. Clause (3) of Ex. W-24 specifically says that "While those persons will be given relaxations in regard to the maximum age for recruitment, their appointments will be subject to their qualifying in an interview and found physically fit in a medical examination and they being approved on verification of character and antecedents in the usual manner." In fairness and justice and equity these 15 Petitioners must also be subject to these conditions, but their date of appointment would relate back to 2-1-1978. The Respondent-Management should also take into consideration the different periods of service rendered by these Petitioners and other conditions being satisfied such interview should be formal and should not be utilised as a scape goat to victimise these Petitioners.

(10) In the result, an Award is passed holding that Petitioners 1 to 15 are the employees of the Respondent-Management and Petitioners 1 to 15 are ordered to be reinstated into service subject to the conditions laid in clause (3) of Ex. W-24. If and when these employees are so appointed they must be deemed to be in the employment of the Respondent-Bank with effect from 2-1-1978 with consequent benefits. In the peculiar circumstances in order to maintain the peace, I direct the parties to bear their respective costs.

WITNESSES EXAMINED

FOR WORKMEN : None.

FOR MANAGEMENT : M. E. 1—Thiru R. Balasubramanian.

DOCUMENTS MARKED

FOR WORKMEN

Ex. W-1/7-6-73—Charter of demands of the State Bank Cooperatives' Employees' Union

Ex. W-2/13-11-73—Letter by the workers to the Management regarding lock out.

Ex. W-3/14-11-77—Letter from the State Bank Co-operatives' Employees' Union to the Labour Officer, Madras for initiating conciliation proceedings.

Ex. W-4/17-11-73—Letter from the State Bank of India Staff Mess, Madras to the Labour Officer, Madras.

Ex. W-5/6-12-73—Letter from the State Bank of Co-operatives' Union to the Labour Officer, Madras requesting to recommend for a reference.

Ex. W-6/29-1-74—Conciliation failure report.

Ex. W-7/11-6-74—Conciliation order passed by the Government (G O RT No. 1061, dated 11-6-74, Labour and Employment Department).

Ex. W-8/17-2-76—Circular of the Management regarding discipline, productivity and cost of effectiveness.

Ex. W-9/30-11-76—Award in Reference No. 63/75 of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta.

Ex. W-10/8-7-77—Letter from the State Bank Co-operatives' Employees' Union to the Management requesting to reinstate 20 workmen.

Ex. W-11/19-10-77—Text of telegram sent to the Management at Bombay regarding termination of the workmen.

Ex. W-12/14-11-77—Letter from the State Bank Co-operatives' Employees' Union to the Government sending copy of Award in Reference No. 63/75 of the Calcutta Industrial Tribunal.

Ex. W-13/27-12-77—Letter from the workmen to the Regional Labour Commissioner (Central), Madras for initiating conciliation.

Ex. W-14/6-1-78—Letter from the Government to the State Bank Co-operatives' Employees' Union, Madras.

Ex. W-15/27-1-78—Remarks submitted by the Management to the Regional Labour Commissioner, Madras in reply to Ex. W-13.

Ex. W-16/22-4-78—Letter from the State Bank Employees' Union, to the Regional Labour Commissioner, Madras regarding non-employment of workmen.

Ex. W-17/1-5-78—Conciliation failure report of the Assistant Labour Commissioner (C) Madras.

Ex. W-18/9-8-63—Circular of the Bank to the Branches enclosing the Text of arrangement agreed to between the Bank and the All India State Bank of India Staff Federation.

Ex. W-19/5-4-66—Staff Circular No. 19 regarding staff welfare fund—Promotion of Canteens.

Ex. W-20/24-11-72—Staff Circular No. 65 regarding staff welfare fund—Promotion of Canteens.

Ex. W-21/20-8-73—Staff Circular No. 66 regarding staff welfare fund—Promotion of Canteens.

Ex. W-22/20-5-75—Letter from the Bank-L H.O. to the Branches regarding Staff Welfare Fund.

Ex. W-23/25-5-75 Letter from the Bank-L H.O. to the Branches regarding Staff Welfare Fund.

Ex. W-24/31-10-77– Agreement between the State Bank of India and their workmen.

Ex. W-25/4-7-75—Letter from the Bank, L.H.O., to the Branches regarding Staff Welfare Fund.

Note : Exs. W-18 to W-24 produced by the Management and marked for workmen).

FOR MANAGEMENT :

Ex. M-1/21-6-68—Award in I.D. No. 76/66 on the file of the Additional Labour Court, Madras.

Ex. M-2/1-10-73—Conciliation letter to the Management.

Ex. M-3/22-10-73—Letter from the Management to the Labour Officer, Madras regarding charter of demands of the canteen employees.

Ex. M-4/31-12-73—Representation of the workers of the State Bank of India Staff Mess to the President of India with forwarding letter to the Chairman of the Bank.

Ex. M-5/3-1-78—Conciliation letter from the Assistant Labour Commissioner (Central), Madras to the parties.

Ex. M-6|26-6-76—Conciliation letter to the Management with copy of petition dated 25-2-76 of the workers of the State Bank Staff Mess.

Ex. M-7|20-5-72—Resignation letter of Thiru N. Manickam, Canteen Worker.

Ex. M-8/20-6-73—Letter from Thiru V. Tagore to the State Bank Mess.

Ex. M-9/20-6-73—Letter from Thiru A. Susainathan to the State Bank Mess requesting for revision of wage scales.

Ex. M-10/20-6-73—Letter from Thiru V. Tagore to the State Bank Mess submitting his explanation for his absence.

Ex. M-11 series—File containing the applications for appointment and termination orders issued to the workers of the canteen.

Ex. M-12—Book containing the notices to the Canteen Sub-Committee members for holding extra-ordinary meeting.

Ex. M-13—Minutes Book of the Canteen Sub-Committee.

Dated, this 13th Day of May, 1980.

T. SUDARSANAM DANIEL, Presiding Officer

[No. L-12011/49/78-DIIA]

New Delhi, the 30th May, 1980

S.O. 1638.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of India, Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on 17-5-1980.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI.

I.D. No. 73 of 1979

In re :

The Secretary, U.P. Bank Employees' Union, Red Gate Hotel, Lucknow (Shri A. K. Kirti). —Petitioner

Versus

The Regional Manager, Bank of India, Mahani Mansion, Naval Kishore Road, Lucknow. —Respondent.

AWARD

The Central Government as appropriate Government vide its order No. L-12012|82|75|DII(A) dated the 11th May, 1976 made a reference u|s 10 of the I.D. Act, 1947 in the following terms to this Tribunal :

'Whether the action of the management of the Bank of India in dismissing Shri A. K. Kirti, clerk, Main Branch of the said Bank at Lucknow w.e.f. the 12th December, 1973 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

2. On receipt of the reference usual notices were sent to the parties and a statement of claim was filed which was later on amended by the workman. Thereafter a written statement was filed by the management and finally a replication was also filed. Upon the pleadings of the parties a preliminary objection regarding raising of a demand was struck vide my order dated 29-12-78 and was decided in favour of the workman. It may incidently be mentioned here that in the month of May, 1977 this matter was transferred to this Tribunal.

3. Having decided preliminary issue against the Management the following two issues on merits were framed :

1. Whether the domestic enquiry is liable to be set aside on the ground alleged by the workman in his statement of claim ?

2. Whether it is open to the workmen to challange the enquiry on grounds other than those in the grounds of appeal and in the demand notice and the conciliation authorities.

Thereafter the case was adjourned for evidence of the Management to prove the enquiry to 20th February, 1979 and on that date only enquiry record was filed by the Bank and the case was adjourned for admission denial in the presence of Shrri R. C. Pathak for the workman and Shri Jagat Arora for the Bank to 28th March, 1979. The case went on for admission and denial until 14th September, 1979 on which date none appeared for the workman while Shri Jagat Arora appeared for the Bank and in consequence it was ordered that admission/denial could not be effected and the case to come up for evidence of the workman on 9-11-79. On 9-11-79 again none appeared for the workman while Shri Madhav Kapoor appeared for the Bank and the case

was adjourned to 19-12-79. On 19-12-79 I was constrained to pass the following order :—

'Present Shri Jagat Arora for Bank None for workman and union. None has been appearing for the last two hearings held on 14-9-79 and 9-11-79. On 14-9-79 after the case was adjourned counsel for union had appeared and filed an application and date was intimated and yet none appeared on the previous hearing. By way of a concession a notice was issued to union on the previous hearing but inspite of it none has appeared for union or workman today. In view thereof I am constarined to proceed ex-parte to determine the case. So far evidence of Bank to come up on 2-1-80.'

4. Thereafter the evidence of the Management was recorded ex-parte. I have gone through the ex-parte evidence and have given my considered thought to the matter before me and I have come to the following findings upon these issues.

Issue No. 1

5. The contention of the workman in his statement of claim was that he was appointed in the clerical cadre of the Bank on 17th December, 1964 and on 30-8-72 a charge sheet was issued to him and thereafter enquiry was held into these charges and the services of the workman were in consequence terminated vide order dated 12-12-1973; that the enquiry was vitiated and the order of termination of his services was not justified.

6. In reply it was contended by the Management that there was no demand raised by the workman and as such the reference was bad. On merits it was contended that the termination of services of the workman was for gross mis-conduct as a result of charges of serious nature and an enquiry held into that charges. It is further urged on behalf of the Management that the termination of his services vide order dated 12-12-1973 in pursuance of a valid enquiry was perfectly in order. It is also urged that the workman had even preferred an appeal against the order of his termination but the said appeal also was rejected and it is urged that the termination and the enquiry was valid, proper and the workman was not entitled to any relief. It is specifically denied that it was a case of victimisation.

7. In order to prove this issue the Management has produced the enquiry proceedings and has examined Shri H. A. Mehta on affidavit as one of the witness. He has stated that he was working as an officer of the Bank of India and during the years January, 1970 to February, 1974 he was Branch Manager at Indore and the General Manager Shri R. S. Balsekar had appointed the witness as Enquiry Officer vide his notice dated 11-8-72 to hold an enquiry into the charges of mis-conduct against this workman and was further empowered to take disciplinary action and award punishment to the workman Shri A. K. Kirti. He has produced the said notice as Ex. P|1. He has also proved Ex. P|2 which is a copy of the charge sheet dated 30-8-72. It is further stated by him that enquiry was held on various dates between 7th January, 1973 to 18th September, 1973 and during the enquiry proceedings Shri Kirti himself represented his case although at some stages Shri J. D. Mishra, Secretary of the UP Bank Employees' Union and Central Committee Member of All India Bank Employees' Association had represented him at the request of the workman. It is further stated in the affidavit that the workman was granted full opportunity in accordance with the provisions of natural justice as well as per the provisions of Bipartite Settlement to cross examine the various witnesses produced on behalf of the Bank and also to put up his evidence in defence. Likewise, it is stated in the affidavit that the record of the proceedings was signed on each page by Shri A. K. Kirti, workman and the representative of the Bank and other persons present on particular date and proceedings were correctly recorded by the Enquiry Officer and it was a record of whatever happened during the course of enquiry. It is then stated by him that he prepared his report dated 10-12-73 finding Shri A.K. Kirti guilty of the charges levelled against him and a show cause notice was then issued on 10th December, 1973 proposing the punishment for the charges and in consequence Shri Kirti alongwith the union representative Shri J. D. Mishra and P. L. Bhaskar appeared before the Enquiry Officer on 11-12-73 and after hearing them final order dated 12-12-73 was passed in which he was awarded punishment of dismissal. I have perused the enquiry proceedings and the report and I find that the enquiry was held properly and is not vitiated and the principles of natural justice were observed in minor details by the Enquiry Officer and as such was not liable to be set aside.

8. The Management has then examined on affidavit Shri Amar Pal Singh who has stated that he was an officer of the Bank and that Shri V. P. Thariani who also was an officer of the Bank in 1972—74 and had since retired from service w.e.f. 10-9-76 and had settled down out of India. It is finally stated by him that Shri Thariani was designated as an Appellate Authority vide letter dated 11-8-72 issued by the General Manager of the Bank and the appeal filed by Shri A. K. Kirti on 24-1-74 before Shri V. P. Thariani was heard and disposed of by the Appellate Officer vide order dated 27-3-74 whereby the appeal was dismissed and the findings and the punishment given by the Enquiry Officer was confirmed. He has proved the signatures of the appellate authority on the order dated 27-3-74.

9. I have perused the enquiry proceedings and find that proper and reasonable opportunity to cross examine the witnesses was given. There is nothing in the enquiry proceedings to suggest that the enquiry officer had in any manner directly or indirectly acted on the advise of the Bank's representative. Likewise, there is nothing to suggest that documents were not permitted to be produced to relevant questions were disallowed by the Enquiry Officer. Likewise, even after completing the enquiry full opportunity to show cause was afforded to the workman so much so that even the appeal was preferred and was dismissed. It would also not be out of place to mention here that as and when the workman wanted he was represented through the representative of the unions and in the face of all these facts it is difficult for me to come to a conclusion other than the one that the enquiry is not vitiated. It is matter of record that each page of the enquiry report bears the signatures of the workman, his representatives as and when they were present and the representative of the Management. It may also be mentioned here that wherever necessary the Enquiry Officer has recorded the statements in questions. From whichever angle I may consider the matter before me I have come to the conclusion that the enquiry is perfectly valid enquiry and does not suffer from any lacunae and accordingly this issue is decided against the workman and in favour of the Management.

10. Issue No. 2

The I.D. counsel for the Management has not been able draw my attention to any principle of law whereby the workman could not challange the enquiry proceedings wherever available to the workman before this court. Even otherwise in view of my findings issue No. 1, Issue No. 2 is of least importance and accordingly it is decided in favour of the workman.

11. For my discussions and findings above, the enquiry proceedings and the enquiry are upheld and the order of termination of the services of the workman is held valid & justified and accordingly it is awarded that the action of the Management of the Bank of India in dismissing Shri A. K. Kirti, Clerk, Main Branch, of the said Bank at Lucknow with effect from the 12th December, 1973 is justified and the workman is not entitled to any relief whatsoever. Parties are however left to bear their own costs.

Sd|- MAHESH CHANDRA Presiding Officer
Central Government Industrial Tribunal
New Delhi

Dated : the 18th April, 1980.

Further Awarded :

Requisite number of copies of this award may be sent to the appropriate Government for necessary action at their end.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

Dated : the 18th April, 1980.

[No. L-12012|82|75-D.II.A]

S. K. BISWAS, Desk Officer

New Delhi, the 4th June, 1980

S.O. 1639.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Chartered Bank and 11 other Banks and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th May, 1980.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/1 of 1977

PARTIES :

Employers in Relation to the Management of Chartered Bank

AND

Their Workmen.

Reference No. CGIT-2/4 of 1977

PARTIES :

Employers in Relation to the Management of United Commercial Bank

AND

Their Workmen.

Reference No. CGIT-2/5 of 1977

PARTIES :

Employers in Relation to the Management of Bank of Maharashtra

AND

Their Workmen.

Reference No. CGIT-2/6 of 1977

PARTIES :

Employers in Relation to the Management of State Bank of Mysore

AND

Their Workmen.

Reference No. CGIT-2/7 of 1977

PARTIES :

Employers in Relation to the Management of Central Bank of India

AND

Their Workmen.

Reference No. CGIT-2/8 of 1977

PARTIES :

Employers in Relation to the Management of Bank of India

AND

Their Workmen.

Reference No. CGIT-2/10 of 1977

PARTIES :

Employers in Relation to the Management of Bank of Baroda

AND

Their Workmen.

Reference No. CGIT-2/11 of 1977

PARTIES :

Employers in Relation to the Management of Union Bank of India

AND

Their Workmen.

Reference No. CGIT-2/12 of 1977

PARTIES :

Employers in Relation to the Management of Syndicate Bank (Goa Branches)

AND

Their Workmen.

Reference No. CGIT-2/13 of 1977

PARTIES :

Employers in Relation to the Management of Overseas Bank, Madras

AND

Their Workmen.

Reference No. CGIT-2/14 of 1977

PARTIES :

Employers in Relation to the Management of Dena Bank

AND

Their Workmen.

Reference No. CGIT-2/15 of 1977

PARTIES :

Employers in Relation to the Management of Canara Bank

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Managements—Shri P. K. Rele, Solicitor and Advocate.

For the Workmen—1. Shri B. W. Vaidya, Advocate.
2. Shri V. A. Nayak, Advocate.

INDUSTRY : Banking STATE : Goa, Daman and Diu

Bombay, the 2nd May, 1980

AWARD

Reference No. CGIT-2/1 of 1977

The Government of India, in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred upon them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 have refered the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication by their Order No. L. 12011|18|77-D|II|A., dated 24-3-1977 :—

"Whether the action of the management of Chartered Bank Swatantrya Path, Vascodagama in discontinuing the payment of Goa Allowance with effect from 1-11-76 is justified ? If not, to what relief are the affected workmen of the Bank entitled ?"

Both the parties filed their claint|written statements in support of their respective stand.

Reference No. CGIT-2/4 of 1977

The Government of India, in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred upon them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication by their Order No. L. 12011|11|77-D.II.A., dated 18-5-1977 :—

"Whether the action of the management of the United Commercial Bank in discontinuing the payment of Goa Allowance to their workmen employed in the branches of the Bank located in the territory of Goa w.e.f. 26-1-77 is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

Both the parties filed their claim/written statements in support of their respective stand.

Reference No. CGIT-2/5 of 1977 :

The Government of India, in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred upon them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication by their Order No. L. 12011/12/77-D. II. A, dated 20-5-1977 :—

"Whether the action of the management of the Bank of Maharashtra in discontinuing the payment of Goa Allowance to their workmen employed in the Bank's Branches located in the territory of Goa is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

Both the parties filed their claim/written statements in support of their respective stand.

Reference No. CGIT-2/6 of 1977 :

The Government of India, in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred upon them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication by their Order No. L. 12011/17/77-D.II.A, dated 20-5-1977 :—

"Whether the action of the management of the State Bank of Mysore in discontinuing the payment of Goa Allowance to their workmen employed in the Bank's Branches located in the territory of Goa w.e.f. 1-4-77 is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

Both the parties filed their claim/written statements in support of their respective stand.

Reference No. CGIT-2/7 of 1977 :

The Government of India, in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred upon them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication by their Order No. L. 12011/19/77-D.II.A, dated 20-5-1977 :—

"Whether the action of the management of the Central Bank of India in discontinuing the payment of Goa Allowance to their workmen employed in the Branches of the Bank located in the territory of Goa w.e.f. 1-2-77 is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

Both the parties filed their claim/written statements in support of their respective stand.

Reference No. CGIT-2/8 of 1977 :

The Government of India, in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred upon them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication by their Order No. L. 12011/10/77-D.II.A, dated 17-5-1977 :—

"Whether the action of the management of the Bank of India in discontinuing the payment of Goa Allowance to their workmen employed in the branches of the Bank located in the territory of Goa w.e.f. 26-1-77 is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

Both the parties filed their claim/written statements in support of their respective stand.

Reference No. CGIT-2/10 of 1977 :

The Government of India, in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred upon them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication by their Order No. L. 12011/13/77-D.II.A, dated 18-5-1977 :—

"Whether the action of the management of the Bank of Baroda in discontinuing the payment of the Goa Allowance to their workmen employed in the Banks Branches in the territory of Goa w.e.f. 29-1-1977 is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

Both the parties filed their claim/written statements in support of their respective stand.

Reference No. CGIT-2/11 of 1977 :

The Government of India, in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred upon them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication by their Order No. L. 12011/8/77-D.II.A, dated 23-5-1977 :—

"Whether the action of the management of the Union Bank of India in discontinuing the payment of Goa Allowance to their workmen employed in branches of the Bank located in the territory of Goa is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

Both the parties filed their claim/written statements in support of their respective stand.

Reference No. CGIT-2/12 of 1977 :

The Government of India, in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred upon them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication by their Order No. L. 12011/16/77-D.II.A, dated 23-5-1977 :—

"Whether the action of the management of the Syndicate Bank (Goa Branches) in discontinuing the payment of Goa Allowance to their workmen employed in the Banks Branches in the territory of Goa w.e.f. February 1977 is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

Both the parties filed their claim/written statements in support of their respective stand.

Reference No. CGIT-2/13 of 1977 :

The Government of India, in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred upon them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication by their Order No. L. 12011/9/77-D.II.A, dated 20-5-1977 :—

"Whether the action of the management of the Indian Overseas Bank, Madras in withdrawing payment of Goa Allowance to its employees working in the Branches in Goa (other than Panaji) is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

Both the parties filed their claim/written statements in support of their respective stand.

Reference No. CGIT-2/14 of 1977 :

The Government of India, in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred upon them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication by their Order No. L. 12011/15/77-D.II.A, dated 16-6-1977 :—

"Whether the action of the management of Dena Bank in discontinuing the payment of Goa Allowance to their workmen employed in the territory of Goa with effect from 1-11-76 is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

Both the parties filed their claim/written statements in support of their respective stand.

Reference No. CGIT-2/15 of 1977 :

The Government of India, in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred upon them under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication by their Order No. L. 12011|19|77-D.II.A, dated 17-5-1977 :—

> 'Whether the action of the Canara Bank in discontinuing the payment of Goa Allowance to their workmen posted in their Branches in the Territory of Goa w.e.f. 1-11-76 is justified ? If not, to what relief are the workmen entitled ?"

Both the parties filed their claim/written statements in support of their respective stand. All the above references have been consolidated at the request of the parties and this common award will govern all the above references.

The above references are in respect of payment of Goa Allowance to the workmen by the above Banks. The workmen in the above references are represented by the All India Bank Employees' Association, the National Confederation of Bank Employees' and National Organisation of Bank workers. The employers are represented by Shri K. Venkatachari on behalf of the Indian Bank's Association. The Unions as well as the Indian Bank's Association arrived at a Settlement regarding payment of Goa Allowance to their workmen. The settlement dated 21-4-1980 is between the Indian Banks' Association and the All India Bank Employees' Association and the National Confederation of Bank Employees. Whereas the settlement dated 25-4-1980 is between the Indian Banks' Association and the National Organisation of Bank Workers. The first settlement dated 21-4-1980 relates to Assam Allowance also with which we are not concerned and we are concerned only with Goa Allowance. The settlement dated 25-4-1980 however is regarding Goa Allowance only. The above settlements being signed by both employers as well as workmens' unions and also witnesses they are legal and proper and also beneficial for the workmen. The parties have prayed that a common consent award may be passed in terms of the above two settlements.

A common award in all the above references is accordingly, given in terms of settlements dated 21-4-1980 and 25-4-1980. The two settlements will form part of the Award which are attached herewith.

Parties to bear their own costs.

JITENDRA NARAYAN SINGH, Presiding Officer

[No. L-12011/8/77-D.II(A)]

S. K. BISWAS, Desk Officer

MEMORANDUM OF SETTLEMENT DATED 21ST APRIL, 1980 BETWEEN INDIAN BANKS' ASSOCIATION AND ALL INDIA BANK EMPLOYEES' ASSOCIATION AND NATIONAL CONFEDERATION OF BANK EMPLOYEES

NAME OF THE PARTIES :

58 Banks

Representing the Employers ;

1. Shri K. Venkatachari
2. Shri N. Vaghul

On behalf of the Indian Bank Association.

Representing the Workmen :

1. Shri D. P. Chadha
2. Shri K. K. Mandul
3. Shri Prabhat Kar
4. Shri Tarakeswar Charabort
5. Shri N. Sampath

On behalf of All India Bank Employees' Association.

1. Shri O. P. Gupta
2. Shri C. L. Rajaratnam
3. Shri C. R. Chandrasekaran
4. Shri N. C. Choudhury.

On behalf of National Confederation of Bank Employees.

Preamable.—Whereas the Goa Allowance and Assam Allowances Paid/Payable to the workmen were under discussion between the parties during the Bipartite negotiations.

And whereas there are cases also pending before tribunals in respect of these allowances.

It is now agreed by and between the parties as under :—

(1) **Goa Allowances**

(a) Till 31-8-1978 Goa allowance will be payable to all employees in all banks which were paying Goa Allowance at the rates obtaining in the respective Banks.

(b) From 1-9-1978—

(i) CCA would be payable in the urban agglomeration of Panaji and Marmugao.

(ii) HRA will be payable in accordance with Bipartite Settlement at the places in Goa eligible for the same.

(iii) In respect of employees covered by (a) above and who continue to be in Goa as on the date of this Settlement, if the aggregate of the HRA and CCA falls short of the Goa Allowance payable to them, such shortfall will be continued to be paid to them from time to time as Goa Allowance.

(2) **Assam Allowance**

(a) All employees who were working prior to 31-3-1980 in the Banks where Assam Allowance (by any name) was being paid, the Assam Allowance will be paid till 31-3-1980 at the respective rates.

(b) From 1st April, 1980 those employees will continue to draw the allowance at the same rates.

(c) In all other cases, in all banks, the allowance will be paid at a flat rate of Rs. 10 from 1st April, 1980.

(d) It is understood that Assam Allowance shall be paid as per clauses (a), (b) & (c) above in other States, viz., Manipur, Tripura, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh & Mizoram where the said allowance (by any name) was being paid till special area Allowances payable in these areas are settled in respect of workmen in these areas.

In respect of the proceedings now pending before Tribunals in respect of 'Goa Allowance' and 'Assam Allowance', this agreement will be submitted to the respective tribunals with the request for a 'Consent Award' for these terms.

FOR INDIAN BANKS' ASSOCIATION

Sd/-
K. Venkatachari

Sd/-
N. Vaghul

FOR ALL INDIA BANK EMPLOYEES ASSOCIATION

Sd/-
D. P. Chadha

Sd/-
Tarakeswar Chakraborty

FOR NATIONAL CONFEDERATION OF BANK EMPLOYEES

Sd/-
C. L. Rajaratnam

Sd/-
C. R. Chandrasekaran

WITNESSES :

1. M. Ram Mohan Rao
2. N. Sampath
3. R. Sivagyanam

Sd/-
(Illegible)

Sd/-
(Illegible)

Sd/-
(Illegible)

Date : April 21, 1980.

Place : Madras.

Copy to :

1. Conciliation Officer (Central), Madras.
2. Regional Labour Commissioner (Central), Madras.
3. Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi.
4. The Secretary to the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi.

MEMORANDUM OF SETTLEMENT DATED 25TH APRIL, 1980 BETWEEN INDIAN BANKS' ASSOCIATION AND NATIONAL ORGANISATION OF BANK WORKERS.

Name of parties : 58 Banks.

Representing the Employers :

1. Shri K. Venkatachari
2. Shri N. Vaghul

On behalf of the Indian Banks' Association.

Representing Workmen :

1. Dr. Subramanian Swamy, M. P.
2. Shri K. N. Shenoy
3. Shri K. N. Malhotra
4. Shri A. M. Puranik
5. Shri M. L. Sabharwal
6. Shri S. D. Deshpande
7. Shri K. Devidas Pai

On behalf of National Organisation of Bank Workers.

Preamable.—Whereas the Goa Allowance paid/payable to the workmen working in Goa branches was under discussion between the parties during the Bipartite negotiations.

And whereas, there are also cases pending before the Industrial Tribunal in respect of payment of Goa Allowance.

It is now agreed by and between the parties as under :—

(1) **Goa Allowance**—

(a) Till 31-8-1978 Goa allowance will be payable to all employees in all banks which were paying Goa Allowance at the rates obtaining in the respective Banks.

(b) From 1-9-1978—

(i) CCA would be payable in the urban agglomeration of Panaji and Marmugao.

(ii) HRA will be payable in accordance with Bipartite Settlement at the places in Goa eligible for the same.

(iii) In respect of employees covered by (a) above and who continue to be in Goa as on the date of this Settlement, if the aggregate of the HRA and CCA falls short of the Goa Allowance payable to them, such shortfall will be continued to be paid to them from time to time as Goa Allowance.

In respect of the proceedings now pending before the Tribunal in respect of 'Goa Allowance', this agreement will be submitted to the Tribunal with the request for a 'Consent Award' on these terms.

For INDIAN BANKS' ASSOCIATION

Sd/-
K. Venkatachari

Sd/-
N. Vaghul

For NATIONAL ORGANISATION OF BANK WORKERS

Sd/-
K. N. Shenoy

Sd/-
S. D. Deshpande

Witnesses :

Sd/- N. S. Pradhan

Sd/- K. Devidas Pai

Date : April 25, 1980

Place : Bombay

New Delhi, the 29th May, 1980

S.O. 1640.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Chairman-cum-Managing Director, Messrs Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, Post Office Dishergarh (Burdwan) and their workmen which was received by the Central Government on 26th May, 1980.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : CALCUTTA

Reference No. 68 of 1979

PARTIES :

Employers in relation to the Chairman-cum-Managing Director, Messrs Eastern Coalfields Limited Sanctoria, P.O. Dishergarh (Burdwan)

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Shri N. Das, Advocate.

On behalf of Workman—Shri T. P. Modak, The concerned workman.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Coalmine

AWARD

By Order No. L-19012(18)/79-D.IV(B), dated 19th October, 1979, the Government of India Ministry of Labour, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the Chairman-cum-Managing Director, Messrs Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, P. O. Dishergarh (Burdwan) and their workmen, to this Tribunal, for adjudication. The reference in the case reads as follows :

"Whether the demand of the Colliery Mazdoor Sabha (AITUC) for fixation of Shri T. P. Modak in Gr. 'B' Technical and Supervisory of National Coal Wage Agreement for operating the Duplicating as well as the Electronic Stencil Cutting Machines is justified ? If so, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. After receipt of the reference parties had been noticed to file their written statements. Before written statements were filed on 19-4-1980 a joint petition of compromise was filed by the parties. The petition was taken up for hearing on 20-5-1980 in the presence of Sri N. Das, Advocate appearing for the management and Sri T. P. Modak, the concerned workman. Both side accept the terms of settlement. After going through the terms of settlement I find that the terms are reasonable and fair.

3. Accordingly in terms of the settlement the award is passed saying that the employer will place the concerned workman Sri T. R. Modak as per the accepted recommendation of the Central Wage Board and subsequently modified by NCWA-II with effect from 1-1-1979 in the Planning Office of C & D Department of Sanctoria in the Technical & Supervisory Grade 'B', that the workman shall be paid his wages and other emoluments accordingly, that the union agrees that other workmen performing more or less similar jobs in the establishment and fixed in grade 'D' will give up their claim relating to fixation of Sri T. P. Modak in Technical and Supervisory Grade 'B', and that parties will bear their own costs.

4. The settlement filed by the parties do form a part of the award.

Dated, Calcutta,

The 21st May, 1980.

B. K. RAY, Presiding Officer.

[No. L-19012(18)/79-D.IV(B)]

A. V. S. SARMA, Desk Officer

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 68 of 1979

Vide Order No. L-19012(18)/79, dated 19-10-1979 of the Ministry of Labour, Government of India

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Eastern Coalfields Limited, P.O. Disergarh, Sanctoria, Distt Burdwan, West Bengal.

AND

Their Workmen.

The employers and workman represented by the Colliery Mazdoor Sabha jointly beg to submit :

(1) That the parties aforesaid have decided to settle the dispute which has been referred to the Honble' Tribunal for adjudication and on the following terms :

Terms

(a) That the employer will place the concerned workman Sri T.P. Modak who has been working as a Gestetner Duplicating Operator-cum-Electric Stencil Cutting Machine Operator in the Planning Office of C&D Deptt., of Sanctoria is the Tech. & Supv. Grade 'D' as per accepted recommendation of the Central Coal Wage Board and as subsequently modified by NCWA-II with effect from 1-1-1979 and pay his wages and other emoluments accordingly.

(b) It is agreed by the Union that in view of the fact that other workmen performing more or less similar jobs in the establishment have been placed in such Tech. & Supv. Grade 'D' they give up their claim made for fixation of Sri T. P. Modak the concerned workman in Tech & Supv. Grade 'B'.

It is further agreed that the parties will bear their respective costs for the reference.

(2) The Hon'ble Tribunal will be pleased to find from the aforesaid terms that the same are fair and reasonable and both the parties feel that for maintaining harmonious industrial relations in the establishment an approval for amicable settlement of the said case in the aforesaid terms is required to be accorded by the Hon'ble Tribunal.

It is therefore, most humbly prayed by the parties that the Hon'ble Tribunal will be pleased to pass an order directing the parties to settle the said dispute in terms recorded in the petition and to pass an Award accordingly treating this petition as a part thereof.

Signature of the Parties :

Ashes Maiti, Secretary

Colliery Mazdoor Sabha—for the Workman.

Amitana Sinha, Dy. Personal Mang.

ECL (HQ)

For the Management.

Eastern Coalfields Ltd.

SANCTORIA,

P. O. Disergarh, Distt. Burdwan

Pin-713333.

नई दिल्ली, 30 मई, 1980

का०आ० 1641.—केन्द्रीय सरकार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का०आ० 3065, तारीख 21 जुलाई, 1971 का निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में :—

1 क्रम संख्या 37 के सामने, स्तम्भ 3 की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात :—

"उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर, लखनऊ, इटावा, झांसी, हमीरपुर, बांदा, जालौन, गोरखपुर, गोंडा, बहराइच, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, गाजीपुर, बाराबंकी, खेरी, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, देवरिया, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, मिरजापुर, वाराणसी, फैजाबाद, फतेहपुर, सुल्तानपुर, मैनपुरी, ललितपुर, रोबर्टसगंज और फरुखाबाद के सिविल जिले।"

2. क्रम संख्या 38 के सामने, स्तम्भ 3 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

"हरियाणा, राज्य में रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, और मोहिन्द्रगढ़ के सिविल जिले और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र ।"

3 क्रम संख्या 40 के सामने :—

(क) स्तम्भ 2 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

"सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) आगरा" ।

(ख) स्तम्भ 2 और 3 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

"उत्तर प्रदेश राज्य में बरेली, नैनीताल, अलमोड़ा, देहरादून, बिजनौर, उत्तरकाशी, टीहरी-गढ़वाल, गढ़वाल, पीलीभीत, रामपुर, आगरा, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुज्जफरनगर, चमोली, पिथौरागढ़, बदायूं, एटा, मुरादाबाद और हरदोई के सिविल जिले ।"

[सं० एस 16025/37/79-एल०डब्ल्यू० (I)]

New Delhi, the 30th May, 1980

S.O. 1641.—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, (37 of 1970), the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3065, dated the 21st July, 1971, namely :—

In the Schedule to the said notification :—

1. against serial number 37 for the entry in Column 3, the following entry shall be substituted, namely :—

"Civil Districts of Kanpur, Lucknow, Etawah, Jhansi, Hamirpur, Banda, Jalaun, Gorakhpur, Gonda, Behraich, Azamgarh, Ballia, Basti, Ghazipur, Barabanki, Kheri, Rai Bareli, Unnao, Sitapur, Deoria, Pratapgarh, Jaunpur, Allahabad, Mirzapur, Varanasi, Faizabad, Fatehpur, Sultanpur, Mainpuri, Lalitpur, Robertganj and Farrukhabad in the State of U.P.".

2. against serial number 38 for the entry in column 3 the following entry shall be substituted, namely :—

"Civil Districts of Rohtak Sonepat, Gurgaon, Faridabad and Mohindergarh in the State of Haryana and Union Territory of Delhi".

3. against serial number 40,

(a) for the entry in Column 2, the following entry shall be substituted, namely :—

"Assistant Labour Commissioner (C) Agra".

(b) for the entry in Column 2 and 3, the following entry shall be substituted, namely :—

"Civil Districts of Bareilly, Nainital, Almora, Dehradun, Bijnor, Uttar Kashi, Tehri-Garhwal, Garhwal, Pilibhit, Rampur, Agra, Shahjahanpur, Aligarh, Meerut, Saharanpur, Ghaziabad, Bulandshahar, Muzaffarnagar, Chamoli, Pithoragarh, Badaun, Etah, Moradabad and Hardoi in the State of U.P.".

[No. S. 16025/37/79-LW(I)]

का०आ० 1642.—केन्द्रीय सरकार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का०आ० 3064, तारीख 21 जुलाई, 1971 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में:—

1. क्रम संख्या 37 के सामने स्तम्भ 3 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:—

"उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर, लखनऊ, इटावा, झांसी, हमीरपुर, बांदा, जौलौन, गोरखपुर, गोंडा, बहराइच, आजमगढ़ बलिया, बस्ती, गाजीपुर, बाराबंकी, खेरी, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, देवरिया, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, मिरजापुर, वाराणसी, फैजाबाद, फतेहपुर, सुलतानपुर, मैनपुरी, ललितपुर, रोबर्टगंज और फरुखाबाद के सिविल जिले ।"

2. क्रम सं० 38 के सामने, स्तम्भ 3 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:—

"हरियाणा राज्य में रोहतक, सोनीपत, गुड़गांवा, फरीदाबाद, और मोहिन्द्रगढ़ के सिविल जिले और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र ।"

3. (क) क्रम संख्या 40 के सामने, स्तम्भ 2 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:—

"सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), आगरा" ।

(ख) स्तम्भ 3 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

"उत्तर प्रदेश राज्य में बरेली, नैनीताल, अलमोड़ा, देहरादून, बिजनौर, उत्तरकाशी, टीहरी-गढ़वाल, गढ़वाल, पीलीभीत, रामपुर, आगरा, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुज्जफरनगर, चमोली, पिथौरागढ़, बदायूं, एटा, मुरादाबाद, और हरदोई के सिविल जिले ।"

[सं०एस० 16025/37/79-डब्ल्यू एल (II)]
आर० कुंजीथापदम, उप सचिव

S.O. 1642.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3064, dated the 21st July, 1971, namely :—

In the Schedule to the said notification ;

1. against Serial number 37 for the entry in Column 3, the following entry shall be substituted, namely :—

"Civil Districts of Kanpur, Lucknow, Etawah, Jhansi, Hamirpur, Banda, Jalaun, Gorakhpur, Gonda, Bahraich, Azamgarh, Ballia, Basti, Ghazipur, Barabanki, Kheri, Rai Bareilly, Unnao, Sitapur, Deoria, Pratapgarh, Jaunpur, Allahabad, Mirzapur, Varanasi, Faizabad, Fatehpur, Sultanpur, Mainpuri, Lalitpur, Rabortsganj, and Farrukhabad in the State of Uttar Pradesh".

2. against serial number 38 for the entry in column 3 the following entry shall be substituted, namely :—

"Civil Districts of Rohtak, Sonepat, Gurgaon, Faridabad, and Mohindergarh in the State of Haryana and Union Territory of Delhi".

3. (a) against serial number 40, for the entry in column 2, the following entry shall be substituted, namely :—

"Assistant Labour Commissioner (Central), Agra".

(b) for the entry in column 3, the following entry shall be substituted, namely :—

"Civil District of Bareilly, Nainital, Almora, Dehradun, Bijnor, Uttar Kashi, Tehri-Garhwal, Garhwal, Pilibhit, Rampur, Agra, Shahjahanpur, Aligarh, Meerut, Saharanpur, Ghaziabad, Bulandshahr, Muzaffarnagar, Chamoli, Pithorgarh, Badaun, Etah, Moradabad, and Hardoi in the State of Uttar Pradesh.

[No. S-16025/37/79-LW-(II)]

R. KUNJITHAPADAM, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 30 मई, 1980

का०आ० 1643.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3291, दिनांक 7 सितम्बर, 1979 के अनुक्रम में राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंग्रहालय परिषद, कलकत्ता के विश्वेश्वरैया औद्योगिक और प्राद्योगिक संग्रहालय, बंगलौर, के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पहली जुलाई, 1979 से 30 जून, 1980 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है ।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात:—

(1) पूर्वोक्त प्रतिष्ठान जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दिखाये जाएंगे ;

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते ;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही किए जा चुके हों तो वे वापिस नहीं किए जायेंगे ;

(4) उक्त प्रतिष्ठान का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस प्रतिष्ठान पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त अवधि" कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी :—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को जिसके प्रति फलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं ;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा —

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है ;

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते हैं ; और

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना, या

(घ) ऐसे कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उसमें उद्धरण लेना ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है, क्योंकि छूट के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र की कार्रवाई पर समय लगा। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं० एस-38014/39/77-एच०आई०]

New Delhi, the 30th May, 1980

S.O. 1643.—In exercise of the powers conferred by section 88 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3291, dated the 7th September, 1979, the Central Government hereby exempts the permanent and temporary employees of Visvesvaraya Industrial and Technological Museum, Bangalore belonging to the National Council of Science Museums, Calcutta from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st July, 1979 upto and inclusive of the 30th June, 1980.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid establishment wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees ;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates ;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded ;

(4) The employer of the said establishment shall submit in respect of the period during which that establishment was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(5) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or

other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) Ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S. 38014/39/78-HI]

का०आ० 1644.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 2752 तारीख 30-6-79 के अनुक्रम में, इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट, इण्डियन आयल कारपोरेशन, लिमिटेड, मुम्बई के कारखानों को, उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पहली जुलाई, 1979 से 30 जून, 1980 तक जिसके अन्तर्गत तारीख भी है, छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् —

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अवधि" कहा गया है। ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे अवधि की बाबत देनी थीं ;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों के सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ अनार्थ ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों की, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत थे, ऐसे उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं ;

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है ; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करने और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करने के लिए कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में उपस्थित हो या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पद धारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में, रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उसमें उद्धरण लेना।

अनुसूची

क्रम सं०	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम-1	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) पोस्ट बाक्स नं० 54, मलकापुरम इंस्टालेशन विशाखापत्तनम-1

1	2	3	4
2.	आन्ध्र प्रदेश	सिकन्दराबाद	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) पोस्ट बाक्स सं० 1634, आर० आर०सी० ग्राउण्ड, सिकन्दराबाद ।
3.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) स्टेशन रोड, विजयवाड़ा ।
4.	आन्ध्र प्रदेश	सिकन्दराबाद-14	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड विमानन ईंधन स्टेशन डाकघर हाकिमपेट वायु सेना स्टेशन, सिकन्दराबाद-14 ।
5.	दिल्ली	दिल्ली	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) एल०पी०जी० आटलिंग, प्लाट शकूर बस्ती, दिल्ली-26
6.	दिल्ली	दिल्ली	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग) शिवाजी पार्क के सामने शकूर बस्ती दिल्ली-26
7.	दिल्ली	दिल्ली	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, विमानन ईंधन स्टेशन, सदर बाजार रोड मोरी लाइन के पास, पालम, दिल्ली कैंट-10
8	केरल	कोचीन	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग) पोस्ट बाक्स सं० 535, विलिंगडन द्वीप, हारबर रोड, कोचीन-3
9.	केरल	कोचीन	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) कोचीन परिष्करण, प्रतिष्ठापन, पोस्ट बाक्स न० 8, त्रिपुर्नीथ द्वारा कोचीन
10.	केरल	कोचीन	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) कर्षक रोड, पोस्ट बैग 1759, एर्नाकुलम, कोचीन-6
11.	तमिलनाडु	मद्रास	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग) एनीबहाई रोड, मद्रास
12.	तमिलनाडु	मद्रास	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) कोम्पेट, मद्रास-21
13.	तमिलनाडु	मद्रास	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), नार्थ रेलवे टर्मिनल रोड, रोयापुरम मद्रास ।
14.	तमिलनाडु	मद्रास	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, विमानन ईंधन स्टेशन मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा मद्रास
15.	तमिलनाडु	मद्रास	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, ट्यब ब्लेंडिंग प्लांट, अन्नेरे हवाई रोड, तनीआ रपेट हो तीरूवथाइर पोस्ट, मद्रास-81
16.	महाराष्ट्र	मुम्बई	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) सरकारी फूड ग्रेन्स गोदाम के पास, वावला, मुम्बई 31
17.	महाराष्ट्र	मुम्बई	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग) टाटा ताप विद्युत संयंत्र के पास, ट्राम्बे कोरीडोर रोड, मुम्बई 74
18.	महाराष्ट्र	मुम्बई	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग से वारी रेलवे स्टेशन के सामने, बम्बई 15
19.	महाराष्ट्र	पूना	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग) राजबहादुर मोतीलाल रोड, पूना
20	महाराष्ट्र	मुम्बई	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, विमानन ईंधन स्टेशन, सांताक्रुज विमान पत्तन, मुम्बई-29
21	कर्नाटक	बंगलौर	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग) नागवी रोड, पोस्ट बैग न० 3, बंगलौर-23
22.	कर्नाटक	बंगलौर	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, विमानन ईंधन स्टेशन, बंगलौर, विमान पत्तन बंगलौर ।

1	2	3	4
23.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड विमानन ईंधन स्टेशन, बेगमपेट विमान हैदराबाद ।
24.	पंजाब	जालंधर	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग) रेलवे गुड्स रोड, जालंधर
25.	हरियाणा	अम्बाला छावनी	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग बल्क सैन्टर अम्बाला छावनी ।
26.	हरियाणा	हिसार	इण्डिया आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग) हिसार ।
27.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग) अरमापुर, कानपुर ।
28	महाराष्ट्र	नागपुर	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), मोती बाग, नागपुर ।
29.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग) दम-दम विमान पत्तन, कलकत्ता ।
30	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग) मोरी ग्राम प्रतिष्ठान डाकघर राधा दामी जिला, हावड़ा ।
31.	पश्चिम बंगाल	पहाड़पुर	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग) पहाड़पुर प्रतिष्ठान पश्चिम बंगाल
32.	पश्चिम बंगाल	24 परगना	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग) बज-बज प्रतिष्ठान डाकघर बज-बज 24 परगना, पश्चिम बंगाल ।
33	असम	गोहाटी	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन गोहाटी प्रतिष्ठान, गोहाटी
34.	बिहार	पटना	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग) पटना प्रतिष्ठान, पटना
35.	उत्तर प्रदेश	आगरा	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), खेरिया विमान क्षेत्र, आगरा-8
36.	केरल	तूतीकोरीन	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) तूतीकोरीन प्रतिष्ठान, बंदरगाह परियोजना परिसर, तूतीकोरीन-4
37.	उड़ीसा	कटक	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), शिकापुर, डाकघर चौलीगंज, कटक ।
38.	गोवा	वास्को-डि-गामा	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), वास्को-डी-गामा, गोवा ।
39.	कर्नाटक	मंगलूर	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), मंगलूर प्रतिष्ठान, मंगलूर ।
40	उत्तर प्रदेश	कानपुर	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, (परिष्करणी और पाइप लाईन्स प्रभाग कानपुर । स्टेशन, अरमापुर, कानपुर ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है, क्योंकि छूट के प्रस्ताव पर विचार करने में समय लगा । तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं० एस०/38014/30/78-एच०-1]

हंसराज छाबड़ा, उप सचिव

S.O. 1644.—In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2752, dated the 30th June, 1979, the Central Government hereby exempts the factories, specified in the Schedule annexed hereto, belonging to the Indian Oil Corporation Limited, Bombay, from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from 1st July, 1979 upto and inclusive of the 30th June, 1980.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

(1) The employer of the said factories shall submit in respect of the period during which the factories were subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other

Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of Section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or oher premises, or any person whom the said Inspector or other official, has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

SCHEDULE

S. No.	Name of the State or Union Territory	Name of Area	Name of factory
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	Visakhapatnam-1	Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division) Post Box No. 54, Malkapuram Installation Visakhapatnam-1.
2.	Andhra Pradesh	Secunderabad	Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division) Post Box No. 1634, RRC Ground, Secunderabad.
3.	Andhra Pradesh.	Vijayawada	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division) Station Road, Vijayawada.
4.	Andhra Pradesh	Secunderabad-14	Indian Oil Corporation Limited, Aviation Fuel Station, Post Office Hakimpet Air Force Station, Secunderabad-14.
5.	Delhi	Delhi	Indian Oil Corporation Ltd. Marketing Division) L. P. G. Bottling Plant, Shakurbasti, Delhi-26.
6.	Delhi	Delhi	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Opposite Sivaji Park, Shakurbasti Delhi-26.
7.	Delhi	Delhi	Indian Oil Corporation Limited Aviation Fuel Station, Sadar Bazar Road, Near More Line, Palam, Delhi Cantt-10.
8.	Kerala	Cochin	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Post Box No. 535, Willington Island, Harbor Road, Cochin-3.
9.	Kerala	Cochin	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Cochin Refinery Installation, Post Box No. 8, Tripunith Via Cochin.
10.	Kerala	Cochin	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Kashaka Road, Post Bag 1759, Ernakulam, Cochin-6.
11.	Tamil Nadu	Madras	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Ernove High Road, Madras.
12.	Tamil Nadu	Madras	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Korukupet, Madras-21.
13.	Tamil Nadu	Madras	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division) North Railway Terminus Road, Royapuram, Madras.
14.	Tamil Nadu	Madras	Indian Oil Corporation Limited, Aviation fuel Station, Meenambakkam Airport Madras.
15.	Tamil Nadu	Madras	Indian Oil Corporation Limited, Tube Blending Plant, Ennere High Road, Teniarpet Tiruvethiyur Post, Madras-81.
16.	Maharashtra	Bombay	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Near Government Food Grains Godowns, Wadala, Bombay-31

1	2	3	4
17.	Maharashtra	Bombay	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division, Near Tata Thermal Power Plant, Trombay, Corridor Road, Bombay-74.
18.	Maharashtra	Bombay	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Opposite Sewaree Railway Station, Bombay-15.
19.	Maharashtra	Poona	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Rajbahadur Motilal Road, Poona.
20.	Maharashtra	Bombay	Indian Oil Corporation Limited, Aviation Fuel Station Santa Cruez Airport, Bombay-29.
21.	Karnataka	Bangalore	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Nagadi Road, Post Bag No. 3, Bangalore-23.
22.	Karnataka	Bangalore	Indain Oil Corporation Limited, Aviation Fuel Station, Bangalore Airport, Bangalore.
23.	Andhra Pradesh	Hyderabad	Indian Oil Corporation Limited, Aviation Fuel Station, Begumpet Airport, Hyderabad.
24.	Punjab	Jullundur	Indian Corporation Limited, (Marketing Division) Railway Goods Shed Road, Jullundur.
25.	Haryana	Ambala Cantonment	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division) Bulk Centre, Ambala Cantonment.
26.	Haryana	Hissar	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Hissar.
27.	Uttar Pradesh	Kanpur	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Armapore, Kanpur.
28.	Maharashtra	Nagpur	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Moti Bagh, Nagpur.
29.	West Bengal	Calcutta	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division) Dum-Dum Aviation Fuel Station Dum-Dum Airport, Calcutta.
30.	West Bengal	Calcutta	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division) Mourigram Installations, Post Office Radhadasi District, Howrah.
31.	West Bengal	Paharpur	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division) Paharpur Installations, West Bengal.
32.	West Bengal	24 Paraganas	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division) Budge Budge Installations, Post Office Budge Budge 24, Paraganas, West Bengal.
33.	Assam	Gauhati	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division) Gauhati Installation, Gauhati.
34.	Bihar	Patna	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division) Patna Installation, Patna.
35.	Uttar Pradesh	Agra	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division) Kheria Air Field, Agra-8.
36.	Kerala	Tuticorin	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Tuticorin Installations, Harbour Project Premises, Tuticorin-4.
37.	Orissa	Cuttack	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Shikapore, P. O. Chauliganj, Cuttack.
38.	Goa	Vasco-de-Gama	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Vasco-de-Gama, Goa.
39.	Karnataka	Mangalore	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division., Mangalore installations, Manglore.
40.	Uttar Pradesh	Kanpur	Indian Oil Corporation Limited, (Refineries and Pipe Lines Division) Kanpur I Station, Armapur Kanpur.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the proposal for exemption took time. However it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38014/30/78-HI]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

New Delhi, the 31st May, 1980

S.O. 1645.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Shantadurga Ore Transport (Vagus), Pale (Goa) and their workmen, which was received by the Central Government on the 19th May, 1980.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/8 of 1978

PARTIES :

Employers in relation to the management of M/s Shantadurga Ore Transport (Vagus) Vagus) Pale (Goa).

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—No apperance.

For the Workmen—No appearance.

INDUSTRY : Mining STATE : Goa, Daman and Diu

AWARD

Bombay, dated the 12th May, 1980

1. The Government of India, in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred by section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Messrs. Shantadurga Ore Transport (Vagus), Vagus, Pale (Goa) and their workmen for adjudication to this Tribunal vide order No. L 26012/3/78-D.III.B., dated 20-10-1978 :—

"Whether the action of the Management of Messrs Shantadurga Ore Transport (Vagus), Vagus, Pale (Goa) in terminating the services of Shri Suresh Naik, Truck-Driver with effect from 19th January, 1978 is justified. If not, to what relief is the aggrieved workman entitled ?"

2. It appears that this reference was received by this Tribunal on 1-11-1978 and, accordingly, notices were issued to both parties to file their claim/written statements. The management filed their written statement on 28-12-1978. Thereafter several notices were issued to both the parties but they never appeared before this Court. The workman did not file his claim statement at all. After I joined here I issued notice on 22-3-1980 directing them to file their claim statement by 14-4-1980 failing which the reference will be disposed of ex-parte, but in spite of it no appearance was made either by the management or by the workman. Again another notice was issued on 16-4-1980 directing the workmen to file his claim statement positively by 7-5-1980. On that date also no appearance was made or any claim statement was filed. The Court, however, waited till 12-5-1980 so that any information may be received even by post. But till today no intimation was received from either party, nor they have appeared before the Court.

3. In the circumstances there is no alternative but to answer the reference against the workman for non-prosecution of his case by his Union and I give my Award accordingly.

JITENDRA NARAYAN SINGH, Presiding Officer

[No. L-26012/3/78-D. III B]

A. K. ROY, Under Secy.

New Delhi, the 3rd June, 1980

S.O. 1646.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Benedih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Nawagarh, District Dhanbad and their workmen which was received by the Central Government on the 27th May, 1980.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2), DHANBAD

Reference No. 73 of 1979

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Benedih colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Nowagarh, Distt. Dhanbad.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri B. Joshi, Advocate.

On behalf of the workman—Shri Lalit Burman, Secretary, United Coal Workers Union, Dhanbad.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated the 12th May, 1980.

Campt : Patna.

AWARD

This is a reference under S. 10 of the I.D. Act, 1947. The Central Government by its notification No. L-20012/132/76-D.III(A), dated 28th July, 1977 had referred this dispute to the Central Government Industrial Tribunal (No. 3) Dhanbad for adjudication on the following terms :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Benedih colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Nawagarh, District Dhanbad, in stopping Shrimati Kaushilya Kamin, Picking mazdoor from duty is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled and from what date ?"

The case has been transferred to this Tribunal from CGIT-cum-Labour Court (No. 3) Dhanbad on 7-7-1979 whereafter due to concerted effort made by this court the hearing has been completed.

Smt. Kaushilya Kamin (Rajwarin) had been working in Benedih colliery as picking kamin since 1965. According to her although her conduct was above reproach the management arbitraliy removed here from work w.e.f. 11-9-1975. The union to which she belonged raised an industrial dispute in which the management participated. On account of the failure of conciliation this reference has been made to this court for adjudication. According to the concerned workman

the action of the management was totally wrong, unjustified and illegal. She has claimed reinstatement in her post with full back wages and other benefits from 11-9-1975 and unpaid wages for the month of August, 1975 and wages from 1-9-75 to 10-9-75.

The management in their written statement alleged that one lady named Kaushilya was employed on 11-2-1965 at Benedih colliery as shale picker and she was aged 45 years on the date of her employment. The management of the colliery was taken by the Central Government w.e.f. 17-10-71 and the colliery was nationalised w.e.f. 1-5-1972. The Payment of Gratuity Act, 1972 came into force w.e.f. 16-9-72 and the employers started compiling all the details of each employees and started superannuating the old employees. But some workmen working in different collieries adopted various tactics to circumvent the provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972 and the case of Kaushilya Kamin was one such. In the year 1975 Smt. Kaushilya Kamin reached the age of 55 years according to the record maintained in the colliery. She was advised by the loading clerk to produce her identity card for the purpose of sending her for medical examination and determination of her physical fitness. The old lady thereafter stopped coming to attend her duties w.e.f. 11-9-75 and sent in her place her daughter who reported for duties as Kaushilya Kamin. The loading clerk Shri P. C. Shah, did not allow the daughter of Kaushilya Kamin to work in the name of Kaushilya Kamin and reported the fact to the manager of the colliery. The manager directed him not to allow the new lady on duty till the matter was enquired into. The manager requested Shri A. K. Bose, the Assistant Manager of Benedih colliery to hold enquiry and to submit a report regarding the allegation levelled against Kaushilya Kamin. Shri Bose submitted his report on 28-9-75. The management after considering all the materials on record and the statement of the co-workers observed that the new lady who reported for duty posing herself as Kaushilya Kamin had made preparatory arrangement for her entry into the colliery in place of her mother surreptitiously. According to the management the new lady was not the real worker and the management was justified in not allowing her to work in place of her mother. It was further alleged that Kaushilya Kamin the old lady who worked prior to 11-9-75 was absenting herself from her duty with the hope to get her daughter employed in her place. The management, however, stated that they did not stop the real Kaushilya Kamin from duties w.e.f. 11-9-75 or from any other date. On the above plea the management has prayed for dismissal of the reference.

The main question to be determined in this case is whether the concerned workman is Kaushilya Kamin or her daughter. The management have filed certain documents in support of their contention. Ext. M 1 is a letter dated 13-9-65 from the manager, Benedih colliery to the Asstt. manager, Shri A. K. Bose. This letter shows that Smt. Kaushilya Kamin had stopped working and sent her daughter in her place and had also drawn payment since the time of take over. It was further stated that the daughter of Kaushilya Kamin had come to work with identity card showing her own photograph Since the case was mysterious, Shri A. K. Bose was asked to make enquiry and to report at the earliest. Ext. M 2 is the enquiry proceeding and Ext. M 3 is the report of the enquiry officer. Ext. M 4 is five attendance registers in Form E, Ext. M 5 is endorsement on the attendance register week ending 1975. Ext. M 6 is 5 wage sheets and Ext. M 7 is extract of form B register in respect of Kaushilya Kamin.

On behalf of the concerned workman a number of documents have been proved. Ext. W. 1 is identity card of Kaushilya Kamin showing the date of issue to be 25-8-73. This contains the photograph of the concerned workman. Ext. W.2 is payment sheet for 9/75 in respect of Kaushilya Kamin (Rajwarin). Ext. W. 3 dated 21-1-76 from the Senior Manager to the Secretary, United Coal Workers Union Ext. W. 3/1 is a letter daed 6-4-76 from the Senior Manager to the Asstt. Labour Commissioner(C) Dhanbad-II. Ext. W. 4 is failure report of conciliation dated 26-5-76 of Asstt. Labour Commissioner(C) Dhanbad. Ext. W. 5 is a letter dated 11-9-75 signed by Shri Kartik Yadav Secretary of the union addressed to the manager. Ext. W. 6 is another such letter dated 17-9-75. Ext. W. 7 is a letter dated 16-9-75 signed by Shri Lalit Burman secretary of the union to the manager. Ext. W. 8 is another such letter dated 6-1-76.

MW. 1, Shri Prabin Chandra Shah is a loading clerk in Benedih colliery since 1972. His evidence is that when he joined in the colliery he found Kaushilya Kamin an old female working as shale picker. He was asked by the manager to prepare a list of loaders and pickers who were about to reach 55 years of age. He prepared a list including the name of Kaushilya Kamin. His evidence is that thereafter a young woman being the daughter of Kaushilya Kamin came to work in the place of Kaushilya Kamin and he did not permit her to work as she was not Kaushilya Kamin. She produced her photograph but even then he did not permit her to work as she was not a genuine worker and informed the manager. Shri Bose, Assistant manager made enquiry into the matter. His evidence is that the old Kaushilya Kamin did not turn up for work. In his cross-examination he has said that the manager asked him to prepare a list of workers who were likely to superannuate, and this happened in october, 1975. He has further said that he did not consult the concerned persons while preparing the list and he estimated their age from their appearance. In the list he did not mention any identity card. With regard to the enquiry conducted by Shri Bose he has said that Shri Bose examined 7 shale pickers the loading supervisor Shri R. N. Choudhury and the witness himself. In that enquiry Kaushilya Kamin and her daughter were also examined.

MW. 2 Shri Ashim Kumar Bose had held the enquiry. In his cross-examination he has said that Kaushilya Kamin was given identity card by the management and her daughter produced it at the time of enquiry. He has proved the identity card, Ext. W. 1. He has further said that the identity card bears the photograph of the concerned workman who was asking for a job. His evidence is that he had checked the register of identity cards and found that the identity card register had the same photographs as in the identity card issued to Kaushilya Kamin. It has been suggested to him in cross-examination that the enquiry proceeding and the enquiry report were all prepared after the reference was made in order to put up a defence.

MW. 3 Shri B. C. Banerjee has been a loading munshi in the Benedih colliery for the last 22 years He knew Kaushilya Kamin who was working since 1965 when she was aged 45 years. In 1975 the loading clerk required Kaushilya Kamin to produce her identity card for sending her for medical examination and thereafter she stopped coming to attend to

her duties. He said that another lady reported in her place. The loading clerk thereafter reported the matter to the manager and did no permit her to work. The identity card of Kaushilya Kamin was shown to the witness who deposed that the photograph appearing in the identity card was not of Kaushilya Kamin. He was not however aware whether any identity card was issued to real Kaushilya Kamin. He has admitted that the retirement age of a workman is 60 years.

On behalf of the workmen, 3 witnesses were examined. WW. 1 is Shri Kartik Yadav. He knew Smt. Kaushilya Kamin (Rajwarin) who started working from 1965. He also knew her mother named Smt. Santi Rajwarin. Smt. Santi Rajwarin was working in the colliery since 1947 and she left the service before the take over of the colliery by the Central Government. She also withdrew her account from Coal Mines Provident Fund. He has proved letters, Ext. W. 5 and Ext. W. 6 signed by him as Branch Secretary of the Union. He has also proved two letters signed by Shri Lalit Burman, which are Exts. W. 7 and W. 8. He has further said that the identity card, Ext. W. 1 bears the signature of Mr. Sen who was the manager of Benedih Colliery in 1972. His evidence is that Kaushilya Kamin was not given any letter or notice before she was stopped from work. According to him the manager informed the police alleging that Kaushilya Rajwarin was an imposter. The police had made enquiries in which the witness and the Welfare Officer of the colliery asserted that the concerned workman, Smt. Kaushilya Rajwarin was a genuine worker. The management, however, did not allow Smt. Kaushilya Rajwarin to join work, and thereafter an industrial dispute was raised.

W.W. 2 is Smt. Kaushilya Kamin. She has asserted that she has been working for 4/5 years before the nationalisation of the colliery as picking kamin and continued to work even after nationalisation till she was stopped from work. She was not given any order or notice before she was stopped from work. She reported the matter to Shri Kartik Yadav, the Union leader. The manager refused to give her work. She has admitted that one of the officer of the colliery Mr. Bose made some enquiries before she was stopped from work. Mr. Bose had simply asked her whether she was Kaushilya Kamin or not. Mr. Bose also made enquiries from other people such as Choudhury Babu, loading babu and Welfare Officer. The police had also made some enquiries from the colliery. With regard to the mother's name she had said that her mother's name was Smt. Santi Rajwarin. According to her her mother was also working in the colliery. But she had left the service. With regard to the photograph in the identity card, she has said that her photograph was taken and the same was affixed in her identity card.

W.W. 3 is Shanti Rajwarin. She has identified the concerned workman as her daughter named Kaushilya Kamin. She has admitted that she was working in Benedih Colliery before nationalisation. She stopped work during the time of the erstwhile employer and her daughter Kaushilya Kamin was employed by the erstwhile employer in her place. Since then, and even after nationalisation, her daughter Kaushilya Kamin continued to work in Benedih Colliery. She said that while she was working in the colliery she was a member of the CMPF and deductions used to be made from her pay. She got refund of the provident fund contribution after she stopped working. She has denied that her name is Kaushilya Kamin.

The above is all the evidence adduced in this case by the parties. Now let us see what conclusion can be arrived at from the above evidence. I have already said that according to the management in October, 1975 a list was prepared of all such workers who were likely to superannuate and that included Kaushilya Kamin. Kaushilya Kamin was also required to produce her identity card, but instead of producing the identity card, she absented herself and instead sent her daughter for work in her place. The loading clerk did not permit her daughter and reported the matter to the manager. Since then the daughter of the real worker Kaushilya Kamin was not permitted to work and the real Kaushilya Kamin herself never appeared for work. But Ext. M 1 gives a different picture. For appreciation of the case I am giving below the first two paragraphs of this letter :

> "A case has come to my notice that one Smt. Kaushilya Kamin designated as picking kamin has stopped working and sent her daughter in her place when she came to know that she is going to be superannuated due to old age. As the report goes, she has all along been working as Kaushilya Kamin and has drawn payment since the time of take over.
>
> How her daughter has come to work with identity card with her photo inserted in the identity card."

Now from the first paragraph it appears that the concerned workman was working as Kaushilya Kamin and has drawn payment since the time of take over. Now let us look into Ext. W. 3/1. I am giving below the contents of the entire letter for a fuller appreciation :

"BHARAT COKING COAL LIMITED.

Ref. No. BC/Asst-L-C/50, Dt. 6th April, 1976.

To,

The Asstt. Labour Commissioner (C).
Dhanbad-II.

Subject :—Industrial dispute in Benedih Colliery over alleged wrongful idleness stop non-payment of wages and harassment of Smt. Kaushilya Rajwarin, picking kamin.

Ref : Your letter No. 1/(93)/76-D-2, dated 20th March, 1976.

Dear Sir,

Our comments in the matter as above are noted herein under :—

1. It is a fact that Smt. Kaushilya Rajwarin, wife of late Ashu Rajwar was a bona fide worker of this colliery working as a picking kamin.

2. The above workman had been absenting without leave or permission from her work and allowed wrongfully her mother Smt. Santi Kamin to work in her place. When it was detected Smt. Santi Kamin was stopped from work on and from 11th September, 1975 as she was not the genuine worker of the colliery. It is not a fact that she was allowed to resume her duty for some time as alleged by the union.

3. The matter was enquired into and it has been found that Smt. Santi Kamin who had been working in place of her di ghter, Smt. Kaushilya Rajwarin was an imposter.

4. As Smt. Santi Kamin had worked without permission of the co iery manager, she was not entitled for any payment whatsoever as above.

5. We may further inform you that a complaint against Smt. Santi Kamin an imposter has been lodged to the officer-in-charge, Baghmara Police Station for necessary action

Under the circumstances as above we shall request you to draw the case under reference as it does not have any merit.

Yours faithfully,

Sd/-

Sr. Manager."

Now this is a letter containing the case of the management at the time of the industrial dispute. The contents of this letter upsets the entire case of the management put forth in the written statement. It will appear that the management admitted the concerned workman to be Smt. Kaushilya Rajwarin wife of late Ashu Rajwar. The management's case was that Kaushilya Kamin had stopped work and in her place Smt. Santi Kamin her mother used to work. But when it was detected Smt. Santi Kamin was not permitted to work from 11th September, 1975. The matter was enquired into by the management and it was found that Smt. Santi Kamin who had been working in the place of her daughter was an imposter. A police case was instituted against Smt. Santi Kamin as an imposter. Ext. W. 4 is a letter written by the Asstt. Labour Commissioner (C), Dhanbad to the Secretary Government of India, Ministry of Labour, New Delhi. The management case has been summarised on the basis of Ext. W. 3/1. In fact, Ext. W. 4 is a letter on the basis of which this reference for adjudication has been made. It is, therefore, clear that the management has reversed the case at the time of filing their written statement in this reference. I do not think that they could be permitted to do so. From the picture presented at the time of conciliation proceeding it is apparent that Kaushilya Kamin had been a genuine worker and she was enrolled as a worker at the time of take over and also worked after nationalisation. The identity card issued in 1972 shows her photograph. In the payment registers there are thumb impressions. If the management was doubtful about the genuinenc s of the thumb impressions on the payment register they could have got it verified from an expert. This was no. done and therefore we have to take it that the concerned workman was working since the time of take over and continued to work till she was stopped from work. Now the allegation has been that she herself stopped work and her mother Smt. Santi Kamin used to come and work in her place. This was detec ed by the management and not only Smt. Santi Kamin was stopped from work but a police case was also instituted. Now the admitted position is that the concerned workman, Kaushilya Kamin would continue to work unless her services were terminated. Now if she has stopped coming from work and her mother was substituted this was an offence for which a charge-sheet should have been issued against her and she could have been dismissed if the charge was proved. What I mean to say is that Kaushilya Kamin should not have been refused work without termination of her service under a regular departmental proceeding. This has been clearly not done. The management in this case has said that the concerned workman was stopped from work as she was an imposter. The management has therefore made a very great cofusion in taking a different stand at different times. When I mean to say is that at the time of conciliation proceeding Kaushilya's mother Smt. Santi Rajwarin was said to be an imposter and in this court Kaushilya was said to be an imposter Both these stand cannot go together and therefore the earlier stand that Kaushilya Kamin was a genuine worker has to be accepted. The management, therefore, cannot be justified in stopping her from work without a departmental proceeding and without establishing her guilt.

In the result, the action of the management of Benedih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Nawagarh, District Dhanbad, in stopping Shrimati Kaushilya Kamin, Picking mazdoor from duty is not justified. Consequently, Smt. Kaushilya Kamin is entitled to be reinstated in the job with effect from 11th September, 1975, the date on which she was stopped from work, with all back wages and other benefits admissible to her.

This is my award.

J. P. SINGH, Presiding Officer

[No. L-20012/132/76-D. III(A)]

S. H. S. IYER, Desk Officer

नई दिल्ली, दिनांक

का० आ० 1647.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 36 के अनुसरण में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष

(यहां 1977-78 वर्ष संबंधी परीक्षित लेखों तथा उनके

कर्मचारी राज्य

1977-78

परिशिष्ट

कर्मचारी राज्य

31 मार्च, 1978 को

पिछला वर्ष (1976-77)	लेखा शीर्ष	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
	1. बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को हितलाभ		
	(क) चिकित्सा हितलाभ		
33,99,42,691	1. चिकित्सा उपचार तथा प्रसूति सुविधाएं आदि की व्यवस्था पर होने वाले खर्च में निगम के शेयर के रूप में राज्य सरकारों आदि को अदायगियां घटाएं—राज्य सरकारों को वर्ष के दौरान चिकित्सा देखरेख की बाबत ऐसी अदायगियां जो पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि में अंतरित की गई	44,46,64,850	
33,99,42,691	2. चिकित्सा उपचार व देखरेख तथा प्रसूति सुविधाएं (निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया व्यय)		
2,42,93,657		2,64,08,246	
36,42,36,348	जोड़—क—चिकित्सा हितलाभ		47,10,73,096
	(ख) नकद हितलाभ		
18,85,54,244	1. बीमारी हितलाभ	27,09,36,456	
2,38,02,242	2. विस्तारित बीमारी हितलाभ	2,62,66,978	
41,98,442	3. परिवार नियोजन के लिए वर्धित बीमारी हितलाभ	6,54,211	
1,51,31,634	4. प्रसूति हितलाभ	1,73,39,538	
	5. अपंगता हितलाभ		
4,39,29,068	(क) अस्थायी	5,01,33,495	
5,20,26,000	(ख) स्थायी (पूंजीकृत मूल्य)	*1,48,69,252	
1,47,11,000	6. आश्रितजन हितलाभ (पूंजीकृत मूल्य)	ब1,67,90,647	
9,13,803	7. अन्त्येष्टि हितलाभ	9,52,449	
34,32,66,433	जोड़ (ख) नकद हितलाभ		39,79,43,077
70,75,02,781	आगे ले जाया गया जोड़		86,90,16,173

12 अप्रैल, 1979

1977-78 सम्बन्धी परीक्षित लेखे तथा उनके संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट आम सूचना के लिए प्रकाशित की जाती है ।

संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सन्निविष्ट करें)

बीमा निगम

वर्ष के लेखे

20

बीमा निगम

समाप्त वर्ष का आय-व्यय लेखा

पिछला वर्ष (1976-77)	लेखा शीर्ष	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
	1. अंशदान		
1,23,61,94,824	नियोजकों तथा कर्मचारियों का शेयर	1,31,11,81,105	
93,97,151	केवल नियोजकों का शेयर	25,97,022	
1,07,22,754	केवल कर्मचारियों का शेयर	48,90,539	
1,78,865	अंशदानों पर ब्याज	5,97,322	
1,25,64,93,594	कुल अंशदान		1,31,92,65,988
14,12,271	निगम द्वारा चिकित्सा हितलाभ पर प्रारम्भ में किए गए व्यय में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों का शेयर	39,77,000.	
14,12,271			39,77,000
	सहायता अनुदान अन्य राजस्व शीर्ष		
7,29,00,062	ब्याज तथा लाभांश	8,00,73,589	
48,29,360	क्षतिपूर्ति	25,88,748	
	किराया महसूल तथा कर		
9,38,934	1. निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	6,57,269	
2,80,08,041	2. अस्पताल, डिस्पेंसरियां तथा स्टाफ क्वार्टर	3,48,62,153	
5,11,904	शुल्क, जुर्माना तथा समपहरण	26,18,074	
18,25,238	विविध	14,05,209	
10,90,13,539	अन्य राजस्व शीर्षों का जोड़		12,22,05,042
1,36,69,19,404	आगे ले जाया गया जोड़		1,44,54,48,030

पिछला वर्ष (1976-77)	लेखा शीर्ष	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
70,75,02,781	पीछे से लाया गया जोड़		86,90,16,173
	टिप्पणी—1977-78 के लिए धन व्यवस्था	5,20,93,000	
	*जोड़ें—स्थायी अपंगता हितलाभ की दरों में वृद्धि के कारण एक बार अतिरिक्त लागत	1,76,00,000	
	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	6,96,93,000	
	मूल्यांकक की पंचवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार घटाएं/अधिशेष	(—) 5,48,23,748	
	निवल :	1,48,69,252	
	"इसमें अस्पतालों के लिए प्रारम्भिक उपस्कर पर हुए व्यय का निगम का शेयर शामिल है।"		
	(ख) वर्ष में की गई धन व्यवस्था	1,26,25,000	
	जोड़ें—अपंगता हितलाभ की दरों में वृद्धि के कारण एक समय की लागत	1,04,00,000	
	जोड़	2,30,25,000	
	व घटाएं—पांचवी पंचवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मूल्यांकक द्वारा घोषित अतिशेष	(—) 62,34,353	
	निवल :	1,67,90,647	
	(ग) अन्य हितलाभ		
52,962	(क) अपंग बीमाकृत व्यक्तियों के पुनर्वास पर व्यय .	49,849	
3,02,065	(ख) चिकित्सा मंडल तथा अपील अधिकरण	3,50,931	
	(ग) बीमाकृत व्यक्तियों को अदायगियां :		
2,28,860	1. सवारी खर्च तथा/या मजदूरी की हानि	2,89,537	
—	2. परिवार नियोजन के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय	67,980	
—	(घ) सहायता अनुदान	—	
4,50,148	(ङ) विविध	5,82,252	
10,34,035	जोड़ (ग) अन्य हितलाभ		13,40,549
70,85,36,816	बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को कुल हितलाभ		87,03,56,722
	2. प्रशासन व्यय :		
	(क) अधीक्षण		
58,431	1. निगम, स्थायी समिति, क्षेत्रीय मंडल आदि	53,382	
2,32,984	2. प्रधान अधिकारी	2,35,188	
52,62,199	3. अन्य अधिकारी	55,35,025	
2,67,43,755	4. लिपिक वर्गीय स्थापना	2,72,91,379	
48,88,564	5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	46,23,122	
1,02,63,731	6. आकस्मिक व्यय	95,16,932	
4,74,49,664	जोड़ (क) अधीक्षण		4,72,56,028
	(ख) क्षेत्रीय कार्य		
9,82,820	1. अधिकारी	11,88,453	
2,52,94,493	2. लिपिक वर्गीय स्थापना	2,73,31,185	
41,36,460	4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	42,75,294	
27,05,691	4. आकस्मिक व्यय	30,72,174	
3,31,19,464	जोड़ (ख) क्षेत्रीय कार्य		3,58,67,106
	(ग) अन्य खर्चे		
89,369	1. अतिरिक्त महंगाई भत्ता जमा पर ब्याज		
3,22,181	2. कानूनी खर्चे	4,04,612	
34,880	3. बीमा न्यायालय	45,170	
72,575	4. प्रचार तथा विज्ञापन खर्चे	63,055	
2,77,254	5. बैंक लेखे रखने के लिए खर्चे	9,79,849'क'	
1,98,890	5. लेखा परीक्षा फीस	20,75,87	
84,722	7. छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान	93,310	
2,93,939	8. कार्यालय भवन स्टाफ कार का मूल्य-ह्रास	3,01,400	
7,45,328	9. कार्यालय भवनों की मरम्मत व अनुरक्षण	7,50,325	
	10. सेवा निवृत्ति हितलाभ		
49,64,352*	(क) निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन आरक्षित निधि	59,84,424**	
78,91,05,944	आगे ले जाया गया जोड़		95,34,79,856

*इसमें 5,93,962- रुपये की राशि शामिल नहीं है जो निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली के कार्यालय के कर्मचारियों की पेंशन देयताओं से संबंधित है, और 'क' (ii) चिकित्सा हितलाभ के अन्तर्गत शामिल की गई है क्योंकि यह राशि दिल्ली प्रशासन के साथ व्यय में शेयर की जानी है ।

पिछला वर्ष (1976-77)	लेखा शीर्ष	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
1,36,69,19,404	पीछे से लाया गया जोड़	1,44,54,48,030	

1,36,69,19,404	आगे लाया गया जोड़	1,44,54,48,030

पिछला वर्ष (1976-77)	लेखा शीर्ष	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
78,91,05,944	पीछे से लाया गया जोड़		95,34,79,856
2,55,688	(ख) क० रा० बी० निगम भविष्य निधि में निगम का अंशदान	2,62,181	
24,36,225	(ग) क० रा० बी० निगम भविष्य निधि में दिया गया ब्याज	29,39,240	
1,09,535	(घ) प्रोत्साहन बोनस	1,64,098	
—	(ङ) निवेशों की वसूली पर हानि	*—	
(—) 28,16,778	(च) घटाएं—भविष्य निधि अतिशेषों के निवेश पर प्राप्त ब्याज	@—	
29,434	11. अनुकंपा आरक्षित निधि	31,000	
64,640	12. भविष्य निधि जमा से जुड़ी बीमा निधि	1,00,000	
—	13. हानियां	8,000	
14,556	14. विविध	83,055	
71,76,790	जोड़ (ग) अन्य खर्चे		1,24,17,306
8,77,45,918	जोड़ शीर्ष—2—प्रशासन व्यय		9,55,40,440
	3. चिकित्सा और औषधालय		
26,30,818	1. चिकित्सालय भवनों का मूल्य ह्रास	31,53,779	
76,88,115	2 चिकित्सालय/औषधालय की मरम्मत तथा अनुरक्षण	91,00,566	
1,03,18,933	जोड़—शीर्ष—3 चिकित्सालय तथा औषधालय		1,22,54,345
	4. पूंजीगत निर्माण/आपात आरक्षित निधि		
12,56,49,360	1. पूंजीगत निर्माण	13,19,26,600	
8,69,33,675	2. आपात आरक्षित निधि	6,70,73,985	
	जोड़ शीर्ष 4—पूंजीगत निर्माण		
21,25,83,035	आपात आरक्षित निधि		19,90,00,585
1,01,91,84,702	राजस्व लेखों पर कुल व्यय		1,17,71,52,092
34,77,34,702	व्यय से अधिक आय को तुलन पत्र में ले जाना		26,82,95,938
1,36,69,19,404	कुल जोड़		1,44,54,48,030

** इसमें 5,82,390/-रुपये की राशि शामिल नहीं है जो निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली के कार्यालय के कर्मचारियों की पेंशन देयताओं से संबंधित है और 'क' (ii) चिकित्सा हितलाभ के अन्तर्गत शामिल की गई है क्योंकि यह राशि दिल्ली प्रशासन के साथ व्यय में शेयर की जानी है ।

(क) "इसमें अंशदान टिकटों की बिक्री पर बैंक द्वारा लिया गया कमीशन शामिल है जो पहले "2. (क) अप्रेक्षण-फुटकर खर्च (ग) अंशदान (ii) विक्रय और वितरण खर्चे के अन्तर्गत लेखागत किया गया था । "

@भविष्य निधि बकाओं के निवेश पर प्राप्त ब्याज "ब्याज और लाभांश" उपशीर्ष के अन्तर्गत जमा किया गया है ।

नई दिल्ली
दिनांक 31 मई, 1978

पिछला वर्ष (1976-77)	लेखा शीर्ष	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
1,36,69,19,404	पीछे से लाया गया जोड़		1,44,54,48,030
1,36,69,19,404	कुल जोड़		1,44,54,48,030

एम०एल० सोबती
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

परिशिष्ट

कर्मचारी राज्य

31 मार्च, 1978 की

पिछला वर्ष (1976-77)	देयताएं	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
	व्यय से अधिक आय का अतिशेष		
74,75,21,794	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,09,52,56,496	
34,77,34,702	वर्ष के दौरान संचयन	26,82,95,938	
1,09,52,56,496			
—	घटाएं—पिछले वर्ष के संचयन से आपात आरक्षित निधि में अंतरित राशि	—	
1,09,52,56,496			1,36,35,52,434
	आरक्षित निधियां		
29,76,67,469	1. पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि आदि शेष	43,73,52,629	
—	व्यय से अधिक आय के अतिशेष से अंतरित राशि	—	
12,56,49,360	जोड़ें—वर्ष में की गई धन व्यवस्था	13,19,26,600	
1,40,35,800	निवेशों पर प्राप्त ब्याज	1,72,42,307	
43,73,52,629			'क' 58,65,21,536
	2. स्थायी (आंशिक तथा पूर्ण) अपंगता हितलाभ आरक्षित निधि		
15,06,25,925	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	18,51,87,173	
5,20,26,000	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	6,96,93,000	'ख'
1,30,30,422	निवेशों से प्राप्त ब्याज	95,13,980	
2,27,571	निवेशों की वसूली पर लाभ	—	
—	घटायें—मूल्यांकन पर पांचवीं पंच वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अतिशेष	(—) 5,48,23,748	
21,59,09,918	इस शीर्ष का आगे ले जाया गया जोड़		20,95,70,405
1,53,26,09,125	आगे ले जाया गया जोड़		1,95,00,73,970

'क' इस राशि में से 19,18,99,835 रुपये निर्माण कार्यों के लिए दिए गए हैं । तथा 30,53,29,804/- रुपये का प्रतिभूतियों में निवेश किया गया है । बाकी 8,92,91,897 रुपये के रूप में अर्जित परिसम्पत्तियों तथा निर्माण एजेन्सियों द्वारा वापिस की गई धनराशियों के सूचक है ।

'ख' इसमें 1-10-77 से स्थायी अपंगता हितलाभ की दरों में वृद्धि के कारण एक बार अतिरिक्त लागत के रूप में 1,76,00,000 रुपये की राशि शामिल है ।

21

बीमा निगम

स्थिति का तुलनपत्र

पिछला वर्ष (1976-77)	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
	भूमि तथा भवन (निगम के पूर्ण स्वामित्व में)		
	(क) निगम कार्यालयों के लिए भवन		
1,59,89,007	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,80,57,416	
20,68,409	वर्ष के दौरान वृद्धि	19,65,477	
1,80,57,416		2,00,22,893	
	(ख) चिकित्सालय तथा औषधालय		
26,47,22,404@	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	29,79,95,923	
3,32,73,519	वर्ष के दौरान वृद्धि	2,52,12,899	
29,79,95,923@		32,32,08,822	
31,60,53,339	भूमि तथा भवन (निगम तथा राज्य सरकारों के संयुक्त स्वामित्व में) निगम का शेयर		34,32,31,715
	(क) चिकित्सालय तथा औषधालय		
9,26,807	*पिछले तुलनपत्र के अनुसार	9,26,807	
—	वर्ष के दौरान वृद्धि	—	
9,26,807			9,26,807

इसमें "चिकित्सालय आदि के लिए उपस्कर" के अन्तर्गत 1975-76 तक के लेखों में बुक किए गए 25,84,885/- रुपये की राशि शामिल है ।

*इसमे "चिकित्सालय आदि के लिए उपस्कर" के अन्तर्गत 1975-76 के लेखों तक बुक किए गए 49,680/- रुपये की राशि शामिल है ।

31,69,80,146	आगे ले जाया गया जोड़	34,41,58,522

@इसमें 1970-71 (बिहार) और 1972-73 (पश्चिमी बंगाल) के दौरान प्रारम्भ में "अस्पताल के लिए उपस्कर" पर विशेष आदेश के अन्तर्गत व्यय की गई 49,542/-रुपये और 25,35,343/- रुपये की राशि शामिल है ।

@"अस्पताल के लिए उपस्कर" पर व्यय (क) चिकित्सा हितलाभ "(1) चिकित्सा उपचार तथा प्रसूति सुविधाएं उपलब्ध करने पर किए गए व्यय के निगम के अपने शेयर के रूप में राज्य सरकार आदि को अदायगी" शीर्ष के अन्तर्गत बुक किया जा रहा है । अस्पताल के लिए प्रारम्भिक उपस्कर पर व्यय का पूंजीकरण निगम के विचाराधीन है ।

पिछला वर्ष (1976-77)	ब्यौरा	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
1,53,26,09,125	पीछे से लाया गया जोड़		1,95,00,73,970
21,59,09,918	इस शीर्ष का पीछे से लाया गया जोड़	20,95,70,405	
(—) 3,07,22,745	घटाएं—वर्ष में की गई अदायगियां	(—) 3,52,55,174	
18,51,87,173			17,43,15,231
	3. आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि		
6,82,35,452	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	8,26,77,671	
1,47,11,000	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	@2,30,25,000	
61,97,786	निवेशों से प्राप्त ब्याज	40,59,767	
76,814	निवेशों की वसूली पर लाभ	—	
--	घटाएं—मूल्यांकन पर पांचवीं पंचवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अतिशेष	(—) 62,34,353	
8,92,21,052			
(—) 65,43,381	घटाएं—वर्ष में की गई अदायगियां	(—) 77,41,226	
8,26,77,671			
	4. कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि :		9,57,86,859
3,00,20,126	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	3,58,92,828	
	जोड़ें—वर्ष में जमा की गई राशि		
1,07,76,205	1. कर्मचारियों का अंशदान	99,50,538	
2,55,688	2. निगम का अंशदान	2,62,181	
24,35,059	3. ब्याज (कर्मचारी तथा निगम के शेयर पर)	29,39,240	
(—) 16,15,141	4. महंगाई भत्ता जमा राशि	—	
1,09,448	5. प्रोत्साहन बोनस	1,64,098	
4,19,81,385	इस शीर्ष का आगे ले जाया गया जोड़	4,92,08,885	
4,19,81,385	इस उपशीर्ष का पीछे से लाया गया जोड़	4,92,08,885	
(—) 60,77,440	घटाएं—वर्ष में की गई अदायगियां	@(—) 79,60,565	
3,59,03,945		4,12,48,320	
	घटाएं—निम्नलिखित में अंतरित राशि		
(—) 11,117	(i) पेंशन आरक्षित निधि	(—) 23,988	
—	(ii) अदावी जमा राशि	—	
3,58,92,828			4,12,24,332
	भविष्य निधि जमा से जुड़ी बीमा निधि		
50,000	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	50,000	
64,640	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	1,00,000	
(—) 64,640	घटाएं—वर्ष में की गई अदायगियां	(—) 74,937	
50,000			75,063
	5. निगम कार्यालयों के भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मूल्यह्रास आरक्षित निधि		
21,77,836	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	26,43,052	
2,53,762	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	2,58,732	
2,11,454	निवेशों से प्राप्त ब्याज तथा लाभ	1,72,025	
26,43,052			30,73,809
1,83,90,59,849	आगे ले जाया गया जोड़		2,26,45,49,264

@इसमें 1-10-77 से अपंगता हितलाभ की दरों में वृद्धि के कारण एक समय की अतिरिक्त लागत के रूप में 1,04,00,000 रु० की राशि शामिल है।

@79,60,565 रु० में "अदावी जमा" में अन्तरित 9,330 रु० की राशि शामिल है।

पिछला वर्ष (1976-77)	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
31,69,80,146	पीछे से लाया गया जोड़		34,41,58,522
	उचंत (i) पूंजीगत व्यय के लिए दी गई राशि		
5,12,54,528	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	4,95,54,760	
—	जोड़ें—वर्ष में की गई अदायगियां	—	
(—) 16,99,768	घटाएं—समायोजन तथा वसूलियां	(—) 41,18,685	
4,95,54,760		(क) 4,54,36,075	
	(ii) पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि में से दी गई राशि		
10,22,96,581	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	13,41,76,637	
6,73,24,863	जोड़ें—वर्ष में की गई अदायगियां	8,23,26,026	
(—) 3,54,44,807	घटाएं—समायोजन तथा वसूलियां	(—) 2,46,02,828	
13,41,76,637		19,18,99,835	
18,37,31,397			23,73,35,910
	स्टाफ कारें		
5,03,517	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	5,31,617	
28,100	जोड़ें—वर्ष में की गई अदायगियां	33,579	
5,31,617			5,65,196
	निगम के कार्यालय अध्यक्षों को स्थायी पेशगी		
56,656	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	64,061	
7,510	जोड़ें—वर्ष में की गई अदायगियां	14,857	
64,166			
(—) 105	घटाएं—वर्ष में की गई वसूलियां	(—) 152	
64,061			78,766
	निगम के कर्मचारियों को स्थानान्तरण पर वेतन की अग्रिम अदायगी		
27,815	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	28,597	
1,03,151	जोड़ें—वर्ष में की गई अदायगियां	1,24,138	
1,30,966			
(—) 1,02,369	घटाएं—वर्ष में की गई वसूलियां	(—) 1,32,377	
28,597			20,358
	निगम के कर्मचारियों को स्थानांतरण पर यात्रा भत्ते की अग्रिम अदायगी		
68,981	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	91,683	
1,39,452	जोड़ें—वर्ष में की गई अदायगियां	1,73,663	
2,08,433			
(—) 1,16,750	घटाएं—वर्ष में की गई वसूलियां	(—) 1,86,110	
91,683			79,236
50,14,27,501	आगे ले जाया गया जोड़		58,22,37,988

(क) 1970-71 में पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि की स्थापना से पहले सामान्य रोकड़ शेष से दी गई अग्रिम राशि का सूचक है।

पिछला वर्ष (1976-77)	देयताएं	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
1,83,90,59,849	पीछे से लाया गया जोड़		2,26,45,49,264
	6. चिकित्सालयों भवनों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि		
2,41,44,626	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	2,91,12,568	
26,30,818	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	31,53,779	
23,37,124	निवेशों से प्राप्त ब्याज	21,96,821	
--	निवेशों की वसूली पर लाभ या हानि	—	
2,91,12,563			3,44,63,168
	7. स्टाफकारों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि		
4,22,960	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	5,04,613	
40,177	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	42,668	
41,476	निवेशों से प्राप्त ब्याज	48,037	
5,04,613			'ख' 5,95,318
	8. निगम कार्यालयों के भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मरम्मत व अनुरक्षण आरक्षित निधि		
38,93,578	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	48,31,089	
7,45,328	वर्ष में की गई धन-व्यवस्था	7,50,325	
1,99,813	निवेशों से प्राप्त ब्याज	1,05,983	
3,404	निवेशों की वसूली पर लाभ	--	
48,42,123			
(--) 11,034	घटाएं--वर्ष में की गई अदायगियां	(--) 7,45,900	
48,31,089			49,41,497
	9. चिकित्सालय भवनों की मरम्मत व अनुरक्षण आरक्षित निधि		
5,20,12,883	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	6,13,81,189	
76,88,115	वर्ष में की गई धन व्यवस्था	91,00,566	
39,95,626	निवेशों से प्राप्त ब्याज	28,19,239	
115	निवेशों की वसूली पर लाभ	--	
6,36,96,739	इस शीर्ष का जोड़	7,33,00,994	
(--) 23,15,550	घटाएं--वर्ष में की गई अदायगियां	(--) 19,56,748	
6,13,81,189			7,13,44,246
	10. निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन आरक्षित निधि		
5,85,15,481	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	6,90,24,383	
55,58,315	वर्ष में की गई धन-व्यवस्था	57,06,876	
58,22,889	निवेशों से प्राप्त ब्याज	42,93,580	
44,913	निवेशों की वसूली पर लाभ	--	
--	जोड़ें--मूल्यांकन पर पांचवीं पंच वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त धन-व्यवस्था	8,59,938	
6,99,41,598			
(--) 9,28,332	घटाएं--वर्ष में की गई अदायगियां	(--) 13,27,806	
6,90,13,266			
11,117	जोड़ें--कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि से अन्तरित राशि	23,988	
6,90,24,383			7,85,80,959
	11. आपात आरक्षित निधि		
11,00,16,095	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	20,75,09,770	
8,69,33,675	वर्ष में की गई धन-व्यवस्था	6,70,73,985	
1,05,60,000	निवेशों पर वसूल किया गया ब्याज	87,63,452	
—	घटाएं--आय से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व लेखों में अन्तरित राशि	--	
20,75,09,770			28,33,47,207
2,21,14,23,461	आगे ले जाया गया जोड़		2,73,78,21,659

'ख' इसमें 33,580 रु० की राशि शामिल है जो इस निधि में से खरीदी गई स्टाफ कार की उस लागत की सूचक है जो प्रशासनिक खर्चे के लेखों में बुक की गई थी और जिसे 1978-79 में अवलेखित किया जा रहा है ।

पिछला वर्ष (1976-77)	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
50,14,27,501	पीछे से लाया गया जोड़		58 22,37,988
	निगम के कर्मचारियों को वाहन खरीदने के लिए पेशगी		
9,41,444	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	8,78,529	
5,29,471	जोड़ें—वर्ष में की गई अदायगियां	7,58,516	
14,70,915			
(—) 5,92,386	घटाएं—वर्ष में की गई वसूलियां	(—) 5,96,201	
8,78,529			10,40,844
	निगम के कर्मचारियों को विविध पेशगियां (त्यौहार पेशगियां)		
2,69,629	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	8,46,031	
11,17,666	जोड़ें—वर्ष में की गई अदायगियां	8,51,071	
13,87,305			
(—) 5,31,274	घटाएं—वर्ष में की गई वसूलियां	(—) 10,27,430	
8,46,031			6,69,672
	गृह निर्माण पेशगी		
46,72,897	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	67,24,154	
26,82,525	जोड़ें—वर्ष में की गई अदायगियां	26,22,991	
73,55,422			
(—) 6,31,268	घटाएं—वर्ष में की गई वसूलियां	(—) 9,65,668	
67,24,154			63,81,477
	राज्य सरकारों को ओर से अग्रिम अदायगियां		
14,763	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	8,643	
6,927	जोड़ें—वर्ष में की गई अदायगियां	1,994	
21,690			
(—) 13,047	घटाएं—वर्ष में की गई वसूलियां	(—) 9,174	
8,643			1,463
	अस्पतालों, औषधालयों, निगम के कार्यालयों तथा स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत तथा अनुरक्षण की बाबत राज्य सरकार/राज्य लोक निर्माण विभाग आदि को दी गई राशि :		
	(क) निगम के कार्यालय		
16,29,831	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	24,87,105	
8,80,180	जोड़ें—वर्ष में की गई अदायगियां	3,35,194	
25,10,011			
(—) 22,906	घटाएं—वर्ष में की गई वसूलियां/समायोजन	(—) 6,84,370	
24,87,105			21,37,929
	(ख) अस्पताल/औषधालय/अनैक्तियां :		
1,14,44,452	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,65,92,609	
53,37,220	जोड़ें—वर्ष में की गई अदायगियां	74,47,292	
1,67,81,672			
(—) 1,89,063	घटाएं—वर्ष में प्राप्तियां	(—) 9,03,080	
1,65,92,609			2,31,36,821
	विविध पेशगियां		
17,90,517	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	17,73,656	
11,78,426	जोड़ें—वर्ष में की गई अदायगियां	22,19,743	
29,68,943			
(—) 11,95,287	घटाएं—वर्ष में प्राप्तियां	(—) 19,10,854	
17,73,656			20,82,545
53,07,38,528	आगे ले जाया गया जोड़		61,96,88,739

पिछला वर्ष (1976-77)	वेयताएं	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
2,31,14,23,461	पीछे से लाया गया जोड़		2,73,78,21,659
	नियम के कर्मचारियों के लिए अनुकम्पा आरक्षित निधि :		
10,000	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	10,000	
29,434	वर्ष में की गई क्षेत्र व्यवस्था	31,000	
39,434			
(—) 29,434	घटायें—वर्ष में की गई अदायगियां	(—) 31,000	
10,000			10,000
	प्रतिभूतियों की जमा राशि		
3,83,840	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	3,55,615	
2,16,815	जोड़ें—वर्ष में जमा राशि	2,76,355	
6,00,655			
(—) 2,45,040	घटायें—वर्ष में लौटाई गई जमा राशि	(—) 2,48,006	
3,55,615			3,85,964
	अन्य पार्टियों को देय बिलों से कटौती		
26,694	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	62,581	
10,88,488	जोड़ें—वर्ष में जमा की गई राशि	12,49,025	
11,15,182			
(—) 10,52,601	घटायें—वर्ष में की गई अदायगियां	(—) 12,79,851	
62,581			31,755
	कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि में अदाकी जमा राशि		
6,579	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	41,961	
33,715	जोड़ें—वर्ष में जमा की गई राशि	9,330	
40,294			
(—) 1,667	घटायें—वर्ष में की गई अदायगियां	(—) 585	
41,961			50,700
2,21,18,93,618	आगे ले जाया गया जोड़		2,73,31,00,084

पिछला वर्ष (1976-77)	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
53,07,38,228	पीछे से लाया गया जोड़		61,96,88,739
	राज्य सरकारों/अन्य पार्टियों को कर्जे		
3,11,25,166	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	2,92,63,430	
4,56,300	जोड़ें—वर्ष में की गई अदायगियां		
3,15,81,466			
(—) 23,18,036	घटायें—राज्य सरकारों द्वारा लौटाई गई राशि	(—) 19,40,330	
2,92,63,430			2,73,23,100
	प्रेषण		
	नकद प्रेषण		
1,98,999	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	(—) 36,95,754	
2,32,96,44,394	जोड़ें—वर्ष में समायोजित डेबिट	2,58,38,85,748	
2,32,98,43,393			
(—) 2,33,35,39,147	घटायें—वर्ष में समायोजित क्रेडिट	(—) 2,57,95,89,575	
(—) 36,95,754			6,00,419
	अन्य प्रेषण		
	विनियम लेखा		
98,646	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	(—) 183	
7,80,83,763	जोड़ें—वर्ष में डेबिट	8,97,66,093	
7,81,82,409			
(—) 7,81,82,592	घटायें—वर्ष में क्रेडिट	(—) 8,97,29,165	
(—) 183			36,745
55,63,05,721	आगे ले जाया गया जोड़		64,76,49,003

पिछला वर्ष (1976-77)	देयताएं	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपय
2,21,13,93,618	पीछे से लाया गया जोड़		2,73,83,00,084
	परिवार नियोजन परियोजना के लिए		
	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से प्राप्त जमा राशि		
—	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	—	
8,00,000	जोड़ें—वर्ष में जमा राशि	5,00,000	
(—)8,00,000	घटायें—परिवार नियोजन परियोजना को दी गई अदायगियां	(—)5,00,000	
—			—
	विविध जमा राशि		
17,74,904	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	14,36,216	
90,29,006	जोड़े—वर्ष में प्राप्त जमा राशि	62,50,102	
1,08,03,910			
(—)93,67,694	घटायें—वर्ष में लौटाई गई जमा राशि	(—)48,73,761	
14,36,216			28,12,557
2,21,33,29,834	आगे ले जाया गया जोड़		2,74,11,12,641

पिछला वर्ष (1976-77)	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
55,63,05,721	पीछे से लाया गया जोड़		64,76,49,003
	लागत पर निवेश		
	1. पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि		
14,03,58,000	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	21,27,31,000	
7,23,73,000	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	9,32,43,804	
—	घटायें—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	(—) 6,45,000	
21,27,31,000			30,53,29,804
	2. स्थायी (आंशिक तथा पूर्ण) अपंगता हितलाभ आरक्षित निधि		
15,06,23,101	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	18,51,86,072	
5,32,96,600	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	2,54,03,752	
20,39,19,701			
(—) 1,87,33,629	घटायें—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	(—) 3,62,74,600	
18,51,86,072			17,43,15,230
	3. आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि		
6,82,35,292	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	8,26,77,106	
2,91,08,900	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	2,71,15,753	
9,73,44,192			
(—) 1,46,67,086	घटायें—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	(—) 1,40,06,000	
8,26,77,106			**9,57,86,859**
	4. कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि		
2,83,57,000	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	3,58,88,000	
	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	1,19,89,732	
3,95,21,000			
(—) 36,33,000	घटायें—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	(—) 66,53,400	
3,58,88,000			4,12,24,332
1,07,27,87,899	आगे ले जाया गया जोड़		1,26,43,05,228

पिछला वर्ष (1976-77)	देयताएं	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
2,21,33,29,834	पीछे से लाया गया जोड़		2,74,11,12,641

2,21,33,29,834	आगे ले जाया गया जोड़	2,74,11,12,641

पिछला वर्ष (1976-77)	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
1,07,27,87,899	पीछे से लाया गया जोड़		1,26,43,05,228
	5. निगम के कार्यालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मूल्यह्रास आरक्षित निधि ।		
21,76,509	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	26,41,400	
10,70,100	जोड़े—वर्ष में किए गए निवेश	12,13,408	
32,46,909			
(—) 6,05,509	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	(—) 7,81,000	
26,41,400			30,73,808
	6. चिकित्सालय भवनों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि		
2,41,42,525	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	2,91,12,525	
1,13,37,000	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	1,19,88,643	
3,54,79,525			
(—) 63,67,000	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	(—) 66,38,000	
2,91,12,525			3,44,63,168
	7. स्टाफ कारों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि		
4,22,735	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	5,02,935	
1,17,700	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	78,803	
5,40,435			
(—) 37,500	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	(—) 20,000	
5,02,935			5,61,738
	8. निगम के कार्यालयों भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मरम्मत व अनुरक्षण आरक्षित निधि		
22,63,240	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	23,43,545	
3,08,000	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	12,96,023	
25,71,240			
(—) 2,27,695	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	(—) 8,36,000	
23,43,545			28,03,568
	9. चिकित्सालय भवनों की मरम्मत व अनुरक्षण आरक्षित निधि		
4,05,62,278	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	4,47,87,593	
65,19,100	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	1,87,40,833	
4,70,81,378			
(—) 22,93,785	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	(—) 1,53,21,000	
4,47,87,593			**4,82,07,426**
	10. निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन आरक्षित निधि		
5,85,12,541	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	6,84,29,455	
1,52,79,300	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	4,39,11,504	
7,37,91,841			
(—) 53,62,386	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	(—) 3,37,60,000	
6,84,29,455			7,85,80,959
1,22,06,05,352	आगे ले जाया गया जोड़		1,43,19,95,895

पिछला वर्ष (1976-77)	देयताएं	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
2,21,33,29,834	पीछे से लाया गया जोड़		2,74,11,12,641
2,21,33,29,834	आगे ले जाया गया जोड़		2,74,11,12,641

पिछला वर्ष (1976-77)	परिसम्पत्तियां	राशि	जोड़
रुपये		रुपये	रुपये
1,22,06,05,352	पीछे से लाया गया जोड़		1,43,19,95,895
	11. भविष्य निधि से जुड़ी बीमा आरक्षित निधि		
—	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	—	
—	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	75,063	
—	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	—	
			75,063
	12. अनुकंपा आरक्षित निधि		
—	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	—	
—	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	9,999	
—	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	—	
			9,999
	13. आपात आरक्षित निधि		
11,00,00,000	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	20,75,00,000	
11,75,00,000	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	1,18,47,207	
(—) 2,00,00,000	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	(—) 1,60,00,000	
20,75,00,000	सामान्य रोकड़ शेष		28,33,47,207
36,83,00,000	पिछले तुलनपत्र के अनुसार निवेश	72,83,10,000	
62,06,60,000	जोड़ें—वर्ष में किए गए निवेश	45,42,21,370	
98,89,60,000			
(—) 26,06,50,000	घटाएं—निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली	(—) 22,30,00,000	
72,83,10,000		95,95,31,370	
25,51,026	हाथ रोकड़	26,98,063	
5,43,63,456	बैंकरों के पास रोकड़	6,34,55,044	
5,69,14,482		6,61,53,107	
78,52,24,482	कुल रोकड़ शेष		1,02,56,84,477
2,21,33,29,834	कुल जोड़		2,74,11,12,641

एम० एल० सोबती,
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

परिशिष्ट 22

हितलाभों आदि की अदायगी की तुलना में प्रशासनिक लागत

	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78
			(रुपये में)			
1. कुल प्रशासनिक लागत	4,40,34,287	7,34,57,795	6,60,68,976	7,77,62,505	8,77,45,918	9,55,40,440
2. अंशदान						
(i) नियोजकों तथा कर्मचारियों के शेयर	—	20,37,86,214	60,34,74,995	73,15,86,339	1,23,61,94,824	1,31,11,81,105
(ii) केवल नियोजकों का शेयर	39,61,61,207	21,41,95,502	2,16,80,542	1,78,07,427	93,97,151	25,97,022
(iii) केवल कर्मचारियों का शेयर	19,16,27,812	22,76,57,964	1,00,74,058	1,00,09,537	1,07,22,754	48,90,539
(iv) ब्याज	—	—	—	—	1,78,865	5,97,322
जोड़	58,77,89,019	64,56,39,680	63,52,29,595	75,94,03,303	1,25,64,93,594	1,31,92,65,988
3. राजस्व लेखों में कुल व्यय	47,23,75,970	59,90,70,572	62,49,05,056	75,58,05,845	1,01,91,84,702	1,17,71,52,092
4. कुल हितलाभ	37,13,48,489	45,14,88,325	46,45,26,360	57,23,86,508	70,85,36,816	87,03,56,722
निम्नलिखित के साथ प्रशासनिक लागत की प्रतिशतता :						
अंशदान	7.50%	7.72%	10.40%	10.24%	6.98%	7.24%
राजस्व लेखे में व्यय	9.32%	8.32%	10.57%	10.29%	8.61%	8.12%
हितलाभ	11.86%	10.04%	14.22%	13.59%	12.38%	10.98%

टिप्पणी :—4 में राज्य सरकारों द्वारा किए गए चिकित्सा हितलाभ व्यय का शेयर शामिल नहीं है ।

लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

मैंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1977-78 के पूर्वोक्त लेखाओं तथा 31 मार्च, 1978 की स्थिति के तुलन पत्र की जांच की है तथा मैंने वह सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये जिनको मुझे आवश्यकता थी । लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप संलग्न लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई आपत्तियों के अधीन मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय में ये लेखा तथा तुलन पत्र सही ढंग से बनाये गये हैं तथा मुझे दी गई अधिकतम सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा निगम की पुस्तकों में दिखाये गये रूप में निगम के कार्यकर्ताओं की सही तथा स्पष्ट स्थिति दर्शाते हैं ।

ह०/

नई दिल्ली : 31 जनवरी, 79 (के० सी० दास)

महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 1977-78 वर्ष के लेखों की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

1. सामान्य

(1) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अक्टूबर, 1948 में हुई थी । यह अधिनियम कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1951, 1966 तथा 1975 द्वारा संशोधित किया गया तथा मौसमी कारखानों के अलावा उन सभी कारखानों पर लागू किया गया जो विद्युत-शक्ति का प्रयोग करते हैं तथा जहां मजदूरों के लिए 20 या 20 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं अथवा काम करते थे । 1000 रुपये तक मासिक पारिश्रमिक पाने वाले सभी कर्मचारी योजना के अन्तर्गत शामिल हैं ।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा (5) के अन्तर्गत स्थापनाओं के निम्नलिखित नये वर्गों पर योजना का उत्तरोत्तर विस्तार किया जा रहा है, यानी :—

(क) विद्युत-शक्ति का प्रयोग करने वाले छोटे कारखाने जिनमें 10 से 19 व्यक्ति काम करते हैं तथा विद्युत-शक्ति का प्रयोग न करने वाले कारखाने जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं ।

(ख) दुकाने, सिनेमा, पूर्वदर्शन, थियेटर, होटल और रेस्तरा, सड़क मोटर परिवहन तथा समाचार पत्र संस्थापनाएं जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं ।

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल राज्यों और चण्डीगढ़, दिल्ली, माही, गोवा, दमन और दीव और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न केन्द्रों पर योजना का विस्तार किया गया था ।

(3) 1977-78 वर्ष के दौरान 5,924 कारखानों/स्थापनाओं पर अधिनियम के उपबन्धों का विस्तार किया गया जिनमें 0.43 लाख कर्मचारी योजना के अन्तर्गत आ गए । 31 मार्च, 1978 की स्थिति के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत आए कारखानों/स्थापनाओं की संख्या 49,304 थी जिनमें 55.43 लाख कर्मचारी थे । 31 मार्च, 1977 को कारखानों/स्थापनाओं की संख्या 43,380 थी जिनमें 55 लाख कर्मचारी थे ।

(4) 1976-77 तथा 1977-78 वर्षों में निगम की आय व्यय का विश्लेषण नीचे दिया गया है :—

आय	1976-77	1977-78
	(लाख रुपयों में)	
नियोजकों तथा कर्मचारियों का अंशदान	12,362	13,112
केवल नियोजकों का अंशदान	94	26
केवल कर्मचारियों का अंशदान	107	49
अंशदानों पर ब्याज	2	6
चिकित्सा हितलाभ की बाबत शुरू में निगम द्वारा किए गए व्यय में राज्य सरकारों का शेयर	14	40
ब्याज तथा लाभांश	729	801
विविध (किराया, रेट तथा कर मिलाकर)	361	421
	13,669	14,455

व्यय	1976-77	1977-78
	(लाख रुपयों में)	
1. बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को हितलाभ		
क चिकित्सा हितलाभ		
(i) चिकित्सा उपचार आदि की व्यवस्था पर होने वाले खर्च में निगम के शेयर के रूप में राज्य सरकारों आदि को अदायगी	3,399	4,447
(ii) चिकित्सा उपचार तथा देख-रेख तथा प्रसूति हितलाभों पर निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किए गए खर्च	243	264
ख. बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों को निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिए गए मद एवं अन्य हितलाभ	3,443	3,993
2. प्रणासनिक खर्चे		
क. अधीक्षण	475	473
ख. फील्ड कार्य	331	359
ग. अन्य खर्चे	72	124
3. अस्पताल एवं औषधालय	103	122
4. पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि	1,257	1,319
5. आपात आरक्षित निधि	869	671
6. व्यय से अधिक आय का अतिशेष	3,477	2,683
	13,669	14,455

2. पेशगियां

(i) राज्य-सरकारों/राज्य लोक निर्माण विभागों को अस्पताल, औषधालय तथा अन्य इमारतों के निर्माण तथा परियोजनाओं के लिए पूंजीगत स्वरूप के अस्पताल उपस्कर खरीदने के लिए दी गई राशियों में से 31 मार्च, 1978 को 2,373.36 लाख रुपये (वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है) की राशि असमायोजित रही :—

वर्ष जिसमें पेशगी दी गई	31 मार्च, 1978 की स्थिति के अनुसार असमायोजित रही राशि
	(लाख रुपये में)
1970-71 तक	505.30
1971-72	72.06
1972-73	59.08
1973-74	51.55
1974-75	164.72
1975-76	214.67
1976-77	553.13
1977-78	752.85
	2,373.36

उपर्युक्त राशियों में से 689.50 लाख रुपये 30 नवम्बर, 1978 तक समायोजित कर लिए गए बताए गए हैं। निगम ने यह भी बताया (सितम्बर, 1978) कि बकाया राशियों के शीघ्र समायोजन के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ लिखा-पढ़ी की जा रही है ।

(ii) सरकारी विभागों तथा अर्ध सरकारी संगठनों को लेखन-सामग्री तथा वर्दी, विधि, प्रकार, स्थान किराये पर लेने के लिए किराया आदि के लिए दी गई राशियों में से 31 मार्च, 1978 को 20.82 लाख रुपये (वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है) की राशि असमायोजित रही ।

वर्ष जिस में पेशगी दी गई	31 मार्च, 1978 की स्थिति के अनुसार असमायोजित रही राशि
	(लाख रुपये में)
1970-71 तक	7.07
1971-72	0.55
1972-73	0.84
1973-74	0.40
1974-75	1.65
1975-76	0.92
1976-77	0.70
1977-78	8.69
	20.82

उपर्युक्त राशियों में से 4.48 लाख रुपये 30 सितम्बर, 1978 तक समायोजित कर लिए गए बताए गए हैं । निगम ने यह भी बताया (सितम्बर, 78) कि बकाया राशियों के समायोजन के लिए जोरों से लिखा-पढ़ी की जा रही है ।

(3) राज्य सरकारों/राज्य-लोक निर्माण विभागों को पूर्णतः निगम के स्वामित्व में आने वाले अस्पतालों/औषधालयों तथा अन्य कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिए दी गई राशियों में से 31 मार्च, 1978 को 252.75 लाख रुपये (वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है) की राशि असमायोजित रही ।

वर्ष जिसमें पेशगी दी गई	31 मार्च, 1978 की स्थिति के अनुसार असमायोजित रही राशि।
	(लाख रुपयों में)
1970-71 तक	25.83
1971-72	7.98
1972-73	15.16
1973-74	14.65
1974-75	18.18
1975-76	43.79
1976-77	36.19
1977-78	70.97
	252.75

उपर्युक्त राशियों में से 1.47 लाख रुपये 30 जून, 1978 तक समायोजित कर लिए गए बताए गए हैं। निगम ने यह भी बताया (सितम्बर, 1978) कि बकाया राशियों के शीघ्र समायोजन के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ लिखा-पढ़ी की जा रही है।

3. अंशदानों का बकाया :

(i) 31 मार्च, 1979 की स्थिति के अनुसार, 31 मार्च, 1977 को समाप्त अवधि के 12,175 कारखानों के नियोजकों और कर्मचारियों से 2094.78 लाख रुपये का बकाया अंशदान देय था (वर्ष वार विवरण नीचे दिया गया है)

वर्ष	नियोजकों का विशेष अंशदान	कर्मचारियों का अंशदान	नियोजकों और कर्मचारियों का संयुक्त अंशदान (1-7-73 से आरम्भ)	जोड़
	(लाख रुपयों में)			
दिसम्बर, 1971 तक	488.91	171.08	—	659.99
1-7-72 से 31-12-72 तक	154.43	63.39	—	217.82
1-1-73 से 31-12-73 तक	147.51	92.16	39.21	278.88
1-1-74 से 31-12-74 तक	—	—	129.43	129.43
1-1-75 से 31-12-75 तक	—	—	245.81	245.81
1-1-76 से 31-12-76 तक	—	—	379.47	379.47
1-1-77 से 31-3-1977 तक	—	—	183.38	183.38
	790.85	326.63	977.30	2,094.78

31 मार्च, 1978 की स्थिति के अनुसार 31 मार्च, 1977 को समाप्त अवधि के लिए अंशदानों की अदायगी करने वाली 12,175 फैक्टरियों में से 457 कारखानों में से प्रत्येक की ओर 0.50 लाख रुपये से अधिक देनदारी थी। निगम ने बताया (जनवरी, 1979) कि (क) उन्होंने 1,563.84 लाख रुपये की बकाया राशियों की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही की है।

(ख) 347.72 लाख रुपये की राशि के मामलों में कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है और (ग) 183.22 लाख रुपये के शेष बकायों के मामलों में वसूली रोकने के न्यायालय के न्यायदेशों/आदेशों कारखाने परिमापन के अन्तर्गत आने अथवा उनकी व्याप्ति संदिग्ध होने आदि के कारण कानूनी कार्रवाई करना संभव नहीं है। 31 मार्च, 1978 को समाप्त अवधि के लिए देय बकायों की स्थिति निगम द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई।

(ii) 31 मार्च, 1977 की स्थिति के अनुसार नियोजकों के विरुद्ध अनिष्पादित 33.64 लाख रुपये की डिक्रियों में से 31 मार्च, 1978 को 30.75 लाख रुपये की डिक्रियां (वर्ष वार विवरण नीचे दिया गया है) अनिष्पादित रहीं।

डिक्री का वर्ष	लाख रुपयों में
1970-71 तक	19.44
1971-72	0.67
1972-73	1.93
1973-74	1.50
1974-75	1.87
1975-76	0.55
1976-77	4.79
	30.75

31 मार्च, 1978 की स्थिति के अनुसार 1977-78 वर्ष की 1.22 लाख रुपये की डिक्रियां अनिष्पादित रहीं। यह बताया गया (सितम्बर, 1978) की डिक्रियों की वसूली करने के लिए निगम को राज्य सरकारों और निष्पादन न्यायालयों पर निर्भर करना पड़ता है।

(iii) 30 सितम्बर, 1978 की स्थिति के अनुसार 1977 कलेण्डर वर्ष तक 3025 कारखानों/स्थापनाओं का निरीक्षण शेष रहा। (वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है) :—

वर्ष	किए जाने वाले निरीक्षण	किए गए निरीक्षण	30 सितम्बर, 1978 की स्थिति के अनुसार बकाया निरीक्षण
1974	30,453	30,374	79
1975	31,645	31,413	232
1976	36,299	35,257	1,042
1977	47,104	44,079	3,025*

*प्रभारी कारखाने/स्थापनाएं जिनका 1974, 1975 और 1976 वर्षों में भी निरीक्षण नहीं किया गया।

(4) जिन कारखानों/स्थापनाओं की सर्वेक्षण/निरीक्षण रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं उनमें से 9409 कारखानों/स्थापनाओं की व्याप्ति की सही तारीख अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं की गई।

क्र० संख्या	राज्य का नाम	अन्तिम व्याप्ति के लिए बकाया मामलों की संख्या	स्थिति
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	545	नवम्बर, 1978 तक
2.	असम	35	अक्टूबर, 1978 तक
3.	बिहार	289	अक्टूबर, 1978 तक
4.	कर्नाटक	146	सितम्बर, 1978 तक

1	2	3	4
5.	केरल	62	सितम्बर, 1978 तक
6.	मध्य प्रदेश	271	सितम्बर, 1978 तक
7.	महाराष्ट्र	3,777	अक्टूबर, 1978 तक
8.	उड़ीसा	4	अक्टूबर, 1978 तक
9.	पंजाब	1,449	अगस्त, 1978 तक
10.	राजस्थान	410	अक्टूबर, 1978 तक
11.	तमिलनाडु	1,984	अक्टूबर, 1978 तक
12.	दिल्ली	437	अक्टूबर, 1978 तक
		9,409	

निगम ने अंतिम व्याप्ति के लिए रुके हुए बकाया मामलों की वर्ष-वार स्थिति प्रस्तुत नहीं की । यह बताया गया (जनवरी, 1979) कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल की आहरण क्षेत्रीय निदेशकों से आंकड़े आने बाकी हैं ।

4. वार्षिक लेखे : तुलन-पत्र

(क) विविध जमा

31 मार्च, 1978 की स्थिति के अनुसार विभिन्न विविध मदों पर बैंकों तथा अन्य फुटकर क्रेडिटों द्वारा गलत जमा के सुबक 28.13 लाख का क्रेडिट शेष "उच्चत लेखा विविध जमा" के अन्तर्गत असमायोजित रहा । इसमें से 0.54 लाख रुपये 30 जून, 1978 तक समायोजित किए गए तथा 27.59 लाख रुपये की राशि असमायोजित रही (वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है) :—

वर्ष	(राशि लाख रुपयों में)
1974-75	0.15
1975-76	2.35
1976-77	3.21
1977-78	21.88
	27.59

निगम ने बताया (जनवरी, 1979) कि 30 सितम्बर, 1978 को 27.37 लाख रुपये की राशि असमायोजित रही ।

(ख) तुलन पत्र में उपस्कर पर व्यय को न दिखाना

निगम ने 31 मार्च, 1977 तक विभिन्न राज्यों में 10 से लेकर 700 बिस्तर तक की क्षमता वाले 59 अस्पतालों और 25 औषधियों का निर्माण किया और उनकी निर्माण लागत अपने तुलन-पत्र में परिसम्पत्तियों के रूप में दिखाई । 1967-68 के बाद इन अस्पतालों और औषधियों को आरम्भ में दिए गए उपस्कर पर किया गया व्यय (जो निगम और राज्यों के बीच 7 : 1 के अनुपात में शेयरधारण है) 31 मार्च, 1977 तक 277.29 लाख रुपये था जिसमें निगम का शेयर 242.63 लाख रुपये था । लेकिन उपस्कर की लागत तुलन-पत्र में नहीं दिखाई गई है । निगम ने बताया (सितम्बर, 1978) कि 1968 तक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में उपस्कर की व्यवस्था निगम की लागत पर ही की गई थी तथा व्यय की गई 26.35 लाख रुपये की राशि पूंजीकृत करके 31 मार्च, 1977 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र में दिखाई गई थी । यह भी बताया गया कि 1967-68 के बाद खरीदे गए उपस्कर की लागत तुलन-पत्र में दिखाने की व्यावहारिकता पर विचार किया जा रहा है और इस मामले में राज्य सरकारों से परामर्श किया जाना है ।

(ग) परिसम्पत्तियों और देयताओं का मूल्यांकन

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 37 के अनुसार निगम की परिसम्पत्तियों और देयताओं का हर पांच वर्षों के बाद मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है । पंचवार्षिक मूल्यांकन 1973-74 के अन्त में होना था जिसके बारे में मूल्यांकन की रिपोर्ट 1977-78 में प्राप्त हुई और उसे अभी निगम द्वारा (नवम्बर, 1978) स्वीकार किया जाना है । निगम ने बताया (जनवरी, 1979) कि मूल्यांकन की रिपोर्ट के एक भाग पर अक्तूबर, 1977 में निर्णय लिए गए थे और शेष रिपोर्ट पर मूल्यांकन से परामर्श करके विचार किया जा रहा है और उन पर जनवरी/फरवरी, 1979 में निर्णय लिए जाने की आशा है ।

5. प्रयोग में न लाई गई भूमि

विभिन्न राज्यों में अस्पताल, औषधालयों आदि के निर्माण के लिए निगम द्वारा खरीदे गये 18 भू-खण्ड खाली पड़े हैं । इनमें से सर्वप्रथम पहला भू-खण्ड 1962 में खरीदा गया था । 1976 तक खरीदी गई इस प्रकार की खाली भूमि की लागत 20.26 लाख रुपये थी ।

क्रय वर्ष	खाली पड़े भू-खण्डों की संख्या	खर्च की गई राशि (लाख रुपयों में)
1962	3	1.95
1965	2	0.28
1966	2	6.21
1967	4	6.42
1968	3	3.58
1972	1	0.09
1974	1	1.13
1975	1	0.20
1976	1	0.40
	18	20.26

निगम ने बताया (जनवरी, 1979) कि एक मामले में (अप्रैल, 1975 में खरीदी गई भूमि) औषधालय के निर्माण के लिए प्राक्कलन मंजूर किए गए हैं ।

6. कन्तबहल (उड़ीसा) में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण

निगम ने अक्टूबर, 1970 में उत्कल मणीनरा लिमिटेड (एक प्राइवेट नियोजक) द्वारा उपहार में दी गई 5 एकड़ भूमि पर कंपधहल में 5.94 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 40 बिस्तर वाले अस्पताल जल पूर्ति की व्यवस्था सहित के निर्माण का अनुमोदन किया। उड़ीसा सरकार की सिफारिश पर (अक्टूबर, 1970) यह काम उड़ीसा राज्य आवास बोर्ड को इस शर्त पर सौंपा गया कि काम को "समय पर" तथा "विशिष्ट विवरण के अनुसार" पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी लेकिन काम पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी ।

नवम्बर, 1972 में निर्माण कार्य के प्राक्कलन परिशोधित करके 7.98 लाख रुपये के प्राक्कलन तैयार किए गए जिसका कारण श्रम और निर्माण सामग्री की लागत में वृद्धि तथा कुछ ऐसे मद जोड़े जाना बताया गया जो मूल प्राक्कलन में शामिल नहीं किए गए थे । उड़ीसा आवास बोर्ड का कहना है कि निर्माण कार्य जून, 1973 में पूरा हो गया था लेकिन निगम ने भवन का कब्जा इस आधार पर नहीं लिया कि अस्पताल के लिए जल-पूर्ति की व्यवस्था करने का काम पूरा नहीं किया गया था । बाद में (जुलाई, 1974) यह निर्णय किया गया कि अस्पताल भवन के लिए जल-पूर्ति की व्यवस्था का काम प्राइवेट नियोजक उत्कल मशीनरी लिमिटेड को सौंप दिया जाए । अक्टूबर, 1975 में निगम ने नियोजक के अनुरोध पर उसे राज्य सरकार के माध्यम से जल-पूर्ति की व्यवस्था करने के लिए अपेक्षित मशीनरी और उपस्कर आदि की लागत पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए शून्य वार्षिक ब्याज-मुक्त पेशगी के रूप में 2 लाख रुपये दिए ।

निगम ने अक्टूबर, 1975 में भवन का कब्जा लिया और अस्पताल जनवरी, 1976 में चालू किया गया । इस अवधि में जल-पूर्ति व्यवस्था को छोड़कर स्टाफ क्वार्टर, पहुंच सड़क आदि के निर्माण का शामिल करके निर्माण व्यय मार्च, 1977 तक 12.72 लाख रुपये हो गया । इसके अलावा जल-पूर्ति व्यवस्था करने के लिए प्राइवेट नियोजक को 2 लाख रुपये की पेशगी दी गई थी ।

ह०/—

महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व

[संख्या जी-25012/1/79-एच० आई०]

हंस राज छाबड़ा, उप सचिव

MINISTRY OF

New Delhi, the

S.O. 1667.—In pursuance of section 36 of the Employees' State Insurance the Employees' State Insurance Corporation, together with audit report

ACCOUNTS

'EMPLOYEES,' STATE INSU

FOR THE

APPENDIX

EMPLOYEES' STATE

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

EXPENDITURE

Previous year (1976-77)	Heads of Account	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
	1. Benefits to Insured Persons & their families.		
	A. Medical Benefits.		
	(i) Payments to State Govts. etc. as Corporation's Share of their expenses on providing medical treatment and maternity facilities etc.	'A'44,46,64,850	
33,99,42,691	Deduct, Payments to State Govts. towards medical care during the year transferred to the Capital Construction Reserve Fund	..	
..			
33,99,42,691			
	(ii) Medical treatment and care and maternity facilities (expenses incurred direct by the Corporation)	2,64,08,246	
2,42,93,657			
36,42,36,348	Total A—Medical Benefits. Shoes		47,10,73,096
	B. —Cash Benefits.		
18,85,54,244	1. Sickness Benefit	27,09,56,456	
2,38,02,242	2. Extended Sickness Benefit	2,62,66,978	
41,98,442	3. Enhanced Sickness Benefit for Family Planning	6,54,211	
1,51,31,634	4. Maternity Benefit	1,73,39,589	
	5. Disablement Benefit		
4,39,29,068	(a) Temporary	5,01,33,495	
5,20,26,000	(b) Permanent (Capitalised Value)	1,48,69,252 'B'	
	6. Dependants' Benefit.		
1,47,11,000	(Capitalised Value)	'C' 1,67,90,647	
9,13,803	7. Funeral Benefit	9,52,449	
34,32,66,433	Total B Cash Benefits.		39,79,43,077
70,75,02,781	Total Carried over		86,90,16,173

Note :—'A' This includes the Corporation's Share of the expenditure on the initial equipments for the Hospitals

'B' Provision for the year 1977-78 Rs.5,20,93,000

Add one time additional cost on account of increase in rates of P.D.B. Rs. 1,76,00,000

Total 6,96,93,000

Less surplus as per 5th quinquenntial Report on the Valuer. Rs. (—) 5,48,23,748

Net Rs. 1,48,69,252

'C' Provision during the year 1977-78 Rs. 1,26,25,000

Add one time cost on account of increase in rates of D.B. Rs. 1,04,00,000

Total Rs. 2,30,25,000

Less surplus declared by the valuer as per 5th quinquennial Report of the valuer Rs. (—) 62,34,353

Net. Rs. 1,67,90,647

LABOUR

12 April, 1979

Act, 1948 (34 of 1948), the audited accounts of
thereon, for the year 1977-78, are hereby published for general information.

OF THE

RANCE CORORATION

YEAR 1977-78

'A'

INSURANCE CORPORATION

FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1978 **INCOME**

Previous year (1976-77)	Heads of Account	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
	Contributions.		
1,23,61,94,824	Employers' and Employees' Shares	1,31,11,81,105	
93,97,151	Employers' Share only	25,97,022	
1,07,22,754	Employees'—Share only	48,90,539	
1,78,865	Interest on Contributions	5,97,322	
1,25,64,93,594	Total Contributions		1,31,92,65,988
14,12,271	State Government/Union Territories share towards medical benefits initially incurred by the Corporation.	39,77,000	
14,12,271			39,77,000
..	Grants-in-aid.	..	
	Other Heads of Revenue.		
7,29,00,062	Interest & Dividends	8,00,73,589	
48,29,360	Compensations.	25,88,748	
	Rents, Rates and Taxes.		
9,38,934	(i) Offices of the Corporation (including Staff Quarters).	6,57,269	
2,80,08,041	(ii) Hospitals, Dispensaries & Staff Quarters.	3,48,62,153	
5,11,904	Fees, Fines & Forfeitures.	26,18,074	
18,25,238	Miscellaneous.	14,05,209	
10,90,13,539	Total of Other Heads of Revenue.		12,22,05,042
1,36,69,19,404	Total Carried Over.		1,44,54 48,030

Previous year (1976-77)	Heads of Account	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
70,75,02,781	Total Brought Forward.		86,90,16,173
	C—Other Benefits.		
52,962	(a) Expenditure on the Rehabilitation of Disabled Insured Persons.	49,849	
3,02,065	(b) Medical Boards & Appeal Tribunals.	3,50,931	
	(c) Payments to Insured Persons.		
2,28,860	(i) Conveyance Charges and/or loss of wages.	2,89,537	
..	(ii) Incidental Charges under Family Planning.	67,980	
..	(d) Grants-in-aid.	..	
4,50,148	(e) Miscellaneous.	5,82,252	
10,30,035	Total C—Other Benefits.		13,40,549
70,85,36,816	Total Benefits to Insured Persons and their families.		87,03,56,722
	2. Administration Expenses.		
	A. Superintendence.		
58,431	1. Corporation, standing Committee, Regional Boards etc.	53,382	
2,32,984	2. Principal Officers.	2,35,188	
52,62,199	3. Other Officers.	55,36,025	
2,67,43,755	4. Ministerial Establishment.	2,72,91,379	
48,88,564	5. Class IV Servants.	46,23,122	
1,02,63,731	6. Contingencies.	95,16,932	
4,74,49,664	Total A—Superintendence.		4,72,56,028
	B—Field Work.		
9,82,820	1. Officers.	11,88,453	
2,52,94,493	2. Ministerial Establishment.	2,73,31,185	
41,36,460	3. Class IV Servants.	42,75,294	
27,05,691	4. Contingencies.	30,72,174	
3,31,19,464	Total B—Field Work.		3,58,67,106
	C—Other Charges.		
89,369	1. Interest on Additional D.A. Deposits.	..	
3,22,181	2. Legal Charges.	4,04,612	
34,880	3. Insurance Courts.	45,170	
72,575	4. Publicity & Advertisement Charges.	63,055	
2,77,254	5. Charges for maintaining Banking Accounts	@9,79,849	
1,98,890	6. Audit Fees.	2,07,587	
84,722	7. Leave Salary & Pension Contributions.	93,310	
2,93,939	8. Depreciation of Office Buildings/Staff Cars.	3,01,400	
7,45,328	9. Repairs & maintenance of Office Buildings.	7,50,325	
	10. Retirement Benefits.		
49,64,352*	(a) Pension Reserve Fund for the employees of the Corporation.	59,84,424**	
2,55,688	(b) Corporations' Contribution towards Employees' State Insurance Corporation Provident Fund.	2,62,181	
24,36,225	(c) Interest Paid to ESIC Provident Fund.	29,39,240	
1,09,535	(d) Incentive Bonus.	1,64,098	
..	(e) Loss on realisation of investments.	..	
(—)28,16,778	(f) Less Intersest realised on investment of Provident Fund Balances.	÷ —	
29,434	11 Compassionate Reserve Fund.	31,000	
64,640	12. Provident Fund Deposit—Linked Insurance Fund.	1,00,000	
..	13. Losses.	8,000	
14,556	14. Miscellaneous.	83,055	
71,76,790	Total C—Other Charges.		1,24,17,306
8,77,45,918	Total Head 2—Administration Expenses.		9,55,40,440
79,62,82,734	Total Carried Over.		96,58,97,162

* This excludes Rs. 5,93,962/-pertaining to pensionary liability of the employees of D.M.D. office which is included under 'A' (ii) Medical Benefits' being shareable expenditure with Delhi Administration.

**This excludes Rs. 5,82,390/pertaining to pensionary libility of the employees of D.M.D. Office which is included under 'A' (ii) Medical Benefits being shareable expenditure with Delhi Administration.

÷ Interest realised on Investment of Provident Fund Balances has been credited under the Sub-head 'Interest and Dividends'

@ 'This includes commission charged by the bank on the sale of contribution stamps which was earlier accounted for under '2 A. Superintendence-Contingencies—C. Contribution (ii) Slaes & Distribution Charges'.

Previous year (1976-77)	Heads of Account	Amount	Total
Rs.		Rs	Rs
1,36,69,19,404	Total Brought Forward.		1,44,54,48,030

1,36,69,19,404	Total Carried Over.	1,44,54,48,030

Previous year (1976-77)	Heads of Account	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
79,62,82,734	Total Brought Forward.		96,58,97,162
	3. Hospitals and Dispensaries.		
26,30,818	1. Depreciation of Hospital Buildings Transferred to fund.	31,53,779	
76,88,115	2. Repairs and Maintenance of Hospitals/Dispensaries.	91,00,566	
1,03,18,933	Total Head 3—Hospitals and Dispensaries.		1,22,54,345
	4. Capital Construction/Emergency Reserve Fund.		
12,56,49,360	1. Capital Construction	13,19,26,600	
8,69,33,675	2. Emergency Reserve Fund.	6,70,73,985	
21,25,83,035	Total Head 4—Capital Construction Emergency Reserve Fund.		19,90,00,585
1,01,91,84,702	Total Expenditure on Revenue Account.		1,17,71,52,092
34,77,34,702	To excess of Income over Expenditure carried over to Balance Sheet.		26,82,95,938
1,36,69,19,404	GRAND TOTAL.		1,44,54,48,030

New Delhi,
Dated 31st May, 1978.

Previous year (1976-77)	Heads of Accounts	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
1,36,69,19,404	Total Brought Forward,		1,44,54,48,030
1,36,69,19,404	GRAND TOTAL		1,44,54,48,030

(M. L. SOBTI)
Financial Adviser &
Chief Accounts Officer,
Employees' State Insurance Corporation.

APPENDIX

EMPLOYEES' STATE

Balance Sheet as at

Previous year (1976-77)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
	Balance of Excess of Income over Expenditure.		
74,75,21,794	As per last Balance Sheet.	1,09,52,56,496	
34,77,34,702	Accumulations during the year.	26,82,95,938	
1,09,52,56,496			
..	LESS Amount transferred to Emergency Reserve Fund from last year's Accumulation.	..	
1,09,52,56,496			1,36,35,52,434
	RESERVE FUNDS.		
	1. Capital Construction Reserve Fund.		
29,76,67,469	Opening Balance.	43,73,52,629	
..	Amount transferred from balance of Excess of Income over Expenditure.	..	
12,56,49,360	ADD Provision made during the year.	13,19,26,600	
1,40,35,800	Interest received on Investments.	1,72,42,307	
..	LESS Payments made during the year.	..	
43,73,52,629			58,65,21,536 'A
	2. Permanent (Partial and Total) Disablement Benefit Reserve Fund.		
15,06,25,925	As per last Balance Sheet.	18,51,87,173	
5,20,26,000	Provision made during the year.	6,96,93,000 'B'	
1,30,30,422	Interest received from Investments.	95,13,980	
2,27,571	Gain on realisation of Investments.	..	
..	LESS Surplus as per Fifth quinquennial Report on Valuation.	(—)5,48,23,748	
(—)3,07,22,745	LESS Payments made during the year.	(—)3,52,55,174	
18,51,87,173			17,41,15,231
	3. Dependant's Benefit Reserve Fund.		
6,82,35,452	As per last Balance Sheet.	8,26,77,671	
1,47,11,000	Provision made during the year.	@ 2,30,25,000	
61,97,786	Interest received from Investments.	40,59,767	
76,814	Gain on realisation of Investments.	..	
—	LESS Surplus as per 5th quinquennial Report on Valuation.	(—)62,34,353	
8,92,21,052			
(—)65,43,381	LESS payments made during the year.	(—)77,41,226	
8,26,77,671			9,57,86,859
	4. Employees' State Insurance Corporation Provident Fund.		
3,00,20,126	As per last Balance Sheet.	3,58,92,828	
	ADD Amount credited during the year.		
1,07,76,205	(i) Employees' Subscription.	99,50,538	
2,55,688	(ii) Corporation's Contribution.	2,62,181	
24,35,059	(iii) Interest on (Employees' & Corporation's Shares)	29,39,240	
(—)16,15,141	(iv) D.A. Deposits.	—	
1,09,448	(v) Incentive Bonus.	1,64,098	
4,19,82,385	Total Carried Over of this head.	4,92,08,885	
1,80,04,73,969	Total Carried Over.		2,22,01,76,060

'A' Out of this amount Rs. 19,18,99,835/-has been advanced for construction works and Rs. 30,53,29,804/-has been invested in securities.

@ The balance of Rs.8,92,91,897/-represents assets created in lands and buildings.

'B' This includes Rs. 1,76,00,000/-as one time additional cost on account of increase in the rates of P.D.B. with effect from 1-10-77.

@ This includes Rs. 104,00,000 as one time additional cost on account of increase in the rates of dependants Benefit with effect from 1-10-1977

'B'

INSURANCE CORPORATION

31st March, 1978

Previous year (1976-77)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs
	Lands and Buildings (wholly owned by the Corporation).		
	(a) Buildings for Offices of the Corporation.		
1,59,89,007	As per last Balance Sheet.	1,80,57,416	
20,68,409	Additions during the year.	19,65,477	
1,80,57,416		2,00,22,893	
	(b) Hospitals and Dispensaries.		
26,47,22,404(a)	As per last Balance Sheet.	29,79,95,923	
3,32,73,519	Additions during the year.	2,52,12,899	
29,79,95,923(@)		32,32,08,822	
31,60,53,339			34,32,31,715
	Lands and Buildings (Jointly owned by the Corporation and State Governments) Corporation's Share.		
	(a) Hospitals and Dispensaries.		
9,26,807	As per last Balance Sheet.	9,26,807	
..	Additions during the year.	..	
9,26,807			9,26,807
31,69,80,146	Total Carried Over.		34,41,58,522
5,12,54,528	As per last Balance Sheet.	4,95,54,760	
—	ADD Payments made during the year.	—	
(—)16,99,768	LESS Adjustments and Recoveries.	(—)41,18,685	
4,95,54,760		4,54,36,075 'A'	
	(ii) Amount advanced from Capital Construction Reserve Fund.		
10,22,96,581	As per last Balance Sheet.	13,41,76,637	
6,73,24,863	ADD Payments made during the year.	8,23,26,026	
(—)3,54,44,807	LESS Adjustments and Recoveries.	(—)2,46,02,828	
13,41,76,637		19,18,99,835	
18,37,31,397			23,73,35,910
	Staff Cars.		
5,03,517	As per last Balance Sheet.	5,31,617	
28,100	ADD Payments made during the year.	33,579	
5,31,617			5,65,196
50,12,43,160	Total Carried Over.		58,20,59,628

@ The Expenditure on 'Equipment for Hospital' is being booked under the head 'A' Medical Benefits (i) payment to State Government etc. as the Corporation's Share of their expenditure on providing Medical treatment and Maternity facilities'. Capitalisation of expenditure on the initial equipment for hospital is under consideration of the Corporation.

(a) This includes expenditure of Rs. 49,542/- and Rs. 25,35,343/- incurred under special orders on initial 'Equipment for Hospital' during 1970-71 (Bihar) and 1972-73 (West Bengal).

'A' Represents amount advanced from General Cash Balance before the creation of the Capital Construction Reserve Fund in 1970-71.

Previous Year (1976-77)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
1,80,04,73,969	Total Brought Forward.		2,22,01,76,060
4,19,81,385	Total Brought Forward of the Sub-Head	4,92,08,885	
(—)60,77,440	LESS Payments made during the year.	*(—)79,60,565	
3,59,03,945		4,12,48,320	
	LESS amount transferred to:—		
(—)11,117	(i) Pension Reserve Fund.	(—)23,988	
—	(ii) Unclaimed Deposit.	—	
3,58,92,828			4,12,24,332
	Provident Fund Deposit Linked Insurance Fund.		
50,000	As per last Balance Sheet.	50,000	
64,640	Provision made during the year	1,00,000	
(—)64,640	LESS Payments made during the Year.	(—)74,937	
50,000			75,063
	5. Depreciation Reserve Fund of Building for the Offices of the Corporation (including Staff Quarters).		
21,77,836	As per last Balance Sheet.	26,43,052	
2,03,762	Provision made during the year.	2,58,732	
2,11,454	Interest and Gain received from Investments.	1,72,025	
26,43,052			30,73,809
	6. Depreciation Reserve Fund of Hospital Buildings.		
2,41,44,626	As per last balance Sheet.	2,91,12,568	
26,30,818	Provision made during the year.	31,53,779	
23,37,124	Interest received from Investments.	21,96,821	
—	Loss or Gain on realisation of Investments.	—	
2,91,12,568			3,44,63,168
	7. Depreciation Reserve Fund of Staff Cars.		
4,22,960	As per last Balance Sheet.	5,04,613	
40,177	Provision made during the year.	42,668	
41,476	Interest received from investments.	48,037	
5,04,613			'B' 5,95,318
	8 Repairs & Maintenance Reserve Fund of Building for the Offices of the Corporation (including Staff Quarters).		
38,93,578	As per last Balance Sheet.	48,31,089	
7,45,328	Provision made during the year.	7,50,325	
1,99,813	Interest received from investments.	1,05,983	
3,404	Gain on realisation of investments.	—	
48,42,123			
(—)11,034	LESS Recoveries made during the year.	(—)7,45,900	
48,31,089			49,41,497
	9. Repairs & Maintenance Reserve Fund of Hospital Buildings.		
5,20,12,883	As per last Balance Sheet.	6,13,81,18	
76,88,115	Provision made during the year.	91,00,566	
39,95,626	Interest received from investments.	28,19,239	
115	Gain on realisation of investments.	—	
6,36,96,739	Total Carried Over of this Head.	7,33,00,994	
1,87,35,08,119	Total Carried Over.		2,30,45,49,247

*Rs. 79,60,565/- includes Rs. 9,330/- transferred to "Unclaimed Deposits".

'B' This includes Rs. 33,580/- representing the cost of a staff car purchased out of this Fund but booked in Accounts against Administrative expenses which is being written back in 1978-79.

Previous Year (1976-77)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
50,12,43,160	Total Brought Forward.		58,20,59,628
	Permanent Advance to the Heads of Offices of the Corporation.		
56,656	As per last Balance Sheet.	64,061	
7,510	ADD Payments made during the year.	14,857	
64,166			
(—)105	LESS Recoveries made during the year.	(—)152	
64,061			78,766
	Advance of Pay on transfer to the Employees of the Corporation.		
27,815	As per last Balance Sheet.	28,597	
1,03,151	ADD Payment made during the year.	1,24,138	
1,30,966			
(—)1,02,369	LESS Recoveries made during the year.	(—)1,32,377	
28,597			20,358
	Advance of T.A. on transfer to the Employees of the Corporation.		
68,981	As per last Balance Sheet.	91,683	
1,39,452	ADD Payments made during the year.	1,73,663	
2,08,433			
(—)1,16,750	LESS Recoveries made during the year.	(—)1,86,110	
91,683			79,236
	Advance for the purchase of Conveyance to the Employees of the Corporation.		
9,41,444	As per last Balance Sheet.	8,78,529	
5,29,471	ADD Payments made during the year.	7,58,516	
14,70,915			
(—)5,92,386	LESS Recoveries made during the year.	(—)5,96,201	
8,78,529			10,40,844
	Miscellaneous Advance to the Employees of the Corporation, (Festival Advances).		
2,69,639	As per last Balance Sheet.	8,46,031	
11,17,666	ADD Payments made during the year.	8,51,071	
13,87,305			
(—)5,41,274	LESS Recoveries made during the year.	(—)10,27,430	
8,46,031			6,69,672
	House Building Advance.		
46,72,897	As per last Balance Sheet.	67,24,154	
26,82,525	ADD Payments made during the year.	26,22,991	
73,55,422			
(—)6,31,268	LESS Recoveries made during the year	(—)9,65,668	
67,24,154			83,81,477
	Advance Payments on behalf of State Governments.		
14,763	As per last Balance Sheet.	8,643	
6,927	ADD Payments made during the year.	1,994	
21,690			
(—)13,047	LESS Recoveries made during the year.	(—)9,174	
8,643			1,463
50,98,84,858	Total Carried Over.		59,23,31,444

Previous Year (1976-77)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
1,87,35,03,119	Total Brought Forward.		2,30,45,49,247
6,36,06,739	Total Brought Forward of this Head.	7,33,00,994	
(—)23,15,550	LESS Payments made during the year.	(—)19,56,748	
6,13,81,189			7,13,44,246
	10. Pension Reserve Fund for the Employees of the Corporation.		
5,35,15,481	As per last Balance Sheet.	6,90,24,383	
55,58,315	Provision made during the year.	57,06,876	
58,22,889	Interest received from investments.	42,93,580	
44,913	Gain on realisation of Investments.	—	
—	ADD Additional provision as per 5th Quinquennial Report on Valuation.	8,59,938	
6,99,41,598			
(—)9,28,332	LESS Payments made during the year.	(—)13,27,806	
6,90,13,226			
11,117	ADD Amount transferred from ESI Provident Fund	23,988	
6,90,24,383			7,85,80,959
	11. Emergency Reserve Fund		
11,00,16,095	As per Last year's Accumulation.	20,75,09,770	
8,69,33,675	Provision made during the year.	6,70,73,985	
1,05,60,000	Interest realised on Investments.	87,63,452	
—	LESS Amount transferred to the Revenue Account for meeting the Excess of Expenditure over the Income.		
20,75,09,770			28,33,47,207
	Compassionate Reserve Fund for the Employees of the Corporation.		
10,000	As per last Balance Sheet.	10,000	
29,434	Provision made during the year.	31,000	
39,434			
(—)29,434	LESS Payments made during the year.	(—)31,000	
10,000			10,000
	Deposits of Securities.		
3,83,840	As per last Balance Sheet.	3,55,615	
2,16,815	ADD Deposits during the year.	2,76,355	
6,00,655			
(—)2,45,040	LESS Deposits repaid during the year.	(—)2,46,006	
3,55,615			3,85,964
	Deduction from Bills Payable to other Parties.		
26,694	As per last Balance Sheet.	62,581	
10,88,488	ADD amount credited during the year.	12,49,025	
11,15,182			
(—)10,52,601	LESS Payments made during the year.	(—)12,79,851	
62,581			31,755
	Unclaimed Deposits in the ESIC Provident Fund.		
6,579	As per last Balance Sheet.	41,961	
33,715	ADD amount credited during the year.	9,330	
40,294			
(+)1,667	LESS Payments made during the year.	(—)585	
41,961			50,706
2,21,18,93,618	Total Carried Over.		2,73,83,00,084

Previous Year (1976-77)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
50,98,84,858	Total Brought Forward.		59,23,31,444
	Amount advanced to State Govt./ State P.W.D. etc. towards Repairs and Maintenance of Hospitals/Dispensaries/Offices of the Corporation and Staff Quarters.		
	(a) Offices of the Corporation.		
16 29,831	As per last Balance Sheet.	24,87,105	
80,180	ADD Payments made during the year.	3,35,194	
25,10.011			
(—)22,906	LESS Recoveries/Adjustments made during the year.	(—)6,84,370	
24,87,105			21,37,929
	(b) Hospitals/Dispensaries/Annexes.		
1,14,44,452	As per last balance Sheet.	1,65,92,609	
53,37,220	ADD Payments made during the year.	74,47,292	
1,67,81,672			
(—)1,89,063	LESS Receipts during the year.	(—)9,03,080	
1,65,92,602			2,31,36,821
	Miscellaneous Advances.		
17,90,517	As per last Balance Sheet.	17,73,656	
11,78,426	ADD Payments made during the year.	22,19,743	
29,68,943			
(—)11,95,287	LESS Receipts during the year.	(—)19,10,854	
17,73,656			20,82,545
	Loans to State Governments/Other Parties.		
3,11,25,166	As per last Balance Sheet.	2,92,63,430	
4,56,300	ADD Payments made during the year.	—	
3,15,81,466			
(—)23,18,036	LESS amount refunded by State Governments.	(—)19,40,330	
2,92,63,430			2,73,23,100
	Remittances.		
	Cash Remittances.		
1,98,999	As per last Balance Sheet.	(—)36,95,754	
2,32,96,44,394	ADD Debits adjusted during the year.	2,58,38,85,748	
2,32,98,43,393			
(—)2,33,35,39,147	LESS Credits adjusted during the year.	(—)2,57,95,89,575	
(—)36,95,754			6,00,419
	Other Remittances. Exchange Account.		
98,646	As per last Balance Sheet.	(—)183	
7,80,83,763	ADD Debits during the year.	8,97,66,093	
7,81,82,409			
(—)7,81,82,592	LESS Credits during the year.	(—)8,97,29,165	
(—)183			36,745
55,63,05,721	Total Carried Over.		64,76,49,603

Previous Year (1976-77)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
2,21,18,93,618	Total Brought Forward.		2,73,83,00,084
	Deposits from I.L.O. for Family Planning Project.		
—	As per last Balance Sheet.	—	
8,00,000	ADD Deposit during the year.	5,00,000	
(—)8,00,000	LESS Payments to the Family Planning Project.	(—)5,00,000	
—			—
	Miscellaneous Deposits		
17,74,904	As per last Balance Sheet.	14,36,216	
90,29,006	ADD Deposits received during the year.	62,50,102	
1,08,03,910			
(—)93,67,694	LESS Deposits repaid during the year.	(—)48,73,761	
14,36,216			28,12,557
2,21,33,29,834	Total Carried Over.		2,74,11,12,641

Previous Year (1976-77)	Assets	Amount	Total
Rt.		Rs.	Rs.
55,63,05,721	Total Brought Forward.		64,76,49,003
	Investments at Cost.		
	1. Capital Construction Reserve Fund.		
14,03,58,000	As per last Balance Sheet.	21,27,31,000	
7,23,73,000	ADD Investments d made during the year.	9,32,43,804	
—	Deduct—Realisation on Maturity or Sale of Investments.	(—)6,45,000	
21,27,31,000			30,53,29,804
	2. Permanent (Partial and Total) Disablement Benefit Reserve Fund.		
15,06,23,101	As per last Balance Sheet.	18,51,86,072	
5,32,96,600	ADD Investments made during the year.	2,54,03,758	
20,39,19,701			
(—)1,87,33,629	LESS Realisation on Maturity or Sale of Investments.	(—)3,62,74,600	
18,51,86,072			17,43,15,230
	3. Dependants Benefit Reserve Fund.		
6,82,35,292	As per last Balance Sheet.	8,26,77,106	
2,91,08,900	ADD Investments made during the year.	2,71,15,753	
9,73,44,192			
(—)1,46,67,086	LESS Realisation on Maturity or Sale of Investments.	(—)1,40,06,000	
8,26,77,106			9,57,86,859
	4. Employees' State Insurance Corporation Provident Fund.		
2,83,57,000	As per last Balance Sheet.	3,58,88,000	
1,11,64,000	ADD Investments made during the year.	1,19,89,732	
3,95,21,000			
(—)36,33,000	LESS Realisation on Maturity or Sale of Investments.	(—)66,53,400	
3,58,88,000			4,12,24,332
	5. Depreciation Reserve Fund of Buildings for the Offices of the Corporation (including Staff Quarters).		
21,76,509	As per last Balance Sheet.	26,41,400	
10,70,400	ADD Investments made during the year.	12,13,408	
32,46,909			
(—)6,05,509	LESS Realisation on Maturity or Sale of Investments.	(—)7,81,000	
26,41,400			30,73,808
	6. Depreciation Reserve Fund of Hospital Buildings.		
2,41,42,525	As per last Balance Sheet.	2,91,12,525	
1,13,37,000	Add Investments made during the year.	1,19,88,643	
3,54,79,525			
(—)63,67,000	LESS Realisation on Maturity or Sale of Investments.	(—)66,38,000	
2,91,12,525			3,44,63,168
	7. Depreciation Reserve Fund of Staff Cars.		
4,22,735	As per last Balance Sheet.	5,02,935	
1,17,700	ADD Investments made during the year.	78,803	
5,40,435			
(—)37,500	LESS Realisation on Maturity or Sale of Investments.	(—)20,000	
5,02,935			5,61,738
1,10,50,44,759	Total Carried over.		1,30,24,03,942

Previous Year (1976-77)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
2,21,33,29,834	Total Brought Forward.		2,74,11,12,641

2,21,33,29,834	Total Carried Over.	2,74,11,12,641

Previous Year (1976-77)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
1,10,50,44,759	Total Brought Forward.		1,30,24,03,942
	8. Repairs & Maintenance Reserve Fund of Buildings for the Offices of the Corporation (including Staff Quarters)		
22,63,240	As per last Balance Sheet.	23,43,545	
3,08,000	ADD Investments made during the year.	12,96,023	
25,71,240			
(—)2,27,695	LESS Realisation on Maturity or Sale of Investments.	(—)8,36,000	
23,43,545			28,03,568
	9. Repairs & Maintenance Reserve Fund of Hospital Buildings.		
4,05,62,278	As per last Balance Sheet.	4,47,87,593	
65,19,100	ADD Investments made during the year.	1,87,40,833	
4,70,81,378			
(—)22,93,785	LESS Realisation on Maturity or Sale of Investments.	(—)1,53,21,000	
4,47,87,593			4,82,07,426
	10. Pension Reserve Fund for the Employees of the Corporation.		
5,85,12,541	As per last Balance Sheet.	6,84,29,455	
1,52,79,300	ADD Investments made during the year.	4,39,11,504	
7,37,91,841			
(—)53,62,386	LESS Realisation on Maturity or Sale of Investments.	(—)3,37,60,000	
6,84,29,455			7,85,80,959
	11. Provident Fund Deposit Linked Insurance Reserved Fund.		
—	As per last Balance Sheet.	—	
—	ADD Investments made during the year.	75,063	
—	Deduct Realisation on Maturity or Sale of Investments.	—	
—			
	12. Compassionate Reserve Fund.		75,063
—	As per last Balance Sheet.	—	
—	ADD Investments made during the year.	9,999	
—	LESS Realisation on maturity or Sale of Investments.	—	
—			9,999
1,22,06,05,352	Total Carried Over.		1,43,20,80,957

Previous Year (1976-77)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
2,21,33,29,834	Total Brought Forward.		2,74,11,12,641
2,21,33,29,834	GRAND TOTAL		2,74,11,12,641

NEW DELHI,
Dated : 31st May, 1978.

Previous Year (1976-77)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
1,22,06,05,352	Total Brought Forward		1,43,20,80,95 7
	13. Emergency Reserve Fund.		
11,00,00,000	As per last Balance Sheet.	20,75,00,000	
11,75,00,000	ADD Investments made during the year.	9,18,47,207	
(—)2,00,00,000	Deduct-Realisation on Maturity or Sale of Investments.	(—)1,60,00,000	
20,75,00,000			28,33,47,207
	General Cash Balance		
36,83,00,000	Investment as per last Balance Sheet.	72,83,10,000	
62,06,60,000	ADD Investments made during the year.	45,42,21,370	
98,89,60,000			
(—)26,06,50,000	LESS Realisation on Maturity or Sale of Investments.	(—)22,30,00,000	
72,83,10,000		95,95,31,370	
25,51,026	Cash in Hand.	26,98,063	
5,43,63,456	Cash with Bankers.	6,34,55,044	
5,69,14,482		6,61.53,107	
78,52,24,482	Total Cash Balance.		1,02,56,84,477
2,21,33,29,834	GRAND TOTAL		2,74,11,12,641

Sd/-

(M. L. Sobti)
Financial Adviser &
Chief Accounts Officer,
Employees' State Insurance Corporation

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the foregoing accounts for the year 1977-78 and the Balance Sheet as on 31st March, 1978 of the Employees' State Insurance Corporation and obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations in the Audit Report appended. I certify as a result of my audit, that in my opinion these accounts and the Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Corporation according to the best of my information and explanation given to me and as shown by the books of the Corporation.

(K. C. Das)

New Delhi, Accountant General

Dated 31st January, 1979. Central Revenues

AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION FOR THE YEAR 1977-78

1. GENERAL :

(i) The Employees' State Insurance Corporation was set up in October, 1948, under the Employees' State Insurance Act, 1948. The Act was amended by Employees' State Insurance (Amendment) Acts of 1951, 1966 and 1975 and applied to all factories other than seasonal factories which use power and where twenty or more persons are or were employed for wages. All employees getting monthly remuneration upto Rs. 1,000/- are covered under the Scheme.

(ii) The Scheme is being extended gradually to the following new classes of establishments under Section 1(5) of the Employees' State Insurance Act, 1948 namely :—

(a) smaller power using factories employing 10-19 persons and non-power using factories employing 20 or more persons.

(b) Shops, Cinemas, preview theatres, hotels and restaurants, road motor transport and newspaper establishments employing 20 or more persons.

The Scheme was in operation at different Centres in the States of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal and Union Territories of Chandigarh, Delhi, Mahe, Goa Daman & Diu and Pondicherry.

(iii) During 1977-78 the provisions of the Act were extended to 5,924 factories/establishments covering 0.43 lakhs employees. The number of factories/establishments covered by the Act as on 31st March, 1978 was 49,304 having 55.43 lakhs employees (43,380 factories/establishments and 55.00 lakhs employees respectively on 31st March, 1977).

(iv) An analysis of the income and expenditure of the Corporation for the year 1976-77 and 1977-78 is given below :—

Income	1976-77 (lakhs of Rupees)	1977-78 (lakhs of Rupees)	Expenditure	1976-77 (lakhs of Rupees)	1977-78 (lakhs of Rupees)
Employees' & Employers' Contribution	13,362	13,112	1. Benefits to insured persons and their families.		
Employers' Contribution only	94	26	A. Medical Benefits		
Employees Contribution only	107	49	(i) Payment to State Govt. etc. as Corporation's share of their expenses on providing medical treatment etc.	3,399	4,447
Interest on Contributions	2	6			
State Government's share towards medical benefits initially incurred by the Corporation.	14	40	(ii) Medical treatment and care and maternity benefits expenses incurred directly by the Corporation.	243	264
Interest and dividends	729	801	B. Cash and other benefits to insured persons and their dependants paid directly by the Corporation.	3,443	3,993
Miscellaneous including rents, rates and taxes	361	421	2. Administrative Expenses		
			A. Superintendence	475	473
			B. Field work	331	359
			C. Other Charges	72	124
			3. Hospitals and Dispensaries	103	122
			4. Capital Construction Reserve Fund	1,257	1,319
			5. Emergency Reserve Fund	869	671
			6. Excess of Income	3,477	2,683
			Over expenditure	13,669	14,455
	13,669	14,455			

2. ADVANCES :

(i) Out of the amounts advanced to State Governments/ State Public Works Departments for construction of hospitals, dispensaries and other buildings and for purchase of hospital equipments of capital nature for projects, Rs 2,373 36 Lakhs (year-wise details given below) remained unadjusted on 31st March, 1978

Year in which advance paid	Amount remaining unadjusted as on 31st March, 1978 (lakhs of Rupees)
Upto 1970-71	505 30
1971-72	72 06
1972-73	59.08
1973-74	51.55
1974-75	164 72
1975-76	214.67
1976-77	553.13
1977-78	752 85
	2,373.36

Out of the above, Rs. 689.50 lakhs were stated to have been adjusted upto 30th November, 1978. The Corporation also stated (September, 1978) that the matter was being pursued with the concerned authorities for early adjustment of the balances.

(ii) Out of the amounts advanced to Government Departments and semi-Government Organisations for stationery and liveries, law charges, rent for hiring accommodation, etc., Rs. 20.82 lakhs (year-wise details given below) remained unadjusted on 31st March, 1978.

Year in which paid	Amount remaining unadjusted as on 31st March, 1978 (lakhs of Rupees)
Upto 1970-71	7 07
1971-72	0.55
1972-73	0.84
1973-74	0.40
1974-75	1.65
1975-76	0.92
1976-77	0.70
1977-78	8 69
	20.82

Out of the above, Rs 4 48 lakhs were stated to have been adjusted upto 30th September, 1978 The Corporation also stated (September, 1978) that the matter was being pursued vigorously for adjustment of the balances

(iii) Out of the amounts advanced to State Governments/ State Public Works Departments for repairs and maintenance of hospitals/dispensaries and other office buildings wholly owned by the Corporation, Rs 252 75 lakhs (year-wise details given below) remained unadjusted on 31st March 1978

Year in which advance paid	Amount remaining unadjusted as on 31st March, 1978 (Lakhs of Rupees)
Upto 1970-71	25.83
1971-72	7 98
1972-73	15.16
1973-74	14 65
1974-75	18 18
1975-76	43 79
1976-77	56 19
1977-78	70.97
	252 75

Out of the above, Rs. 1.47 lakhs were stated to have been adjusted upto 30th June, 1978. The Corporation also stated (September, 1978) that the matter was being pursued with the concerned authorities for early adjustment of the balances.

3. ARREARS OF CONTRIBUTIONS :

(i) As on 31st March, 1978, arrears of contribution amounting to Rs. 2,094.78 lakhs for the period ending 31st March, 1977 were due from the employers and employees of 12,175 factories (year-wise details given below) :—

Year	Employers' Special Contribution	Employees' Contribution	Employers' and employees' combined contribution (started w.e.f. 1-7-1973)	Total
			(Rupees in lakhs)	
Upto December, 1971	488.91	171.08	—	659.99
1-1-1972 to 31-12-1972	154.43	63.39	—	217.82
1-1-1973 to 31-12-1973	147.51	92.16	39.21	278.88
1-1-1974 to 31-12-1974	—	—	129.43	129.43
1-1-1975 to 31-12-1975	—	—	245.81	245.81
1-1-1976 to 31-12-1976	—	—	379.47	379.47
1-1-1977 to 31-3-1977	—	—	183 38	183.38
	790 85	326.63	977.30	2,094.78

Out of 12,175 factories from whom contributions for the period ending 31st March, 1977 were due as on 31st March, 1978, 457 factories were in default for more than Rs. 0.50 lakh each. The Corporation stated (January, 1979) that (a) it had already taken legal action to recover outstanding arrears of Rs. 1,563.84 lakhs; (b) action in cases involving Rs. 347.72 lakhs was under its consideration and (c) for the remaining arrears of Rs. 183.22 lakhs legal action was not possible due to court injunctions/ orders restraining recovery, factories going into liquidation or disputed coverage etc. The position of arrears due for the period ending 31st March, 1978 could not be furnished by the Corporation.

(ii) Out of decrees for Rs. 33.64 lakhs against employers remaining unexecuted as on 31st March, 1977, decrees for Rs. 30.75 lakhs (year-wise details given below) remained unexecuted as on 31st March, 1978.

Year of decree	(lakhs of rupees)
Upto 1970-71	19.44
1971-72	0.67
1972-73	1.93
1973-74	1.50
1974-75	1.87
1975-76	0.55
1976-77	4.79
	30.75

The decrees for the year 1977-78 remaining unexecuted as on 31st March, 1978 were for Rs. 1.22 lakhs. It was stated (September, 1978) that the Corporation had to depend on the State Governments and the executing Courts to get the decrees realised.

(iii) Inspection of 3,025 factories/establishments upto the calendar year 1977 remained in arrears as on 30th September, 1978 (Year-wise details given below) :—

Year	Inspections due	Inspection conducted	Inspections in arrears as on 30th September, 1978
1974	30,453	30,374	79
1975	31,645	31,413	232
1976	36 299	35,257	1,042
1977	47,104	44,079	3,025*

*Includes factories/establishments which could not be inspected during the year 1974, 1975 and 1976 also.

(iv) Out of the factories/establishments in respect of which Survey/Inspection Reports had been received the exact date of coverage in respect of 9,409 factories/establishments had not been determined finally.

Sl. No.	Name of State	No. of cases lying pending final coverage	Position upto
1.	Andhra Pradesh	545	November, 1978
2.	Assam	35	October, 1978
3.	Bihar	289	October, 1978
4.	Karnataka	146	September, 1978
5.	Kerala	62	September, 1978
6.	Madhya Pradesh	271	September, 1978
7.	Maharashtra	3,777	October, 1978
8.	Orissa	4	October, 1978
9.	Punjab	1,449	August, 1978
10.	Rajasthan	410	October, 1978
11.	Tamil Nadu	1,984	October, 1978
12.	Delhi	437	October, 1978
	Total	9,409	

The Corporation could not furnish the year-wise position of the pending cases awaiting final coverage. Figures in respect of Gujarat, Uttar Pradesh and West Bengal were stated (January, 1979) to be awaited from the Regional Directors.

ANNUAL ACCOUNTS : BALANCE SHEET :

(a) Miscellaneous Deposits :

A credit balance of Rs. 28.13 lakhs representing erroneous credits afforded by the banks and certain sundry credits on various miscellaneous items, was lying unadjusted under "Suspense Account-Miscellaneous Deposits" as on 31st March, 1978, out of which Rs. 0.54 lakhs had been adjusted upto 30th June, 1978 leaving an unadjusted amount of Rs. 27.59 lakhs (year-wise details given below) :—

Year	Amount (In lakhs of rupees)
1974-75	0.15
1975-76	2.35
1976-77	3.21
1977-78	21.88
	27.59

The Corporation stated (January, 1979) that the unadjusted amount as on 30th September, 1978 was Rs. 27.37 lakhs.

(b) Non-exhibition of cost of equipment in Balance Sheet :

The Corporation constructed 59 hospitals and 25 annexes with bed capacity ranging from 10 to 700 in different States upto 31st March, 1977 and exhibited the cost of their construction as asset in its Balance Sheet. The expenditure incurred on the equipment provided initially to these hospitals and annexes after 1967-68 (which is shareable between the Corporation and the States in the ratio of 7:1) was Rs. 2,77.29 lakhs upto 31st March, 1977 of which the share of the Corporation was Rs. 2,42.63 lakhs. The cost of the equipment has however, not been exhibited in the Balance Sheet.

The Corporation stated (September, 1978) that upto 1968 the E.S.I. hospitals were equipped at the sole cost of the Corporation and that expenditure incurred viz., Rs. 26.35 lakhs had been capitalised and shown in the Balance Sheet as on 31st March, 1977. It added that the practicability of exhibition of the cost of the equipments acquired after 1967-68 in the Balance Sheet had been under consideration and the State Governments had to be consulted in the matter.

4 (c) Valuation of assets and liabilities :

In terms of Section 37 of the Employees' State Insurance Act, 1948 the valuation of the assets and liabilities of the Corporation is required to be done after every five years. For the quinquennial valuation due at the close of 1973-74, the Valuer's Report was received in 1977-78 and the same has yet (November, 1978) to be adopted by the Corporation. The Corporation stated (January, 1979) that decisions on a part of the Valuer's Report were taken in October, 1977 and that the decisions on the rest of the Report, which had been under consideration in consultation with the Valuer, were expected to be taken in January/February, 1979.

5. LAND LYING UNUTILISED :

Eighteen plots of land purchased by the Corporation for the construction of hospitals, dispensaries, etc., in various States were lying vacant; the oldest being those purchased in 1962. The cost of such vacant land purchased upto 1976 was Rs. 20.26 lakhs.

Year of purchase	No. of plots lying vacant	Amount involved (Rupees in lakhs)
1962	3	1.95
1965	2	0.28
1966	2	6.21
1967	4	6.42
1968	3	3.58
1972	1	0.09
1974	1	1.13
1975	1	0.20
1976	1	0.40
	18	20.26

The Corporation stated (January, 1979) that in one case (land purchased in April, 1975) estimates for construction of dispensary had been sanctioned.

6. "Construction of E.S.I. Hospital at Kansabal (Orissa)" The Corporation approved in October, 1970 the construction of a 40 bedded hospital at Kansabal at an estimated cost of Rs. 5.94 lakhs (including water supply arrangements) on 5 acres of land ifted by Utkal Machinery Ltd., a private employer. On the recommendation of the Government of Orissa the work was entrusted, October, 1970 to the Orissa State Housing Board subject to the State Government taking responsibility to ensure execution of the work "in time" and "according to the specification" but no time limit was fixed for completion of the work.

The estimates for the work were revised in November, 1972 to Rs. 7.98 lakhs stated to be due to increase in the cost of labour and building materials and inclusion of a few items which had not been included in the original estimates. While the Orissa Housing Board contended that the work was completed in June, 1973, the Corporation did not take possession of the building on the ground that arrangements for supply of water for the hospital had not been completed. Later (July, 1974) it was decided to entrust to the private employer-Utkal Machinery Ltd.,—making of water supply arrangements for the hospital building. In October, 1975 the Corporation advanced to the employer, at its request, through the State Government a ten years interest-free advance of Rs. 2 lakhs to meet the cost of machinery and equipment etc. required for making the water supply arrangements.

The Corporation took possession of the building in October, 1975 and the hospital was commissioned in January, 1976. Meanwhile, the expenditure on the work including construction of staff quarters, approach road, etc. but excluding water supply arrangements, incurred upto March, 1977 had gone up to Rs. 12.72 lakhs; in addition Rs. 2 lakhs had been advanced to the private employer for making water supply arrangements.

[No. G. 25012/1/79-HI]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980